

January to March 2025  
E-Journal  
Volume I, Issue XLIX

RNI No. – MPHIN/2013/60638  
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793  
Scientific Journal Impact Factor- 8.054  
ISO 9001:2015 - E2024049304  
(Quality Management System)

# Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



# नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)  
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

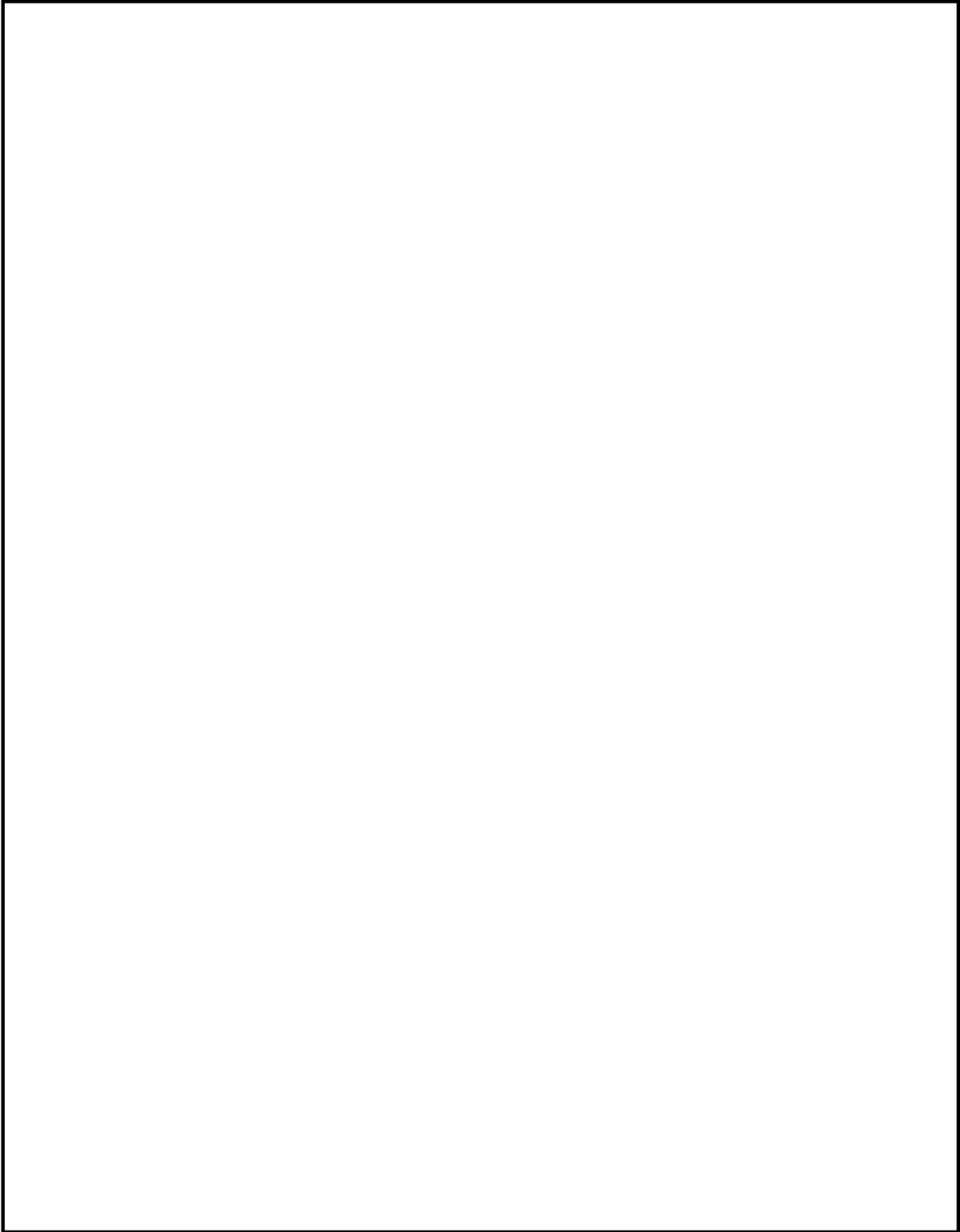
## Index

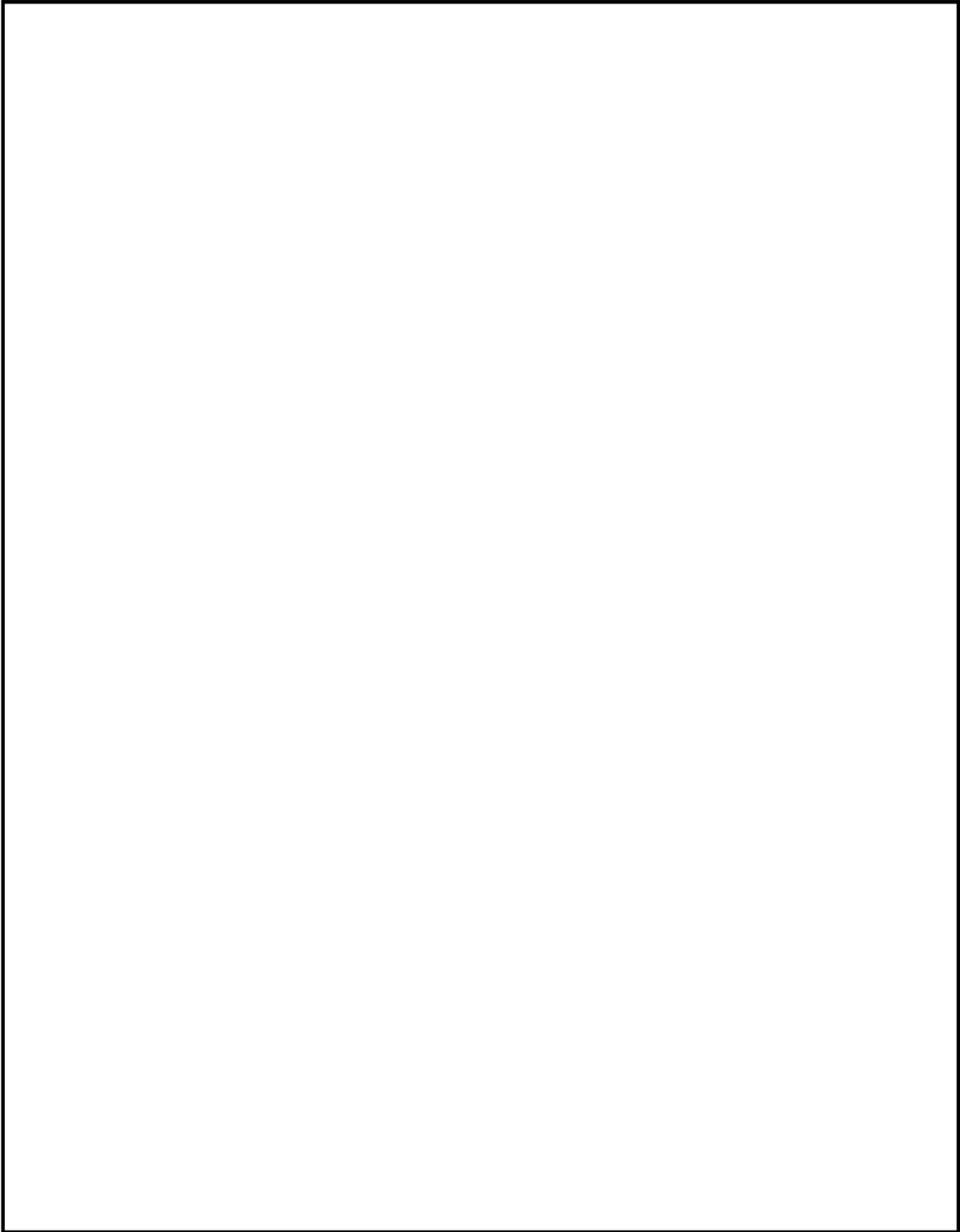
01.	Index .....	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board .....	08/09
03.	Referee Board .....	10
04.	Spokesperson .....	12
05.	Effect of GST on Small and Micro Enterprises in Himachal Pradesh: A Study of South Zone ..... (Dr. Bhumander Singh Jaswal)	14
06.	Rural Women's Development and Self-Help Groups (Narendra Singh Panwar) .....	20
07.	Study of Ethno-Medicinal Plant's Use Increasing Immunity (Dr. Sarita Ghanghat) .....	23
08.	Ethnobotany: Traditional herbal remedies used by Tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, ..... India (Dr. Kamal Singh Alawa)	27
09.	New Education Policy 2020 - Opportunities and Skill Building (Dr. Ruchi Rathore) .....	31
10.	Issues and Prospects in Teacher Education Programme (Dr. Kalpana Singh) .....	33
11.	Enhancing Environmental Education Through Pre-Service Teacher Training: ..... Strategies, Benefits, and the Role of Educators (Ranjana Sharma, Ramesh Chandra Nagda)	36
12.	Comparison of Perceived Motivational Climate by Male and Female Intercollegiate Players ..... of Selected Team Games (Manish Mukherjee, Dr. Jai Shankar Yadav)	41
13.	Chemical Study of Indigenous Plants for Respiratory Health of Nimar Region of ..... Madhya Pradesh (Vineeta Dawar, Dr. Pramod Pandit)	45
14.	Culture of Madhya Pradesh : GOND TRIBAL ART (Dr. Vandana Sharma) .....	48
15.	Characteristic Studies of 2D Materials PVA Augmented by Vanadium Oxide .....	51
16.	Incubation Centers in Academic Institutions and Expectations of Students who Aspire to be ..... Entrepreneurs (Sunder L Dindugal)	55
17.	Negative Impact of Rhesus Monkeys in some states of North India .....	60
18.	Effect of Over Consumption and Lack of Sugar on Human Being (Dr. Rajesh Masatkar) .....	63
19.	Understanding Indian Popular Literature (Pr Minu Gidwani) .....	66
20.	Exploration of Indian Medicinal Plant i.e, <i>Uraria Picta</i> in term of their extraction and ..... processing for pharmacological and toxicological studies (Mahesh Kumar Ahirwar, Asha Verma, Santosh Ambhore, Laxmi Bareliya)	71
21.	Advancing Green Catalysis: Pioneering Innovations and Sustainable Applications in ..... Chemistry (Dr. S.K. Udaipure)	74
22.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन एक अध्ययन (जोधपुर जिले के संदर्भ में) ..... (डॉ. नीति चौहान)	78
23.	महिला कथाकारों के उपन्यासों में मानवीयता (डॉ. राजेश श्रीवास) .....	84
24.	महात्मा गाँधी और उनका दर्शन (डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते) .....	87
25.	भारतीय जनता पार्टी में धार जिले की जनजातीय महिला नेतृत्व की भूमिका ..... (दयाराम डावर, डॉ. ममता पाण्डेय, डॉ. सीमा सस्त्या)	89
26.	कार्यक्षेत्र में तनाव प्रबंधन का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव (डॉ. आराधना श्रीवास) .....	92
27.	भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री विमर्श (श्रीमती अनीता अग्रवाल) .....	95
28.	उषा प्रियवंदा के उपन्यासों में नारी जीवन के विविध आयाम (डॉ. अर्चना बापना) .....	98

29.	रावजोधा की प्रमुख उपलब्धियाँ (डॉ. सुमित मेहता) .....	103
30.	पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण (विजय लक्ष्मी जोशी) .....	105
31.	दमोह जिले के पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन..... (ललित ताम्रकार, डॉ. आभा वाष्णैय)	108
32.	भारत के पुनरुत्थान के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय दृष्टिकोण एवं उसका समग्र अध्ययन..... (गरीमा राठौर, महेन्द्र पटेल)	111
33.	न्याय की देवी : भंगाराम माई (बस्तर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग, प्रो. एन. आर. साव) .....	114
34.	शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर में पाए जाने वाले इथनोमेडिसिनल पौधों का अध्ययन .....	116
	(डॉ. राजेश बकोरिया)	
35.	Civil-Military Relations: A Comparative Study of India and Pakistan..... (Dr. Vinay Girotra, Dr. Ranjit Singh)	119
36.	NEP 2020: Transforming Higher Education in India (Dr. Nayia Mahajan) .....	125
37.	Legal Response to Mob Lynching: Effectiveness, Challenges, and Recommendations .....	129
	(Sarvesh Kumar, Dr. Surya Sharma)	
38.	Innovative Materials for Environmental Remediation: A Comprehensive Review .....	132
	(Dr. Rashmi Ahuja)	
39.	India's Role as a Mediator in the US-China Hegemony Conflict: A Comprehensive Study .....	137
	(Kaustubh Nihal)	
40.	Impact of Monetary policy on Inflation in India (Anil Chouhan) .....	141
41.	कृषि क्षेत्र के विकास में भूमि सुधार का योगदान (श्रीमती सुमन भवर, डॉ. नीमा चुण्डावत) .....	144
42.	किशोरियों का साथियों के साथ समायोजन का अध्ययन (डॉ. ममता खपेडिया, रिंकी भाबर) .....	146
43.	व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं रोजगार (नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में) (डॉ. पूजा तिवारी).....	148
44.	वेद, उपनिषद एवं भारतीय साहित्य में महिलाओं की भूमिका : श्रीमद्भगवद्गीता के विशेष संदर्भ में .....	150
	(भावना तिवारी)	
45.	भारत में पर्यावरण सम्बन्धी कानून एवं नीतियों का अध्ययन (डॉ. नीतू) .....	154
46.	जीव विज्ञान की उपलब्धि में इण्टरनेट की उपयोगिता का अध्ययन (डॉ. नाजिया कौशर, रेनुका शर्मा) .....	157
47.	भारतीय इतिहास में भक्तिकालीन संत पीपाजी का जीवन एवं कृतित्व एक अध्ययन (डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत) .....	159
48.	उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिलाषाओं का विश्लेषण .....	161
	(राकेश कुमार जीनगर, डॉ. राखी शर्मा)	
49.	छठी शताब्दी ईसापूर्व में पर्यावरण चेतना का विकास (डॉ. नीलम सोनी) .....	164
50.	पृथ्वी पर जलीय चक्र एवं जल चक्र की क्रिया-विधि का अध्ययन (नेहा शर्मा, डॉ. राजू शर्मा) .....	167
51.	लिंगीय असमानता और चुनौतियां (डॉ. पिंकी सोमकुवर) .....	169
52.	आधुनिक कृषि यंत्रीकरण में नवीन तकनीकी ज्ञान का अध्ययन मध्यप्रदेश के बड़वानी एवं धार जिले..... के सन्दर्भ में (श्रीमती सुमन भवर, डॉ. नीमा चुण्डावत)	173
53.	मुंशी प्रेमचन्द के लघु उपन्यास, निर्मला, प्रतिज्ञा का अनुशीलन (डॉ. अर्चना बापना) .....	175
54.	Study of Effect of Temperature, Light intensity and Irradiation time during Decolouration .....	178
	Process of Methyl Green Dye (Dr. David Swami)	
55.	Role of Judiciary in the Elimination of Juvenile Delinquency in the Present .....	180
	Social Justice System (Vikram Singh Chandel)	

56.	डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अख) का उपयोग (डॉ. अनिल तौहेल) .....	184
57.	नई शिक्षण क्षमताएँ: आधुनिक शिक्षा में नवाचार और तकनीकी एकीकरण (डॉ. अनिल तौहेल) .....	187
58.	डाकघर की सुकन्या योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन इन्दौर जिले के सन्दर्भ में .....	191
	(डॉ. जे.के. जैन, डॉ. पी.के. सन्से, विभा सोहरा)	
59.	स्वामी दयानंद सरस्वती के वैचारिक आंदोलन का भारतीय शिक्षा नीति पर प्रभाव .....	194
	(हीरा लाल अहीर, डॉ. राखी शर्मा)	
60.	नवीकरणीय ऊर्जा : भविष्य की आवश्यकता (प्रो. रेणुका पाटीदार) .....	196
61.	Digital Farming: New Perspective in Agricultural Development .....	200
	(Dr. Kumud Dubey, Dr. Avinash Dube)	
62.	Digital Data Protection and Artificial Intelligence: A New Era in the World (Deepika Joshi) .....	202
63.	The Future of Fintech and its Role in Streamlining the Commerce Experience .....	205
	(Dr. Preeti Anand Udaipure)	
64.	Sustainable Marketing Strategies and Their Impact on Consumer Purchase Intentions .....	212
	(Ritvik Roonwal)	
65.	फैशन ब्रांडों की बिक्री बढ़ाने में सोशल कॉमर्स की भूमिका (डॉ. रुक्मणि यादव, प्रो. प्रमोद यादव) .....	220
66.	ई.एम.आई. चार्वाक दर्शन और मानव जीवन (सुभाषनगर, सागर के संदर्भ में) (प्रिया ठाकुर डॉ. सुनील साहू) .....	223
67.	To Study the Dietary Pattern in the Second Trimester of Pregnancy .....	227
	(Dr. Mamta Khapediya, Roshni Singh)	
68.	मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष .....	229
	संदर्भ में) (डॉ. संगीता कुम्भारे)	
69.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता : कारण, प्रभाव और समाधान (प्रो. आरती बारोटिया) .....	233
70.	Water Quality Index of Mansarovar Pond at Dhar (M.P.) .....	236
	(Dr. Dara Singh Waskel, Dr. Bhagwan Singh Patel)	
71.	Unemployment in India: A Qualitative Exploration of Challenges and Possibilities .....	238
	(Dr. Vibha Nigam)	
72.	Financial Literacy and Portfolio Diversification: Evidence from India's Middle-Class .....	243
	Investors (Dr. Preeti Anand Udaipure)	
73.	Study of Ambient Air Quality in Rewa City (M.P.) in Reference of Respirable Suspended .....	248
	Particulate Matter (Rspm), Sulphur Di Oxide and Nitrogen Oxide. (Shrishti Singh, Dr. Atul Tiwari)	
74.	सिंदूर पौधे का महत्व एवं उपयोगिता (डॉ. मनीषा दंडवते) .....	252
75.	Status, Cause and Resurrection of Rare, Endangered and Threatened Forest Tree .....	255
	species of Madhya Pradesh (Dr. Dinesh Kumar Dahare)	
76.	Effect of Yoga as a Relaxation Technique on Sleep quality among School Students .....	258
	Appearing Board Exam (Ms. Sushruta Sahu, Dr. Varsha Sharma)	
77.	प्राचीन भारतीय प्रतिरक्षा एवं सैन्य संगठन व युद्ध में नैतिक नियमों की उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में .....	261
	(डॉ. जे.के. संत)	
78.	21वीं सदी का भारत और गांधीवाद (डॉ. नीरज कुमार) .....	263
79.	English for a Specific Purpose: Essay Writing for Undergraduate Students in North India .....	269
	(Dr. Omprakash Upadhyay)	
80.	सोनभद्र जिले में मनरेगा का क्रियान्वयन : एक सामाजिक अंकेक्षण (डॉ. गुंजन श्रीवास्तव) .....	271

81. Impact of Ayushman Bharat Scheme on Beneficiaries in Rewa, Madhya Pradesh ..... 276  
(Eshika Agrawal, Dr. Kumud Shrivastava)
82. भारतीय चित्रकला के वर्तमान आयाम व प्रो० भगवती प्रकाश काम्बोज (कुलदीप कुमार, डॉ. निशा गुप्ता) ..... 278
83. सरकारी कामकाज में हिंदी : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. आराधना सिंह) ..... 280
84. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन .... 283  
(राधा रानी गौतम, डॉ. खेल शंकर व्यास)
85. मध्य प्रदेश में कृषि विकास की आधारभूत संरचना (फसल में नियोजन का अध्ययन) (डॉ. भावना भटनागर) ..... 286
86. 'संचार के आधुनिक साधन मोबाईल' का युवाओं के सामाजीकरण पर प्रभाव का अध्ययन कसरावद शहर ..... 289  
के महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. उषा यादव)
87. The Role of Incubation Centers in Nurturing Startups: Fostering Innovation, Growth, ..... 292  
and Sustainability (Anchal Ramtake)
88. Between the Space and the Earth : A Study of 'Orbital' as Creative Non-Fiction ..... 295  
(Dr. Kiran Sitole)
89. राष्ट्र निर्माण एवं शैक्षणिक समस्याएँ एक अध्ययन (श्रीमती चित्रमाला भिमटे) ..... 297
90. राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्र निर्माण में योगदान का अध्ययन (डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे) ..... 299
91. मध्यप्रदेश के धार जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता का वितरण प्रतिरूप : एक भौगोलिक अध्ययन ..... 302  
(डॉ. किरण मण्डलोई)
92. आचार्य विशुद्धसागर के साहित्य में अध्यात्म और दर्शन : एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण ..... 305  
(डॉ. रचना तैलंग, दिलीप कुमार जैन)





## Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India



## Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

## Referee Board

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Maths                | - | (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)  |
| Physics              | - | (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)   |
| Computer Science     | - | (1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)  |
| Chemistry            | - | (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)  |
| Botany               | - | (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)<br>(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)   |
| Life Science         | - | (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)<br>(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)   |
| Statistics           | - | (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)  |
| Military Science     | - | (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)  |
| Biology              | - | (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)   |
| Geology              | - | (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)   |
| Medical Science      | - | (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)  |
| Microbiology Sci.    | - | (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)  |
| **** Commerce ****   |   |  |
| Commerce             | - | (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)<br>(4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)   |
| **** Management **** |   |  |
| Management           | - | (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)  |
| Human Resources      | - | (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)  |
| Business Admin.      | - | (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)<br>(2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)   |
| **** Law ****        |   |  |
| Law                  | - | (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)<br>(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)<br>(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)                  |
| **** Arts ****       |   |  |
| Economics            | - | (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)<br>(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) |
| Political Science    | - | (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)   |
| Philosophy           | - | (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)  |
| Sociology            | - | (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)<br>(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)<br>(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)   |

- Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)  
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)  
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)  
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)  
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- \*\*\*\*\* Home Science \*\*\*\*\*
- Diet/Nutrition Science - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)  
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)  
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- \*\*\*\*\* Education \*\*\*\*\*
- Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)  
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)  
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)  
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)  
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- \*\*\*\*\* Architecture \*\*\*\*\*
- Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- \*\*\*\*\* Physical Education \*\*\*\*\*
- Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)  
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)  
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- \*\*\*\*\* Library Science \*\*\*\*\*
- Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

## Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 46. Prof. Dr. R.K. Yadav           | - | Govt. Girls College, Khargone (M.P.)                              |
| 47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta     | - | Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)                                |
| 48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi     | - | Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)                                   |
| 49. Prof. Dr. Prabha Pandey        | - | Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)                    |
| 50. Prof. Dr. Rajesh Kumar         | - | Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)                     |
| 51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel | - | Govt. P.G. College, Satna (M.P.)                                  |
| 52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta     | - | Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)                         |
| 53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash   | - | Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)                 |
| 54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava    | - | Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)                        |
| 55. Prof. Dr. Sunil Vajpai         | - | Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)                            |
| 56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya        | - | Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)                                   |
| 57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain   | - | Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)                             |
| 58. Prof. Dr. Niyaz Ansari         | - | Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)                      |
| 59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel    | - | Govt. College, Harda (M.P.)                                       |
| 60. Dr. Suresh Kumar Vimal         | - | Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)                     |
| 61. Prof. Dr. Amar Chand Jain      | - | Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)                       |
| 62. Prof. Dr. Rashmi Dubey         | - | Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)       |
| 63. Prof. Dr. A.K. Jain            | - | Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)                     |
| 64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar      | - | Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)                    |
| 65. Prof. Dr. Rajiv Sharma         | - | Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)                    |
| 66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava    | - | Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)                    |
| 67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela   | - | Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)                   |
| 68. Prof. Dr. Balram Singotiya     | - | Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)                  |
| 69. Prof. Dr. Vimmi Bahel          | - | Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)                  |
| 70. Dr. Aprajita Bhargava          | - | R.D.Public School, Betul (M.P.)                                   |
| 71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan    | - | Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)                      |
| 72. Prof. Dr. Pallavi Mishra       | - | Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)                         |
| 73. Prof. Dr. N.P. Sharma          | - | Govt. College, Datia (M.P.)                                       |
| 74. Prof. Dr. Jaya Sharma          | - | Govt. Girls College, Sehore (M.P.)                                |
| 75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi      | - | Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)                 |
| 76. Prof. Dr. Ishrat Khan          | - | Govt. College, Raisen (M.P.)                                      |
| 77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi   | - | Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)                                 |
| 78. Prof. Dr. Bhawana Thakur       | - | Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)                       |
| 79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma    | - | Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)       |
| 80. Prof. Dr. Renu Rajesh          | - | Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)                   |
| 81. Prof. Dr. Avinash Dubey        | - | Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)                                |
| 82. Prof. Dr. V.K. Dixit           | - | Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)                       |
| 83. Prof. Dr. Ram Awdesha Sharma   | - | M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)                           |
| 84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri  | - | Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)            |
| 85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla    | - | Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)                      |
| 86. Prof. Dr. Anoop Parsai         | - | Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh ) |
| 87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain      | - | Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)               |
| 88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya     | - | Govt. Girls College, Barwani (M.P.)                               |
| 89. Prof. Dr. Archana Vishith      | - | Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)                         |
| 90. Prof. Dr. Kalpana Parikh       | - | S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)                   |
| 91. Prof. Dr. Gajendra Siroha      | - | Pacific University, Udaipur (Rajasthan)                           |
| 92. Prof. Dr. Krishna Pensia       | - | Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan) |
| 93. Prof. Dr. Pradeep Singh        | - | Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)                |
| 94. Prof. Dr. Smriti Agarwal       | - | Research Consultant, New Delhi                                    |

# Effect of GST on Small and Micro Enterprises in Himachal Pradesh: A Study of South Zone

Dr. Bhumander Singh Jaswal\*

\*Assistant Professor (Commerce) Govt. College, Bilaspur (H.P.) INDIA

**Abstract :** The introduction of GST simplified the country's indirect tax structure, ensuring smooth commercial transactions across the country. In this system there are four GST types namely Integrated Goods and Services Tax (IGST), State Goods and Services Tax (SGST), Central Goods and Services Tax (CGST), and Union Territory Goods and Services Tax (UTGST). The government must make GST a landmark tax reform rather than a tax regime laden with fears and apprehensions. The GST is help to avoid the tax on tax of production distribution chain of the business. By implementation of GST get many changes in the tax system.

**Keyword:** Indirect Tax, GST, Impact of GST, Cost Effect.

**Introduction** - The Central Government and the State Governments each levy their own taxes under the taxation system in India. A few small taxes are also collected by local governments like the municipality and other local governments. All the tax system is classified into two categories i.e. direct and indirect system. In 2017 a major change occurred in indirect tax system when GST implemented in India. The introduction of GST simplified the country's indirect tax structure, ensuring smooth commercial transactions across the country. In this system there are four GST types namely Integrated Goods and Services Tax (IGST), State Goods and Services Tax (SGST), Central Goods and Services Tax (CGST), and Union Territory Goods and Services Tax (UTGST). GST imposed by specific State governments on the intra-state trade and services or trade within the state is called SGST (State-GST). Here the revenues are earned by the state govt. due to SGST as the transaction occurred within the state. For example: suppose goods manufactured and sold within Himachal state then SGST will be collected by the Himachal state. In case of union territories such as Chandigarh, instead of state govt. the GST is collected by the central administration and is referred to as UGST (Union-GST). Intra-State transaction of goods and services, CGST (Central-GST) is levied by the central government. It is collected along with the SGST or UGST, and the revenues collected are distributed between the state and the central govt. For example: if the goods or services are provided within State Himachal, then along with SGST or UGST, CGST will also be collected. IGST: Integrated GST is collected on goods and services transactions between different states.

The government must make GST a landmark tax reform rather than a tax regime laden with fears and apprehensions. The GST is help to avoid the tax on tax of production distribution chain of the business. It is also applied to imports or exports of goods and services. Here the SGST portion of the tax collected is given to the state, which is the consumer of the said goods or services. The IGST earned is then divided between the state and the central government. The impact of GST on retail sector is going to be positive from taxation and operation point of view. During the implementation stage of GST, the retailers faced some complexities because they were not fully aware about GST. Sometimes consumers feel higher price for goods and services after the implementation of GST. But in certain circumstances, they will also get benefits from GST. They were relieved from earlier overall tax burden. Whether the impact of GST is good or bad, its implementation in retail shops helps our society work in more efficient and cost-effective manner.

## Literature Review

**Abhijith and Meenu Suresh (2019)** have concluded that most of the retailers are worrying about the fact that complex formalities and documentation coupled with vague or low clarity provisions has been adversely affected the retailers in their daily routine. Pre-GST is preferred to Post-GST in certain aspects constituting demand for products, services and compliance costs whereas Post-GST is dominated in transparency and tax credit availability. The study discovered that the implementation of GST created a bleak impact even though various wholesalers and retailers had benefitted from the same. Despite the idea is tenable and exemplary, still GST has made certain problems to the

business to operate. The major portion of the respondents have an opinion that GST can be revamped to an ideal system by eliminating technicality issues, diminishing tax rates, more clarity on provisions and avoiding needless complications. It can be concluded that GST is a scientific system of taxation but in India it needs lot of amendments, convenience e and rationalizations.

**Sheela et al. (2019)** observed that the GST is help to avoid the tax on tax of production distribution chain of the business. By implementation of GST get many changes in the tax system. GST system is an invoice matching by the way to ensure flow of return in various parts of country. By the GST return is use common language to filling the tax it so easy to understand to everyone in the country. GST increase the paying of tax payer and also increase the revenue level of the county. Now most of the retailer is get awareness about GST. The study also suggested that the GST is good to their business by avoiding the black money it makes digital India it benefits for the future business retailers. GST is improving step by step in future period cashless transaction are realized than the black money fully destroy in our economy.

**Priyanka Sharma (2020)** observed that the government is trying to smoothen the road to GST. It is important to take a leaf from global economies that have implemented GST (like France was the first country to implement GST in 1954) and who overcame the teething troubles to experience the advantage of having a unified tax system and easy input credits. GST will make taxation easy for industries. Customer will also be benefited as the overall tax burden on goods and services are reduced. The government must make GST a landmark tax reform rather than a tax regime laden with fears and apprehensions.

**P. Sarkar and S. Rani (2020)** have observed that the Indian business situation producing industry is the assuming critical job, in business world. Assembling part is financial development of country. At the point when the nation centre's on assembling industry, the nation conquers mechanical hindrances. In spite of the fact that the positive effects are reliant on an unbiased and sound plan of the GST, adjusting the clashing interests of different partners, full political duty for a major expense change with a protected alteration, the switchover to an impeccable GST has been a major jump in the backhanded tax assessment framework and furthermore give another driving force to India's financial change.

**P. Varalakshmi and K. Santha Kumari (2021)** have exhibited that the customers may be pleased about the reduction in the amount of payments they are paying now in order to please their taste buds and hotel and restaurant owners can celebrate because they can now claim input tax credits easily. The restaurant industry has been burdened with high and multiple taxations. However, liquor should be included in GST. Exempting it defeats the very purpose of bringing in a uniform single tax structure. This

is neither beneficial for 'ease of doing business' nor for the customers, "Everybody likes consolidation of taxes as it leads to greater transparency and will help guests and buyers understand the overall costs. Overall, GST should be positive for the sector assuming that the multiplicity of taxes will go away in food and beverages.

**Anchal Ojha et al. (2022)** has observed that the tax policies play a vital role in the economy as a source of money. With the new online policies of Good and services tax, it will break all barriers between central and state government and help in boost the economy. The journey of indirect taxation is momentous. Few years ago the concept of GST was introduced in India but the bill was not passed; now the enforcement of GST has done under the guidance of honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. After this dynamic step, all the sectors in economy have clearer and transparent taxation system as all the process is online. It has reduced the hidden and embedded taxes. The Central and State Government's levies have been unified with the introduction of GST. The drawbacks of previous taxes have been overcome by GST as it removed the cascading effect of tax and multiple taxes to boost up the economy. With the implementation of GST, the difficulty of filing indirect taxes has decreased. Doing business at National and International level is easier now because of GST.

**S. Bhuvanewari and Deepak. M (2022)** suggested that the Government has to create awareness regarding rules, regulations, and compliances of GST by arranging workshops, seminars, conferences to educate proprietors of SSIs, the government of India should have to increase threshold limit from 20 lakhs to 1.5 crores hence that reduces tax burden to small businesses, the government has to take initiative measures to reduce compliance cost. This will help full to lower their product prices. The study also suggested that the GST is IT backed infrastructure that needs necessary training to the employees hence government should provide necessary training facility to employees and proprietors of SSIs. The business is in different states needs separate registration may increases compliance cost hence one registration should be there for entire business. That encourages business to diversify their business activities beyond their states. The study also revealed that exemption should be given to certain products of small industries in order to encourage small traders in the country.

**Kanimozhi (2023)** has analyzed that the GST is one of the most significant tax reforms since independence. It has consolidated multiple indirect taxes into a single statute in order to achieve consistency in the form of "One Nation, One Tax." However, in order for it to be acceptable to everyone, it is critical that everyone's representation be taken into account. It should take into account the issues that MSMEs face and make it easier for them to accept it as a normal business element rather than a requirement for compliance. To obtain a broadly acknowledged

conclusion, the impact of GST on the economy must be examined in its entirety. The introduction of GST simplified the country's indirect tax structure, ensuring smooth commercial transactions across the country and beyond the world.

**Rajeev Kumar Gupta (2023)** conclusion has been drawn and has found that Direct tax collection is showing increasing trend. ii. In comparison to direct tax indirect tax collection is showing decreasing trend. iii. Direct tax to GDP ratio is also showing increasing trend. iv. Indirect tax to GDP ratio is not showing stationary trend but it was found that indirect tax contribution is continuously decreasing in trend total tax collection during the study period. v. Total tax collection to GDP ratio is also showing increasing trend.

**M. Senthil kumar (2023)** has observed that implementation of GST in retail shops affects our everyday lives in different ways. Implementation of GST is one of the best decisions taken by the Indian government. The impact of GST on retail sector is going to be positive from taxation and operation point of view. During the implementation stage of GST, the retailers faced some complexities because they were not fully aware about GST. Sometimes consumers feel higher price for goods and services after the implementation of GST. But in certain circumstances, they will also get benefits from GST. They were relieved from earlier overall tax burden. Whether the impact of GST is good or bad, its implementation in retail shops helps our society work in more efficient and cost-effective manner.

**K. Rithu Varjitha (2023)** has concluded that the tourism has been an important aspect in Agra since many decades' not only domestic but also international tourists visits the destination for its spiritual significance. The introduction of GST rates in tourism and hotel industry was initially from the company owners and it effects in understanding its implementation in various tourism companies in Agra, a city in the state of UP. The sector May benefit in the form of lower tax rates which should help in attracting more tourists in India. Since Agra is one among the leading tourist destinations in India thanks to its pilgrimage and spiritual significance, the taxes should be maintained intrinsically to chop down the value of the services. The rates should be maintained simultaneously in order that the tourist count doesn't fall and therefore the destination doesn't decline. GST may be a glimmer of hope for the Hotel and Tourism Industry if we will keep the GST rate between 10 to fifteen. GST might herald its uniformity of tax. To combat such issues steps should be taken not only by the government but also the host community and tourists to guard the rates of the services within the destination.

**Deepti Daga and P. Ganesh Anand (2024)** has observed that existing enterprises, GST has simplified the tax structure, unified the market hence improved the overall operational efficiencies of small, so far the unorganized small enterprises were growing fast than the organized ones because of the tax avoidance, with GST in effect, it has

made the taxation system has got transparent thus making the entities liable for tax payment. For a new entrepreneur, the application of GST, made the registration for taxation easy, relieved them from previous VAT registration. The Government has implemented GST with a view of long-term better prospect for the country by various aspects. The goods and services tax (GST) makes the tax system easy and thus contributing in the growth of the country. The Government applied GST by summing up of various taxes under CGST & SGST, transparent taxation, reduced raw material cost, to bring down the cost of goods and services and the ease of doing business in India. Initially there was huge chaos regarding the enactment of GST, but many successful businesspersons supported it and considered it as a boon for the long-term development of the nation. GST being the big step of Government of India to simplify the previous tax system has both positive and negative impact on business regulations of Micro, Medium & Small Enterprises.

**Objectives of the Study:** The objectives of the study will be as under:

1. To examine the impact of GST on Inflationary cost, income, documentary process, manual work etc.
2. To analyses the qualification-wise impact of GST on Income of entrepreneurs business.

**Methodology adopted:** The study primarily based on the primary data which is collected from 500 entrepreneurs selected randomly is base for the analysis. A questionnaire was developed exclusively for the purpose of collecting the primary data, particularly to examine the impact of GST on compliance factors. Consistent with the objective of the study, different techniques like the simple percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis and chi-square have been used for the analysis of the collected data.

### Results and Discussion

**Impact of GST (Compliance Factors):** It is evident from the table-1 that the mean score of the respondent views regarding the impact of the GST on inflationary cost is more the standard average score. The variation in their opinions is recorded at 1.1934, while skewness is -0.591. It depicts that their opinion is distributed more towards the higher side to agree and strongly agree. Further, the calculated value of kurtosis reveals that the distribution is scattered towards the higher side of the mean score which supports the above opinion. The  $\chi^2$  test of goodness of fit is significant at 1 percent level of significance; so null hypothesis is rejected. It reveals that the opinions of the respondents are not equally distributed. Thus, it can be concluded that the major chunk of the respondents have opined that GST successful in reduction the inflation cost in the economy, around 24.8% of the businessman's considers that GST has failed in reducing the inflation.

It is revealed that the mean of the entrepreneurs' views regarding the impact of the GST on income is more than



the standard average score. The standard deviation is 1.1627, while skewness is -0.443. Thus, the major chunk of the respondents (56.4.%) either agrees or strongly agrees with the statement that the GST helps increase the income. The calculated value of kurtosis also supports the above opinion. Further, the value of  $X^2$  when compared with the table value is at 1 percent level of significance. It shows that the opinions of the respondents are not equally distributed. Thus, the above analysis reveals that the GST has helped in increasing the income of the businessman's of Himachal Pradesh.

It is inferred from the table that the mean score of the businessman's views regarding the Introduction of GST has increased the documentary process above the standard average score. The standard deviation is 1.3144. Further, the negative value of skewness implies that an overwhelming majority of the respondents either agree or strongly agree to the statement that the implementation of GST has increased the documentary work in the state. The test of goodness of fit also indicates significant difference in the distribution of opinions of these respondents with maximum concentration towards the higher side on the five point scale. Thus 55.8% of the responded answered that GST has increased in their documentation as for each transaction they need proofreading.

It is exhibited that the mean score is 3.566 and it is above the average mean score (3). It depicts that the majority opinion is divided between agree and strongly agree responses. The standard deviation is 1.3570 and negative value of skewness is (-0.812), which also point out that the majority of opinions of the respondents are highly concentrated towards the higher side on the five point scale. The  $X^2$  test of goodness of fit also supports the above findings as there is significant difference in the distribution of opinions of the respondents. Thus, it is clear from the above statistical analysis that the GST has made it mandatory to provide bill to the customers.

It is inferred that the mean of the responses of entrepreneurs relating to the impact of the GST on reduction of manual work is higher than the standard average mean score. It reveals that the majority of the respondents agree with the statement that the reduced the manual work by providing the online registration in the filing process of tax. The value of skewness also supports that the opinion of the businessmen is tilted towards the higher side of the mean score. The calculated value of kurtosis is 1.127 which depicts that the distribution of responses is platykurtic. The highly significant value of  $c_2$  also supports the fact that the opinion is not equally distributed. Thus, it is clear from the above statistical analysis that a large number of respondents, about 55.02 percent are of the opinion that the introduction of online filling of tax has reduced their manual work as they need to submit the framed form with required information in the state.

**Table 1 (See last page)**

**Educational Level and Impact of GST on Income:** The total sample of 500 businessmen is categorized into four different education groups, matric, 10+2, graduate and post graduate or above. It is exhibited from Table 2 and Figure-1 that the mean scores of the respondents of each qualification level is more than the mean standard score. It infers that an overwhelming majority of the respondents either agree or strongly agree to the statement that the GST has increased the income of the respondents and their business in the state.

**Table 2 & Fig. (See last page)**

The standard deviation is recorded more in the respondents of the graduate group and the lowest in the matric group. The value of skewness of the aggregate opinion of the respondents is negative (-0.443) and it ranges between -0.431 to -0.819 qualification wise. It also indicates that the responses are highly concentrated towards the upper side of the standard mean score. While applying the test of goodness of fit, it depicts significant difference in the distribution of opinion of the respondents. Thus, it is clear from the above statistical analysis that a large chunk of the respondents opine that the GST has helped to increase the income of the entrepreneurs and their enterprise in the state.

**Conclusion :** The major portion of the respondents have an opinion that GST can be revamped to an ideal impact on cost reduction, increasing income of retailers, GST increase easy way for implementation of documentary process and reduced manual work. After implementation of GST it reduces technicality issues, diminishing tax rates, more clarity on provisions and avoiding needless complications. It can be concluded that GST is a scientific system of taxation but in India it needs some amendments, convenience and rationalizations.

#### References:-

1. Abhijith and Meenu Suresh, "A Study on Impact and Influence of GST on Retailers in Kerala With Special Reference to Kottayam District," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, "Vol. 6, No. 6, June 2019, pp. 171-177.
2. Sheela and R. Murugesan, A. Subangini Devi, "A Empirical Research on Retailer Perception on GST in Vellore District," *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, "Vol. 9, Issue 2S3, December 2019, pp. 419-421.
3. Priyanka Sharma, "Impact of Goods and Services Tax (GST) on Indian Economy," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, "Vol. 11, No. 2, August 2020, pp. 803-807.
4. PurnimaSarkar and Sangeeta Rani, "The Impact of GST on Manufacturing Sector in India," *Journal of Engineering Science*, "Vol. 11, No. 7, July 2020, pp. 560-565.
5. SahooAditya and Nayak, YajnyaDutta, "Impact of GST

- on Hotel Industry- A Study in Bhubaneswar City in Odisha,” *International Journal of Innovative Research in Engineering & Management (IJIREM)* 2021,” Vol. 8, No. 3, May 2021, pp. 8-11.
6. AnchalOjha, IshikaChouriya and NileshAnute, “Impact of Indirect Tax Reforms in India,” *Journal of Accounting Research, Business and Finance Management*,” Vol.3, No. 2, July-December 2022, pp. 1-8.
  7. S. Bhuvanewari, Deepak. M, “Impact of GST among Small Scale Business,” *International Journal of Research Publication and Reviews*,” Vol. 3, No.12, December 2022, pp. 425-429.
  8. Kanimozhi, “A Study on Impact of GST on MSME in India,” *International Journal of Research Publication and Reviews*,” Vol. 4, No.2, February 2023, pp. 859-864.
  9. Rajeev Kumar Gupta, “Comparative Study of Direct and Indirect Tax Collection in India (from 2000-2001 to 2018-2019),” *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*,” Vol. 10, No.2, Feb. 2023, pp. 490-495.
  10. M. Senthilkumar, “Impact of GST in Retail Shops at Urban Areas,” *International Journal of Novel Research and Development*,” Vol. 8, No.8, August 2023, pp. 790-792.
  11. K. RithuVarjitha, “Impact of GST on Tourism Sector,” *American Journal of Engineering Research (AJER)*,” Vol. 12, No.7, July 2023, pp. 25-34.
  12. DeeptiDaga and P. Ganesh Anand, “Impact of GST on Small Business Enterprises,” *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*,” Vol. 11, No.1, January 2024, pp. 432-434.

**Table 1: Respondents Views Regarding Impact of GST on Compliance Factors**

Responses	Nature of Response					Total	Mean	S.D.	SKW	Kurt.	X <sup>2</sup>	P. Value
	Strongly agree	Agree	Undecided	Disagree	Strongly agree							
Inflationary cost reduce due to GST	84(16.8)	215(43.0)	77(15.4)	81(16.2)	43(8.6)	500(100)	3.432	1.1934	-0.591	-0.641	176.20	<0.01
GST Effect the Income	100(20.0)	182(36.4)	101(20.2)	88(17.6)	29(5.8)	500(100)	3.472	1.1627	-0.443	-0.732	119.10	<0.01
Implementation of GST increase the Documentary Process	85(17.0)	194(38.8)	83(16.6)	60(12.0)	78(15.6)	500(100)	3.296	1.3144	-0.521	-0.911	114.34	<0.01
GST Made it Mandatory to Provide bills to the Customers	134(26.8)	205(41.0)	45(9.0)	42(8.4)	74(14.8)	500(100)	3.566	1.3570	-0.812	-0.602	192.46	<0.01
Implementations of GST Reduces the Manual works	98(19.6)	178(35.6)	99(19.8)	41(8.2)	84(16.8)	500(100)	3.330	1.3374	-0.549	-0.861	98.26	<0.01

**Note:** Figures in parenthesis indicate the percentages of the row total

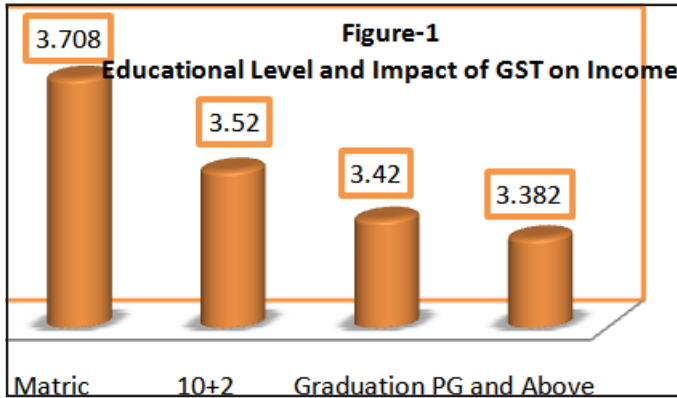
**Source:** Various Questionnaires from Respondents.

**Table 2: Educational Level and Impact of GST on Income**

Educational Level	Nature of Response					Total	Mean	$\sigma$	SKW	$\chi^2$	P. Value
	S.A.	A.	UD.	D.	S.D.						
Matric	5(10.4)	16(33.3)	10(20.9)	15(31.3)	2(4.1)	48(100)	3.708	1.091	-0.819	32.76	<0.01
10+2	12(7.9)	77(50.7)	21(13.8)	25(16.4)	17(11.2)	152(100)	3.520	1.139	-0.471	76.55	<0.01
Graduation	47(21.0)	92(41.1)	31(13.8)	34(15.2)	20(8.9)	224(100)	3.420	1.199	-0.431	154.63	<0.01
PG & Above	20(26.3)	30(39.5)	15(19.8)	7(9.2)	4(5.3)	76(100)	3.382	1.143	-0.196	29.20	<0.01
Total	84(16.8)	215(43.0)	77(15.4)	81(16.2)	43(8.6)	500(100)	3.472	1.163	-0.443	119.10	<0.01

Note: Figures in parenthesis indicate the percentages of the row total

Source: Various Questionnaires from Respondents



\*\*\*\*\*

# Rural Women's Development and Self-Help Groups

Narendra Singh Panwar\*

\*Research Scholar (Sociology) Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Introduction** - Self-help groups play a crucial role in the development and upliftment of rural women. In India, several government and non-government organizations are organizing women into self-help groups to make them self-reliant and economically empowered by providing various employment opportunities and skill training. These groups have played a significant role in making women financially capable. During the COVID-19 pandemic, when millions of people lost their jobs, self-help groups in India carried out commendable work. While cities witnessed mass migrations and rising unemployment, self-help groups contributed significantly by making masks, distributing sanitizers, and engaging in other essential activities to combat the pandemic. Their efforts proved highly effective during COVID-19, and various global organizations also appreciated the contributions of India's self-help groups during this crisis.

In July 2018, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, interacted with over 10 million women associated with self-help groups through an app. During the interaction, the Prime Minister emphasized the vital role of women in the development of domestic industries, stating that progress cannot be envisioned without their participation. He mentioned that around 5 million self-help groups are operating in India, and by inspiring and encouraging them, the vision of a developed India can be realized.

A self-help group is a collective of individuals formed to achieve a specific goal. These small groups are created to support each other. The members voluntarily join without dependency on external support, as the name suggests- **Self-Help**-which means assisting themselves. Such groups typically consist of 10 to 20 members, all belonging to a common social background. Women's self-help groups include only women as members. Each member contributes a fixed amount monthly, which is collected and recorded by designated office-bearers in a register. A savings account is opened in the group's name, managed by its office-bearers. Banks also provide loans to these groups at an interest rate, further assisting them in their economic activities.

**Origin of Self-Help Groups:** The origin of self-help groups

in India dates back to the 1970s. In 1972, Dr. Ela Bhatt founded the Self-Employed Women's Association (SEWA), which played a significant role in poverty eradication, women's employment, and women's empowerment. However, the self-help group movement became more organized and systematic under the leadership of Bangladesh's Nobel Prize winner, Muhammad Yunus. His working model influenced the entire world and achieved remarkable success in inculcating the habit of saving among people.

## Objectives of Self-Help Groups:

1. To uplift the poor in rural India who have a strong will to eradicate their poverty and to develop their potential to achieve progress.
2. To improve the living standards of poor women and families in rural societies while fostering a sense of social solidarity, enabling them to grow as a strong organization and awaken their true potential.
3. To spread awareness among women, enhance their skills, and strengthen women's empowerment.
4. To provide employment opportunities to rural poor families at the local level, ensuring the fulfillment of their basic needs.

## Members and Formation Process of Self-Help Groups:

1. Extremely poor women or those below the poverty line are included in these groups.
2. The age of women joining the group should be between 18 and 65 years.
3. Members of the group contribute a fixed amount every month, so it is essential that members are capable of depositing the agreed minimum amount regularly.
4. Women willing to engage in collective work when required should be included in the group.
5. Members must attend regular group meetings.
6. The group should consist of 10 to 20 female members.
7. The activities assigned to self-help groups are categorized as priority tasks.

## Rules and Conditions of Self-Help Groups:

1. The group should have been actively operating for at least six months.
2. Members should have been consistently saving their

- monthly contributions from their available resources.
3. The group should have provided loans to its members from the accumulated savings, maintaining complete records of transactions, including details of loans and monthly savings, in a register.
4. Regular weekly or monthly meetings should be held, with meeting details recorded in a register.
5. The group should operate democratically, ensuring the participation of all members, with everyone's opinions being considered.
6. The primary objective of the group should be mutual support and self-employment rather than merely obtaining loans from banks.
7. Banks evaluate these aspects carefully before granting loans. The bank officer or branch manager must be satisfied that the group genuinely aims at self-employment and mutual assistance. A rating table on the application form determines eligibility based on a specific score.
8. All members should belong to the same background, meaning they should be engaged in the same type of occupation. For example, if the group is involved in selling milk, all members should be engaged in the dairy business; if the group is focused on tailoring, all members should be engaged in tailoring work.

#### Regular Group Meetings:

1. Determining the weekly savings amount for members.
2. Deciding the time and place for weekly meetings.
3. Taking the initiative for collective organizational activities.
4. Making collective decisions and implementing them.
5. Informing group members about the five key principles (Panchsutra).
6. The group is managed by a president, a treasurer, and a secretary.

To understand the functioning and operational process of women's self-help groups, we are studying a case from Udaipur district, where institutions like Seva Mandir Udaipur and Rajasthan Bal Kalyan Samiti Jhadol are running self-help groups. With institutional support, women from Kaliwas village in Girwa Tehsil of Udaipur district have become self-reliant through self-help groups by engaging in activities such as agriculture, horticulture, and tailoring. By saving money and contributing to their family's livelihood, they have emerged as exemplary role models.

#### Case Study 1

##### Pipliya Village Development Group

**Village:** Kaliwas

**Tehsil:** Girwa

**District:** Udaipur

**Group Formation:** September 2021

**Key Activities:** Development of irrigation and drinking water sources, Construction of a Chekdem, tank, and well's

**Supporting Organization:** Seva Mandir, Udaipur

Pipliya is a village group under the Kaliwas Gram Panchayat

in the Girwa Panchayat Samiti of Udaipur district. In September 2021, a Village Development Committee was formed here through Seva Mandir. Due to awareness created by this committee, an anicut, a well, and a tank were constructed with the support of Seva Mandir. In March 2022, the village faced an issue where debris would fall into the well while drawing water using a motor. The Village Development Committee held a meeting and, with collective agreement, decided that the beneficiary families using the water source would contribute small amounts to clear the debris. During this process, 10 financially capable families collected Rs 1,000 in the name of the women, hired an external vehicle, and removed the debris from the well. Through the unity and organization of the group, the drinking water problem was resolved.

Conversations with rural women revealed that, two years ago, there was a severe drinking water crisis in the village. Women had to walk 2 to 3 kilometers to fetch water. With the village group's efforts and the construction of the anicut, the issue of drinking water for agriculture and livestock was resolved. From July to December, water was available within 1 to 2 kilometers. However, from January to June, people had to walk 4 to 5 kilometers to fetch water, which took 2 to 4 hours.

Previously, agriculture was entirely dependent on rainfall, and in years of poor rainfall, the problems of farming, drinking water, and livestock rearing became severe. Earlier, farmers only cultivated maize, but with the availability of wells, anicuts, and other facilities, they started growing cash crops and vegetables, leading to an increase in household income and an improvement in their economic condition. Thus, the inspirational efforts of the Women's Self-Help Group not only solved the drinking water crisis but also boosted agricultural productivity and enhanced household income.

#### Personal Study 2

**Respondent's Name:** Dharmi Gameti

**Age:** 50 years

**Husband's Name:** Pratap Bhil

**Occupation:** Agriculture

**Village:** Popalti

**Tehsil:** Girwa

**District:** Udaipur

**Group Formation Year:** 2020

**Supporting Organization:** Seva Mandir, Udaipur

**Main Activities:** Rose, Jamun, Marigold (Genda Hajari) Flower Nursery etc.

In the Popalti Panchayat under the Girwa Tehsil of Udaipur district, there are 8 revenue villages. Seva Mandir has been working in this village for several years. However, in the year 2020, with the support of the Colgate Project and Seva Mandir, Dharmi Gameti, wife of Pratap Ji, planted 950 marigold and rose plants in Purnia. From these plants, she earned an income of Rs 55,000 in 2021, which she utilized for house construction and household expenses.

In the same year, Dharmi and Pratap Ji, along with other rose cultivators, received training from the Seva Mandir team for a rose nursery. In November 2020, they prepared a nursery of 5,000 rose plants through cuttings from their existing rose plants. By selling these plants in April 2021, they earned Rs 41,000 from the rose nursery, which they used to pay their daughter-in-law's BSTC course fees. In February 2022 alone, they earned Rs 20,000 and sold 20-25 kg of roses daily. With this income, they completed the work of installing doors, windows, and painting in their house. Dharmi and Pratap Ji initially started with three cultivators, which has now increased to nine rose cultivators in the village. Additionally, 26 other cultivators started growing roses by using the cuttings discarded by Dharmi and Pratap Ji. These cuttings were properly trimmed and directly planted in the fields, yielding good results and generating significant income annually. Like every year, in 2021, Pratap Ji prepared around 12,000 plants, and approximately 130,000 plants are being cultivated. Many families in the village are now engaged in making flower garlands, providing them with daily employment. Inspired by Dharmi and Pratap Ji, many people from other villages have also started flower farming.

For the past two years, with the support of the Seva Mandir organization, many other women in self-help groups such as Sai Baba Ki Leela in Akeli and Kaliwas villages have been cultivating flowers. These families earn an additional annual income of Rs 35,000 to Rs 50,000. The villagers sell flowers at rates ranging from Rs 80 to Rs 150 per kg. Several families also prepare garlands and sell them on the roadside, earning Rs 200 to Rs 500 per day.

### Case Study 3

#### Kheemaj Mata Women's Savings Group

**Respondent's Name:** Manisha

**Age:** 35 years

**Husband's Name:** Laxman

**Occupation:** Beauty products, grocery, and tailoring

Alsigarh, located about 70 kilometers from Udaipur in the Girwa tehsil, has had the Kheemaj Mata Women's Savings Group since 2018 with the support of Seva Mandir. This group consists of 13 women who each contribute Rs 100 per month in a meeting held on the 5th of every month. In January 2021, Manisha Laxman took a loan of Rs 28,000 from the women's savings group and started a beauty products, grocery, and clothing shop. Initially, she was nervous about how she would repay the money, but as people in the area became aware of her shop, they started purchasing from her. Gradually, her confidence grew, and she began earning Rs 4,000 to Rs 5,000 per month. Later, she purchased a sewing machine. Now, Manisha earns around Rs 9,000 per month, covering her household expenses, including food and daily needs. By taking a loan

from the women's savings group, Manisha successfully established a grocery and beauty products shop at home, playing a crucial role in sustaining her family's livelihood. Encouraged by her growing confidence, she also took tailoring training and opened a clothing shop. Today, the couple works together and earns Rs 2 to Rs 3 lakh annually while staying at home, leading a self-sufficient and happy life. Currently, Seva Mandir is promoting vegetable farming, goat rearing, fish farming, and poultry farming in this village and surrounding areas. They have also provided goats for goat farming, increasing goat sales and helping families sustain themselves.

In Rajasthan, the formation of women's self-help groups (SHGs) has played a significant role in making women financially independent. The Rajasthan Child Welfare Committee, in collaboration with NABARD, is actively working in rural areas to enhance livelihoods. Under this initiative, farmer groups have been formed to promote agriculture. In the Jhadol region, the local community is being encouraged to cultivate ginger, arbi (taro root), ratalu (sweet potato), and chilies. Efforts are also being made for water conservation, infrastructure development, and skill training to enhance self-sufficiency. According to reports from 2019-20, around 170 wells were deepened and concretized, 15 farmers received seed distribution, and 2,000 families were linked to amla (Indian gooseberry) farming for commercial production. With the support of the Government of India, livelihood enhancement programs focus on land, water, livestock, and agricultural development & management. Additionally, horticulture, floriculture, and medicinal plant cultivation are being promoted in partnership with self-help groups. NABARD is also helping establish the Mewar Pottery Cluster, training and supporting potter families in pottery-making and marketing. For poor families, microcredit initiatives are encouraging savings, benefiting around 400 families in the region. Efforts are also being made to ensure fair prices for their produce. Thus, by working together, government and non-government organizations are identifying economically weaker families in rural and tribal areas, forming self-help groups, and creating employment opportunities. These initiatives are significantly contributing to women's empowerment, family development, societal progress, and national growth.

#### References:-

1. Kumawat, Lalit (2004): Emerging Leadership in Panchayati Raj & Women's Groups
2. Annual Report 2021: Rajasthan Child Welfare Committee
3. Jain, M.K. (2020): Tribal Women's Condition & Health, Udaipur Ankur Publications
4. Bi-Annual Report 2021: Seva Mandir Regional Office, Jhadol

# Study of Ethno-Medicinal Plant's Use Increasing Immunity

Dr. Sarita Ghanghat\*

\*Assistant Professor (Botany) Govt. Sanjay Gandhi Smriti P.G. College, Ganj basoda, District Vidisha (M.P.) INDIA

**Abstract:** The present paper reported with Ethno-medicinal plant use for increasing immunity in rural area of Vidisha district, Madhya Pradesh. Total 28 plants belonging to 17 families were identified which were being used by people of the study area. The information about the plants for immunity booster was gathered from rural area people, Hakims, Local Vaidya etc. if our immune system is not properly taken care of, it can result in disease.

**Keywords:** increasing immunity, Ethno-medicinal, Plants, Vidisha, District.

**Introduction** - In India medicinal plants have long been used to treat different kinds of disease. People living in the developing countries rely quite effectively on traditional medicine for primary health care (Sullivan and Shealy 1997; Singh, 2002).

Indian tradition medicine is based on different system such as Ayurveda, Siddha and Unani used by various communities (Gadgil, 1996).

Medicinal plants are main ingredients of local medicine and are of vital importance in traditional healthcare. Villagers have a good knowledge about these plants since ancient times. Atharvaveda is oldest word literature on the plants used against several diseases. Moreover, there are considerable economic benefits in the development of medicine and in the use of medicinal plants for treatment of various diseases.

There is still much that researchers do not know about the intricacies and interconnectedness of the immune response. Nature has blessed mankind with abundant medicinal herbs which provide timely and adequate remedies to several health disorders. Several medicinal plants have been used since times immemorial for treatment of enhance immune system. Some Special plants like Giloy, Tulsi, Ginger, Cinnamon, Turmeric, Clove, Kali Mirch, Amla, Lemon, have been used of increasing immunity plants in rural area of vidishadistrict. Even today, in many villages of this district, so much ethno-medicinal plants are being used to increase immunity boosting.

**Study area**-The present paper on 28 selected Ethno-medicinal plants (belonging to 17 families) of Vidisha district, with correct identification, Botanical Names, Family, Local names, parts used in diseases, by tribal and rural population. For centuries plants have been an important source of drugs.

Vidisha district is one of the most important and centrally located district of M.P. The total area of the district is about 7,433sq K.M. which lies between 23°21' and 24°22'N latitude and 77°15.30' and 78°18'E longitude forming eastern part of Malwa region. The forest cover is about two fifth of the total area in the district (fig.1). Vidisha district is inhabited by tribals like Sahariya, Bhil, Meena. The area is very rich in indigenous ethno-medicinal plants. These are collected by local inhabitant for the preparation of medicines. Perusal of literature (Jain 1995, Ghanghat and Sahu 2006,) revealed that no specific study on ethno-medicinal uses of plants in Vidisha district has been carried out.

**Fig.1 Map (vidisha district)**



**Research Design and Methodology**-The following methods were adopted by the author during the-

1. The study was conducted in the rural area of Vidisha district in Madhya Pradesh.
2. The survey was conducted to collect the information forest department and local people specially Sahariya,

- tribes in Vidisha district.
3. The information about plants was gathered during filed visit by contacting and interviewing traditional healers and other rural people, Vaidya, Hakims for immunity booster. with Help of local medical practitioners was also taken.
  4. Plants were identified by referring to Flora of Bhopal by Oommachan,M.(1977) and Flora of M.P. from Wikipedia.

**Enumeration-** In the following enumeration, plant names have been arranged alphabetically in botanical name wise. (Table-1)

**Table -1 (see in last page)**

**Results and Discussion-**A total of 28 ethno-medicinal plants for enhance immunity booster distributed in 17 families are documented in Table-1.

The people of studied area still had strong belief in ethno-medicinal herbal plants treatment. Herbal treatment is cheap. convenient and easily available in local areas. In the present study, it was found that plants commonly used in immunity booster in rural areas were still found in urban areas of Vidisha. It is essential that ethno-medicinal plants investigation should persistently be carried on and efforts. should be made for proper protections cultivation and conservation of these precious medicinal plants on large scale. Consequently, natural products derived from medicinal herbs are potential candidates for immune boosting therapeutic drugs. if not as the main, then as the accompanying therapy in combination with medications, aimed at boosting immunity for prevention.

**Conclusion-** In summary, We should make people aware about the usefulness of these plants as well as their conservation so that a healthy society can be created. To maintain a strong immunity, we should use plants in which we can get all the multivitamins and we are not prone to disease. Many plants are used to enhance the immune system, which are given in table No.1. But some are mainly used Giloy, Tulsi, Garlic, Ginger, Dalchini, Turmeric, Tejpatana, Clove, Kali Mirch, Mint, Mithi Neem, Sahijanetc. Alone with this, plants from which vitamin C is obtained such as Amla, Guava, Lemon, Orange are also prominent. By using these plants, can increase our immune system, so that we will be healthy and we will not get any disease.

**Acknowledgement-**The author thankful to all the tribes,

local people, Hakims, Vedas for the valuable information required for this survey. who provided merelated to this research. I am sincerely grateful to Dr.M.M.Mehta, Principal Govt. S.G.S.P.G. College, Ganj Basoda

**References:-**

1. Balkrishna Murthy, P. (2008). Vegetation of different place. *Journal of Environment Biology*, 29 (1):522-523.
2. Flora of M.P. from Wikipedia.
3. G. Anywar, E. Kakudidi, R. Byamukama, J. Mukonzo, A. Schubert, H. Oryem- Origa, (2020), Medicinal plants used by traditional medicine practitioners to boost the immune system in people living with HIV/AIDS in Uganda, *J. Eur. J. Integr. Med.*
4. Ghanghat, Sarita and Sahu, Brajesh (2006) Medicinal climbers of Vidisha District . I.J.Applied Life Science., Vol 1, no 1, pp 24-25.
5. Gudgil ,M ; 1996 Documentriy diversity : An experiment *curr.ci* ; 70 (1) : 36
6. J.P. Kaushik (1941). Flora of Shivpuri, Madhya Pradesh (1983). Jiwaji University Gwalior, M.P.
7. Jain ,S.K., 1991 Dictionary of Indian Flok medicine and Ethnobotany .Deep publication, New Delhi. ISBN : 8185622000.
8. Jain, A.K. (1992). Ethno-botanical studies on Sahariya tribals of Madhya Pradesh with special reference to medicinal plants. *J. Econ. Taxonomic Bot.*, Add. Ser. 10, 227-232.
9. Jain, S.K. (1995): Ethnobotanical studies around vidisha district . Ph-D Thesis. Barkatullah University, Bhopal.
10. Jatav, R.D. (2021) Ethno-medicinal Plants use for Immunity Booster in Rural Area of Shivpuri District Madhya Pradesh. *Journal of IJSR*, ISSN :2319-7064 .793-796.
11. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. jain Brothers, Bhopal
12. Olga Babich, Stanislav Sukhikh *et. All.*, (2020): Medicinal Plants to Strengthen Immunity during Pandemic. *Pharmaceuticals*, 13, 313.
13. Sullivan, K. and C.N. Shealy , 1997 Complete Natural Home Remedies. Element Book Limited, Shaftsbury, U.K.
14. Uzun, M. Kaya, A. (2016). Ethnobotanical research of medicinal plants in Mihalgazi. *J. Pharm, Biol.* 54.



Plants pictures



Muraya leaves



Neem leaves, fruits



Munga leaves, drumstick



Amla fruit



Kali Mirch Seeds



Mint leaves



Ashwagandha seeds



Tulsi leaves, manjri



Mulethi stem



Bahera fruits



Giloy roots



Gokhru seeds



Harra seeds



Pipli Fruits

**Table -1 : Ethno- medicinal plants Useinincreasing immunity**

S.	Botanical Name	Family	Local Name	Part used
1.	<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Lehasun	Bulb
2.	<i>Aloe vera</i> L.	Liliaceae	Ghritkumari	Gel inside the leaves
3.	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	Neem	Leaf,
4.	<i>Cassia tora</i>	Caesalpinaceae	Puar	Leaves
5.	<i>Cinnamomum tamala</i>	Lauraceae	Tej Patta	Leaves
6.	<i>Cinnamomum verum</i>	Lauraceae	Dalchini	Bark
7.	<i>Citrus limon</i>	Rutaceae	Nimboo	Fruit
8.	<i>Citrus reticulata</i>	Rutaceae	Santra	Fruit
9.	<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Haldi	Rhizomes
10.	<i>Emblica officinalis</i> Gaert.	Euphorbiaceae	Amla	Fruit
11.	<i>Eugenia jambolana</i>	Myrtaceae	Jamun	Fruit
12.	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Fabaceae	Mulethi	Stem
13.	<i>Mentha arvensis</i>	Lamiaceae	Pudina	Leaves
14.	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringaceae	Sahijan	Leaves, flower,seed,Fruit.
15.	<i>Murrayakoenigii</i>	Rutaceae	Meethi Neem	Leaves
16.	<i>Ocimum sanctum</i>	Lamiaceae	Tulsi	Leaves
17.	<i>Piper longum</i>	Piperaceae	Pippli	Fruit
18.	<i>Piper Nigrum</i>	Piperaceae	Kali Mirch	Seed
19.	<i>Psidium guayava</i>	Myrtaceae	Amrud	Leaves, Fruit
20.	<i>Punica granatum</i>	Lythraceae	Anar	Seed
21.	<i>Solanum nigrum</i>	Solanaceae	Makoi	Leaves, Fruit.
22.	<i>Syzygium aromaticum</i>	Myrtaceae	Long	Bud
23.	<i>Terminalia bellarica</i>	Combretaceae	Bahera	Fruit
24.	<i>Terminalia chebula</i>	Combretaceae	Harra	Fruit
25.	<i>Tribulus terrestris</i>	Zygophyllaceae	Gokhru	Fruit, Seeds
26.	<i>Tinospora cordifolia</i>	Menispermaceae	Giloy	Leaves, Stem, Root
27.	<i>Withaniasominifera</i> (L)Dunal	Solanaceae	Ashwagandha	Whole plant, mainly root
28.	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe.	Zingiberaceae	Adrak	Rhizome

\*\*\*\*\*

# Ethnobotany: Traditional herbal remedies used by Tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India

Dr. Kamal Singh Alawa\*

\*Department of Botany, PM College of Excellence, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

**Abstract :** The present paper deals with 40 plant species which are used traditionally since ancient times by Tribals used for the treatment of various ailments, such as mouth ulcer, constipation, earache, headache, asthma, ringworm, jaundice, snake bite, etc. A total of 40 plant species belonging to 29 genera and 18 families were identified as scientific name, local name and uses. The present observation puts into record some novel traditional uses of certain plants as medicines. Herbal remedies medicinal plants are arranged alphabetically which represents their botanical names, family, vernacular name and medicinal uses.

**Keywords:** Dhar district, Herbal remedies, Medicinal plants, Tribals, Madhya Pradesh.

**Introduction -** Dhar district is situated in the western most part of Madhya Pradesh. Most of village's habitants of Dhar district belong to tribal communities of the remote and rural areas. Major parts of the district is covered by dense forest area in which various tribes, like Bheel, Bhilala, Barela and Patelia are the dominant tribals of Dhar district, Madhya Pradesh. Out of these tribes Bheel and Bhilala stand high in strength Scattered in most of the villages of the study areas. These tribal peoples live close to the forest and mostly dependent on the wild Bioresources for their daily requirement of food, fuel, herbs, tools and implements. The Bheel tribes is an ancient tribal community of archers spread in many parts of India but presently living preponderantly in the forests of Madhya Pradesh and surrounding region of the world. Bheel stands for bow and thus represents archers who traditionally used bows and arrow dating back to hunter-stage of human evolution in the subcontinent. A review of Literature survey of ethnobotanical work was done (Srivastava 1984, Samvatser *et al.* 2004, Jain 2004, Jadhav 2007, Wagh *et al.* 2010, Vijay *et al.* 2010, Alawa *et al.* 2012, Shaikh *et al.* 2012, Alawa 2015, Alawa *et al.* 2016, Alawa 2018, Alawa 2021). Still there are some interior areas which need to be surveyed intensively like Dhar district for searching new traditional remedies medicinal plants. The present paper first time documented of the study area.

**Materials and Methods:** The present paper is outcome of extensive field survey of different tribal villages of Dhar district during 2024- 2025 to collect information on medicinal uses of different plant species. Herbarium of the collected plants specimen was prepared following customary method (Jain and Rao,1977). During field work, interviews were conducted with local knowledgeable villagers; local elders

and experienced tribal peoples (both men and women) were interviewed and cross -interviewed again and again. Local 'Vaidyas,' 'Badwa' and 'Ojhas'. The collected plant species are arranged alphabetically along with their botanical name and family, local names, method of preparation of drug and mode of administration are given below in observation. The plant specimens were collected and identified with local flora available literature (Varma *et al.* 1993, Mudgal *et al.* 1997 & Khanna *et al.* 2001). Herbarium preserved in Department of Botany, PMB Gujarati Science College, Indore, Madhya Pradesh. Under enumeration, plant names have been arranged alphabetically followed by Botanical names, family, vernacular names and medicinal uses.

**Enumeration of species:** During ethnobotanical survey of Dhar district it was found that some wild medicinal plants are used by tribal of Dhar district Madhya Pradesh. The enumerations of field observation are given below:

1. ***Abrus precatorius* L.** (Fabaceae) **V.Ns.** -Ghumchi, Lal chirmi, Lal jurang, Ratti.

Uses: 1. Leaf paste with jaggery mixed is given twice a day for 2-3 days to control typhoid.

2. The leaves are chewed in mouth ulcer.

3. Seed powder is mixed with cow's ghee is used 1-2 drops to during conjunctivitis.

2. ***Achyranthes aspera* L.** (Amaranthaceae) **V.Ns :** Chirchita

Uses: Root paste is applied on a bitten area in scorpion bite.

3. ***Alangium salvifolium* (L.F.) Wang** ((Cornaceae) **V.Ns:** Okali

Uses: Root powder is mixed with water and given orally twice a day in constipation.

4. ***Alstonia scholaris* (L.) R.Br.** (Apocynaceae) **V.Ns:** Saptaparni  
Uses: A glassful stem bark decoction is given twice a day in tuberculosis.
5. ***Butea monosperma* (Lam.) Taub.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Palas, Dhak, Khankro.  
Uses: 1. Paste of seed with water is taken twice a day for 3 day to remove intestinal worms.  
2. Powder bark is taken during bodyache and abdominal pain.
6. ***Butea superba* Roxb.ex Willd.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Palasvel, Bodla.  
Uses: Dried root powder with cow's milk is given during debility.
7. ***Borassus flabellifer* L.** (Arecaceae) **V.Ns:** Tad  
Uses: Leaf base is burned and squashed and the formed juice is put in ear in earache.
8. ***Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.** (Caesalpinaceae) **V.Ns:** Ghatar  
Uses: One teaspoonful seed powder is given twice a day in burning sensation during urination.
9. ***Celastrus paniculatus* Willd.** (Celastraceae) **V.Ns:** Kangan  
Uses: Seed oil is applied on forehead in half headache.
10. ***Costus speciosus* (J. Koeing) Sm.** (Costaceae) **V.Ns:** Jangali Aadu  
Uses: Rhizome paste is applied on the forehead in chronic headache.
11. ***Cajanus cajan* (L.) Huth.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Arhar  
Uses: Paste of leaves is applied on mouth ulcer.
12. ***Clitoria ternate* L.** (Fabaceae) **V.Ns.** Aparajita  
Uses: The extract of leaves is given orally to cure vermicide.
13. ***Crotalaria medicaginea* Lamk.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Piliabuti  
Uses: Powder of roots is mixed in water and taken orally to cure jaundice.
14. ***Crotalaria Juncea* L.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Sann, Sanai  
Uses: 1. Seed powder with milk is given orally twice day to cure paralysis.  
2. Root powder with leaf of (*piper betle*) beetle is given twice a day for a week to cure jaundice.
15. ***Dalbergia sissoo* Roxb. ex DC.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Sissoo, Sisham.  
Uses: 1. Leaf Juice with sugar candy is given twice a day for 3 days to cure diarrhoea.  
2. Paste of leaves is given orally cure for diabetes.  
3. Oil of wood is also massage to cure for paralysis.
16. ***Desmodium gangeticum* (L.) DC.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Chipti  
Uses: Root powder with honey is given orally twice a day to cure cough and fever.
17. ***Desmodium triflorum* (L.) DC.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Kodawla  
Uses: 1. Paste of fresh leaf is applied wounds twice a day to relive fast healing.
2. Root powder with Kukad kand (*Geodorum densiflorm*) to made into "Laddu" given to one week in early morning in the empty stomach to cure spermatorrhoea.
18. ***Desmodium gangeticum* (L.) DC.** (Fabaceae) **V.Ns:** Rinzado  
Uses: Fresh leaves juice is applied externally on scabies and ringworm.
19. ***Euphorbia nerrifolia* L.** (Euphorbiaceae) **V.Ns:** Hathlo thubar  
Uses: Latex of plant is given in Pan (*Piper betel*) leaf in asthma.
20. ***Ficus benghalensis* L.** (Moraceae) Local name: Bargad  
Uses: Latex of the plant is applied in mouth ulcers.
21. ***Haldinia cordifolia* (Roxb.) Ridsd.** (Rubiaceae) **V.Ns:** Haldu  
Uses: Stem bark pounded overnight and the decoction is given twice a day in Jaundice.
22. ***Indigofera tintoria* L.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Neel, Nili.  
Uses: Powder of root with water is given orally to cure for cardiac, hepatic and dropsy.
23. ***Lannea coromondelica* (Houtt.) Merr.** (Anacardiaceae) **V.Ns:** Moyan  
Uses: Stem bark is crushed with 500 ml water and heated gently for 5-20 minutes and the decoction is given twice a day to treat rheumatism.
24. ***Malilotus indica* (L.) Ali.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Van methi  
Uses: Leaves with salt to eaten in case of constipation.
25. ***Momordica dioica* Roxb. ex Willd.** (Cucurbitaceae) **V.Ns:** - Kicoda, Katle  
Uses: Root tuber paste is applied on bitten area in snakebite.
26. ***Mucuna pruriens* (L.) DC.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Kevach, Konch  
Uses: 1. Root paste is given twice a day for 3 days to cure dysentery.  
2. Burn seeds are eaten to cure for cough and cold.
27. ***Ocimum basilicum* L.** (Lamiaceae) **V.Ns:** - Safed Bhabdi,  
Uses: Seed pounded in water overnight, and the extract is given orally in pimple and blemishes.
28. ***Ougeinia oogeinsis* (Roxb.) Hocker.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Tinsa  
Uses: Bark paste is given twice a day for 3 days to cure diarrhea and dysentery.
29. ***Pongamia pinnata* (L.) Pierre.** (Fabaceae) **V.Ns.-** Karanj, Karanji, Kanji.  
Uses: 1. Seed oil is applied on skin for itching, ringworm and eczema.  
2. Seed powder with cow's milk is given twice a day for bodyache.  
3. Leaf juice is applied as ointment in the cure of urinary.
30. ***Pterocarpus marsupium* Roxb.** (Fabaceae) **V.Ns:** - Rangatroeda  
Uses: Decoction of stem bark is given orally twice a day in

kidney stone.

31. ***Pterocarpus marsupium*** Roxb. (Fabaceae) **V.Ns.**- Karanj, Bija-sal, Bilawa.

Uses: 1. Decoction of stem bark is given twice a day for a week to cure anemia.

2. Decoction of stem bark is given twice a day for only women after delivery.

32. ***Pueraria tuberosa*** (Roxb.) DC. (Fabaceae) **V.Ns.**-Patal tumbadi, Bhui kumbra

Uses: 1. Tuber powder is given twice a day for 3 days to cure urinary disorder.

2. Decoction of leaves and tuber is given twice a day for a week to treat increase male potency.

33. ***Sesbenia bispinosa*** (Jacq.) Steud. (Fabaceae) **V.Ns.**- Dadon, Daden

Uses: 1. Seed powder is given with water twice a day for arthritis.

2. Seed

paste is applied as an ointment on cuts, burns and wounds.

34. ***Syzygium cumini*** (L.) Skeels (Myrtaceae) **V.Ns.** - Jamun

Uses: One teaspoonful seed powder is given orally twice a day for blood purification.

35. ***Tamarindus indica*** L. (Mimosaceae) **V.Ns.** - Aamli,

Uses: seed powder mixed with honey and the made pills are given twice a day in diabetes.

36. ***Tephrosia candida*** L. (Fabaceae) **V.Ns.**- Safed serpunkha

Uses: Root powder is given orally to cure diarrhea.

37. ***Tephrosia Purpurea*** (L.) Pers. (Fabaceae) **V.Ns.**- Sarpankha, Bayonia

Uses: 1. Decoction of root is given twice a day for 3 days to cure diarrhoea and urinary disorder.

2. Decoction of plant is used for children to cure blood purification.

38. ***Urginea indica*** (Roxb.) Kunth (Liliaceae) **V.Ns.** - Jangali pyaz

Uses: Bulb paste is bandaged on the swelling in rheumatism.

39. ***Uraria picta*** (Jacq.) Desv.ex.DC. (Fabaceae) **V.Ns.** Prastparni

Uses: Root powder is given to cure fever.

40. ***Wrightia tinctoria*** R. Br. (Euphorbiaceae) **V.Ns.** - Kueda

Uses: One teaspoonful seed powder is given orally thrice a day for one week in Malaria.

**Results and Discussion:** The present study includes information on the total 40 plant species belonging to 29 genera and 18 families were identified as scientific name, local name, and uses. Generally local medicine men are known as 'Badwa' or Vaidyas. The rich treasure of indigenous knowledge of local medicinal plant is also under serious threat in rural areas due to the availability of allopathic medicines and treatment of ailments and disease. The indigenous knowledge of the tribal communities must be properly documented and preserved so that their

knowledge could be passed on the future generation. Such studies and documents provide important for understanding the complex heritage of tribal communities and their association with environment and nature. The important medicinal plants were used against cough and cold, diarrhea and urinary disorder of 3 species; abdominal pain, intestinal worms, typhoid, jaundice, mouth ulcer, eczema, paralysis, fever of 2 species each and arthritis, male impotency, diabetes, anemia, dysentery, spermatorrhoea and blood purification of 1 species. The collection of remote areas of traditional herbal remedies plants of photo graphs (Fig. 1 to 6).

**Acknowledgement :** The author is thankful to Dr. S.S. Baghel, Principal and Dr. K.S. Alawa, Head of Botany Department, Govt. P.G. College, Dhar for their help and support. We are also thankful to Divisional forest officer, Dhar for help during the ethno botanical survey in tribal villages and forest areas of the district. We are thankfully acknowledging the informants for the important information giving regarding ethnomedicinal plants.



Fig.1 ***Abrus precatorius***



Fig.2 ***Momordica dioica***



Fig.3 ***Mucuna pruriens***



Fig.4 ***Butea monosperma***



Fig. 5 Tribal medicine men



Fig.6 Tribal medicine men

Plate1: Traditional herbal remedies used by tribals of Dhar district (M.P.)

**References:-**

1. **Alawa, K.S. and Ray S. 2012.** Ethnomedicinal plants used by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *CIBTech. Jour. Of Pharmaceutical Science*, 2012; 1(2-3): 7-15.

2. **Alawa, K.S. 2015.** Ethnomedicinal plants used for gynecological disorders by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *Naveen shodh Sansar* 2 : 21-22
3. **Alawa, K.S., Ray S., Dubey, A. 2016.** Folklore claims of ethnomedicinal plants used by Bhil tribes of Dhar district Madhya Pradesh. *Bioscience discovery* 7(1): 60-62.
4. **Alawa, K.S. 2021.** Ethnomedicinal plants used for anti-fertility by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *European Jour. Of Biome. and pharma.Science* 8 (8): 495-497.
5. **Jadhav, D. 2007.** Ethnomedicinal plants used by *Bhil* tribes of Matruna, District, Ratlam, Madhya Pradesh, India. *Bull. Bot. Surv. India.* 49 (1-4): 203-206.
6. **Jain, S.P., 2004.** Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products*, Vol. 11(2): 152-157.
7. **Jain, S.K. and Rao R.R., 1977.** *A handbook of field and Herberium methods.* Today and Tomorrow Publishers, New Delhi.
8. **Mudgal, V., Khanna K.K. and Hajra P.K., 1997.** *Flora of Madhy Pradesh*, Vol. II. BSI. Calcutt
9. **Srivastava, R.K., 1984.** Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980. *Man in India.* 64(3): 320-321.
10. **Singh, N.P., Khanna, K.K. Mudgal, V. and Dixit, R.D., 2001.** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. III, BSI, Calcutta.
11. **Samvatsar, S. and Diwanji, V.B., 2004.** Plant used for the treatment of different types of fever by *Bheels* and its sub tribes in India. *Indian J. Traditional Knowledge:* 3(1): 96-100.
12. **Verma, D.M., Balakrishan, N.P. and Dixit, R.D., 1993.** *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta.
13. **Wagh, V.V. and Jain, A.K., 2010.** Traditional herbal remedies among Bheel and Bhilala tribes of Jhabua district Madhya Pradesh. *Inter. Jour. of Biological technology*, 1(2):20-24
14. **Wagh, V.V. and Jain, A.K., 2010.** Ethnomedicinal observations among the *Bheel* and *Bhilala* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India *Ethnobotanical Leaflets*, 14: 715-720.

\*\*\*\*\*

# New Education Policy 2020 - Opportunities and Skill Building

Dr. Ruchi Rathore\*

\*Assistant Professor (Economics) Govt. P.G. College, Rehli (M.P.) INDIA

**Abstract :** The new Education Policy has been approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020. This is the third education policy of India. Many major changes have been made. It will be beneficial for raising the employability. When we talk about present condition youth is running towards seeking the job, they are wandering here and there. The question is why? was the former education policy not perfect according to the present condition. People have skill and talent but their skill and talent was not with the demand. This research paper is an attempt to find out how new education policy 2020 has internship opportunities. This NEP has many beneficial factors in many regards but here we will find out how is it internship opportunities.

**Keywords :** Introduction, objective of the study, research methodology, objective of the new education policy, How does internship help in skill building and finding job opportunities.

**Introduction -** The first NEP was promulgated by the government of India by Prime Minister Indira Gandhi in 196, the second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, and the third by Prime Minister Narendra Modi 2020. This policy aim to transform India's education system by 2040.

As we know very well that the education policy of any country plays a very important role for the development of country and its students. The future of any country depends on its education policy because we know very well that education is an important issue in one's life. It is the key of success in the future and to have many opportunities in our life. With the help of these opportunities not only we are making our future bright but the future of our country too.

**Objective of the Study :**

1. To find out how it's internship opportunities.
2. To find out what are the strong pillar in NEP, which will be used to raise employment.

**Research Methodology :** The present study is an attempt to analyze the impact of new education policy on the internship opportunities. This study has been based on secondary information. The data for the study has been taken from different magazine, books, pdf provided by the higher education related to NEP.

**Objective of New Education Policy 2020:**

1. The education policy aims to encourage the spirit of creative thinking, logical decision making and innovation in the students.
2. Paying attention on technical uses for removing linguistic barriers.

3. NEP 2020 is to pay special attention to issues like access to education for everyone.
4. NEP 2020 emphasizes on equality quality, afterdable education and responsibility.
5. NEP 2020 envisages a shift from summative assessment to regular and formative assessment, which is more competency based higher order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity.
6. It encourages a multidisciplinary approach, allowing students to choose subjects of their interest across streams like science, humanities and commerce.
7. NEP 2020 holds immense potential to revolutionize India's education system and empower its youth for a brighter future.
8. Its success lies in swift and efficient implementation, driven by collaborative efforts and adequate resource allocation.

**How does Internship help in Skill Building and Finding Job Opportunities:**

Major subject, minor subject, elective subject, vocational subject, project, internship, community engagement and apprenticeship are the part of NEP-2020. These are the major changes in education system, which have been made. NEP emphasizes the importance of research and internships in undergraduate education. The internship will be mandatory for students in three year and four year degree programs, with a duration of 60 to 120 hours. Internship programme helps students to test themselves in a real work environment. They can check for themselves whether and with what degree of proficiency

the theoretical lessons that they would have learnt in the classroom can be applied in the workplace. For students pursuing a three year UG degree an internship of 60 to 120 hours duration after the fourth semester will be mandatory, and for those who will opt for a four-year degree a research internship during the eighth semester will be a mandatory component. Here are some benefits of an internship for students.

1. Provides work experience
2. Creates a professional network.
3. Offers career guidance.
4. Builds confidence.
5. Creates a strong resume.
6. Offers mentorship opportunities.
7. Apply theoretical knowledge in the real world.
8. Expand on your transferrable skills.
9. Better job stability.

Above all these are the benefits of an internship for students. With the help of internship programme they can gain real-world experience of what it takes to drive business operation forward. Students will know how to choose strategies to address these issues and how to plan and execute the tactics needed to achieve these goals.

Normal internship can be done with government or private organizations, non-government organizations, enterprises, business organization, local industry, artistes, crafts people and similar other entities, research internship experience can be gained by working with faculty, mentors

in higher education institutions, research institutions, universities, nationally and internationally reputed organization, formers and entrepreneurs, the guidelines started.

**Conclusion:** Now we conclude this paper and find that internship courses are the strong pillar of NEP. It is very helpful for students to achieve their goals not only job side students will set their mind about skill enhancement too. Now this is that time when students can show and enhance their talent and make their future bright instead of running towards job. The integration of formal and internship education under NEP 2020 will help foster future ready skills among the students, making them more adaptable versatile, and well-prepared to excel in the dynamic and competitive landscape of the 21<sup>st</sup> century.

**References :-**

1. Ministry of skill development and entrepreneurship 'My iGot', October 2004.
2. Madhya Pradesh Government, Higher Education Department, National Education Policy 2020, Orientation Program, August-19, 2021
3. Hindustan Times, Retrieved 30 July 2020.
4. <https://www.ugc.in>
5. <https://bhartifoundation.org>
6. Jagranhose.com
7. PM Address on NEP\_Jagran\_Dainik (29 July 2021).
8. <https://www.educationtimes.com>

\*\*\*\*\*



## Issues and Prospects in Teacher Education Programme

Dr. Kalpana Singh\*

\*Assistant Professor, Manyawar Kanshiram Govt. Degree College, Ninowa, Farrukhabad (U.P.) INDIA

**Abstract :** Teacher's education is important programme to improve the quality of higher education. In a landmark directive towards ensuring quality teacher education, the National Council of Teacher Education has made sweeping changes from this academic session. It has increased the duration of B.Ed. programme from one year to two years with major changes in curriculum. However, the revision in the norms regarding duration of the course and curriculum is the result of extensive and exclusive debates and discussions. It has emerged as an idea that has been expressed at various forums over the years. Now that the execution phase has begun, the idea is to be analysed in terms of its actual feasibility. It is to be seen whether the prolonged course duration proves into historical transformation in the system of education or turns to be rather 'a not so preferable profession' in the era of professionalism and human capital. However, it is even more pertinent to understand why such changes were felt needed and what strategies have been evolved to implement the revisions effectively. So far the studies have established that the existing training programme does not provide adequate opportunities to the student teachers to develop competency because of the anomalies and defects in the system of implementation of the programme and curriculum of the programme.

**Keywords:** Teacher education programme, Issues.

**Introduction** - A student teacher should know the meaning of education, its objectives, the socio-cultural and politico-economics background, the principles that guide construction of curriculum etc. Teacher performance is the most crucial input in the field of education. Whatever policies may be laid down, in the ultimate analysis these have to be interpreted and implemented by teachers, as much through their personal example as through the teaching learning processes. We are on the threshold of the development of new technologies likely to revolutionize teaching in classrooms. But unfortunately, the process of updating curricula of teacher education has been very slow. Today teaching is a profession requiring specialization in terms of knowledge and skills. There exists a wide gap between theory and the knowledge and skills of teaching required in the actual classroom curriculum transaction. For this reason, a routine-bound teacher cannot act in accordance with the emerging needs unless he or she is trained and frequently oriented. One of the most important requirements to promote and strengthen education is the training of teachers who are the key resources in the reform, redirection and renewal of education. In this backdrop the present paper reflects upon the actual reasons of revision in the programme. The paper also focuses on various challenges and issues considerable enough in the implementation of the programme. Some of such challenges are increased financial burden on the parents

of aspiring B. Ed. Students, setting up of enriched infrastructure to meet the needs of various curricular enhancements and most importantly the restructuring of teacher education curriculum that aims at all round human development. The paper tries to reflect upon the feasibility of the prolonged programme from the vantage point of the aspiring B. Ed. students and various stakeholders such as administrators, school managements, parents of aspiring candidates and curriculum designers.

**Development of Teacher Education in India :** The training of teachers assumes great significance in the educational system. Teacher education system is an important vehicle to improve the quality of school education. It is a continuous process. It is well recognized that the overall quality in education depends amongst other things on the quality of teacher and that a sound programme of profession education of teachers is essential. The Government of India realized the importance of Teacher Education as a result of which many reforms were brought out particularly after independence. Various committees and commissions have time and again made recommendations to bring about required changes in teacher education programme. The University Education Commission (1948) recommended that theory and practice of pre-service teacher education must support each other. The Secondary Education Commission (1952-53) recommended the adoption of new techniques of evaluation and suggested that more capable

and intelligent persons should be attracted to teaching profession. Education commission (1966) stated that the professional preparation of teachers had been recognized to be crucial for the qualitative improvement of education since the 1960s. In the year 1973, the government of India constitutes the National Council of Teacher Education (NCTE) to act as national advisory body on all matters relating to teacher education and review the progress plan scheme to ensure adequate standards in the field of Teacher Education. The expansion of pre service teacher education is impressive if one looks at the continuous growth in the number of teacher education institutes. From a mere 10 secondary teacher training institutions in 1948, the number increased to 50 in 1965 and 633 in 1995. These figures grew as high as 4868 in 2002 and 11712 in 2010. The significant revisions in the teacher education programme were last recommended in National Curriculum Framework for Teacher Education in 2009 and subsequently with amendment in the constitution to make Education a Fundamental Right, curricular reforms and duration of the programme were reviewed.

#### **Issue of implementation of the two year programme :**

The primary issue that may emerge due to implementation of two year programme is of lack of interest among the students towards the B.Ed. course. Given the fact that two year programme would require higher financial burden on the parents of the aspiring student teachers, such parents are very likely to be reluctant to spend in the course. As far as the attitude of the students is concerned, it may be hypothesized that because of the prolonged duration and increased financial burden, students' participation in the B. Ed. Programme would go down. Importantly, the enrolment in various courses of Education discipline has been slightly fluctuating in the previous years. According to AISHE Report of 2011-12 the enrolment in Education discipline was 3.10%, which remained same in the session 2012-13. As concerns the data of 2013-14 the figures grew to 5.42% of the total enrolment in higher education. Though the pertinent data of 2015, the year in which two year B. Ed. Programme was launched is yet not available. It may be speculated as has been unofficially reported by number of B. Ed. Colleges across the country that the admission in B. Ed. Two year programme is going to be very scant. My visits as external examiner for B.Ed. practicals in couple of colleges affiliated to Kanpur University have revealed the ground realities of fewer admissions in the two year programme so far.

It is important to note that the attitude of the students who earlier got attracted towards the course and the profession was primarily guided by the possibility of easy access and short duration of the course. But now given the fact that the duration of the programme is prolonged and certain eligibility criteria is fixed for the entry in the profession, the students who found it an easy and attractive profession are likely to be reluctant. It has been observed that quite a few students have also dropped the course and most of them have

reported the long duration of the course to be the reason for their withdrawal. Moreover, in the neo liberal and globalised world where human capital and professionalism is cherished, less number of students would get attracted towards a long and expansive course which leads to a low paid profession.

Implementation of Two Year B. Ed. Programme would also require great deal of infrastructural adjustments to meet the curricular requirements of the revised course. The revised curriculum as has been prescribed by the National Council of Teacher Education primarily requires the semester system to be in place, and the duration of teaching practice to be increased to not less than six months. Considering these revisions, there would be a need of more number of faculty members, experimental schools attached to various colleges, enriched library to fulfill the additional course requirements and proactive administration to execute the innovative programme more efficiently. As far as the new course curriculum is concerned, it has been observed that the curriculum constructed by NCTE is focused around complete personal and professional development of the pupil teachers. Drawing upon the constructivist approach of teaching, various changes have been called for. As has been earlier reported by various studies that one year B.Ed. programme is insufficient in realizing the goals of education, the new course focuses on the knowledge construction. Now the idea of learning is not remaining to be a passive process, as it has been established that learner its active himself in the process of learning. Courses like Gender and Education, Art Education and Curriculum Development are some of the newer additions making the B.Ed. course to be much more comprehensive and sensitive towards the present social scenario. However, it would be interesting to observe whether such courses are also transacted with adequate vigor and sensitivity. It is also to be seen whether the combination of theory and practical works towards the intellectual as well as the professional development of the pupil teachers.

#### **Reasons for revisions in teacher education programme**

: An immense writing has appeared on educational quality in recent years, examining factors that help improve education and proposing ways to promote better learning in schools. The issue of quality has become critical in many countries. In countries like India where with constrained resources, the successful effort to increase access to basic education has often led to declining quality of education. In a search for the factors that promote quality, programs as well as the literature increasingly emphasize teachers, schools, societies and communities as the engines of quality, with teacher quality identified a primary focus. The rapid changes in society led to teachers facing new and complex issues, resulting in changes in the area of teacher education. Advances in technology have also posed an issue for future educators. Many educators have focused

on ways to incorporate technology into the classroom. Television, computers, radio, and other forms of mass media are being utilized in an educational context, often in an attempt to involve the student actively in their own education. Hence, many teacher education programs now include courses both in technology operation and how to use technology for education purposes. With the coming on of distance learning utilizing mobile technologies and the internet understanding of technology or we can say e-learning has become crucial for new teachers in order to keep up with the knowledge and interests of their students in these delivery systems. The emergence of a networked knowledge economy presents both opportunities and challenges for teacher education. Considering these changes in the socio economic and political system of the nation, revisions in the existing teacher education programme appears to be the immediate need of the hour.

**Conclusion:** Revisions and experimentations in the existing B.Ed. programme was felt needed and required immediate implementation. However, it's too early to reach to any conclusions about the impact of the programme, as it has only been a few months that the revised programme is in practice. Various curriculum frameworks have time and again pointed out that teacher education programme have direct impact on education system of any country. Therefore, pedagogical revisions and addition of new courses in the existing programme would certainly result in revolution in the education system. It may be concluded that changes in teacher education programme was indeed required at the ideological as well as practical level. The new course should focus around critical pedagogy and realize the agency in every individual learner so that the true meaning of education may be realized. The new course should produce sensitive and innovative teachers trained in their profession of guiding children in building new knowledge. There is a need of effective campaigning of the new and prolonged programme which can attract quality students to pursue teaching as their profession. It is important to highlight that the new course should be implemented efficiently by all the stake holders involved. Though, critics point to the rundown nature of education and the public has accepted that it is because the teachers shirk work and are the problem. This decline in the status of academics has enabled the politicians, bureaucrats and businessmen to intervene even though they neither understand the ground

realities nor accept their own role in running the system down. Therefore, it is expected that all those who have stake in the system of education should contribute in their specific and significant ways. In brief, if talent is to be nurtured, the revised Two Year B. Ed. Programme must overhaul the entire education system based on the ground realities and a holistic perspective. For this, diverse academic voices need to be heard rather than only of those at the top and who have actually been creating the problem and whose agenda may not be real reform.

**References :-**

1. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2011-12.
2. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2012-13.
3. Goel ER, Chhaya Goyal. Teacher Education Scenario in India: Current Problems & Concerns in MIER Journal of Educational Studies Trends & Practices. 2012 Nov;2(2):231-242.
4. Policy Perspective in Teacher Education: Critique and Documentation, National Council of Teacher Education, New Delhi, 1998.
5. Arora GL, Pranati Panda (Eds.). Fifty Years of Teacher Education in India: Post Independence developments, NCERT, New Delhi, 2004
6. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2011.
7. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2012.
8. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2013.
9. Annual Report, University Grants Commission, Government of India, New Delhi, 2013.
10. All India Survey on Higher Education Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, 2013-14.
11. Annual Report, Ministry of Human Resource and Development, Government of India, New Delhi, 2014.
12. Annual Report, University Grants Commission, Government of India, New Delhi, 2014.
13. Education For All Towards Quality and Equity India Report, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi, 2014.

\*\*\*\*\*

# Enhancing Environmental Education Through Pre-Service Teacher Training: Strategies, Benefits, and the Role of Educators

Ranjana Sharma\* Ramesh Chandra Nagda\*\*

\*Assistant Prof. (Education) Nathdwara Institute of Biotechnology & Management, Nathdwara (Raj.) INDIA  
 \*\*Principal, The Nobles T.T. College, Kherwara, (Raj.) INDIA

**Abstract :** Environmental challenges such as climate change, pollution, deforestation, and biodiversity loss pose significant threats to global sustainability. Education plays a critical role in addressing these challenges, with teachers serving as key facilitators in fostering environmental awareness and sustainable behaviors. This paper explores the role of pre-service teacher training in enhancing the effectiveness of environmental education (EE). It examines how well-structured training programs equip future educators with the knowledge, pedagogical skills, and values necessary to deliver impactful EE. The study highlights the benefits of integrating EE into teacher education programs, including improved content knowledge, increased confidence, interdisciplinary teaching strategies, and action-oriented learning approaches. Additionally, it discusses strategies to enhance EE in teacher training, such as hands-on learning experiences, collaboration with environmental organizations, and the integration of sustainability practices. Furthermore, the paper emphasizes the pivotal role of teachers in developing students' environmental responsibility through curriculum integration, critical thinking, eco-friendly role modeling, and community engagement. By effectively preparing teachers through pre-service training, education systems can foster a generation of environmentally conscious individuals who actively contribute to sustainability efforts.

**Keywords:** Environmental Education (EE), teacher education, pre-service teacher training, environmental awareness, sustainability.

**Introduction** - Environmental challenges such as climate change, deforestation, pollution, and biodiversity loss pose significant threats to global sustainability. Education is essential in tackling these challenges, with teachers playing a vital role in raising environmental awareness and encouraging sustainable practices. Achieving sustainable development requires a fundamental shift in society's attitude toward nature and the environment, which can be facilitated through moral and ethical education. It is essential to instill and reinforce environmental values in young minds to develop a sense of responsibility toward nature. By imparting knowledge and sensitizing both students and society about environmental issues, teachers contribute to tackling environmental challenges.

Professional development through training is a key strategy to improve the effectiveness of environmental education (EE). Strengthening pre-service and in-service teacher training programs in EE is crucial for preparing educators who can effectively promote environmental literacy and inspire future generations to engage in sustainable practices<sup>3,4,8</sup>. Studies indicate that many science teachers, who often serve as EE instructors, lack adequate

preparation to teach Education for Sustainable Development (ESD). Their understanding of ESD remains limited, highlighting the need to enhance their capacity to teach environmental concepts effectively<sup>9</sup>. While EE is implemented across all levels of education through structured approaches, few institutions offer specialized EE training alongside general teacher education programs<sup>5</sup>. This gap in teacher training programs, both pre-service and in-service, limits the effectiveness of EE integration in curricula.

Since EE intersects multiple disciplines and levels of study, policymakers and education planners should integrate it as a mandatory component across all educational levels. Teacher training curricula should incorporate EE through both theoretical and practical courses. A structured approach to EE should begin by fostering student awareness of the environment, followed by an understanding of the relationship between humans and nature. Teachers play a crucial role in helping students develop the knowledge and skills needed to address environmental challenges while encouraging participation in environmental protection initiatives. From an early stage,

educators must instill environmental knowledge and cultivate a positive attitude toward conservation and sustainability. There is a growing need to organize and implement educational programs focusing on environmental issues, solutions, and attitudes toward preservation and conservation<sup>7</sup>.

Environmental education training is one of the most commonly attended programs by science teachers and those specializing in environmental studies. Several initiatives have been conducted, including EE training for prospective teachers<sup>6</sup>, EE for sustainability<sup>11</sup>, and EE integrated into science learning<sup>10,12</sup>. Such training programs provide teachers with opportunities to utilize natural surroundings as a learning resource, enhancing students' understanding of environmental concepts<sup>1</sup>. As mastering subject knowledge and pedagogical skills is essential for achieving Sustainable Development Goals (SDGs), continuous professional development through EE training can significantly contribute to the professionalism of teaching and the advancement of environmental education<sup>2</sup>. This paper highlights the significance of pre-service teacher training in enhancing the effectiveness of environmental education (EE). It explores how equipping future educators with environmental knowledge, attitudes, and skills positively impacts their ability to integrate EE into their teaching practices. Additionally, the paper examines the key benefits of incorporating EE into teacher training programs, emphasizing its role in fostering environmental awareness, critical thinking, and responsible behavior among students. Various strategies for improving EE within teacher training are also discussed, including experiential learning opportunities, interdisciplinary integration, and hands-on activities that bridge theory with practice. Furthermore, the paper underscores the crucial role of teachers in shaping students' environmental consciousness and promoting sustainable practices, ultimately contributing to a more environmentally responsible society.

**Research Questions:** This study aims to address the following research questions:

1. How does pre-service teacher training influence the effectiveness of environmental education?
2. What are the key benefits of incorporating environmental education into pre-service teacher training programs?
3. What strategies can be adopted to improve environmental education in teacher training programs?
4. How do teachers contribute to enhancing students' environmental awareness and responsibility?

**Research Methodology:** This paper is theoretical in nature.

**Influence of Pre-Service Teacher Training on the Effectiveness of Environmental Education:** Pre-service teacher training is essential in enhancing the impact of environmental education (EE). Well-designed training programs equip future teachers with the necessary knowledge, skills, and attitudes to deliver impactful EE in

classrooms.

Enhancing content knowledge is essential for effective environmental education, as teachers need a strong understanding of environmental concepts, sustainability, and ecological interconnections. Pre-service teacher training programs are instrumental in establishing this foundation by incorporating subjects like environmental science, climate change education, and sustainable development. These programs provide future educators with thorough and precise knowledge, empowering them to teach environmental topics with confidence and clarity. A well-rounded understanding of these concepts allows teachers to present complex environmental issues in an accessible and engaging manner, helping students develop a deeper awareness of sustainability and ecological responsibility.

Developing pedagogical skills is also crucial for effective environmental education, as it enables teachers to create engaging and student-centered learning experiences. Pre-service training equips future educators with interactive teaching strategies such as inquiry-based learning, problem-solving, and experiential education, which encourage students to think critically about environmental issues. Additionally, methods like outdoor education, project-based learning, and interdisciplinary approaches make environmental education more practical and relevant by connecting classroom lessons to real-world environmental challenges. By mastering these teaching strategies, educators can foster deeper student engagement and inspire meaningful discussions on sustainability and ecological responsibility.

Fostering environmental attitudes and values in teachers is essential for promoting a meaningful and impactful approach to environmental education. Educators with strong environmental awareness and a personal commitment to sustainability are more likely to inspire students to develop a sense of responsibility toward the environment. Pre-service training programs that incorporate eco-literacy and value-based learning help cultivate this intrinsic motivation, encouraging teachers to integrate environmental education into their teaching practices. By fostering a deep appreciation for nature and sustainability, these programs empower educators to instill similar values in their students, ultimately contributing to a more environmentally conscious generation.

Building confidence and competence is crucial for pre-service teachers, as many feel unprepared to teach environmental education due to a lack of knowledge or effective teaching methods. Hands-on experiences, micro-teaching, and exposure to real-world environmental challenges help them develop the confidence and skills needed to deliver impactful lessons. Similarly, encouraging interdisciplinary approaches enhances the effectiveness of environmental education by integrating it across subjects such as science, social studies, ethics, and policy

discussions. This interdisciplinary connection enables teachers to present environmental concepts in a more holistic and meaningful way.

Providing access to resources and networks further strengthens pre-service training by introducing educators to environmental organizations, teaching materials, and technological tools that support environmental education. Collaborations with NGOs, environmental agencies, and community-based projects enhance the practical application of environmental education in schools, giving teachers valuable opportunities to engage with real-world environmental issues. Additionally, promoting action-oriented education ensures that environmental learning leads to tangible behavior changes. Training programs that incorporate service-learning projects, eco-clubs, and community engagement activities encourage teachers to design lessons that inspire students to take real-world environmental action.

Despite the benefits of environmental education, many teachers face challenges such as curriculum constraints, lack of administrative support, and inadequate resources. Pre-service training that includes discussions on overcoming these barriers equips future educators with strategies to integrate environmental education effectively, even in challenging circumstances. By addressing these obstacles, training programs empower teachers to become advocates for environmental education, fostering a generation of students who are knowledgeable, engaged, and committed to sustainability.

#### **Key Benefits of Incorporating Environmental Education into Pre-Service Teacher Training Programs:**

Incorporating environmental education (EE) into pre-service teacher training programs provides a range of key benefits that enhance both teacher preparedness and student outcomes. Pre-service teachers gain a solid understanding of environmental concepts, sustainability, and ecological issues, allowing them to deliver accurate and well-informed lessons. Training in EE equips educators with effective, student-centered teaching strategies such as inquiry-based learning, experiential education, and project-based approaches, making lessons more engaging and interactive. Many teachers may feel unprepared to teach environmental topics, but pre-service training builds their confidence through hands-on experiences, lesson planning, and practice teaching. Additionally, exposure to EE fosters environmental literacy and a personal commitment to sustainability, encouraging teachers to integrate these values into their lessons and inspire students to adopt eco-friendly behaviors.

EE training also promotes an interdisciplinary approach, allowing teachers to incorporate sustainability topics across various subjects such as science, social studies, ethics, and policy discussions. Pre-service training connects future educators to environmental organizations, teaching materials, and digital tools, providing resources

that enhance the learning environment. Furthermore, EE training encourages action-oriented education by involving students in real-world projects, eco-clubs, and community engagement activities that inspire them to take environmental action. Teachers are also prepared to overcome barriers, such as curriculum limitations and lack of resources, by gaining strategies to integrate EE effectively despite challenges. Finally, teachers trained in EE are more likely to inspire students to develop critical thinking skills, environmental responsibility, and sustainable habits, creating a lasting impact on student engagement and contributing to a more environmentally conscious future generation.

#### **Strategies to Improve Environmental Education in Teacher Training Programs:**

Enhancing the integration and effectiveness of environmental education (EE) in teacher training programs requires strategic approaches. Incorporating experiential learning opportunities—such as field trips, outdoor classrooms, and community-based projects—helps pre-service teachers bridge theoretical knowledge with practical applications, strengthening their ability to teach environmental concepts effectively. Additionally, embedding EE across various disciplines, including social studies, ethics, and the arts, fosters a holistic understanding of environmental issues. This interdisciplinary approach encourages educators to view EE as a fundamental, cross-cutting theme that enriches the overall curriculum.

Training programs should also focus on specific pedagogical strategies for teaching EE, such as project-based learning, inquiry-based learning, and problem-solving approaches, which foster critical thinking and action-oriented learning. Emphasizing eco-literacy and sustainability practices allows future teachers to model sustainable behaviors in their classrooms, promoting values like energy conservation, waste reduction, and green technologies. Collaborations with environmental organizations and NGOs can provide teachers with valuable resources, guest speakers, and service-learning opportunities that enhance the environmental education experience.

Incorporating technology and digital tools, such as environmental apps and virtual field trips, can make EE more engaging and interactive. Teacher training programs should also offer continuous professional development opportunities, including workshops and conferences, to keep educators up-to-date on the latest environmental issues and teaching strategies. Encouraging reflective practices helps teachers connect their personal environmental values to their teaching, fostering a deeper commitment to sustainability. Additionally, fostering collaboration and networking with fellow educators, environmental experts, and community leaders provides teachers with fresh ideas and resources to enhance their teaching. Lastly, creating a school culture of sustainability

within teacher training programs by adopting eco-friendly practices reinforces the importance of environmental stewardship. By adopting these strategies, teacher training programs can better prepare future educators to teach environmental education in innovative and impactful ways.

**The Role of Teachers in Enhancing Students' Environmental Awareness and Responsibility:** Teachers play a critical role in fostering environmental awareness and responsibility among students by shaping how they perceive and interact with the environment. They contribute in several impactful ways. By incorporating environmental education into the curriculum, teachers embed topics such as ecosystems, human impact, and sustainability across subjects like science, social studies, and language arts, helping students understand the interconnectedness of the world around them. This integration highlights the urgency and relevance of environmental issues in students' daily lives. Teachers also model sustainable practices, demonstrating eco-friendly behaviors like waste reduction, energy conservation, and recycling. When students see their teacher's practicing sustainability, they are more likely to adopt similar habits.

Through promoting critical thinking and problem-solving skills, teachers encourage students to engage with real-world environmental challenges, empowering them to explore solutions and develop a deeper understanding of sustainability. Teachers also facilitate environmental action and engagement by organizing initiatives like eco-clubs and service-learning projects, motivating students to take responsibility for positive change in their communities. By creating spaces for open discussions on environmental topics, teachers help students develop a sense of environmental justice, raising awareness about issues like climate change and pollution.

Teachers who connect students to the outdoors, through field trips to parks or reserves, help them develop a deeper appreciation for nature and an understanding of the importance of protecting natural resources. Instilling values of sustainability in their lessons, teachers foster a sense of responsibility and stewardship, teaching students the long-term benefits of making environmentally conscious choices. Finally, by empowering students to become advocates for environmental causes, teachers provide the knowledge and skills needed to participate in campaigns and raise awareness. Through these efforts, teachers not only educate students about environmental issues but also inspire them to act with care and responsibility, contributing to the development of environmentally conscious citizens.

**Conclusion:** Incorporating environmental education into pre-service teacher training programs is essential for equipping future educators with the knowledge, skills, and values necessary to address the environmental challenges of the 21st century. By enhancing content knowledge, developing pedagogical skills, fostering environmental attitudes, and providing hands-on learning experiences, pre-

service training programs can empower teachers to deliver impactful environmental education in the classroom. Teachers, in turn, play a critical role in shaping students' environmental awareness and responsibility, contributing to the development of a sustainable, environmentally conscious society.

#### References:-

1. Cheah, K. S. (2019). Implementation of Environmental Education Program (EEP) in A Nature Education School (NES): Strategies, Benefits & Challenges. *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management*, 7(2), 92-121. Retrieved from <https://mojom.um.edu.my/article/view/17308>
2. Darmawan, M. D., & Dagamac, N. H. (2021). Situation of environmental education in senior high school programs in Indonesia: Perspectives from the teachers of Palembang. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 17(3), e2241. <https://doi.org/10.21601/ijese/9605>
3. Eliyawati, E., Widodo, A., Kaniawati, I., & Fujii, H. (2023a). The Development and Validation of an Instrument for Assessing Science Teacher Competency to Teach ESD. *Sustainability*, 15(4), 3276. <https://doi.org/10.3390/su15043276>
4. Eliyawati, E., Widodo, A., Kaniawati, I., & Fujii, H. (2023b). Merancang Program Pelatihan Guru Yang Dapat Mengembangkan Kompetensi Guru IPA dalam Mengajarkan ESD. Paper presented at the Proceeding Seminar Nasional IPA, Semarang.
5. Gautam, G. (2015). Need of Environmental Education in Teacher Education, *International Journal for Research in Education (IJRE)*, 4(7), 34-37.
6. Gulomiddinovna, A. U., & Musayevich, O. S. (2022). Ways of environmental education in the teaching of chemistry in higher education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 341-343. <http://dx.doi.org/10.5958/2249-7315.2022.00293.3>
7. Kaur, S. (2013). Role of Teachers in Imparting Environmental Education for Sustainable Development. *International Educational E-Journal*, 2(2), 10-16.
8. Mulyadi, D., Ali, M., Ropo, E., & Dewi, L. (2023). Correlational Study: Teacher Perceptions and The Implementation of Education for Sustainable Development Competency for Junior High School Teachers. *Journal of Education Technology*, 7(2). <https://doi.org/10.23887/jet.v7i2.62728>
9. Novidsa, I., Purwianingsih, W., & Riandi, R. (2020). Exploring knowledge of prospective biology teacher about education for sustainable development. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 6(2), 317-326. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v6i2.12212>
10. Purwianingsih, W., Novidsa, I., & Riandi, R. (2022).

- Program for Integrating Education for Sustainable Development (ESD) into Prospective Biology Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(2). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii/article/view/34772>
11. Wahyudin, D., & Malik, R. S. (2019). Teaching environmental education for sustainable development: strategies and challenges. *Journal of Sustainable Development Education and Research*, 3(1), 51-70. <https://doi.org/10.17509/jsder.v3i1.17172>
  12. Wichmann, C.-S., Fischer, D., Geiger, S. M., HonoratoZimmer, D., Knickmeier, K., Kruse, K., Thiel, M. (2022). Promoting pro-environmental behavior through citizen science? A case study with Chilean schoolchildren on marine plastic pollution. *Marine Policy*, 141, 105035. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105035>

\*\*\*\*\*



# Comparison of Perceived Motivational Climate by Male and Female Intercollegiate Players of Selected Team Games

Manish Mukherjee\* Dr. Jai Shankar Yadav\*\*

\*Research Scholar (Physical Education) Dr. CV Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

\*\* Professor and Dean (Education and Physical Education) Dr. CV Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

**Abstract :** The present study aims to assess the difference in perceived motivational climate by male and female players from selected team games namely basketball, volleyball and soccer. In the present study, 300 intercollegiate players from Chhattisgarh were selected in which equal representation was given to male and female players. The sample consists of 150 male and 150 female players. Out of these, 50 male and 50 female basketball players, 50 male and female volleyball players and 50 male and 50 female soccer players were selected. The age group of the sample was 18 to 27 years. To assess athletes' perceptions of the motivational climate, the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire – 2 (PMCSQ-2) prepared by Newton, Duda, and Yin (2000) was used. The result reveals male players high perception of both mastery and performance climate as compared to female players. Hence it can be concluded that male players' higher mastery and performance climate perceptions are consistent with the theory of gender socialization, competitiveness, and motivation differences and therefore an inclusive training program is prepared for a balanced motivational climate for both genders.

**Keywords:** Motivational Climate, male and female players, team games.

**Introduction** - Motivation is a key element of sports performance and athletes experience in sports. Motivation also plays a part in the efforts put in by athletes. Motivation is a psychological force that drives a person to think, behave and act towards achieving a goal with sustained effort. Motivation affects decision-making processes and it shapes human acts that are beneficial for success in allied fields in life. Motivation can be extrinsic or intrinsic. The term "motivational climate" is derived from achievement goal theory. Motivational climate is related to environmental factors. How these environmental factors affect motivational climate i.e. regarding a person's goal setting and perception of abilities. Nicholls (1989) and Elliot (1999) opined that personal and social attributes form a motivational climate which then affects the goals pursued by an individual. In simple terms, motivational climate defines the environment created by the surroundings and coaching induced atmosphere around a person. McArthur and Baron (1983) and Nicholls (1989) opined that every individual has a perception of success and goal achievement which are their own beliefs. Motivational climates are mainly of two types i.e. mastery and performance climate. Biddle et al. (1995) suggest that motivation is influenced by personal goals as well as situational factors i.e. if a person is more inclined to

self-improvement a mastery climate will be useful for success. It has been opined that a mastery climate is conducive and more suited to achieving goals (success) because it encourages the development of new skills which eventually helps in winning and performing better than others. The second motivational climate described in achievement goal theory is performance climate. Ames and Archer, 1988 defined it as a climate created by trainers, coaches and teachers which stressed the need for competition, comparing achievement with others and winning as the sole objective. The present study will offer useful information on gender-specific differences in the perception of motivational climate by players. This will enable coaches to customize their training plan to create a supportive environment for players and facilitate athletes' performance and motivation.

## Review Of Literature

**Castro-Sánchez et al. (2018)** explored the relationship between motivational climate, emotional intelligence, and anxiety in Spanish athletes from different team and individual sports. **Jakobsen (2021)** investigated how ice hockey players' perceptions of coach support, motivation, and goal orientation are connected. It was observed that when young players feel that their decisions are supported

by coaches, then they are much more motivated to adopt task-oriented pursuits to improve their game with more rigorous effort. **Morales-Sánchez et al. (2022)** assessed young soccer players' perception of motivational climate and its impact on competitive anxiety and self-confidence. It was found that an increase in ego orientation leads to a decrease in self-confidence and an increase in anxiety in young soccer players. In contrast, the task-oriented climate was positively linked to self-confidence in soccer players. Male players perceive a stronger ego climate than girls while ego orientation has a more detrimental effect on female players than male players. **Tomar and Shubam Kumar (2023)** highlighted the impact of motivational climate on badminton players' success. A positive climate, with supportive coaching and teamwork, boosts motivation, dedication, and growth. Encouraging intrinsic motivation and resilience helps players excel. **Rismayanthi et al. (2023)** in this study found that male athletes are significantly more motivated to achieve success than female athletes but the result was not proven statistically. **Azzahra et al. (2024)** used a quantitative descriptive method to examine the motivational climate of athletes based on the nature of sports. Results showed that team athletes had a slightly higher motivational climate than individual athletes. **Kiss and Nagy (2024)** explored the link between sports motivation and psychological factors like perceived motivational climate, coping skills, and anxiety in 293 Hungarian ice hockey players. The authors emphasized the need to address amotivation to enhance performance, self-confidence, and resilience in athletes. **Nunes et al. (2024)** explained the effect of various coaching styles on soccer players' perception towards motivational climate. It was concluded that coaching behaviour is directly linked to players' thoughts on the training environment and while a supportive and feedback-driven approach creates a task-oriented climate whereas too much punishment and lack of encouragement lead to the creation of an ego-oriented climate.

**Objective:** The present study aims to assess the difference in perceived motivational climate by male and female players from selected team games namely basketball, volleyball and soccer.

**Hypothesis:** There will be a significant dissimilarity in the perceived motivational climate by male and female players.

**Methodology:** The Following Methodological Steps Were Taken To Conduct The Present Study.

**Sample:** The sample consists of 150 male and 150 female players. Out of these, 50 male and 50 female basketball players, 50 male and female volleyball players and 50 male and 50 female soccer players were selected. The age group of the sample was 18 to 27 years

**Tools:**

**Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire – 2 (PMCSQ-2):** To assess athletes' perceptions of the motivational climate, the Perceived Motivational Climate in

Sport Questionnaire – 2 (PMCSQ-2) prepared by Newton, Duda, and Yin (2000) was used. The questionnaire assesses motivational climate in two dimensions namely mastery-orientated and performance-oriented goals. It consists of 33 items of which 17 items are for the assessment of mastery-oriented climate and 16 items for the assessment of performance-oriented climate. In this questionnaire, subjects rate statements on a 5-point Likert Scale about their perception of the motivational climate in a team environment. The five choices are strongly disagree, disagree, neutral, agree and strongly agree with a numerical weightage of 1 to 5. This questionnaire is highly reliable and valid.

**Procedure:** 150 male and 150 female intercollegiate players were selected from different team games namely basketball, volleyball and soccer. Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire – 2 (PMCSQ-2) prepared by Newton, Duda, and Yin (2000) was administered and responses were scored for mastery and performance climate. After the classification of data, an independent sample 't' test was applied and results were obtained.

### Result And Discussion

#### Table 1 (See in last page)

Results given in Table 1 indicate that male players ( $55.50 \pm 13.38$ ) have a significantly higher perception of mastery climate as compared to female players ( $48.68 \pm 14.32$ ). The t-value of 4.26 proves that the mean difference of 6.82 is statistically significant ( $p < .01$ ).

Results given in Table 1 indicate that male players ( $48.30 \pm 12.74$ ) have significantly higher perceptions of performance climate as compared to female players ( $43.78 \pm 11.61$ ). The t-value of 3.21 proves that the mean difference of 4.52 is statistically significant ( $p < .01$ ).

Results in Table 1 show that male players perceive both the characteristics of motivational climate (mastery and performance) more favourably than female players.

#### Table 2 (See in last page)

Results given in Table 2 indicate that male basketball players ( $57.12 \pm 10.90$ ) have a significantly higher perception of mastery climate as compared to female basketball players ( $48.48 \pm 16.14$ ). The t-value of 3.13 proves that the mean difference of 8.64 is statistically significant ( $p < .01$ ).

Results given in Table 2 indicate that male basketball players ( $48.16 \pm 10.42$ ) have significantly higher perceptions of performance climate as compared to female basketball players ( $43.92 \pm 9.73$ ). The t-value of 2.10 proves that the mean difference of 4.24 is statistically significant ( $p < .05$ ).

Results in Table 2 show that male basketball player's perception of both the characteristics of motivational climate (mastery and performance) are more favourable than female basketball players.

#### Table 3 (See in last page)

Results given in Table 3 indicate that male volleyball players ( $55.22 \pm 13.59$ ) have a significantly higher perception of mastery climate as compared to female volleyball players

(48.82±11.76). The t-value of 2.51 proves that the mean difference of 6.40 is statistically significant ( $p < .05$ ).

Results given in Table 3 indicate that although male volleyball players (46.60±13.79) have a higher perception of performance climate as compared to female volleyball players (44.32±11.51). The t-value of 0.89 did not prove that the mean difference of 2.28 was statistically significant.

**Table 4(See in last page)**

Results given in table 4 indicate that although male soccer players (54.16±15.37) have a higher perception of mastery climate as compared to female soccer players (48.74±15.00). The t-value of 1.78 did not prove that the mean difference of 5.42 is statistically significant ( $p > .05$ ).

Results given in Table 4 indicate that male soccer players (50.16±13.73) have significantly higher perceptions of performance climate as compared to female soccer players (43.12±13.48). The t-value of 2.58 proves that the mean difference of 7.04 is statistically significant at 0.01 level.

**Discussion:** The result reveals male players high perception of both mastery and performance climate as compared to female players. This may be due to gender socialization which encourages boys to be more competitive and for that, they need to acquire and learn new skills. The higher perception of performance climate denotes that male players are more inclined towards social identity and rewards. Mastery climates augment intrinsic motivation by nurturing capability and self-sufficiency, which male players may experience more. In contrast, female players' lower insight of performance climate indicates that they are less prejudiced by external competition or reward or find it less conducive to their motivation and growth.

**Conclusion:**

1. The perception of mastery climate in male players was higher as compared to female players.
2. The perception of performance climate in male players was higher as compared to female players.
3. The perception of both types of motivational climate was higher in male players as compared to female players across different team games namely basketball, volleyball and soccer.

Hence it can be concluded that male players' higher mastery and performance climate perceptions are consistent with the theory of gender socialization, competitiveness, and motivation differences and therefore an inclusive training program is prepared for a balanced motivational climate for both genders.

**References:-**

1. Ames, C. (1992a). Classrooms: goals, structures, and motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84, 261-271.
2. Azzahra, S. F., Fitri, M., Zaky, M., & Apriady, H. (2024). Understanding motivational climate in sports: A

comparative perspective on team and individual athletes Syabani Fatimah Azzahra. *Jurnal SPORTIF/ : Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 10(4), 1–16.

3. Biddle, S. J. H., Cury, F., Goudas, M., Sarrazin, P., Famose, J. P., & Durand, M. (1995). Development of scales to measure perceived physical education class climate: A cross-national project. *British Journal of Educational Psychology*, 65, 341-358.
4. Castro-Sánchez, M.; Zurita-Ortega, F.; Chacón-Cuberos, R.; López-Gutiérrez, C.J.; and Zafra-Santos, E. (2018). Emotional Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different Categories of Sports: Analysis through Structural Equations. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 15, 894.
5. Elliot, A. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. *Educational Psychologist*, 34, 169-189.
6. Jakobsen, A.M. (2021). The relationship between Motivation, Perceived Motivational Climate, Task and Ego Orientation, and Perceived Coach Autonomy in young ice hockey players. *Balt J Health Phys Act.*; 13(2):79-91.
7. Kiss, C. and Nagy, A. (2024). Motivation Profiles, Perceived Motivational Climate, Coping Perceptions and Anxiety Among Elite Young Ice Hockey Players. *Physical Culture and Sport. Studies and Research*, Vol. 105, 65-81.
8. McArthur, L. Z., & Baron, R. M. (1983). Toward an ecological theory of social perception. *Psychological Review*, 90, 215-238.
9. Morales-Sánchez, V., Caballero-Cerbán, M., Postigo-Martín, C., Morillo-Baro, J.P., Hernández-Mendo, A. and Reigal, R.E. (2022). Perceived Motivational Climate Determines Self-Confidence and Precompetitive Anxiety in Young Soccer Players: Analysis by Gender. *Sustainability*; 14(23):15673.
10. Nicholls, J. G. (1989). *The competitive ethos and democratic education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. Nunes, N.A., Doncom, T. and Discombe, R. (2024). Variation in Perceived Motivational Climate in Sports Among Young Football Players: A Case Study During a Tournament Preparation. *Advances in Social Sciences and Management*, Vol-2, No-2, pp. 17-25.
12. Rismayanthi, C., Tomoliyus, A.A., and Fauzi, E.R.S. (2023). Analysis of Achievement Motivation in Male and Female Tennis Athletes at the Competitive Level of Yogyakarta," *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, Vol. 11, No. 5, pp. 1168-1173.
13. Tomar, V.S. and Shubam Kumar (2023). Enhancing Performance and Passion in Badminton: The Role of Motivational Climate. *International Journal of Science and Research*, 12(8), 7-9.

**Table 1: Comparison of Perception of the Motivational Climate by Male and Female Players**

Motivational Climate	Male Players (N=150)		Female Players (N=150)		Mean Diff.	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mastery Climate	55.50	13.38	48.68	14.32	6.82	4.26**
Performance Climate	48.30	12.74	43.78	11.61	4.52	3.21**

\*\* p value < 0.01

**Table 2: Comparison of Perception of the Motivational Climate by Male and Female Basketball Players**

Motivational Climate	Male Basketball Players (N=50)		Female Basketball Players (N=50)		Mean Diff.	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mastery Climate	57.12	10.90	48.48	16.14	8.64	3.13**
Performance Climate	48.16	10.42	43.92	9.73	4.24	2.10*

\*\* p value < 0.01, \* p value < 0.05

**Table 3: Comparison of Perception of the Motivational Climate between Male and Female Volleyball Players**

Motivational Climate	Male Volleyball Players (N=50)		Female Volleyball Players (N=50)		Mean Diff.	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mastery Climate	55.22	13.59	48.82	11.76	6.40	2.51*
Performance Climate	46.60	13.79	44.32	11.51	2.28	0.89 <sup>NS</sup>

\* p value < 0.05, <sup>NS</sup> Not Significant

**Table 4: Comparison of Perception of the Motivational Climate between Male and Female Soccer Players**

Motivational Climate	Male Basketball Players (N=50)		Female Basketball Players (N=50)		Mean Diff.	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mastery Climate	54.16	15.37	48.74	15.00	5.42	1.78 <sup>NS</sup>
Performance Climate	50.16	13.73	43.12	13.48	7.04	2.58**

\*\* p value < 0.01, <sup>NS</sup> Not Significant

\*\*\*\*\*

# Chemical Study of Indigenous Plants for Respiratory Health of Nimar Region of Madhya Pradesh

Vineeta Dawar\* Dr. Pramod Pandit\*\*

\*Research Scholar, Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

\*\* HOD (Chemistry) Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

**Abstract:** In recent years, there has been a growing focus on indigenous plants that have been traditionally used by local communities for the treatment of various ailments. In the Nimad region of Madhya Pradesh, India, respiratory diseases are a significant health concern, particularly among rural populations (Prakash 2024). The use of medicinal plants by indigenous communities in the Nimad region of Madhya Pradesh (M.P.), India (Figure 1.1), represents a longstanding tradition deeply rooted in cultural heritage and practical healthcare solutions.

This research study documents the medicinal uses and local names of eight native plants that are commonly used by folk healers. The plants were collected, dried and ground into powder for phytochemical and antimicrobial analysis. The study focused on preliminary phytochemical screening and spectroscopic analysis of these plants that are used in both Monoherbal and polyherbal formulations to treat respiratory disorders.

**Keywords:** Indigenous Plants, Respiratory Health, Nimar region.

**Introduction** - In rural and tribal regions, where access to modern healthcare facilities is scarce, traditional medicine plays a vital role in meeting the healthcare needs of communities. These areas, rich in natural biodiversity, rely heavily on local healers and ethnobotanical knowledge passed down through generations. Medicinal plants like **Neem**, **Tulsi**, and **Amla** are commonly used to treat ailments such as fevers, skin conditions, and respiratory issues. Tribal healers prepare remedies using roots, leaves, and fruits, often combined with spiritual practices.

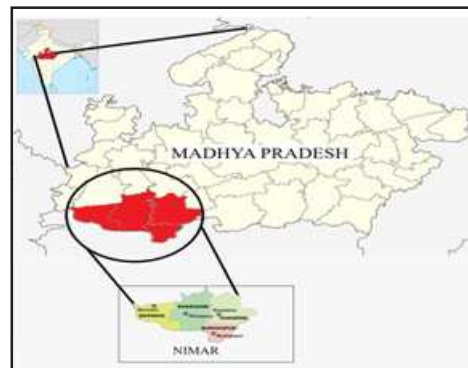
Research emphasizes the importance of medicinal plants such as aloe, ginger, turmeric and Tulsi in addressing numerous common respiratory conditions. These plants are rich in bioactive compounds, including tannins, alkaloids, sugars, terpenoids, steroids, and flavonoids, which have various therapeutic applications (Shrinet 2021; Chanda and Ramachandra 2019). Certain medicinal plants, especially *Echinacea purpurea* and *Zingiber officinale*, show promise as adjunctive treatments for respiratory disorders like chronic obstructive pulmonary disease (COPD), bronchitis, asthma, the common cold, cough, and whooping cough (Rayburn 2007).

Leaves from plants such as *Acacia torta*, *Ocimum sanctum*, *Convolvulus pluricaulis*, and *Acalypha indica* are frequently utilized for treating pneumonia, bronchitis, asthma, colds, and coughs (Firdaus *et al* 2024). The study seeks to highlight particular medicinal plants with therapeutic potential, offering valuable insights for researchers in herbal medicine (Anand *et al* 2019). These

plants may serve as innovative therapeutic agents in combating respiratory diseases (Izahet *al* 2024).

The study of physico-chemical properties of Indigenous medicinal plants for respiratory diseases is essential in understanding the therapeutic potential of these traditional remedies (Saeidyet *al* 2021). Indian medicinal plants have long been used in Ayurveda and traditional medicine to treat various ailments, including respiratory diseases. By analyzing the physico-chemical properties of these plants, researchers can identify key compounds responsible for their medicinal properties, such as antioxidants, anti-inflammatory agents, and antimicrobial substances (Sinha 2016; Shahrajabian and Sun 2023).

**Fig 1.1: Madhya Pradesh, Nimar Region**



Source: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_districts\\_of\\_Madhya\\_Pradesh](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_districts_of_Madhya_Pradesh)

**Objective of the study:** To conduct chemical study of

native plants for respiratory health of Nimar region of Madhya Pradesh.

**Material and Methods :** This section details the procedures and methodologies employed in the physico-chemical study of certain indigenous medicinal plant parts used for respiratory diseases by the tribal community of the Nimad region of Madhya Pradesh (M.P.). The objective of this study is to evaluate the chemical composition, phytochemical properties, and potential therapeutic benefits of these plants. This investigation is crucial for validating traditional medicinal practices and possibly discovering new therapeutic agents.

The study documented medicinal uses and vernacular names of eight indigenous plants commonly used by folk practitioners. The plants were collected, dried, and ground into powder for phytochemical and antimicrobial analysis. The study focused on the preliminary phytochemical screening and spectroscopic analysis of these plants, which are used in both monoherbal and polyherbal formulations to treat respiratory disorders.

This study undertook the preliminary phytochemical screening and spectroscopic analysis of these 8 plants.

**Name of Indigenous plants for respiratory health**

S.	Symbol	Plant Name	Family Name	Plant Parts
1	P <sub>1</sub>	<i>Albizialebbeck</i>	Fabaceae	Seed
2	P <sub>2</sub>	<i>Curcuma amada</i>	Zingiberaceae	Rhizome
3	P <sub>3</sub>	<i>Madhucaindica</i>	Sapotaceae	Flower
4	P <sub>4</sub>	<i>Solanum xanthocarpum</i>	Solanaceae	Berries
5	P <sub>5</sub>	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae	Leaves
6	P <sub>6</sub>	<i>Acacia nilotica</i>	Fabaceae	Bark
7	P <sub>7</sub>	<i>Ocimum sanctum</i>	Lamiaceae	Leaves
8	P <sub>8</sub>	<i>Zingiberofficinale</i>	Zingiberaceae	Rhizome

**Results and Discussion:** The discussion interprets these results in the context of existing literature and their implications for traditional medicine and potential therapeutic applications. Herbal medicine, or ethnomedicine, is a traditional healing practice used by indigenous people to treat human and animal illnesses. It integrates cultural perspectives on health and illness and is increasingly important due to antibiotic resistance. Phytochemicals from plants are used in ethnopharmacology to treat plant-based illnesses, but their chemical compositions are still unknown.

Analysis of the plant used in respiratory disorders revealed the presence of phytoconstituents including n-Hexadecanoic acid, 9,12-Octadecadienoic acid, Phthalic acid, bis(2-pentyl) ester, Hentriacontane, 17-Pentatriacontene, Vitamin E, Campesterol, Tetradecane, (Z,Z)-9-Hexadecenoic acid, 9-octadecenyl ester, Tetrapentacontane, 1,54-dibromo,  $\alpha$ -Curcumene,  $\beta$ -Curcumene, Camphor, Curzerenone, 1,8-Cineole, Curcumin, Demethoxy Curcumin, Bis-Demethoxy Curcumin, Caffeic Acid, Ferulic Acid, Ethane, 1,2-bis[(4-amino-3-furazanyl)oxy]-, 1,3-Cyclopentenedione, 5-

Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 1,2-Cyclohexanedione, Ethanone, 1-(6-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl)-, 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, Propanoic acid, 2-oxo-, 1-(Methylencyclopropyl)-ethanol, 2,2,6-Trimethyl-3,5-heptanedione, 1-Pyrrolid-2-one, N-carboxyhydrazide, Hexanoic acid, ethyl ester, Dodecanoic acid, (1R,3R,4R,5R)-(-)-Quinic acid, Tetradecanoic acid, 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, n-Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid, ethyl ester, Phytol, 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-, 2-Propanone, 1-hydroxy-, Propargyl alcohol, Furfuryl alcohol, 2,3-Dihydro-2,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one, Cyclohexasiloxane, dodecamethyl-, 4-Vinylguaiacol, Bicyclo[5.2.0]nonane, 2-methylene-4,8,8-trimethyl, Germacrene-D, 4-Epi-cubedol, Caryophyllene oxide, Oct-2-ynoic acid, Bergamotol, Z-Alpha-Trans, Neophytadiene, Octadecanoic acid, 1,E-6,Z-11-Hexadecatriene, 9,12-Octadecadienoyl chloride, (Z,Z)-, 9-Octadecenamamide, 12-Hydroxy-9-Octadecenoic acid (Ricinolic acid), Stigmast-5-En-3-ol, Oleate, Stigmast-5-En-3-ol, (3.Beta.)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl, Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)-, [1S-(1.alpha.,2.beta.,4.beta.)], 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E), decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-, [4aR-(4a.alpha.,7.alpha.)], 1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa[e]azulene-4,7-diol, Neophytadiene, Ethyl 9-hexadecenoate, Dotriacontane, 1-iodo-, Tetrapentacontane, Hexatriacontane,  $\alpha$ -Pinene, Camphene,  $\beta$ -Pinene, 1-Phellandrene, 1,8-Cineol, Z-Citral, E-Citral, Ar-Curcumene, Zingiberene,  $\alpha$ -Farnesene, attributed activity like antibronchitic, antibacterial, bronchodilator, antioxidant, COX-2 inhibitor, antispasmodic, bronchotonic, antitussive, antipharyngitic candidicidal, antiviral, anticancer (lung), anticystic antibacterial, antiseptic, antiedemic, antimicrobial, analgesic and anti-inflammatory properties. In the present investigation the antimicrobial activity of benzene, acetone, chloroform, ethyl acetate and distilled water extracts of 8 (eight) plants against 6 (six) clinically important disease-causing microorganisms was analyzed using disk diffusion methods.

Various plant species used in treating respiratory disorders include P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Extracts from these plants demonstrated sensitivity to the pathogen *Streptococcus pneumoniae* and showed inhibitory effects against *Corynebacterium diphtheriae*. Additionally, these extracts exhibited antimicrobial activity against *Mycobacterium tuberculosis* and sensitivity to *Pseudomonas aeruginosa*. *Bordetella pertussis* also displayed antimicrobial sensitivity to extracts from Pistacia, a plant traditionally used for respiratory issues. It is concluded that *Streptococcus pneumoniae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Candida albicans*, and *Streptococcus pharyngitis* were particularly sensitive to the extracts from these respiratory disorder treatments.

Furthermore, the extracts reacted to all tested Gram-negative bacteria.

**Conclusion:** The comprehensive physico-chemical study of indigenous medicinal plant parts used for respiratory diseases by the tribal community of the Nimad region in Madhya Pradesh (M.P.) has yielded significant insights into the traditional medicinal practices and the potential therapeutic properties of these plants. This research has underscored the importance of integrating traditional knowledge with modern scientific techniques to validate and potentially expand the applications of these natural remedies in contemporary medicine.

The tribal communities of Nimad, including the Bhil, Bhilala, and Barela tribes, have utilized local flora for generations to treat respiratory ailments such as asthma, bronchitis, and tuberculosis. The ethnobotanical survey conducted as part of this research provided a wealth of information on the methods of preparation, dosage, and administration of these plants, thus preserving this invaluable traditional knowledge.

Infectious agents, which are mostly transmitted by respiratory droplets expelled while coughing, sneezing, talking, singing, or physical exertion, play a critical role in the research of respiratory disorders. The danger of transmission is greatly increased by crowded environments and close closeness. The common pathogens that cause respiratory infections include adenoviruses, rhinoviruses, and human coronaviruses. Bacteria like Mycobacterium TB and Streptococcus pneumoniae also play a significant role. Vulnerable groups, such as the elderly, young children, and those with long-term medical issues, are disproportionately affected by these illnesses.

A wide variety of secondary metabolites with distinct solubility profiles were identified by phytochemical investigations of these plants. Potential therapeutic uses and the choice of suitable extraction techniques are informed by this variety in solubility, which ranges from wide to selective. Flavonoids, tannins, alkaloids, and steroids are among the important substances that have been found; each has unique solubility properties that affect their potential as therapeutic agents.

#### References:-

1. Abate, L., Bachheti, R. K., Tadesse, M. G., & Bachheti, A. (2022). Ethnobotanical uses, chemical constituents, and application of Plantagolanceolata L. *Journal of Chemistry*, 2022(1), 1532031.
2. Ahmad, I., Zahin, M., Aqil, F., Hasan, S., Khan, M. S. A., & Owais, M. (2008). Bioactive compounds from Punicagranatum, Curcuma longa and Zingiberofficinale and their therapeutic potential. *Drugs of the Future*, 33(4), 329.
3. Ahmed, D., Kumar, V., Verma, A., Gupta, P.S., Kumar, H., Dhingra, V., Mishra, V. and Sharma, M., 2014. Antidiabetic, renal/hepatic/pancreas/cardiac protective and antioxidant potential of methanol/dichloromethane extract of Albizzia LebbeckBenth. stem bark (ALEx) on streptozotocin induced diabetic rats. *BMC complementary and alternative medicine*, 14, pp.1-17.
4. Ahmed, M. U. (2019). Isolation of marker compounds from the leaves of adhatodavasica and their biological activities.
5. Akbar, S., & Akbar, S. (2020). Justiciaadhatoda L.(Acanthaceae) (Syns.: AdhatodavasicaNees.; A. pubescensMoench.; A. zeylanicaMedik.; Diantheralati-foliaSalisb). *Handbook of 200 Medicinal Plants: A Comprehensive Review of Their Traditional Medical Uses and Scientific Justifications*, 1059-1066.
6. Bhadra, P., & Sethi, L. (2020). A review paper on the Tulsi plant (Ocimum sanctum). *Indian Journal of Natural Sciences*, 10(60), 20854-20860.
7. Bhargava, S. (1986). Estrogenic and postcoitalanti conceptive activity in rats of butin isolated from Buetamonosperma Seed, *J Ethnopharmacol*, 1: 95-101.
8. Bhat, S. G. (2021). Medicinal plants and its pharmacological values. *Natural medicinal plants*, 12, 217-228.
9. Bhowmik, D., Tripathi, K. K., Chandira, M. R., & Kumar, K. P. (2010). Zingiberofficinale the herbal and traditional medicine and its therapeutically importance. *Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 2(2), 102-110.
10. Jain, J. B., Kumane, S. C., & Bhattacharya, S. (2006). Medicinal flora of Madhya Pradesh and Chattisgarh—a review.
11. Jamshidi-Kia, F., Lorigooini, Z., & Amini-Khoei, H. (2017). Medicinal plants: Past history and future perspective. *Journal of herbmed pharmacology*, 7(1), 1-7.
12. Sinha, R. (2016). *A Pharmaceutico-Analytical Study of TriphalaMasi and its Anti-Microbial Activity* (Doctoral dissertation, Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India)).
13. Sobia, H. N., Khan, S., & Nadeem, F. (2018). Use ofmalabar nut (Justiciaadhatoda L.) from traditional medicine to current pharmacopeia—A review study. *Int J ChemBiochem Sci*, 13, 46-51.
14. Zhukovets, T., & Özcan, M. M. (2020). A review: composition, use and bioactive properties of ginger (Zingiberofficinale L.) rhizoms. *J. Agroaliment. Proc. Technol*, 26, 216.
15. Zia-Ul-Haq, M., Ahmad, S., Qayum, M., & Erciöli, S. (2013). Compositional studies and antioxidant potential of Albizialebbeck (L.) Benth. Pods and seeds. *Turkish journal of Biology*, 37(1), 25-32.

## Culture of Madhya Pradesh : GOND TRIBAL ART

Dr. Vandana Sharma\*

\*Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

**Abstract :** The tribal community is a symbolic of a country's culture and its values. The gond is the only tribe that has a presence in all the district of Madhya Pradesh. The Gond tribe, one of the India's largest tribal communities is of around four million people spread all over Central India. Gonds have a recorded history of 1400 years.

Over the past few decades, gond paintings have gained global recognition. It reflects the rich culture heritage of the gond tribe from Madhya Pradesh India. The work of gond artist is rooted in the folk Tales of culture. Gond artist allow themselves the freedom to depict anything their fertile imagination creates. They believe that natural objects, mountains, lakes and animals are inhabited by a spirit of life force. The gond also have a tradition of painting the wall and floors of their huts during important Hindu festivities.

Gold art is known for its striking use of colors. The Artist also uses geometrical shapes and patterns to add motion and vitality to their work. The painting express enthusiasm and happiness with various vibrant and dynamic primary colours.

Primarily, thanks to the work of artist Jangarh Singh Shyam, for many years members of the gond tribe have continued to practice the and pass down this traditional art from through generations.

**Introduction** - Scholars believe that the word "Gond" is derived from the word "Konda" which means "the green mountains". The gond are one of the largest tribal groups in India with a population of around 13 million, who lives in the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Bihar and Odisha. The majority of their presence can be found in Madhya Pradesh.

The languages of Gond are regional such as Marathi, Odia and Hindi. Their native their native language is "Gondi".

Art of gond was traditionally done as wall paintings that originated from folk and tribal art. Lines dots and dashes are commonly used in the painting by applying bold hues like red, green, yellow and blue. Natural materials such as cow dung, colours obtained from sand, plants, leaves and flowers have been used as sources of colour traditionally para change art of gold was traditionally.

Gond art is a famous art of gond tribal community of Central India which not only include painting but also include folk dances, song and performances. It is performed in traditional way to preserve and communicate the culture of Gond tribal community.

In the 80's a group of researchers, in search of indigenous art found a relief made by a young Pradhan Gond. Jangarh Singh Shyam (1962-2001). He is he was astonished by the talent of jangarh and was persuaded to study painting and he started painting and he started painting on the paper and canvas. Besides his awn painting work

Jangarh taught the village people how to paint. This gave rise to Gond art as we know now and is flourishing as g gond artist worldwide.

**Historical Background :** Gond art is a traditional Indian tribal art form, that originated in Central India particularly in the regions of Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh.

Gond art reflects the tribe's cultural heritage mythology and connection to nature. Traditionally this art was not confined to paper or canvas but was created as wall murals on the mud walls of their homes. These murals depicted animals, trees and scenes from everyday life, often believed to bring prosperity and ward off Evil spirits.

Today gond art has gained international recognition, celebrated for its vibrant aesthetics and cultural depth. It continues to serve as a medium for story telling and reflection of the gone communities way of life. Artist uses complex shapes and patterns that represents the various components of nature. The paintings are not just an expression of nature worship but also a means of protection and presenting evil.

**Techniques :** Gond art is a traditional Indian folk-art form practiced by the gond tribe, one of the largest indigenous communities in India. Gond artists traditions utilized natural material sourced from their surroundings including plant based colours brushes made from natural fibers and surfaces such as walls, floors and clothes. However, with



modernization artists have embraced new materials such as acrylic paints canvas and papers allowing for greater experimentation in their artwork. Originating from Madhya Pradesh and neighboring states gond is characterized by intricate patterns, vivid colours and storytelling. Below are some key techniques used in Gond art.

**Texture & patterns :** Artists apply different dots to create texture and patterns that form the structure of the artwork. These dots are often used to represent elements of nature such as trees animals and people. This is the most distinctive features of Gond art.

**Geometric pattern :** Gond artists often incorporate geometrical shapes and patterns including spiritual circles and triangles to fill in spaces and add detail to the composition. Use of both straight and curved lines are used to define shapes and outlines outline various figures. The lines the lines are sometimes thick bold and geometric but they can also be delicate for also so be delicate forming patterns within the artwork. These patterns help create a rhythm and flow in the artwork.

**Colours :** Gond art is known for its textural contrast and bright vibrant colour palette. Artist traditionally uses natural pigments such as white, yellow, red and green to create contrast. Modern artist may use synthetic paints but the emphasis is always be bold contrasting colours.

**Contrast :** Gond artist often used contrasting textures such a shiny and matte surfaces. They use a combination of techniques to achieve this effect including the layering of different types of paint.

**Nature :** The subjects of Gond art represent nature including animals, birds, trees and other elements, often blending reality with fantasy. Many elements of gond art are symbolic, representing aspects of the natural world. For example, the fish might symbolize abundance or the tree could represent life and growth.

Traditionally Gond artist create their design free hand without any preliminary sketches relying on their imagination. These techniques combined with the unique artistic vision of each artist, result in the rich and dynamic art form that gond painting is known for.

**Culture :** Gond art painting is a captivating and lively form of tribal artwork that pays homage to the gond tribes culture. The gond tribe is one of the largest and oldest tribes in India, with a rich history and a unique culture. The tribe is renowned for its distinctive artistic and manufacturing techniques developed for centuries.

The gond artist utilize many natural resources including plant sap, charcoal cow dung and apply them to various surfaces such as walls, floors and many more. Through these techniques their artwork evokes atmosphere of nature and countryside living. Tribal paintings often depict scenes of nature, designs and ornamentations that reflects their culture cultural traditions. Artists use complex shapes and patterns that represents the various components of nature. The paintings are not just an expression of nature worship

but also a means of protection and preventing evil.

**Contribution In Society :** Don't art at traditional art from practice by the Gond community in India make significance significant cultural social and economical contribution to society.

**Cultural prevention:** Preventing gond art in society involves integrating it into border cultural educational and economic frameworks. Gond tribal community in India carries immense cultural significance. Preserving this art form is essential for maintaining the cultural heritage of gond people.

**Environmental awareness:** Gond art frequently defects animals trees and natural landscapes which reflect the community deep connection with the environment which case Awareness to society. It also inspires respect for nature and promotes harmony with the environment with global consciousness.

**Economic empowerment:** The commercialization of gold art has provided livelihoods for tribal artist particularly in rural communities. It also contributes to the economy, attracting tourist by Indian handicraft in international markets.

**Women empowerment :** It highlights the talent and history of indigenous communities many gold artist a woman and their participation in the art form help elevate their status and Independence within the community.

**Education impact:** Gond art introduces students and artists worldwide to the richness of tribal traditions encouraging cultural exchange.

Creative expression is a vital to healthy and open-minded society. The artist has a unique skillset to influence, inspire and help others.

Art contributes the role in the development in society. It can communicate information shape our everyday lives. In 1880's one of the known Gond artist Jangarh Singh Shyam created art on paper and Canvas. Besides his own painting work Jangarh taught the village people to paint. This gave rise to gond art as we know. His effort made him worldwide fame.

By bridging tradition and modernity gond art enriches culture diversity promotes sustainability and supports social development making it a valuable contribution to society.

#### **Suggestions:**

1. Gond tribal art represents a deep connection between the gond community and their environment beliefs and cultural traditions.
2. The gond people believe that viewing a good image brings good luck. That is why they decorate their homes and tradition, tattoos and motifs.
3. Their art often depicts nature-based themes because they believe that spirits reside in every element of nature.
4. The hypothesis can be explored through various dimensions such as connection with nature. This art frequently features animals, trees and natural elements

which reflects that tribes, respect and depend on their environment.

5. The art illustrates stories from gond mythology, emphasizing preventing cultural narratives.
6. The pattern and techniques of using dots, lines, dash and vibrant colours may be symbolic of the interconnectedness of life and the vibrant spirit of the community.
7. The hypothesis posits those functions as both a storytelling medium and spiritual practice, reflecting the tribe's values and ecological awareness.

**Conclusion:** The don't drive is the most diverse and largest tribal group in India. They have a rich heritage traditions and creativity of the indigenous Gond community. Go on ART with its integrate integrate pattern vibrant colours and deep connection to nature mythical story and daily life is rooted in a tradition traditional believe that viewing good image being good fortune.

In the modern era Gond art has progressed from traditional wall painting to Canvas and papers. With the support of government and other organizations, artist have got numerous opportunities to showcase their work on a global scale through exhibitions and trade fairs.

Lastly it can conclude that gond tribal art is a vital part of Madhya Pradesh's cultural identity preserving ancient traditions while adapting to modern contexts ensuring the

survival across generations. It serves bridge between past and present bending storytelling and artistic expression and continues to inspire both local and global audience.

Thus, it becomes a way to preserve this heritage art and promote it on international platforms.

**References:-**

1. Gupta, Sanjay-"Tribes of Madhya Pradesh (Heritage, folk culture of folk literature) Vol-10
2. Kumar Anup- "Indian Folk and tribal Art."
3. Restogi. Twinkle (2022)" Temple in Gond art of Madhya Pradesh (Gwalior) International Journal of Crative Research thought vol.10.
4. Deshmukh, Ranjit- "Folk and Triable art of India.
5. Saxena, Anupam (2018) An account of dots and lines- "The Gond Triable Art of Madhya Pradesh".
6. Mitra, Channa Subhadra- "Anthropological perspectius of India Tribes" FIRST Edition.
7. Paul, Anuradha- "The grounds" (genesis History and Culture)

**Websites:-**

1. [https://gondartindia.com>gond\\_art](https://gondartindia.com>gond_art)
2. <https://www.studio3india.com >ce...>
3. <https://en.wikipedia.org?wiki>G...>
4. [https://iaeme.com/Master Admin/journal uploads/IJFARD/VOLUME\\_2\\_ISSUE\\_1/IJFARD-02\\_01\\_001.pdf](https://iaeme.com/Master Admin/journal uploads/IJFARD/VOLUME_2_ISSUE_1/IJFARD-02_01_001.pdf)

\*\*\*\*\*

# Characteristic Studies of 2D Materials PVA Augmented by Vanadium Oxide

Shiwani Jat\* Anubha Vijay Pandya\*\*

\*Department of Chemistry, PMCoE Rajiv Gandhi Govt. P. G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

\*\* Department of Chemical Sciences, Christian Eminent College, Indore (M.P.) INDIA

**Abstract :** Blends of vanadium pentoxide ( $V_2O_5$ ) and polyvinyl alcohol (PVA) have attracted significant interest for their potential applications in electrochemical devices, sensors, batteries, and optical coatings.  $V_2O_5$ , a transition metal oxide with semiconducting and catalytic properties, enhances the thermal stability, conductivity, and mechanical strength of PVA, a flexible, water-soluble polymer. The structural and morphological characteristics of these composites are often analysed using FTIR spectroscopy. The blend exhibits strong UV-visible absorption, making it suitable for photodetectors and optical coatings.  $V_2O_5$  doping improves PVA's electrical conductivity, enabling applications in electrochemical energy storage, including lithium-ion and sodium-ion batteries, supercapacitors, and solid-state electrolytes. Additionally, PVA- $V_2O_5$  composites contribute to electrochromic devices for smart displays and windows, leveraging  $V_2O_5$ 's ability to undergo color changes under applied voltage. This study highlights the multifunctionality of PVA- $V_2O_5$  composites and their potential for next-generation energy and sensing technologies.

**Keywords**-Electrochemical devices, sensor, optical, composite, electrochromic devices.

**Introduction** - Two-dimensional (2D) materials have attracted significant research interest due to their remarkable electrical, optical, and mechanical properties, making them promising candidates for next-generation electronic, sensing, and energy-storage applications [1]. Among these materials, transition metal oxides (TMOs) such as vanadium pentoxide ( $V_2O_5$ ) are particularly noteworthy due to their ability to exist in multiple oxidation states, a result of their half-filled d-orbitals. This characteristic enhances their catalytic and electronic properties, enabling their use in applications ranging from semiconductors and photovoltaics to electrodes and environmental sensors [2-4]. However, despite their advantages, many 2D materials face challenges related to structural stability, mechanical flexibility, and processability, which limit their widespread adoption.

To address these limitations, researchers have focused on integrating TMOs with polymeric matrices to develop novel composite materials with enhanced functionality. Polyvinyl alcohol (PVA) has emerged as a suitable polymer for this purpose due to its excellent film-forming ability, mechanical flexibility, biocompatibility, and environmental friendliness. The incorporation of  $V_2O_5$  into a PVA matrix offers a unique approach to developing hybrid materials with improved conductivity, mechanical integrity, and stability while maintaining flexibility [5-7]. These PVA- $V_2O_5$  composites hold significant potential for various

applications, including electrochemical sensing, photodetection, and energy-efficient coatings [8].

Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy is a powerful analytical technique used to study the structural and chemical interactions within composite materials. In the case of PVA- $V_2O_5$  composites, FTIR spectroscopy provides crucial insights into the bonding mechanisms, phase interactions, and functional group modifications that occur during the blending process. The analysis of characteristic vibrational modes helps in understanding how  $V_2O_5$  interacts with PVA at the molecular level, influencing the material's overall properties. The study of these interactions is essential for optimizing the composite's electrical, optical, and mechanical behaviour.

Electrochemical sensors based on 2D nanomaterials have been extensively studied for detecting environmental contaminants such as heavy metals, toxic gases, organic pollutants, pesticides, and bacteria [9-11]. The incorporation of  $V_2O_5$  into PVA-based composites can enhance sensor sensitivity, selectivity, and stability, making them promising candidates for industrial safety and environmental monitoring. Additionally,  $V_2O_5$  is strong UV-absorbing properties, when combined with PVA, enable the development of advanced optical coatings and flexible photodetectors for UV-visible light detection, which can be incorporated into wearable sensors and optoelectronic devices.

Beyond sensing applications, PVA- $V_2O_5$  films exhibit potential in biomedical applications due to their antibacterial properties, making them suitable for coatings on medical devices, wound dressings, and controlled drug release systems [12]. Furthermore, the integration of these composites into flexible electronics enables their use in transparent conductive films, thin-film transistors, and electrochromic displays, where mechanical flexibility and electrical conductivity must be balanced.

The goal of the current study is to offer some information on new compounds that are expected to be easily exfoliable from a parent bulk molecule and have anisotropies that significantly outperform those of previously found 2-dimensional substances [13,14]. The findings of this study will be a comprehensive guide for future research on anisotropic response in thin crystals and will highlight opportunities and challenges for the creation of gauges based on two-dimensional materials [15,16].

This research investigates the physicochemical properties of PVA- $V_2O_5$  composites, with a particular focus on their structural, electronic, and magnetic characteristics. By utilizing FTIR spectroscopy, we aim to analyse the molecular interactions and bonding changes that contribute to the enhanced properties of these composites. Additionally, this study explores how the integration of  $V_2O_5$  with PVA can improve the electrical performance of 2D materials, contributing to advancements in high-performance electronic, optical, and sensing technologies. The findings will provide valuable insights into the design and development of novel anisotropic 2D materials and their potential applications in flexible electronics, environmental monitoring, and biomedical engineering.

**Materials and Methods:** Vanadium pentoxide ( $V_2O_5$ ), PVAc with the medium molecular weight of  $86.09 \text{ g mol}^{-1}$ , were obtained from Merck Chemical Co. (Germany). Sodium hydroxide (NaOH), Hydrochloric Acid (HCl), was acquired from Sigma-Aldrich (Germany). Ethanol and distilled water were attained from local market.

**Preparation of Poly Vinyl Alcohol solution:** Exactly 1 gm of Polyvinyl acetate (PVAc) is dissolved in a mixture of ethyl alcohol and distilled water around 30ml. The temperature has been maintained at around  $60-80^\circ\text{C}$  to ensure proper dissolution. The solution stirred continuously to achieve a homogeneous mixture. A measured amount of sodium hydroxide solution has been added to the PVAc solution. The catalyst facilitates the hydrolysis (saponification) of PVAc into PVA and acetic acid. The reaction mixture has been maintained at  $60-80^\circ\text{C}$  and stir continuously. The reaction progress monitored. Partial hydrolysis yields partially hydrolyzed PVA, while complete hydrolysis produces fully hydrolyzed PVA. Once the desired degree of hydrolysis is achieved, the reaction mixture has been neutralized by adding a weak acid (e.g., acetic acid or hydrochloric acid). This step prevented further reaction and stabilizes the PVA solution. The PVA precipitated by

pouring the reaction mixture into a large volume of cold water. The PVA precipitate has been collected by filtration or centrifugation. The precipitate washed multiple times with water to remove residual catalysts and by-products. The washed PVA dried under in an oven at a low temperature ( $50-70^\circ\text{C}$ ) until a constant weight is achieved [17].

**Preparation of PVA- $V_2O_5$  composite:** Exactly 1g of PVA dissolved in 30 ml of distilled water. The temperature has been maintained at around  $60-80^\circ\text{C}$  to ensure proper dissolution. The solution stirred continuously to achieve homogeneous mixture. In another beaker 0.1 g of  $V_2O_5$  is dissolved in minimum quantity of  $H_2SO_4$  by continuous stirring at room temperature until orange homogenous solution was obtained. Then  $V_2O_5$  solution was added dropwise to PVA solution with continuous stirring for 2-3 hr, solution color turns to lemon green. The reaction temperature is maintained between  $60-80^\circ\text{C}$ . A black color precipitate starts to appear of PVA- $V_2O_5$  composite then later filtered with Buchner funnel using vacuum pump, washed 2-3 times with distilled water and left for complete drying in air for 2-3 days. A black amorphous solid of PVA- $V_2O_5$  was obtained.

**Results and Discussion:** The incorporation of  $V_2O_5$  into PVA results into enhancement in several properties of polymer. The FTIR spectrum provides insights into the chemical bonding, structural changes, and interactions between PVA and  $V_2O_5$ . Additionally, FTIR spectroscopy has been employed to identify the functional groups present in the synthesized compounds.

The Table 1 shows the most characteristic bands of PVA and their respective assignment. Fig.2 shows the FTIR spectra of PVA. All major peaks related to hydroxyl group were observed. The large bands observed between  $3550$  and  $3200 \text{ cm}^{-1}$  are linked to the stretching O-H from the intermolecular and intramolecular hydrogen bonds (Fig.2). The vibrational band observed between  $2840$  &  $3000 \text{ cm}^{-1}$  refers to the stretching C-H from alkyl groups (Fig.2) and the peaks between  $1750-1735 \text{ cm}^{-1}$  (Fig.2) are due to the stretching C=O and C=O from acetate group remaining from PVA [17].

The FTIR spectra to PVA crosslinked with  $V_2O_5$  is presented in Fig.3. The reaction of the PVA with the  $V_2O_5$  results in a considerable reduction of the intensity of the O-H peaks (in Fig.3) from the composite, indicating a possible formation of acetal bridges. For instance, FTIR spectra of PVA- $V_2O_5$  samples (Fig.3) reveal bands at ( $\nu=3090-2990 \text{ cm}^{-1}$ ) signifies the C-H stretching, (Fig.3) a duplet absorption with peaks attributed to the alkyl chain. Also, strong band from carbonyl group was verified (C=O at  $\nu=1677-1685 \text{ cm}^{-1}$ ). These bands are overlapping and broadening PVA bands in these regions. In addition to that, by crosslinking PVA with  $V_2O_5$ , the O-H stretching vibration peak ( $\nu=3250-3450 \text{ cm}^{-1}$ ) was relatively decreased when compared to pure PVA. Stretching vibration peak ( $\nu=1143 \text{ cm}^{-1}$ ) for C-O crystallinity. C-O-C stretching vibration peak

( $\nu=1038-1073\text{ cm}^{-1}$ ) which remained almost constant.  $\text{CH}_2$  Bending vibration peak ( $\delta=1384\text{ cm}^{-1}$ ) which is constant. Polymer composite show the same pattern with additional stretching bands at ( $\nu=400-600\text{ cm}^{-1}$ ) which is due to  $\text{V}_2\text{O}_5$  vibrations [18]. It is apparent from the fig.3 that the intensity of peaks is getting decrease with addition of  $\text{V}_2\text{O}_5$ . It is due to the compatibility of  $\text{V}_2\text{O}_5$  with polymer.

Figure 1. FTIR spectra of  $\text{V}_2\text{O}_5$

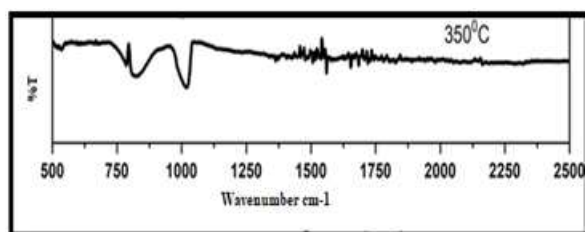


Figure 2. FTIR spectra of PVA

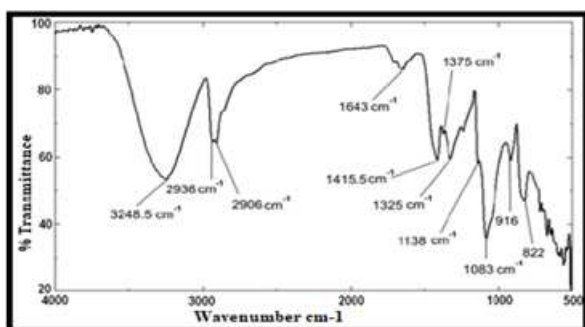


Figure 3. FTIR Spectra of PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  (Original)

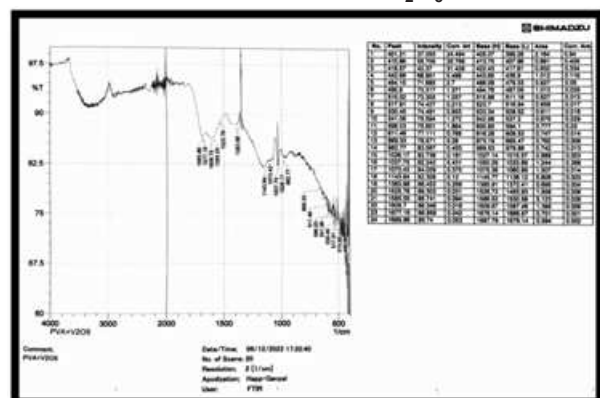


Table 1: FTIR of PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  (extracted)

No.	Peak	Intensity	Corr. Int
1	401.21	37.055	24.494
2	410.86	55.705	25.768
3	418.57	42.37	31.428
4	442.68	66.951	5.488
5	484.15	71.685	2.7
6	490.9	73.317	1.371
7	515.02	73.305	1.037
8	517.91	74.427	0.213
9	530.45	74.491	0.853
10	541.06	75.594	1.272
11	596.03	75.601	1.864

12	611.46	77.111	0.769
13	669.33	79.571	0.28
14	982.77	83.587	0.453
15	1026.17	82.738	0.181
16	1037.75	82.242	5.431
17	1073.43	84.029	0.375
18	1143.84	82.308	0.12
19	1363.98	88.453	0.259
20	1525.76	89.303	0.131
21	1585.65	87.741	0.094
22	1609.87	86.346	0.08
23	1677.18	86.859	0.042
24	1685.86	86.74	0.053

**Conclusion and Future Scope:** The incorporation of vanadium pentoxide ( $\text{V}_2\text{O}_5$ ) into polyvinyl alcohol (PVA) matrices results in multifunctional composite materials with enhanced mechanical strength, thermal stability, and electrical conductivity. These composites exhibit significant potential for various applications, including electrochromic smart windows, energy-efficient coatings, flexible photodetectors, and biomedical coatings. The PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  films also demonstrate high sensitivity to environmental gases such as humidity, ammonia ( $\text{NH}_3$ ), and nitrogen dioxide ( $\text{NO}_2$ ), making them suitable for industrial safety and environmental monitoring. Additionally, the antibacterial properties of PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  composites enable their use in wound dressings and medical device coatings, with the potential for controlled drug release applications.

FTIR spectroscopy has been instrumental in analysing the chemical interactions and bonding mechanisms within these composites, providing valuable insights for optimizing their properties. The results highlight the role of  $\text{V}_2\text{O}_5$  in significantly improving the physicochemical characteristics of PVA, where the degree of enhancement is influenced by factors such as particle size, concentration, and dispersion within the polymer matrix.

Further studies can focus on optimizing the size, concentration, and distribution of  $\text{V}_2\text{O}_5$  particles within the PVA matrix to achieve superior mechanical, optical, and electronic properties. Advanced surface modifications and functionalization techniques can be explored to enhance the compatibility of  $\text{V}_2\text{O}_5$  with PVA. Investigating the potential of PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  composites as electrode materials for supercapacitors and lithium-ion batteries. Exploring their role as solid polymer electrolytes to improve ionic conductivity and battery cycle life. Enhancing the sensitivity and selectivity of PVA- $\text{V}_2\text{O}_5$  composites for detecting toxic gases and pollutants in environmental applications. Integration into flexible and wearable sensor devices for real-time monitoring. Expanding research on the biocompatibility and antimicrobial efficiency of these composites for advanced wound healing and infection control. Studying their potential for controlled drug release in targeted therapy. Developing high-performance optical coatings, UV-blocking films, and flexible photodetectors for

wearable electronics. Investigating the potential of these composites in smart windows and electrochromic display technologies.

By addressing these research directions, the PVA- $V_2O_5$  composite system can be further refined for widespread adoption in various industrial, environmental, and biomedical applications, paving the way for next-generation functional materials.

**Conflict of Interest:** The writers have indicated that they have no conflicts of interest.

**Funding Source:** none

**Authors' Contributions :** Author-1 performed experiments and researched literature and conceived the study. Author-2 involved in protocol development. Both authors reviewed and edited the manuscript and approved the final version of the manuscript.

**Acknowledgements:** We thank our institutes for providing research facilities as well as the infrastructure and the UGC-DAE Consortium for Scientific Research (formerly known as IUC-DAEF), Indore for providing the sample characterization facilities.

#### References :-

1. Y.-G. Guo, J.-S. Hu, and L.-J. Wan, "Nanostructured materials for electrochemical energy conversion and storage devices," *Advanced Materials*, Vol.20, Issue 15, pp.2878-2887, 2008.
2. H. Cheon, Y. J. Kim, M. C. Hwang, J. Hong, T. K. An, S.-K. Kwon, and Y.-H. Kim, "Synthesis and characterization of new TPD-based copolymers and applications in bulk heterojunction solar cells," *Macromolecular Research*, Vol.26, pp.29-34, 2018.
3. Y. Liu, L. J. Duan, M. J. Kim, J.-H. Kim, and D. J. Chun, "In situ sodium alginate-hyaluronic acid hydrogel coating method for clinical applications," *Macromolecular Research*, Vol.22, pp.240-247, 2014.
4. R. Raguvaran, B. K. Manuja, M. Chopra, R. Thakur, T. Anand, A. Kalia and A. Manuja, "Sodium alginate and gum acacia hydrogels of ZnO nanoparticles show wound healing effect on fibroblast cells," *International Journal of Biological Macromolecules*, Vol.96, pp.185-191, 2017.
5. R. M. Abdel-Latif, "DC Electrical measurements on evaporated thin films of vanadium pentoxide," *Physica B: Condensed Matter*, Vol.254, Issues 3-4, pp.273-276, 1998.
6. J. Haemers, E. Baetens, and J. Vennik, "On the electrical conductivity of  $V_2O_5$  single crystals," *Physica Status Solidi A-Appl. Res.*, Vol.20, Issue 1, pp.381-386, 1973.
7. D. A. Semenenko, D. M. Itkis, E. M. Pomerantseva, E. A. Goodilin, T. L. Kulova, A. M. Skundin, and Y. D. Tretyakov, "Lix $V_2O_5$  nanobelts for high capacity lithium-ion battery cathodes," *Electrochemistry Communications*, Vol.12, Issue 9, pp.1154-1157, 2010.
8. K. Sieradzka, D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, G. Kiriakidis, E. Aperathitis, V. Kambilafka, F. Placido, and S. Song, "Structural and optical properties of vanadium oxides prepared by microwave-assisted reactive magnetron sputtering," *Optica Applicata*, Vol.41, No. 2, pp.463-469, 2011.
9. O. W. Guirguis and M. T. H. Moselhey, "Thermal and structural studies of poly (vinyl alcohol) and hydroxypropyl cellulose blends," *Natural Science*, Vol.4, No.1, pp.57-67, 2012.
10. C. Navone, J. P. Pereira-Ramos, R. Baddour-Hadjean, and R. Salot, in *Proceedings of the International Workshop "Advanced Techniques for Energy Sources Investigation and Testing"*, 4-9 Sept, Sofia, Bulgaria.
11. M. C. Rao, "Vanadium Pentoxide Cathode Material for Fabrication of All Solid-State Lithium-Ion Batteries - A Case Study," *Research Journal of Recent Sciences*, Vol.2(3), pp.67-73, 2013.
12. C. K. Chan, H. Peng, R. D. Twisten, K. Jarausch, X. F. Zhang, and Y. Cui, "Fast, completely reversible Li insertion in vanadium pentoxide nanoribbons," *Nano Letters*, Vol.7, issue 2, pp.490-495, 2007.
13. S. L. J. Ling, K. Li, F. Yao, O. Oderinde, Z. Zhang, and G. Fu, "Bio-inspired and lanthanide-induced hierarchical sodium alginate/graphene oxide composite paper with enhanced physicochemical properties," *Composites Science and Technology*, Vol.145, pp.62-70, 2017.
14. P. Zahedi, I. Rezaeian, S. H. Jafari, and Z. Karami, "Preparation and release properties of electrospun poly(vinyl alcohol)/poly([ε-caprolactone) hybrid nanofibers: Optimization of process parameters via D-optimal design method," *Macromolecular Research*, Vol.21, pp.649-659, 2013.
15. R. Y. M. Huang and J. W. Rhim, "Modification of poly (vinyl alcohol) using maleic acid and its application to the separation of acetic acid water mixtures by the pervaporation technique," *Polymer International*, Vol.30, Issue 1, pp.129-135, 1993.
16. B. Jin, J. Shen, R. Peng, Y. Shu, S. Chu, and H. Dong, "Synthesis, characterization, and thermal stability properties of PVTNP-co-PVAA through the azidoacetylation of polyvinyl 2,4,6-trinitrophenylacetal," *Macromolecular Research*, Vol.22, pp.117-123, 2014.
17. S. Jat, A. V. Pandya, "Synthesis and study of novel material using zinc oxide and PVA," *Global Journal of Engineering Science and Researches*, Vol.11, Issue 2, pp.1-6, 2024.
18. A.M. Abdelghany and H. A. ElBatal, "Optical and FTIR mapping: a new approach for structural evaluation of  $V_2O_5$ -lithium fluoroborate glasses", *Materials & Design*, Vol.89, pp.568-572, 2016.

\*\*\*\*\*

# Incubation Centers in Academic Institutions and Expectations of Students who Aspire to be Entrepreneurs

Sunder L Dindugal\*

\*Indian Institute of Management, Indore (M.P.) INDIA

**Abstract :** Governments across the world are keen on encouraging entrepreneurship and innovation. This is driven by the expectation that new and small businesses create jobs and will help in reducing unemployment. Further introduction of new products lead to increased competition in the market.

One important policy decision of the government of India is to encourage setting up of incubation centers across the country that will support and handhold nascent entrepreneurs in their entrepreneurial journey. The support provided by the government comes in various forms and the most important one is the grant provided to set up and run incubation centers. Many educational institutions have set up incubation centers and are actively trying to promote entrepreneurship.

This study explores the expectations of students with respect to the incubation centers. Data was collected from students of a course on entrepreneurship using a questionnaire in an open-ended format. Subsequently some of the students were interviewed to identify the key support expected from incubation centers. One of the interesting findings was the importance placed on mentoring support. Based on the findings, suggestions are provided on what academic institutions planning to set up incubation centers should focus on.

Considering the increasing interest in entrepreneurship among students and the support extended by central and states governments to promote entrepreneurship, insights from this study can also be used for policy decisions.

**Keywords:** Incubators, Startups, Entrepreneurs.

**Introduction -** Launching a new business is a life-changing event for an entrepreneur. Many think about becoming an entrepreneur, but not all of them take the plunge. Entrepreneurship is not easy, and it requires a lot of courage because, for many, it involves committing more resources than one has and having to deal with the risk of losing it all. It is a widely acknowledged fact that more than 70% offirst-generation entrepreneurs fail within the first three years. The high rate of failures can be attributed to any of the numerous factors that contribute to the success or failure of a new venture, like prior experience in the industry or in entrepreneurship, access to resources and the liability of newness. This highlights the need to handhold and support nascent entrepreneurs. Given the belief that new venture creation is important as it contributes to innovation and economic growth, governments across the world have been introducing policies to encourage and support entrepreneurs. One such policy initiative is providing access to funds. The government of India has categorized loans to small business as priority sector lending and this has helped many small startups in accessing funds from

commercial banks. The benefit of this categorization is that these loans have a lower interest rate and up to a certain limit, additional collateral is not required. Another important policy decision of the government is the support extended to business incubators. The government through various schemes has been providing financial support to institutions and encouraging them to establish business incubators that support startups. The table 1, below lists the numbers of incubators supported by the government of India in some of the states.

**Table 1: Number of Incubators supported by DST in various states.**

Sr.	State	No. of Incubators
1	Andhra Pradesh	5
2	Delhi	6
3	Goa	3
4	Gujarat	18
5	Haryana	1
6	Himachal Pradesh	2
7	Jammu & Kashmir	2
8	Jharkhand	1

9	Karnataka	19
10	Kerala	8
11	Madhya Pradesh	2
12	Maharashtra	19
13	Mizoram	1
14	Odisha	3
15	Punjab	9
16	Rajasthan	4
17	Tamil Nadu	26
18	Telangana	13
19	Uttar Pradesh	9
20	Uttarakhand	4
21	West Bengal	5

**Sources of data:** <https://dst.gov.in/sites/default/files/75-Impactful-Startup-DST-Incubation-Program.pdf>

**Table 2: Number of Incubators supported by Atal Incubation Centre in various states.**

Sr.	State	No. of Incubators
1	Andhra Pradesh	2
2	Assam	2
3	Chhattisgarh	1
4	Delhi	6
5	Goa	1
6	Gujarat	6
7	Haryana	1
8	Jammu & Kashmir	1
9	Karnataka	11
10	Kerala	2
11	Madhya Pradesh	3
12	Maharashtra	8
13	Pondicherry	1
14	Odisha	2
15	Punjab	1
16	Rajasthan	4
17	Sikkim	1
18	Tamil Nadu	6
19	Telangana	5
20	Uttar Pradesh	4
21	Uttarakhand	0

**Sources of data:** <https://www.nstedb.com/List-NSTEDB-TBIs.pdf>

[https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1898728#:~:text=632%20Host%20Institutes%20\(HIs\)%20have,Innovation%20Centres%20across%20the%20country.](https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1898728#:~:text=632%20Host%20Institutes%20(HIs)%20have,Innovation%20Centres%20across%20the%20country.)

**What is Business Incubation:** Sherman and Chappel (1998) state that Business Incubators are economic development tools primarily designed to help create a new business in a community. Business incubators help emerging businesses by providing various support services such as assistance in developing business & marketing plans, building management teams, obtaining capital and providing access to a range of more specialized professional services. Entrepreneur.com (nd) defines the business incubator as “an organization designed to

accelerate the growth and success of entrepreneurial companies through an array of business support resources and services that could include physical space, capital, coaching, common services, and networking connections”. Allen and McCluskey (1991) define incubators as a facility that provides affordable space, shared office services, and business development assistance in an environment conducive to new venture creation, survival, and early-stage growth. Business Incubators (BIs) provide support to new ventures with the expectation that they will develop into self-sustaining and profitable companies.

**Services offered by Incubators:** The services offered by the incubators directly affect the performance, survival rates and growth of the incubated firms (Peters and Sunderarajan 2004). During the 80’s business incubators became widespread offering office space and some support services (Bruneel et al., 2012). With time, their role expanded, and they offered other services like training, consulting, business support services and networking. Hansen et al (2000) opined that networking is the most important factor in successful BI programs, which view is also supported by others who claim that access to networks is critical for incubating companies’ growth and development. (McAdam and McAdam, 2008). A list of services offered through incubation centers are listed in table 3 below. It is important to note that it is rare for any incubator to offer all the services mentioned in the table.

**Table 3: List Of Services Offered By Incubators**

Office Space on subsidized rent	Accounting & Financial Management Assistance	Security/Technology transfer/commercialization services
Shared resource (reception, car parking, meeting rooms and commodities)	Intellectual Property Rights management	Support for R&D activities /product development
Coaching/Mentoring	Virtual services to offsite clients	Access to business and alumni networks
Training & education	Access to training room/conference room/Meeting room	Labs/Workshops
Business assistance /Advise/Consulting	Basic Utility (Water, electricity, communication, transport)	Access to Local/Regional National/International events, conferences etc.
Financial assistance Access to providers of capital (Angel Investors, Venture Capitalists).	Marketing Assistance Organizing events for networking.	Library service Stipend
PC/computer	Connect to Banks	Social Activities

**Sources of data:** Compiled from various sources and interactions with some incubators.



**Challenges faced by Incubators:** Despite the success of some business Incubators in attracting and growing startups, many incubators fail to achieve their objectives. Broadly speaking, the success of the business incubator can be determined by the ability of Incubators to (i) attract and select incubatees that have potential for success and (ii) the ability to attract and retain skilled professionals for managing the activities and functions of the incubators. However, a review of literature suggests that criteria used for measuring success differs, no standard or uniform measures of success exist.

Incubators also require resources in the form of funds and talented manpower for carrying out their activities. Lack of funding can impede the growth and success of the incubator as it impacts infrastructure creation, and the ability to attract and retain talented executives to manage the operations. As many of the services offered by the incubators are free, availability of funds is critical to the success of the incubators. In addition, incubators also require funding that can be offered to the startups as seed money support. It is therefore important that the incubators look at various sources of funding both from the private and public sectors (Thobekani, Lose. & Robertson, Tengeh., 2015). Funding for incubators can be in the form of grants, donations, funding support for targeted activities, rent and charges paid by the incubated startups etc. An important source of funding in India is the grants from the state and central governments towards running the incubator and to be offered as seed money to the startups. When an incubator offers seed money, it is normal that they take a small stake in the venture. If the ventures are successful, on exit, the incubators can expect high returns which can again be invested in other incubated entities.

Identifying, attracting, and selecting startups that are likely to make the best use of the support services and succeed is a major challenge for the incubators. In the initial years, the focus is on increasing awareness about the incubator and attracting an adequate number of applicants. Once this stage is crossed, the challenge is how to select from the available pool, the most promising applicants. It is important to understand that the business plans of the applicants are often exaggerated and do not have any hard data to support their projections. There is also the question of whether the selected venture survives because of the incubation support, or whether they would have survived even without incubation. One of the criteria used by some incubation centers is the assessment of commitment by the entrepreneur or the team towards their venture.

In this context Bergek and Norrman (2008) find that selection of incubates can be categorized in idea-focused selection and entrepreneur-focused selection, whereas Merrifield (1987) proposed a method of selection based on qualitative business attractiveness factors by rating each factor on a scale of 0–10. It is also argued that the incubate selection model must incorporate survivability prediction

because the incubate survival rate is an important measure of success of the incubator.

**Motivation for the study and identification of a gap:** As the services offered by incubators are numerous and varied, all incubators will not be able to offer all the services. The focus of most university incubators are their students and nascent entrepreneurs and therefore, it would be helpful if we can identify services that students who are aspiring to become entrepreneurs expect from an incubator. This can help the design of the structure and offerings of the incubator.

**Objectives of this study:** To identify the expectations of students who are aspiring to become entrepreneurs on what they expect from an incubator. These would be students who have shown interest in taking up a career in entrepreneurship after their graduation (probably immediately after their degree).

**Methodology:** As the study is exploratory in nature, it uses qualitative research methodology to understand the expectations of students who are aspiring to be entrepreneurs on what they would like an incubator to provide. The researcher identified students who had registered for an advanced course on entrepreneurship and requested them to participate in the study. The researcher explained the objectives of the exercise and requested them to think about the support services they would like to have from an incubator. They were asked to write down in detail their expectations and send them to the researcher. The documents were analyzed to come up with a list of the most important services a student aspirant hopes to get from an incubator. As it is an exploratory study, convenience sampling was used.

**Findings:** Five students agreed to participate in the study and sent their detailed response to the researcher. An analysis of the responses showed that the expectations of the participants in the study varied and as such, initially all the expectations were listed. Subsequently the common expectations were across identified and they were ranked based on how many of the participants expected to receive the service from the incubator. Where there was a doubt with respect to the response, the participants were contacted, and clarifications sought. The services expected by the respondents from an incubator are listed below.

Expectations of the student entrepreneurial aspirants:

- a. Funding: All the participants of the study considered Funding Support in the form of seed money or providing access to funding organizations an important service to be provided by the incubation center. While some funding from the incubator was considered desirable, they acknowledged the fact that they would have to pitch and acquire funding from external sources like government schemes, angel investors and venture capitalists.
- b. All the participants considered Mentorship as an important service to be provided by the incubator. Some

of them were very elaborate on why this was important. They said that students planning to start after graduation had zero or very low work experience and this could affect their ability to run a business. They also mentioned that the nature of activities carried out by an entrepreneur was different from that of a manager in an established organization and as such knowledge of entrepreneurial decision making was important. They suggested that mentoring from the faculty alone would not be sufficient and the mentors should also be industry experts and /or entrepreneurs from different sectors.

- c. All the participants felt that networking was important to entrepreneurial success. They were particular that the incubator should organize networking events with alumni who were working in the industry, were successful entrepreneurs or industry leaders. They suggested that these events can be organized both on a the regional and national level.
- d. Keeping in mind the lack of industrial and entrepreneurial experience, all the participants suggested that workshops, accelerator programmes etc., should be organized to help the incubatees access knowledge on challenges faced during running a business and their resolution. Some of them suggested that workshops on how to approach international markets could also be organized by the incubators.
- e. Some of the participants emphasized on the importance of the incubator developing strategic partnerships with funding organizations, local industry, other incubators so that these can be leveraged to the benefit of the incubatees.
- f. Some of the participants suggested that technology support by the way of laboratories or access to these in other institutions would be helpful. These would help in product development and prototyping.
- g. Some of the participants suggested that marketing support was critical to a nascent entrepreneur and as such connect to potential customers through the alumni network or industry contacts was important.
- h. One of them suggested that the incubator should provide for some ongoing support to the incubatees even after the end of the incubation programme.
- i. Some of the participants suggested that their business plans should be vetted by the incubator and feedback provided on how to improve them.
- j. One of the participants suggested that the university incubator should have structural mechanisms wherein the incubatee could hire student interns for marketing, product development etc.

**Additional data Collection:** Subsequently twenty candidates interested in entrepreneurship were requested to identify the top three expectations from the above list. They were provided with the above list and requested to place a tick mark against three of the above they considered

important. They were specifically told that they could put a tick only against three of the above. When the data was analyzed the top three services expected from incubators were as follows,

1. Funding support.
2. Mentoring
3. Marketing support

While some of the other listed services also were ticked by some students, the highest number of ticks were for the above three.

**Discussions and Conclusions:** Many support services are being offered by incubators across the world. The number and extent of these offerings depends on the financial strength of the incubators and their age. Some incubators are sector specific while others are sector agnostic. This study focusses on incubators set up by academic institutions. While these incubators are expected to support the entrepreneurial aspirations of their students, many of them also accept incubatees from outside. It is expected that the university incubator will leverage their faculty expertise, laboratories, workshops, and other infrastructure that is available to support the incubatees. Some educational institutions in science and technology have the advantage of huge investments in laboratories and workshops which can be used by the incubatees to develop new technological products and services. Others may have to tie up with other institutions or industry to offer these services. Management institutions can leverage their faculty expertise (both regular and visiting faculty) in mentoring incubatees on various managerial aspects of the businesses.

A review of literature suggests that understanding the needs and expectations of students who have entrepreneurial aspirations could be useful to design the offerings of the incubation center set up in academic institutions. This would facilitate a smooth transition from academics to business for these aspiring entrepreneurs. The findings of the study suggest that access to funding and mentoring are very high on the list of expectations of the students. A very interesting finding is the fact that students recognize their limitations with respect to lack of industry and entrepreneurial experience. As such they expect the incubator to offer networking opportunities to overcome these limitations. They also expect that many of the mentors would be from the industry experts or entrepreneurs from various sectors who could guide them through their entrepreneurial journey. Students also recognize the importance of knowledge, be it technological or market related, and suggest workshops and knowledge sharing sessions. The follow-up study in identifying the top three expectations showed that marketing support was also very important in addition to the funding and mentoring support.

The study provides a basic understanding of the expectations of students (who are aspiring to become

entrepreneurs) from an incubator. The findings are important because the participants of the study were those who had clearly expressed a desire to pursue a career in entrepreneurship after their graduation. This will help universities or academic institutions planning to start incubators structure their offerings in a way that meets the expectations of the aspiring entrepreneurs. This would increase the survival rate of the incubatees and the performance of the incubator. These findings can also be used by policymakers in their design of incubator support schemes, courses on entrepreneurship etc. Course on entrepreneurship can factor these expectations of the aspiring entrepreneurs.

The limitation of the study is that the sample size was small. A quantitative survey-based study with a larger number of participants can provide additional insights.

**References:-**

1. Allen, D. N., & McCluskey, R. (1991). Structure, Policy, Services, and Performance in the Business Incubator Industry. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 15(2).
2. Bergek, A., Norrman, C., (2008). Incubator best practice: a framework. *Technovation* 28 (1–2).
3. Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012). The Evolution of Business Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations. *Technovation*, 32(2).
4. Entrepreneur.com (nd). Business Incubator. Accessed at <https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-incubator>
5. Hansen, M.T., Chesbrough, H.W., Nohria, N., Sull, D.N., (2000). Networked incubators. *Harvard Business Review* 78 (5).
6. Merrifield, D.B., (1987), New Business Incubators. *Journal of Business Venturing* 2.
7. McAdam, M., McAdam, R., (2008). High tech start-ups in University Science Park incubators: the relationship between the start-up’s lifecycle progression and use of the incubator’s resources. *Technovation* 28 (5), 277–290.
8. Peters, L., Rice, M., Sundararajan, M., (2004). The role of incubators in the entrepreneurial process. *The Journal of Technology Transfer* 29 (1).
9. Sherman, H., Chappell, D.S., (1998). Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes. *Economic Development Quarterly* 12 (4).
10. Thobekani Lose and Robertson K. Tengeh (2016). An evaluation of the effectiveness of business incubation programs: a user satisfaction approach. *Investment Management and Financial Innovations*, 13(2-2).

\*\*\*\*\*

## Negative Impact of Rhesus Monkeys in some states of North India

Dr. Neha Shrivastava\* Mr. Vikas Shrivastava\*\*

\*Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

\*\* Naturalist, Kota District, Kota (Raj.) INDIA

**Abstract :** Rhesus monkeys (*Macaca mulatta*) are primates, native to forest in Northern India. The population of monkeys has grown at an alarming rate during the last decade. Rhesus monkeys have been leaving forests and are constantly migrating to urban, semi urban and rural areas. Rhesus monkeys are very aggressive and unsociable towards humans. This wild species affects the life of human beings in the forms of physical attacks, damage to livestock, property, crops, etc. This is considered as HWC-Human Wildlife Conflict. Damage to human property & harassment by the rhesus monkeys are common occurrences in various parts of India. Due to intolerable activities, a majority of residents strongly believe that these monkeys are unwanted species than a species to be conserved. There have been several strategies to solve the problem in India.

**Keywords:** Rhesus Monkey, North India, Damage.

**Introduction** - Rhesus monkeys (*Macaca mulatta*) are native to mainland Asia. Their natural habitat spans across Afghanistan, Pakistan, India, Bhutan Nepal, Bangladesh Thailand and China. There has been consistent increase in rhesus monkey population over the years in some states of North India like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Rajasthan. The rhesus monkeys are leaving forests and are constantly migrating to urban, semi urban and rural areas because of their shrinking habitat, and availability of delicious and easy food in urban areas. High levels of macaque aggressive towards humans are common in such places, leading to physical attacks and high level of stress posing risk to humans. The monkey menace is not restricted to crop raiding, biting and fear psychosis but it also includes raiding kitchens, breaking chimneys, breaking electricity bulbs, chewing internet and electric wires, bursting water pipes. City dwellers are also struggling to cope with monkey menace. According to the Primate Research Centre, Jodhpur, which is one of the three Union government-run institutes on primates, more than 1,000 cases of monkey bites are reported every day in Indian cities. 'Monkey Management' is one of the most challenging issues in North India. They have become a big nuisance. Human-monkey conflict has attained a serious problem.

**Rhesus Monkeys:** Rhesus monkeys (*Macaca mulatta*) are sand-colored primates. They are wild animals and very aggressive in nature. They are native to forest but also found coexisting with humans in northern India. They adapt to different environments; they are both arboreal and

terrestrial. They are usually medium sized monkeys at 18-22 inches in length, tail 8.27 -9 inches and 4-10 kg in weight. These wild and free ranging monkeys have life span of 25-30 years. They are found to be docile as kids but bad tempered as adults. They are omnivorous. They live in groups consists of several adults of both sexes and their young's. A social group of monkeys is made up of a few male adults, a number of females and their offsprings. They live in large families called troops. There may be 20 to 200 members in a troop. These troops are found in urban areas near human settlement, river side and forests. Their natural diet consists of fruits, seeds, roots, herbs and insects. In area of human habituation, they also eat crops and search through garbage for food.

**Population of Rhesus monkeys:** The population of rhesus monkeys has grown at an alarming rate during the last decade. According to the last count there were 50 million monkeys in India. This has resulted in their migration from the forest areas towards towns and cities and also to the cultivated areas. The rapid increase in the number of rhesus monkeys' population has led to increased competition for food & space between humans & monkeys.

**Rhesus monkey-Human Conflict:** When wild species affect the life of a human beings in the form of physical attacks, damage to livestock, property and crops, it is considered as HWC-Human Wildlife Conflict. Damage to human property & harassment by the monkeys are common features in various parts of India. It was reported by various people that they entered houses, stole food, clothing and other goods, uprooted vegetables and garden plants,

pulled on electric wires and TV antennae, threatened and attacked peoples, often causing serious bites. Rhesus monkeys are especially aggressive and unsociable towards humans. Due to their intolerable activities a majority of residents strongly consider the monkeys as unwanted species than a species of conservation. Damage and harassment caused by macaques is very common features that can be seen in many parts of India. They colonized area around the parliament and offices of the finance and defense ministries, frightening both civil servants and the public. They snatched food from people as they were walking, tore files and documents by climbing in through windows, according to the home ministry employee. Biting humans, destroying orchards crops and studding household things are the major damages caused by rhesus monkeys. Rhesus monkey learned to exploit human habitat.

**Damage of crop and biodiversity caused by Rhesus monkey:** In India rhesus monkeys cause significant damage to crops and gardens and have a part to play in economic loss. Farmers claimed 20 to 30 % damage to their crops has been caused due to monkeys. Many mango orchard owners claimed 20 to 25% annual damage to mango crops was due to these monkeys. Rhesus monkeys had been declared vermin in 93 tehsils of the state by the union ministry of forest, environment and climate in 2016. Later they were declared vermin in Shimla. The damage to the maize crop from monkey ranges from 20 to 90 %. They cause financial losses to farmers due to crop depredation. Besides of direct loss, they also cause indirect loss like feeding upon the fruiting trees and the flowers, which reduces the fruit production considerably. They cause severe threat of loss of biodiversity since they destroy biodiversity a lot. Rhesus monkeys eat tender leaves and immature leaves of plants and photosynthesis is seriously affected. They destroy the seedling of wild and cultivated plants in early stage. They pluck and uproot the plants. They eat unripe fruits of several plants therefore fruits not ripe on the trees for regeneration. Seeds and kernel of several plants are eaten up by rhesus monkeys therefore regeneration is seriously affected. They destroy the twigs and branches of trees and shrubs while jumping and playing. They eat flower buds and flowers of several plants therefore the development of fruits and seeds are seriously affected.

**Rhesus monkeys' bites and carriers of diseases :** High levels of macaque aggressive towards humans are common and cause high level of stress to humans. Sometimes people get fatally attacked by troops of monkeys hiding nearby. On an average 60 to 70 cases of monkey bites are reported monthly at two hospitals in Shimla, the Indra Gandhi Medical college and Deen Dayal Upadhyay hospital. Monkeys are carriers of rabies and other zoonotic diseases. B virus can spread from infected macaque monkeys to people and exposure can result in the transmission of the Herpes B viruses which has a 70%

mortality rate in humans if not treated immediately. Patients of rhesus monkey bites carry risk of tetanus, bacterial infection, rabies and herpes virus. The bite of rhesus can transmit Herpes virus that can cause a potentially fatal swelling of spina. In urban areas, these monkeys commonly carry viruses especially free ranging monkeys.

**Decisions on Rhesus monkeys taken by Government in North India:** During hearing of a public interest petition filed by the residents of New Friend colony in Delhi in 2000, Delhi high court banned feeding monkeys in public areas, and allowed municipal authorities to fine those who violate the directive and directed the government to round up monkeys from human habit actions and translocate them to the Asola-Bhatti wildlife Sanctuary on Delhi -Haryana border. The court also asked a special committee to explore the option of sterilization of monkeys. Rhesus monkeys has finally been declared as vermin in Himachal Pradesh. In December 2022, the center removed rhesus monkeys from schedule II of the wild life act. Stripped of the protection that comes with being labeled as an endangered species whose killing and hunting is illegal, rhesus macaques are now akin to stay cats and dogs. Himachal Pradesh has reported damage to life and property, including large scale destruction of agriculture by rhesus monkeys in areas outside forests and Central Government has considered it necessary to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the state for ensuring conservation of wild life in forest. The state Government has officially informed the high court about the urgency of the situation. The government assured the court that it would collaborate to control the monkey problem. The notification was issued on May 2024 and the monkeys will be treated as vermin for a period of one year in 38 tehsils of 10 districts of Himachal Pradesh.

**Solution of Rhesus monkey problem:** Indian authorities have tried several strategies to solve the problem of rhesus monkeys. The management practices can be followed to manage rhesus monkeys in India particularly in North India. It involves both preventive and reactive management practices.

**1. Translocation:** Translocation of monkeys to forest areas can be successful technique for their rehabilitation. In 1995–2001 in orchards in Mathura District, India, found that rhesus monkeys *Macaca mulatta* reintroduced into forest patches without resident macaques along with other interventions, remained at their release sites for at least four years. A post-translocation study in 2001 confirmed that all of the 600 monkeys captured from 12 troops and translocated to eight different forest patches, had settled, were healthy, showed no signs of stress, and behaved normally.

**2. Preventing management:** Behavioral biologists and primatologist narrate that by offering food to monkeys, we accept the dominance of monkeys. So, the monkeys start

commanding us. All primatologists are against the feeding of monkeys in public places except within permanent shelters /parks specially designed for them. In Shimla municipal limits, under section 302 of municipal corporation Act. People offer bananas, gram and bread to monkeys along the roads. This often results into traffic jams and accidents. Installing of solar fencing, electric fencing (non-lethal), monkey repellent, monkey scare guns and laser guided alarm around the field installing motion-activated sprinkler system can startle and discourage monkeys from entering gardens. Monkeys have a strong sense of smell and be repelled by certain scents. Consider using citrus peels, garlic cloves vinegar-soaked rags placed strategically around gardens to deter them.

**3. Sterilization:** Sterilization can be a better option. The work carried out by the wildlife wing of the “Himachal Pradesh Forest Department” had a major impact on the control of monkeys throughout India and can be adopted. It is easily possible for one small team to efficiently sterilize at least 60 monkeys in a day. Himachal Pradesh has sterilized at least 1.4 million monkeys since 2006 to 2018. As a result of the constant efforts put in by the forest department of HP, now the numbers of Rhesus macaques have started dwindling.



**Fig.1: encroachment of road**

**Fig.2: Destruction of biodiversity**



**Fig.3: Rhesus monkey Fig.4: Damage the crop**

**Conclusion:** Rhesus monkey are wild animals and they cannot be treated as pets. They are primates and native to

forest. They live in groups consisting of several adults of both sexes and their young ones. There has been consistent increase in population of rhesus monkey over the years. The rapid increase in the number of rhesus monkeys' population has led to increased competition for food & space between human & monkey. Destruction of habitats, overpopulation and improper disposal of wastes are major causes of human monkey conflict. In India rhesus monkeys cause significant damage to crops and gardens and therefore are responsible for economic loss in Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh Madhya Pradesh and Delhi. The magnitude of the problem is so high that farmers have formed associations to raise their voice against rhesus monkey problem. They are observed to wreak havoc in major cities of northern India. Later they were declared vermin in Shimla. 'Monkey Management' is one of the most challenging issues the forest and wildlife managers of India are facing today. Sterilization can be a better option. Translocation of monkeys to forested areas can be a successful technique for their rehabilitation.

**References:-**

1. Chakraborty, D., Borah, R.K. and Chakraborty, A. (2022). Does a divinity turn into a nuisance? Mankind-Rhesus Macaque Relationship in Assam, North East India. *Plant Health Archives*. 1(1):16-17.
2. Cauhan, A. & Pirta, R. (2010). Public Opinion regarding Human-Monkey Conflict in Shimla, Himachal Pradesh. *Journal of Human Ecology*. 30:105-109.
3. Rathi, R. and Bhatt, D. (2020) Human-monkey conflict in human dominated landscape of Naziabad Forest division Bijnor. *Indian Journal of Animal Sciences*. 90(5):788-791.
4. Reddy, A.R.M. and Chander J. (2016). Human Monkey conflict in India: Some available solutions for conflict Mitigation with special reference to Himachal Pradesh. 142(10):104-130.
5. Sharma, G., Ram, C., Lal, D. and Rajpurohit, L.C. (2011). Study of man-monkey conflict and its management in Jodhpur, Rajasthan (India). *Journal of Evolutionary Biology Research*. 3(1):1-3.
6. Shrivastava, A. (1999) *Primates of Northeast India, Bikaner Rajasthan*. Mega diversity Press, Bikaner.
7. Tomar, S. and Sikarwar, R.L.S. General Economic loss caused by Rhesus Monkey *Macaca mulatta ssp.* (2013). *National Journal of Life Sciences*. 10(2):159-163.

\*\*\*\*\*

# Effect of Over Consumption and Lack of Sugar on Human Being

Dr. Rajesh Masatkar\*

\*Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA

**Abstract:** Overconsumption of sugars on health, particularly as a risk factor for overweight, obesity or diabetes mellitus. Current guidelines recommend a daily limit of intake, and notably a restriction on added sugars. Keto diets and intermittent fasting are trending in this era of sugar mistrust. However, the metabolic benefits are not yet clearly established, and the underlying risks should restrain the prescription of these diets to a population of carefully selected patients.

**Keywords** – Obesity, Diabetes, Drains Energy, Craving.

**Introduction** - Sugar is a sweet, crystalline substance obtained primarily from sugarcane and sugar beets. It is used as a sweetener in food and beverages. Chemically, sugar refers to a group of compounds known as carbohydrates, which include glucose, fructose, and sucrose. Sugar provides a quick source of energy, but consuming too much can have health implications, such as weight gain and an increased risk of diabetes. It's important to enjoy sugar in moderation as part of a balanced diet.

**Objectives** – The main objectives are as given below.

1. To clean and detoxify an individuals' body naturally.
2. To save the individuals from side effects of sugar.
3. To make the people of the country healthy and wealthy.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economic status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment of an individual at zero level.
8. To save the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the overall health of an individuals.

**Methodology** – By observing the lifestyle of an individual.

**Symptoms** – Signs and symptoms caused by the sugar will vary depending on how much sugar eat an individual. Some general signs and symptoms associated with sugar.

1. Digestive problems.
2. Energy crashes.
3. Frequently craving sugary foods and drinks.
4. Increased headaches.
5. Increased hunger or thirst.

6. Mood swings.
7. Skin related issues
8. Sugar causes glucose levels to spike and plummet
9. Sugar accelerates aging
10. Sugar causes tooth decay
11. Sugar affects cognition in children
12. Sugar can cause gum disease, which can lead to heart disease

**Weight Gain** – Obesity rates are rising worldwide and evidence suggests that added sugar often from sugar-sweetened beverages is a major contributor to obesity. Sugar sweetened drinks like Sodas, Juices and sweet teas are loaded with fructose, a type o simple sugar. Consuming fructose increase your hunger and desire for food more than glucose, the main type of sugar found in starchy foods. Additionally, animal studies show that excessive fructose consumption may cause resistance to leptin, an important hormone that regulates hunger and tells your body to stop eating. Also, drinking a lot of sugar-sweetened beverages is linked to an increased amount of visceral fat. A kind of deep belly fat associated with conditions with diabetes and heart disease.

**Risk of Heart Disease** – Evidence suggests that high-sugar diets can lead to obesity and. inflammation as well as high triglycerides, blood sugar and blood pressure levels all of which are risk factors for heart disease. Additionally, consuming too much sugar, especially from sugar – sweetened drinks, has been linked to atherosclerosis, a disease characterized by fatty, artery clogging deposits. A study in over 25,877 adults found that individuals who consumed more added sugar had a greater risk of developing heart disease and coronary complications

compared to individuals who consumed less added sugar. Not only does increased sugar intake increase cardiovascular risk, but it can also increase risk of stroke.

**Acne**— A diet high in refined carbs, including sugary foods and drinks, has been associated with a higher risk of developing acne. Foods with a higher glycemic index, such as processed sweets, raise your blood sugar more rapidly than foods with a lower glycermic index. Consuming sugary foods can cause a spike in blood sugar and insulin levels, leading to increased androgen secretion, oil production, and inflammation all of which play a role in acne-development. Additionally, many population studies have shown that rural communities that consume traditional, non-processed foods have much lower rates of acne compared to more urban, high-income areas where processed food is part of a standard diet.

**Risk of Type 2 Diabetes** – Diabetes is a leading cause of mortality and reduced life expectancy. Its prevalence has more than doubled over the past 30 year and projection estimate its burden will continue to rise. Excessive sugar consumption has been historically associated with an increased risk of diabetes. Eating large amount of sugar can indirectly raise diabetes risk by contributing to weight gain and increased body fat both of which are risks for developing diabetes. Prolonged high sugar consumption drives resistance to insulin, a hormone produced by the pancreas that regulates blood sugar levels. A study including individuals who drank sugar beverages for over a 4-year period found that increased consumption of sugary beverages including soft drinks and 100% fruit juice is associated with a higher risk for type 2 diabetes.

**Risk of Cancer** – Eating excessive amount of sugar may increase your risk of developing certain cancers. Diets high in sugar increase inflammation in your body and may cause insulin resistance, both of which increase cancer risk. A study in over 22,720 men source spanning over 9 years found that increased sugar consumption from sugar sweetened beverage was associated with a greater risk of prostate cancer.

**Risk of Depression** – A healthy diet can help improve your mood, a diet high in added sugar and processed Foods may contribute to change in mood and emotions. It may even increase your chances of developing depression. High sugar consumption has been linked to cognitive impairments, memory problems, and emotional disorders like anxiety and depression. Researchers believe that chronic systemic inflammation, inulin resistance, and a disrupted dopaminergic reward signaling system all of which can be caused by increased sugar consumption may contribute to sugar detrimental impact on mental health.

**Accelerate the Skin Aging Process**- Wrinkles are a natural sign of skin aging. However, poor food choices can worsen wrinkles and speed up the skin aging process. Advanced glycation end products (AGEs) are compounds formed by reactions between sugar and protein in your body. They

are suspected to play a key role in skin aging. AGEs damage collagen and elastin, which are protein that help the skin stretch and keep its youthful appearance. When collagen and elastin become damaged, the skin loses its firmness and begins to sag.

**Can Increase Cellular Aging** – Telomere are structure found at the end of chromosomes, which are molecules that hold part or all of your genetic information. Telomere act as protective caps, preventing chromosomes from deteriorating or fusing together. Although the shortening of telomeres is a natural part of aging, certain lifestyle choices can speed up the process. Consuming high amounts of sugar has been shown to accelerate telomere shortening, which increases cellular aging.

**Drains your Energy** – Foods high in added sugar quickly spike blood sugar and insulin levels, leading to increased energy. Product that are loaded with sugar but lacking in protein, fiber, or fat lead to a brief energy boost that's quickly followed by a sharp drop in blood sugar, often referred to as a crash. Having constant blood sugar swings can lead to major fluctuations in energy levels. A meta-analysis examining sugar's effect on mood found that carbohydrate consumption, especially sugar, lowers alertness within 60 minutes of consumption, and increases fatigue within 30 minutes after consumption. To avoid this energy-draining cycle, choose carb sources that are low in added sugar and rich in fiber. Pairing carbs with protein or fat is another great way to keep your blood sugar and energy levels stable.

**Lead to Fatty Liver** – a high intake of fructose has been consistently linked to an increased risk of fatty liver. Unlike glucose and other types of sugar, which are taken up by many cells throughout the body, fructose is almost exclusively broken down by the liver. In the liver, fructose is converted into energy or stored as glycogen. Large amounts of added sugar in the form of fructose overload your liver, leading to nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), a condition characterized by excessive fat buildup in the liver.

**Cognitive Decline** –. Excessive added sugar intake promotes inflammation, insulin resistance and stress in the body. Over time, these things can damage neurons and disrupt communication.

**Discussion** – Overconsumption and a lack of sugar in human beings can have notable effects on health, though they exist on opposite ends of the spectrum. Here's a closer look at both sides: Excessive sugar intake can lead to a variety of health problems. **Obesity and weight gain** added sugars are calorie-dense and can contribute to weight issues. **Diabetes** constantly high blood sugar levels strain the body's ability to manage insulin. **Heart Disease** overconsumption is linked to inflammation and increased triglyceride levels. **Tooth Decay** sugary foods and drinks promote the growth of harmful bacteria in the mouth. **Energy Fluctuations** the "sugar rush" is often followed by an energy crash, affecting productivity and mood. It's a significant issue in modern diets, as sugar is hidden in many



processed foods and drinks, sometimes making it harder to control intake. On the flip side, insufficient sugar—or glucose, the body’s primary energy source—can lead to Low Blood Sugar (Hypoglycaemia) symptoms include fatigue, dizziness, confusion, and fainting. Brain function decline the brain relies heavily on glucose to function, so deprivation can impair cognitive abilities. Physical weakness without enough glucose, muscles may feel weak or fatigued, affecting daily tasks. Mood swings lack of glucose can disrupt hormonal balance, leading to irritability and anxiety. Risk for ketoacidosis (in extreme cases) prolonged glucose scarcity forces the body to break down fat for energy, producing acidic ketones that can affect overall health. A healthy diet focuses on moderating sugar intake while ensuring the body has enough glucose from natural and nutrient-rich sources like fruits, vegetables, and whole grains. It’s also worth noting that “added sugars” (such as those in sodas or candies) differ from natural sugars found in whole foods, which come bundled with fibers and nutrients that help regulate absorption.

**Findings :**

1. Maintain ideal weight.
2. Eat a healthy diet.

3. Maintain calorie intake.

**Suggestion :**

1. Avoid junk food and fast food.
2. Stop smoking and drinking.
3. Avoid excess sugar.
4. Eat natural sugar.
5. Avoid added sugar.
6. Eat alternatives of added sugar.

**Conclusion :** It is old says that “Health is Wealth”. If health is well then, all things is in our hand. But being author of this paper, I want to aware the people of our country to minimize the intake of sugar by developing healthy active lifestyle. it is advisable to pay special attention to what you eat. avoid junk food simple carb as much as possible and avoid intake of medicines for the little reason. Make a healthy routine for long time with consistently will minimize the side effect of sugar.

**References :-**

1. <https://www.healthline.com/nutrition/too-much-sugar#how-to-reduce>
2. <https://www.verywellhealth.com/what-happens-if-you-eat-too-much-sugar-8718337>

\*\*\*\*\*

# Understanding Indian Popular Literature

Pr Minu Gidwani\*

\*Asst. Professor (English) PMCoE, BKSJ Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA

## Introduction

“Literature adds to reality, it does not simply describe it.”

— C. S. Lewis

“You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.”

— Ray Bradbury

**Defining Popular Literature:** The term “popular” derives from the Latin *populus* (people), signifying works created for and consumed by the masses (Frow 23). As John Frow argues, popular literature functions as a “cultural practice” that both reflects and shapes societal values, often serving as a mirror to the anxieties and aspirations of its time (24). In the Indian context, this includes fiction and non-fiction works that prioritize broad accessibility over elitist literary conventions, straddling the tension between “high” and “low” culture (Anjaria 5).

Popular literature distinguishes itself from “high literature”—a category historically associated with experimental forms, thematic complexity, and institutional validation (Bourdieu 112). While canonical texts like Rabindranath Tagore’s *Gitanjali* emphasize artistic innovation, popular literature prioritizes immediate engagement, often through genre-driven narratives designed for commercial success (Gelder 8).

## Key Characteristics of Popular Literature

**1. Accessibility:** Popular texts employ straightforward language and linear narratives to cater to diverse audiences. For instance, ChetanBhagat’s *Five Point Someone* (2004) uses colloquial English to critique India’s education system, selling over 1.5 million copies (Amazon India). This aligns with Ken Gelder’s assertion that popular fiction “invites readers in rather than excluding them” (14).

**2. Genre Orientation:** Organized into recognizable genres (romance, thriller, fantasy), popular literature relies on familiar tropes to ensure reader comfort. The *Feluda* detective series by Satyajit Ray, modeled on Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes, exemplifies this through its formulaic mysteries (Chaudhuri 89). As John G. Cawelti notes, genre conventions act as “cultural rituals” that reinforce shared societal myths (35).

**3. Commercial Focus:** Market viability drives production, with publishers prioritizing trends like mythological retellings (e.g., Amish Tripathi’s *Shiva Trilogy*, 4 million+ copies sold) or campus romances (Bhagat, *2 States*). TabishKhair critiques this as the “commodification of storytelling,” where profit motives overshadow artistic risk (*Babu Fictions* 67).

**4. Ephemeral Nature:** Unlike high literature’s pursuit of timelessness, popular works often reflect transient cultural moments. For example, Hindi pulp fiction of the 1990s, such as Ved Prakash Sharma’s *VardiWalaGunda*, capitalized on post-liberalization urban anxieties but faded from mainstream discourse (Gupta 112).

**Debates: Literary Merit vs. Market Forces:** The tension between artistic value and commercial appeal remains central to Indian popular literature. While critics like Pankaj Mishra dismiss mass-market fiction as “intellectual fast food” (23), scholars like UlkaAnjaria argue that texts like *The White Tiger* (Adiga 2008) challenge elitist hierarchies by democratizing access to literary culture (*Reading India Now* 45). Similarly, the Progressive Writers’ Movement (1930s–50s) blended social critique with populist themes in works like Mulk Raj Anand’s *Untouchable* (1935), bridging the gap between art and activism (Rajan 78).

Popular literature serves as a vital cultural mirror, reflecting everyday experiences and aspirations while shaping collective consciousness. Unlike canonical works, it prioritizes accessibility over aesthetic complexity, offering insights into socio-political anxieties and values (Frow 45). In India, this is evident in the success of mythological retellings like Amish Tripathi’s *Shiva Trilogy* (4 million+ copies sold) and socially charged narratives such as Mulk Raj Anand’s *Untouchable* (1935), which critiques caste hierarchies (Anjaria 78; Sen 112). These works inspire film adaptations like *3 Idiots* (2009) and academic inquiries into postcolonial identity (Khair 34).

Leslie Fiedler argued that popular literature encompasses “song and story, mostly story,” forms often dismissed by academia (*What Was Literature?* 23). He critiqued their marginalization, noting their cultural ubiquity despite being “ghettoized” (27). This includes genres like

“kitchen maid romances” and oral folktales, which reflect gendered and class-based struggles yet remain excluded from syllabi (Spivak 56). For example, Tamil *kadhai* (folktales) and Bengali *kavigan* (bardic poetry) preserve subaltern voices, gaining academic traction only recently (Dharwadker 89).

Popular literature spans genres like detective fiction, spy thrillers, and mythological graphic novels. Arthur Conan Doyle’s *Sherlock Holmes* and Satyajit Ray’s *Feluda* series exemplify mystery writing’s adaptability across cultures (Gelder 67). Similarly, Ian Fleming’s *James Bond* inspired Hindi pulp novels like Ved Prakash Sharma’s *VardiWalaGunda* (Gupta 102). Contemporary forms, such as *Amar Chitra Katha* and *Terribly Tiny Tales*, blend oral traditions with digital storytelling (Natarajan 45).

Debates about artistic merit persist. Critics like Pankaj Mishra dismiss mass-market fiction as “intellectual fast food” (21), while Ken Gelder defends its role as “cultural rituals” reinforcing shared myths (*Popular Fiction* 15). In India, ChetanBhagat’s campus novels, despite simplistic prose, democratize access to English-language literature (Anjaria 112).

### Inverse Relationship between Literary Merit and Popular Literature

Popular literature attain success in market, but they are not taught in schools and colleges on the notion floated by elitist critics is that they are not worthy for serious attention and cannot be admitted into academia. These so-called guardians of “good” taste “ghettoize” certain writers even before reading their works. Even librarians “ghettostack” these books. They call them as juveniles, teenage diction and pornography. Such books are never considered for any major prize. Fiedler calls this an “untouchable category.” However, today, the borders that divide the pop from the elite are merging. Media also has a role in this.

**Literature and Media:** In the last two decades, a paradigm shift has happened for literature as other modes of representations – cinema, stage, television, comic books, etc –have promoted them. As mass public culture, art practice and vehicle of propaganda, literary adaptations on celluloid and cinema have created an extended narrative text for the audience. About 50 per cent of the films today are based on popular literature. Ian Fleming’s *James Bond* spy thrillers is an example. Film Adaptations Overview Indian cinema has a long tradition of adapting popular literature, bringing stories from books to the screen. These films often capture the essence of Indian society, from urban youth struggles in “3 Idiots” to historical epics like “Padmaavat.” They are typically in Hindi, Bengali, or other Indian languages, produced in India, and reflect the popularity of the source material through sales and cultural impact.

### Notable Examples:

1. “3 Idiots” (2009), based on ChetanBhagat’s “Five Point Someone,” sold over 7 million copies, satirizing the

education system with stars like Aamir Khan.

2. “Devdas” (2002), from Sarat Chandra Chattopadhyay’s novel, is a classic romantic tragedy, with multiple adaptations winning awards.
3. “GangubaiKathiawadi” (2022), based on S. Hussain Zaidi’s “Mumbai Fables,” explores Mumbai’s underworld, starring Alia Bhatt.
4. The White Tiger (2021, Netflix): RaminBahrani’s Oscar-nominated film adapts AravindAdiga’s 2008 Booker Prize-winning novel, exposing class struggle in modern India. The book has sold 2+ million copies worldwide.

**Popular Literature Today:** Popular literature has now got the attention of a literate reading public. For example, ChetanBhagat, the creator of campus novels, has captured the pulse of the youngsters. This is because he gives them narratives in which the youth live and survive. Some writers like Surender Mohan Pathak, who writes in Hindi, are no longer considered as trashed. They have now been the subject of literary and academic conferences and university curricula. The doyen of chick-lit, Advaita Kala and several of her kind would like to equally claim academic space within the elite corridors, but they are yet to be included. Marc Angenot in Pawling’s *Popular Fiction and Social Change* says, “Para literature occupies the space outside the literary enclosure, as a forbidden taboo, a degraded product.” Flash fiction has emerged as a significant form of literature. Ernest Hemmingway’s “For sale: Baby shoes, never worn” was applauded as a story with intense depth, gravity and minimal expressions. Today flash fiction provides a unique reading experience. The United States made significant contributions in flash fiction with Narrative and Smith magazines. In India *Terribly Tiny Tales* has been popular on social media in 2013 with **AnujGosalia**. Launched in 2016, *Mirakee* is another writing mobile application that has been a platform for flash fiction writers. It allows a writer embellish their writing in an image form. *Mirakee* has become an instrument which helps writers to explore the realm of flash fiction. In the 21st century, India saw the rise of a new kind of readers who have become an increasingly emboldened social class. **ChetanBhagat’s** *Five Point Someone* (2004), *One Night at a Call Centre* (2008) and *The 3 Mistakes of My Life* (2008) have seen commercial success. Romance and campus fiction became the two genres that gave the Indian audience a literature that was thoroughly Indian. Post 2000s, the new brigade of engineers or management graduates- turned authors held, the baton of commercial Indian fiction. **DurjoyDatta** who was not just a commercial author, but a social media person, is an example. Post 2000s, the new brigade of engineers or management graduates-turned authors held, the baton of commercial Indian fiction such as **DurjoyDatta** who was not just a commercial author, but a social media person

**The scope of Indian popular literature**, deeply rooted in **ancient oral traditions** like the *Panchatantra* (3rd century BCE) and epics such as the *Mahabharata* and *Ramayana*—

later reimagined in regional narratives like the Tamil *Kamba Ramayanam* (12th century)—has evolved dynamically since India's independence in 1947. Post-independence democratization of vernacular languages spurred growth, blending folk storytelling with modern themes, exemplified by the socially driven Progressive Writers' Movement (1930s–50s) and works like Mulk Raj Anand's *Untouchable*. The 1950s witnessed a pulp fiction boom, with magazines merging traditional motifs with contemporary issues. Globalization post-1990s liberalization amplified Western influences and English-language literature, epitomized by Arundhati Roy's *The God of Small Things* (1997), while mythological retellings like Amish Tripathi's *Shiva Trilogy* bridged ancient sagas with modern secularity. The 21st-century digital revolution democratized access further through e-books, blogs, and platforms like Wattpad and Pratilipi, alongside social media's rise in micro-stories (Instagram/Twitter poets) and diaspora voices (Jhumpa Lahiri). From folk *Pandvani* performances to Netflix adaptations (*Sacred Games*), Indian popular literature mirrors the nation's socio-cultural metamorphosis, balancing regional heritage with globalized modernity.

**Beyond the Divide: Blurring the Lines Between Pulp and Prestige:** The rigid distinctions between “popular”/ “pulp” fiction and “mainstream” literature have increasingly dissolved in contemporary literary discourse, reflecting shifting cultural, academic, and commercial paradigms. This convergence is particularly evident in India, where postcolonial identity crises, globalization, and digital democratization have reshaped literary hierarchies.

Critics argue that the academy's historical disdain for popular literature—derided as “lowbrow” or “commercial”—is waning. Leslie Fiedler's seminal essay “*Cross the Border—Close the Gap*” (1975) posited that the divide between high and low culture is artificial, urging scholars to embrace “the guilty pleasures of pulp” (Fiedler 12). This is exemplified by the inclusion of authors like Chetan Bhagat (*Five Point Someone*) in university syllabi, despite critiques of his “simplistic prose” (Khair, *Babu Fictions* 89). Similarly, Amish Tripathi's *Shiva Trilogy* (2010–2013), a mythological pulp series, is now studied alongside classical texts like the *Ramayana* in courses on Indian epics (Sen, “Mythopoeic Modernity” 45).

Postmodernism's rejection of rigid categories has enabled authors to blend literary depth with populist appeal. Salman Rushdie's *Midnight's Children* (1981), though celebrated as canonical literature, employs magical realism and pulp-style cliffhangers. Rushdie himself acknowledges borrowing from “Bollywood's melodrama and comic-book vitality” (*Imaginary Homelands* 15). Similarly, Amitav Ghosh's *Ibis Trilogy* (2008–2015) merges historical scholarship with swashbuckling adventure, a genre once dismissed as “nautical pulp” (Dharwadker 112).

The commercial success of popular fiction has pressured mainstream publishers to prioritize marketability.

Arundhati Roy's *The Ministry of Utmost Happiness* (2017), despite its experimental structure, was marketed as a “global bestseller” akin to pulp thrillers (Roy, Penguin India). Conversely, pulp authors like Durjoy Datta (*Of Course I Love You!*) now collaborate with literary festivals, signaling a bid for cultural legitimacy (Anjaria, *Reading India Now* 76). Tabish Khair critiques this as “the neoliberal commodification of storytelling,” where “literary merit is conflated with sales figures” (*The New Xenophobia* 134). Despite this blending, purists resist the trend. Pankaj Mishra laments that “the Rushdie-esque ambition to marry art and commerce has birthed a generation of writers who prioritize plot over prose” (“The Cult of the Bestseller” 21). Others, like Gayatri Chakravorty Spivak, caution against conflating accessibility with intellectual compromise, arguing that “popular forms can subvert hegemony if critically engaged” (*Death of a Discipline* 72).

**Exploring Colours of Indian Popular Literature:** Indian popular literature is a vibrant field, deeply rooted in ancient oral traditions, myths, and epics like the Mahabharata and Ramayana, which have been retold across regional languages for centuries. This literature has evolved significantly, especially post-independence in 1947, reflecting India's socio-cultural transformation. The Progressive Writer's Movement, active from the 1930s to the 1950s, emphasized socially relevant narratives, with Mulk Raj Anand's “*Untouchable*” highlighting Dalit struggles, setting a precedent for literature engaging with societal issues.

**Fiction: Best-Sellers and Cultural Resonance:** Fiction is a cornerstone of Indian popular literature, with authors like Chetan Bhagat leading the charge. His novels, such as “*Five Point Someone*” and “*The 3 Mistakes of My Life*,” have sold over 7 million copies, resonating with young urban readers (Amazon.in). Amish Tripathi's “*Shiva Trilogy*,” including “*The Immortals of Meluha*,” has sold over 4 million copies, blending mythology with fantasy, and reflecting a modern reinterpretation of ancient tales (Booksetgo.com). Arundhati Roy's “*The God of Small Things*” (1997), with over 5 million copies sold globally, won the Booker Prize, showcasing India's literary global impact.

**Poetry: From Tradition to Digital Platforms:** Poetry in India has a long history, with Rabindranath Tagore's “*Gitanjali*” earning the Nobel Prize in Literature in 1913, selling widely and influencing global literature (Nobel Prize website). Other notable poets include Nissim Ezekiel, Jayanta Mahapatra, and A.K. Ramanujan, whose works explore urban and cultural themes. While poetry sales may not match fiction, social media platforms like X have boosted visibility, with contemporary poets like Rupi Kaur (of Indian origin) selling millions of copies of “*Milk and Honey*.”

**Non-Fiction: Diverse and Impactful:** Non-fiction spans biographies, history, and self-help, with A.P.J. Abdul Kalam's “*Wings of Fire*” selling over 1 million copies, inspiring readers with his life story (Goodreads).

RamachandraGuha’s “India After Gandhi” has been critically acclaimed, offering a detailed history of post-independence India, with strong sales figures (Goodreads). Other best-sellers include S. Hussain Zaidi’s “Dongri to Dubai” and AmartyaSen’s “The Argumentative Indian,” reflecting diverse interests.

**Essays: Intellectual Discourse and Cultural Insights:**

Essays by Indian authors like Tagore, Jawaharlal Nehru, and Nirad C. Chaudhuri have shaped intellectual discourse, exploring India’s societal and political landscape. Modern essayists like ShashiTharoor and Amitav Ghosh continue this tradition, with collections addressing contemporary issues, often gaining traction through digital platforms.

**Impact of Globalization and Digital Platforms:**

Globalization has exposed Indian literature to international audiences, with authors like JhumpaLahiri (of Indian origin) gaining global acclaim for “The Namesake.” Digital platforms like Amazon Kindle and Flipkart have revolutionized access, with e-books and self-publishing through Amazon KDP enabling new voices. Social media, particularly X, has been pivotal, with authors like ChetanBhagat and PreetiShenoy using it to promote works and engage readers, enhancing visibility and sales. Platforms like Wattpad have also allowed amateur writers to gain popularity, democratizing the literary landscape.

**Table1: Top-Selling Indian Authors and Their Works**

Author	Work	Copies Sold	Genre
Chetan Bhagat	Five Point Someone	Over 7 million	Fiction
Amish Tripathi	Shiva Trilogy	Over 4 million	Fiction
Arundhati Roy	The God of Small Things	Over 5 million	Fiction
A.P.J. Abdul Kalam	Wings of Fire	Over 1 million	Non-Fiction
Ramachandra Guha	India After Gandhi	High sales	Non-Fiction

**Social Media Trends: Instagram/Facebook/ Rekhta/ KavitaKosh Poets and Micro-Fiction:**

Social media has been a game-changer, especially for poetry and short-form content. Instagram poets have gained immense popularity, using the platform to share their work and connect with global audiences. Notable examples include:

1. Rupi Kaur: An Indian-born poet based in Canada, her collection “Milk and Honey” (2014) has sold over 3 million copies worldwide, spending 77 weeks on the New York Times Best-Seller List PR Newswire. While specific sales in India are not detailed, her work resonates strongly, given her cultural roots and social media presence.
2. KarunaEzara Parikh: A poet and screenwriter, her Instagram posts explore themes like love and social issues, gaining a significant following for their emotional depth Harpers Bazaar.
3. Pavana: Known for vivid, personal poetry, her work on Instagram appeals to a broad audience, reflecting everyday experiences Vogue India.

Micro-fiction platforms have also flourished, offering concise narratives for quick consumption. Terribly Tiny Tales, launched by AnujGosalia in 2013, is India’s largest micro-fiction community, with stories limited to 140 characters. It boasts over 1.5 million weekly engagements and has published “Terribly Tiny Tales: Volume 1” with Penguin Random House India, featuring over 100 writers Terribly Tiny Tales website. Another platform, Mirakee (2016), combines text with images, enhancing visual appeal and reaching diverse audiences Homegrown.

**Facebook :**Facebook: Beyond mere promotion, Facebook has birthed literary works in India. Authors like Ira Trivedi and JeetThayil leverage their followings, but a striking example is Atul Kumar Rai, whose viral Hindi posts on everyday life evolved into a published book by Hind Yugm. This phenomenon—posts turning into books—highlights how Facebook fosters grassroots creativity, with over 100 writers credited annually for such transitions [Hindustan Times, 2017]. The platform’s 400 million+ Indian users (2023) make it a literary incubator.

**Literary Platforms: Rekhta and KavitaKosh**

**Rekhta:** Dedicated to Urdu literature, Rekhta hosts over 130,000 works by 8,000+ poets, drawing 2 million monthly visitors (2023). A surprising detail: 60% of its users are under 35, proving Urdu poetry’s appeal to youth, often non-readers of Perso-Arabic script [The Hindu, 2017]. Its Jashn-e-Rekhta festival (Delhi, 10th edition in 2024) attracts 200,000+ attendees, blending live performances with digital access. Rekhta’s e-books, like Ghalib’s collections, see 500,000+ downloads annually, reviving classics.

**KavitaKosh:** The world’s largest online Indian poetry library, KavitaKosh offers over 60,000 pages across languages like Hindi, Urdu, and Bhojpuri, with 500,000 monthly visitors reading 2 million pages (2013 data, likely higher now) [World Records India, 2013]. A salient fact: it includes folk songs from 25+ Indian dialects and translations from 40 foreign languages into Hindi, showcasing unexpected diversity. Volunteers, not professionals, built this free resource, a surprising testament to community effort since its 2006 launch by Lalit Kumar.

**Audiobooks and Podcasts: Growing Popularity:**

Audiobooks have seen a surge in India, driven by platforms catering to diverse tastes and languages. Key players include:

1. Kuku FM: Founded in 2018, it has over 1 crore listeners and 6 crore listening hours, offering audiobooks in 7 languages like Hindi, Marathi, and Tamil. It adds one new book weekly, with spiritual texts like the Bhagavad Gita available The Hindu BusinessLine.
2. Pocket FM: With 15 million monthly active listeners and over 3 billion minutes of monthly audio streaming, it covers Hindi, Bengali, and other regional languages, hosting over 12,000 stories The Hindu BusinessLine.
3. Audible: Backed by Amazon, it offers over 200,000 audiobooks and 40,000 podcasts, popular among Indian

listeners for its vast library and offline access TechRadar.

4. Storytel: A subscription-based platform with 700,000 books in its catalog, it provides access in over 30 languages, including Indian languages, for Rs.149–199 monthly Himalayan Writing Retreat.

Specific examples highlight their impact. “The Palace of Illusions” by Chitra Banerjee Divakaruni, a retelling of the Mahabharata, is noted for high listenership, with claims of over 1 million listens, though exact figures are unverified Audible. Other popular titles include Ravinder Singh’s works on Audible, reflecting the growing market for audio formats.

**Cultural and Market Impact:** These digital formats have not only increased accessibility but also fostered a new generation of writers and readers. Social media platforms like X enhance visibility, with authors like ChetanBhagat using X posts to engage fans, boosting sales and reach. ChetanBhagat’s X profile. The audiobook market, valued at Rs.739 billion in 2020, continues to grow, with platforms like Kuku FM boasting 1.5 lakh paid subscribers India Today.

**Conclusion:** Indian popular literature is a living, breathing entity that mirrors the nation’s socio-cultural evolution, from ancient oral traditions to the digital age. Rooted in epics like the *Mahabharata* and *Ramayana*, it has dynamically adapted to reflect changing times—whether through the socially charged narratives of the Progressive Writers’ Movement, the pulp fiction boom of the 1950s, or the mythological reimaginings of Amish Tripathi. Authors like ChetanBhagat (7+ million copies sold) and Arundhati Roy (Booker Prize-winning *The God of Small Things*) exemplify how popular literature bridges accessibility and artistic ambition, while digital platforms like Wattpad and Instagram democratize storytelling for a new generation. Films like *3 Idiots* and *Sacred Games* further amplify literature’s reach, proving that stories thrive when they resonate with the masses. Despite elitist critiques, Indian popular literature has carved its niche, balancing commercial success with cultural relevance. Its future lies in embracing globalization while preserving regional authenticity, ensuring it remains a mirror to India’s pluralistic soul.

**References:-**

1. Anjaria, Ulka. *Reading India Now: Contemporary Formations in Literature and Popular Culture*. Temple UP, 2019.
2. Bourdieu, Pierre. *The Field of Cultural Production*. Columbia UP, 1993.
3. Cawelti, John G. *Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*. U of Chicago P, 1976.
4. Dharwadker, Aparna. *Theatres of Independence: Drama, Theory, and Urban Performance in India Since 1947*. U of Iowa P, 2005.
5. Fiedler, Leslie. *Cross the Border—Close the Gap*. Stein and Day, 1975.
6. —. *What Was Literature? Class Culture and Mass Society*. Simon & Schuster, 1982.
7. Frow, John. *Cultural Studies and Cultural Value*. Oxford UP, 1995.
8. Gelder, Ken. *Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field*. Routledge, 2004.
9. Gupta, Charu. *Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India*. Permanent Black, 2001.
10. Khair, Tabish. *Babu Fictions: Alienation in Contemporary Indian English Novels*. Oxford UP, 2001.
11. Mishra, Pankaj. “The Cult of the Bestseller.” *The New York Review of Books*, vol. 55, no. 2, 2008, pp. 19–22.
12. Natarajan, Srividya. *Dalit Pulp: Print Capitalism and New Marginalities in India*. Oxford UP, 2021.
13. Roy, Arundhati. *The Ministry of Utmost Happiness*. Penguin India, 2017.
14. Sen, Sankar. *Mythopoeic Modernity: Postcolonial Reimaginings in Indian Popular Fiction*. HarperCollins, 2019.
15. Spivak, GayatriChakravorty. *Death of a Discipline*. Columbia UP, 2003.
16. —. *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*. Routledge, 1988.

\*\*\*\*\*

## Exploration of Indian Medicinal Plant i.e, *Uraria Picta* in term of their extraction and processing for pharmacological and toxicological studies

Mahesh Kumar Ahirwar\* Asha Verma\*\* Santosh Ambhore\*\*\* Laxmi Bareliya\*\*\*\*

\*Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\* Professor (Chemistry) Govt. Shyama Prasad Mukherjee Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\*\* Asst. Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

\*\*\*\* Asst. Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

**Abstract:** *Uraria picta* is a woody herb found throughout Asia, Africa and Australia. It has been long known to possess significant ethno-medicinal value. It is a key ingredient of more than a hundred Ayurvedic formulations and an important component of many patents in countries like India, China, Japan and USA. *U. picta* is commercially important and in high demand in India and Western African countries. As a consequence, *U. picta* has now been classified as a rare, bioactive and threatened species in India. Biochemical analysis of different plant parts of *U. picta* and its tissue culture has shown that it is a valuable source of several bioactive phytochemicals. In this work, relevant details on ethnobotany, bioactive compounds, pharmacology, toxicology, tissue culture and commercial applicability. The plant possesses several medicinal properties viz., anticancer, anti-inflammatory, anti-diabetic, antimicrobial, etc.

**Keywords**—ethno-medicinal , phyto-chemicals, bioactive, investigation, endangered.

### Introduction

**Geographical Distribution:** *Uraria Picta* is widely distributed throughout India .It is commonly found in dry grasslands, growing densely and producing poorly viable seeds and it also extend upto Tarai Region of the Himalayas .Apart from India it can also be found in various parts of Asia including China, Japan, Bangladesh, Pakistan, Bhutan and Nepal. The plant is also found in regions of Africa like Nigeria, Egypt, Ethiopia, Congo, South Africa, Queensland Australia and in Philippines, Malaysia.

*Uraria Picta* (Syn.doodia Picta, family- Leguminasae) is commonly called prishnaparni or pithvan plant. It is also found throughout India and almost all place in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Uttarakhand , New Delhi, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Kerala and this Bundelkhand comprises, Agra, Jhansi, Lucknow, (All in Uttar Pradesh). The study sitewise regularly visited to collect the plant sample. The whole plant *Uraria Picta* samples were collected from the natural habitate plant sample were identified by using the available literature.

**Various therapeutic values and traditional uses of *Uraria Picta*:** It is an interdisciplinary science that connects knowledge of biology, chemistry, physics, engineering and material science. Remarkable advance are made in the field of biotechnology and nanotechnology to harness the benefit of life science, health care and industrial

biotechnology. It also have extensively been achieved for the treatment of cancer diabetes allergy, infection, inflammation.

Almost all parts of the *U. picta* have therapeutic value and used for treating fatigue, oral sores and several gynecological disorders in Indian system of medicine (Yadav et al., 2009; Bhattacharya and Datta, 2010; Kale et al., 2012; Saxena et al., 2016). It has also been reported as an antidote to snake *Echis carinatus* and in fracture healing It has antiseptic, antimicrobial, acaricidal, antiulcerogenic, anti-hypodyanamic and anti-pulmonary hypertensive properties and exhibited partial vasorelaxing effect (Yadav et al., 2009; Pathak et al., 2005).

Besides use in the traditional system of medicines, it is highly exploited by the drug and pharmaceutical industries for preparation of various formulations. The quality and efficacy of herb depend on their biologically active compound rhoifolin (Apigenin-7-o-neohesperidoside) which is used as a chemical marker and the rhoifolin content considerably influenced by the environment, genotype, season, etc. (Saxena et al., 2016). Saxena et al. (2016), reported that the rhoifolin content varied from 0.039 % to 0.195 % among the aerial part of samples collected from eight places belonging to seven agro-climatic regions of the Madhya Pradesh. The highest content was found in aerial parts collected from Pandado, Sehore (0.25 %)

followed by Kapoorana, Chhindwara (0.167 %) and Pamakhedi, Khandwa (0.152 %) and lowest content in plant sample from Navali, Mandsaur (0.039 %). Prishniparni herb sold in market @ Rs. 1,500–2000/kg with frequent adulteration and substitution of *Desmodium gangeticum*. Due to high demand and indiscriminate collections from wild, the natural population of this plant is depleting day-by-day and has become rare and critically endangered species (Anand et al.,1998) and enlisted in threatened species in the red list of IUCN (Groom, 2012). WHO and modern pharmacopeia are also giving strong emphasis on quality and efficacy of medicinal plants concerning their biologically active ingredients (Saxena et al., 2016).

*Uraria picta*. (Prishnaparni) is one of the most important medicinal plants used in different traditional systems of medicines including the Ayurveda and Traditional Chinese medicine. The major use of this plant was found in the most popular Ayurvedic formulation “Dashmula” and in several many other important Ayurvedic formulations. IUCN placed this woody herb in the least concern category as per version 3.1. It has extensive therapeutic uses and pharmacological activities. Though this plant is a source of many phytochemicals, the uses are uncertain because the raw plant parts or crude extracts are being used in all formulations. Therefore, extensive investigations are necessary to focus on the identification of these phytochemicals. It is an urgent need to give special attention to collecting various aspects and more efforts are required in all areas for utilization and conservation of this valuable medicinal herb. Herein, a compilation of all information with various aspects has been presented, including the authors published work on *Uraria picta*. This review pursues attention towards biological activity, phytochemical profile, utilization, propagation and conservation of *Uraria picta*.

Traditionally various species of *Uraria Picta* are used by the in habitat of Indian country for the treatment of variety of including asthma, cough, fever, cancer, renal diseases. Several pharmacological attributes of *Uraria Picta* species such as anti oxidant , anti viral, anti bacterial , anti tumor have already been provided. In the recent years , plenty of research has been conducted to explore the phytochemical composition and pharmacological activities crude extract and isolated compounds obtained from different parts of *Uraria Picta*.

**Botanical Description:** *Uraria picta* is annual herb, stem woody at maturity, and it covered with scarce modified fine, short, straight and hooked hairs. Plant body is erect, height ranging from 0.5 to 2.0 m. Leaves are dimorphic, young leaves are simple and at maturity they are odd-pinnately compound covered with the hairs as present of stem (Figure 1). Inflorescence is of raceme type. Racemes are terminal and elongated upto 1.5 feet. The flowers are small, present in large number (35-75) on dense spike (figure 1). The inflorescence axis is pink, purple or pale lead in colour. Flowers are purple, pink or

bluish in colour. Flowers are bracteate, bracts persistent at the base and apex. Calyx is four mm long; teeth plumose much longer than the short tube. Corolla papilionaceous, sepals are 4-5 mm long. Pods are segmented with 3-6 segments, each 2-3 mm broad and 5-9 mm long, smooth, polished, folded on one another (Bhattacharya & Datta, 2010). Pods contain 2-6 seed and segments are nearly separated (Waghire et al.,2011).



**Figure 1**

**Material and Methodology:** The prepared extract of *Uraria Picta* was used to detect the presence of various compounds in the aerial part of plant to confirm the presence of nanoparticle. The available information about the traditional uses phytochemical and pharmacological properties of *Uraria Picta* was searched through web of science , google, scholar science direct and springer using english as the search language. The keywords use are *Uraria Picta* prishnaparnia traditional use, phytochemistry, bioactive substance, pharmacological activities, toxicological and other related words investigation the essential oils from 25 species of medicinal plant were tested as mycelia growth inhibitors six important pathogenic and toxinogenic fungal species (Zabka et.al.2009).

Recently develop techniques like UV, IR, NMR and ,mass spectroscopy can be used for spectral analysis and structural elucidation of the isolated biodynamic constituents. Common separation techniques like thin layer chromatography, column chromatography can be used and important biophysical technique that enable the separation, identification, purification of the components of a mixture for qualitative and quantitative analysis.

Quantitative analysis accounts for the quantity or the concentration of the phyto-chemical present in the plant sample. It's a part of the analytical chemistry, in which quantitative analysis help in the determination of the absolute or relative abundance (often expressed as a concentration) of one, several or all particular substance present in the sample. Column chromatography is a preparative technique used to purify compounds depending on their polarity. In column chromatography, a mixture of molecules is separated based on their differentials partitioning between a mobile phase and a stationary phase (Dhanalakshmi et.al. 2023).

**Morphological Characteristics :** *Uraria Picta* is a straight free between one and two meter tall. At the bottom are



wooden stems. The leaves are composed of 2-6 leaves and pinnate pares. In the vegetation phase, in the pare of leaves appear without the final sugar and honey, powdered route prishnaparni with meat soup for promotion adhesion fractured bone.

**Photochemistry, Pharmacology, Toxicology :** The plant is said to contain alkaloids steroids, terpenoids, phenols and all the which are components of plants the tannis were not in the stem and root the glycosides in the internal organs were in the roots(26). Recently flavanoid (Apigenin 7- o-neohesperido side) has been isolated from this plant (10).Pharmacological activities like antioxidant , anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-arthritis , antimicrobial, antifungal, anticancer.

A cute toxicity studies on different extract of *Uraria Picta* were conducted using albino mouse and rat models. Three different seed extract i.e. petroleum ether, ethyl acetate and alcoholic did not provoke any of toxicities during the first 24 hours and no mortality in any of the test groups was observed (Jalalpure at.al.2013)

**Conclusion:** This study t is based on the comprehensive study conducted on *U. picta*, which summarizes the botany, geographical distribution, propagation, phytochemical constituents and pharmacological properties of plant. This shows that the plant treasures a great medicinal wealth as each part of the plant reportedly has various phytochemical constituents having their respective pharmacological properties. These pharmacological properties are providing the evidence to various ethno-medicinal uses of the plant which have been in practice in many continents for centuries. Hence the whole plant plays an important area of research and developmental properties for pharmacologists and researchers. Due to its high therapeutic use and growing need, the plant is becoming rare and endangered; therefore it is necessary to create awareness of this plant to support its propagation in large numbers.

The development of modern drugs from less toxic plant products with proven medicinal properties is now being supported globally. There is no doubt that the products of this plant consecrate bright prospects as a reliable cure for various ailments.

The study of nanoparticle and flavenoid constituents and their antimicrobial properties may be an important substitution for various important drugs. *Uraria Picta* as an excellent medicinal plant with traditional bioactive ingredients such as antioxidant , anti-diabetic, anti-inflammatory, anti-arthritis , antimicrobial, antifungal, anticancer. The reported pharmacological studies indicated that this plant. These synthesis methods may be require the use of different raw material and yield reaction by using toxic products or wastes. This formulation also known as green chemistry, an environmental- friendly approach has

become a new option in chemistry.

#### References:-

1. Anand A, Lognay G, Wathélet B, Malaisse F. Micropropagation of *Uraria picta*, a medicinal plant, through axillary bud culture and callus regeneration. *In vitro Cellular and Developmental Biology- Plant*. 1998;34:136-140. DOI: 10.1007/BF02822778
2. *Antifungal effect of Pimenta dioica essential oil against dangerous pathogenic and toxinogenic fungi-* Martin Zabka, Roman Pavela, Ludmila Slezakova .*Industrial crops and products* Volume-30, Issue 09, pages 250-253, September 2009
3. AYUSH. *Agro-techniques of Selected Medicinal Plants* (Vol. 1). National Medicinal Plants Board, Government of India. 2008;211-213. ISBN 978-81-7993-154-7
4. Bhattacharya, A., & Datta, A. K. (2010) *Uraria picta: An overview. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology*, 4, 1-4.
5. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) and the CSIR-National Botanical Research Institute (NBRI) 2020-21 annual report2020-21.
6. Dhanalakshmi, K., Jaswanth, A., & Subramainan, E. Anti inflammatory Antioxidant and Antimicrobial activity of green Synthesized Silver nanoparticles from combined leaf extract-An In Vitro Approach. August 2023; DOI:10.14704/NQ.2022.20.9.NQ442697.
7. Kale, R. H., Halde, U. K., & Biyani, K. R. (2012). Protective effect of aqueous extract of *Uraria picta* on acetaminophen induced nephrotoxicity in rats. *International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences*, 3, 110-113.
8. Pathak, J.M., Krishnamurthy, R., Chandorkar, M.S., Gulkari, V., Gupta, R., 2005. Identification of high yielding geno types of Dashmool Shalparni (*Desmodium gangeticum*) drug plant and its cultivation under high density planting. *Indian J.Hortic.*62(4),378–384.
9. S.S. Jalalpure *etal "Antiarthritic activity of various extracts of Mesuaferrea Linn. SeedJ. Ethnopharmacol. (2011)"*
10. Saxena HO, Soni A, Mohammad N, Kakkar A, Singh N. HPLC analysis of rhoifolin in different plant parts of *Uraria picta*: A dashmool species. *Indian J Trop Biodivers* 2014;22:199-201.
11. Waghire, H. B., Shaikh, F. K., Jaiwal, B. V., & Pogle, D. S. (2013). Polymorphism of albumin like proteins in three species of genus *Uraria*. *International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences*, 4, 939-942.
12. Yadav, A. K., Yadav, D., Shanker, K., Verma, R. K., Saxena, A. K., & Gupta, M. M. (2009). Flavone glycoside based validated RP-LC method for quality evaluation of Prishniparni (*Uraria Picta*). *Chromatographia*, 69,653-658.

# Advancing Green Catalysis: Pioneering Innovations and Sustainable Applications in Chemistry

Dr. S.K. Udaipure\*

\*Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

**Abstract :** Green catalysis, an alternative sustainable option to replace traditional catalytic techniques has, in fact, appeared with the surging interest in green chemistry in process chemical synthesis. Unlike traditional catalytic techniques, this paper discussed the developments as well as advantages of sustainability achieved by green catalysis. The study examines the economic and environmental impacts of introducing green catalysts in the energy production, agrochemical, and pharmaceutical sectors, keeping in mind factors such as energy consumption, waste output, CO<sub>2</sub> emissions, and cost-effectiveness. The findings indicate significant sustainability gains as green catalysis is associated with less energy consumption, waste generation, and CO<sub>2</sub> emissions. Green catalysts have good recyclability and higher turnover frequency, with drastic cost savings with each cycle, at a higher start-up cost. Green catalysts further drive the economic and environmental benefits by doubling the product yields and reducing the energy consumption at the industrial scale. This study stresses the way green catalysis could be a game-changing technology, promoting more environmentally friendly chemical manufacturing and reducing the footprint of industrial processes on the environment.

**Keywords:** Green Catalysis, Traditional Catalysis, Sustainability, Pioneering Innovations, Chemistry.

**Introduction** - Chemistry has now brought revolution by finding ways through the name green catalysis. In these approaches, this concept works toward increasing the product by decreasing environmental negative impacts while eliminating the excess energy wastage through by-products as waste material, also the harmful chemical substance being utilized within catalytic procedures. This new area of catalyst improvement is supposed to maintain its economic viability, thereby simultaneously reducing the environmental impact that the older catalytic process caused.

Recently, the development of green catalyst has been accelerated because of increased demands for an industrial method being sustainable in multiple industries such as agrochemical, medicines, cleanup of contaminants, and energy creation. Due to these developments more effective and better catalysts designed which not only reduce their pollution impact but even give a strong cost advantage over others through efficient productivity and even longer catalytic life. This study aims to investigate the recent breakthroughs in green catalysis, with emphasis on its application in industrial processes, relative benefits over conventional catalytic techniques, and the possibility of future advancements in improving sustainability.

## Literature Review

**Rothenberg, G. (2017)** included every facet of catalysis. With more than 600 references, it also connected green

chemistry, industrial applications, and computational approaches. With numerous examples and practical exercises, the book was appropriate for senior undergraduate and graduate-level courses and was written with chemistry and chemical engineering students in mind. The author, who was a well-known catalysis researcher, was elected "lecturer of the year" by the chemistry students for his lucid writing and instruction. The book covered the fundamentals of catalysis and green chemistry before delving into the concepts and uses of bio catalysis, heterogeneous catalysis, and homogeneous catalysis. Industry examples that illustrated how catalysis aided in our society's pursuit of sustainable development objectives were included in each chapter. The most widely used catalysis textbook since its release in 2008 was *Catalysis: Concepts and Green Applications*. The most recent advancements in academic and industrial catalysis research were incorporated into this second edition. Based on recommendations from chemistry and chemical engineering instructors and students worldwide, it included fifty more activities.

**Nagpal, S. (2023)** intended to showcase state-of-the-art studies and significant developments in sustainable industrial technology, green chemistry, and green chemical engineering. The following were included (though not only) in the area of coverage:-Green catalysis, green solvents and reagents, atom-economy synthetic methods, and other environmentally friendly chemical syntheses and processes

were utilized.-Green energy and chemicals were made from carbon dioxide, biomass, and other renewable materials.-New technologies and materials for energy production and storage (such as fuel cells, solar cells, lithium-ion batteries, hydrogen, bio-fuels and bio energies, etc.) were developed.-Green chemical engineering methods (e.g., efficient separation procedures, energy conservation, waste reduction, materials variety, and process integration) were utilized.-Green technology contributed to environmental sustainability (e.g., pollution prevention, carbon dioxide capture, treatment of waste and hazardous chemicals, environmental redemption, etc.) For postgraduate students, academic researchers, and industry professionals who were interested in green chemistry and technologies for sustainable development, the Green Chemistry and Sustainable Technology series aimed to offer an easily accessible reference resource.

**Idoko, et al. (2024)** offered a thorough analysis of the ways in which green chemistry concepts were used in different manufacturing industries to reduce energy use and hazardous waste. The first section of the paper outlined the fundamental ideas of green chemistry and emphasized how they related to environmentally friendly industrial processes. The utilization of renewable raw materials, energy-efficient procedures, and waste reduction were highlighted as key developments in chemical engineering. The study illustrated how the use of green chemistry had greatly decreased the environmental impact of the pharmaceutical, textile, and automobile industries through in-depth case studies. The evaluation also looked at the difficulties businesses had implementing green chemistry and where the sector was headed, with a focus on how policy and regulatory frameworks might have spurred more innovation. The results indicated that although there had been progress, there was still a lot of room for improvement, particularly in terms of extending the application of green chemistry to a wider range of industries. In order to support sustainable production, this paper ended with suggestions for more study and wider use of green chemistry.

**Slimani, Y., & Hannachi, E. (2021)** explained the principles and measurements of GChem and how they affected the entire chemical life cycle, from design to removal. In order to maintain global economies and to support upcoming scientific and technological advancements in new products, less toxicological materials, highly efficient industrial processes, and renewable energy products, the chemical industry was crucial. The goal of green chemistry (GChem) was to create novel chemical products that were more efficient and contained less harmful compounds for the environment and human health. The nanotechnology instance had been taken into consideration once the key measurements and the most recent advancements in the theme had been reported inside this framework. The effects and uses of GChem were investigated, and the context provided by nanotechnology made it easier. The

transformation of the nature of technology was the goal of both disciplines' interdisciplinary innovations. Future opportunities for interdisciplinary collaborations were explored, along with the uses and implications of emerging green technologies.

## RESEARCH METHODOLOGY

**Research Design:** The research study design that has been followed is that of comparative quantitative research, where the performance comparison of traditional catalysis and green catalysis is brought about through key parameters such as energy consumption, waste generation, cost effectiveness, and environmental sustainability. This empirical data is collected through industrial-scale case studies and laboratory experiments. The objective is to evaluate the advances in sustainability, cost competitiveness, and environmental value brought about by green catalysts and further amplify their impact on fields like pharmaceuticals, agrochemicals, and energy production.

**Data Collection :** Examples of secondary sources, where the data for this study were collected, are from peer-reviewed journal papers, industry reports, and experimental research in respectable scientific databases such as ScienceDirect, Wiley Online Library, and Springer. These resources offered the empirical information related to the performance and effectiveness of traditional and eco-friendly catalysts in real industrial scenarios. The accompanying data contains comprehensive statistics on the use of energy, waste production, CO<sub>2</sub> emissions, and other factors pertinent to assessing catalytic processes as well. The accompanying vital data parameters are the emphasis of this study:

1. Energy Consumption (kWh/kg reaction)
2. Waste Generated (kg/reaction)
3. CO<sub>2</sub> Emissions (kg CO<sub>2</sub> /kg product)
4. Catalyst Cost (\$/kg)
5. Recyclability and Turnover Frequency
6. Annual Output and Energy Usage
7. CO<sub>2</sub> Emissions Reduction

**Data Analysis Techniques:** The study will use both descriptive and inferential statistical techniques in analyzing the data collected. Some of the analysis methods include:

**1. Percentage Change Calculation:** This technique is for calculating improvement in energy consumption, waste production, and CO<sub>2</sub> emission between conventional and green catalysis, which quantifies the benefits of the adoption of green catalysis technology.

**2. Comparative Analysis:** Data for both traditional and green catalysis are compared using multiple parameters for the assessment of the overall influence of green catalysts on sustainability, productivity, and cost-effectiveness.

**3. Economic Impact Assessment:** This takes the view of assessing the economic performance of green catalysts in terms of factors like the cost of the catalyst, ability to recycle, frequency of turnover, and cost per cycle. This will

effectively account for how green catalysts can reduce costs and improve efficiency.

**4. Environmental Impact Assessment:** Environmental impact is evaluated through reductions in CO<sub>2</sub> emissions and energy consumption as green catalysis highlights greener and more sustainable catalytic processes.

**Data Analysis :** The comparison of key performance indicators on traditional and green catalysis is done under the data analysis section, and the focus areas are on energy consumption, waste generation, CO<sub>2</sub> emissions, and cost efficiency. Descriptive and inferential statistical techniques are employed to evaluate the environmental and economic advantages of green catalysis.

**Table 1: Reduction of Waste and Energy**

Parameter	Traditional Catalysis	Green Catalysis	Improvement (%) [(Traditional Catalysis-Green Catalysis)/ Traditional Catalysis]×100
Energy Consumption (kWh/kg reaction)	100	65	35%
Waste Generated (kg/reaction)	3.5	2.1	40%
CO <sub>2</sub> Emissions (kgCO <sub>2</sub> /kg product)	2.8	1.4	50%

From the data in Table 1 (Reduction of Waste and Energy), the improvements in the use of green catalysis include improved energy efficiency, waste reduction, and CO<sub>2</sub> emissions compared to the traditional catalysis. In more detail, there is a decrease of 35% in energy consumption from 100 kWh/kg reaction to 65 kWh/kg reaction, meaning green catalysis will consume less energy to produce the same reaction output. In terms of waste generation, green catalysis has a reduction of 40%, which is lowering the waste from 3.5 kg per reaction to 2.1 kg per reaction. This depicts a significant advancement in the process sustainability. Secondly, the amount of CO<sub>2</sub> emitted is halved, where it decreases from 2.8 kg of CO<sub>2</sub> per kg of product to 1.4 kg, which reflects a 50% reduction in the environmental footprint. In general, such results emphasize environmental and energy efficiencies when green catalysis is integrated into industrial operations.

**Table 2: Cost and Efficiency of Catalysis**

Parameter	Traditional Catalyst	Green Catalyst	Improvement
Catalyst Cost (\$/kg)	150	200	Higher by 150(200-150) ×100=33.33%
Recyclable Cycles	1	10	1(10-1) ×100=900% increase

Cost per Cycle (\$)	150	20	150-20=130 saved per cycle
Turnover Frequency (TOF, mol/hour)	2	5	(5-2) ×100=150% increase

Cost and Efficiency of Catalysis, the comparison between the green and traditional catalysts regarding the cost efficiency and effectiveness of catalysis is reflected in table 2. The catalyst's cost for the green catalysts is at \$200 per kg compared to the traditional catalysts, priced at \$150 per kg, meaning a 33.33% increase in the former. However, that initial cost higher than the regular catalyst is overcome by a greatly improved recyclability; green catalysts can run 10 times, an unbelievable 900 percent improvement over single-use traditional catalysts. Therefore, it resulted in a reduction of the per-cycle cost-150 dollars from traditional catalyst to just 20 dollars for green catalysts, translating to a cost saving of 130 dollars in every cycle. In addition, the turnover frequency of green catalysts is much higher, at 150% more than that of traditional catalysis, from 2 mol/hour in traditional catalysis to 5 mol/hour in green catalysis. This is an improvement in TOF, which means a better catalytic efficiency, thus making green catalysts more efficient in driving reactions at higher rates.

**Table 3: Industrial Scale Impact**

Parameter	Traditional Catalyst	Green Catalyst	Improvement (%)
Annual Output (kg)	5,000	6,500	(6,500-5,000)/ 5,000 ×100=30%
Annual Energy Usage (kWh)	500,000	350,000	(500,000-350,000) / 500,000×100 =30%
CO <sub>2</sub> Emissions Reduction (tons/year)	150	75	Reduction by 50% (calculated as 150×0.5=75)

In contrast, Table 3 represents industrial scale benefits, where the difference between the yield of green catalysis and that of the old catalysis lies in 30% productivity higher with green catalysis compared with the traditional catalysis. Thus, the products amount to 5,000 kg per year versus 6,500 kg of product in case of green catalysis. Again, 30% annual reduction in energy utilization is witnessed. The value reaches 350,000 kWh/year from 500,000 kWh/year. This saves energy and hence reduces the cost and also decreases the environmental footprint. In addition, the reduction in CO<sub>2</sub> emissions is impressive at 50%, from 150 tons/year for traditional catalysis to 75 tons/year for green catalysis. This shows the huge environmental advantage of using green catalysts, especially in reducing greenhouse gas emissions.

**Conclusion:** This research has emphasized the sustainability, cost-effectiveness, and environmental

implications of green catalysis in comparison with the conventional catalytic process. In demonstrating large reductions in energy consumption, waste generation, and CO<sub>2</sub> emissions, green catalysis is considered to be more sustainable for industrial applications in several fields such as pharmaceuticals, agrochemicals, and energy production. Although the initial investment in green catalysts is much higher, the higher recyclability and turnover frequency enhance long-term savings and efficiency gains. Results of both laboratory-scale and industrial applications indicate the enormous potential of green catalysis for reducing environmental footprints while increasing productivity. This study strengthens further efforts to push into green catalysis technologies that necessitate even broader applications and therefore will propel toward more environmentally sound and less-harmful chemical processes for future times.

#### References :-

- Anastas, P. T., & Beach, E. S. (2007). Green chemistry: the emergence of a transformative framework. *Green Chemistry Letters and Reviews*, 1(1), 9-24.
- Anastas, P., & Eghbali, N. (2010). Green chemistry: principles and practice. *Chemical Society Reviews*, 39(1), 301-312.
- Beach, E. S., Cui, Z., & Anastas, P. T. (2009). Green Chemistry: A design framework for sustainability. *Energy & Environmental Science*, 2(10), 1038-1049.
- Ciriminna, R., & Pagliaro, M. (2013). Green chemistry in the fine chemicals and pharmaceutical industries. *Organic Process Research & Development*, 17(12), 1479-1484.
- Idoko, F. A., Ezeamii, G. C., & Ojochogwu, O. J. (2024). Green chemistry in manufacturing: Innovations in reducing environmental impact. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(3), 2826-2841.
- Kar, S., Sanderson, H., Roy, K., Benfenati, E., & Leszczynski, J. (2021). Green chemistry in the synthesis of pharmaceuticals. *Chemical Reviews*, 122(3), 3637-3710.
- Kartal, O. (2024). Navigating the Future of Chemistry: Priorities and Opportunities for Sustainable Innovation. *Bulletin of the LN Gumilyov Eurasian National University. Chemistry. Geography. Ecology Series*, 147(2), 61-80.
- Nagpal, S. (2023). Green Chemistry and Sustainable Technology: Pioneering a Greener Future. *Green Chemistry*, 10(6).
- Rothenberg, G. (2017). *Catalysis: concepts and green applications*. John Wiley & Sons.
- Sanghi, R., & Singh, V. (Eds.). (2012). *Green chemistry for environmental remediation*. John Wiley & Sons.
- Saranghi, P. K., Singh, A. K., Ganachari, S. V., Pengadeth, D., Gunda, M., & Aminabhavi, T. M. (2024). Biobased heterogeneous renewable catalysts: Production technologies, innovations, biodiesel applications and circular bioeconomy. *Environmental Research*, 119745.
- Shaikh, I. R. (2014). Organocatalysis: key trends in green synthetic chemistry, challenges, scope towards heterogenization, and importance from research and industrial point of view. *Journal of Catalysts*, 2014(1), 402860.
- Slimani, Y., & Hannachi, E. (2021). Green chemistry and sustainable nanotechnological developments: Principles, designs, applications, and efficiency. In *Green Polymer Chemistry and Composites* (pp. 1-18). Apple Academic Press.
- Tiwari, A. (2023). Advancement of materials to sustainable & green world. *Advanced Materials Letters*, 14(3), 2303-1724.
- Trucillo, P., & Campardelli, R. (2023). Editorial Overview of the Special Issue "Innovation in Chemical Plant Design". *Processes*, 11(10), 3023.

\*\*\*\*\*

## राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन एक अध्ययन (जोधपुर जिले के संदर्भ में)

डॉ. नीति चौहान\*

\* सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) चोपासनी महाविद्यालय, चोपासनी, जोधपुर (राज.) भारत

**शोध सारांश** – किसी भी राष्ट्र के विकास में उच्च शिक्षा अपनी अहम भूमिका अदा करती है क्योंकि व्यक्ति को उसके ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, आलोचनात्मक चिन्तन के विकास, दृष्टिकोण व कार्य करने के ढंग में उच्चता की ओर अग्रसर करती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने पर ध्यान स्वतः ही राष्ट्र की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट हो जाता है। जहां सभी नागरिक समान हैं, और सभी को अपनी योग्यतानुसार कार्य करने तथा शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारा ध्यान ऐसे वर्गों पर भी जाता है। जो किन्हीं कारणों से महत्वाकांक्षी होते हुए भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिनमें से 'बालिका' भी एक ऐसा ही वंचित वर्ग है जो चाहते हुए भी अपनी विभिन्न समस्याओं के कारण माध्यमिक शिक्षा से वंचित है। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कारणों के साथ-साथ विद्यालयों की न्यूनता अथवा दूरी, बालिका विद्यालयों की कमी/अनुपलब्धता भी माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की पहुँच में बाधक रही है। अब यद्यपि सरकारी, अनुदानित एवं गैर सरकारी विद्यालयों की बढ़ी संख्या ने विद्यालयी शिक्षा में बालिका सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। किन्तु अब भी बालिकाओं की अपेक्षित जनसंख्या माध्यमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रही है, किन्तु अब उनके समक्ष खुली-शिक्षा व्यवस्था का विकल्प आने से माध्यमिक शिक्षा में उनकी सहभागिता में सुधार नितांत अपेक्षित है। यह ज्ञातव्य है कि खुली शिक्षा-प्रणाली में समय, स्थान, आयु एवं जाति सम्बन्धी कोई सीमा नहीं रखी गई तथा उसे अधिक लचीली एवं व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है। खुली शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करने की बात की गई है जो किन्हीं व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते, अथवा बीच में ही विद्यालय त्याग कर देते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विद्यालय स्तर पर सत्र 1989 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना की गई।

**शब्द कुंजी** – सांस्कृतिक, प्रजातांत्रिक व्यवस्था।

**प्रस्तावना** – राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति के कारण शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच नहीं पाई है। यद्यपि राजस्थान की साक्षरता दर बढ़ाने, शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने और नामांकन बढ़ाने की दिशा में सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसके लिए प्रत्येक शैक्षिक स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। इस संदर्भ में लोक जुम्बिश, गुरु मित्र परियोजना, मध्याह्न पोषण कार्यक्रम, शिक्षा आपके द्वार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत भी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, राज्य के अनेक जिलों को पूर्ण साक्षर घोषित करने के बावजूद भी आज राजस्थान में शैक्षिक पिछड़ापन दृष्टिकोण होता है। विद्यार्थियों को पुनः इस धारा से जोड़ने तथा माध्यमिक स्तर पर नामांकन संख्या में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

यह एक छत्र (Umbrell) की भांति है जो सम्पूर्ण राष्ट्र में अधिक संख्या में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों के जाल के सहयोग से भारत की प्रत्येक जनशक्ति से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसके प्रमुख अधि-देश (Mandate) इस प्रकार है-

1. समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. विभिन्न स्तरों पर उच्च गुणवत्ता के नवीन और आवश्यकता आधारित

कार्यक्रम चलाना।

3. सुविधा वंचित वर्गों के लिए देश के सभी भागों में शैक्षिक कार्यक्रम वहन योग्य लगात में उपलब्ध कराना।
4. देश में दूर तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के मानकों का संवर्धन, समन्वयन और विनिमयन करना।

अधिकाधिक लोगों तक पहुँचने और सुविधाओं की समानता, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निरन्तर व्यावसायिक क्षमता का विकास तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने हेतु विविध संचार माध्यमों एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के जिलों में इसके अध्ययन केन्द्रों का जाल बिछा है जो राजस्थान के लगभग सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः इसे राजस्थान के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रति बालिका अनुक्रियाशीलता के अध्ययन का आधार बनाया जाना उपर्युक्त प्रतीत होता है।

मुक्त विद्यालयी व्यवस्था को मूल्य प्रभावी (Cost effective) बनाने के लिए बालिकाओं की अधिकतम अनुक्रियाशीलता अनिवार्य है क्योंकि देश की आय का एक बड़ा भाग इसके विभिन्न कार्यक्रमों के व्यवस्थापन एवं संचालन पर व्यय हो रहा है और यदि इसका लाभ जनसामान्य न उठाये तो

यह निवेश तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि वांछित परिणाम सामने न आये।

अतः यह जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की वैकल्पिक एवं आवश्यकता आधारित व्यवस्था उपलब्ध होने पर कितनी बालिकाएँ ऐसी हैं जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रहने पर इसका लाभ उठा रही हैं? संभवतः वे सभी बालिकाएँ जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा में अध्ययनरत नहीं हैं वे सभी इस व्यवस्था में सहयोगी होनी चाहिए। अतः प्रश्न यह भी उठता है कि मुक्त अधिगम व्यवस्था में प्रवेश लेने वाली बालिकाएँ कौन हैं? वे राजस्थान राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? उनका शैक्षिक स्तर (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) क्या है? वे किस संवर्ग की हैं? क्या केवल कतिपय जाति संवर्गों की बालिकाएँ ही इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रही हैं? अथवा वंचित वर्गों यथा- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं द्वारा भी इस लचीली एवं सुविधाप्रदायक व्यवस्था का उपयोग अपने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विकास के लिए किया जा रहा है। रक्षा संवर्ग की बालिकाएँ जिनके अधिकांश परिवारों के निवास स्थान में स्थायित्व नहीं होने के कारण क्या ये बालिकाएँ भी अपनी शैक्षिक व सामाजिक उन्नति हेतु इसके प्रति सजग हैं? शारीरिक विकलांग वर्ग की बालिकाएँ जिनके समक्ष अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ हैं क्या इस संवर्ग की बालिकाएँ भी अपने जीवन साफल्य हेतु उसके प्रति अनुक्रियाशील हैं? क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में इन सभी संवर्गों की बालिकाओं की समान अनुक्रियाशीलता है? अथवा वे अलग-अलग अनुपात में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं?

विभिन्न संवर्गों की वे बालिकाएँ जो मुक्त विद्यालयी शिक्षा में अनुक्रियाशील हैं वे किन क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं? क्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली बालिकाएँ इस व्यवस्था का समान लाभ उठा रही हैं? किन क्षेत्रों की बालिकाओं ने इस व्यवस्था के प्रति अधिक अनुक्रियाशीलता व्यक्त की है?

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में स्तरवार बालिकाओं की अनुक्रियाशीलता किस प्रकार की है? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर कितनी बालिकाएँ अधिक सहभागी हो रही हैं? दोनों ही स्तरों पर सत्रवार इनकी सहभागिता किस प्रकार की है? क्या सत्रवार उनके नामांकन में परिवर्तन परिलक्षित होता है?

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में राजस्थान राज्य के अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सत्रवार कुल नामांकन में प्रविष्ट बालिकाओं की सहभागिता कैसी है? अर्थात् इस व्यवस्था में सत्रवार कुल (बालक-बालिकाएँ) नामांकन में से कितने प्रतिशत बालिकाएँ में लाभान्वित हो रही हैं? क्या सत्रवार कुल नामांकन में बालिका नामांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है? इस मुक्त विद्यालयी व्यवस्था में सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग एवं रक्षा संवर्ग की बालिकाओं की सत्रवार कुल नामांकन में अनुक्रियाशीलता की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में नामांकित जनसंख्या में बालिकाओं का जिलेवार, स्तरवार, संवर्गवार, क्षेत्रवार एवं माध्यमवार प्रवृत्ति किस प्रकार की है? क्या जनसांख्यिकी अनुपात के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नामांकन में इनकी सहभागिता है।

इस प्रकार मुक्त राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका अनुक्रियाशीलता के संदर्भ में इन सभी प्रश्नों पर गहनता से विचार करने

की आवश्यकता प्रतीत होती है। इन प्रश्नों के साथ-साथ प्रश्न यह भी है कि मुक्त विद्यालयी शिक्षा में बालिका अनुक्रियाशीलता की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। अतः इन प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु अनुसंधात्री द्वारा अग्रान्वित विषय का शोध अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

**समस्या कथन** - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन एक अध्ययन (जोधपुर जिले के संदर्भ में)।

**अध्ययन के उद्देश्य** -

(1) जोधपुर जिले के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन (सत्र 2005-06 से सत्र 2014-15 तक) की प्रवृत्ति का निम्न संदर्भों में अध्ययन करना।

- **कक्षा स्तर** - माध्यमिक व उच्च माध्यमिक।
- **संवर्गवार** - रक्षा संवर्ग, शारीरिक विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति।
- **क्षेत्रवार** - ग्रामीण व शहरी।

**जनसंख्या एवं न्यादर्श** - प्रस्तुत शोध में चूंकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन का जोधपुर जिले के संदर्भ में अध्ययन करने का उद्देश्य रखा गया है। अतः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विभिन्न संवर्ग (रक्षा संवर्ग, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति), क्षेत्र (ग्रामीण व शहरी) की वे सभी बालिकाएँ जो (सत्र 2005-06 से 2014-15 तक) जोधपुर जिले के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में नामांकित हैं, प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या है।

**प्रदत्तों के स्रोत** - प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित स्रोतों से द्वितीयक प्रदत्ता प्राप्त किए गए-

- (1) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के मुख्य कार्यालय (दिल्ली) व क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर) में उपलब्ध अभिलेखा।
- (2) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट।
- (3) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के जोधपुर जिले में स्थित अध्ययन केन्द्र।

**प्रदत्तों की प्रकृति** - प्रस्तुत अध्ययन में संवर्ग, क्षेत्र एवं कक्षा स्तर में नामांकन के रूप में प्राप्त होने के कारण प्रदत्तों की प्रकृति संख्यात्मक (आंकिक) है।

**प्रदत्ता संकलन हेतु उपकरण** - शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार उपरिलिखित स्रोतों से विस्तृत संख्यात्मक द्वितीयक प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए, स्वनिर्मित समंक सारणी का प्रयोग किया गया है। इसके लिए विभिन्न चर व सत्रवार सारणी निर्मित की गई है।

**विश्लेषण प्रक्रिया** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राप्त प्रदत्तों का प्रतिशत विश्लेषण एवं रेखाचित्रिय निरूपण द्वारा विश्लेषण किया गया।

**जोधपुर** - सूर्य नगरी के नाम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए इस जिले की स्थापना 1459 ई. राठौड़ सरदार राव जोधा ने की थी। जिले का क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है।

सन् 2001 की जनगणनानुसार स्त्री पुरुष लिंगानुपात 907 : 1000 है। यहाँ की कुल जनसंख्या 28,86,505 है। ग्रामीण क्षेत्रीय जनसंख्या 66.15% तथा शहरी क्षेत्र में 33.85% है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्रमशः 15.81% एवं 2.76% है।

इस जिले में सत्र 2013-14 में पुरुष साक्षरता दर 72.96% एवं महिला

साक्षरता दर 38.64% है। ग्रामीण क्षेत्र में 46.21% तथा शहरी क्षेत्र में 75.54% है।

जिले में माध्यमिक स्तर पर कुल 162 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में से 15 राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय है। अनुदानित माध्यमिक बालिका विद्यालय एक तथा गैर अनुदानित माध्यमिक बालिका 11 है। इस प्रकार माध्यमिक स्तरीय कुल 389 विद्यालयों में से 27 बालिका विद्यालय है। उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 106 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 23 बालिका विद्यालय है। अनुदानित बालिका विद्यालय 3 तथा एवं गैर अनुदानित विद्यालय 7 है। इस प्रकार कुल 201 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 33 उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है।

जोधपुर जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के 3 अध्ययन केन्द्र शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

जोधपुर जिला देश भक्ति साहस, त्याग, संस्कृति तथा विकास के लिए सदा गौरवाशाली रहा है। तथा अपने कलात्मक एवं नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण धोरो के मरुस्थल का प्रवेश द्वारा कहे जाने वाले इस जिले की राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिका नामांकन सम्बन्धी प्रदत्तों को सारणी 1 में प्रस्तुत किया है।

### सारणी 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

**माध्यमिक स्तर पर संवर्गवार बालिका नामांकन प्रवृत्ति** – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर पर रक्षा संवर्ग में बालिका नामांकन सत्र 2005-06 से सत्र 2009-10 तक (सत्र 2008-09 के अतिरिक्त) यथावत होने के उपरान्त आगामी सत्र में नगण्य 0.9% (कुल 111 विद्यार्थियों में से 1 बालिकाएँ) रहा है। तथा सत्र 2011-12 में यह शून्य दृष्टव्य है। तत्पश्चात् सत्र 2012-13 से सत्र 2014-15 तक नामांकन प्रतिशत आंशिक विचलन के साथ स्थिर बना हुआ है। सत्र 2005-06 में बालिका नामांकन सर्वाधिक 3.9% (कुल 52 विद्यार्थियों में से 2 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 की तुलना में सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन 2.1% कम हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति अधोगामी दृष्टिगोचर है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति में बालिका नामांकन सत्र 2005-06 से सत्र 2008-09 तक स्थिर, तत्पश्चात् आगामी सत्र में 1.3% की गिरावट दिखाई दी है। सत्र 2010-11 की तुलना में सत्र 2011-12 में नामांकन प्रतिशत में 2.4% की वृद्धि तथा 2012-13 से सत्र 2014-15 तक नामांकन में सतत् गिरावट दृष्टव्य है। सत्र 2014-15 में सर्वाधिक न्यूनतम बालिका नामांकन 3.6% (कुल 168 विद्यार्थियों में से 6 बालिकाएँ) रहा है एवं सत्र 2011-12 में सर्वाधिक बालिका नामांकन 9.6% (कुल 124 विद्यार्थियों में से 12 बालिकाएँ) है। सत्र 2005-06 की तुलना में सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन में 2.2% कमी हुई है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति अधोगामी दृष्टव्य है। है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत बालिका नामांकन सत्र 2005-06 से सत्र 2012-13 तक यथावत रहने के उपरान्त आगामी सत्र में इसमें 4.7% की वृद्धि दिखाई दी है। सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक 35.2% (कुल 168 विद्यार्थियों में से 59 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में नामांकन प्रतिशतता में 6.3% वृद्धि हुई है। अतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन

प्रतिशतता प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी दृष्टिगोचर है।

पश्चिमी दिशा में जोधपुर जिले की सीमा जैसलमेर से होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक जाती है। अतः जिले में वायु सेना के सैनिक एयर फोर्स क्षेत्र में तथा बनाड छावनी में आर्मी के जवान रहते हैं। वायु सेना व थल सेना की यहाँ पर अलग-अलग यूनिट बनी हुई हैं। इन सभी यूनिट को केन्द्रीय सरकार के द्वारा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती है। जिसके कारण इस संवर्ग की बालिकाएँ इन क्षेत्रों में रहते हुए इन विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रही होगी तथा अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही होगी।

जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.81% है जो कि कुल जनसंख्या के सापेक्ष बहुत कम है। अतः इस संवर्ग की बालिकाओं का मुक्त विद्यालयी शिक्षा में वास्तविक नामांकन कम होना उचित होगा।

जोधपुर जिले में मुख्यतः खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ, ग्वार, तिल, मूंग, ज्वार, मिर्च, कपास, मक्का तथा रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, जीरा, सरसों की खेती होती है। जीरा उत्पादन अत्यधिक होने के कारण जिले में गुजरात की उंझा मण्डी के पैटर्न पर जीरा मण्डी बनी है। सामान्य संवर्ग की बालिकाओं का कृषि व इससे सम्बन्धित कार्यों में सहयोग रहता है। फलस्वरूप वह अपने अध्ययन हेतु अधिक समय नहीं निकाल पाती है। अतः समय की नियमितता न होने के कारण इस संवर्ग की बालिकाओं को मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान आकर्षित कर रहा होगा।

**माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रवार बालिका नामांकन प्रवृत्ति** – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बालिका नामांकन में सत्र 2005-06 से सत्र 2010-11 तक (सत्र 2008-09 को छोड़कर) आंशिक विचलन के साथ स्थिर है। तथा सत्र 2011-12 की तुलना में सत्र 2012-13 में नामांकन 0.9% बढ़ा है। सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन सर्वाधिक 37.6% (कुल 168 विद्यार्थियों में से 63 बालिकाएँ) हैं। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में 8.8% वृद्धि हुई है। अतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी दृष्टव्य है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में शहरी क्षेत्र में बालिका नामांकन प्रतिशत सत्र 2005-06 से सत्र 2010-11 तक (सत्र 2009-10 को छोड़कर) नामांकन प्रतिशत यथावत है तथा सत्र 2011-12 में इसमें 2.6% की कमी दिखाई दी है। तदुपरान्त सत्र 2012-13 की तुलना में सत्र 2013-14 में नामांकन प्रतिशत में पूर्व सत्र के अनुरूप 6.1% दृष्टव्य है। सत्र 2014-15 में सर्वाधिक न्यूनतम नामांकन 3.6% (कुल 168 विद्यार्थियों में से 6 बालिकाएँ) है। सत्र 2005-06 में अधिकतम बालिका नामांकन 9.7% (कुल 52 विद्यार्थियों में से 5 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में 6% कमी दृष्टव्य है। अतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति अधोगामी दृष्टव्य है।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विश्वनोई सम्प्रदाय के परिवार अधिक निवास करते हैं। इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय अफीम की खेती, उसकी तस्करी तथा पशुपालन करना है। अन्य परिवारों के द्वारा बादले (मेटल की सुराही पर शनील चढ़ाया जाता है।) लाख का सामान, एल्यूमिनियम के खिलौने व सजावटी वस्तुएं तथा जोधपुर चित्र शैली, जिसमें प्रमुख रूप से भूमल निहालदे, ढोला मारु, कल्याण रागिनी, दरबारी जीवन, राजसी ठाठ, मारु के टीले, इत्यादि चित्रों को बनाते समय पीले रंग को प्रधानता दी जाती



है। इन सभी खेलों, सजावटी वस्तुएं, चित्र शैली बादलें इत्यादि को बनाने में तथा रंगों के संयोजन व चयन करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिसमें कि महिलाओं व बालिकाओं की अहम भूमिका होती है। अतः इन परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है। किन्तु फिर भी वे बालिकाएँ जो कि इन परम्परागत कुटीर उद्योगों में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहती है वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में नामांकित होकर शिक्षा द्वारा अपनी सृजन क्षमता को उन्नत कर लाभान्वित हो रही होगी।

जिले में अनुदानित माध्यमिक बालिका विद्यालय एक तथा गैर अनुदानित 11 है। एवं राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय कुल 15 है। अधिकांश बालिका विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित होंगे। फलतः इन विद्यालयों की भव्य इमारतें व आकर्षक सुविधाओं से आकर्षित होकर शहरी क्षेत्र की बालिकाएँ इस प्रकार के विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने में अधिक रुचि रखती होगी।

**जोधपुर जिले में माध्यमिक स्तर पर कुल बालिका नामांकन प्रवृत्ति -** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में संवर्ग एवं क्षेत्रवार, माध्यमिक स्तर पर कुल बालिका नामांकन प्रवृत्ति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 2005-06 से सत्र 2014-15 तक नामांकन प्रतिशत में घटाव एवं बढ़ोतरी के साथ विचलन दृश्य है तथा सत्र 2014-15 में सर्वाधिक बालिका नामांकन 41.1% रहा है तथा सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में 2.6% वृद्धि हुई है।

**समेकन (Consolidation)** - समग्र रूप से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में इस जिले की बालिका नामांकन प्रवृत्ति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि राजस्थान नहर परियोजना से कृषि की पैदावार अच्छी है। वहीं हस्तशिल्प (बंधेज, बादले, एल्यूमिनियम के खेलौने आदि) से तैयार उत्पाद के अच्छे बाजार ने जिले में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा दिया है। जिससे निवेश का उचित प्रतिफल मिलने के कारण अनेक वृहत, लघु एवं माध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है। फलतः विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है व मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर बालिकाएँ आकर्षित हुई हैं। जिले में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के तीन अध्ययन केन्द्रों के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण कम दूरी एवं आसान पहुँच वाले अध्ययन केन्द्रों तक बालिकाओं के पहुँचने में सरलता हुई है। अतः माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन प्रतिशतता बढ़ी है।

आबादी के लिहाज से राजस्थान में दूसरा स्थान रखने वाले इस जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मात्र 3 अध्ययन केन्द्र होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं ने शैक्षिक अवसरों का पर्याप्त लाभ उठाया है। जो बालिकाओं की शैक्षिक सजगता को प्रकट करता है किन्तु संभवतः रक्षा संवर्ग की बालिकाओं को सरकार द्वारा दी जा रही विशेष सुविधाओं के कारण तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग बालिकाओं में शैक्षिक जागरूकता एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण इन दोनों संवर्गों की बालिकाओं की नामांकन प्रतिशतता अत्यन्त कम है। माध्यमिक स्तर पर सामान्य संवर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में बालिका नामांकन प्रतिशतता अधिक दृश्य है। संभवतः जिले में खुली शिक्षा प्रणाली के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने पर माध्यमिक स्तर पर बालिका नामांकन में वृद्धि की जा सकती है।

राजस्थान की सूर्य नगरी व मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला

यह जिला राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ राज्य की कुल आबादी लगभग 5.10% जनसंख्या निवास करती है। जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता होने के बावजूद भी कुल विद्यार्थियों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन 50% से भी कम होना इस ओर संकेत करता है कि यह बालिकाएँ सामाजिक व पारिवारिक कारणों से माध्यमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रही है। अतः इन बालिकाओं को और अधिक जागरूक बनाकर इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के लिए और अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता है।

**उच्च माध्यमिक स्तर पर संवर्गवार बालिका नामांकन प्रवृत्ति -** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर रक्षा संवर्ग में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत सत्र 2005-06 में 2.7% रहा, तत्पश्चात् आगामी दो सत्रों में नामांकन प्रतिशत यथावत है। तथा सत्र 2011-12 में सत्र 2014-15 तक बालिका नामांकन प्रतिशत में 1.1% की कमी के उपरान्त अन्तिम सत्र में यह नगण्य 0.8% दृश्य है। सत्र 2008-09 में बालिका नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक 3.6% (कुल 7 विद्यार्थियों में से 2 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशत में 1.9% की कमी हुई है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति अधोगामी है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति में बालिका नामांकन प्रतिशतता सत्र 2005-06 की तुलना में सत्र 2008-09 में आंशिक वृद्धि 0.8% दिखाई दी है। तत्पश्चात् सत्र 2009-10 से सत्र 2012-13 तक बालिका नामांकन 6.3% की बढ़ोतरी के साथ यथावत् दृश्य है। न्यूनतम बालिका नामांकन सत्र 2014-15 में 4.9% (कुल 132 विद्यार्थियों में से 6 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशत में 2.2% की गिरावट दिखाई दी है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति अधोगामी दृश्य है।

खुली शिक्षा प्रणाली में उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत बालिका नामांकन प्रतिशतता सत्र 2005-06 से सत्र 2009-10 में आंशिक विचलन के साथ स्थिर है। तत्पश्चात् सत्र 2010-11 में 3.3% की वृद्धि दिखाई दी है। सत्र 2011-12 से सत्र 2005-06 तक बालिका नामांकन में आंशिक विचलन तथा आगामी सत्रों में निरन्तर वृद्धि दिखाई दी है। सत्र 2014-15 में सर्वाधिक नामांकन 47.7% (कुल 132 विद्यार्थियों में से 63 बालिकाएँ) है एवं सत्र 2012-13 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में अत्यधिक वृद्धि 14.4% दिखायी दी है। अतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण है।

जोधपुर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संवर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधा दी गई है। जिसके अन्तर्गत इस जिले में एयर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल तथा आर्मी सेन्ट्रल स्कूल लगभग 10 है। नौकरी में स्थानान्तरण अधिक होने के कारण यह अभिभावक बालिकाओं को इन विद्यालयों में शिक्षा दिलवाना अधिक पसन्द करते होंगे।

जिले में अनुसूचित जाति के परिवार अधिकांशतः ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस संवर्ग के परिवारों की अफीम की खेती, शराब बनाना व बेंचना तथा कचरा चुगने इत्यादि कार्यों पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

जिसके कारण इनकी प्रति व्यक्ति आय भी कम है। अतः इन परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है। तथा आर्थिक व सामाजिक कारणों से सभी बालिकाएँ मुक्त विद्यालयी शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाती होगी।

जिले में सर्वाधिक जनसंख्या सामान्य संवर्ग की है। अधिकांश परिवार जोधपुरी कोट पेन्ट बनाने, जोधपुरी साफा बनाने व बांधने, बंधेज की साड़ियों की रंगाई करने तथा चमड़े से निर्मित मोजड़ी (जूतियाँ), डूंगरशाही ओढ़नी बनाने इत्यादि परम्परागत उद्योगों से जुड़े हुए हैं। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि सामान्य संवर्ग की वे बालिकाएँ जो कि इन उद्योगों के द्वारा परिवार की आर्थिक रूप से सहायता कर रही है वह नियमित अध्ययन नहीं कर सकने के कारण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में नामांकित होती होगी।

**उच्च माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रवार बालिका नामांकन प्रवृत्ति** – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बालिका नामांकन प्रतिशत सत्र 2005-06 की तुलना में सत्र 2008-09 में 7.3% की वृद्धि तथा आगामी सत्र में आंशिक कमी दिखाई दी है। सत्र 2011-12 में पूर्व सत्र 2008-09 के समरूप बालिका नामांकन 35.3% दृष्टव्य है एवं सत्र 2012-13 से सत्र 2014-15 तक बालिका नामांकन प्रतिशतता में निरन्तर बढ़ोतरी दृष्टिगोचर है। सत्र 2014-15 तक नामांकन प्रतिशतता सर्वाधिक 50.0% (कुल 132 विद्यार्थियों में से 66 बालिकाएँ) रही है। तथा सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में 22.2% की वृद्धि हुई है। अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी दृष्टिगोचर है।

मुक्त विद्यालयी शिक्षा में शहरी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिका नामांकन में सत्र 2005-06 से सत्र 2009-10 तक (सत्र 2008-09 को छोड़कर) स्थिर तत्पश्चात् सत्र 2010-11 में नामांकन में 4.5% की कमी दिखाई दी है। सत्र 2011-12 की तुलना में सत्र 2012-13 में बालिका नामांकन 1.6% कम होने के उपरान्त अन्तिम सत्र 2014-15 में न्यूनतम 3.0% (कुल 132 विद्यार्थियों में से 4 बालिकाएँ) हैं। तथा सत्र 2009-10 में बालिका नामांकन सर्वाधिक 11.4% (कुल 61 विद्यार्थियों में से 7 बालिकाएँ) रहा है। सत्र 2005-06 के सापेक्ष सत्र 2014-15 में नामांकन प्रतिशतता में (8.2%) कमी दिखायी दी है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बालिका नामांकन प्रतिशतता प्रवृत्ति शहरी क्षेत्र में अधोगामी दृष्टव्य है।

सर्वाधिक परती भूमि तथा विभिन्न प्रकार के बालूका स्तूप वाले इस जिले के खारिया खंगार कस्बे में सफेद सीमेन्ट का राज्य का सबसे बड़ा करखाना है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश परिवारों के सदस्य कार्य करते हैं। विभिन्न उद्योगों के साथ-साथ यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राजस्थान नहर परियोजना से जिले में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। जिसके फलस्वरूप यहाँ बाजरा 5000 हेक्टेयर भूमि में उत्पादित होता है। साथ ही ग्वार, मोठ, तिल, मूंग, कपास आदि की भी अच्छी पैदावार होती है। गरिमा गुप्ता (शून्य गुरुत्वाकर्षण वाली फ्लाइट में जीरो ग्रेविटी प्रयोग करने वाली), कु समता शर्मा (चमड़े पर स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध), गवरी बाई (सादी मांड गायिका) तथा जमीला बानू (राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका) जैसी महान विभूतियों के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता आयी है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश बालिकाएँ विभिन्न कार्यों में व्यस्त होते हुए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा

संस्थान के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की चाह रखती होगी। अतः यह बालिकाएँ मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में नामांकित होकर उच्च माध्यमिक शिक्षा का लाभ उठा रही होगी।

ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य इस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या 66.15% तथा शहरी क्षेत्र में 33.85% है। जिसके कारण मुक्त विद्यालयी शिक्षा में इन बालिकाओं का वास्तविक नामांकन कम है। संभवतया शहरी क्षेत्र की यह बालिकाएँ जिले में स्थिति विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में नामांकित होकर उच्च माध्यमिक शिक्षा से लाभान्वित हो रही होगी।

**जोधपुर जिले में उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल बालिका नामांकन प्रवृत्ति**

– राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर संवर्ग एवं क्षेत्रवार बालिकाओं की नामांकन प्रतिशतता देखने से स्पष्ट होता है कि सत्र 2005-06 से सत्र 2014-15 तक (सत्र 2011-12 से सत्र 2012-13 को छोड़कर) बालिका नामांकन प्रतिशतता में सतत वृद्धि दृष्टव्य है। सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता सर्वाधिक 53.0% है। तथा 2005-06 की तुलना में सत्र 2014-15 में बालिका नामांकन प्रतिशतता में 14.1% की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।

**समेकन (Consolidation)** – जोधपुर जिले के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन प्रवृत्ति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत 50% से अधिक होना जिले में बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति का द्योतक है। ग्रामीण क्षेत्र तथा हिन्दी माध्यम में बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत उच्च होना जिले में बालिका शिक्षा के विकास का बेहतरीन उदाहरण है। सिंचाई और परम्परागत उद्योगों में निवेश के उत्पादन और आय में इजाफा हुआ है। जिससे बालिकाओं में शैक्षिक जागरूकता तथा शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। अतः यह बालिकाएँ मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से अधिक से अधिक लाभान्वित होने लगी हैं।

जिले में जनसंख्या 15.81% भाग का निर्माण करने वाली अनुसूचित जाति तथा रक्षा संवर्ग के परिवारों की उन्नति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में इन दोनों वर्ग के लिए आरक्षण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऋण और अनुदानों की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। संभवतया इन सभी सुविधाओं के मिलने के कारण अनुसूचित जाति व रक्षा संवर्ग की बालिकाओं का मुक्त विद्यालयी शिक्षा के प्रति आकर्षण कम रहा है। जिले में शहरी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 201 विद्यालयों के होने के कारण इस क्षेत्र की बालिकाएँ इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में अधिक रुचि रखती होंगी। फलतः खुली शिक्षा प्रणाली में इन बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम दृष्टव्य है।

निष्कर्षतः प्रगतिशील जिला जोधपुर में निवेश हेतु अनुकूल माहौल है। आर्थिक स्तर उन्नत होने के कारण उपभोक्ता बाजार का विस्तार हो रहा है। जिससे सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो रहा है। बालिकाओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त व अनुकूल अवसर उपलब्ध होने से जिले की प्रगति व विकास के लिए मजबूत आधार तैयार हो रहा है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :-**

1. **आपटे, प्रभा** : भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996

2. **गोयल, अरुना एवं गोयल, एस.एल.:** डिस्टेन्स एज्युकेशन इन द 21 सेन्चुरी, दीप एण्ड पब्लिकेशन्स प्रा.लि. न्यू देहली, 2001
3. **गुड, सी.वी. :** डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन, मैकग्राव हिल कम्पनी, न्यूयार्क, 1989
4. **तपन नीता :** नीड फॉर एमपावरमेन्ट रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एण्ड न्यू देहली, 2000
5. **दत्ता, आर, 1987 :** डिस्टेन्स एज्युकेशन वर्सेज ट्रेडीशनल हायर एज्युकेशन : ए फास्ट कम्पैरीज इन बी.एल. कॉल एड ऑल (एडी) स्टेडीज इन डिस्टेंस एज्युकेशन न्यू देहली, ए.आई.यू. एण्ड इन्वू इन ओपन एण्ड डिस्टेंस इन फिफथ सर्वे एज्युकेशनल रिसर्च (1988-92) वॉल्यूम-1, एन.सी.ई.आर.टी., न्यू देहली।
6. **प्रधान, सुसान्ता कुमार एण्ड प्रधान प्रतिभा 1997 :** एटीट्यूड टुवर्डस ओपन लर्निंग सिस्टम ए कम्परेटिव स्टेडी ऑफ फॉर्मल लैन्स, इन जनरल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 34(1) जुलाई-सितम्बर, 1997 बायउड पब्लिशिंग कम्पनी इन्क।
7. **प्रेसर हैरीट वी. एवं सेन गीता :** वूमेन्स एम्पावरमेन्ट एण्ड डेमाग्राफिक प्रोसिस मूविंग बियॉड केयर, वॉल्यूम-1, पब्लिशिड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस, 2002
8. **मृदुला 1991 :** इकोनोमिक्स ऑफ द ओपन लर्निंग सिस्टम : कम्परेटिव फास्ट ऑफ हायर एज्युकेशन थो इन्वू पी.एच.डी. एज्युकेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन फिफथ सर्वे एज्युकेशनल रिसर्च (1988-92), एन.सी.ई.आर.टी. न्यू देहली।
9. **मुखोपाध्याय, एम.एण्ड सुजाता, के. 1988 :** ओपन लर्निंग सिस्टम एट स्कूल लेवल जनरल ऑफ एज्युकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इन फिफथ सर्वे एज्युकेशन रिसर्च (1988-92) वॉल्यूम-1, एन.सी.ई.आर.टी. न्यू देहली।
10. **राव, सुधा के, 1988 :** ओपन लर्निंग सिस्टम : कॉन्सेप्ट एण्ड फ्यूचर : जनरल आूप एज्युकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इन फिफथ सर्वे एज्युकेशन रिसर्च (1988-92) वॉल्यूम-1, एन.सी.ई.आर.टी. न्यू देहली।

**सारणी 1:जोधपुर जिले के एन.आई.ओ.एस. में बालिका नामांकन(बालिका नामांकन कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में)**

कक्षा स्तर		वर्ग	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13	2013 -14	2014 -15	
माध्यमिक स्तर	संवर्ग	रक्षा संवर्ग	3.9	3.5	3.8	2.7	3.1	0.9	-	1.4	2.1	1.8	
		विकलांग	-	-	-	-	-	-	0.9	1.4	0.7	0.5	
		अनु.जाति	5.8	5.4	5.8	5.3	4.0	7.2	9.6	6.3	5.4	3.6	
		अनु.ज.जाति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सामान्य	28.9	28.5	28.9	28.0	28.5	28.8	28.2	28.9	33.6	35.2	
	क्षेत्र	ग्रामीण	28.8	28.6	28.8	26.7	28.6	27.9	32.3	33.2	34.2	37.6	
		शहरी	9.7	9.4	9.6	9.4	7.2	9.1	6.5	5.6	6.1	3.6	
उच्च माध्यमिक स्तर	संवर्ग	रक्षा संवर्ग	2.7	2.3	2.7	3.6	3.3	2.3	1.2	1.9	1.0	0.8	
		विकलांग	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	
		अनु.जाति	2.7	2.4	2.7	3.5	9.8	9.8	9.5	9.9	8.2	4.9	
		अनु.ज.जाति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		सामान्य	33.3	33.5	33.3	33.3	32.8	36.1	34.2	33.4	40.8	47.7	
	क्षेत्र	ग्रामीण	27.8	27.6	27.8	35.1	34.4	41.7	35.3	39.3	45.9	50.0	
		शहरी	11.2	11.4	11.2	5.3	11.4	6.9	9.5	7.9	4.1	3.0	

नोट - सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जोधपुर जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विकलांग, अनुसूचित जनजाति संवर्ग में बालिका नामांकन प्रतिशत शून्य अथवा नगण्य मात्र होने से इन संवर्गों की बालिका नामांकन प्रवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

## महिला कथाकारों के उपन्यासों में मानवीयता

डॉ. राजेश श्रीवास\*

\* सहा.प्राध्यापक (हिन्दी) सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम) रायपुर (छ.ग.) भारत

**प्रस्तावना** - साहित्य मनाव-मानस की विशिष्ट एवं रमणीय अनुभूति है। 'साहित्य का पहला अंग है -भाव, जिसके लिए कल्पना का योगदान अपेक्षित है, परन्तु कल्पना ऐसे जो अनुभूति के आधार पर निर्मित हो।' इसी यथार्थानुभूति की विशिष्ट व्यंजना करने वाला साहित्यिक रूप-विधान कथा (उपन्यास, कहानी) साहित्य है। इसीलिए इसमें हृदय को स्पंदित करने की शक्ति होती है। मानव-चेतना समाज-सापेक्ष हुआ करती है और उपन्यास, कहानी-जो मानव चेतना का संवाहक है-नितांत समाज-निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, वह तो जीवन की परिकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा जीवन के सौंदर्यात्मक और आनंदात्मक पक्ष का उद्घाटन होता है। 'साहित्य के सृजन में साहित्यकार के संस्कार, पारिवारिक वातावरण उसके मानस-पटल पर अंकित प्रभाव तथा इस प्रभाव के द्वारा निर्मित विचारधारा और मान्यताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है।'<sup>2</sup> क्योंकि किसी भी साहित्यकार का जीवन तथा साहित्य संस्कार, अनुभूतिजन्य मान्यताओं एवं विचारधाराओं का उनके साहित्य पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी भी साहित्यकार के साहित्य को समझने के लिए उसके जीवन एवं व्यक्तित्व से भली-भाँति परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन किसी न किसी रूप में उसकी रचनाओं में अवश्य प्रतिबिम्बित होता है।

आज के संघर्षशील, यथार्थवादी युग में जीने वाली नारी का दृष्टिकोण उसके पारिवारिक एवं सामाजिक परिपेक्ष्य में परखने के लिए समाज और परिवार को लेकर पनपी अभिनव मान्यताओं की चर्चा कर लेना युक्तिसंगत होगा। भारतीय समाज की संरचना आदिकाल से पुरुषप्रधान रही है। मातृप्रधान समाज के दर्शन यदा-कदा ही मानव-इतिहास में होते हैं। परन्तु समय परिवर्तनशील होता है और साहित्य के क्षेत्र में सदा ही परिवर्तित समय की प्रतिच्छवि अंकित की जाती रही है। स्वतंत्रता-पूर्व तक के हिंदी कथा-साहित्यों में नारी को घर की चहारदीवारी में सीमित रखकर समाज में उसकी महत्ता, पुरुष सापेक्ष चित्रित की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की सामाजिक व आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आये हैं। आज परिवार एवं समाजविषयक अनेक प्राचीन मान्यताएँ टूटती जा रही हैं और उनका स्थान नयी मान्यताएँ लेती जा रही हैं। आधुनिक कथा-साहित्य की विधा इस नवीनता और प्राचीनता के संधि-स्थल की ओर संकेत करने में सतत गतिमान है। पारिवारिक और सामाजिक परिपेक्ष्य में नारी की मानसिकता को विविध रूपों में रेखांकित करने की चेष्टा आलोच्य वर्षों के उपन्यास-कहानियों में परिलक्षित होती है। विगत दो से तीन दशकों का समय नारी की पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं में होने वाले

परिवर्तनों का काल रहा है। जैसे तो यह परिवर्तन स्वतंत्रता संघर्ष के समय से ही दृष्टिगोचर होने लगा था। किन्तु पाँचवे दशक के उपरांत देश के सामाजिक गतिविधियों में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया, जो नारी सशक्तिकरण का दौरे था। यही वह समय था, जब महिला कथाकारों ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं, दुःखः, दर्द, पीड़ा, संत्रास, कुंठा, घरेलू अत्याचार जैसी अमानवीय घटनाओं पर खुलकर समाज के सम्मुख अपने उपन्यास, कहानियों के माध्यम से बात रखने की साहस की। और अपने अनुभूति की प्रखर अभिव्यक्ति में वे काफी सीमा तक आज सफल भी हो सकी। उन महिला कथाकारों में -महादेवी वर्मा, मन्नू भण्डारी, ममता कालिया, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियंवदा, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मधु कांकरिया, मृदुला गर्ग, डॉ. उर्मिला शुक्ल, डॉ. जया जादवानी, श्रद्धा थवाईत, शुभा ठाकुर, डॉ. नलिनी श्रीवास्तव आदि जैसे साहित्यकारों ने परिवार, समाज में घुट रही नारी आवाज को बुलंद की। इस प्रकार आधुनिक महिला कथाकारों की लेखनी ने नारी के उस रूपाभाव को उजागर किया है जो अंधेरी बंद कमरे में सिसक रही थी। महादेवी वर्मा का नारी चिंतन व लेखन नारी वेदना और आत्म-पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ इसीलिए शिक्षा पर भी जोर देता है। महादेवी वर्मा नारी के अधिकारों के प्रति हमेशा सजग व पक्षधर रही हैं। उन्होंने हमेशा नारी के सम्मान और बराबरी के अधिकारों के लिए पुरजोरता से आवाज उठाई है। नारी अधिकारों पर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि 'हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व। केवल अपना वह स्थान, वे स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों क निकट कोई उपयोग नहीं है, परन्तु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकेगी।'<sup>3</sup> महादेवी वर्मा ने नारी के शिक्षित होने पर बल दिया है। उनका मानना है कि नारी को यदि सम्मान जनक स्थान प्राप्त हो सकता है तो शिक्षा के माध्यम से ही।

समकालीन परिवेश में न सिर्फ नारी के संघर्षों, चुनौतियों को व्यक्त किया है बल्कि उसकी संवेदनाओं से गहरे जुड़ते हुए नारी मन में विश्वास की रोशनी से सराबोर करने का प्रयास हुआ है। मन्नू भण्डारी के कथा साहित्य में चित्रित नारी आज समाज की संरचना में पुरुष के समकक्ष होने का दावा करती है। 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास की रंजना मध्यकालीन भारतीय नारी की मानसिकता में जीने वाली नारी है। संपूर्ण निष्ठा के साथ प्यार समर्पण करना अपना दायित्व समझती है। प्रतिदान स्वरूप पति का संपूर्ण प्यार पाना अपना अधिकार मानना रंजना की स्वभावगत विशेषता है। वह सुशिक्षित एवं सुन्दर है। सामान्य परिवार का होकर भी अपने परिक्षम से

कॉलेज में प्राध्यापिका है और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक स्वतंत्रता का निर्णय भी स्वयं लेती है। वह अपना जीवनसाथी अमर को बना चुकी है। घरवालों की किसी प्रकार की बाधा अपने विवाह के संबंध में अस्वीकार है। परन्तु अमर की महिला मित्र अमला को लेकर अंतिम सीमा तक विरोध बढ़ जाती है। और बात टुट कर ही रहती है। यहाँ रंजना एक साहसी एवं स्वतंत्र निर्णय लेने वाली नारी के रूप में उपस्थित होती है। जिस साहस के साथ उसने अमर के लिए पिता का घर त्याग दिया था, उसी साहस के साथ अपने प्यार एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए अमर का भी परित्याग करके चली जाती है। अमर उसकी मानसिकता की व्याख्या करता हुआ कहता है- 'उसने शुरू से ही अपने आस-पास देखा है कि पति नौकरी करता है। इसके बाद दोनों या तो कहीं घुमने, सिनेमा चले जाते हैं या किसी को बुला लेते हैं। ..... अब उसे न मेरे मित्र पसंद है न मेरा व्यवहार, न मेरी दिनचर्या। मेरे पुरुष मित्र उसे पसंद नहीं है और महिला-मित्रों से वह ईर्ष्या करने को विवश है..... दूसरे पति के महिला-मित्रों से ईर्ष्या करने की परम्परा है। वह तो साफ कहती है यह मित्र क्या चीज है ? या तो पत्नी होती है या बहन-भाभी।'<sup>14</sup> रंजना, अमर को संपूर्ण मन की गहराई से प्रेम करती है परन्तु जिस क्षण इस निष्ठा में व्याघात अनुभव करती है किसी साहसी नारी की तरह-अपना मार्ग स्वयं तय कर नये जीवन पथ पर बढ़ जाती है।

सूक्ष्म संवेदनशीलता के धरातल पर नारी का वास्तविक मन अपनी पूरी गहराई के साथ शिवानी के उपन्यास 'कृष्ण कली' में चित्रित हुआ है। नारी-मन की गहरी पकड़ शिवानी में है, और वे अपनी सजग दृष्टि से परिवेश को यथार्थ के धरातल पर अंकित करने में सक्षम है। 'कृष्ण कली' में शिवानी ने नारी की मानसिकता को आंतरिक एवं बाह्य धरातलों पर बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित किया है। उपन्यास में अवचेतन की रहस्यात्मकता की थाह पाने के लिए शिवानी का नारी-मन सदैव सचेत रहा है। उपन्यास में एक ओर जहाँ रोमांस से ओत-प्रोत, स्नेह और ममता से भीगी हुई नारी का चित्रण है तो दूसरी ओर मानसिक वृत्तियों की जटिलता से जूझती नारी का भी सशक्त चित्रण है। कृष्ण कली, उपन्यास की प्रमुख नारी-पात्र है। 'कली' का जन्म और परवरिश दोनों ही अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुए हैं जिसका कुप्रभाव कली के मानस पर गहरे पड़ता है। कली के चरित्र की ये दुर्बलताएँ कुछ तो उसकी आत्मकुंठा का परिणाम थी कुछ उसे अपनी जन्मदात्री से विरासत में भी मिली थी। कली अपनी विद्वेहिणी नारी को लिए अपने अन्तस् की ज्वाला से सारे संसार को फूँकना चाहती थी, संसार के लिए 'बुरी लड़की' बनना अपनी नियति मानने को उसका निष्कलुष हृद्य तैयार नहीं होता, इसे भूलने के लिए वह मसान साधती है, गांजा चरस पीती है, हिप्पियों की गाईड बन उनकी प्रमोद-लीला की प्रेरणास्रोत बनती है। कली का मादक सौन्दर्य किसी को वासना की आग में झुलसा देने वाला है तो किसी के संतप्त हृदय पर शीतल प्रलेप का कार्य करता है। अपने अधिकारी शेखरन को वह रहस्यमयी ढंग से अनेक रूपों में प्रभावित करने की कोशिश करती है, परन्तु यह कली का दुर्भाग्य था कि पुरुष की लोलुप दृष्टि ने उसमें मादक सौन्दर्य को ही देख सकी, उसकी भूखी आत्मा को कभी नहीं देखा। इस संदर्भ में कली सोचती है - 'क्या कभी भी कोई उसके अन्तर की व्यथा को नहीं जान पायेगा ? कोई मुग्ध दृष्टि से उसकी बड़ी-बड़ी आँखों को ही देखता रहता है, कोई निर्लज्ज दृष्टि का अदृश्य भाला उसके सुडौल वक्ष के आर-पार भेदकर उसकी वैकलैस चोली के बंधन शिथिल कर देता है। जितने भी लोलुप पुरुष, उतनी ही विभिन्न-विभिन्न दृष्टियाँ। पर क्या आज तक एक भी दृष्टि में उसे सच्चे-

निश्चल स्नेह की ऐसी झलक मिल सकी है।'<sup>15</sup> यही निश्चल स्नेह की प्यास कली को दर-ब-दर भटकाती है। इस भटकाव का अंत प्रवीर के मोहपाश में पड़कर होता है। प्रवीर कली का सिद्धि-सोपान सिद्ध होता है। वह उसके समक्ष अपने हृदय की समस्त पवित्रता से आत्मा का दुख उड़ेल देती है। कली का अतीत गर्व करने लायक नहीं है, इस कारण वर्तमान का ऐश्वर्य भी उसे अतीत की घृणास्पद स्थिति में उबरने नहीं देता। यही कली की विडम्बना है। कली का आरंभ जितना वीभत्सता लिये था, अन्त उतना ही कारुणिक होता है।

'सूरजमुखी अंधेरे के' में कृष्णा सोबती ने एक ऐसी लड़की (रत्ती) के अनुभवों की कहानी कही है जो बचपन में बलात्कार की शिकार हो जाती है। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप वह अपने आस-पास के परिवेश को अपने प्रतिकूल पाती है। रत्ती के मनोमस्तिष्क में एक बद्धमूल मानसिक ग्रंथि है, जिसमें वह पूरी तरह गिरपतार है - 'वह तीव्र इच्छा से भर उठती है और हताश हो अपने में ही लौट आती है। अपने से टकराती है, संघर्षरत होती है। लड़ाई लड़ती है कही बाहर नहीं, बाहरी शक्ति से नहीं, अपने से ही-गहरे में कही भीतर-अपनी ही मानसिक ग्रंथि से जिसके कारण वह सिर्फ एक चिथड़ा है जिससे वह एक बार भी समुची औरत नहीं बन पाती। हर बार कहीं पहुँच सकने की न मारने वाली चाह और हर बार वीरान वापसी अपनी ओर।'<sup>16</sup> कैशी उससे कहता भी है हमेशा अपने से अपने अन्दर लड़ने का कोई फायदा नहीं। पर रत्ती भीतर की लड़ाई को बाहर नहीं मोड़ पाती। इस मानसिक पीड़ा से छुटकारा पाने का अहसास रक्तिका को कुछ-कुछ असद भाई से मिलने पर होता है। असद से मिल कर वह असद की अकृत्रिम सहृदयता पा अपने आपको मानों बदले हुए परिधान में पाती है। असद उसके पुराने खोल से मुक्ति दिलाने की शक्ति जुटाता कि इससे पूर्व ही उसकी अचानक मृत्यु रत्ती को एक बार फिर उसी पुरानी आंतरिक घुटन भोंगने को विवश कर देती है। असद के बाद रोहित, मुकुल, राजन, भानुराव, सुमेर सुब्रामनियम, श्रीपत अनेक पुरुष रत्ती की देह पर घात लगाये दिखाई देते हैं। प्रेम और सहृदयता का नाम लेकर ये सभी रत्ती की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं पर तुरंत ही वे उसे बिस्तर पर खींचने को बेताब दिखाई देते हैं। जब-जब रत्ती किसी पुरुष के संसर्ग में आती है वह एक काला जहरीला क्षण हर बार उसे झपट लेता है और रत्ती काठ हो जाती है। आधुनिक उपन्यास में स्त्री-पुरुष का संबंध भावात्मक धरातल पर ही गहराने की अपेक्षा अब नये आयामों के अनुरूप शारीरिक संपर्कों को लेकर ही अधिक मुखर हुआ है। किन्तु रक्तिका का मानस ही सारे फसाद की जड़ है। 'ममता कालिया' का 'बेघर' संजीवनी को इसीलिए 'बेघर' बनाता है, क्योंकि परमजीत संभोग के क्षणों में अपने को पहला पुरुष नहीं पाता। पुरुष द्वारा पहला होने की धारणा ही नारी के दुर्भाग्य का कारण बने यह हर स्थिति में आवश्यक नहीं। स्वयं नारी भी अपने आपसे इस लड़ाई में कहीं हारी हुई स्वयं को पाती है। रत्ती, सुब्रामनियम से अपनी इसी बेबसी का इकबाल करती है- 'जिसने गरीबी को ओढ़ने के लिए कीमती कपड़े पहने हो, जिसके संबंधो की कोई रियासत न हो-दिखाने के नाम पर एक तेवर तक नहीं.....'<sup>17</sup> मानों सारी बेबसी रत्ती की अपनी निर्मित की गई है। इस प्रकार 'सूरजमुखी अंधेरे के' अकेली रत्ती की ही कथा है जिसमें स्त्री के मन को परत-दर-परत उकेरने का प्रयास है। मानवीय-मन की नितांत उलझी हुई चाहत और जीवट भरे संघर्ष का संकेत रत्ती के जीवन का संघर्ष है।

भारतीय नारी की सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से जन्मी मानसिक

यंत्रणा का अत्यंत मार्मिक चित्रण उषा प्रियंवदा के उपन्यास 'पचपन खम्भे लाल दीवारों' में देखने को मिलता है। छात्रावास के पचपन खम्भे और उसकी लाल दीवारों के सदृश्य ही अपनी हमचाही उलझनों में कैद सुषमा को एक घुटन का तीखा अहसास होता है। उन उलझनों को सुलझाने के लिए नील जैसा सुलझा हुआ युवक सुषमा के जीवन में सहभागी होने की इच्छा व्यक्त करता है किन्तु सुषमा का अन्तर्मन स्वयं अपनी ही खींची सीमा-रेखाओं में बँधा रहता है। इन परिस्थितियों के बीच जीना ही उसकी नियति बन गई है। आधुनिक नारी-जीवन की भी यही विडम्बना रही है कि वह जिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं उन्हें ही झेलने की विवशता में उसे जीना पड़ता है। परम्परागत बंधनकारा से मुक्ति पाने की स्थिति का स्पर्श करने का चाव लेकर भी भारतीय नारी ऐसा आत्मसाहस नहीं जुटा पाती। यही उसके चरित्र का भावात्मक पहलू उसे दूसरों की तुलना में अर्किचन बना देता है। सुषमा छोटी बहिन नीरू का विवाह धूमधाम से कराती है और स्वयं नील के प्रणय-निवेदन को ठुकराने के लिए विवश कर दी जाती है।

सुषमा महाविद्यालय में इतिहास विभाग की लेक्चरर तथा गर्ल्स होस्टल की वार्डन है। तैंतीस वर्ष की आयु, अपाहिज पिता, छोटे भाई-बहिन तथा माँ की आर्थिक माँग को पूरा करने के निमित्त कर देती है। जीवन की भाग-दौड़ और आजीविका के प्रश्नों में चुपचाप विलीन हो गये वे वर्ष-और अब तो उसके चारों ओर दीवारें खिंच गई थी, दायित्व की, कुंठाओं की, अपने पद की गरिमा और परिवार की।' '.....कभी-कभी उसका मन न जाने क्यों डूबने लगता। अपने परिवार का सारा बोझ अपने उपर लिए सुषमा काँपने लगती। तब वह चाह उठती कि दो बाँहें उसे भी सहारा देने को हों। इस नीरवता में कुछ अस्फुट शब्द उसे भी सम्बोधन करें।' नील की सबल बाँहें सुषमा के जीवन की नीरसता को रस-रिन्गध बनाने के लिए आगे बढ़ती है किन्तु सुषमा की आत्मकुंठा उसे नील पर भरोसा नहीं करने देती है। सुषमा घर से दूर रह कर गर्ल्स कालेज में पढ़ाने और घर रूपया भेजने में ही अपने जीवन की पूर्णता मानने को विवश है। सुषमा का अन्तर्मुखी व्यक्तित्व आत्मपीड़न में ही सुखानुभव करने का अभ्यस्त बन गया है। नील का संपूर्ण समर्पण भी उसमें साहस नहीं भर पाता है। अकेलेपन का दर्द उसकी नियति बन गया है। भारतीय समाज की यह स्थिति आज की नहीं है, बल्कि यह पुरुषवादी सोच का परिणाम है। महिला कथाकारों ने इसीलिए लेखनी से अपनी बात रखकर विकृत समाज में बदलाव लाना चाहती है। मैत्रेयी पुष्पा जी ने भी अपनी रचनाओं में जहाँ एक ओर उत्पीड़न, यातना और अपमान का प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण किया है, वहीं उन्होंने आत्मविश्वास और स्वाभिमान जैसी ऊर्जा को अंतर्मन में बिठाने का भी काम किया है। वे रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े वर्चस्वादी समाज को सोते से जगाने का काम बखूबी करती दिखाई देती है। जीवन को परखती-खंगालती उनकी रचनाएँ सामाजिक रीतियों-कुरीतियों के अनेक पक्षों को अपने में समेटे हुए हैं। मैत्रेयी का 'चाक' उपन्यास ग्रामीण परिवेश में स्त्री चेतना को आख्यायित करता है। उपन्यास की नायिका सारंग है। वह अपनी फुफेरी बहन रेशमा की हत्या से विद्रोह हो उठती है। इस गाँव की औरतें पुरुष, अंह, शील और सतीत्व की रक्षा के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती है। इसका वर्णन लेखिका ने इस प्रकार किया है कि- 'इस गाँव के इतिहास में दर्ज दस्ताने बोलती है-रस्सी के फंदे पर झूलती रूखमणी, कुएँ में

कूदने वाली समदेई, करबन नदी में समाधिस्थ नारायणी-ये बेबस औरतें सीता मईया की तरह 'भूमि प्रवेश' कर अपना शील-सतीत्व की खातिर कुरबान हो गई। ये ही नहीं, और न जाने कितनी.....।' मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में ब्राह्मणवादी-सामंतवादी पूँजीवादी, बौद्धिक सोच को तोड़ते हुए वंचित, उत्पीड़ित समूहों-आदिवासी, दलित, पिछड़ी जाति की स्त्रियों के क्षमता को उन्मुक्त और सक्रिय करने पर बल दिया है। इनके उपन्यासों में स्त्री का संघर्ष दरअसल एक ऐसी समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष है जिसमें बराबरी हासिल करने की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ मौजूद हो। इसी तरह से चित्रा मुद्गल की उपन्यास 'नाला सोपारा' प्रभा खेतान की 'अन्या से अनन्या' मधु कांकरिया के उपन्यास 'दलती सांझ का सूरज', मृदुला गर्ग के 'कठगुलाब' साथ ही डॉ. जया वादवानी, डॉ. उर्मिला शुक्ल की कहानियों में भी नारी अस्मिता को लेकर, संघर्ष की आधुनिक समस्याओं को रेखांकित किया गया है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला कथाकारों का साहित्य वर्तमान सामाजिक परिवेश से जुड़ते व्यक्ति के दुखों का साहित्य है। वह जिन्दगी के सही अर्थों में जीने का पर्याय बनकर टुकड़ों में बँटी आदमी की जिन्दगी को जोड़ने का प्रयास करता है। रचनाकारों ने समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपनी लेखनी चलायी है। इनमें समाज के वे तबके शामिल हैं जिन्हें सदियों से उपेक्षित तथा शोषित किया जाता रहा है। महिला कथाकारों ने कथा साहित्य समाज में हो रहे बदलाव के लिए जन संघर्ष के प्रति पूर्ण समर्पित है। इस दौर की महिला कथाकार मुक्ति का मार्ग तलाशती आधुनिक स्त्री जीवन के विविध पहलुओं को परत-दर-परत उकेरती नजर आती है। चाहे वह स्त्री की 'आर्थिक स्वायत्तता' का प्रश्न हो, या 'यौन सुचिता' का प्रश्न हो या स्त्री के अन्तः संबंधों का प्रश्न हो, अथवा उनकी स्वतंत्र सत्ता एवं अस्तित्व का प्रश्न हो, चाहे पुरुष के हवस का शिकार होती स्त्री का प्रश्न हो, या आधुनिक स्त्री का प्रतिक्रियात्मक आक्रोश हो। उनकी पीड़ा, त्रासदी, संत्रास तथा संपूर्ण कष्टपूर्ण जीवन को महिला रचनाकारों ने सर्जनात्मक स्तर पर पुरुष-समाज की स्त्री-विरोधी मूल्य-मर्यादाओं, मिथकों, आदर्शों एवं विधि-निषेधों आदि की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें तोड़ने के लिए अपने कथा-साहित्य में अपने मन तथा विचार के अनुकूल 'स्त्री-पात्रों' को गढ़ा है और लेखन में उन्हें प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। जिससे समाज में नवचेतना का संचार हो।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, डॉ. त्रिभुवन - हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद - पृष्ठ - 31
2. शुक्ला, डॉ. इन्दू - साहित्यकार भागवतीचरण वर्मा - पृष्ठ - 01
3. वर्मा, महादेवी - शृंखला की कड़ियाँ, अपनी बातें से - आमुख
4. यादव, राजेन्द्र, मन्नू भण्डारी - एक इंच मुस्कान - पृष्ठ - 192
5. शिवानी, कृष्ण कली - पृष्ठ - 130
6. मोहन, डॉ. नरेन्द्र - आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ - पृष्ठ - 130
7. सोबती, कृष्णा - सूरजमुखी अँधेरे के - पृष्ठ - 85
8. प्रियंवदा, उषा - पचपन खम्भे लाल दीवारों - पृष्ठ - 26
9. पुष्पा, मैत्रेयी - 'चाक' - पृष्ठ - 07

## महात्मा गाँधी और उनका दर्शन

### डॉ. श्रीमती विन्दू पररस्ते\*

\* सहा. प्रा. (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शा. कला एवं वाणिज्य महा. इन्दौर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** – महात्मा गाँधी ना तो एक दार्शनिक थे जिन्होंने गहन अध्ययन एवं मनन के पश्चात एक सुव्यवस्थित दर्शन प्रस्तुत किया हो ना ही वे एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने राजनीति को राजनीति मानकर एक नेता की भूमिका निभाई हो और न ही वे एक संत थे जिन्होंने इस जगत को मिथ्या मानकर अपने को ब्रह्म में लीन कर लिया हो। किंतु अजीब बात है – वे यह सब कुछ न होते हुए भी यही सब कुछ थे। अपने जीवन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने का अवकाश नहीं था। फिर भी दार्शनिक मुद्रा में कठोर सिद्धांतों का पालन किया। राजनीतिक राजनीतिज्ञ ना होते हुए भी उन्होंने अपने देश और विदेश की राजनीति से हर क्षण सम्बन्ध रखा। गुफावासी संसार त्यागी संत न होते हुए भी मसीहायी अन्दाज प्रखर रहा। उनका सर्व व्यापी व्यक्तित्व अक्षितज फैला रहा तथा उनके कृतित्व में मानव जीवन के हर पहलू को सधिकार आत्मसात किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, संस्कार, संपत्ति, भोजन, चिकित्सा, वाणिज्य, कला, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, विवाह, ब्रह्मचर्य, पठन-पाठन, भाषण, लेखन, सम्पादन, आंदोलन, अहिंसा, सत्य, ईश्वर, धर्म, नीति, नियम, जीवन, मृत्यु, इन सभी विषयों पर उन्होंने चिंतन किया। लोगों ने उन्हें देखा, सुना, पढ़ा, सहमत असहमत हुए, उनका तीव्र समर्थन किया, उनका घोर विरोध किया किंतु प्रेम और श्रद्धा उन्हें जितना मिला, उतना विश्व में किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, क्योंकि उनके विरोधी भी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में प्रेम करते रहे।

राजदर्शन के महारथियों का नाम यदि इस संदर्भ में लिया जाए तो प्लेटो के बजाय सुकरात का नाम निश्चय ही सार्थक होगा- मार्क्स नहीं रूसो अधिक निकट सिद्ध होंगे -रसेल नहीं तालजताप की भाव - भूमि गाँधी जी की अपनी भावभूमि सिद्ध होगी किन्तु इन चिन्तकों का नाम भी गाँधी जी के संदर्भ में लेना न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि गाँधी जी किसी भी रूप में केवल मात्र दार्शनिक नहीं थे। 'मेरा जीवन ही मेरी वाणी है' - कहने वाले गाँधी जी दार्शनिक एवं आंदोलनकर्ता दोनों थे। यदि वे केवल आंदोलन करता होते तो मैजिनी और लेनिन होते, सर्वथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। किंतु गाँधी जी केवल बहिर्मुखी तो नहीं थे वे अंतर्मुखी भी थे और अंतर्मुखी भी इतने की भीषण आंदोलन के दौर में भी 'स्व' को नहीं भूल पाए। वे हर क्षण अपने कड़े टटोलते रहे, खोजते रहे, प्रयोग करते रहे। किंतु यह अंतर्मुखी प्रक्रिया किसी दम्भिक अहमवादी की 'स्व' को निर्मित कर उसे प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया नहीं थी। यह आत्मबोध की प्रक्रिया थी। इस प्रकार की एक प्रक्रिया से लगातार गुजरते रहने के कारण गाँधी जी न तो विशुद्ध बुद्धि

वादी बन सके और न ही एक सन्त की तटस्थता उनमें आरोपित हो सकी। वे बच्चों की तरह खुलकर हंसते थे और संवेदना आने पर खुलकर रोने में भी नहीं हिचकिचाए। करुणा और संवेदना उनमें इतनी थी कि हर किसी का दर्द बाँटने के लिए वह लालायित रहते थे किन्तु अनुशासन में भी इतने कठोर भी थे कि किसी को दण्ड देने में वह नहीं हिचकिचाते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता और विचित्रता के साथ एकसपना एवं अनुशासन को इस प्रकार संजोए हुए था कि उनमें व्यक्तित्व और विचारों के विरोधाभास का चमत्कारी सह -अस्तित्व सर्वथा सहज प्रतीत होता है।

महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सूक्ष्म अध्ययन का यदि प्रयास किया जाए तो उसे पर हजारों पृष्ठ लिखने पर भी संतोष नहीं होगा। श्री तन्दूलकर ने आठ भागों में उनकी जीवनी को उतारा है। किन्तु उसे भी पढ़कर लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। उनके जीवन का हर दिन या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा, हर क्षण इतना महत्वपूर्ण था कि उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कौनसा क्षण छोड़ दिया जाए और कौनसा क्षण ग्रहण किया जाए, एक समस्या बन जाती है। इसलिए गाँधी जी के जीवन का हर पहलू किसी न किसी रूप में किसी दूसरे महापुरुष के समकक्ष रखा जा सकता है। किन्तु अपने ही विचारों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने के लिए स्वयं आंदोलन छेड़ने और उन्हें संचालित करना गाँधी जी के व्यक्तित्व को एक अनुष्ठान प्रदान करता है। इसलिए गाँधी जी का संपूर्ण जीवन हमारे लिए हर पल एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका जीवन मनुष्य के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

गाँधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ लिखा कई संदर्भों में लिखा। इस प्रकार उनका लिखा हुआ साहित्य काफी व्यापक है। किन्तु उन्होंने अपने विचारों को छोटे या बड़े निबन्धों के रूप में या प्रश्नों के उत्तरों के रूप में लिखा। पुस्तक के रूप में उन्होंने काम ही लिखा। इस दृष्टि से यदि हम गाँधी जी द्वारा किए गए साहित्य का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे की मौलिक पुस्तक के रूप में उन्होंने जितना लिखा, उससे कई गुना अधिक उनके विचारों का संकलन प्रस्तुत हुआ। यह एक अजीब बात है कि गाँधी जी ने बहुत कुछ लिखा कई विषयों पर लिखा किंतु अपने दर्शन को क्रमबद्ध रूप में एक थीसिस के रूप में कभी नहीं लिखा। अंतिम दिनों में उनकी श्रद्धा थी कि वह अपने विचारों की थीसिस प्रस्तुत करें किन्तु कर्मयोगी होने के नाते उन्हें जीवन के संघर्षों के ने इतना बांध रखा था कि वे व्यापक व्यापक धरातल पर केवल एकान्तिक लेखन नहीं कर सके। वे अपने विविध कार्यों के बीच में समय निकालकर निबंध लिखते रहे जो अलग-अलग संकलन के रूप में

प्रस्तुत किया है। अतः गाँधी जी द्वारा लिखे गए, साहित्य की कोस मूल रूप में गाँधी जी के बिखरे हुए विचार ही मान सकते हैं। गाँधी जी से संबंधित दूसरे प्रकार का साहित्य, विशाल है जिसमें गाँधी जी के जीवन से संबंधित है और विचारों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त गाँधी जी साहित्य के संबंध में कई बायोग्राफी भी प्रकाशित हुई हैं।

स्वयं गाँधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत अधिक नहीं पढ़ा था किंतु उन्होंने स्वयं अपने द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों को उँगलियों पर गिनाया है किंतु उनकी अपनी मौलिकता एवं सृजनशीलता इतनी प्रखर थी कि वे जो कुछ पढ़ते थे उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया में उस पुस्तक को अपने अनुरूप ढाल लेते थे। इस संदर्भ में उनके जीवन से संबंधित एक संस्मरण प्रस्तुत है। गाँधी जी ने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है- एक बार दक्षिणी अफ्रीका में रेलगाड़ी में सफर करते हुए उन्होंने टरिक्न की लिखी हुई पुस्तक अद्योपांत पढ़ डाली। पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें रात भर चैन नहीं आई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने जीवन को उसे पुस्तक के अनुसार ढालेंगे और उसी के आधार पर उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में अपना प्रसिद्ध 'फोनेक्स आश्रम संगठित किया। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार लुई फिशर ने लिखा है कि टरिक्न की पुस्तक में इतना कोई चमत्कार नहीं था कि किसी के जीवन को रातों-रात बदल दे। यह तो गाँधी जी की विशेषता थी कि जब किसी पुस्तक को पढ़ते थे तो केवल उसमें पाठक नहीं बने रहते थे बल्कि उसमें सह लेखक की भी बन जाते थे और जो कुछ भी उसमें लिखा होता उसे अपनी कल्पना से जोड़ लेते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तक को पढ़ने में अंतर होता है इसलिए विद्वान के लिए यह आवश्यक होता है कि वह जो कुछ पढ़े उसे पर अपनी मौलिकता की छाप भी छोड़ दें।

यूँ तो थोड़ा विरोध हर विचारक में होता है विशेषताया ऐसे विचारक में जो एक लंबे समय तक विचारों की बुनियाद में चिंतन मनन होता है कभी-कभी जो विचारक पहले जो बात करता है उसे बात में बदल देता है कभी पहले जिम मान्यता को उसने प्रतिबद्धित किया है उसे मान्यता को बाद में अस्वीकार कर देता है। गाँधी जी के लेखन में यह प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही है इसलिए उन्हें अक्सर विरोधाभासी विचारक कहा जाता है। समय-समय पर गाँधी जी के सामने ही उन पर यह आरोप लगाया गया है कि इसके प्रतिउत्तर में गाँधी जी की स्वीकारोक्ती बड़ी यांत्रिक है। उन्होंने यही मान्यता प्रतिपादित की है कि वे एक सत्यार्थी हैं। इस नाते वे हमेशा, हर घड़ी सत्य का अन्वेषण कर रहे हैं सत्य के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे सत्यों के बीच से गुजरते हैं। उनका आज का सत्य निश्चय ही कल का सत्य है। यह सत्य अनुभव जन्म सत्य है, चरम सत्य नहीं। इसलिए हो सकता है कि कल का

सत्य आज के सत्य को अस्वीकार कर दे और उस समय गाँधी जी विगत सत्य के साथ जिद के कारण चिपके रहे वे सत्य के अन्वेषक हैं। सत्य का उनका अन्वेषण ही उन्हें इस बात पर अधिक अमादा करता है कि उन्हें यदि विगत कल के कथन का प्रतिवाद करना पड़े तो उन्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए।

महात्मा गाँधी जी के जीवन के शुरुआती दौर से लेकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनने तक के सफर के बारे में उनसे बेहतर आखिर कौन जान सकता है। ऐसे उनकी लिखी अमूल्य किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज का मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन करती है। इस पुस्तक को 1920 में खत्म किया गया। इस दौरान गाँधी जी एक चर्चित व्यक्ति बन चुके थे। गाँधी जी ने इस पुस्तक का नाम सत्य के प्रयोग इसलिए रखा है कि क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और अभियानों में सत्य के प्रयोग यानी सत्याग्रह के जारिये सभी लड़ाईयाँ लड़ी। इस पुस्तक को गाँधी जी ने गुजराती में लिखा हिंदी में यह पुस्तक गाँधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के नाम से जानी जाती है। हिंद स्वराज महात्मा गाँधी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इस किताब को भी गाँधी जी गुजराती भाषा में लिखा है। इसलिए गाँधी जी ने विदेशी सभ्यता संस्कृति की आलोचना की है। साथ ही मौजूदा समय में मानवता की समस्याओं के बारे में भी बताया है। इस किताब की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह प्रश्न उत्तर के प्रारूप में लिखी गई है। इसमें कानूनी पेसे से संबंधित वकीलों, डॉक्टरों तथा रेलवे से जुड़े लोगों और उनके विचारों के बारे में लिखा गया है।

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह का जो मार्ग अपनाया वह केवल राजनीति में ही नहीं मनुष्य के सारे कार्यकलापों के साथ बंधा हुआ है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, प्रादेशिक राष्ट्रीय जीवन में, सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। गाँधी जी के जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं, जब उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों में सत्याग्रह का प्रयोग किया है, और सफल भी रहे हैं। इतिहास में हमें कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महात्मा गाँधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग
2. डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य - गाँधी दर्शन
3. गाँधी, हिज लाइफ एंड मैसेज फॉर दी वर्ल्ड - लुई फिशर
4. माय फाउंड नो पीस - वेब मिलर

\*\*\*\*\*



## भारतीय जनता पार्टी में धार जिले की जनजातीय महिला नेतृत्व की भूमिका

दयाराम डावर\* डॉ. ममता पाण्डेय\*\* डॉ. सीमा सरस्या\*\*\*

\* शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, जयसिंह नगर, शहडोल (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, जयसिंह नगर, शहडोल (म.प्र.) भारत

\*\*\* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शास. महाविद्यालय, अमरपुर, डिण्डौरी (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जिले में जनजातीय क्षेत्रीय पंचायतों और राज्य विधानसभा की आरक्षित सीटों का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश के जिलों में भाजपा ने जनजाति समाज के मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियाँ तैयार की हैं, और यहाँ की जनजातीय महिलाओं को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है।

भारत में जनजाति समुदाय की विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान रही है। जनजाति समुदाय लंबे समय तक मुख्यधारा की राजनीति और समाज से अलग-थलग रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में जनजाति समुदाय की भागीदारी और विशेष रूप से जनजाति महिला नेतृत्व का महत्व बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जनजाति समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से महिलाएं, अब अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में उभर रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिला पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से भील, पंवार और अन्य जनजातियों का गढ़ है। इस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय पंचायतों, राज्य विधानसभा और लोकसभा की आरक्षित सीटों का विशेष महत्व है। धार जिले में भाजपा ने जनजाति समाज के मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियाँ तैयार की हैं, और यहाँ की महिला को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है।

**शब्द कुंजी** - भाजपा, राजनीति, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक, जनजाति, महिला सशक्तिकरण।

**प्रस्तावना** - भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जनजाति महिला नेतृत्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में जहाँ जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण संख्या है, भारतीय जनता पार्टी ने समय-समय पर इन समुदायों के बीच नेतृत्व को प्रोत्साहित किया है। मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय का प्रभाव चुनावी राजनीति में विशेष है। राज्य में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के लिए एक रणनीतिक अवसर है। भाजपा ने विशेष रूप से इन समुदायों में महिला नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, ताकि वे अधिक प्रभावी रूप से इन समुदायों के मुद्दों को उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के नारे के तहत जनजाति महिलाओं को मंच देने का प्रयास किया।

मध्यप्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के धार जिला जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी जनजाति समुदाय में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवार बुजुर्ग महिला मुखिया होती हैं। भारत देश वास्तव में एक विविधतापूर्ण और विशाल राष्ट्र है, जिसमें गावों की एक बड़ी संख्या है, और जनजातियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के विभिन्न हिस्सों में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातियों की बड़ी आबादी बसती है। भारत में जनजाति समुदाय की विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान रही है। जनजाति समुदाय लंबे समय तक मुख्यधारा की राजनीति और समाज से अलग-थलग रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में जनजाति

समुदाय की भागीदारी और विशेष रूप से जनजाति महिला नेतृत्व का महत्व बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जनजाति समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से महिलाएं, अब अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में उभर रही हैं।

भारत में महिलाओं के प्रति आदर का भाव रहा है उन्हें देवी और शक्ति की उपमा दी गई है। वह परिवार में स्नेहमयी दुलारी बनी है तो माता के रूप में ममतामयी और वात्सल्य की प्रतिभूति धर्मपत्नी के रूप में पति की अनुगामिनी सहचरी, सहयोगी और मार्गदर्शिका आदि सही अर्थों में यह परिवार की धूरी है। कहा गया है कि नारी धरती जैसा फर्ज निभाती है और अपने अंक में समुद्र जैसी ममता समेटे आकाश हो जाती है। महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिये सर्वप्रथम उन्हें विकास के बारे में जाग्रत करना होगा सदियों से होती आ रही बालिकाओं की उपेक्षा और उनके प्रति भेदभाव एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता है लेकिन सभ्य समाज के सहयोग से देशभर में उनकी शिक्षा का स्तर उँचा उठाने की योग्यताएँ यदि सावधानी पूर्वक बनायी जायें तो स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य ही संभव है। आज की महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखा रही हैं। सामाजिक, आर्थिक व्यवसायिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों में उपलब्धियाँ बढ़ी है। आज वे किसी भी सम-सामयिक विषय पर किसी भी व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक चर्चा कर सकती है। उसने अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्याग कर अपने में आत्मविश्वास पैदा कर लिया

है। आज महिलाएँ अपने दोहरे रूप को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं। एक तरह वह कैरियर वूमन का खिताब हासिल किये हुये हैं तो दूसरी और होम मेकर के रूप में घर गृहस्थी की तमाम जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहण कर रही हैं।

वर्तमान में महिला सही मायने में आधुनिक हैं, उन्होंने अपनी सामान्य दुर्बलताओं को दूर करके अपने आपको मजबूत करने अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करने और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है। केन्द्र सरकार ने महिलाओं के चहुंमुखी विकास के लिये वर्ष 2001 के 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' घोषित किया। इसमें महिलाएँ अधिक सशक्त हैं, तो ऐसा ध्येय रखा गया। हाल के वर्षों में महिलाओं ने अपनी विशेष पहचान इस समाज के सामने प्रस्तुत की है, जिसमें वह साहसी, परिपक्व, सहिष्णु और एक मजबूत इरादे वाली महिला के रूप में उभर कर सामने आयी हैं।

मध्यप्रदेश में धार जिला पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से भील, पंवार और अन्य जनजातियों का गढ़ है। इस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय पंचायतों, राज्य विधानसभा और लोकसभा की आरक्षित सीटों का विशेष महत्व है। धार जिले में भाजपा ने जनजाति समाज के मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियों तैयार की हैं, और यहाँ की महिला को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है।

**शोध प्रविधि** – प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के धार जिले पर आधारित है। उक्त जिले का चयन सविचार निदर्शन विधि के आधार पर चयन किया गया है। 'भारतीय जनता पार्टी में धार जिले की जनजातीय महिला नेतृत्व की भूमिका' का अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों पर आधारित है। **द्वितीयक समंक** : द्वितीयक समकों का संकलन, पुस्तकों, पत्र-पत्रिका, जिला सांख्यिकी विभाग, तहसील कार्यालय, विकासखण्ड, कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय रिपोर्ट, इंटरनेट से प्राप्त सामग्री एवं संबंधित विषय में विगत वर्षों से प्रकाशित लेखों इत्यादि से समकों का संकलन किया गया है।

**प्राथमिक समंक** : प्राथमिक समकों का संकलन धार जिले में 13 विकासखण्ड, 7 विधानसभा पद, 1 संसद सदस्य, 761 ग्राम पंचायत, नगर परिषदों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न राजनीतिक दलों की महिला कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों में देव निदर्शन विधि द्वारा जनजातीय महिलाओं नेत्रियों का चयन किया। देव निदर्शन विधि से चयनित जनजातीय महिला उत्तरदाताओं से राजनीति में भूमिका एवं ग्रामीण विकास के अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर ग्रामीण विकास में जनजातीय महिलाओं की भूमिका सम्बन्धित समंक संकलित किये गए।

**जनजाति महिलाओं की पंचायत में नेतृत्व** – जनजाति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सभी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होना, स्वैच्छिक रूप से निर्णय लेना, यंत्र के रूप में, निर्णय निरूपण तथा क्रियान्वयन रूप एवं किसी कार्य की सहमति देना या सहमति न देना आदि गतिविधियों में सम्मिलित हैं। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक राजनितिक संरचना सहभागिता के मूल्य पर आधारित है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रदान किया गया है। समाज के निर्बल वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को राजनीतिक सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाओं को मुख्य रूप से अपनाया गया है। प्रथम, अनुसूचित जनजाति समुदाय की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए शैक्षणिक कल्याण की योजनाएं अपनायी गयी हैं। द्वितीय, सरकारी

नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अधीन लोकसभा, विधानसभा एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के कुछ स्थानों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 16 प्रतिशत के लगभग जनजाति महिलाएं प्रतिनिधि बन कर नेतृत्व कर रही हैं।

**भाजपा में आदिवासी महिला नेतृत्व की नयी समीकरण** – भाजपा गढ़ रही नए समीकरण के माध्यम से आदिवासी जनजाति महिलाओं को नेतृत्वकी नयी अवसर मिल रही हैं। भाजपा को जीत का पर्याय बनाने के लिए जनाधार बढ़ाने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपना ही अंदाज है। जो वर्ग सियासत के लिए कमजोर माने गए, उन्हीं को मजबूत कर भाजपा चुनावी बाजी पलटने के लिए माहिर माने जाते हैं। ऐसा ही एक वर्ग इस लोकसभा, विधानसभा एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उभर कर सामने आया है, जिसे ताश कर मोदी भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। राजनीति में दशकों तक उपेक्षित आदिवासी वर्ग की राजनीतिक पार्टीयों द्वारा पूछ-परख तो बढ़ी, पर इस जनजाति वर्ग की महिलाओं को अधिक मौका देकर भाजपा नए समीकरण गढ़ रही हैं। आदिवासी जनजाति बहुल राज्य मध्यप्रदेश हो या झारखण्ड, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भी प्रवास पर जाते हैं, तो आदिवासी जनजाति महिलाओं से संवाद अवश्य करते हैं उनकी जीवन शैली, संस्कृति, कला और परंपराओं से न केवल रुबरू होते हैं, बल्कि अपने अनुभव साझा कर उन्हें प्रभावित करने में भी सफल रहते हैं। जनजाति महिलाओं के बीच ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा, जब प्रधानमंत्री ने उनके गांवों तक पहुंच कर मुलाकात की हो। मध्यप्रदेश में विशानसभा चुनाव से पहले शहडोल आए प्रधानमंत्री मोदी ने गोंड (कोयतोर), कोल और बैगा वर्ग की महिलाओं के साथ संवाद किया था। लोकसभा से पहले झाबुआ आए थे तो विलुप्त हो रही विशिष्ट पिछड़ी जनजाति सहरिया महिलाओं से बातचीत की थी। तब मोदी की दूरदृष्टि का अंदाज किसी को नहीं था। आदिवासी वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करने का यह तरिका कोई भाप नहीं सका था।

**भाजपा राजनीति में जनजाति महिला नेतृत्व का योगदान:**

1. भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जिसमें जनजाति महिलाओं की महत्वपूर्ण योगदान है।
2. जनजातीय महिलाओं को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है।
3. भारत में जनजाति समुदाय की विशेष रूप से प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान रही है।
4. भारत देश में जनजाति समुदाय मूलतः गांवों में निवास करने वाली होती हैं। यह जनजाति समुदायों में महिला प्रधान या नेतृत्व युक्त परिवार होती हैं।
5. भाजपा राष्ट्रीय समानता, एकता और अखण्डता के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। भाजपा ने यह जनजाति महिला नेतृत्व को मुख्यधारा में लाने के लिए हमेशा से आगे रही है।
6. आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

**जनजातीय महिला नेतृत्व का समीक्षात्मक विश्लेषण :**

1. जनजातीय महिला प्रतिनिधियों के क्षेत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व की स्थिति।

2. जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों की यामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विश्लेषण करना।
3. शिक्षण संस्थाओं में जनजाति महिलाओं नेतृत्व से सामाजिक स्तर में परिवर्तन करना।
4. पंचायत राज संस्थाओं में जनजाति महिला नेतृत्व की सहभागिता व सक्रियता का विश्लेषण करना।
5. त्रिस्तरीय पंचायती राज की कार्यप्राणली में जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषण करना।

**जनजातीय महिला नेतृत्व की आवश्यकता** – भारत की विभिन्न जातियों तथा समाजों में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी हुई है। महिलाएँ अपने जीवन में परिवार तथा समाज से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करना तथा परिवर्तनों पर जनजाति महिला नेतृत्व की चिन्तन के द्वारा मार्ग प्रस्तुत करना ही शोध प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है। केन्द्र तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित हैं जैसे संपूर्ण साक्षरता अभियान, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, अनुपूरक सम्पोषण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला बाल एवं विकास कार्यक्रम के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक संगठनों जैसे महिला मण्डल युवा क्लब स्वावलंबी समूह आदि संस्थाओं को प्रोत्साहित कर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। यद्यपि शासन सभी वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सक्रिय है। फिर भी लाभान्वित हो सकने वाली महिलाओं का विकास कार्यक्रमों से जुड़ने के प्रति रुझान कम है इस तथ्य को ध्यान में रखकर उक्त शोध का उद्देश्य धार जिले की जनजातीय महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तनों की जाँच करना तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की स्थिति का अध्ययन करना तथा महिला जनजातिप्रतिनिधियों के जीवन स्तर में आये बदलाव का विश्लेषण करना है।

**वर्तमान स्थिति** – वर्तमान समय में आज भाजपा प्रदेश एवं देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है और विभिन्न प्रदेशों एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है। 12 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी में जनजाति महिलाओं की नेतृत्व भारतीय राजनीति में भागीदारी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। भाजपा नीतिगत राजनीति के माध्यम से समिति, संगठनों, त्रिस्तरीय पंचायत, विधानसभा और लोकसभा में जनजाति महिलाओं के द्वारा प्रत्येक में नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। जनजातीय महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक तरफ जहाँ भाजपा सरकार ने इस समाज की महिला को राष्ट्रपति पद पर विराजमान किया। वहीं दमसरी ओर प्रदेश स्तर पर भी इस समाज से जुड़ी हुई महिलाओं को बड़े स्तर सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। इनमें जनजातीय राजनैतिक भागीदारी, जनजातीय महिलाओं पर विभिन्न योजनाओं का प्रभाव, प्रवासन और सामाजिक – सांस्कृतिक रूप से जनजातियों को किस प्रकार प्रभावित करता है।

**निष्कर्ष** – भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो भारत को एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित

करने के लिए कृतसंकल्प है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जिले में जनजातीय क्षेत्रीय पंचायतों और राज्य विधानसभा की आरक्षित सीटों का विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश के जिलों में भाजपा ने जनजाति समाज के मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियाँ तैयार की हैं, और यहाँ की जनजातीय महिलाओं को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है।

भारत में जनजाति समुदाय की विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान रही है। जनजाति समुदाय लंबे समय तक मुख्यधारा की राजनीति और समाज से अलग-थलग रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में जनजाति समुदाय की भागीदारी और विशेष रूप से जनजाति महिला नेतृत्व का महत्व बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जनजाति समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से महिलाएँ, अब अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में उभर रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिला पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से भील, पंवार और अन्य जनजातियों का गढ़ है। इस जिले में जनजातीय क्षेत्रीय पंचायतों, राज्य विधानसभा और लोकसभा की आरक्षित सीटों का विशेष महत्व है। धार जिले में भाजपा ने जनजाति समाज के मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियाँ तैयार की हैं, और यहाँ की महिला को विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता का अवसर दिया गया है। जिससे धार जिले की जनजाति महिलाएँ अपने क्षेत्रिय मुद्दों और शासकीय योजनाओं को अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा जन समुदाय एवं समाज के लोगों तक पहुंचाने का कार्य बखूबी निभा रही हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, डॉ, गायत्री एवं चर्मकार, बेबी (2022), भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास, ijrrss 0(4); अक्टूबर-दिसंबर, 2022.
2. वाजपेयी, अटल बिहार (1996), अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ भाषण और कुछ लेख, दिल्ली, 1996, 4अ - 225.
3. Constitution and Rules Of Bharatiya Janta Party (New Delhi A BJP Publication) 1984.
4. Sisodia, Yatindra Singh and Jha Sumit Kumar (2024); Explaining the BJP's Triumph in the 2023 Madhya Pradesh Electons, Economic & Political weekly EPW (2024), Vol. Lix No. 13.
5. अहुजा, गुरुदास (1996); भारतीय राजनीति भाजपा का आगमन दिल्ली 1996, पेज - 241
6. वैद्य, नरेश कुमार (2023); 'जनजाति विकास' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
7. श्रीवास्तव, अरुण कुमार (1994) : भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 71
8. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000): पंचायतीराज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ 48।
9. सिंह, लता (1995): 'विकास में महिलाओं की भागीदारी' कुरुक्षेत्र।
10. उपाध्याय, हेमंत कुमार (2024): 'आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, भाजपा के नयी समीकरण' नई दुनिया, मार्च, 2024।

## कार्यक्षेत्र में तनाव प्रबंधन का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉ. आराधना श्रीवास\*

\* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – तनाव प्रबंधन कार्यक्रम कर्मचारियों को तनाव की प्रकृति और स्रोतों, स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों और तनाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत कौशल के बारे में सिखाते हैं-उदाहरण के लिए, समय प्रबंधन या विश्राम अभ्यास। कार्यस्थल का तनाव आज की तेज रफतार जीवनशैली में एक आम समस्या बन गया है। यदि इसका सही प्रबंधन न किया जाए तो यह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तनाव प्रबंधन की उचित रणनीतियाँ अपनाने से व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक तनाव प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों का विश्लेषण करना है।

**प्रस्तावना** – 'स्वास्थ्य मानव जीवन की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व मानसिक निरोगता व सामान्यता की स्थिति है।'

प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन स्वस्थ एवं सामान्य बनाये रखने के लिये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का निरन्तर सहारा लेना पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से ही व्यक्ति समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं, अर्न्तद्धन्दों तथा परेशानियों से बचकर निकल सकता है। अपने जीवन को सुखमय, शान्तिमय तथा समायोजित बनाने के लिये हम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

**विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार** – 'स्वास्थ्य सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक निरोग्यता की अवस्था है तथा मात्र बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं माना जा सकता।'

तनाव मनोवैज्ञानिक, जैविक एवं पर्यावरणीय कारणों से उत्पन्न होता है जो दीर्घकालिक रूप से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अवसाद एवं चिन्ता जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में कार्यशील आयु वर्ग के लगभग 15 वयस्क किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रस्त थे। इसके परिणामस्वरूप, हर वर्ष अवसाद और चिन्ता के कारण वैश्विक स्तर पर अनुमानित 12 अरब कार्य दिवसों का नुकसान होता है, जिससे उत्पादकता में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होती है।

ब्रटेन में 2023-24 के दौरान कार्य संबंधित बीमारियों के कारण प्रति व्यक्ति औसतन 17.7 कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। विशेष रूप से तनाव, अवसाद या चिन्ता के मामलों में यह औसत 21.1 दिन प्रति व्यक्ति था।

इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन न केवल कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह संगठन की उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। उचित तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जबकि तनाव के उच्च स्तर से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

**कार्य तनाव** – छोटी मात्रा में तनाव आपको समयसीमा को पूरा करने और काम पर लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि, जब काम से संबंधित तनाव पुराना हो जाता है, तो यह चिन्ता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और हृदय रोग और उच्चचाप जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।

**कार्य क्षेत्र में तनाव-प्रबंधन** – स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यवसाय से सदैव सन्तुष्ट नहीं रहता है। यदि देखा जाये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवसाय का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण विशेष महत्व रखता है। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय से सन्तुष्ट नहीं है वह किसी दशा में अपने आपको स्वस्थ नहीं रख सकता। वास्तव में व्यवसाय से सन्तुष्ट होने के लिये एक विशेष प्रकार का रूख अपनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति को अपना व्यवसाय आनंदमय प्रतीत होता है, वह व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट होता है। यदि किसी व्यक्ति के लिये उसका व्यवसाय केवल धन उपार्जन का साधन मात्र है तो वह व्यक्ति वास्तव में अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं माना जायेगा। इस प्रकार का व्यवसाय कुछ समय बाद बोझ प्रतीत होने लगता है। अपने व्यवसाय से असन्तुष्ट व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो जाता है।

**तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव** – वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस तनाव से मुक्त हो। तनाव अपने आप में अच्छा है न बुरा। यह सिर्फ जीवन की सच्चाई है, अनुसंधान बताता है कि तनाव की चिरकालिक अधिकता रोग पूर्व की स्थिति है प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक जीवन शक्ति दी है। जो सदा बीमारी रोकने और हमें स्वस्थ रहने में लगी हुई है। यह जीवन शक्ति कार्य करना बंद कर देती है जैसे ही तनाव साधारण सीमाओं से अधिक हो जाता है अतः तनाव की अधिकता तुरन्त रक्तचाप और हृदय गति की अधिकता, रक्तप्रभाव में वसा युक्त अम्लों और शर्कराओं के घामिल होने, माँसपेशियों के तनाव, पाचन प्रक्रिया में उपद्रव आदि उत्पन्न कर देती है।

1. हाइपोथैलेमस से एडोनेलिन व कार्टिसोल का अधिक स्रावण रक्त	1. पुतलियों का फैलना।
--	-----------------------

में होना।	
2. माँसपेशियों में अधिक रक्त पहुँचना।	2. फेफड़ों में श्वसन दरका बना।
3. एडिनल ग्रन्थि द्वारा अधिक एडिनेलिन हार्मोन का स्राव।	3. अत्यधिक पसीना ग्रन्थियों द्वारा स्राविक होना हृदय दर का बढ़ना।

### शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

**हृदय स्वास्थ्य** - लंबे समय तक तनाव रहने से रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है।

**प्रतिरक्षा प्रणाली** - दीर्घकालिक तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

**मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव**- मानसिक अस्वस्थता व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति या दशा है जिसमें उसका व्यवहार एवं कार्य असामान्य हो जाते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित तथा असन्तुलित हो जाता है ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में समायोजन नहीं कर पाता। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असफल रहता है परन्तु समय सामान्य रूप से वह अपनी असफलताओं का जिम्मेदार अपने आप को नहीं स्वीकार करता, ऐसा व्यक्ति अपनी समस्त असफलताओं का दोष अन्य लोगों के सिर मढ़ता है तथा परिस्थितियों को प्रतिकूल कहकर स्वयं को दोष मुक्त करने का प्रयास करता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अपने मुख्य व्यवसाय को न तो अधिक महत्व देता है और न ही उसमें रुचि ही लेता है।

**कार्यभार प्रबंधन**- अत्यधिक कार्यभार मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रबंधनीय कार्यभार वाले कर्मचारी, काम से अभिभूत कर्मचारियों की तुलना में 27 बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं।

**कार्यस्थल संस्कृति**- सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। प्रबंधकों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर 33 अधिक होते हैं।

**कार्यक्षेत्र पर तनाव** - हम अनेक कारणों से तनाव का अनुभव कर सकते हैं।

1. यदि अनुपस्थिति की दर अत्यधिक हो।
2. अपने सहकर्मी आपकी अंतर्क्रिया अथवा अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध ठीक न हो।
3. संस्थान में सुरक्षा की कमी हो।
4. गुणवत्ता नियंत्रण उचित न हो।
5. कार्य, उलझन, कार्य से असन्तुष्टि, पदोन्नति के अवसर का न होना।
6. संप्रेषण के उचित तरीकों का विकसित न होना।

**लक्षणों की पहचान**- एकतनाव ग्रसित व्यक्ति अनेक लक्षणों से ग्रसित हो सकता है।

शारीरिक लक्षण	सांवेगिक लक्षण
1. अनिद्रा अति सांवेगिक अथवा	
2. निरन्तर थकान महसूस करना	आक्रमकता अव्यवस्थित रहन-
3. सिर दर्द	सहन अवधान केंद्रण में कमी
4. त्वचा रोग	
5. पाचन सम्बन्धी बीमारियाँ	अवसाद पश्चाताप,
6. अल्सर	असफलता के मनोभावों
7. भूख न लगना	की उपस्थिति आत्मविश्वास
8. अत्यधिक खाना में कमी।	
9. शरीर में दर्द	

### व्यवहारिक लक्षण:

1. सिगरेट अथवा शराब का अत्यधिक सेवन।
2. चाय कॉफी के सेवन में वृद्धि।
3. तम्बाकू का सेवन इत्यादि।

**कार्यस्थल पर तनाव के कारण** - काम से संबंधित तनाव कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है और तनाव कारक व्यक्तिगत कर्मचारियों, टीम की गतिशीलता, कंपनी की संस्कृति और समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। दीर्घकालिक तनाव और विशाक्त तनाव नकारात्मक कार्य वातावरण, उच्च टर्नओवर दरों, काम के दौरान उपस्थित न होने और कंपनी के लिए कम दक्षता का कारण बन सकते हैं।

**1. चुनौती या संलग्नता का अभाव**- यदि आपको लगता है कि आपके कौशल और प्रतिभा का कम उपयोग किया जा रहा है, तो आप ऊब, असंलग्नता और संतुष्टि की कमी से जूझ सकते हैं।

**2. अस्पष्ट प्रदर्शन अपेक्षाएँ**-जब आपको यह स्पष्ट नहीं होता कि आपसे क्या अपेक्षित है, तो इससे भ्रम, चिंता और तनाव हो सकता है। आपसे जो अपेक्षित है और आप जो करने में सक्षम महसूस करते हैं, उसके बीच भी बेमेल हो सकता है।

**3. नियंत्रण की कमी**-कार्य प्रक्रियाओं या परिणामों पर कम या कोई नियंत्रण न होने से तनाव का स्तर बढ़ सकता है।

**4. कम वेतन**-ऐसा वेतन जो कार्यभार, अपेक्षित कौशल स्तर या उद्योग मानकों को प्रतिबिंबित नहीं करता, वित्तीय तनाव का कारण बन सकता है, जो कार्यसंबंधी तनाव को और बढ़ा देता है।

**5. अत्यधिक कार्यभार**-लंबे समय तक काम करना, अवास्तविक समय सीमाएँ और लगातार पीछे रहने की भावना आपको परेशान कर सकती है, जिससे थकान, उत्पादकता में कमी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

**6. विकास के सीमित अवसर**- विकास के कम अवसर आपको अटका हुआ और कम मूल्यवान महसूस करा सकते हैं, जिससे निराशा और अलगाव पैदा हो सकता है।

**7. अनिश्चितता**-अपनी नौकरी में क्या अपेक्षा की जाये, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा या भविष्य की संभावनाएं, यह न जानना तनावपूर्ण हो सकता है।

**8. संघर्ष**-कार्य वातावरण में सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों के साथ पारम्परिक संघर्ष बहुत अधिक भावनात्मक स्थान ले सकता है।

**9. समर्थन की कमी**-समर्थन की कमी से आप अलग-अलग और परेशान महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है।

**10. कार्य जीवन असंतुलन**-अपने निजी जीवन के साथ व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना कठिन हो सकता है।

**तनाव से निपटने की रणनीतियाँ**- व्यक्ति के लिये उत्तम शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य संबंधी उपायों एवं नियमों का पालन करना आवश्यक है उसी प्रकार मानसिक विकास तथा स्वास्थ्य की रक्षा तथा संवृद्धि के लिये उपायों का ज्ञान व पालन करना अति आवश्यक है।

**1. समस्या केन्द्रित समायोजी उपाय**- इस तरह के उपायों में व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति या समस्या का मूल्यांकन करता है।

● **नियंत्रण उपाय**- जब व्यक्ति तनावपूर्ण घटना पर नियंत्रण कायम करने में सफल होता है तो तनाव की गंभीरता स्वतः कम हो जाती है।

● **पूर्वकथन उपाय**- इसके लिये समाधान के अनेकों विकल्प पहले से

खोज कर रखे जाते हैं।

**2. संवेग केन्द्रित उपाय-** इस तरह के उपाय में व्यक्ति समस्या से उत्पन्न सांवेगिक अनुक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करता है।

● **व्यवहारात्मक उपाय-**व्यक्ति खास तरह के व्यवहार करके अपना तनाव दूर करने का प्रयास करता है।

● **संज्ञानात्मक उपाय-**इसमें तनावपूर्ण परिस्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

**निष्कर्ष-** तनाव के कारण शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से अवगत है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक तनाव के आधार पर शरीर में ऐसे परिवर्तनों को मापना आसान है, जैसे कि हृदय गति, चयापचय परिवर्तन, श्वसन पद्धति, त्वचा की समस्याएँ आदि। तनाव से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण रोग और बीमारी की अधिक घटनाएँ होती हैं। इसमें हृदय रोग, संज्ञान संबंधी हानि, टाइप 2 मधुमेह आदि शामिल हैं। कई अध्ययनों ने कार्यस्थल पर तनाव को अस्थमा, पेट के अल्सर, शराब और तंबाकू के दुरुपयोग और अनिद्रा से भी जोड़ा है।

न केवल शारीरिक परिणाम बल्कि मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है जो दीर्घकालिक तनाव के कारण समान रूप से समस्या है। अवसाद और चिन्ता सामान्य मनोवैज्ञानिक विकार हैं, जो इस सदी की पीढ़ी में विकसित हो रहे हैं। अवसाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति उदासी और निराशा की अनुभूति करता है। चिन्ता किसी भी अज्ञात चीज के बारे में आशंका या घबराहट की सामान्य स्थिति है। ये दोनों समस्याएँ लंबे समय तक तनाव के कारण मस्तिष्क रसायन विज्ञान में परिवर्तन के कारण होती हैं। चिंतन भी एक अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो तनाव के कारण होती है। यह पिछली घटनाओं के बारे में सोचना बंद करने और उनके बारे में निरंतर सोचने की असमर्थता है। अतीत के बारे में निरंतर सोचने से भविष्य की मनोदशा प्रभावित हो सकती है। अफवाह तनाव के स्तर में और वृद्धि करती है। यहाँ तक कि निराशा और उत्तेजना भी कार्यस्थल तनाव के सामान्य मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं। लंबे समय तक थकावट और कार्यक्षेत्र में रूचि में कमी से बर्नआउट होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति जिस काम में संलग्न है वह ऊर्जा के निम्न स्तर या नौकरी में असंतोष की भावनाओं के कारण नौकरी की मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं होता है।

कार्यस्थल में तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सही तकनीकों और आदतों को अपनाकर हम न केवल कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। कार्यस्थल पर तनाव को सही ढंग से प्रबंधित करना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

**कार्यक्षेत्र में तनाव प्रबंधन के सुझाव:**

1. **समय प्रबंधन-**कार्यों को प्राथमिकता दें, यथार्थवादी समय सीमाएं

निर्धारित करें और बड़ी परियोजनाओं को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। अपने कार्यभार को व्यवस्थित करने में मदद के लिए कैलेंडर का और सूचियों का उपयोग करें।

2. **विश्राम तकनीकें-**तनावपूर्ण स्थितियों में मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम और निर्देशित कल्पना जैसी तकनीकों का अभ्यास करें।

3. **शारीरिक गतिविधि-**व्यायाम आपके मूड को बेहतर बना सकता है, नींद में सुधार कर सकता है और चिन्ता, अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है। तनाव को दूर करने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए पैदल चलना, दौड़ना, योग या टीम स्पोर्ट्स आजमाएँ।

4. **सामाजिक समर्थन-**तनावपूर्ण समय में भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक मदद के लिए मित्रों, परिवार और सहकर्मियों का एक सहायक नेटवर्क बनाएं और उसे बनाए रखें।

5. **सकारात्मक सोच-**अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपको तनाव से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें और समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करें।

6. **स्पष्ट संचार प्रदान करें-**नियमित प्रतिक्रिया और स्पष्ट अपेक्षाएं अनिश्चितता को कम कर सकती हैं और आत्मविश्वास का निर्माण कर सकती हैं।

7. **प्रतिस्पर्धी वेतन प्रदान करें-**उचित वेतन वित्तीय तनाव को कम कर सकता है और मनोबल में सुधार कर सकता है।

8. **कार्यभार की संतुलित करें-**कार्य को पर्याप्त रूप से वितरित करने और उच्च मांगों को प्रबंधित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने से बर्नआउट को रोका जा सकता है।

9. **विकास के अवसर सृजित करना-**उन्नति के लिए स्पष्ट मार्ग विकसित करना तथा प्रशिक्षण और विकास के विकल्प प्रदान करना कर्मचारियों को प्रेरित और संलग्न कर सकता है, जिससे नौकरी से संतुष्टि में वृद्धि होगी।

10. **सहायक वातावरण का निर्माण करें-**टीमवर्क को प्रोत्साहित करना, सहायता प्रणालियां प्रदान करना तथा सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना, कर्मचारियों को मूल्यवान और समर्थित महसूस करने में मदद कर सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. महेश भर्गव 'शिक्षा मनोविज्ञान' पेज नं. 231-.239
2. श्री जागरन, 'तनाव दूर करने के लिए सोच बदले' 12 जुलाई 2022
3. श्री अरुण कुमार सिंह, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जावाहर नगर, दिल्ली।
4. श्री आर. डी. सिंह, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, जगदम्बा पब्लिशिंग कम्पनी, दरियागंज, नई दिल्ली।
5. डॉ. मयूरनाथ रेड्डी, मानसिक रोगों की चिकित्सा, 06 फरवरी 2023

\*\*\*\*\*

## भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री विमर्श

श्रीमती अनीता अग्रवाल\*

\* पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खंडवा(म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – स्त्री विमर्श समकालीन साहित्य की महान उपलब्धी है। यह महिलाओं को मिले लोकतान्त्रिक अधिकार शिक्षा और स्वावलम्बन का परिणाम है, इसका श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है। इस विमर्श में नारी जीवन के उन पक्षों को प्रस्तुत किया है जिनकी चर्चा से साहित्य और समाज विज्ञान में परहेज किया जाता था। स्त्री विमर्श सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु पूरी दुनिया इसके दायरे में है जहाँ स्त्रियाँ अपनी पीड़ा और समस्या को ही नहीं व्यक्त कर रही बल्कि अपनी शक्ति की समीक्षा भी कर रही हैं। भारतीय चिंतन को नई धारा देने में स्त्री विमर्श ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। काल और परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को समकालीन स्त्री शक्ति के अवसरों में बदल दिया है। वर्तमान सन्दर्भ में आधुनिक स्त्री ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता के दम पर अपनी पहचान बनाई है। स्त्री की बदलती सोच परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, राष्ट्र और संस्कृति पर नये सिरे से सोचने को प्रेरित किया है। अंग्रेजी साहित्य में भी भारतीय लेखकों द्वारा स्त्री विमर्श पर विचार किया गया है। स्त्री विमर्श एक ऐसा विमर्श है जो जाति, धर्म, वर्ग, वंश, प्रीत और देश आदि से अलग हटकर है, जहाँ स्त्री अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा आदि का विरोध करती है। स्त्री विमर्श को पश्चिम से आई एक अवधारणा के रूप में देखा और विचार किया जाता है। स्त्री के स्वभाव, मन और उसकी सम्बन्धनाओं को समझने के लिए स्त्री विमर्श एक महत्वपूर्ण दृष्टि है। बदलते हुए समाज में स्त्री के पारंपरिक मंडन को तोड़ने की पहल स्त्री विमर्श है ताकि स्त्री को समानता का अधिकार सम्मान अस्तित्व और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।

**प्रस्तावना** – स्त्री विमर्श एक वैश्विक विचारधारा है जिसने पूरे विश्व की स्त्रियों का संघर्ष अपने पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में देखने को मिलता है। स्त्री विमर्श एक प्रकार का साहित्यिक आंदोलन है जिसके केंद्र में समानता का अधिकार, स्त्री अस्मिता और मुक्ति का सवाल है। यह सब स्त्री को तभी प्राप्त हो सकता है जब पुरुषों की मानसिकता को बदला जाए। स्त्री विमर्श चेतना और जागृति का विषय है। स्त्री की विविध समस्याएं उनके अपने सवाल हैं और उनका अपना अधिकार है। यह सब स्त्री विमर्श के अंतर्गत शामिल है। समय के साथ परिस्थितियों में आए बदलाव के कारण स्त्री की सोच, स्वभाव, स्थिति में बदलाव आना ही स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श का एक मात्र उद्देश्य स्त्री को उसकी गुलामी से अवगत करना है तथा उसे उसके अधिकारों और कर्तव्य तथा समाज में परिवार में उसकी क्या स्थिति है इससे अवगत कराना है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म बोला जाता है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद शब्द प्रचार में रहा। नारीवाद लैंगिक समानता के लिए प्रयास करता है और महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को सुधारने में मदद करता है। पश्चिमी विचारको ने नारी मुक्ति के लिए जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हीं से स्त्री विमर्श का उदय हुआ। यह माना जाने लगा कि स्त्री ने अपना पिंजरा तोड़ डाला, स्त्री की वेशभूषा तथा देह मुक्ति के सवाल तेजी से उठे और धीरे से स्त्री मुक्ति का रूपांतरण देह मुक्ति में हो गया। यह समझा जाने लगा कि यही स्त्री सशक्तिकरण है।

**भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री विमर्श** – स्त्री चिंतन उतना ही प्राचीन है जितना हमारा साहित्य। फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक 'परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' के अनुसार व्यक्ति संपत्ति के विकास के साथ स्त्री के

शोषण का आरंभ होता है। जिस प्रकार का रिश्ता मजदूरों का पूंजीपतियों से है कुछ उसी प्रकार का रिश्ता स्त्रियों का पुरुषों से है। इस संबंध के क्रूर विरोधाभास आज भी महसूस किये जा रहे हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक विषमता जरूर है पर बौद्धिक क्षमता में दोनों बराबर है। वैसे भी विषमता को असमानता मनाना अमानविय है। सिमोन द वोउवार, 'द सेकंड सेक्स' में अकारण नहीं लिखती है कि 'स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है'। स्त्री विमर्श समकालीन साहित्य की महान उपलब्धि है यह महिलाओं को मिले लोकतान्त्रिक अधिकार, शिक्षा और स्वावलम्बन का परिणाम है। इसका श्रेय केवल उन्हीं को जाता है। इस विमर्श ने नारी जीवन के उन पक्षों को प्रस्तुत किया है जिनकी चर्चा से साहित्य और समाज विज्ञान में परहेज किया जाता था। स्त्री विमर्श सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु पूरी दुनिया इसके दायरे में है। यहां स्त्रियाँ अपनी पीड़ा और समस्या को ही नहीं व्यक्त कर रही हैं बल्कि अपनी शक्ति की समीक्षा भी कर रही हैं। स्त्रीवादी विमर्श से संबंधी आदर्शों का मूल्य यही रहता है कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग ना बने। आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श की मुख्य आलोचना हमेशा से यही रही है कि इसके सिद्धांत एवं दर्शन मुख्य रूप से पश्चिमी मुल्यों एवं दर्शन पर आधारित रहे हैं। नारीवाद राजनीतिक आंदोलन का एक सामाजिक सिद्धांत है जो स्त्रियों के अनुभवों से जनित है। हालांकि मूल रूप से यह सामाजिक संबंधों से अनुप्रेरित है लेकिन कहीं स्त्रीवादी विचारक का मुख्य जोर लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार इत्यादी पर ज्यादा बल देते हैं।

**स्त्री विमर्श का आरम्भ** – नारी विमर्श का प्रारम्भ कब हुआ इसके सम्बन्ध में विद्वानों में सुनिश्चित एक मतता नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इसका

प्रारम्भ 19वीं शताब्दी में हुआ जब पश्चिम में स्त्रियों के माताधिकार और पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों के योगदान पर चर्चा होने लगी थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विमर्श 20वीं शताब्दी की शुरुआत है। 20वीं शताब्दी में भी कुछ लोग इसका आरंभ फ्रांसिसी लेखक सिमोन द बुआ (1949) के प्रकाशन वर्ष से शुरू हुआ और कुछ मैरी एल्मन की पुस्तक 'थिंकिंग अबाउट वीमेन' 1968 के प्रकाशन वर्ष से। लेकिन अधिकांश विद्वान इस तरह के किसी वर्ष विशेष को स्त्री विमर्श का प्रथम बिंदु मनाना उचित नहीं समझते, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही इस पहले भी स्त्री की अलग पहचान उसके स्वतंत्र अस्तित्व और उसके अधिकारों की श्रृंखलाओं को उठाया जाने लगा था। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक 'ऐ रूम आफ वन्स ओन' 1929 में यूरोप और अमेरिका के स्त्री विमर्श को ही नहीं, भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया है। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान भी इस पुस्तक से प्रभावित हुई है। यूरोप और अमेरिका में नारीवाद में 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में खूब जोर पकड़ा।

**अंग्रेजी साहित्य में स्त्री विमर्श** - अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को कई पीढ़ियों के प्रयासों के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिली है, खासकर सलमान रुश्दी द्वारा मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 के प्रकाशन के बाद से, और अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास को आखिरकार एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रयास के रूप में स्वीकार किया गया है। धीरे-धीरे भारतीय महिला लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य में लेखन करना शुरू कर दिया। जिसका मुख्य श्रेय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरुंधति रॉय को जाता है। परंपरागत रूप से, पुरुषप्रधान होने के कारण स्त्रियों को कम महत्व दिया गया। अंग्रेजी में भारतीय महिला लेखक भी पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ रही थी। पितृसत्तात्मक धारणाओं के कारण भारतीय महिला लेखकों के काम को कम आंका गया है।

इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी में भारतीय महिला लेखक भी पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ रही थी। चूंकि अंग्रेजी में लेखन केवल बौद्धिक, समृद्ध, शिक्षित वर्ग के लेखकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए ऐसा माना जाता था कि लेखक और उनके लेखन कार्य सामाजिक स्तर से संबंधित हैं, और भारतीय जीवन की वास्तविकता से कटे हुए हैं। अधिकार उपन्यास दुखी ग्रहणी की मन की व्यथा के बारे में बताते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के चित्रों को सही माना जाता है। गीतों और दंतकथाओं के माध्यम से कहानी कहने की मौखिक परम्परा की शुरुआत करने वाली महिलाएँ ही थीं जब धीरे-धीरे समाज में साक्षरता फैलने लगी तो इन कहानियों को नाटक व उपन्यास में रूपांतरित किया गया। अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य की मात्रा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य से कम है, और यह समय की एक छोटी सी सीमा को कवर करता है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा और शिक्षा के प्रसार के साथ ही हुई। लेकिन पिछले दो दशकों में अंग्रेजी में भारतीय महिलाओं के लेखन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, इस अवधि का साहित्य भारत और अन्य जगहों पर प्रकाशित हुआ है।

भारतीय महिलाओं ने पारंपरिक रूप से सौंपी गई भूमिकाओं के आगे समर्पण करके और खुद को हावी होने देकर पितृसत्तात्मक मूल्य प्रणाली की सर्वोच्चता को सचेत रूप से स्वीकार कर लिया है। लेकिन बढ़ती शिक्षा, बेहतर नौकरी के अवसर और अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूकता ने लगातार बदलाव की शुरुआत की है। लेखिकाएँ ज्यादातर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हैं। मध्यवर्गीय लेखिका महिलाएँ जो अपने लेखन में

बाल-विवाह, दहेज, महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध, तयशुदा विवाह, सती प्रथा और जबरन विधवा विवाह जैसी दमनकारी संस्थाओं में फँसी उच्च जाति और वर्ग की पारंपरिक हिंदू महिलाओं की दुर्दशा के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करती हैं। उत्तर-औपनिवेशिक भारत में महिला लेखकों ने महिलाओं को बदलते सामाजिक परिदृश्य के संदर्भ में रखते हुए, विशेष रूप से ऐसी महिलाओं की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपना खुद का साहित्य रचा है।

अंग्रेजी में भारतीय कथा साहित्य में विषय वस्तु के रूप में महिलाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन उपन्यासकारों का दृष्टिकोण निश्चित रूप से अलग है। 1960 के दशक के उपन्यास में भारतीय कथा साहित्य में महिलाओं को विभिन्न गुणों वाली आदर्श स्त्री के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें विद्रोह का कोई स्थान नहीं थी, जबकि बाद के उपन्यासों में महिलाओं को शिक्षित और अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति जागरूक दिखाया गया है जो समाज में अपने उचित स्थान की मांग कर रही हैं कमला मार्कडेय, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, शोभा डे, भारती मुखर्जी और कुछ अन्य लेखकों ने शुरू में अपने लेखन में किसी भी तरह के नारीवादी पूर्वाग्रह से इनकार किया है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर एक मजबूत नारीवादी इरादे का पता चलता है। क्योंकि महिलाओं के मुद्दे उनके कथानक का मुख्य विषय हैं अरुंधति रॉय ने 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' में अलगाव, उत्पीड़न, अवसाद, हताशा और समामेलन के केंद्र से पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य की कल्पना की है। गीता हरिहरन, नमिता गोखले, अनीता नायर और मंजू कपूर नामक भारतीय महिला उपन्यासकारों की नई पीढ़ी ने बहुत आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया है। महिलाओं के बीच बढ़ती साक्षरता के बावजूद और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाने के बावजूद और न केवल सामान्य कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान देने के बावजूद, बल्कि पारंपरिक रूप से सौंपी गई घरेलू जिम्मेदारियों की उपेक्षा किए बिना परिवार और समाज में एक प्रमुख सहायक भूमिका निभाने के बावजूद, लिंग-केंद्रित समाज समुदाय में उनके रचनात्मक और सकारात्मक योगदान की सराहना करने में विफल रहता है। साहित्य के द्वारा हम किसी भी मुद्दे को उजागर तथा स्थिति को दोहरा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिलाओं का रचनात्मक लेखन कार्य निरंतर बढ़ रहा है फिर भी पुरुष प्रधान भारतीय साहित्य ने जान बुझकर उनकी भूमिका को नजरंदाज कर दिया है। हाल के वर्षों में सिमोन डी ब्यूवोइर सेकेंड सेक्स, 1952 बेट्टी फ्रीडन फेमिनिन मिस्टिक, 1963 और केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970 जैसे लेखकों द्वारा प्रस्तुत पश्चिमी नारीवादी सिद्धांतों का प्रभाव देखा गया है। इन प्रभावों के तहत भारतीय महिला लेखकों ने अतीत के साहित्यिक और सामाजिक मानदंड को तोड़ने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। वे अपने पात्रों की मानसिकता में गहराई से उतरते हैं और नैतिकता की एक नई अवधारणा की शुरुआत भी करते हैं।

**कविता में भारतीय महिलाएँ** - स्वतंत्रता के बाद भारतीय अंग्रेजी कविता ने कई जबरदस्त विकास देखे हैं। महिला काव्य स्वरों का उदय उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। महिला कविता, वास्तव में, एक पत्नी और माँ के रूप में महिला की पारंपरिक भूमिका के खिलाफ एक विद्रोह है। भारतीय महिला कवियों द्वारा पश्चिमी नारीवादी सिद्धान्तों को अंग्रेजी की भारतीय कविताओं में अपनाया। महिला कवियों ने प्रतिरोध और आत्मविश्वास दोनों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। तोरु दत्ता (1856-77) अंग्रेजी में लिखने वाली



पहली भारतीय महिला कवि थीं और उनकी रचना में भारतीय नारीत्व के आदर्श उदाहरण, जैसे सीता और सावित्री, महिलाओं को पीड़ित, आत्म-बलिदान की भूमिकाओं में दिखाती हैं।

स्वतंत्रता के बाद बड़ी संख्या में भारतीय महिला कवि परिदृश्य में उभरी हैं और आज भी लिखना जारी रखती हैं। वे प्रेम में हताशा, निराशा और अकेलेपन की भावना को व्यक्त करने में पुरुषों की तुलना में अधिक तीव्र, प्रामाणिक और जरूरी हैं। ऐसी महिला कवियों में कमला दास, लीला रे, मोनिका वर्मा, गौरी देशपांडे, यूनिंस डीसूजा, ममता कालिया, सुनीति नामजोशी, मीना अलेक्जेंडर, रोशन अल्काजी हमारा ध्यान आकर्षित करने लायक हैं। कमला दास ने एक जोरदार और मार्मिक स्त्री स्वीकारोक्ति कविता की शुरुआत की। अंग्रेजी में लिखने वाली सभी भारतीय महिला कवियों में कमला दास (1934-2009) का स्थान सबसे ऊपर है। वे स्त्री-पुरुष संबंधों के विषय पर आधारित एक सशक्त और मार्मिक स्त्री-कविता के लिए जानी जाती हैं। महिला लेखिकाएँ सहजशील, आत्म-बलिदान करने वाली महिलाओं के पारंपरिक चित्रण से हटकर पहचान की तलाश करने वाली संघर्षशील महिला पात्रों की ओर बढ़ी हैं, जिन्हें अब केवल उनकी पीड़ित स्थिति के संदर्भ में चित्रित और परिभाषित नहीं किया जाता है। बल्कि उनकी वीर गाथाओं से साहित्य को सजाया जाता है। पहले के उपन्यासों के विपरीत, 1980 के दशक के बाद की महिला पात्र खुद को मुखर करती हैं और विवाह और मातृत्व को चुनौती देती हैं। हाल के लेखकों ने महिलाओं के जीवन को एक आदर्श तक सीमित करने के बजाय, महिलाओं की विविधता और प्रत्येक महिला के भीतर की विविधता दोनों को दर्शाया है।

अमृता प्रीतम के अनुसार-जब कोई पुरुष महिलाओं की शक्ति को नकारता है तो वह अपने ही अवचेतन को नकार रहा होता है ऐसी कई कहानियाँ हैं जो कागजों में नहीं हैं, बल्कि औरतों के शरीर और उनके अंदर लिखी हुई हैं। यह पंक्ति अमृता प्रीतम के लेखों में देखने को मिलती है, पश्चिमी विचारों ने नारी मुक्ति के लिए जो विचार प्रस्तुत किये उन्हीं से स्त्री विमर्श का उदय हुआ। स्त्री की वेशभूषा तथा देहमुक्ति के सवाल तेजी से उठे और धीरे से स्त्री मुक्ति का रूपांतरण देह मुक्ति में हो गया। यह समझा जाने लगा कि यही स्त्री सशक्तिकरण है अपने शुरुआती विकास में स्त्री लेखन एक निश्चित सन्देश और सन्दर्भ में रूढ़ हो गया। सिमोन द बोबा ने कहा था- औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है। कृपा बाई सत्यानंद अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदू स्त्री के जीवन की दुर्दशा बयान की थी। कृपा बाई ने जनाना मिशन स्कूल में जाकर महिलाओं को पढ़ाया और मुस्लिम लड़कियों के लिये एक स्कूल भी खोला। कृपा बाई स्त्री के प्रति जागरूक थी और लगातार स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं में लिखती थी। पुरुष प्रधान देश होने के कारण भारतीय

पुरुष एक बुद्धिमान स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह स्त्री को अपने से ऊपर देख नहीं सकता था। समय के साथ साथ महिलाओं की स्थिति बदल रही है साथ ही महिला चिंतन और लेखन धारा भी बदल रही है। स्त्री चिंतन इतना ही प्राचीन है जितना हमारा साहित्य है। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना डी सब्जेक्शन ऑफ वूमन के अनुसार 'स्त्री और पुरुष बौद्धिक क्षमता में दोनों बराबर हैं'। सेकेंड सेक्स के अनुसार 'स्त्री पैदा नहीं होती स्त्री बना दी जाती है'। हिंदी प्रसिद्ध लेखिका प्रभा खेतान का साहित्य स्त्री जीवन के संघर्ष, मनोकामना, उसकी इच्छा, पीड़ा एवं मानसिकता का जीवंत उदाहरण है। पुरुष प्रधान संस्कृति रुढ़ी परंपरा का संघर्ष करने वाले नारी का वर्णन उनके लेखों में मिलता है प्रभा खेतान में अपनी रचनाओं में नारियों को भावनाओं में बहता हुआ ना बता कर और उसके समग्र खड़े होने की मांग है ताकि उनका मानसिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हो विकास हो सके।

**निष्कर्ष-** लेख महिलाओं के अधिकारों का समाज में उनकी स्थिति पर आधारित है भारतीय महिला लेखको द्वारा समाज को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है समाज में स्त्री और पुरुष दो गाड़ी के पहिये हैं जब दोनों ठीक बराबारी में चलेंगे तभी समाज भी परिवार की तरक्की होगी यह विमर्श स्त्री को पुरानी सोच से निकल कर आगे मार्ग प्रशस्त करने का कार्य कर रहा है स्त्री विमर्श के प्रश्नों ने समाज को एक नई सोच प्रदान की है जिसके समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो समानता पर आधारित है और स्त्री विमर्श के मध्यम से स्त्री के मन को आत्मविश्वास धर्म मनोबल प्रदान किया गया है। निष्कर्ष रूप में यहीं कहा जाएगा कि अब भारतीय नारी अबला नहीं रही सबला हो चुकी है क्योंकि यह वह शक्ति है जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हुए हैं तो पुरुष क्या चीज है, नारी के बिना परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है। नारी कोमल है, कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है। कमजोर और कोमल समझकर जिसको सबने देखा है, वह कमजोर नहीं शक्तिशाली है और सभी गुणों की अवतार है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अभिषेक कुमार गौड़ हिंदी विभाग सागर।
2. आदमी की निगाह में औरत, राजेंद्र यादव राजकमल प्रकाशन 2021 पृष्ठ 15
3. मेरी प्रिय कहानियां, अमृता प्रीतम राजपाल प्रकाशन 2014 पृष्ठ 15
4. मोनोग्राफी, रघुवीर सहाय प्रथम संस्करण 2014 पृष्ठ 63
5. आधी जमीन, सरोज चौबे अक्तूबर 2001 पृष्ठ 79
6. जनसत्ता, चन्द्रभान सिंह यादव जनवरी 11, 2021
7. संध्या तिवारी, अंग्रेजी में उत्तर आधुनिक भारतीय महिला लेखिकाएं: आलोचनात्मक चिंताएं और रुझान, रिसर्च इंडिया प्रेस।

\*\*\*\*\*

## उषा प्रियवंदा के उपन्यासों में नारी जीवन के विविध आयाम

डॉ. अर्चना बापना\*

\* सहा. प्राध्यापक, एडवास महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** – नारी, समाज का एक अभिन्न अंग है। 'नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती' है। यही कारण है कि अपने जन्मकाल से ही हिन्दी उपन्यास नारी जीवन और उसकी विभिन्न समस्याओं के प्रति सजग रहा है। प्रेमचन्द पूर्व के उपन्यासों में प्राचीन आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा होने के कारण उपन्यासकारों ने उन्ही आदर्शों के सहारे नारी का चित्रण किया और उन आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में ही नारी, जीवन की सार्थकता को दिखाने का प्रयास किया।

प्रेमचन्द के आदर्शों-मुख्यतः यथार्थवाद उपन्यासों में परिवार में पुरुष को प्रधान मानते हुए भी वे नारी को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। नारी शिक्षा की आवश्यकता मानते हुए भी वे नारी के स्वतंत्र अर्थोपार्जन को उचित नहीं समझते थे और सामाजिक, राजनीतिक कार्यों में नारी की रूचि को श्रेयस्कर माना पर भी पाश्चात्य नारी जीवन को गलत मानते थे।

जैनेन्द्र ने नारी-जीवन को कुछ अधिक गहराई से समझने का प्रयास किया। उन्होंने नारी जीवन की विविधता का चित्रण किया। यशपाल ने राजनीतिक दल में काम करने वाली नारी व समाज में नारी के विभिन्न बंधनों का रूप उपस्थित किया। इस समय के उपन्यासों में नारी के प्रेम की समस्या, वैवाहिक असंगति की समस्या और घर बाहर की समस्या पर लेखकों ने दृष्टि-पात किया।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पुरुष मन का जितना मनोविश्लेषण मिलता है उतना नारीमन का नहीं मिलता। अधिकांश उपन्यासों में पुरुष के परिप्रेक्ष्य में ही नारी के मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया है। जिसके कारण नारी-मन के बहुत से सूक्ष्म पहलू अछूते रह गये हैं। नारी के मनोविज्ञान का चित्रण भी कहीं-कहीं ही दिखाई देता है।

कुछ महिला उपन्यासकारों ने नारी जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया परन्तु उन्होंने भी नारी का केवल स्वप्नशील और भावुक रूप में ही देखा।

उपन्यासकार उषा प्रियवंदा ने नारी जीवन का गहरा यथार्थ और सटीक चित्रण प्रभावशाली ढंग से करने की चेष्टा की है। प्रेमचन्द के होरी, अज्ञेय शेखर की तरह ही उनके उपन्यासों की राधिका, सुषमा और अनुका ये पात्र पाठक पर छाप छोड़ते हैं।

नारी के हर पहलू और हर विशेषता का चित्रण उषा-प्रियवंदा के उपन्यासों में दिखाई देता है।

आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में नारी जीवन के एक और पहलू पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है। सन् 1935 के आर्थिक संकट से ही भारतीय नारी

अर्थोपार्जन की ओर ध्यान देती आई है और सन् 1950 तक हम अनेक पुरुषोचित धन्धों में नारी को प्रवेश करते पाते हैं। क्लर्क, अध्यापिका, अभिनेत्री, लेडी डॉक्टर, लेडी वकील, राजनीतिक कार्यकर्ता, मंत्रालय, दूतावास में भी नारी की प्रतिष्ठा हो चुकी है। परन्तु नारी के इन अनेक रूपों में से उपन्यासकार लेखक ने केवल दो-तीन की ओर ही ध्यान दिया है इस प्रकार के व्यवसाय अपनाने से उनके पारिवारिक, सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आता है, जिन कठिनाईयों का उसे सामना करना पड़ता है उनका कोई उल्लेख हिन्दी उपन्यासकारों ने नहीं किया है। परन्तु उषा-प्रियवंदा के तीनों उपन्यासों में इस प्रकार की कई समस्याओं का कठिनाईयों का प्रशंसनीय प्रयास हमें देखने को मिलता है।

इसी प्रकार स्वावलम्बिनी नारी के अस्वाभाविक जीवन का और विवाह को अपनी स्वतंत्रता का अपहरण समझ कर उससे दूर रहने वाली नारी का चित्रण हमें हिन्दी उपन्यासों में नहीं मिलता। उषा प्रियवंदा के तीनों उपन्यासों की नायिकाएँ कुछ हद तक ऐसी ही हैं, जो स्वावलम्बी तो हैं और पुरुष विशेष को केवल उतना ही महत्व देती हैं, जहाँ तक वे उनके विकास में सहायक होते हैं। अन्यथा ये नारियाँ पुरुष से दूर रखकर ही अपना जीवन जीने को प्रस्तुत दिखाई देती हैं।

स्वावलम्बन की इस दौड़ में इसी प्रयत्न में उसे अपने परिवार से अनेक प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है उसे प्राचीन संस्कार एवं समाज की रूढ़िवादिता से जुझना पड़ता था। समाज की संकीर्ण मानसिकता से उसे लोहा लेना पड़ता था। उपन्यासकारों ने उसके संघर्ष को अनदेखा किया था। साथ ही उपन्यासकारों की दृष्टि भी नारी को परिवार व पति से मिलने वाली यातनाओं की ओर नहीं गई। न उस तेजस्विनी नारी का चित्रण किया गया है जो इन सारी बाधाओं और संकटों को पार करती हुई अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है।

नारी जीवन की उपरोक्त बहुत सारी कमियों को उषा प्रियवंदा के उपन्यासों के कारण दूर हो गई है उषा जी ने नारी के पिछड़ेपन की निन्दा की जगह पुरुष के पिछड़ेपन का वर्णन किया।

उषा जी ने अपने उपन्यास पचपन खम्भे, लाल दीवारे, रूकेगी नहीं राधिका एवं शेषयात्रा इन तीनों उपन्यासों में नारी जीवन का जो विविधतापूर्ण और सूक्ष्म चित्रण किया है, उसे हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं।

1. भारतीय और पाश्चात्य संस्कारों से प्रभावित नारियाँ।
2. उच्च वर्ग की नारियाँ।

3. उच्च मध्य वर्ग की नारियाँ।
4. मध्य वर्ग की नारियाँ।
5. निम्न वर्ग की नारियाँ।
6. किशोर वर्ग की नारियाँ।

पाश्चात्य और भारतीय संस्कारों से प्रभावित नारियाँ।

1. सुषमा।
2. राधिका।
3. अनुका।

सुषमा मध्य वर्ग की एक शिक्षित युवती है। घर की बड़ी बेटी होने के नाते, पिता की बिमारी में वह घर की जिम्मेदारी संभालती है। दिल्ली के एक कॉलेज में वह अपनी नौकरी एवं घर की जिम्मेदारी निभाने का कार्य पूरी ईमानदारी से करती है। इस प्रकार सुषमा जानती है कि वह अर्थ प्राप्ति का एक साधन मात्र बनी हुई है। क्योंकि पिता उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। जिम्मेदारी होने के साथ-साथ सुषमा भी चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका घर हो परन्तु घर के जिम्मेदारी के कारण वह शादी नहीं कर सकती। सुषमा एक भारतीय नारी है। इसलिए वह पहले दूसरों के सुख का विचार करती है। कृष्णा मौसी जब उसके विवाह की बात छेड़ती है तो सुषमा कहती है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है, सिर्फ विवाह ही तो नहीं ओर देशों में देखिए बिना शादी किए ही औरते कैसे मजे से रहती है।

नील नामक एक युवक को मित्र बना लेती है वह सुषमा के इस अकेले पन और दुःख से उभारने का एक सहारा उसे मिल जाता है। नील से सुषमा को सच्चे प्यार है परन्तु वह यह खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, अपनी इसी विवशता से उसे चिढ़ है। नील के बिना उसका जीवन अर्थहीन होगा यह जानकर भी वह उससे दूर जाने का निश्चय कर लेती है। सुषमा के मानसिक अन्तर्द्वन्द्व, कर्तव्य, भावना के संघर्ष अशान्ति अतृप्ति आदि मनोभावों के परिस्थिति सापेक्ष मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित करने में लेखिका विशेष रूप से सफल हुई है। सुषमा अपने समाज की अनेक अदृश्य में मर्यादाओं और नीति नियमों की चौखट में बंधी है। उसका मानस और अंतकरण उसे कुछ और करने को कहता है तो उसके बाह्य परिवेश की मांग कुछ और ही है।

अतः सुषमा उन भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो आज के आधुनिक युग में भारतीय और पाश्चात्य संस्कारों से प्रभावित होकर, द्वन्द्ववस्था के कारण अपना सुख और चैन खो बैठती है। न वो पूरी तरह से भारतीय जीवन जी सकती है न पूर्णतः पाश्चात्य जीवन अपना सकती है और इस बीच की अनिर्णित और अत्यन्त संघर्षमय अवस्था में उपन्यास की नायिका जीवन जीने के लिए मजबूर होती है।

**राधिका** - 'रूकेगी नहीं राधिका' उपन्यास की नायिका राधिका अपने विचारों के अनुसार जीवन जीने वाली उच्चवर्ग की एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की युवती है वह मेधावी है तथा उसमें आत्मविश्वास पूर्ण गरिमा है प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली वह एक आकर्षक युवती है। अपनी जिद के कारण पिता से झगड़कर पीटरसन संवाददाता के साथ विदेश जाकर राधिका शिकागो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती है। अपने घर की बिगड़ी हुयी असहनीय परिस्थिति से उबरने का राधिका, यह एक अच्छा मार्ग ढूँढ निकालती है। राधिका के लिए विदेश यात्रा एक स्वप्न था, वह एक महत्वाकांक्षी युवती होने के कारण उसे यह स्थान वास्तविकता में ले जाता है।

अन्यत्र कहीं रहने की व्यवस्था न हो सकने के कारण राधिका करीबन

एक साल तक डेनियल के साथ ही रह लेती है। राधिका पर भारतीय संस्कारों की छाप गहरी होने के कारण विदेशी संस्कृति की अनेक बातें उसे खटकती है। जब वह विदेश यात्रा से लौटकर पहली बार अपने पापा से मिलने जाती है तो रास्ते में उसे उँट मिल जाते हैं तो वह मन ही मन कामना करती है कि उसका पापा से मिलना ठीक तरीके से हो जाए। राधिका को इस बात की निरर्थकता मालूम है परन्तु वह बात को दिल से पूरी तरह निकाल भी नहीं सकती। पिता के मिलने पर उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार करना, मामा के घर अतिथि धर्म को जानकर कुशलक्षेम पूछना, उनके बच्चों को आशीष देना चाहना। इन सभी छोटी-छोटी बातों से राधिका पर हुए गहरे भारतीय संस्कारों का दर्शन होता है। इसके विपरीत राधिका पर पाश्चात्य आधुनिक संस्कारों का भी पर्याप्त प्रभाव है जैसे विदेश में पढ़ना, साथ में रहना आदि।

अतः राधिका उन नारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संस्कारों से भारतीय तथा शिक्षा एवं विचारों से पाश्चात्य होती है। संस्कारों एवं विचारों के परस्पर भिन्नत्व के कारण ऐसी नारियों का जीवन एक पहली बन जाती है। ये किसी भी परिस्थिति एवं परिवेश में संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। उनका भविष्य अनिर्णित एवं प्रश्नचिन्हित ही रह जाता है।

### अनुका

'शेषयात्रा' उपन्यास की नायिका अनुका मध्यवर्ग में पली हुई एक साधारण युवती है बचपन में ही माता-पिता केवल बसने के कारण वह नैनिहाल में पली है। वह स्वभाव से अत्यन्त नर्म-मिजाज और सहनशील है। उसकी शादी डॉ. प्रणव कुमार के साथ तय होती है। एक घरौंदे से निकलकर अपने पति के साथ चकाचौंध वाली विदेशी दुनिया में अनुका चली जाती है। जीवन के नये सुख और खुशियाँ प्रदान करने वाले पति के प्रति अनुका कृतज्ञता से उसके पैरों पर समर्पित हो जाती है। अनुका की हर बात प्रणव के संकेतों पर चलती है। वह सखी सम्मेलन की सदस्य है परन्तु वहाँ की औरतों के साथ कभी वह खरीदारी के लिए भी नहीं जाती। प्रणव की सलाह के बिना वह कोई भी निर्णय नहीं लेती। बचपन से ही अनुका के व्यक्तित्व को किसी ने अलग रूप से स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा किसी न किसी संदर्भ में पहचानी गयी है। आदर्शों को ग्रहण करने वाली वह एक कठपुतली मात्र रह गयी है। अपने स्वत्व को जानने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। अपने जीवन से संबन्धित निर्णय भी उसने खुद नहीं लिये।

अनुका अपने सौंदर्य से भी बेखबर है प्रवासी भारतीयों पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाने के लिए जब उसे चुना जाता है तब वह उत्तेजना से काँप उठती है। एक ओर जब वह परिणाम के भय से आंतकित है। तभी दूसरी ओर अपनी जिंदगी के अत्यधिक आनन्द की चरमसीमा के अनुभव से रोमांचित है। घर आये हुए बड़े-बड़े मेहमानों से प्रशंसा सुनकर वह शर्म से लाल हो जाती है। उन्हें जलपान देते हुए वह एक सहज स्वाभाविक कुशल गृहस्थिन की तरह लगती है। फिल्म की डायरेक्टर चंद्रिका राणा जब उसे पूछती है कि क्या वह सिर्फ यही काम करती है। तो अनु को यह प्रश्न बमगोले की तरह लगता है। अनु ने इस पर कभी सोचा ही नहीं है। उस समय प्रणव ही आगे बढ़कर सफाई पेश करते हुए कहता है मुझे कैरियर गर्ल नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था सरल स्नेहशीला बीबी, जिसके साथ बैठकर मुझे सुख-चैन मिले।

उसी रात से प्रणव के बर्ताव में लाक्षणिक फर्क आता है। उसके व्यवहार में रूखापन आ जाता है। वह सनकी बन जाता है। डॉक्टर छोड़ के वह फिल्मे बनाने की ठान लेता है। इस निर्णय से अनु चिंताग्रस्त हो जाती है। परन्तु कुछ कहने-सुनने की उसकी हिमत नहीं होती। अनु को प्यार और विश्वास

के बदले दुनियाँ के ऐशोआराम देने से ही अपनी पति की जिम्मेदारी खत्म होती है ऐसा प्रणव को लगता है। पति के बदले हुए तेवर के सामने अनु विवश है। अनु पति के स्वभाव को जानकर सब कुछ चुपचाप सहना ही उचित समझती है। पति पर बोझ न बनने तथा उन्हें कष्ट न देने का वह प्रयत्न करती है। एक बार पार्टी में प्रणव जब सबके सामने अनु को एक बंधन के रूप में अपनी प्रगति का रोड़ा कह देता है तब अनु अपमान से जल जाती है। पति के कठिन शब्दों से उसका कोमल हृदय घायल हो जाता है। अनु पति के व्यवहार और सनकीपन का अर्थ जानना चाहती है, पर असफल रहती है एक बार प्रणव से झगडा हो जाने पर वह अनु से कहता है, छोड़ दो मुझे अलग हो जाओ। मुझसे अब तुम्हें कुछ भी संतोष नहीं मिलता।

फिर भी अनु अपने बिगड़े हुए दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ नहीं कहती।

अनुका मूलतः एक पारंपरिक और पुराने ख्यालों की भारतीय नारी है। भारतीय संस्कारों की जकड़ में वह आबद्ध है। परन्तु धीरे-धीरे वह अपने को उससे मुक्त करती है। इस प्रकार एक आदर्श भारतीय नारी है, एक आधुनिक से पाश्चात्य नारी की ओर अनुका की यह यात्रा है।

**उच्चवर्ग की नारियाँ**— उषाजी ने अपने उपन्यासों में प्रधानता आधुनिक नारियों का चित्रण किया है। आधुनिक युग की उच्च वर्ग की नारियों का रहन-सहन आचार-विचार प्रकृति एवं स्वभाव का यथार्थ वर्णन करने में उषा जी सफल हुई है।

उषाजी ने उच्चवर्ग की जिन नारियों का चित्रण किया है वे अपने वर्ग की प्रतिनिधि पात्र के रूप में हैं एवं दिखाई देती हैं। उषाजी के उपन्यासों में निम्नलिखित प्रमुख पात्रों का चित्रण हुआ है। पहला उपन्यास पचपन खम्बे, लाल दिवारे में कौशल्याजी, नील की माँ, नील की बहन, विद्या, भाभी, विजया, नयनतारा, कारिन, गोगी, अंजलि, अक्षय, के अफसर की पत्नी, क्रिस्त, डॉ. विभाषहा, कीरत, चन्द्रिका राणा, रोजलिन हैं।

**कौशल्याजी**— कौशल्याजी सुषमा की कृष्णा मौसी की सहेली है। वही नील की बुआ है। सुषमा की साड़ियाँ कौशल्याजी नील के हाथों होस्टल पहुँचाती है वह खुद मेहमान बनकर आती है। कौशल्या जी एक आधुनिका है। वहा सुस्वभावी औरत है। पति के साथ वलब जाने जैसा आधुनिक रिवाज निभाते हुए भी उसकी संस्कृति प्रतिभा उसके बर्ताव से झलकती है।

**नील की माँ**— नील की माँ अपने उच्च वर्ग की हैसियत एवं प्रतिष्ठा से रहने वाली एक कुलीन स्त्री है। वह अपने खानदान तथा रहन सहन आदि के बारे में बहुत सतर्क है। नील की माँ नील की शादी अपने जैसे ही बड़े खानदान में करना चाहती है। सुषमा से प्यार होने के कारण नील जब शादी के लिए तैयार नहीं होता तब कृष्णा मौसी से झगड़ती है कि उनकी भानजी के पीछे नील शादी नहीं कर रहा है। इस प्रकार नील की माँ संकीर्ण विचारों की तथा अपने ही घेरे में रहने वाली एक अमीर औरत है।

**नील की बहन**— नील की बहन एक नवयौवना किशोरी है। सुषमा के प्रति उसके मन में उत्सुकता कुदून तथा खिंचवा का भाव है। अपने भाई को फुसलाने वाली सुषमा की बदनामी करने में वह माँ का साथ देती है।

**विद्या**— विद्या 'रूकीगी नहीं राधा' उपन्यास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पात्र है, जो अपने प्रभावशील व्यक्तित्व से पाठकों पर एक अनूठी छाप छोड़ती है। विद्या राधिका की विमाता है। राधिका कभी विद्या को समझने की कोशिश नहीं करती। विद्या और राधिका के पिता के बीच भी मनमुटाव है इसीलिए वे विद्या से अलग अकेले गंगापर वाली कोठी में रहने लगते हैं। इससे विद्या

अपनी उपेक्षा और अपमान सह नहीं सकती। जब वह जिंदगी से उब जाती है तो एक रात नींद की गोलियों खाकर अत्महत्या कर होती है। इस उपन्यास में विद्या एक उच्च वर्गीय शिक्षित स्वाभिमानी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। **राधिका की भाभी**— राधिका की भाभी अपने अमीर पिता की एक इकलौती संतान है। उसके पति ने शादी के बाद उसके पिता का सारा कारोबार संभाला है। बेशुमार धन और दौलत का असीम अहंकार उसमें भरा हुआ है। अपनी विदेश यात्रा से लौटी युवा नन्द की शादी हो जाए ऐसी भाभी की इच्छा है। इसलिए वह उसे वलब ले जाती है।

**विजया**— एक सुंदर युवती है। वह मनीष की वागदत्ता है। मनीष के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वह बेहद दुःखी हो जाती है। वह अमीर और ऐयाशी युवक के मनोरंजन का साधन बनी हुई नारी के रूप में विजया को हम पाते हैं ऐसी नारियाँ जो धनवान युवकों की शान और सुख प्राप्त कर उन्हें भूला देते हैं। ऐसी ही धोखा खाई हुई आहत नारी का प्रतिनिधित्व विजया करती है।

**नयन तारा**— एक अत्यन्त सुंदर युवती है। उसकी सुंदरता किसी प्राचीन मंदिर के स्तम्भ पर खुदी यक्षिणी की बराबरी करती है। मनीष उसकी सुंदरता से प्रभावित है और उसी के पीछे अपनी बागदत्ता विजया से सम्बन्ध विच्छेद कर देता है। मनीष जैसे धनवान युवकों के मनोविनोद का साधन बन जाने वाली नारियों में नयनतारा भी एक है।

**कारिन**— यह राधिका के मित्र मनीष की सहेली और छात्रा भी है। कारिन एक खूबसूरत युवती है वह किसी भी सुंदर युवक से झट से प्रभावित हो जाती है। कारिन आर्ट इन्स्ट्रीटयूट के रिसर्च ट्रेनिंग में काम कर रही है, जिसे मनीष ही एक अधिकारी के रूप में संभाल रहा है कारिन मनीष को चाहती है। वह मनीष को अपना समझती है। कारिन मनीष के साथ शादी करना चाहती है।

**गोगी**— कीरत की लडकी तथा एक अमीर घर की बेटी है। वह उद्वण्ड और लाड प्यार से बिगड़ी हुई है। उसके बर्ताव की तरह उसके कपड़ों भी अत्यन्त वीभत्स है। गोगी ने कार्मेडिशन का कोर्स किया है वह और उसकी मां दोनो ब्यूटी ट्रैटमेंट ले रही है। अपनी मुख-मुद्रा का ख्याल रखना, मेकअप की कई परतें चेहरे पर चढाना ये उनका रोजमर्रा का काम है। गोगी को अगर लडका पसन्द आए तो वे उनकी शादी करा देने। परंतु गोगी का अपने युवा दोस्तों के साथ मजे लुटना और घुमना रहना इन बातों से माता-पिता अनजान है। पाश्चात्य संस्कारों में पली और बिगड़ी हुई गोगी एक साधारण प्रतिनिधि पात्र है।

**डॉ. विभा शहा**— डॉ. शहा की पत्नी है। विदेश में रहने वाली यह एक उच्च वर्गीय औरत है। उसकी प्रकृति उच्छखल औरत की तरह है। वह डॉ. प्रणव में बड़ी दिलचस्पी रखती है। विभा का आचार-विचार व्यवहार अत्यन्त मुक्त है। वह नव विवाहित प्रणव की बॉहे पकडकर उसे घर ले जाती है। अनु के मौन रहने पर वह उसे टोकती है। प्रणव उसे कहता है कि अब विभा ही उसे अपनी तरह सब कुछ सीखा दें। विभा को इस बात में अपना सम्मान और प्रशंसा नजर आती है। विभा को अपनी डॉक्टर पर घमंड है।

**चन्द्रिका राणा**— चन्द्रिका राणा न्यूयार्क में टी.बी. स्टेशन में प्रोग्रामों की प्रोड्यूसर है, चन्द्रिका पूरी तरह से पाश्चात्य ढंग की औरत है, जो लगातार सिगरेट और बीच-बीच में बोटल से बीयर के घूंट पीती रहती है। अनु की अतिथेया बनकर सबको जलपान देते हुए देखकर चन्द्रिका व्यंग्य से मुस्कुराती है और अनु से पूछती है कि क्या अनु हमेशा सिर्फ यही काम करती है तब अनु निरुत्तर हो जाती है, प्रणव और चन्द्रिका दोनों एक दूसरे के प्रति

आकर्षित है, इसी कारण प्रणव को अनु के साथ का जीवन लंचर और बेमानी लगने लगता है।

**अंजलि:-** अंजलि यह राधिका की परिचित मित्र की बड़ी बहन है। वह एक समाज सुधारक है वह चाहती है कि उसका भाई ऐसी ही किसी कन्या से विवाह करके उसका उद्धार करे जो बहुत बेचारी और निरुपाय है। सामाजिक सुधार के लिए प्रयास करने वाली नारियों का प्रतिनिधि पात्र अंजलि है। परंतु अंजलि ने समाज सुधार के जो उपाय ढूँढ़े हैं वे अनुचित एवं असफल होते हुए दिखाई देते हैं।

**अफसर की पत्नि:-** अक्षय के अफसर की पत्नि को भारतीय तिब्बतियों में बड़ी रूचि है। वह उनके लिए स्कूल चलाती है जिसमें उन्हें ट्रेनिंग देकर नौकरी करने योग्य बनाया जाता है। उसके घर में ऐसे ही एक गरीब तिब्बती को रसोईये के रूप में रखा है। अपनी अमीरी और अपने समय का सदुपयोग करके समाज के कल्याण के लिए प्रयत्न करने वाली विवेकशील नारियों का प्रतिनिधित्व अक्षय के अफसर पत्नि करती है।

**क्रिस्त:-** क्रिस्त का असली नाम कृष्णा है। मनीष एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित करता है। इस पार्टी में क्रिस्त अपने सौंदर्य, श्रेष्ठता और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही आती है। वह अपने मद्यपान की आदत के बारे में चढाचढाकर बातें कर रही है। उसे कोरी शराब पसंद है और उसकी इस पसंद पर उसे गर्व है। क्रिस्त का अहंकारी स्वभाव तथा उसकी निम्न मनोवृत्ति का दर्शन होता है। क्रिस्त का संभाषण भी बड़ा कृत्रिम और नाटकीय है।

**कीरत:-** सखी सम्मेलन नामक एक विदेशी संगठन की सदस्या है। उसके पति धनराज ने घर में बार लगवाया है। एक अमीर स्त्री की सारी विशेषताएँ उसमें हैं। बाहर और पार्टियों में उसका रूप चकाचौंध करा देने वाला होता है। तो घर में वह एकदम सीधी-सादी और अलग दिखाई देती है।

**रोजलिन:-** अनु की पडोसिन है। यह संवेदनशील दयालु और उदार नारी है जो अनु की कठिन और असहाय स्थिति में अनु की पूछताछ करती है अनु का दिल बहलाने के लिए वह अनु को सँहलियों के पास चली जाने के लिए कहती है। उषा जी ने अपने उपन्यासों में हर वर्ग की नारियों के जीवन का चित्रण किया है। समाज में उच्च मध्यवर्ग ही कुछ नारियों में अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थान एवं दर्जे को लेकर अत्यधिक आत्म सम्मान की भावना होती है। घमंड से दूर रहती है जिनका आचरण स्वाभाविक होता है।

**उच्च मध्यवर्ग की नारियाँ:-**

**उषा जी द्वारा चित्रित उच्च मध्य वर्ग के प्रमुख पात्र निम्ननुसार है।**

1. प्रिसिपल 2. रमा 3. दिवाकर 4. प्रेमा 5. अनिला 6. नीना 7. दिव्या 8. दिव्या की माँ 9. नीरजा 10. ज्योत्स्ना पटेल 11. नमिता 12. डौली दीदी

**प्रिसिपल:-** सुषमा के कालेज की प्रिसिपल एक बुजुर्ग, गंभीर महिला है सुषमा के काम से वह संतुष्ट है। सुषमा के प्रति उसके मन में सहज स्नेह एवं सदभावना है। सुषमा के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनकर उन्हें गहरा धक्का पहुंचता है। सुषमा को वे एक गंभीर जिम्मेदार टीचर बार्डन समझती है। सुषमा प्रिसिपल के प्रति आदर का भाव रखती है। प्रिसिपल अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाती है।

**रमा:-** रमा यह राधिका की सहपाठिनी है। रमा राधिका की विमाता विधा की छोटी बहन है। वह एक मुखर और बहिर्मुख प्रवृत्ति की नारी है। रमा राधिका को सीधे स्पष्ट शब्दों में कहती है। न जाने कहाँ-कहाँ का सैर-सपाटा, जाने किस-किस घाट का पानी पीकर तुम आई हो। राधिका के पास रमा को

बताने के लिए बहुत-सी बातें होगी ऐसे संभाषण से असभ्यता ही झलकती है।

**दिवाकर:-** दिवाकर ने मैकमिल युनिवर्सिटी फिजिक्स विषय में डाक्टरेट की है। असंतुष्ट जीवन की त्रुटियों और अभावों से परेशान दिवाकर को दिवाकर की बीबी अपने देश के लिए त्याग करने की बातें सीखाती है।

**प्रेमा:-** प्रेमा राधिका की मकान मालिकन है। वह एक साधारण गृहस्थीन का प्रतिनिधित्व प्रेमा करती है। प्रेमा एक व्यवहार कुशल औरत है इसीलिए वह राधिका के सामने अपने मकान की तारिफ करती है। वह वहाँ की अनेक असुविधाओं को सुविधा साबित कर देती है।

**अनिला:-** राधिका के मकान मालिक एवं अक्षय के मित्र शंकर की बड़ी बेटी है। वह बीस-इक्कीस बरस की युवती है। वह अक्षय की ओर आकर्षित है। और उससे मुग्ध प्यार करती है। वह सजने संवारने की अतिरिक्त महत्व देती है।

**नीना:-** नीना राधिका के मकान मालिक की बेटी है। वह कॉलेज में बीए. में पढती है। नीना अल्हड है। वह जोर-जोर से बातें करती रहती है। उसका आचरण और उसकी बातें सहज और अक्रान्तिम है। वह राधिका के विदेश जीवन के बारे में वह कौतहुल भरे प्रश्न करती है। खासकर टेलीवीजन और फिल्मों के विषय में उस ज्यादा दिलचस्पी है। उसके मन है कि अगर मजे की जिंदगी हो तो वह कभी मेहनत से नहीं घबराएगी। नीना को ऐशो आराम और सुविधापूर्ण जीवन पसंद है।

**दिव्या:-** दिव्या अनु की बचपन की सहेली है। यह उच्च मध्यवर्ग के परिवार की लडकी है। दिव्या की माँ फैशन बुल औरत है। दिव्या का बचपन बड़े से बंगले में फुलवारी, कुत्तों और नौकर चাকरों तथा भाई बहनों के बीच रहने वाली अमीर लडकी है। एम.ए. करते-करते दिव्या की शादी जयन्त से हो जाती है। और दोनों साथ-साथ आगे पढने के लिए विदेश चले जाते हैं। इस परिवर्तन से दिव्या बदल जाती है। आत्म विश्वास आचरण का खुलापन, सहज मुस्कान और बर्ताव का सीधापन उसके स्वभाव की महत्वपूर्ण विशेषताएं बन जाती है।

**नीरजा:-** सखी सम्मेलन की सदस्या है। नीरजा ने दूसरी शादी कर ली है और शादी के दस महीने बाद उसे बेटा हुआ है। वह अपने बेटे का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाती है। वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करके अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन करती है। नीरजा खुद पढ़ी लिखी जिम्मेदार पद पर नौकरी करने वाल स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्त्री है।

**ज्योत्स्ना:-** एक अर्धे उम्र की बुजुर्ग स्त्री है जो अपने पति के साथ कैलिफोर्निया में रह रही है। वह अनु और प्रणव से परिचित है। प्रणव को जब वह चन्द्रिका राणा के साथ देखती है तो उसे दुःख होता है कि अनु इन सब बातों से बेखबर है। अनु को इस बात की खबर करा देना ज्योत्स्ना अपना कर्तव्य समझती है। ज्योत्स्ना एक जिम्मेदार स्त्री है। वह पुराने ख्यालों की है। अतः दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती है।

**निम्न वर्ग की नारियाँ:-** उषा जी ने अपने उपन्यासों में ज्यादातर आधुनिक उच्च मध्यवर्ग की नारियों का ही चित्रण किया है। अतः निम्नवर्ग नारियों का चित्रण स्वाभाविक तौर पर बहुत कम हुआ है। प्रसंग कहीं-कहीं निम्न वर्ग की नारियों का चित्रण मिलता है। निम्न वर्ग की इन प्रतिनिधि नारी पात्रों से उनके जीवन की झलक दिखाई देती है ये प्रमुख पात्र है।

1. मीरी
2. देकी

उषा प्रियंवदा उन कथाकारों में से एक हैं। जिन्होंने आधुनिक जीवन की उब छटपटाहट संत्रास और अकेलेपन की अनुभूति के सार को पहचान कर अपने रचनाओं में व्यक्त किया है। उच्च वर्ग के साथ-साथ उन्होंने मध्य वर्ग की नारियों के जीवन की विभिन्न प्रकार की सामाजिक धार्मिक संस्कृतिक समस्याओं को भी स्त्री चेतना की दृष्टि से बहुत ही सारगर्भित अभिव्यक्ति दी है। भारतीय मध्यवर्गीय परिवार अपनी कन्या का विवाह प्रवासी से कराकर बहुत खुश होते हैं परन्तु जब अनु का मोहभंग तब होता है जब अमेरिका आने का सौभाग्य दुर्भाग्य में परिणित होता प्रतीत होता है।

भारतीय मध्यवर्गीय परिवार बेहतर अवसर की खोज में जीवन से प्रभावित होकर प्रवासी भारतीयों से अपनी कन्याओं का विवाह करा देने पर स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगते हैं परन्तु विदेश जाने के बाद

शुरू होता है संघर्ष और मोहभंग का अटूट सिलसिला। आज का व्यक्ति नई परिस्थिति में स्वयं से टूटते हुए जिन्दगी से जूझते हुए आर्थिक संकट से संघर्ष कर रहा है। स्त्री अस्मिता को लेकर बाहरी और भीतरी मोर्चे का अतः संघर्ष लम्बे समय तक चला और इसे सामाजिक साहित्यिक विमर्श का स्वाभाविक हिस्सा उषा जी ने बनाया।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. प्रमिला कपूर- भारत में विवाह और कामकाजी महिला पृष्ठ. 4
2. उषा प्रियंवदा- पचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास
3. उषा प्रियंवदा- रूकोगी नहीं राधिका उपन्यास
4. उषा प्रियंवदा- शेष यात्रा उपन्यास

\*\*\*\*\*

## रावजोधा की प्रमुख उपलब्धियाँ

डॉ. सुमित मेहता\*

\* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

**प्रस्तावना** – राजस्थान के इतिहासमें ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास में भी जोधपुर राज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी वीरता, शौर्य, स्वामिभक्ति और बलिदान के लिए विख्यात जोधपुर ने राजस्थान के इतिहास को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। जोधपुर के राठौड़ नरेशों ने अपने शौर्य और बलिदान से पश्चिमी राजस्थान में अपनी सीमा का निरन्तर विस्तार किया। प्रारम्भिक राठौड़ इतिहास में लगभग सभी शासकों को युद्ध में अपनी जान गवानी पड़ी। राव जोधा द्वारा जोधपुर दुर्ग की स्थापना किये जाने के पश्चात् राठौड़ों को एक सुरक्षित स्थान मिल गया।

राव जोधा को ही राठौड़ साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं राठौड़ साम्राज्य को निश्चित स्वरूप प्रदान करने वाला माना जाता है। (1) महाराणा मोकल की हत्या के पश्चात् राव जोधा के पिता राव रणमल ने चित्तौड़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। अनेकों शत्रुओं से घिरे होने एवं अल्पव्यस्क होने के कारण (2) मेवाड़ के महाराणा कुम्भा ने भी मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। राव रणमल का पुत्र जोधा भी चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी के महलों में रहता था। (3) राव रणमल की हत्या के बाद राव जोधा के सम्मुख अनेकों कठिनाईयां थी। मारवाड़ के सभी प्रदेशों पर अलग-अलग वंशज शासन कर रहे थे। सीवाना पर जैतमालोत, नागौर पर खानजादा, जैतारण पर सिंधल राठौड़ आदि।

राव रणमल की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही राव जोधा लगभग 700 साथियों (4) के साथ मंडौर की ओर रवाना हो गये। रेउजी के अनुसार जोधा की सेना की प्रथम मुठभेड़ चित्तौड़ के रावत चूंडा की सेना से हुई, जो पहले से ही उनका पीछा कर रही थी। ओझाजी के मतानुसार प्रथम युद्ध कपासन नामक स्थान पर हुआ। रावत चूंडा के पास अत्यधिक सैनिक थे एवं इस युद्ध में जोधा के लगभग 200 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गये। अतः जोधा की सेना अवसर पाकर युद्धभूमि से निकल गई।

मार्ग में जोधा की सेना ने अनेकों युद्धों का सामना किया। अतः सोमेश्वर पहुँचते-पहुँचते उसके पास केवल 250 सैनिक ही बचे। (5) जिनका उद्देश्य राव जोधा को सकुशल मंडौर तक पहुंचाना था। सोमेश्वर में पीछा करती हुई मेवाड़ की सेना के साथ जोधा की सेना का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधा के लगभग सभी सैनिक मारे गये (6) किन्तु जोधा को सकुशल मंडौर पहुंचा दिया गया। जोधा के चचेरे भाई बरजांग भीवोत को बंदी बना लिया गया।

मंडौर में भी सुरक्षित महसूस न करने के कारण जोधा जांगलू की तरफ निकल गये तथा वहां पर काहुनी नामक गाँव में ठहरे। चित्तौड़ की सेना ने

मंडौर पर अपना अधिकार कर लिया। राव जोधा की सूचना प्राप्त होते ही मेवाड़ की सेना ने काहुनी पर आक्रमण कर दिया। अतः जोधा को काहुनी से भी भागना पड़ा। इसके बाद जोधा इधर-उधर भटकता रहा और धीरे-धीरे उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ली।

जोधा का चचेरा भाई बरजांग, जो कि मेवाड़ की कैद में था, कैद से निकल भागा। उसने गागरोन के स्वामी खीचीं-चौहान चाचिगदेव की कन्या से विवाह कर लिया और यहां से पर्याप्त आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर जोधा के पास पहुँचा। पर्याप्त सैन्य बल हो जाने के उपरान्त भी राव जोधा के पास सैन्य बल का अभाव था। अतः राव जोधा ने, सेतरावा के रावत लूणा जिनके पास पर्याप्त घोड़े थे, से सहायता मांगी। रावत लूणा की पत्नी जोधा की मौसी थी। रावत लूणा ने तो घोड़े देने से इन्कार कर दिया। किन्तु अपनी मौसी के सहयोग से उसको 140 घोड़ों की सहायता प्राप्त हो गई। पर्याप्त सैन्य बल इकट्ठा होने के बाद राव जोधा ने मंडौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने अपने विश्वासपात्र मंगलिया काला को दुर्ग की स्थिति का पता लगाने हेतु भेजा एवं स्वयं मंडौर से थोड़ी दूरी पर अपनी सेना सहित रुक गया। मंगलिया से दुर्ग की स्थिति का पता लगा जोधा ने अर्धरात्रि में दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ी सेना के प्रमुख योद्धा मारे गये और मंडौर दुर्ग पर राव जोधा का अधिकार हो गया। (7) इस तरह से राव जोधा ने मंडौर में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसके बाद जोधा ने मारवाड़ में स्थापित मेवाड़ की अन्य सैनिक चौकियों पर भी आक्रमण कर दिये। सबसे पहले जोधा ने चौकड़ी पर आक्रमण किया। जहां पर मेवाड़ के राणा की ओर से जोधा का चचेरा भाई राघवदेव सहस्रमलोत को नियुक्त किया हुआ था। युद्ध के बाद राघवदेव भाग खड़ा हुआ और चौकड़ी पर जोधा का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने कोसाना पर अधिकार किया और सोजत के निकट धणला गांव में मेवाड़ी सेना को पराजित किया। इस तरह से राव जोधा ने मारवाड़ को मेवाड़ी आधिपत्य से मुक्त करवाया।

मंडौर पर आधिपत्य के बाद राव जोधा ने महाराणा कुंभा से अपने पिता की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई। इधर महाराणा कुंभा भी मारवाड़ में मेवाड़ी सेना के परास्त होने एवं अपने कई योद्धाओं एवं सामंतों के मारे जाने के कारण क्रुद्ध था। रावत चूंडा भी राव जोधा का प्रबल विरोधी था। जोधा की एक विशाल सेना मारवाड़ पर आक्रमण के उद्देश्य से पाली की तरफ रवाना हुई। अश्वों का अभाव होने के कारण मारवाड़ी सेना बैलगाड़ियों में सवार होकर ही युद्ध के लिए निकल गई। उधर मेवाड़ की भी एक विशाल सेना मारवाड़ की ओर रवाना हुई। किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि जोधा की

सेना बैलगाड़ियों में आ रही है और वे युद्ध से कदापि पीछे नहीं हटेंगे तो मेवाड़ी सेना में आतंक छा गया और वह बिना युद्ध किये ही पाली से वापस लौट गई।

इससे राव जोधा की सेना बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई और उन्होंने मेवाड़ी भूमि में प्रवेश कर चित्तौड़ दुर्ग के द्वार जला दिये। चित्तौड़ आक्रमण से लौटते समय सेना मेवाड़ के सेठ पदमचंद को बंदी बना लाई। यह सेठ बहुत सारा धन भेंट कर कैद से मुक्त हुआ। सेठ के धन से मेहरानगढ़ किले के निर्माण में भी सहायता मिली। किले के पास सेठ की स्मृति में पदमसागर तालाब बनवाया गया।

सांखला नापा के कहने पर महाराणा कुंभा ने भी राव जोधा से विरोध नहीं बढ़ाया। महाराणा ने राजकुमार उद्ध व सांखला नापा को भेजकर राव जोधा से संधि कर ली। संधि की शर्त के अनुसार आंवले के पेड़ों वाली भूमि महाराणा के और बबूल के पेड़ों वाली भूमि राव जोधा के अधिकार में रहेगी।(8) 1458 ई. में मंडोर के किले में राव जोधा का राज्याभिषेक हुआ। राव जोधा के नाम पर मंडोर के पास ही जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया गया।(9) 1459 में राव जोधा ने एक पहाड़ी पर सुहृद दुर्ग का निर्माण करवाया। 1516 ई. में राव जोधा ने अपनी माता कोडमदेसर के नाम पर एक तालाब का निर्माण करवाया तथा एक कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की।

राव जोधा द्वारा जैतारण के सींधलों पर भी आक्रमण किया गया। सींधलों के द्वारा राव जोधा के चचेरे भाई आसकरण सत्तावत की हत्या कर दी गई थी। नरसिंह सींधल जो कि जैतारण का स्वामी थी उसकी मृत्यु होने के पश्चात् उसका पुत्र मेघा वंहा का स्वामी था। राव जोधा ने अपने पुत्र दूदा को जैतारण भेजा। दोनों के बीच में द्वन्द्व युद्ध हुआ जिसमें मेघा मारा गया।(10)

छापर-द्रोणमुख के मोहिलों पर हुई विजय राव जोधा की महत्वपूर्ण विजयों में से थी। राव जोधा भी अब नवीन प्रदेशों को विजित करना चाहता था। छापर के स्वामी अजीतसिंह मोहिल, जो कि राव जोधा का संबंधी भी था, ने मारवाड़ में उपद्रव मचा रखे थे। अतः अजीत सिंह व जोधा के बीच गगराणा में भंयकर युद्ध हुआ जिसमें अजीतसिंह मारा गया। कुछ समय पश्चात् जोधा ने छापर के स्वामी बच्छराज, जो कि अजीतसिंह का भतीजा था, पर भी आक्रमण कर दिया। बच्छराज की मृत्यु हो गई और छापर-द्रोणमुख पर जोधा का अधिकार हो गया। जोधा ने वहां बीदा का नियुक्त कर दिया। लोदी वंश के सामंत सारंगखां और राव जोधा के छोटे भाई कांधल के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कांधल की मृत्यु हो गई। कांधल की मृत्यु की सूचना जोधा

के पुत्र बीका ने राव जोधा को दी। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राव जोधा ने बीका की सेना के साथ मिलकर झांसल नामक स्थान पर सारंगखां से युद्ध किया। युद्ध में सारंगखां की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात् जोधा का साम्राज्य विस्तार हिसार तक हो गया। भारतीय सत्ता में महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोदी वंश के सामंत को पराजित करने के बाद जोधा की गणना उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शासकों में होने लगी।

राव जोधा के पुत्र बीका द्वारा ही बीकानेर की स्थापना की गई। राव दूदा और वरसिंग द्वारा मेड़ते की स्थापना की गई। मारवाड़ में दृढ़ रूप से सामंत प्रथा की स्थापना भी जोधा के शासन काल में ही मानी जाती है। महाराणा कुंभा की हत्या कर उद्धा मेवाड़ का स्वामी बन गया किन्तु राव जोधा के शौर्य और प्रताप को देख उसने राव जोधा को सांभर व अजमेर दे दिये। अत्यन्त प्रतापी होने के साथ जोधा धार्मिक भी थे। उन्होंने गया व प्रयाग की यात्राएं की और गया में लगने वाले करों को समाप्त कराने का प्रयास किया।

उनकी एक रानी हाडी जसमादेवी ने किले पास रानीसर तालाब और दूसरी रानी चांद कुंवरी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। राव जोधा को राठौड़ साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। अपने शासन काल में उन्होंने राठौड़ साम्राज्य की सीमाओं में अत्यधिक वृद्धि की। मंडोर राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करने के साथ-साथ मारवाड़ में सुहृद प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। 1545 ई को 73 वर्ष की आयु में जोधपुर में राव जोधा का देहान्त हो गया। उनके स्थापित किये हुए साम्राज्य के बल पर ही उनकी पीढ़ियों ने अनेक वर्षों तक शासन किया।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दशरथ शर्मा, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ. 85
2. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 315
3. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग-1, पृ. 29
4. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 236
5. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग-1, पृ. 31
6. नैणसी री ख्यात, भाग-2, पृ. 119
7. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग-1, पृ. 34
8. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग-1, पृ. 36
9. पं. विश्वेश्वरनाथ रेड, मारवाड़ का इतिहास, भाग-1, पृ. 91
10. नैणसी री ख्यात, भाग-2, पृ. 131-133

\*\*\*\*\*



## पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण

विजय लक्ष्मी जोशी \*

\* सहायक प्राध्यापक, शासकिय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए इसे प्राचीन काल से ही जीवन दर्शन के साथ पिरोह कर रखा गया है। भारतीय वेदों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप देकर पर्यावरण संरक्षण को उँचा दर्जा दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है-

**यावत् भूमंडलं धत्ते, सशैलवन काननम्।**

**तावत्तिष्ठति में दिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी॥**

अर्थात् जब तक धरती पर पर्वत और हरे-भरे वन रहेंगे, तब तक हम और हमारी भावी पीढ़ियाँ जीवित और खुशहाल रहेगी। आधुनिक जीवन शैली और वैश्वीकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून बनाए जा चुके हैं, किन्तु प्रस्तुत शोध पत्र में उनका वर्णन न करके केवल भारतीय संविधान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों का संक्षिप्त में वर्णन कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण को समझाया गया है।

**शब्द कुंजी**- पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संविधान।

**पर्यावरण की परिभाषा :-** पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि+आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है वातावरण। अतः पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का वातावरण। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को Environment कहते हैं। Environment शब्द दो अंग्रेजी शब्दों Environ+ment से मिलकर बना है। Environ का अर्थ है to encircle अर्थात् घेरना है एवं ment का अर्थ है from all sides अर्थात् चारों ओर से घेरना है। अतएव पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरने से है। अतः पर्यावरण बाह्य आवरण का घटक है।

प्रथम बार पर्यावरण को वृहद रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(क) में परिभाषित किया गया है। धारा 2 (क) के अनुसार – 'पर्यावरण के अंतर्गत जल, हवा और भूमि तथा जल, भूमि और हवा तथा मानव प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर्सम्बन्ध सम्मिलित है।' उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पर्यावरण में

(1) भूमि, जल, वायु शामिल है और

(2) भूमि, जल, वायु तथा मानव प्राणियों एवं अन्य

जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जैविक और सम्पत्ति तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध शामिल है।

**वुडवर्थ के अनुसार :-** 'पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सब बाहरी शक्तियों एवम् तत्वों से है, जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं।'

पर्यावरण का सामान्य अभिप्राय उस वातावरण से है, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जल, वायु, मृदा, वन, वन्य जीव पादप सभी पर्यावरण के

घटक है। पृथ्वी पर पर्यावरण की उपस्थिति के कारण ही मानव जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। वायु, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना करना अशक्य है। अतः पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है।

**पर्यावरण संरक्षण :-** पर्यावरण संरक्षण से आशय है- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना एवं प्रकृति के अनवीनीकरण स्रोत जैसे-जल, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना।

वर्तमान में आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण एवं वाहनों, कारखानों से निकलते धुएँ के कारण, कारखानों से नदियों में हानिकारक रसायनों के बहाव के कारण पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण हो रहा है एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे भविष्य में बर्फीले ग्लेशियरों के पिघलने के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ जाएगा एवं पृथ्वी जल में समाहित हो जाएगी, जिससे मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। अतः पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

**पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण :-** भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके संविधान में पर्यावरण संरक्षण को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, के साथ-साथ मूल कर्तव्यों में भी पर्यावरण संरक्षण को समाहित किया गया है। स्टॉक होम घोषणा 1972 जिसे 119 देशों ने स्वीकार किया जिसमें भारत भी शामिल

था, के परिणामस्वरूप भारत में पर्यावरणीय सोच में चतुर्दिक विकास हुआ, संविधान का 42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 इस विकसित सोच का स्पष्ट उदाहरण है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों, मूल कर्तव्यों तथा विधायी प्रविष्टियों में संशोधन करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को व्यक्त कर संविधान ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने सृजनात्मक व्याख्या के द्वारा मूल अधिकारों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करके इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से समझा जा सकता है-

**अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार :** - संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अधीन न्यायपालिका ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल माना है। निम्नलिखित वाद इसके जीवन्त उदाहरण हैं-

**वाद- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य**

के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार में शामिल है।

**वाद- चरनलाल साहू बनाम भारत संघ**

में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल को अनुच्छेद 21, 48-क, और 51-क(छ) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार माना।

**वाद- विरेन्द्र गौर बनाम हरियाणा राज्य**

के वाद में मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन, वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिकी संतुलन और आरोग्य को शामिल माना।

**वाद- एम.सी मेहता बनाम भारत संघ**

के वाद में न्यायालय ने दिल्ली स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कंपनी को ऑलियम नामक खतरनाक गैस बनाने से रोक दिया, जब तक कि कंपनी गैस के रिसाव को रोकने हेतु उचित उपाय नहीं अपनाती है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार के रूप में विवक्षित रूप से स्वीकार किया।

**वाद- एस. के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य**

के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थ्य का रख-रखाव संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

**वाद- राजीव रंजन सिंह बनाम बिहार राज्य**

के वाद में यह विचार व्यक्त किया गया कि डिस्टीलरी के बहाव एवं दुर्गंध के जहरीले और हानिकारक प्रभाव से आवासियों को सुरक्षित करने की असफलता संविधान के अनुच्छेद 47 और 48-क के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 21 में प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन है।

**वाद- एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ**

में पत्थर पिसाई से उत्पन्न पर्यावरण संकट को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि 'प्रत्येक नागरिक का शुद्ध वायु एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने का अधिकार है।'

**वाद- वी. ए. जैकब बनाम सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस, कोट्टायम**

के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार

के अंतर्गत सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार है और सुरक्षित पर्यावरण में सुरक्षित ध्वनि, सुरक्षित हवा की गुणवत्ता भी शामिल है।

**अनुच्छेद 32 :-** अनुच्छेद 32 नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में लोकहित वाद दायर करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का प्रयोग कर कई समाजसेवियों एवं संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण के मूल अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर कर पर्यावरण संरक्षण में इस अनुच्छेद 32 के महत्व को सार्थक किया है।

**वाद- वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ**

के वाद में वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर करके तमिलाण्डु में चमड़ा तथा अन्य व्यवसाय करने से निकलने वाले अशुद्ध मलवे से पर्यावरण को होने वाली भंगकर हानि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने पर न्यायालय ने चमड़ा कारखानों को बंद करने एवं प्रत्येक चमड़ा कारखाने पर 10 हजार रुपये प्रदूषण दण्ड लगाने का आदेश दिया।

**वाद- इण्डियन काउन्सिल फॉर इनविरोमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ**

के वाद में एक पर्यावरण वादी संस्था द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर कर देश के रासायनिक कारखानों के आस-पास रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे कारखाने जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना स्थापित किए जाते हैं और कानून का उल्लंघन करके अपने आस-पास रहने वाले नागरिकों को प्राप्त दैहिक स्वाधीनता को हानि पहुंचाते हैं, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय ने दोषी कंपनी को पीड़ितों को प्रतिकर देने का आदेश दिया।

**अनुच्छेद 48क :-** अनुच्छेद 48क संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसके अनुसार 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'

**वाद- सच्चिदानंद पाण्डेय बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य**

के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कभी न्यायालय के समक्ष पारिस्थितिकी से संबंधित कोई समस्या प्रस्तुत की जाएगी, न्यायालय अनुच्छेद 48क और अनुच्छेद 51क(छ) को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।

**वाद- टी. दामोदर राव बनाम एस. ओ. म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैदराबाद**

के मामले में न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 48क और 51क(छ) के आलोक में यह स्पष्ट कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही नहीं है बल्कि न्यायालय सहित राज्य के सभी अंगों का दायित्व है।

**अनुच्छेद 51क(छ) :-** स्टॉकहोम घोषणा 1972 से प्रेरित होकर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4क मूल कर्तव्य में 51क(छ) के रूप में पर्यावरण संबंधी नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान का अनुच्छेद 51क(छ) यह उपबंधित करता है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उनका

संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

**अनुच्छेद 252 :-** संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अनुसार 'यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मंडलों ने यह संकल्प पारित कर दिया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि को अन्य राज्य भी संकल्प पारित करके अंगीकार कर सकते हैं। संसद ने इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न राज्य मण्डलों की सहमति पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1954 पारित किया है।

**अनुच्छेद 253 :-** संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के क्रियान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची का विषय क्यों न हो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। संसद ने इस अनुच्छेद में दी गई विधायी शक्ति का प्रयोग कर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है।

**निष्कर्ष :-** अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु फिर भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम पूर्णतः सफल नहीं हो पाये हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न केवल मानव स्वास्थ्य पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई **मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23** के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण 2030 तक जीडीपी में 4.5% तक की गिरावट का अनुमान है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अतः हम सब को मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी आनी वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर एक हरी-भरी पृथ्वी छोड़कर जाए।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, चतुर्थ संस्करण, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 2006
2. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, 42वां संस्करण, इलाहाबाद, CLA, 2009
3. The study IQ, 21 october 2021, पर्यावरण की परिभाषा, 22 march, 2024, <https://www.thestudyiq.com>.
4. Social-work.in, 22 february 2023, Paryavaran-Kya-hai, 21 march, 2024, <https://socialwork.in>.
5. Drishti Ias, How pollution impact Economic growth?, 4 may 2024, <https://youtu.be/0Nuyk9ISh70?si=m7PkWfbTXZd47gOj>.

\*\*\*\*\*

## दमोह जिले के पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन

ललित ताम्रकार\* डॉ. आभा वाष्ण्य\*\*

\* शोधार्थी (भूगोल) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक, कमला राजा महिला महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - पर्यटन किसी भी क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दमोह जिला प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों से भरपूर है। परंतु संरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण यह क्षेत्र अपेक्षित पर्यटन विकास प्राप्त नहीं कर सका है।

इतिहास में जाकर यदि देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि इस जिले का पुराना नाम तुंडीकेर था तथा इसे अपना वर्तमान नाम राजा नल की पत्नी रानी दमयंती के नाम से मिला। 14वीं शताब्दी में दमोह मुगलों के अधिकार क्षेत्र में रहा तत्पश्चात 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह ने दमोह को अपने साम्राज्य में शामिल किया। बुंदेलो और मराठों का भी कुछ समय इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। इस प्रकार अपने समृद्ध इतिहास के साथ दमोह जिले ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। यही कारण है कि यहां पर ऐतिहासिक अवशेष बिखरेपड़े हुए हैं, जिनके उचित रखरखाव से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में इस जिले के पर्यटन स्थल लाभ करने की स्थिति में नहीं हैं बल्कि अल्प विकसित होने के कारण आसपास के पर्यटकों के लिए भी अज्ञान बने हुए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य स्थलों पर उपलब्ध आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं पर विमर्श करना है ताकि इन सुविधाओं की उपलब्धता में जो कमियां हैं उन पर प्रकाश डाला जा सके एवं भविष्य में इन कमियों को पूरा कर इस क्षेत्र में आदर्श पर्यटन स्थलों का विकास किया जा सके।

### अनुसंधान प्रश्न

(अ) दमोह जिले के के पर्यटन स्थलों पर कौन-कौन सी संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध हैं?

(ब) इन सुविधाओं में क्या कमियां हैं?

(स) इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

**अनुसंधान विधि**-यह शोध गुणात्मक प्रकृति का है। जिसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु सर्वेक्षण एवं क्षेत्रीय अवलोकन किया गया है तथा चयनित स्थानों पर आने वाले पर्यटकों से, आसपास के लोगों से, वहां के कर्मचारियों आदि से साक्षात्कार करके भी शोधार्थी द्वारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया गया है। जबकि द्वितीय तथ्यों के संकलन हेतु सरकारी रिपोर्ट, जिले की वेबसाइट, पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

**अध्ययन क्षेत्र का परिचय**-दमोह जिला मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में

स्थित है, जो 23° 09' उत्तरी अक्षांश से 24° 27' उत्तरी अक्षांश तक तथा 79° 03' पूर्वी देशांतर से 79° 57' पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसका क्षेत्रफल 7306 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला सोनार नदी के दक्षिण-पूर्व में लगभग 12 मील पठारी क्षेत्र में स्थित है तथा यह क्षेत्र 595 मीटर की औसत ऊंचाई में स्थित है। यह जिला भौगोलिक रूप से रीवा-पन्ना के पठार पर स्थित होने के कारण यहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। यहां गर्म और आर्द्र ग्रीष्म काल, मध्यम और शुष्क सर्दी तथा वर्षा का मौसम होता है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर तथा गर्मियों और सर्दियों का औसत तापमान क्रमशः 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा 12.5 डिग्री सेल्सियस रहता है।

यह जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यह जिला रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा अपने आसपास के जिलों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह जिला पश्चिम में सागर से दक्षिण में जबलपुर और नरसिंहपुर से तथा पूर्व में पन्ना और कटनी से घिरा हुआ है। शहर का नाम पौराणिक हिंदू कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर रखा गया है।

### जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता

**(अ) बांदकपुर**-यह स्थान दमोह कटनी-मार्ग पर दमोह से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर भगवान जागेश्वर नाथ स्वयंभू रूप में स्थापित हैं इस कारण इस स्थान को जागेश्वर धाम भी कहा जाता है। इसी मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय, मुंडन स्थल एवं विवाह मंडप बने हुए हैं यहां का संस्कृत विद्यालय भी अपने धार्मिक प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध है। इस स्थान की मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर सवा लाख कांड़ियों द्वारा लाए गए जल को भगवान शिव पर चढ़ाने से माता पार्वती तथा भगवान शिव के मंदिरों पर लगी दो-दो ध्वज जो माता पार्वती एवं भगवान शिव के प्रतीक हैं एक दूसरे की ओर झुककर आपस में मिलकर अपने आप बंध जाते हैं। इस साक्षात चमत्कार के दर्शन हेतु दर्शनार्थी लाखों की संख्या में यहां उपस्थित होते हैं।

यदि इस क्षेत्र के संरचनात्मक विकास की बात की जाए तो यह क्षेत्र रेल तथा सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है लेकिन प्रसिद्ध स्थल होने के बाद भी यहां का रेलवे स्टेशन विकसित नहीं है तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मंदिर क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो पता चलता है कि मंदिर का बाहरी क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण है एवं स्वच्छता का अभाव है तथा बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा नहीं है। यह

क्षेत्र सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के कारण ही प्रसिद्धि प्राप्त है किसी अन्य प्रकार के पर्यटन या भ्रमण क्षेत्र न होने के कारण इस क्षेत्र का पर्यटन सीमित है। यद्यपि यह स्थान आसपास के क्षेत्र में 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है परंतु फिर भी उचित प्रचार तथा मार्केटिंग के अभाव में यह क्षेत्र कम पर्यटक प्राप्त कर पा रहा है।

**(ब) कुंडलपुर**—यह स्थान जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। यह दमोह-पटेरा मार्ग पर दमोह से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां पहाड़ी के ऊपर तथा नीचे 58 जैन मंदिर बने हुए हैं जो 16वीं-17वीं शताब्दी में निर्मित माने जाते हैं यहां अंबिका मठ तथा रुक्मणी मठ नाम के दो राज्य संरक्षित स्मारक भी हैं जिसमें से रुक्मणी मठसे 2002 में चोरी हुई प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया गया है। वैसे तो इस जगह पर मंदिरों वाले स्थान पर सभी प्रकार की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है पर मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र अभी भी अविकसित और ग्रामीण अवस्था में है जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र के पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहां विश्व भर से जैन धर्म के अनुयायियों का आगमन होता रहता है। विशेष मौकों पर यहां पर पर्यटकों की संख्या लाखों में भी पहुंच जाती है।

यहां के लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य एवं अन्य ग्रामीण कार्यों द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं। यदि सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को देखें तो यह क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र है यहां सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं जो 24 घंटे यहां उपलब्ध होते हैं। यहां धार्मिक क्षेत्र की सीमा के अंदर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ छना हुआ जल एवं भोजन की उपलब्धता है जो जैन रीति के अनुसार बनाया जाता है। यद्यपि यह क्षेत्र सड़क मार्ग द्वारा जिला मुख्यालय से ठीक तरह से जुड़ा हुआ है परंतु यहां पर रेल मार्ग अभी तक नहीं पहुंच पाया है जो वर्षों से यहां के लिए प्रस्तावित है। पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में इस स्थान पर उपलब्ध है।

**(स) सिंग्रामपुर**—यह स्थान दमोह से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर दमोह-जबलपुर मार्ग पर स्थित सिंग्रामपुर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक मनोरम ग्रामीण क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटन को अपने आप में समेटे हुए हैं क्योंकि यहां बिल्कुल पास-पास ही कई पर्यटन स्थल स्थित है जिसमें सिंगौरगढ़ किला, निदान कुंड (भैंसा घाट), नजाराप्वाइंट, सद्भावना शिखर, रानी दुर्गावती अभयारण्य आदि प्रमुख हैं। सिंगौरगढ़ किला इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख आकर्षण है रानी दुर्गावती इसी किले से अपना राज-काज देखा करती थीं।

सद्भावना शिखर विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसे कलुमर या कालुम्बे नाम से भी जाना जाता है। नजारा पॉइंट का नाम यहां से देखी जा सकने वाले जंगलों के विहंगम दृश्य के कारण पड़ा है जहां से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से सारे जंगल को देखा जा सकता है। निदान कुंड जलप्रपात (भैंसा घाट) भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है जहां से जल ऊंची पहाड़ी से सुंदर दृश्य बनाते हुए नीचे गिरता है। वैसे तो सिंग्रामपुर के सभी पर्यटन स्थल अपने में अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं परंतु यह स्थान वर्तमान में अपनी योग्यता अनुसार पर्यटकों को प्राप्त नहीं कर सका है।

इसके अतिरिक्त यहां सुरक्षा व्यवस्था जंगली क्षेत्र होने के कारण एकदम शून्य है, जिससे हर समय इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए खतरा बना रहता है। यहां किसी भी प्रकार की आवासीय व्यवस्था नहीं है नही पर्यटकों हेतु आसपास खाने-पीने की सुविधा है अतः पर्यटकों को अपने साथ ही भोजन-

पानी लाना पड़ता है। इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन अपर्याप्त है।

**(द) नोहलेश्वर मंदिर**—यह स्थान दमोह से 24 किलोमीटर दूर दमोह-जबलपुर मार्ग पर स्थित नोहटा ग्राम में स्थित है। इस ग्राम में बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिरों के ध्वंसावशेष देखे जा सकते हैं। इन सभी अवशेषों में नोहलेश्वर मंदिर प्रमुख है जो अभी भी अच्छी अवस्था में है। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक है। कलचुरी नरेश युवराज देव प्रथम की रानी नोहला देवी द्वारा निर्मित यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है जो वास्तु कला की अनुपम कृति है। यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है।

मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां पहुंचना आसान है। स्वच्छता के मामले में भी मंदिर क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। इस क्षेत्र में सिर्फ प्रचार तथा मार्केटिंग का अभाव होने के कारण पर्यटन अपर्याप्त है।

**(ई) रानी दमयंती संग्रहालय दमोह**—यह संग्रहालय दमोह नगर के मध्य स्थान में ही बना हुआ है। इस संग्रहालय का शुभारंभ 25 अगस्त 1989 ई में तत्कालीन राज्यपाल सरला बोवाल द्वारा किया गया था। यह संग्रहालय एक पुराने किले में बना हुआ है। इस संग्रहालय की 5 वीथिकाओं में कलचुरी काल की विशिष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय में छठवीं से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक की अद्भुत प्रतिमाओं को रखा गया है जिसमें अभिविज्ञान राम, त्रिविक्रम विष्णु, बुद्ध भगवान, हेखीव विष्णु अवतार, सूर्य प्रतिमा, नृत्य गणेश, स्वरसुंदरी प्रतिमा आदि प्रमुख हैं।

जैसा कि ज्ञात है यह संग्रहालय शहर में ही स्थित है अतः यहां पहुंचना आसान है। स्वच्छता एवं सुरक्षा भी शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहां की मुख्य समस्या इस संग्रहालय का उचित प्रचार-प्रसार ना होना है।

### तालिका क्र. 01:- जिले के पर्यटन स्थलों पर संरचनात्मक सुविधाओं का विश्लेषण।

क्र.	स्थान	स्वच्छता	सुरक्षा	आवास	परिवहन	भोजन-पानी	मार्केटिंग
1	बाँदकपुर	अपर्याप्त	औसत	अपर्याप्त	पर्याप्त	औसत	औसत
2	कुण्डलपुर	अच्छा	अच्छा	अच्छा	औसत	अच्छा	औसत
3	सिंग्रामपुर	-	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अपर्याप्त	अनुपलब्ध	अपर्याप्त
4	नोहलेश्वर मंदिर	पर्याप्त	पर्याप्त	-	अच्छा	औसत	औसत
5	रानी दमयंती संग्रहालय	अच्छा	अच्छा	-	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त

**जिले में पर्यटन की प्रमुख समस्याएं**—ऐसे तो दमोह जिले में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं पर यदि ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि देश तथा प्रदेश में पर्यटन हेतु दमोह जिले का नाम कहीं भी नहीं आता। कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाकर दमोह जिले को पर्यटन मानचित्र पर उचित स्थान दिलाया जा सकता है-

(अ) जिले के पर्यटन स्थलों का उनकी विशेषताओं के साथ ठीक तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना।

(ब) परिवहन साधनों तथा मार्गों का अपर्याप्त विकास।

(स) स्थलों का अविकसित तथा जीर्ण अवस्था में होना।

(द) कई स्थलों पर सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति होना जिससे सुरक्षा की समस्या होती है।

(ई) पर्यटकों के लिए अच्छे होटलों तथा अन्य आवासीय सुविधाओं की कमी होना।

**पर्यटन विकास हेतु सुझाव**—जैसा कि इस अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि अध्ययन हेतु चुने गए पर्यटक स्थलों में प्रत्येक की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अतः प्रत्येक स्थान के विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(अ) बांदकपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु दूर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए उचित आवासीय व्यवस्था की जानी चाहिए तथा मंदिर के द्वार निर्माण का जो प्लान प्रस्तावित है उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि मंदिर के अंदर होने वाली भीड़-भाड़ को कम किया जा सके और मंदिर के बाहर लगने वाली अस्त-व्यस्त दुकानों से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(ब) कुंडलपुर क्षेत्र विशाल जैन तीर्थ क्षेत्र है जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। साथ ही यहां प्रस्तावित रेल मार्ग निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(स) सिंग्रामपुर एक अपार संभावनाओं वाला पर्यटन क्षेत्र है परंतु यहां पर पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अतः यहां पर चहुँमुखी विकास की आवश्यकता है, जिसमें परिवहन, आवास, स्वच्छता, सुरक्षा, पेय जल, प्रचार-प्रसार सभी शामिल हैं। यहां मुख्य सड़क से पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण भी किया जाना चाहिए।

(द) नोहलेश्वर मंदिर की प्राचीनता की प्रादेशिक स्तर पर मार्केटिंग की

जानी चाहिए तथा इस स्थान पर आयोजित किए गए नोहलेश्वर उत्सव को और भी व्यापक रूप से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना चाहिए।

(ई) रानी दमयंती संग्रहालय दमोह शहर का मुख्य आकर्षण है। शहर के स्कूली तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को इसस्थान के शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इस स्थान का प्रचार हो सके।

**निष्कर्ष**— पर्यटन की संभावनाओं की बात की जाए तो दमोह जिले में ऐतिहासिक अवशेष, प्राकृतिक सौंदर्य तथा मनोरंजन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परंतु निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि यह जिला पर्यटन की दृष्टि से अभी पिछड़ा हुआ है। इस अध्ययन में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं और उनकी कमियों का विश्लेषण किया गया है जिसमें पाया गया कि उचित संरचनात्मक सुधारों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से दमोह जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बेहतर सड़क, होटल, स्वच्छता, सुरक्षा और प्रचार-प्रसार से यह जिला एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन सकता है।

**संदर्भग्रंथ सूची:—**

1. Damoh.nic.in
2. www.mpinfo.org
3. जॉनसन धीरज, दमोह दर्शन
4. दैनिक भास्कर
5. दमोह दृष्टि पत्र - 2047
6. Bais Priyanka Sing, role of historical monuments of Bundelkhand region of Madhya Pradesh in tourism development ( Jiwaji University Gwalior ), 2023

\*\*\*\*\*

## भारत के पुनरुत्थान के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय दृष्टिकोण एवं उसका समग्र अध्ययन

गरीमा राठौर\* महेन्द्र पटेल\*\*

\* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, अशोकनगर (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, बीना (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – भारत के पुनरुत्थान के लिए पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। जो कि मानव जाति के विकास के साथ ही देश यानि भारत का विकास सुनिश्चित है और मानव जाति के लिए उनके पद-पद पर विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है जो कि स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ मनुष्य को जन्म देती है जिससे व्यक्ति बेहतर तरीके से भारत के पुनरुत्थान में योगदान देगा। जल, जीव, जन्तु, मनुष्य एवं वनस्पति यह सब पर्यावरण का एक भाग है। यदि हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो हमारे लिए मानव जाति के विकास के लिए पर्यावरण का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पर्यावरण संरक्षण पुराने काल में कुछ ऐसी परंपराओं के साथ किया जाता था, कि उसका केन्द्र बिन्दु मनुष्य एवं उसके साथ जीव-जन्तु और वनस्पति की रक्षा करना होता था। इसलिए हमें एक होकर मानव जाति के लिए और भारत वर्ष के लिए पर्यावरण संरक्षण को आगे लाना होगा, इसी से ही भारत का पुनरुत्थान निश्चित होगा।

**शब्द कुंजी** – पर्यावरण, नियम, संरक्षण, वातावरण, व्यक्ति, परंपराएँ, प्राचीन, भारतीय, पुनरुत्थान, दृष्टिकोण, जीवन।

**पर्यावरण संरक्षण** – पर्यावरण के शब्द में यह ध्वनि होता है कि 'परि' एवं 'आवरण' से मिलकर 'पर्यावरण' शब्द का जन्म हुआ। 'परि' अर्थात् चारों ओर एवं आवरण यानि घेरा। मतलब पर्यावरण प्रकृति की ऐसी संरचना है, जो कि हमारे चारों तरफ एक आवरण की तरह है। इसके अन्तर्गत जैविक और अजैविक यानि मृदा, जल, वायु तथा रसायन, पौधे, पशु तथा सूक्ष्म जीवाणु आते हैं और इन्हीं सभी चीजों के संरक्षण को जो स्थलमण्डल, वायुमण्डल एवं जलमण्डल से मिलकर बना है, इसी को पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। इसी के अन्तर्गत विधिक पर्यावरण की बात की जाए, तो विधिक पर्यावरण का आशय उन कानूनों, नियमों, विनियमों और नीतियों से है जो कि किसी देश, राज्य या समाज में व्यवसायिक गतिविधियों, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करता है।

**पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टिकोण** – पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टिकोण एक अलग ही महत्व प्रदान करता है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक है भारतीय परंपरा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण जैविक और अजैविक एक संरक्षण है जो कि हमारे आसपास रहता है इसके अंतर्गत हमें अपने आसपास की चीजों को संरक्षण प्रदान करना होता है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का अपना ही महत्व है प्राचीन काल से ही व्यक्तियों के बीच इस विचारधारा को विकसित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण में भारत ने हमेशा ही भाग लिया है उसने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी सहभागी व्यक्त की है और उसे भारतीय स्तर पर लाने का पुरजोर प्रयास किया है भारतीय दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो हमेशा ही भारत में पर्यावरण

संरक्षण के लिए एक आध्यात्मिक अभिवृद्धि को बढ़ावा दिया है उसने इसे संस्कृत से भी जोड़ा है आदिवासी लोगों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कई उपायों को उसने शहर में भी लागू करने की प्रक्रिया की है सबसे ज्यादा पर्यावरण संरक्षण जंगलों में अनुसूचित जनजातियों के द्वारा किया जाता है क्योंकि उनका यह मानना होता है कि उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई है तो यह पर्यावरण है जहां पर वह जीवित रहते हैं और इसी पर्यावरण के द्वारा ही वह अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। इसीलिए भारतीय दृष्टिकोण में वनों और जंगलों में रह रहे व्यक्तियों के खान-पान और उनके रहने के तरीके और उनके पर्यावरण संरक्षण के तरीके, इलाज करने के तरीके पर शोध किया जा रहा है, कि किस प्रकार हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं हुये, तो एक दिन हमारी पृथ्वी खतरे में आ जाएगी और पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण व्यक्ति नकारात्मकता से ग्रसित हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंध किया गया है। पर्यावरणीय विकास के लिए शिक्षा को जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ उत्पादकता के लिए नहीं बल्कि उनकी देखभाल और उनका संरक्षण उनकी महत्वता पर जोर दिया जाने लगा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल, जंगल, जमीन इन तीनों ही चीजों पर बहुत ही ध्यान दिया जाने लगा है। हर साल राज्यों के द्वारा 'पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो' जैसी चीज भी आने लगी हैं। अंकुरण के माध्यम से पेड़ों को लगाना और इसकी मॉनिटरिंग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाने लगा है। जैसे कि बिजली बचाना क्योंकि बिजली जो होती है वह पानी या फिर खदानों के प्रयोग से बनती है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। इसको बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्लास्टिक को यूज न करना, इससे बचना यह भी

हमारा एक नैतिक कर्तव्य माना गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्यों में जो कोशिश की जा रही है यह भी पर्यावरण संरक्षण का ही भाग है जैसे कि हर समाज में राज्य में अगर हम अपने स्तर पर पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखते हैं तो पर्यावरण भी हमारा धीरे-धीरे संरक्षित होने लगता है।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारा भारतीय दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक के साथ कार्य कर रहा है। वह घर-घर जाकर व्यक्तियों को जागरूक कर रहा है, कि किस प्रकार उन्हें पर्यावरण के प्रति चिंतित होना चाहिए। क्योंकि यह वही पर्यावरण है जहां पर आप रहते हैं और श्वांस लेते हैं। अगर आप अच्छे वातावरण में सांस नहीं लेंगे तो कैसे जिंके। पर्यावरण को लेकर पर्यावरण दिवस के दिन कई कार्यक्रम निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन राज्य के द्वारा करवाए जाते हैं। जिससे कि व्यक्तियों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हो सके। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य के द्वारा अंकुर प्रोजेक्ट चलाया गया जिसके अंदर हर व्यक्ति को कुछ पेड़ लगाकर उसकी फोटो को अपलोड करना होता है और इसकी मॉनीटरिंग के लिए उसे हर 2 महीने में फोटो डालकर दिखाना होता है कि वह पौधा कितना बड़ा हो गया है। भारत के पुनरुत्थान के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दें। क्योंकि भारत का विकास यहां पर रहने वाली जनता पर निर्भर करता है और यह विकास भी उन्हीं के लिए किया जा रहा है। अगर वह स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा तो भारत का पुनरुत्थान निश्चित है।

### पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या एवं इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है, हर जगह घने वृक्ष काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है और यह सब पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है।

आज विश्व भर में पर्यावरण सेवा संसाधनों के विनाश की समस्याएं बढ़ रही हैं। जिसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति पारिस्थितिकी संकटों के रूप में आ रही है। प्राकृतिक अवस्था में परिस्थितिकीय संतुलन अपने आप बना रहता है। लेकिन पिछले कई दशकों में मानव के हस्तक्षेप के कारण कई चीजे होना शुरू हुई है। जिनमें भूकंप आना, बाढ़ आना, मरुस्थलीकरण, जैव विविधताओं को संकट, जीव के विनाश आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। परिणाम स्वरूप संतुलन के समय गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और प्राणी तंत्र और मनुष्य के साथ होने वाले पर्यावरण के इस व्यवहार को हम इस प्रकार छोड़ नहीं सकते। इसी प्रयास में मार्च 2022 में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका का एक वार्षिक प्रकाशन है। जिसमें जैव विविधता, वन, वन्य जीव, ऊर्जा उद्योग, आवास प्रदूषण अपशिष्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास भी शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित संस्था है। जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह संगठन भारत में पर्यावरण खराब नियोजन जलवायु परिवर्तन और पहले से मौजूद नीतियों के बेहतर क्रियान्वन आदि से संबंधित मुद्दों को उठाता है।

वहीं अगर बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों

पड़ी तो इसके बहुत सारे कारण थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लेशियर पिघल के समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ा रही है, जो कि बाद में बाढ़ का भी काम कर रहा है। और ज्वार भाटा जो कि पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, यह भी पर्यावरण संरक्षण न होने का एक बहुत बड़ा कारण है।

पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक हॉल इफेक्ट आदि को कम या कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। वन क्षेत्र का कम होना एक बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। जिससे कि पर्यावरण संरक्षण में दिक्कत पैदा हो रही है और पर्यावरण में बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही है।

नदियों का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है जिसका पर्यावरण संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। पर नदियों में ज्यादातर गंदी नालियों का पानी मिलाया जा रहा है और पानी दूषित और विषैला होने लगा है।

ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। कितने पेड़ हम लगाएंगे जिससे की ठंडक पैदा होगी दिन पर दिन पृथ्वी का टेंपरेचर हर 5-10 सालों में दो डिग्री बढ़ता जा रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक चीजों को जन्म दे रहा है।

मेथेन गैसों के साथ-साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भारी उपस्थिति ने ओजोन परत को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया है। घर पर कई क्षेत्रों में अम्ल वर्षा, त्वचा कैंसर हुआ है इसलिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

**पर्यावरण संरक्षण के तरीके** - आज के युग में अगर बात की जाए तो सरकार के प्रयास सराहनीय है। पर सरकार के प्रयास तभी पूरे हो पाएंगे जब व्यक्ति पर्यावरण के लिए अपनी उपस्थिति को प्रासंगिक बनाएगा। अगर आदमी अपनी तरफ से कोई प्रयास न करें तब पर्यावरण का संरक्षण करना सरकार के लिए भी असंभव हो जाएगा। जरूरत है कि हर आम आदमी अपनी जिम्मेदारियां को समझे, वह समझे कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वह कौन से छोटे-छोटे उपाय कर सकता है। हर पुरुष, स्त्री, बच्चों को अपनी-अपनी तरफ से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और एक दूसरे को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ कर जन आंदोलन के रूप में जन भागीदारी को बताना चाहिए। आज का युग वैज्ञानिक युग है। नई-नई खोज और अविष्कार लगातार किये जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का उपयोग करने के लिए उसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, यूट्यूब चैनल जहां भी उसे लगे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के तरीके की अगर बात की जाए, तो व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के तरीके और मुख्य विधियों को समझते हैं। जिनसे की पर्यावरण संरक्षण को सरल बनाया जा सकता है। जैसे की प्रथम प्रयास हमें फॉरेस्ट कन्वर्सेशन का करना चाहिए, क्योंकि पेड़-पौधे, हवा, भोजन के साथ-साथ हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले दैनिक उत्पाद शामिल है, जो की वन से हमें प्राप्त होते हैं या फिर वन्य जीवों से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि पारिस्थितिक संतुलन भी बनाया जा सके और व्यक्ति को इन्हीं सब चीजों की पूर्ति की जा सके। दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा है जिसके अंतर्गत हम पानी के उपयोग को संभाल कर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि व्यक्ति ज्यादातर पानी का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। अगर तीसरे तरीके की बात की जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण कम



फैले और चीजों का उपयोग दोबारा किया जा सके इसी प्रयास में सूती बैग का प्रयोग अगर हम करते हैं और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाते हैं तो प्लास्टिक के द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण को रोका जा सकता है। और जानवरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथे स्तर पर अगर बात की जाए तो सॉइल कन्वर्सेशन यानी मृदा संरक्षण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और पृथ्वी पर हो रहे मृदा के दोहन को रोका जा सकता है। पांचवें स्तर पर बात की जाए तो हम वाटर कन्वर्सेशन यानी जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। जल संरक्षण हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां पर जल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और भारत भी अवस्था में आने में कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी प्राकृतिक नदियां हैं और बरसाती नदियां हैं। उसके बाद भी पानी का कन्वर्सेशन या संरक्षण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है।

अगले पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वाइल्डलाइफ प्रोटैक्शन यह बहुत ही जरूरी है। इसके द्वारा हम उन प्रजातियों को विलुप्त होने से रोक सकते हैं, जो कि आज खतरे के निशान पर है। इसके लिए पेड़ों की कटाई को रोकना, वहां पर पानी की पूर्ति होना, वहां पर हाइवि का न निकलना, यह सब चीज वाइल्डलाइफ रिजर्व को सुरक्षित रखती हैं।

डाइवर्सिटी संरक्षण यानी जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जरूरी प्रक्रिया है। इसके द्वारा हमारी जैव विविधता को बचाया जा सकता है।

**पर्यावरण संरक्षण में समस्याएँ** – पर्यावरण संरक्षण में बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है। इन समस्याओं में वायु प्रदूषण, जलप्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी, कचरे का प्रबंध, भूजल स्तर गिरना और मिट्टी का क्षरण शामिल है। इसके अलावा जंगलों की कटाई और वनों का उपयोग काफी मात्रा में किया जा रहा है। जिससे मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। जिससे कि मनुष्य को कई राज्य में पानी उपलब्ध नहीं है, जिसमें राजस्थान इसमें पहले नंबर पर आता है। वहीं पर अगर गुजरात और दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर वायु प्रदूषण, कंपनियां होने के कारण चरम सीमा पर है। सही बात तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव स्तर पर कार्य बहुत ही निम्न किया जा रहे हैं। जिससे कि पर्यावरण संरक्षण एक सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर हमें पर्यावरण संरक्षण को करना है, तो मनुष्य को एक सही दिशा में कार्य करना होगा और उसे आगे आकर और भी लोगों को प्रेरित करना होगा। समस्याओं का जन्म मनुष्यों के द्वारा ही होता है और आज जो समस्या, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आ रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है। हमें चाहिए कि मनुष्य शिक्षा के साथ-साथ जागरूक भी बने। शिक्षा के महत्व को समझें और अपने दैनिक दिनचर्या में पर्यावरण के प्रति अपनी कर्तव्यों को पूर्ण करें। आज का प्राणी बहुत ही व्यस्त प्राणी है। वह हर उस चीज का उपयोग कर रहा है, जो कि उसके जीवन को सही दिशा की वजह गलत दिशा की ओर ले जा रही है। आज भी कुछ गांव कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर मनुष्य, जागरूकता को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वही कुछ राज्य और गांव ऐसे भी हैं, जहां पर प्रदूषण और पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए आज से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए और अपने आने वाले बच्चों को भी

पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएं। पर्यावरण संरक्षण में अगर सबसे बड़ी समस्या है, तो वह जनसंख्या समस्या है। प्राचीन काल में जनसंख्या कम होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के पास भूखंड अत्यधिक हुआ करते थे। जिसके कारण वह कुएं, तालाब, पेड़-पौधे काफी मात्रा में लगाता था और उसका उपयोग भी करता था। अब जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधन की कमी होती जा रही है और उनका दोहन अत्यधिक हो रहा है। जिसकी वजह से अब पहले जैसे तालाब कुएं का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिससे कि वाटर कन्वर्सेशन में भी कमी आने लगी है और मृदा का संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। हमारी वायु प्रदूषण होने लगी है, हमारा जल भी प्रदूषित होने लगा है और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सिर्फ बातें की जा रही है। लेकिन उसे सकारात्मक रूप नहीं दिया जा रहा है।

**निष्कर्ष** – जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता भी आती है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ लेके चलता है। अगर हम सकारात्मकता की बात करें, तो हर व्यक्ति जो कि पर्यावरण में अपना समय दे रहा है और पर्यावरण में सुधार कर रहा है, साथ में लोगों को जागरूक बना रहा है। ये एक सकारात्मकता है जो कि भारतीय दृष्टिकोण में पाई जाती है। वहीं इसका दूसरा पहलू जो कि नकारात्मक है व्यक्ति पानी को गन्दा कर रहा है, वायु प्रदूषण फैला रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, जंगलों को काट रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। यह एक नकारात्मकता का उदाहरण है। भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण का महत्व सर्वाधिक है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सारे प्रयास किए गए। आज भी मनुष्य पर्यावरण से जुड़कर कई प्रकार के एनजीओ के साथ मनुष्यों को जाग्रत कर रहा है। हमारे भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल के साथ-साथ कॉलेजों में भी शिक्षाओं का प्रारम्भ किया जा चुका है। भारतीय युवा अब जागृत हो चुका है और आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण में भाग ले रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज कानूनों का विकास किया जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण में हर प्रकार के कानून बनाए जा चुके हैं, जिसके द्वारा हर प्रकार से पर्यावरण के लिए दोहन को रोका जा सके। चाहे भूमि की बात हो या फिर वायु, जल, ध्वनि और अन्य प्रकार के प्रदूषणों की। राज्य सरकार सभी को रोकने के लिए कड़े उपबंध बना रही है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (परीक्षा मंथन : अनिल अग्रवाल)
2. पर्यावरणीय विधि (चुनौतियाँ, विश्लेषण और भविष्य : अनूप कुमार और प्रो. बी.सी. निर्मल)
3. पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण विधि की रूपरेखा (डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद)
4. पर्यावरण अध्ययन (मोतीलाल बनारसीदास)
5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (माजिद हुसैन)
6. इंटरनेट
7. न्यूनजपेपर लेख जनसत्ता (पर्यावरण की खातिर)
8. पर्यावरण : भारत सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली : लेखक आर. के. गुप्ता, ऋचा शर्मा)
9. ENN : Environment News Network
10. पर्यावरण पत्रिका : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिन्दी पत्रिका

## न्याय की देवी : भंगाराम माई (बस्तर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग\* प्रो. एन. आर. साव\*\*

\* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.) भारत

**प्रस्तावना** - प्रत्येक क्षेत्र के जनजातियों की अलग-अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएँ होती हैं, जो उनके विशिष्ट पहचान को परिष्कृत करती हैं। जनजाति समुदाय में मृतकों की पूजा देवतुल्य मानकर की जाती है, आत्माओं का विशिष्ट स्थान होता है। धर्म और जादू-टोना कर मान्यता उनके समाज की आस्थाओं की पूर्ति नहीं करता बल्कि प्रकृति से भी जोड़कर रखता है। धर्म और जादू-टोना शारीरिक और मानसिक आस्थाओं की पूर्ति के साथ-साथ उपयोगी साधन के रूप में समाज में स्थापित प्रचलित मान्यताओं को पूर्णजीवित करती है। धार्मिक शक्तियों को जब तक नहीं माना जाता, तब तक व्यक्ति और समाज के लिये हितकारी नहीं होता। धर्म लाभदायक और विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जनजाति समाज में जादू-टोना स्थानीय बीमारियों एवं उनके उपचार के स्वरूप का निर्धारण भी करता है। जीववाद एक जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिये सार्थक मार्ग प्रशस्त करते हैं।

बस्तर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यह आदिम मनुष्य की सबसे अनोखी और दुर्लभ संस्कृति को संरक्षित करने के साथ-साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तान्तरित भी करती है। जनजातियों के अपने नियम और कानून हैं।

छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र हमेशा से ही लोगों के लिए आर्कषक का केन्द्र है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में अनेक जनजाति निवास करते हैं जिसमें गोड़, मुरिया, दोरला, परजा, भरता, धुवा प्रमुख हैं। इनकी अनोखी परंपराएं रहस्यमयी संस्कृति धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी अनेक देवी देवताएँ हैं। ऐसी देवी देवताओं से संबंधित एक प्रमुख देवता है जिनकी अद्भूत अदालत है जो प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान आश्चर्यजनक रूप से देवी देवताओं का अदालत लगता है, यहाँपर जज से रूप में स्थापित देवी '**भंगाराम देवी**' है। देवी देवताओं पर मुकदमा चलाया जाता है और जो भी देवी-देवता अपने कार्यों के प्रति दोषी पाये जाने पर दण्ड भी दिया जाता है। यह अदालत भंगाराम देवी मंदिर में तीन दिनों तक चलती है। इस अद्भूत और अनोखे उत्सव में 240 गाँवों के लोग दिव्य अदालत की प्रक्रिया को जानने के लिए एकत्र होते हैं। जिन देवी देवताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज मिलती हैं उनकी समस्याओं को सुनकर मुकदमा चलायी जाती है। शिकायतें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं- फसल उत्पादन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, लंबी बीमारी, गवाही के रूप में मुर्गियों को प्रस्तुत किया जाता है। जिन लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर और समस्या का समाधान नहीं मिल पाता तो वह देवता दोषी माने जाते हैं। गवाही देने और आरोप सत्य पाये जाने पर दोषी

देवी-देवता के लिए सजा का निर्धारण होता है। देवी-देवताओं के सजा का निर्धारण दो तरीके से होता है उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी-कभी उन्हें जीवन भर के लिए अर्थात् आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और दूसरा उन्हें सुधरने का मौका भी दिया जाता है। यहाँ पर परिवारिक देवी-देवताओं से संबंधित एवं ग्राम देवी देवताओं के लिए सजा का निर्धारण होता है। पहले इस मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित था लेकिन विगत दो तीन वर्षों से महिलाओं को भी प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है।

भंगाराम देवी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करने से साफ होता है कि भंगाराम मंदिर की स्थापना 1700-1800 ईस्वी में राजा भाई राम देव के शासन काल में किया गया था। जनजातियों के विषय में विशेषकर बस्तर के संदर्भ में जानकारी रखने वाले प्रबुद्ध विद्वान **प्रो. एम. अली. एन सैय्यद** के अनुसार :- 'जनजातियों के देवी-देवताओं में विविध अंतर पाये जाते हैं सभी गाँवों में एक ही तरह के देवी-देवताओं को अराध्य मानकर पूजा पाठ, अराधना करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी देवता को सजा मिलती है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। मंदिर के पिछले हिस्से में उन्हें छोड़ दिया जाता है।

स्थानीय ग्रामीणजनों, जनजातियों को इस बात का विश्वास होता है कि भंगाराम देवी द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम फैसला होता है। टॉइम्स ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर डोली, कुल्हाड़ी, बॉक्स, ड्रम जैसे आकार के कुल देवता भी मिले। इन सभी देवताओं की मूर्ति पत्थर और लकड़ियों से बनी होती है। स्पष्ट है कि यहाँ पर मूर्तियों में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से निर्माण किया जाता है।

भंगाराम देवी को लेकर ऐसी मान्यता है कि वह कई शताब्दी पूर्व वारंगल (जो वर्तमान में तेलंगाना) से बस्तर आयी थी। भंगाराम देवी ने यहाँ के स्थानीय राजा से बसने के लिए जमीन भी मांगी थी तब उन्हें केशकाल के पास प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्वतों से परिपूर्ण रमणीय स्थल पर जमीन प्रदान की गयी थी। यहाँ पर अवस्थित डॉक्टर खान के बारे में यह कहा है कि, वे आदिवासियों को हैजा और छोटी माता जैसी महामारी के दौरान मद्द की थी। उन्हें स्थानीय लोग देवतुल्य मानकर देवता का दर्जा दिया था। खान डॉक्टर एक छड़ी के रूप में भंगाराम देवी के मंदिर में स्थापित है। ग्रामीण लोग उन पर नीबू और अण्डे अर्पित करते हैं। डॉक्टर खान नागापुर से बस्तर आये थे, बस्तर में यह वह स्थान है जहाँ पर भक्तगणों के संकट का निदान करने पर देवताओं का परीक्षण और निर्णय किया जाता है। बस्तर के केशकाल घाटी के शिखर पर भंगाराम देवी का दरबार लगता है।

केशकाल में देवी भंगाराम माई का मंदिर न्याय की देवी के रूप में सैकड़ों वर्षों से पूजनीय है। जहाँ वर्ष भर में किये गये कार्यों का लेखा जोखा होता है। आदिम व्यवस्थाओं ऐसी हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं जिन देवी-देवताओं की पूजा पूरी आस्था और विश्वास की जाती है। उन्हीं देवी-देवताओं को भक्तों के शिकायतों के आधार पर दण्ड भी दिया जाता है। यह दण्ड सामान्य दण्ड नहीं होता बल्कि सामूहिक बहिष्कार, निष्काशन, आजीवन सजा, सुधारने का मौका जैसे सम्मिलित हैं। देवी की अदालत में ग्रामीण वकीलों की भूमिका का निर्वहन करते हैं और मुर्गियों को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हर सुनवाई के बाद मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है तत्पश्चात सजा का ऐलान किया जाता है और इसे देवी की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाता है। प्रोबेशन और पैरोल की तरह भंगाराम मंदिर में केवल सजा नहीं मिलती बल्कि यहाँ पर देवी सुधार का भी अवसर देती है और अगर सुधार जाते हैं तो उन्हें फिर से मंदिर में रख लिया जाता है।

इन आस्थामूलक परम्पराओं को बाह्य व्यक्तियों की नजर में मूल्यांकित करना गलत होगा। इस परम्परा को मंदिर के पांचवी और छठी पीढ़ी के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष बात यह है जिन देवी-देवताओं के आरोप सिद्ध हो जाते हैं उनकी मूर्तियों पर लगी सोने और चांदी के श्रृंगार को नहीं हटाया जाता। अब तक बाहर रखी मूर्तियों की चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है क्योंकि जनजातियों की मान्यताएं हैं कि उनका ऐसा कृत्य दैविय न्याय की मांग करेगा। किसी भी अदालत की तरह मंदिर में एक बही-खाता भी रखा जाता है जिसमें सभी मामलों का विवरण सूचीबद्ध होता है। आरोपी देवताओं की संख्या, उनके कथित अपराधों की प्रकृति, गवाह और अंतिम निर्णय सब कुछ इनमें दर्ज होता है। हर चीज का दस्तावेजीकरण होता है कि कितने देवता उपस्थित हुए और कितने को दण्डित किया गया है।

प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था भिन्न-भिन्न होती है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुछ नीति-नियमों का निर्माण किया जाता है, जो नियमों का पालन करते हैं तो समाज में व्यवस्था बनती है और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करने उन्हें दण्डित भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार देवी-देवताओं से संबंधित भी नियम होते हैं उन्हें अपने कर्जव्यों का निर्वाह करना होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर दण्डित होना पड़ता है। बस्तर जिले के केशकाल कस्बे में प्रतिवर्ष **भादों जात्रा उत्सव** उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ की भंगाराम देवी इस क्षेत्र के **नौ परगना** के राजस्व ग्राम में स्थापित एक हजार से भी अधिक ग्राम देवी देवताओं की प्रमुख अराध्य देवी है। भादो महीने के अंतिम शनिवार को सभी भंगाराम देवी के दरबार में उपस्थित होते हैं। इससे पूर्व देवी भंगाराम की सेवा, अराधना, पूजा, लगातार छः शनिवार तक होती है।

उपस्थित देवी देवताओं का परम्परानुसार स्वागत कर उन्हें पद और प्रतिष्ठा के अनुसार स्वागत करके स्थान दिया जाता है। इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में पुजारी, गायता, सिरहा, ग्राम प्रमुख, मांझी-मुखिया और पटेल भी सम्मिलित होते हैं। पूजा-सत्कार के पश्चात वर्ष भर प्रत्येक गांव के सुख-शांति, सबके स्वास्थ्य रहने, अच्छी उपज और किसी भी तरह से दैवीय आपदा से हर जीव की रक्षा के लिए मन्नत मांगी जाती है। देवी देवताओं को प्रसन्न और शांत रखने के लिए प्रधानुसार बलि और अन्य भेंट भी दी जाती है। बिना मान्यता के किसी भी नये देव की पूजा का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। यहाँ सजा के प्रावधान होते हैं वह भी लोगों को अचंभित करने वाला होता है। न्यायाधीश के रूप में भंगाराम देवी सजा का निर्धारण करती है। देवी-देवताओं को यहाँ निलम्बन, बर्खास्तगी, मान्यता समाप्ति से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है। इस पूजा में 20 कोस बस्तर, 7 पाली ओड़िसा, 10 परगना सिहावा के 500 से अधिक देवी-देवता सम्मिलित होते हैं। वर्ष भर में लगने वाले इस मेले में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भंगाराम माई के अलावा डॉक्टर देव, किसौली देव, फण्डपार बाबा भी उपस्थित होते हैं। इस वर्ष 200 आंगा देव, डोली, छत्र, डाँग के अनेक देवी देवता शामिल हुए। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि हर विपत्ति के लिए देवी-देवता ही जिम्मेदार होते हैं, विभिन्न गांवों से आये देवी-देवताओं में से शैतान देवी देवताओं की शिकायत की जाती है। तत्पश्चात आंगा, डाँग, डोली के साथ लाए गये मुर्गी, बकरी, डाँग को खाई नुमा गहरे गड्डे के किनारे फेंक दिया जाता है। उन्हें ग्रामीण कारागार (जेल) कहते हैं। वास्तव में धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उस विश्वास और अधिमान्यताओं को दर्शाता है जो मानवीय सोंच से परे होते हैं। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीकरण के विकास होने के कारण इसका प्रभाव सभी समाजों में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन परिवर्तन के इस दौर में उसपर अटूट विश्वास, धर्म और धार्मिक मान्यताओं को जीवंत रख कर अपने विशिष्ट पहचान से साक्षात्कार कराते हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 NBT नवभारत टाइम्स 08 सितम्बर 2024, <https://naybharattimes.indiatimes.com>
- 2 जनसत्ता 10 सितम्बर 2024 (पवन उप्रेती)
- 3 The Times Of India
- 4 NDTV India
- 5 बस्तर भूषण
- 6 Express MPCG NEWS
- 7 Research Journal of Humanities and Social Science.

\*\*\*\*\*

## शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर में पाए जाने वाले इथनोमेडिसनल पौधों का अध्ययन

**डॉ. राजेश बकोरिया\***

\* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर जिले का एक मात्र कन्या महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में लगभग 150 पौधों में से कुछ इथनो-मेडिसनल पौधे हैं जैसे नीम, तुलसी, शीशम, आक, धतूरा, आंवला, गोंदी, रातरानी, नींबू, गुड़हल आदि इन पौधों में से इस रिसर्च पेपर में हम पाँच इथनो-मेडिसनल पौधे अपामार्ग, जामुन, तुलसी, नींबू एवं सहजन के बारे में विस्तृत वर्णन कर रहे हैं।

क्र.	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम	कुल
1	नीम	एजेडेरेवटा इंडिका	मेलीऐसी
2	तुलसी	ऑसीमम सेंक्टम	लेमीऐसी
3	रातरानी	सेक्ट्रम नॉक्टर्नम	सोलेनेसी
4	नींबू	सिट्रस ऑरेंटीफोलिया	रूटेसी
5	शीशम	डेलवर्जिया सिस्सु	फेबेसी
6	आक	केलोट्रोप्रिस प्रेसेरा	एस्क्लेपियाडेसी
7	धतूरा	धतूरा स्ट्रेमोनियम	सोलेनेसी
8	आंवला	फाइलेंयस एम्बलिका	फाइलेंथेसी
9	बेलपत्र	एगल मार्मेलोस	रूटेसी
10	लेमनग्रास	सिम्पोगान प्लेक्सुओसस	पोऐसी
11	गुड़हल	हिबिस्कस रोजा-साइनेसिस	मालवेसी
12	अशोक	सराका इंडिका	फेबेसी
13	करंज	पोंगैनिया ग्लैब्रम	फेबेसी
14	कबीट	सिमोनिया एसीडिसिनिया	रूटेसी
15	गिलोय	टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया	मेनीस्पर्मिएसी
16	जामुन	साइजीजियम क्यूमिनी	मिर्टेसी
17	पुंवार	केसिया टोरा	फेबेसी
18	भटकटेरी	सोलेनम जेन्थेकारपम	सोलेनेसी
19	मीठा नीम	मुराया कोएगिनी	रूटेसी
20	सहजन	मोरिंगा ओलीफेरा	मोरिंगेसी
21	अरंडी	रेसीनस कम्प्यूनिस	यूफोरबिएसी
22	अपामार्ग	एकाइरेंथस एस्परा	एमेरेंथेसी
23	पीली कनेर	थेर्वेसिया पुरवियाना	एपोसाइनेसी
24	अनार	प्यूनिका ब्रेनेटम	लिथेसी
25	आम	मेंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डियेसी
26	इमली	टेमरेडिस इंडिका	फेबेसी

27	एलोय वेरा	ऐलो बार्बर्डिसिस	लिलियेसी
28	पीपल	फाइकस रिजेजीओसा	मोरेसी
29	गुलर	फाइकस रेसीमोसा	मोरेसी
30	सत्यानाशी	आर्जीमोन मेक्सिकाना	पेपावरेसी

### 1. अपामार्ग (लटजीरा)

सामान्य नाम - अपामार्ग

वानस्पतिक नाम - एकाइरेंथस एस्परा

कुल - एमेरेंथेसी

यह पौधा भारत में जंगली अवस्था में गाँवों, शहरों में रोड के किनारों पर सर्वत्र पाया जाता है यह सामान्यतः बारिश के मौसम में पाया जाता है, शीत ऋतु में फलता फूलता है एवं गर्मी में सूख जाता है इसके बीज चावल जैसे होते हैं, अपामार्ग का पौधा 1-3 फुट ऊँचा होता है शाखाएँ पतली होती हैं पर्वसंधि फूली एवं मोटी होती है, पुष्प स्पाइक क्रम में लगे होते हैं, कटि युक्त वृत्त होने के कारण फल कपड़े में चिपक जाते हैं। यह कफ एवं पित्त शोधक होता है।

### औषधीय महत्व :

1. अपामार्ग की जड़ खांसी, दमा नाशक होती है इसके 8-10 सूखे पत्तों को हुक्के में रखकर पीने से श्वास रोगों में फायदा होता है।
2. अपामार्ग की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम व 7 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण सुबह शाम ताजे जल के साथ लेने से लाभ होता है।
3. अपामार्ग के बीजों को पीसकर 3 ग्राम चूर्ण चावलों की धोवन से साथ लेने से बवासीर में फायदा होता है।
4. अपामार्ग के पंचाग का काढ़ा 50-60 ग्राम के लगभग खाने से पहले लेने पर पेट दर्द में आराम मिलता है।
5. अपामार्ग की ताजी जड़ 5 से 10 ग्राम पानी में घोलकर पीने से पथरी टुकड़े में टूटकर निकल जाती है।
6. प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले अपामार्ग की जड़ को धागे में बाँधकर कमर में बांधने से प्रसव आसानी से होता है प्रसव के बाद इसे हटा देना चाहिए।
7. बिच्छु, ततैया एवं जहरीले कीड़ों के काटने पर पत्तियों का रस लगाने से जहर उतर जाता है।
8. अपामार्ग के 10-20 पत्तों को 5-10 काली मिर्च एवं 5-10 ग्राम लहसन को पीसकर 05 गोलियाँ बना ले एवं 1-1 गोली खाने से

सर्दी के कारण आने वाला बुखार ठीक हो जाता है।

- अपामार्ग के पत्तों को पीसकर फोड़े-फुंसी एवं चर्म रोगों पर लगाने से ठीक हो जाते हैं।

## 2. जामुन

सामान्य नाम - जामुन

वानस्पतिक नाम - साइजीजियम क्यूमिनी

कुल - मिटिसी

जामुन का पौधा सदाबहार जंगली एवं सर्वत्र पाए जाते हैं, इसका वृक्ष बड़ा 100 फुट ऊँचा तथा 12 फुट तक मोटा होता है इसके पत्ते 3-6 इंच लंबे, 2-3 इंच चौड़े, भालाकार, चर्मवत चिकने चमकीले होते हैं। इसके फल ) से 1 ) इंच लंबे, अंडाकार गहरे नीले काले रंग के होते हैं। इसमें उड़नशील तैल, गैलिक एसिड, वसा, राल आदि पाए जाते हैं। जामुन की गुठली में ग्लूकोसाइड होता है जो डायबिटीज रोधी होता है, छाल में टेनिन पाया जाता है इसमें गोंद भी पाया जाता है।

### औषधीय महत्व :

- जामुन के पत्तों की राख दाँतों एवं मसूड़ों पर मालिश करने से दाँत और मसूड़े मजबूत होते हैं।
- जामुन के 5-6 नरम एवं ताजा पत्तों को पीसकर कुल्ला करने से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं।
- जामुन की 100 ग्राम जड़ साफ करके 250 ग्राम पानी में पीसकर 20 ग्राम मिश्री डालकर सुबह-शाम भोजन से पहले पीने से डायबिटीज में लाभ होता है।
- जामुन के फलों को धूप में सुखाकर चूर्ण बना लें 10-20 ग्राम चूर्ण दिन में तीन बार सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है।
- जामुन के कोमल पत्तों के 20 ग्राम रस में थोड़ी शक्कर मिलाकर दिन में तीन बार पीने से बवासीर में लाभ होता है और खून बहना बंद हो जाता है।
- जामुन की छाल का 2-5 ग्राम चूर्ण 250 ग्राम दूध के साथ 2 चम्मच शहद के साथ पीने से दस्त में लाभ होता है।
- आम तथा जामुन के कोमल पत्तों को (समभाग) 20 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में पकावें एक चौथाई भाग बचने पर काढ़े को ठंडा करके पिलाने से उल्टी में लाभ होता है।
- पके हुए जामुन खाने से पथरी गल कर निकल जाती है।
- जामुन के 5-6 पत्तों का पुल्टिस बाँधने से घावों में से पीव निकल जाती है और घाव ठीक हो जाता है।
- जूता काटने से यदि पांव में घाव हो जाए तो जामुन की गुठली को पानी में पीसकर लगाने से घाव ठीक हो जाता है।

## 3. नींबू

सामान्य नाम - नींबू

वानस्पतिक नाम - सिट्रस ऑरेंटिफोलिया

कुल - रूटेसी

नींबू का पौधा छोटा, झाड़ीनुमा कंटीले वृक्ष होते हैं। पत्तियाँ छोटी होती हैं, पत्तियों को रगड़ने पर सुगंध आती है, फल गोल, चिकने होते हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में हरे तथा पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। नींबू की विशेषता है कि इसके फल पकने पर भी खट्टे रहते हैं यह विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। फलों के रस में सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मेलिक

एसिड आदि पाया जाता है।

### औषधीय महत्व :

- नींबू के रस को मस्तक पर लेप करने से मस्तिष्क रोगों में आराम मिलता है।
- नींबू की दो फाँकों को गरम करके कनपटियों पर एक घंटे तक सेक करने से मस्तिष्क पीड़ा ठीक होती है।
- नींबू के रस में आंवले के फलों को पीसकर बालों में लगाने से रूसी नष्ट हो जाती है।
- नींबू का रस चेहरे पर लगाने से कील मुँहासे ठीक हो जाते हैं।
- झुर्रियाँ ठीक करने के लिए नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए।
- जीभ के छालों व मसूड़ों पर नींबू का छिलका रगड़ने से लाभ होता है।
- भोजन करने के बाद होने वाली उल्टी को ठीक करने के लिए नींबू का रस 5-10 मि.ली. सेवन करना चाहिए।
- नींबू के रस का सेवन करने से आंतों के अंदर टायफाइड दस्त, हेजा आदि के कृमि मर जाते हैं।
- सुबह-सुबह खाली पेट 200 ग्राम गुनगुने पानी में 2 चम्मच नींबू का रस और 01 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है।
- दाढ़, खाज, खुजली पर नींबू काटकर रगड़ने से फायदा होता है।

## 4. सहजन

सामान्य नाम - सहजन

वानस्पतिक नाम - मोरिंगा ओलीफेरा

कुल - मोरिंगेसी

सहजन का पौधा छोटा, मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं इसकी छाल एवं काष्ठ मृदु होती है। जब पेड़ पर फलियाँ लगती हैं तो वजन के कारण डालियाँ टूट जाती हैं इसकी शाखाएँ कमजोर होती हैं। इसमें मौरिंगिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है, जड़ में टेरिगोस्पार्मिन होता है जो जीवाणु एवं कवकनाशी होता है इससे गोंद निकलता है जो लाल भूरा होता है।

### औषधीय महत्व :

- सहजन की छाल को जल में घिसकर 1-2 बूंद नाक में डालने से मस्तिष्क ज्वर में लाभ होता है।
- सहजन के पत्तों को पानी के साथ पीसकर लेप लगाने से मस्तक पीड़ा ठीक होती है।
- सहजन के गोंद को मुँह में रखकर चूसने से दाँतों का सड़न रुक जाता है।
- इसकी जड़ के 10 ग्राम रस में 2 ग्राम सोंठ डालकर सुबह शाम पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है।
- सहजन की फलियों की सब्जी खाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं।
- इसकी छाल को जल में घिसकर 10 ग्राम का सेवन करने से सभी प्रकार की सूजन उतर जाती है।
- इसकी छाल का लेप करने से सूजन में आराम मिलता है।
- इसकी जड़ की छाल जल में घिसकर लेप करने से दाढ़ में लाभ होता है।
- सहजन के पत्ते, लहसन, हल्दी, नमक एवं काली मिर्च सभी को समान मात्रा में लेकर एक साथ पीस लें और कुत्ते के काटे हुए स्थान पर लगाने से सूजन उतर जाती है और लाभ मिलता है।
- इसके पत्तों को तेल के साथ पीसकर लेप करने और धूप में बैठने से

चोट व मोच में आराम मिलता है।

11. सहजन की गोंद को तिल्ली के तेल में गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से कान दर्द में लाभ मिलता है।

## 5. तुलसी

सामान्य नाम - तुलसी

वानस्पतिक नाम - ओसीमम सेंक्टम

कुल - लेमीऐसी

तुलसी का पौधा 2-4 फीट उँचा होता है इसकी मंजरी बैंगनी रंग की होती है बीज, चिकना एवं भूरे तथा काले रंग का होता है। यह सर्वत्र सुलभ, सुगंधित, सुंदर होता है। यह सर्वरोग निवारक एवं शक्ति वर्धक होती है। तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व का होता है इसकी पत्तियों में तेल पाया जाता है।

### औषधीय महत्व :

1. तुलसी के पत्रों को नींबू के रस में पीसकर दाढ़, कुष्ठ आदि पर लेप करने से लाभ होता है।
2. तुलसी के 5 पत्ते प्रतिदिन पानी के साथ निगलने से बुद्धि एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है।
3. तुलसी का तेल नाक में डालने से पुराना सिरदर्द ठीक हो जाता है।
4. काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दाँत के नीचे रखने से दाँतों का दर्द दूर हो जाता है।
5. तुलसी के पत्तों का रस छोटी इलाइची तथा अदरक का रस सेवन करने से उल्टी में आराम मिलता है।
6. खाँसी में तुलसी पत्ती का रस 5-10 मि.ग्रा. तथा काली मिर्च का चूर्ण डालकर पीने से खाँसी में आराम मिलता है।
7. तुलसी पत्तों का ताजा रस गरम करके 2-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है।
8. तुलसी का पौधा मलेरिया प्रतिरोधी होता है इस कारण इसके आसपास मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर नहीं रुकते वहाँ से भाग जाते हैं।
9. तुलसी की जड़ को पीसकर सौँठ के साथ मिलाकर पानी के साथ लेने से कुष्ठ में लाभ होता है।
10. घावों को जल्दी ठीक करने के लिए तुलसी के 10-10 ग्राम पत्तों को उबाल कर ठंडा करके उनका लेप लगाना चाहिए।

**निष्कर्ष** - इथनोमेडिसिनल प्लांट भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान

रखते हैं, इनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता रहा है, इस रिसर्च पेपर में हमने तुलसी, नींबू, सहजन, अपामार्ग एवं जामुन के औषधीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया है ये प्राकृतिक औषधियाँ स्वास्थ्य के लिए हितकारी मानी जाती हैं। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एवं एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो हमें विभिन्न संक्रमणों से बचाते हैं, यह मानसिक तनाव को कम करती है। इसकी चाय सर्दी, जुकाम, खाँसी में उपयोग मानी जाती है। नींबू विटामिन २ से भरपूर होता है इसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग वजन कम करने एवं शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में होता है। इसी प्रकार सहजन को सुपरफूड की संज्ञा दी गई है इसमें कई प्रकार के विटामिन, खनिज एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं यह हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन सुधारता है एवं रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप आदि के काम आता है, पत्तियों का उपयोग त्वचा एवं बालों के उपचार में किया जाता है। अपामार्ग में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीइन्फ्लामेट्री गुण होते हैं यह खाँसी, पेटदर्द संबंधी एवं गठिया रोगों के उपचार में काम आता है। जामुन का फल, बीज एवं छाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होती है यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। जामुन के बीजों का उपयोग खाँसी एवं बुखार में भी किया जाता है।

इन सभी के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ इनका प्रयोग सुरक्षित एवं प्रभावी हो सकता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य - आचार्य बालकृष्ण
2. Jain SK. Dictionary of Indian Folk medicine and ethnobotany. New Delhi: Deep Publications Paschimvihar; 1991
3. HEALTH AND MEDICINAL PROPERTIES OF LEMON (CITRUS LIMONUM) M.Mohanapriya\*, Dr. Lalitha Ramaswamy\*\* and Dr.R. Rajendran\*\*\*
4. An industrial cultivation of Tulsi (Ocimum sanctum) for medicinal use and rural empowerment Subhash Chandra, Pradeep Dwivedi, KM Arti and LP Shinde
5. Prasad, P.V.V. & Subhaktha, P.K.J.P. Apamarga (Achyranthes aspera Linn) Medico-Historical review., 2001, 31(1), pp.12
6. Ethnomedicinal plants of Jodhpur District, Rajasthan used in herbal and folk remedies B.B.S.Kapoor and Swati Lakhera\*

\*\*\*\*\*

# Civil-Military Relations: A Comparative Study of India and Pakistan

Dr. Vinay Girotra\* Dr. Ranjit Singh\*\*

\*Assistant Professor & Head (Political Science) Doaba College, Jalandhar (Punjab) INDIA

\*\*Assistant Professor (Political Science) Doaba College, Jalandhar (Punjab) INDIA

**Abstract :** India and Pakistan were ideologically different states but shared same military heritage at the time of independence from British colonial rule in 1947. The military in British India served as its strong shield, but avoided an active involvement in politics and largely accepted the principle of supremacy of civilian elites. The Indian military retained this tradition but Pakistan reflected a major shift. This paper deals largely with the theories of various scholars like Huntington, Fitch, Larry Diamond, and Douglas. C. North for the purpose of generalizing the reasons behind this difference in approach adopted by two neighboring states in terms of various socio-political and religious factors. Further on, this research aims at providing the list of checks and balances required for preventing unwarranted military intervention in domestic politics.

**Keywords:** Civil-Military Relations, Democracy, Military Coups , Authoritarianism, Pakistan Army, Indian Army, Military Intervention, Political Legitimacy ,Civilian Control, Military Dictatorship, Garrison State, Military Governance, Democratic Transition, Military Economy, Nationalism, State-Building, Military’s Role in Development Civilian Authority.

**Introduction** - Democratic theory does not admit the possibility that any group possesses greater legitimacy than the will of the people, determined through free and inclusive elections and tempered by the interplay of constitutionally established institutions.<sup>1</sup>The acceptance of a civilian supremacy over the military elites, whereby the latter willingly execute the policies of the former and only influence policy making in relevant areas through normative, group, or institutional, processes, is crucial to the idea of democracy. Military interventions appear to stem from problems in civilian-military relations which, as Amos Perlmutter notes,<sup>2</sup> is gravely exacerbated in many developing and underdeveloped areas by the absence of a consensus on what the proper civilian-military relationship is, unlike in the West, where a Sandhurst tradition of defending civilian authority prevails. Due to this absence of consensus, the dynamics of civil-military relations significantly vary in various developing states. Some of these have completely adopted the Western model of civilian supremacy. But, at the same time, in few of these societies, the military exercises independent political power, thus turning the “classical” civil-military arrangement “upside down.”<sup>3</sup>

This difference is best represented in the study of military’s role in the politics of India and Pakistan, two neighbouring, nuclear weapon capable states of South Asia. These states were part of one country before independence from British colonial rule in 1947. Pakistan was carved out

of India when Mahatma Gandhi failed to convince Muhammad Ali Jinnah that both Hindus and Muslims could live together in an independent India. The armed forces of India and Pakistan shared common culture, ethos, and traditions, including the acceptance of the principle of civilian supremacy. However, the total subordination of the Indian military by the civilian entity is in direct contrast to the primacy that the Pakistani counterpart has appropriated. Indian Military is an outstanding example of an ‘apolitical and professional force, almost a bureaucratic instrument of state policy’. India’s democratic system is a model for other developing countries. On the contrary, the dynamics of civil-military relations in Pakistan have created an ongoing negotiation for power in which the military, civilian politicians and Islamist forces have individually and in alliance with one another vied for control of Pakistan’s politics.<sup>4</sup>

## Patterns of Government in Pakistan

Civilian Bureaucratic Rule	1947-58
Civilian Authoritarianism	1971-77
Direct Military Rule	1958-62, 1969-71, 1977-85, 1999-2002
Elected Civilian Governments Under Civilian Presidents	1988-99, 2008-
Elected Governments Under Military Presidents	1962-69, 1985-88, 2002-08

Frequent military interventions in politics of Pakistan and their absence in India has initiated a political debate which attempts to explain this difference of approach

towards civil-military relations in terms of various socio-political and religious factors.

In his book 'Political order in changing societies', Huntington has linked the likelihood of a military coup to levels of institutionalization and political participation. He suggested that in a "civil society," where there are high levels of institutionalization but low levels of political participation, civil-military relations were absorbed within a wider, stable political system. In contrast, he argued that in "praetorian societies" with low levels of institutionalization and high levels of participation, the coup becomes the primary way by which the military exerts its institutional influence.<sup>5</sup> Civil society is also considered to play a key role in the consolidation of democracy, in checking abuses of state power, preventing the resumption of power by authoritarian governments and encouraging wider citizen participation and public scrutiny of the state. Such actions enhance state legitimacy; 'a vibrant civil society is probably more essential for consolidating and maintaining democracy than for initiating it'<sup>6</sup>

In India there was undoubtedly the existence of a sizeable 'civil society' which was a product of its politically liberalized society and a general level of religious tolerance in a traditionally historic multi-racial society. It also emerged from a well educated middle class and an enlarging one fuelled by its high rate of economic growth. In the countries where such a middle class does exist, there will always be a call for more personal freedom and democracy. Education and economic progress automatically undermine any autocratic or elitist form of government.<sup>7</sup> Pakistan has not yet developed a large, educated and fairly well to do middle class-a class of people who have overcome traditional clan and tribal loyalties, and have become genuinely interested in personal liberty, independent information media and scope for participation in the political decision making process.

Political culture of two states has also been instrumental in determining the nature and kind of military's role in politics. Finer argues that national political cultures can be assessed and ranked in levels, according to following criteria.<sup>8</sup>

1. Does there exist a wide public approval of the procedure for transferring (political) power, and a corresponding belief that no exercise of power in breach of these procedures is legitimate?
2. Does there exist a wide public recognition as to who or what constitutes the sovereign authority, and a corresponding belief that no other person or centre of power is legitimate or duty worthy?
3. Is the public proportionally large and well mobilized into private associates? Do we find cohesive churches, industrial associations, and political parties (that are capable of acting independently of the state)?

The higher a nation ranks on the first two criteria, the more likely it is that a military coup would be seen as

illegitimate. The higher a nation ranks on the third criteria- that is presence of civil society-the more society can mobilize itself in defense of the legitimate holders of power.<sup>9</sup> In comparison to Pakistan, India was more fortunate in having sound political institutions that functioned in a democratic manner, a strong political party with a mass base, and a team of seasoned political leaders. Pandit Jawaharlal Nehru was India's first Prime Minister for 17 years, from 1947 to 1964 until his death. The respect he enjoyed from general public and his commitment to liberal democratic values laid the foundation of India's political culture which had no role for military in politics. Nehru encouraged parliamentary debate, maintained internal democracy within the Congress party, continued the British tradition of a politically neutral civil service, fostered judicial independence, encouraged press freedom, boosted secularism, and firmly entrenched civilian control of the military.<sup>10</sup> On the contrary, Pakistan lost its two premier leaders Mohammad Ali Jinnah and Liaquat Ali Khan within a few years after independence. This proved to be the decisive factor in determining the future of civil and military relationship in Pakistan, as after them, there was no one left on the political scene of Pakistan who could generate mass support for democratic values. Muslim league relied heavily on the towering personality of Jinnah and afterwards up to some extent on Liaquat Ali Khan. Soon after their death, it began to become disunited and lose direction. Other political parties, established mostly by those depicting from the Muslim league, suffered from similar discord, indiscipline and weak organization. They were neither able to bring forward a national alternative to the Muslim League or evolve a broad based consensus on the operational norms of the polity, and thus failed to produce a coherent government.<sup>11</sup>

Indian National Congress was able to provide stability and better administration to Indian people because of training that it specifically and the Hindus got during the independent struggle - right from the formation of Congress under Dadabhai Naoroji. That training was ingrained in Congress psyche - however inept its brains may have been. This thinking of Indian civilian elites can be well understood in the words of present Prime Minister Manmohan Singh, when he says, "If there is an 'idea of India' by which India should be defined, it is the idea of an inclusive, open, multi cultural, multi-ethnic, multi-lingual society. ... We have an obligation to history and mankind to show that pluralism works. ... Liberal democracy is the natural order of political organization in today's world. All alternate systems, authoritarian and majoritarian in varying degrees, are an aberration."<sup>12</sup> On the other hand, Pakistan falls into the category of what Clifford Greetz calls 'old societies and new states.'<sup>13</sup> It didn't exist prior to independence in discrete form but rather was always part of larger systems. Therefore there was serious lack of elite and experienced civilian politicians, who could guarantee steady development of



civilian political institutions to safeguard democratic civil and military elite relations. Many of the able civilian elites were not that much influential as they belonged originally to the states that were left behind in India and they were not able to attract the popular support in independent Pakistan. Lack of administrative ability in civilian leaders and common man's disrespect towards them and faith in military led the military officers to revise their understanding of the military's proper role.

Pakistan did not have an indigenous bourgeoisie that was rooted to the Pakistani soil. The nascent bourgeoisie that emerged after partition comprised migrants from Bombay, Gujarat and Bengal. The leading members of the Muslim League and the founding fathers were also mostly Indian migrants. Similarly, the bureaucracy, industrial and commercial class were also mostly from the migrant community. In the 1950s, the migrants dominated the government policies. The ruling elites were led by the migrant elites. The army's officer cadre consisting of mostly Punjabis was the local elite. But Muhajirs (the Urdu-speaking migrants) and the Punjabis constituted the bureaucracy. Therefore, Pakistan was known as a Muhajir-Punjabi state, which was criticised by Bengalis, Sindhis and others. For years after independence, this state of affairs continued. The civil-military bureaucracy structurally emerged as 'overdeveloped' institution which in alliance with landed-feudal projected and institutionalised 'Hindu India' to pursue politico economic interests. The military being part of the praetorian oligarchy planned and fought war against India over Kashmir in 1947-48. This exercise helped the oligarchy to rule authoritatively in the 1950s. The civil bureaucracy led the praetorian oligarchy in this period. However from 1958 onward, the military has, from within the praetorian oligarchy, emerged as a powerful political actor due to its coercive power and became leader of the oligarchy.<sup>14</sup> India was also historically the nation of landlords but the power of landlords has been broken over there by the successive Indian governments. As a result, it is now recognized as the largest democracy in the world, while Pakistan, until recently, was defined as a rogue state.

For civilian institution building, it is necessary to have effective constitutive rules of politics. These rules have fundamental impact on how the philosophic vision embodied in political culture of a country is translated into the reality of politics. By establishing precedents and constitutional guarantees, these rules lend legitimacy to certain themes while denying it to others. They also affect, directly or indirectly, who can participate in the domestic political game as well as how.<sup>15</sup> India was able to provide a constitution as early as in 1950 which laid constitutive rules of politics clearly in favour of democratic government headed by civilian elites. This Constitution vests "the supreme command of defence forces of the Union" in the President but he is obliged to be "regulated by law" and actual control is vested in the council of ministers led by the Prime Minister. Conventions

established over the years ensured that "aid and advice" given by the council is authoritative and no President has ever attempted to exercise independent command over armed forces. On the other hand, faced with the task of governing a new nation with considerable linguistic, sectarian, and regional diversity, the civilian leaders in Pakistan proved to be ill equipped for the task. They lacked the skills of negotiation, compromise, and debate that their counterparts in India under the leadership of Pundit Nehru had virtually institutionalized. As a consequence, Pakistan's Constituent Assembly quickly became bogged down, and could not produce a basic law till 1956.<sup>16</sup>

The constitutionally determined role for Indian Army is quite narrow and it provides a check on attempts to politicise the military. The Indian political system is an inspiration for rest of the world. Unlike Pakistan, the Opposition in India plays a vital role and commands respect. Everyone is expected to abide by the law, including the politicians. Military elites in India know that the final power of decision making is always going to remain in the hands of civilian elites. Indian civilian elites were able to provide a political culture where the respect for the civilian institutions like judiciary was unchallengeable but on the contrary, in Pakistan, military elites and even civilian ones, when in power misused institutions like judiciary and press for providing strength to their autocratic rules. Pakistan has so far seen three constitutions—created in 1956, 1962, and 1973—and in 1985 military ruler Zia ul-Haq fundamentally altered the constitution with his introduction of the Eighth Amendment establishing a President-dominated executive so that military could enjoy control over government even when civilians were in power.

Military establishment that deals with many non military functions is likely to be more autonomous and freer from civilian control. Pakistan faced food crisis in many of its parts during 1952 and 1953. Hard pressed civilian government was forced to call for military's assistance in this situation. Army launched operation Jute (1952-53) to solve food problem in country and started many anti smuggling operations too. The anti-Ahmadi riots turned Lahore into a nightmarish inferno in March 1953 and crippled the administrative machinery of the state. This led to the imposition of martial law in Lahore and gave the military its first taste of power in state. There were many other instances where military was called upon for help. All this made impression in general people's mind that military was their only savior and civilian elites lacked the ability to govern. Military elites also started believing that they were more able to govern the state. Field Marshal Ayub Khan has stated in his biography *Friends Not Masters*, "Pakistan's survival was vitally linked to the establishment of a well-trained, well-equipped and well-led army." The army was entrusted with wide and varied duties in 1947. Initially, "it had to assist the depleted ranks of the civil administration in maintaining law and order"; secondly, "there were gigantic

problems of extrication, protection, movement and administration of millions of refugees from India"; thirdly, "it was entrusted with the task of protecting "the Hindus and Sikhs migrating to India"; lastly, it had to protect the new, ill-defined, lengthy and sensitive borders.<sup>17</sup>

After Pakistan formally became a republic in 1956 under President Mirza, it faced an array of serious threats to its stability. Its conflict with India over Kashmir remained unresolved, relations with Afghanistan were poor, and the country suffered continuing economic difficulties, frequent cabinet crises, and widespread political corruption. It was the period of grave crisis for Pakistan. The inability of civilian elites to provide a stable government at centre and their continuously increasing reliance on bureaucracy paved the way for first military regime of General Ayub in 1958. Since then, military has played the most important role in decision making process of Pakistan and has never allowed civilian institutions to flourish. On the other hand India has long been host to free and fair elections leading to peaceful changeovers of power; has a vibrant, spirited press and independent judiciary; has spawned political parties all over the ideological spectrum; and has been defended by a military establishment that has remained firmly under civilian control. Civil supremacy-of-rule in India came under its gravest threat when defeat in the 1962 Sino-Indian War for the first time called into question the competence of the civilian government. However military elites did not try to make use of these circumstances mainly because the Nehru administration took pains to address field officers' grievances with the country's top civil-military personnel, decision-making procedures and resource allocation. Apart from a 21-month interlude of authoritarian "emergency" rule from 1975 to 1977 under a civilian Prime Minister India has never formally suspended democratic procedures.

Religion has played perhaps the most important role in determining the nature of civilian control in two countries. Liberal values of Hinduism have been instrumental in the establishment of democracy with civilian dominance in India. Notwithstanding the caste system in Hinduism, Indian democracy has an inbuilt trend of acceptance for the principle of civilian supremacy. Whereas military is the great reality in the Muslim states and civilian government have existed either with the support of the military or may be if it is indifferent or neutral but never in opposition to it.<sup>18</sup> Huntington has asserted in the Clash of Civilizations that Muslim countries will have the most trouble establishing and consolidating democracy as opposed to Protestant countries. They historically belonged to the Ottoman or Tsarist empires and were only lightly touched by the shaping events in the rest of Europe; they are generally less advanced economically; they seem much less likely to develop stable democratic political systems.<sup>19</sup>

There is an extensive body of literature arguing that many key aspects of democracy are lacking in the Islamic tradition. The lack of separation between religion and the

state is seen as stemming from the Prophet Mohammed's fusion of military and spiritual authority. The lack of space for democratic public opinion in making laws is seen as deriving from the *Koran*, in which God dictated to the Prophet Mohammed the content of fixed laws that a good Islamic polity must follow. The lack of inclusive citizenship is seen as originating in interpretations of the *Koran* that argue that the only true polity in Islam is the fused religious-political community of the *Ummah*, in which there is no legitimate space for other religions. Certainly, with the rise of Islamic fundamentalism these claims have been frequently asserted by some Islamic activists. Especially in the context of the Algerian crisis of 1991–92, this gave rise to scholarly assertions that Islam and democracy are incompatible.<sup>20</sup>

Religious cleavages in a state founded on religion have a limited role to play in the context of mass mobilisation but slogans like "threat to the religion" are often exploited by the elites to mobilise the masses. This is true in the case of Pakistan. At various points of time in its political history, religion has been exploited to gain cheap popularity and fight political opponents. In Pakistan, religion has not only provided a political foundation to the country but has provided legitimacy to the military rulers.<sup>21</sup> The decade-long rule of General Zia was a giant step backward for the development of secular norms and civilian institutions in Pakistan. Zia was a shrewd politician and a religious zealot who believed that Western democracy was inappropriate for Pakistan and who sought to make Islam the dominant national force.<sup>22</sup>

Education also plays important part in determining the nature of civil-military relations in a state. Lipset refers to education predicting that a better educated population entails better chances for democracy and democratic practices. The positive relationship may be because education may teach individuals towards having a higher value of staying politically involved.<sup>23</sup>

In a country with high level of education, one can expect a considerable interest of the population in participating in the process of political decision making. There is a definite desire to be free from political suppression and exploitation, here people want democratic civil-military relations and are prepared to fight for it.<sup>24</sup> In order to follow and perform the democratic norms to its true meaning, there is a need of population that can not only understand but also has the capacity to follow it. After independence when majority of educated non-Muslim migrated to India and influx of uneducated Muslims from India started, there was little hope that the masses of newly born Pakistan would be well equipped to understand and follow the democratic system that would be imposed on them. Muslims also refrained from acquiring Western education as it was considered to be a deviance from the religion. Hindus and Sikhs on the other hand were more integrated into the British system and were already well incorporated into it. So after partition,

there was not much deviance from their usual self and India was able to settle down more easily than its neighbour.

The adult literacy rate, female literacy rate, gross enrollment ratios at all levels, and education index of India have moved way ahead of Pakistan. Health access to the population and infant mortality rates are also better in India and thus the overall picture of social indicators, although not very impressive by international standards, emerges more favorable. The two most important determinants of Pakistan's dismal performance in social development are its inability to control population growth and the lack of willingness to educate girls in the rural areas.

Factors or developments beyond the borders of a nation state can also contribute either to military intervention or to the maintenance of civilian rule. Great powers...citing ideological, geographic and other vital interests...have intervened (directly or indirectly) in the affairs of smaller states to prop up unpopular regimes, help suppress popular revolutions, or bring down "undesirable government." Harold Lasswell suggested that high level of external threat creates a "Garrison state" where the willingness and ability of the military to intervene in politics, as well as the popular acceptability of such actions is very high.<sup>25</sup> From the very beginning Pakistan has faced several external threats. Some of these threats were assumed, some were real, but they all proved source of legitimacy for the ruling military. Over the past 61 years since independence, Pakistan has fought several wars with India, two of them major, primarily over Kashmir. After India and Pakistan effectively became nuclear weapons states in 1998, the localized war over Kashmir, fought at Kargil raised even the fear of nuclear war among world community. Military elites in Pakistan were able to convince general public that they were better than their civilian counterparts to deal with such crisis situations. On the contrary, Indian civilian elites were able to safeguard territorial integrity of nation and after the defeat from China in 1962, were able to emerge victorious against Pakistan on all the occasions. Indian military was ready to work only as a tool in the hand of civilian government for guarding the borders of nation.

Currently, the most dominant theory of coups d'état posits that militaries perform much like interest groups. When the interests of militaries are negatively affected, military officers have a potent rationale to intervene. The Pakistan military not only defines policy - it is entrenched in the corporate sector and controls the country's largest companies. So Pakistan's economic base, its companies and its main assets, are in the hands of a tiny minority of senior army officials. On the contrary, Indian military's corporate interests are limited to salaries and wages of the officers and soldiers. As Pakistan military remains heavily involved in economic activities, it is likely to remain more concerned about their safeguard and this has been sometimes the main reason behind their excessive involvement and even intervention in the politics of the state.

On the contrary, fewer opportunities exist for the Indian military to engage in business undertakings, and thus fewer are the chances for Indian Military to intervene. While political power is prerequisite for the military's exploitation of national resources, the armed forces financial autonomy deepens its interest in retaining control of the state. However, Pakistan's military disagrees with this analysis. Ayesha Siddiqi<sup>26</sup> interviewed 40 senior Pakistani military officers for her study, some of whom had sewed, or were sewing in responsible civilian positions in the Musharraf regime and almost all denied that economic interests had caused the military to intervene, or had any link with its political power. But, no one can deny that the Pakistan Army is not just involved in defense but it also has quite a complex conglomerate. It has direct control over many corporate entities. Most of these small scale and large scale corporate enterprises range the gamete from private security firms and bakeries, farms, schools, to insurance companies, cement and cereal manufacturing plants. Pakistan's generals, Ayesha Siddiqi states, control empires that would put to shame those of many despots worldwide. On average, senior commanders of the Pakistan armed forces retire with legally acquired assets of between \$2.5 and 6.9 million, depending on their rank.<sup>27</sup>

The rule of law, civil liberty or stable methods for peaceful succession in power, educated middle class, military professionalism, workable practices for electing officials and a government and governing process that are legitimate in the eyes of both key elites and the general public are the main indicators of civil-military reforms and signs of civilian control over decision making process in India. The integrated ministry of defense is a crucial locus of civilian control. On the other hand, inefficiency of civilian elites, frequent coups, suspensions and rewriting of the constitution has been the feature of 'praetorianism' in Pakistan. One of the major obstacles in democratization of civil and military elite relations in Pakistan has been the negative role of the ruling elites. Civil-military reforms cannot be affected if elites in power do not want it to happen for. Central European elites were more open to reforming their civil-military relations in democratic shape than were the elites in the former Soviet Union. Pakistan is also such a case where we do not generally see elites in power making strong attempt towards democratization of civil-military relations. The ruling elites in Pakistan enunciated and implemented a conservative domestic policy and an expedient foreign policy. They always supported the strength of 'controlled democracy', with severe limitations on popular participation.<sup>28</sup>

Pakistan has presented a semblance of democracy for the last few months under the pressure of the U.S, but the crucial question is whether the civilian politicians of Pakistan have wrested the political control of Pakistan's governance from the Pakistan Army?<sup>29</sup> If Pakistan does not transcend the dynamic created by an ideology defined

by an overly dominant military, it runs the risk of becoming a failed state with nuclear weapons. It is hoped now that the present democratic transition will lead to a period of peace, stability and sustained development in Pakistan. It is the responsibility of all social and political groups to sustain the present gifted democracy by ridding from the vested interests so as to correct the evils and misdoing of earlier political forces.

**References:-**

1. Fitch, J. S. (1998). *The armed forces and democracy in Latin America*. The Johns Hopkins University Press.
2. Perlmutter, A. (n.d.). Civil-military relations in socialist authoritarian and praetorian states: Prospects and retrospects. In R. Kolkowicz & A. Karbonski (Eds.), *Soldiers, peasants* (pp. 310–331).
3. Ibid, p.318
4. Nasr, V. (2004). Military rule, Islamism, and democracy in Pakistan. *Middle East Journal*, 58(2), 196.
5. Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
6. Diamond, L. (1994). *Political culture and democracy in developing countries*. Lynne Rienner Publishers.
7. Holzhausen, W. (1986). *Vision creates hopes*. University Press Limited.
8. Finer, S. E. (n.d.). *The man on horseback: The role of the military in politics* (2nd ed.). Westview Press.
9. Fitch, J. S. (n.d.). [Pages 120–140].
10. Ganguly, S. (2002). India's multiple revolutions. *Journal of Democracy*, 13, 39.
11. Rijvi, H. A. (2004). *Civil-military relations in contemporary Pakistan*. In R. J. May & V. Selochan (Eds.), *The military and democracy in Asia and the Pacific*. ANU E-Press.
12. Singh, M. (2005, February 25). *Speech at India Today Conclave*. Retrieved from <http://www.pmindia.nic.in/speech/content.asp?id=78>
13. Geertz, C. (n.d.). Old societies. Quoted in R. Jahan, *Pakistan: Failure in national integration* (p. 5). Columbia University Press.
14. Hussein, E. (2005). *Pakistan: Politics in a post-colonial state* (Master's thesis). Lund University, Centre for South and Southeast Asian Studies.
15. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change, and economic preference*. Cambridge University Press.
16. McGrath, A. (2008). The destruction of Pakistan's democracy. In S. Ganguly, *The burden of history*. *Journal of Democracy*, 19(4), 28.
17. Salamat, Z. (1992). *Pakistan: 1947–58*. National Institute of Historical and Cultural Research.
18. Kamal, K. L. (1982). *Pakistan: The garrison state*. Intellectual Publishing House.
19. Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 30–31.
20. Stepan, A. (2000). Religion, democracy, and the "twin tolerations". *Journal of Democracy*, 11(4), 48.
21. Pattanaik, S. S. (1998). Islam and the ideology of Pakistan. *Strategic Analysis*, 22(9). Retrieved from [http://www.ciaonet.org/olj/sa/sa\\_dec98.html](http://www.ciaonet.org/olj/sa/sa_dec98.html)
22. constable P. ,p.18
23. Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. *American Political Science Review*, 53, 79.
24. Holzhausen, W. (n.d.). [Page 4].
25. Lasswell, H. D. (1941). The garrison state. *The American Journal of Sociology*, 46, 455–468.
26. Siddiqi, A. (2007). *Military Inc.: Inside Pakistan's military economy*. Pluto Press.
27. Ibid.
28. Bindra, S. S. (2005). Continuity and change in Indo-Pakistan relations. *World Affairs*, 9(3), 41.
29. Kapila, S. (2008, September 2). The Pakistan army still controls governance. *South Asia Analysis Group*, Paper No. 2828.

\*\*\*\*\*

# NEP 2020: Transforming Higher Education in India

Dr. Nayia Mahajan\*

\*Assistant Professor (Economics) Doaba College, Jalandhar (Punjab) INDIA

**Abstract :** The National Education Policy (NEP) 2020, introduced by the Government of India, represents a significant overhaul of the country's educational system, with a vision to transform India into a global knowledge hub. This paper examines the key provisions of NEP 2020 and explores their potential impact on higher education in India. The policy aims to address challenges in the sector such as quality, accessibility, and inclusivity, while aligning with global educational trends. This paper outlines the policy's major reforms, discusses its challenges, and evaluates the potential outcomes for the Indian higher education system.

**Keywords:** NEP 2020, Higher Education, Indian Education System, Reforms, Inclusivity, Quality Education.

**Introduction** - Education is the basis for fully utilising human potential, creating an equitable society, and supporting the country's development. Providing quality education to all is essential for a country's progress and leadership on the world stage in terms of economic growth, quality and equality, scientific progress, national integration and cultural preservation. Promoting good education is the best way to develop and make the most of a country's talents and resources to benefit people, society, government and the world. In the next decade, India will have the world's largest youth population, and its ability to provide them with the best education will determine its future.

The global education development agenda is reflected in Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDG4), adopted by India in 2015. It aims to "ensure quality and equity in education and promote lifelong learning opportunities for all" by 2030. Overhauling the entire education system to support and promote learning for the achievement of key goals (SDGs) of the 2030 Agenda is required for Sustainable Development.

The world is changing rapidly in the field of information. With the rise of many science and technology giants such as big data, machine learning and artificial intelligence, many unskilled jobs around the world are being replaced by machines, resulting in an increased demand for skilled workers, especially in the fields of mathematics, computer science, and technology. With climate change, increased pollution, and depletion of natural resources, many changes are occurring in the way the requirements of energy, water, food, and sanitation are fulfilled, leading to the need for skilled workers. The increasing number of epidemics around the world still requires collaborative research (approach) in disease control and vaccine development, and the

challenges that arise in society arise when there is much more to learn.

As India moves towards becoming one of the world's three largest economies, the demand for humanities and arts will also increase. In this changing working environment and the global ecosystem, it has become important not only to learn but how to learn. Thus, the education system should be creative, innovative, and adaptive and assimilate new things in a new and changing environment. In addition to science and mathematics, the curriculum should include arts, crafts, humanities, games, sports and physical activity, languages, literature, cultural rules and values, supporting all types and abilities of learners; making learning and supporting learning increasingly effective. Education should build character and prepare students to be moral, conscientious, compassionate, and loving while preparing them to be successful in their jobs.

Major reforms are required to close the gap between current educational outcomes and needs, including efficiency, equity and integrity, from childhood education to higher education. National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to solve many development problems in our country. While addressing India's heritage, the Act refers to reforms in various aspects of the education system, including regulations and management, to create new systems that meet the educational goals of the 21st century, including Sustainable Development Goal 4. It is based on the principle that education should develop not only cognitive skills but also social, moral and emotional.

**Vision of the NEP:** This National Education Policy is a policy in India that will directly help transform India (i.e. Bharat) into a nation that empowers all knowledge

communities by providing quality education, thereby making India a world-class knowledge superpower. The policy envisages that curriculum and teaching should be evolved to ensure that students respect their basic duties and constitution, and be aware of their roles and responsibilities in a changing world. The vision of the policy is to encourage students to take a deep interest in being Indian not only intellectually but also in spirit, wisdom and conduct. A true global citizen emerges from a commitment to human rights, sustainable development, livelihoods and global well-being.

**The Origin:** India formulated its first education policy in 1968 by former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. The second education policy was introduced by the Rajiv Gandhi government in 1986 and some amendments were made to it by the Narasimha Rao government in 1992. Finally, after 34 years, the present government has taken steps and launched the National Education Policy 2020.

To formulate a new education policy, the central government prepared the draft in 2017 under the chairmanship of the Kasturirangam Committee. It was approved by the government of the country in July 2020. Shri Narendra Modi intimated about NEP 2020 through a tweet and also announced that the name of the Ministry of Human Resources Development had been changed to “Ministry of National Education” (Sahu and Bahera, 2022)

**NEP and Higher Education:** National Education Policy, 2020 (NEP) envisages a massive transformation in the Indian education system through– “an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, thereby making India a global knowledge superpower.” It focuses on five core concepts, viz Affordability, Accessibility, Quality, Equity, and Accountability to ensure lifelong learning.

In school education, the 2020 National Education Policy outlines the core values and principles that education should not only develop skills and problem-solving but also social and emotional skills, including cultural awareness (also known as “soft skills”) and talent, Harmony, patience and courage, teamwork, leadership, communication and more. The 2020 NEP in higher education provided great information and advice on many aspects of education, including the transition to multi-disciplinary teaching and learning, home management, promoting good research through the establishment of the National Research Foundation, professional development of teachers, integration of technology, restructuring of regulatory systems, mixed pedagogy, reliable and blended evaluation system and comprehensive content in Indian languages. The policy is expected to have a positive impact on education and make India a global intelligence hub in the next 25 years of “Amrit Kaal”. Its implementation requires the cooperation of the Centre, states, UTs, HEIs, Regulatory Bodies and all other stakeholders. (Ministry of Education,

2020)

The New Education Policy 2020 (NEP 2020) aimed at increasing the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% to 50% by 2035 (Shukla, 2020). It states that all universities must become multi-university by 2040, and all universities are again expected to have 3,000 or more students. By 2030, there will be at least one major disciplinary organization in or near every region. At the same time, individual universities will be cut and all universities will switch to a multidisciplinary approach. The system of ‘affiliated colleges’ will eventually be phased out in 15 years.

Existing complex names of universities such as “Deemed University”, “Affiliated University”, “Affiliated Technical University” and “Unitary University” should be replaced with “university”. The university shall be described as a multidisciplinary institution providing undergraduate and graduate courses with excellent teaching, research and community engagement. (Shukla, 2020)

One of the significant changes will be the set-up of the Higher Education Commission of India (HECI) for all higher education institutions. HECI will act as a single regulator and various responsibilities such as accreditation, financing and training organization will be carried out by a single vertical body. This entity will gradually replace other governing bodies such as the University Grants Commission (UGC) and the All India Council for Technical Education (AICTE).

**Key impact areas:**

1. Quality Universities and colleges through large-scale consolidation.
2. A higher education system that is accessible and inclusive.
3. Equity and Inclusiveness in Higher Education.
4. A quality and well-incentivized faculty at the core of higher education transformation.
5. Promoting excellence through internationalization.
6. Accountability and transparency as levers for improved governance.

**Implementation and Challenges in Implementation of NEP 2020:**

In early August 2021, Karnataka became the first state to issue an order concerning implementing NEP. Three years since the National Education Policy (NEP) launch, most states have either adopted the policy wholly or picked specific parts of it for application. In July 2023, National Digital University launched. While NEP 2020 presents a progressive approach to higher education, its implementation may face several challenges.

**Infrastructure and Resources:** Many Indian higher education institutions face challenges in terms of outdated infrastructure, lack of resources, and limited access to cutting-edge technologies. Addressing these disparities will require significant investment in infrastructure and human resources.

**Teacher Training and Development:** The success of NEP

2020 will depend heavily on the capacity of teachers to adapt to new teaching methodologies and interdisciplinary approaches. A comprehensive teacher training program is essential to equip educators with the necessary skills.

**Equity and Inclusivity:** While the policy emphasizes inclusive education, there is a need for focused efforts to ensure that students from underrepresented communities, such as those from rural areas or economically disadvantaged backgrounds, have equal access to quality higher education.

**Resistance to Change:** As with any major policy reform, there is potential resistance from institutions, faculty, and other stakeholders. Overcoming institutional inertia and ensuring broad-based acceptance of the new policy will be crucial for its success.

There are many hurdles to implementing the policy as it was proposed. Some are discussed below.

**(i) Multiple Exits is not a good idea:** While changing the higher education model with various exit strategies is an important step in reducing the number of people leaving, questions remain over the value of such certificates. The Indians are such that they want to join the business with a degree. Therefore, to adapt to the new system, we first need to eliminate the old idea that “it is necessary to have a degree to find a job.” This is a dangerous paradigm that may destroy the talent of individuals.

**(ii) Multi-disciplinary approach in education:** There is a need for training for college and university teachers to implement this approach. It requires a revision of the curriculum designed to make the curriculum flexible and organic so that thinking and the impact of thinking and skills can be achieved at many levels of education. The policy is required to establish multi-disciplinary institutions for higher education substituting single-disciplinary ones.

**(iii) Funding:** Implementation of any significant measures requires several years of adequate financing. In this regard, NEP said that the country should increase public expenditure to 6% of GDP to achieve the goals of the new policy. Government officials are understandably divided over the economic hardship experienced by much of the population in the face of the Covid-19 pandemic, but there is no clear plan on how to raise capital. The policy wants private schools to provide more scholarships to increase access to low-income students, but the NEP did not discuss how to do that. The new policy requires more public funding; merely increasing education expenditure from 3 per cent to 6 per cent of GDP is not enough to meet demand.

**(iv) Technology Use:** The new education Policy talks about technology use, online and digital education. There is a widespread need for internet access in remote and rural areas as well. As the pandemic has shown, e-learning is the way forward. This will continue to be one of the biggest challenges of the next decade.

The challenges outlined in Mallik’s 2023 study highlight the significant hurdles faced in the implementation of NEP

2020. The policy aims to reform India’s education system and address long-standing issues, but the need for substantial investment in infrastructure, teacher training, and resource allocation is critical. These elements are essential for achieving the ambitious targets set by the NEP, which include universal access to education, improving quality, and integrating technology.

India’s vast size and incredible diversity create significant challenges for implementing NEP 2020. The country has a mix of urban and rural areas, varying levels of economic development, and multiple languages and cultures, all of which require tailored strategies for effective implementation. This diversity means that a one-size-fits-all approach won’t work, and the policy must be adapted to local contexts, needs, and capacities. Additionally, the educational infrastructure and quality of teaching vary widely across states, making uniform implementation even more difficult. Ensuring that resources are equitably distributed and that teacher training and support are available in all regions becomes crucial to avoid deepening existing disparities (Bhandwalker, 2023).

Moreover, the cooperation between the central and state governments is fundamental to the success of NEP 2020. While the policy was developed with input from various stakeholders, its execution will require seamless collaboration across multiple levels of governance. The tension between federal authority and state autonomy is a long-standing issue in India, and it can make policy implementation tricky, especially in a country as diverse as India, where states have different priorities and needs.

The resistance from some states to key NEP policies is a reflection of the complex political, social, and economic factors at play. Some states may fear that the central government is pushing policies that don’t align with their local priorities, or they might feel that they lack the resources or capacity to implement the changes effectively.

For the policy to work, the Center needs to balance its vision with the realities on the ground in each state. This could involve tailoring certain aspects of the policy to suit local needs while ensuring that core objectives are still met. Open dialogue and ongoing consultation with states, as well as providing financial and technical support, will be crucial in overcoming opposition and ensuring smoother implementation. “Creating a shared responsibility and ownership amongst key stakeholders, including the private sector, at the state and district levels that have extraordinary diversity is going to be a major challenge for the education leadership” (Sahoo, 2021).

**Potential Impact on Higher Education:** The successful implementation of NEP 2020 is expected to bring several positive changes to the higher education landscape in India:

**Improvement in Quality:** The emphasis on multidisciplinary education, research, and innovation is likely to result in a significant improvement in the overall quality of education. Institutions will be incentivized to focus on

academic excellence, and students will benefit from a more holistic learning experience.

**Enhanced Access:** The policy's focus on digital learning and inclusive education has the potential to democratize access to higher education. Students from remote areas or disadvantaged backgrounds can benefit from online courses and other distance learning opportunities.

**Global Competitiveness:** By promoting international collaborations and research, NEP 2020 is likely to increase the global visibility and competitiveness of Indian institutions, attracting international students and faculty.

**Skilled Workforce:** The integration of skill development and vocational training into the curriculum will help bridge the gap between academic learning and industry requirements. This is expected to produce a workforce that is better equipped for the challenges of the global job market.

**Conclusion:** The National Education Policy 2020 offers a comprehensive framework for transforming higher education in India. The reforms introduced by NEP 2020 have the potential to address long-standing issues such as quality, access, and inclusivity in higher education. However, the successful implementation of these reforms will depend on overcoming challenges such as infrastructure deficits, resistance to change, and ensuring equitable access for all students. With the right investments and a strategic approach, NEP 2020 could help position India as a leader in global higher education, contributing to both national development and global knowledge exchange.

**References:-**

1. Aithal, P.S., & Aithal, S. (2019). Analysis of higher education in Indian National education policy proposal 2019 and its implementation challenges. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 3(2), pp. 1-35.
2. Aithal, P.S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), pp. 19-41.
3. Bal, D., & Singh, K. (2023). National Education Policy-2020: A driving force for higher education of India. *International Journal of Research in Library Sciences*, 9(4), pp. 200-209.
4. Bhandwalker, S. (2023). Implementation of NEP 2020 at Higher Educational Institutions. *International Journal of Creative Research Thought*, 11(10), pp 125-129.
5. Chatwal, T. (2019). Digitalization of higher education in India: A boom or a bane. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 10(4), pp. 1083-1088.
6. Deb, P. (2020). Vision for Foreign Universities in the

7. National Education Policy 2020: Acritique. *Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies*, pp. 1-29.
8. Gohain, M.P. (2020). NEP language policy broad guideline: Government. *The Times of India*. Retrieved on January 13, 2025 from <https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/nep-language-policy-broad-guideline-government/articleshow/77272709.cms>.
9. Jaiswal, R. (2014). Vocational Education & Skill Development in India. *Tactful Management Research Journal*, ISSN: 2319-7943.
10. Jha, P., & Parvati, P. (2020). National Education Policy, 2020. *Governance at Banks*, 55(34), pp. 14.
11. Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2021). How National Education Policy 2020 can be a lodestar to transform future generations in India. *Journal of Public Affairs*, 21(3), e2500.
12. Mallik, C. (2023). Critical analysis of NEP 200 and Its Implementation. *International journal of novel Research and Development*. 8(6) pp. 877-880.
13. Ministry of Education (2020) available at <https://www.education.gov.in/nep/about-nep>
14. Ministry of Human Resource Development. (2018). All India survey on higher education.
15. Ministry of Education (2020) available at <https://www.education.gov.in/nep/about-nep>
16. National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India.
17. Nayak, S.R., Kant, N., & Anjali, K. (2020). Strategy of using ICT in ODL to disseminate higher education in tribal communities: A case of MP, India. *Asian Association of Open Universities Journal*, 15(2), pp. 189-206.
18. Rana, S., Verma, S., Haque, M.M., & Ahmed, G. (2022). Conceptualizing international positioning strategies for Indian higher education institutions. *Review of International Business and Strategy*, 32(4), pp. 503-519.
19. Sahu, N. and Bahera, H. (2022). National Education Policy 2020: A Historical Perspective. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering & Technology*, 10(VI). Pp. 3767-3773
20. Sahoo, N. (2021). Five Challenges that would shape the outcome of NEP 2020. *Observer Research Foundation (ORF)*. Published on November 26, 2021.
21. Shukla (2020) available at <https://www.hindustan times.com/education/new-education-policy-2020-highlights-key-takeaways-of-nep-to-make-india-a-global-knowledge-superpower/story-eIXTkJrcNJHhXdshWDpu1I.html>

\*\*\*\*\*



# Legal Response to Mob Lynching: Effectiveness, Challenges, and Recommendations

Sarvesh Kumar\* Dr. Surya Sharma\*\*

\*Research Scholar, Jiwaji University Gwalior (M.P.) INDIA

\*\*Assistant Professor, Govt. Law College, Datia (M.P.) INDIA

**Abstract :** Mob lynching, a collective violence form, has become a significant social and legal problem in India. This paper scrutinizes the legal responses to mob lynching, assessing their effectiveness and identifying the challenges faced during implementation. Additionally, it offers recommendations for enhancing legal and social interventions to better address and mitigate the issue. Mob lynching, and extrajudicial killings by groups intending to punish alleged offenders, is rising alarmingly in India, driven by communal tensions, rumors, and deep-seated prejudices. Despite existing legal frameworks, the effectiveness of laws and the justice system in curbing this violence is questionable. India's response includes sections of the Indian Penal Code addressing murder, rioting, and promoting enmity, along with Supreme Court guidelines for prevention and victim compensation. However, prosecution and conviction rates are low due to delays, lack of evidence, and witness tampering. Implementation of guidelines and state-specific laws varies significantly. Challenges include societal prejudices, lack of witness protection, judicial delays, and inadequate police training. Recommendations for improvement involve enacting a comprehensive anti-lynching law, uniform guideline implementation, strong witness protection, fast-track courts, public awareness campaigns, and specialized police training. Strengthening these areas is crucial to combating mob lynching and ensuring justice for victims in India.

**Keywords:** Mob lynching, Collective violence, Legal responses, Effectiveness, Implementation challenges, social interventions.

**Introduction** - Mob lynching, characterized by extrajudicial killings carried out by a group seeking to punish an alleged offender, has seen a disturbing rise in India. This violent phenomenon is often driven by communal tensions, misinformation, and entrenched prejudices. Despite existing legal frameworks aimed at protecting individuals, the persistent issue of mob lynching raises critical questions about the efficacy of these laws and the justice system's ability to address such violence effectively. Recent data underscores the severity of the problem: between 2017 and 2023, over 100 cases of mob lynching were reported across various states. Notably, incidents linked to cow vigilantism and social media-driven rumors have surged. In 2022 alone, there were 28 reported cases, marking a significant increase from previous years. These incidents not only result in loss of life but also cultivate an atmosphere of fear and distrust within communities. Legal provisions, such as Sections 302 and 304 of the Indian Penal Code, which address murder and culpable homicide, and the Supreme Court's 2018 guidelines, aim to mitigate such violence. However, low prosecution and conviction rates, combined with delayed investigations and witness intimidation, highlight the urgent need for more effective legal and social interventions.

**Rising Incidence of Mob Lynching in India:** The alarming

rise in mob lynching incidents in India is a grave concern. Defined as extrajudicial killings by groups aiming to punish alleged offenders, mob lynching is fueled by communal tensions, rumors, and deep-seated prejudices. Recent data accentuates the growing severity of this issue. Between 2017 and 2023, India witnessed over 100 reported cases of mob lynching, reflecting a disturbing trend of violence. The year 2022 alone saw 28 reported incidents, a significant increase from previous years. This rise has been particularly notable in cases related to cow vigilantism and the spread of misinformation via social media. A 2023 report by the National Crime Records Bureau (NCRB) highlighted that states like Uttar Pradesh, Jharkhand, and Rajasthan are among those with the highest incidence of mob violence. These incidents often lead to the tragic loss of life and foster a climate of fear and mistrust in affected communities.

**Legal Framework and Challenges:** India's legal response to mob lynching includes several provisions under the Indian Penal Code (IPC), state-specific laws, and guidelines issued by the Supreme Court.

**Indian Penal Code (IPC):**

- Sections 302 and 304:** Address murder and culpable homicide not amounting to murder.
- Sections 147-151:** Cover offenses related to rioting

and unlawful assembly.

**3. Sections 153A and 153B:** Deal with promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, or language.

**Supreme Court Guidelines:** In July 2018, the Supreme Court of India issued comprehensive guidelines aimed at preventing mob lynching. These include:

1. Appointing nodal officers in each district to oversee and manage cases.
2. Setting up fast-track courts to expedite trials.
3. Establishing compensation schemes for victims.
4. Implementing detailed plans for police training and community outreach.

Despite these measures, challenges persist. A 2023 review revealed that only a fraction of the recommended fast-track courts have been established, and implementation of the guidelines varies significantly across states. For instance, some states have proactively appointed nodal officers and implemented victim compensation schemes, while others have lagged. This inconsistency undermines the effectiveness of the legal framework in addressing mob lynching effectively.

**Effectiveness of Legal Responses:** The effectiveness of legal responses to mob lynching in India is mixed. Prosecution and conviction rates remain low due to delays in investigations, insufficient evidence, and widespread witness tampering. According to a 2023 National Crime Records Bureau (NCRB) report, only 15% of mob lynching cases resulted in convictions between 2017 and 2023. Although the Supreme Court's 2018 guidelines recommended the establishment of fast-track courts, their implementation has been inconsistent. By mid-2023, only a few states had set up these courts, resulting in prolonged legal processes. Additionally, while some states have enacted specific anti-lynching laws, their effectiveness in reducing violence or improving conviction rates is still largely unassessed. Overall, the current legal measures face significant hurdles in addressing the root causes of mob lynching and ensuring timely justice for victims.

**Prosecution and Conviction Rates:** Prosecution and conviction rates in mob lynching cases remain troublingly low. Delays in investigations, lack of concrete evidence, and extensive witness tampering are major obstacles to securing justice. The National Crime Records Bureau (NCRB) report for 2023 indicates that only 15% of mob lynching cases led to convictions between 2017 and 2023. Despite recommendations from the Supreme Court in 2018 to establish fast-track courts for expediting trials, implementation has been uneven. By mid-2023, only a small number of these courts had been established, leading to prolonged legal processes. This has discouraged victims and their families from pursuing justice and highlights the need for more effective legal interventions and procedural reforms to address these issues.

**Implementation of Supreme Court Guidelines:** The

Supreme Court's guidelines for tackling mob lynching, issued in 2018, are comprehensive but face inconsistent implementation across states. The guidelines recommend appointing nodal officers, setting up fast-track courts, and establishing compensation schemes for victims. As of mid-2023, states like Maharashtra and Karnataka have made notable progress by implementing these recommendations. Maharashtra has established fast-track courts and appointed nodal officers, while Karnataka has initiated victim compensation schemes. However, other states, such as Uttar Pradesh and Jharkhand, have been slow to implement these measures. The National Crime Records Bureau (NCRB) report reveals that only 30% of the recommended fast-track courts have been set up, leading to delays in the judicial process. This inconsistency in implementing the Supreme Court's guidelines hampers the effectiveness of legal responses to mob lynching and underscores the need for uniform enforcement across all states.

**State-Specific Laws:** Certain states, including Manipur and West Bengal, have enacted specific laws targeting mob lynching, with provisions for enhanced punishment and victim compensation. Manipur introduced the Manipur (Prevention of Mob Violence) Act in 2021, which imposes stricter penalties on those involved in mob violence and includes comprehensive measures for victim support. Similarly, West Bengal passed the Anti-Lynching Act in early 2023, which provides severe penalties for perpetrators and establishes a compensation framework for victims. Despite these advancements, recent evaluations indicate that the effectiveness of these laws remains unassessed. As of mid-2024, there is limited data on how these laws have impacted the reduction of mob violence or improved conviction rates. Continued monitoring and evaluation are necessary to gauge their success and identify any gaps in their implementation. Enhanced enforcement and public awareness campaigns are crucial to ensure these laws meet their intended goals.

**Challenges in Legal Responses:** Several challenges continue to impede the effectiveness of legal responses to mob lynching in India:

**Societal Attitudes and Prejudices:** Deep-seated societal prejudices and communal tensions are significant drivers of mob violence. These entrenched biases often contribute to the escalation of violence despite the existence of legal frameworks. For example, in 2023, the surge in lynching incidents linked to communal tensions highlights the need for broader social reforms alongside legal measures.

**Lack of Witness Protection:** Witnesses in mob lynching cases frequently face severe threats and intimidation, leading to high rates of hostile witnesses and acquittals. Data from 2023 indicates that witness intimidation remains a critical issue, with many witnesses retracting their statements or remaining silent due to fear of retribution.

**Delays in Justice Delivery:** The Indian judicial system is plagued by delays, which significantly affects mob lynching

cases. The National Crime Records Bureau (NCRB) reports that the average trial duration for mob lynching cases extends beyond three years, contributing to prolonged suffering for victims and discouraging families from pursuing justice.

**Inadequate Police Training:** Law enforcement agencies often lack the specialized training necessary to handle mob violence effectively. A 2024 review reveals that many police forces still lack comprehensive training in crowd control and investigation of mob lynching cases. This inadequacy hampers effective response and investigation, further complicating efforts to address and prevent mob violence. Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including social reforms, improved witness protection, expedited judicial processes, and enhanced police training to combat mob lynching effectively and ensure justice for victims.

### Recommendations

To improve the effectiveness of legal responses to mob lynching, the following recommendations are proposed:

**Strengthening Legal Framework:** India should enact a comprehensive national anti-lynching law that includes stringent penalties for perpetrators and robust victim protection mechanisms. This law should address gaps identified in current state-specific laws and provide a uniform standard across the country. Additionally, ensuring the uniform implementation of the Supreme Court's 2018 guidelines is crucial. This includes appointing nodal officers, establishing fast-track courts, and providing victim compensation, which has been inconsistently applied.

**Enhancing Witness Protection:** Robust witness protection programs must be implemented to ensure the safety and anonymity of witnesses in mob lynching cases. Recent incidents in 2024 demonstrate that witness intimidation remains a significant barrier to securing convictions. Effective witness protection can mitigate these risks and encourage more witnesses to come forward.

**Expediting Justice Delivery:** Establishing fast-track courts specifically for mob lynching cases in all states is essential for ensuring swift justice. As of mid-2024, only a few states have set up these courts, contributing to delays in the judicial process. Increasing the number of judges and improving court infrastructure can help manage cases more efficiently.

**Community Engagement and Awareness:** Comprehensive awareness campaigns are needed to educate the public about the legal consequences of mob lynching and promote communal harmony. Engaging community leaders and civil society organizations can help address the root causes of mob violence and foster a more informed and cohesive society.

**Training and Capacity Building:** Providing specialized training to police personnel on crowd control, investigation of mob violence, and protection of human rights is crucial. Developing standard operating procedures (SOPs) for law enforcement agencies will ensure a consistent and effective response to mob lynching incidents.

Implementing these recommendations will help address current challenges, improve the legal response to mob lynching, and ensure justice for victims.

**Conclusion:** Mob lynching poses a severe threat to the rule of law and social harmony in India. Although existing legal frameworks provide a foundation for addressing this issue, substantial improvements are necessary in implementation and enforcement. To effectively combat mob lynching, India must strengthen its legal framework by enacting a comprehensive national anti-lynching law with stringent penalties and robust victim protection. Enhancing witness protection programs is crucial for safeguarding those who come forward; while establishing fast-track courts can expedite justice delivery. Promoting community engagement through awareness campaigns and involving civil society organizations can address the root causes of mob violence. By focusing on these areas, India can make significant progress in curbing mob lynching, ensuring timely justice for victims, and restoring public trust in the legal system.

### References:-

1. National Crime Records Bureau (NCRB). *Crime in India 2023*. Government of India, Ministry of Home Affairs. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>.
2. Supreme Court of India. *Guidelines for Preventing Mob Lynching*. July 2018. Available at: <https://main.sci.gov.in>
3. Manipur (Prevention of Mob Violence) Act, 2021. Available at: <https://legislative.gov.in/acts/parliament/2021/manipur-prevention-mob-violence-act-2021>.
4. West Bengal Anti-Lynching Act, 2023. Available at: <https://wb.gov.in/>.
5. National Crime Records Bureau (NCRB). *Crime in India 2023: Special Report on Mob Lynching*. Government of India, Ministry of Home Affairs. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>.
6. National Crime Records Bureau (NCRB). *Prosecution and Conviction Rates for Mob Lynching Cases, 2023*. Government of India, Ministry of Home Affairs. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>.
7. Supreme Court of India. *Review of Implementation of Guidelines on Mob Lynching*. 2023. Available at: <https://main.sci.gov.in/>
8. National Crime Records Bureau (NCRB). *Establishment of Fast-Track Courts for Mob Lynching Cases, 2023*. Government of India, Ministry of Home Affairs. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>.
9. Review of Police Training Programs for Handling Mob Violence. 2024. Available at: <https://www.mha.gov.in/>.
10. National Crime Records Bureau (NCRB). *Witness Intimidation and Its Impact on Mob Lynching Cases, 2023*. Government of India, Ministry of Home Affairs. Available at: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>.
11. Indian Penal Code
12. Supreme Court Guidelines on Mob Lynching
13. State-Specific Laws on Mob Lynching

# Innovative Materials for Environmental Remediation: A Comprehensive Review

Dr. Rashmi Ahuja\*

\*Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

**Abstract :** Advanced materials have emerged as transformative solutions for pollution control, offering innovative capabilities to mitigate environmental contaminants across air, water, and soil. Recent research in nanomaterials, metal-organic frameworks, mixed matrix membranes, and single-atom catalysts has demonstrated remarkable progress in enhancing pollutant adsorption, catalysis, and degradation. These materials exhibit high surface areas, tunable porosity, and unique reactivity, enabling more efficient capture and breakdown of stubborn pollutants. Their versatile applications span from photocatalytic air purification and water treatment to soil remediation and heavy metal immobilization. This review examines the synthesis, properties, and performance of these advanced materials, critically evaluating their potential benefits and addressing challenges related to scalability, cost, and environmental safety. The integration of sustainable synthesis methods, such as green chemistry approaches and biomass-derived precursors, is highlighted as a key strategy for reducing the environmental footprint of material production. In addition, the development of smart, stimulus-responsive materials offers promising avenues for adaptive and efficient pollution control solutions. By bridging the gap between laboratory studies and practical applications, advanced materials are set to transform the field of environmental remediation. Continuous efforts are needed to optimize their functionality, ensure long-term stability, and minimize potential risks. Overall, the evolving landscape of advanced material technologies provides both opportunities and challenges, making it imperative for interdisciplinary collaboration among chemists, engineers, and environmental scientists. This review synthesizes recent progress in the field, outlines key scientific and engineering hurdles, and proposes future research directions that may enable the transition from experimental innovations to widespread environmental applications.

**Introduction** - Environmental pollution represents one of the most significant challenges facing modern society. The accelerated pace of industrialization, urbanization, and population growth has led to unprecedented levels of contaminants in our air, water, and soil. These pollutants not only degrade ecosystem health but also pose serious threats to human well-being through various exposure pathways. Traditional pollution control technologies, while valuable, often struggle with limitations in efficiency, selectivity, and sustainability, particularly when addressing emerging contaminants and complex pollution scenarios. Recent advances in materials science and nanotechnology have opened new frontiers in pollution control through the development of engineered materials with exceptional properties. These advanced materials overcome many limitations of conventional approaches by offering enhanced surface area, tunable porosity, specific binding sites, and improved catalytic activity. Their ability to interact with pollutants at the molecular or atomic level enables unprecedented control over contaminant capture, transformation, and degradation processes.

This review examines four major classes of advanced materials that show particular promise for environmental applications: nanomaterials, metal-organic frameworks (MOFs), mixed matrix membranes (MMMs), and single-atom catalysts (SACs). Each of these material categories brings unique advantages to pollution control challenges, enabling targeted interventions across different environmental media. We explore their synthesis methods, structural characteristics, mechanisms of action, and performance metrics in various pollution control scenarios. Furthermore, this review addresses critical considerations regarding scalability, cost-effectiveness, and potential environmental implications of these materials. By acknowledging both the opportunities and challenges associated with advanced materials, we aim to provide a balanced assessment of their potential contribution to sustainable environmental management strategies. The concluding sections outline promising research directions and practical recommendations for translating laboratory discoveries into real-world pollution control solutions.

**Types of Advanced Materials for Pollution Control**

**Nanomaterials:** Nanomaterials, with dimensions ranging from 1 to 100 nanometers, exhibit unique physical and chemical properties distinct from their bulk counterparts due to quantum confinement effects and dramatically increased surface-to-volume ratios. These properties make them particularly effective for pollution control applications. Carbon-based nanomaterials, including carbon nanotubes, graphene, and graphene oxide, possess exceptional adsorption capacities for organic pollutants due to their high specific surface area (often exceeding 2000 m<sup>2</sup>/g) and pi-electron rich structures that facilitate strong interactions with aromatic contaminants.

Metal and metal oxide nanomaterials, such as nano-TiO<sub>2</sub>, nano-ZnO, and nanoscale zero-valent iron (nZVI), demonstrate remarkable catalytic and photocatalytic properties for pollutant degradation. Their enhanced reactivity stems from a high density of surface active sites and unique electronic configurations. For example, nZVI particles have proven highly effective for the reductive degradation of chlorinated organic compounds and immobilization of heavy metals in contaminated groundwater and soil systems.

The versatility of nanomaterials extends to their modification potential, where surface functionalization can enhance selectivity toward specific contaminants or improve stability in environmental matrices. These modifications enable tailored solutions for diverse pollution scenarios, from capturing volatile organic compounds in indoor air to removing pharmaceutical residues from wastewater.

**Metal-Organic Frameworks (MOFs):** Metal-Organic Frameworks represent a revolutionary class of crystalline porous materials composed of metal ions or clusters coordinated to organic ligands. Their exceptional characteristics include record-breaking porosity (surface areas up to 7000 m<sup>2</sup>/g), uniform and tunable pore sizes, and modular design that allows precise control over structure and functionality.

The virtually limitless combinations of metal nodes and organic linkers enable MOF design with specific chemical affinities for target pollutants. This structural versatility allows researchers to develop MOFs with tailored properties for particular environmental applications, from selective adsorption of greenhouse gases to catalytic degradation of persistent organic pollutants.

Recent innovations in MOF development have addressed stability limitations in aqueous environments through strategies such as hydrophobic modification and incorporation of stable metal-ligand bonds. These advancements have expanded the practical utility of MOFs for water treatment applications, where they show remarkable selectivity and capacity for heavy metals, organic dyes, and emerging contaminants.

**Mixed Matrix Membranes (MMMs):** Mixed Matrix Membranes combine polymeric matrices with inorganic or MOF fillers to create composite materials that overcome

the inherent limitations of conventional polymeric membranes. This hybrid approach addresses the traditional permeability-selectivity trade-off that has constrained membrane technology, offering improved separation performance without sacrificing process efficiency.

The incorporation of nanomaterials, zeolites, or MOFs into polymer matrices creates synergistic effects that enhance contaminant rejection, reduce membrane fouling, and improve mechanical stability. These improvements extend operational lifetimes and reduce energy requirements in filtration processes, offering more sustainable solutions for water purification and gas separation.

MMMs have demonstrated particular promise for removing emerging contaminants such as pharmaceuticals, personal care products, and microplastics from water sources. The ability to fine-tune membrane properties through careful selection of both polymer matrices and filler materials enables customized solutions for specific pollution challenges.

**Single-Atom Catalysts (SACs):** Single-Atom Catalysts represent the frontier of heterogeneous catalysis, featuring isolated metal atoms dispersed on appropriate support materials. This atomic-level dispersion maximizes metal utilization efficiency and creates unique catalytic environments that often demonstrate superior activity and selectivity compared to conventional nanoparticle catalysts. The precisely defined active sites in SACs enable unprecedented control over catalytic reactions, making them particularly valuable for selective pollutant degradation. Recent studies have shown that SACs can achieve complete mineralization of recalcitrant organic contaminants under mild conditions with minimal energy input, offering environmentally benign approaches to water purification.

Innovations in SAC design include nanoconfinement strategies that dramatically enhance catalytic performance by creating optimized microenvironments around active sites. These confined systems have demonstrated reaction rate enhancements exceeding 30-fold compared to conventional catalysts, representing a paradigm shift in catalytic pollution control technologies.

**Applications in Air Pollution Control:** Advanced materials have revolutionized air pollution control strategies across multiple applications, from indoor air quality management to industrial emission control. Their exceptional properties enable more efficient capture and degradation of both particulate and gaseous pollutants compared to conventional technologies.

Nanoengineered filtration materials demonstrate remarkable capabilities for particulate matter removal, including the challenging ultrafine particles (PM<sub>2.5</sub> and smaller) that pose significant health risks. Electrospun nanofiber filters, with fiber diameters ranging from 50-500 nm, create highly porous structures that combine low air

resistance with excellent particle capture efficiency. These materials achieve filtration performance comparable to HEPA filters but with significantly reduced pressure drop, translating to energy savings in air handling systems.

For gaseous pollutant control, functionalized nanoporous adsorbents offer solutions that exceed the capabilities of traditional activated carbon. Hierarchically structured materials combining micro-, meso-, and macropores optimize both mass transfer kinetics and adsorption capacity, enabling efficient capture of volatile organic compounds (VOCs), formaldehyde, and other indoor air pollutants. Metal-organic frameworks with tailored pore geometries and chemical functionalities provide selective adsorption of specific target gases, offering potential for removing trace contaminants from complex air mixtures.

Photocatalytic air purification represents another frontier application of advanced materials. TiO<sub>2</sub>-based nanostructures and sensitized derivatives enable the solar-driven or artificial light-driven degradation of gaseous pollutants through the generation of reactive oxygen species. Recent developments in visible-light-responsive photocatalysts through strategies such as doping, heterojunction formation, and surface plasmon resonance effects have expanded the practical applications of these systems beyond UV-dependent processes.

**Applications in Water Pollution Control:** Water pollution control represents perhaps the most extensively developed application area for advanced materials, spanning from drinking water treatment to industrial wastewater remediation. Materials innovation has addressed persistent challenges in contaminant removal efficiency, energy requirements, and treatment of emerging pollutants.

Advanced adsorbents with engineered porosity and surface chemistry demonstrate exceptional performance for removing heavy metals, organic micropollutants, and emerging contaminants from water. Hierarchically porous carbon materials derived from sustainable biomass precursors have achieved record-breaking adsorption capacities for various water contaminants while offering cost advantages over conventional alternatives. Functionalized adsorbents with specific binding sites for priority pollutants enable selective removal even at trace concentrations or in complex water matrices.

Membrane technologies have benefited substantially from materials innovation. Two-dimensional nanomaterial-based membranes leveraging graphene oxide or MXenes enable precise molecular sieving with water permeability orders of magnitude higher than conventional reverse osmosis membranes. Mixed matrix membranes incorporating MOFs or other functional fillers demonstrate enhanced selectivity for specific contaminants while maintaining high water flux, addressing the traditional permeability-selectivity trade-off that has limited membrane performance.

Catalytic and photocatalytic systems for water purification have advanced through the development of materials that enable pollutant degradation under increasingly mild conditions. Single-atom catalysts for persulfate activation achieve complete degradation of recalcitrant pollutants at catalyst loadings orders of magnitude lower than conventional materials. Visible-light-responsive photocatalysts based on strategies such as Z-scheme heterojunctions, plasmonic enhancement, and quantum dot sensitization enable solar-driven water treatment without the need for additional chemical inputs.

**Applications in Soil Remediation:** Soil contamination presents unique challenges for remediation technologies due to the complex, heterogeneous nature of soil matrices and the limited mobility of treatment agents. Advanced materials have enabled innovative in situ approaches that minimize site disturbance while effectively addressing various contaminant classes.

Nanoremediation using engineered particles represents a transformative approach for treating subsurface contamination. Zero-valent iron nanoparticles (nZVI) have demonstrated exceptional effectiveness for in situ degradation of chlorinated solvents and immobilization of heavy metals through reduction reactions. Surface modifications and stabilization strategies enhance nZVI mobility in soil matrices, enabling treatment of larger contamination zones with fewer injection points. Bimetallic nanoparticles incorporating catalytic metals such as palladium or nickel achieve accelerated contaminant transformation rates and expand the range of treatable compounds.

For heavy metal contamination, engineered sorbents provide sustainable immobilization strategies that reduce bioavailability and leaching potential. Modified biochars combining high adsorption capacity with alkalinity effectively sequester metals through multiple mechanisms including surface complexation, precipitation, and redox reactions. These materials offer cost-effective alternatives to conventional amendments while providing additional soil quality benefits such as improved water retention and enhanced microbial activity.

Stimuli-responsive materials represent an emerging frontier in soil remediation, enabling triggered contaminant capture or degradation in response to specific environmental conditions. These intelligent systems can adapt their properties based on factors such as pH, temperature, or contaminant concentration, maximizing remediation efficiency while minimizing resource consumption and potential side effects.

**Challenges and Limitations:** Despite the promising performance of advanced materials for pollution control, several significant challenges must be addressed to realize their full potential in real-world applications. These limitations span technical, economic, and environmental dimensions, requiring interdisciplinary approaches for

effective resolution.

Scalability represents a primary barrier to widespread implementation, as many advanced materials involve sophisticated synthesis procedures that are challenging to translate to industrial production scales. Laboratory synthesis methods often employ expensive precursors, hazardous reagents, or energy-intensive processes that become prohibitively costly or impractical at larger scales. Bridging this scaling gap requires innovative manufacturing approaches that preserve critical material properties while enabling economical mass production.

Cost considerations extend beyond production to include implementation, operation, and end-of-life management of advanced materials. High material costs can be justified only when performance advantages significantly outweigh price premiums compared to conventional alternatives. Life cycle economic analysis must account for all aspects of material deployment, including potential savings from improved efficiency, reduced energy consumption, or extended operational lifetimes.

Environmental implications of the materials themselves require careful assessment to ensure that pollution control solutions do not create new environmental problems. Questions regarding the fate, transport, and potential ecological effects of nanomaterials or other advanced materials after use or accidental release remain incompletely answered. These knowledge gaps necessitate comprehensive risk assessment frameworks specific to novel material properties and applications.

Technical challenges in material stability and regeneration capacity affect long-term performance in real-world conditions. Many advanced materials demonstrate excellent initial performance but suffer from degradation or fouling during extended operation in complex environmental matrices. Developing more robust materials that maintain their functionality across varying conditions and multiple treatment cycles represents a critical research need.

**Future Directions:** Several promising research directions are emerging to address current limitations and expand the potential applications of advanced materials for pollution control. These approaches combine fundamental materials science with practical engineering considerations to develop more effective, sustainable, and implementable solutions. Sustainable synthesis approaches represent a critical area for advancement, focusing on green chemistry principles to reduce the environmental footprint of material production. Biomass-derived precursors offer renewable alternatives to petroleum-based starting materials, while solvent-free or water-based synthesis methods minimize waste generation and environmental impacts. Mechanochemical approaches and continuous flow synthesis enable more efficient production with reduced energy requirements, addressing both environmental and economic concerns. Smart and responsive materials that adapt to changing environmental conditions show particular promise for next-

generation pollution control. Stimuli-responsive systems that modify their properties in response to specific triggers enable more efficient resource utilization and improved performance across varying pollution scenarios. Self-healing materials that autonomously repair damage during operation offer potential for extended service lifetimes in challenging environmental applications.

Digital and computational approaches increasingly guide materials design and optimization, reducing reliance on traditional trial-and-error methods. Machine learning algorithms that identify structure-property relationships accelerate the discovery of high-performance materials for specific applications. Computational screening of thousands of potential material candidates enables researchers to focus experimental efforts on the most promising candidates, streamlining the development process.

Integration of multiple functional materials into hierarchical or multifunctional systems represents another frontier, enabling simultaneous detection, capture, and degradation of pollutants within unified platforms. These integrated approaches offer potential for more comprehensive pollution control strategies that address complex contamination scenarios with improved efficiency and reduced complexity.

**Conclusion and Suggestions:** Advanced materials have demonstrated exceptional potential for transforming pollution control across air, water, and soil media. Their unique properties enable more efficient, selective, and sustainable approaches to environmental remediation compared to conventional technologies. By harnessing the precise control offered by materials engineering at the nano and molecular scale, researchers have developed solutions that address persistent challenges in pollution management. Despite their promising performance characteristics, the transition from laboratory demonstration to practical implementation requires addressing significant challenges in scalability, cost-effectiveness, and environmental safety. Sustainable approaches to material design, production, and application are essential for ensuring that pollution control solutions do not create unintended environmental consequences.

For future development, we suggest several key priorities: (1) standardized testing protocols that simulate realistic environmental conditions to enable meaningful performance comparisons; (2) life cycle assessment methodologies specific to advanced materials that account for their unique properties and applications; (3) green synthesis approaches that align with circular economy principles and minimize resource consumption; and (4) collaborative research frameworks that bridge disciplinary boundaries between materials science, environmental engineering, and regulatory science.

The growing environmental challenges associated with industrial development, urbanization, and emerging contaminants necessitate innovative approaches that

transcend the capabilities of conventional pollution control technologies. Advanced materials, thoughtfully designed and responsibly implemented, offer promising pathways toward more effective environmental protection strategies. By addressing current limitations through interdisciplinary collaboration and sustainable design principles, these materials can contribute significantly to creating cleaner, healthier environments for current and future generations.

#### References:-

1. Saparov, K., Yakshieva, Z., Kholdorova, G., Sangirova, M., Dadaeva, G., Rajabov, K., Asallaev, U., & Safarova, N. (2024). Advanced Materials for Pollution Control that Integrate Engineering Science with Environmental Conservation. *Natural and Engineering Sciences*, 9(3), 77-87.
2. Khin, M. M., Nair, A. S., Babu, V. J., Murugan, R., & Ramakrishna, S. (2012). A review on nanomaterials for environmental remediation. *Energy & Environmental Science*, 5(8), 8075-8109.
3. Qu, X., Alvarez, P. J., & Li, Q. (2013). Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment. *Water Research*, 47(12), 3931-3946.
4. Wang, B., Lv, X. L., Feng, D., Xie, L. H., Zhang, J., Li, M., Xie, Y., Li, J. R., & Zhou, H. C. (2016). Highly stable Zr(IV)-based metal-organic frameworks for the detection and removal of antibiotics and organic explosives in water. *Journal of the American Chemical Society*, 138(19), 6204-6216.
5. Mauter, M. S., & Elimelech, M. (2008). Environmental applications of carbon-based nanomaterials. *Environmental Science & Technology*, 42(16), 5843-5859.
6. Wang, Q., & Yang, Z. (2023). Advances in heterogeneous catalysts for water pollution control. *Nature Communications*, 14, 1287-1302.
7. Zhang, S., Liu, D., & Meng, X. (2022). Confined single-atom catalysts: Design strategies and applications. *Journal of the American Chemical Society*, 144, 13087-13104.
8. Li, Y., Zhou, J., & Dai, Y. (2023). Nanoconfined catalysts for water pollution control. *Nature Sustainability*, 6, 416-426.

\*\*\*\*\*



# India's Role as a Mediator in the US-China Hegemony Conflict: A Comprehensive Study

Kaustubh Nihal\*

\*Research Scholar (JRF) (Political Science) Jai Prakash University, Chapra (Bihar) INDIA

**Abstract :** This paper will study the role of India as a mediator between the USA and China's conflict for hegemony. Through the in-depth study, the paper will explore the various dimensions of relations between the US and China. The paper will emphasize India's fitness for the role of a mediator between two major powers of the world including the sources, effectiveness, challenges and major takeaways for India.

**Keywords:** mediation, strategic, burgeoning, counter-balancing, hegemony, indispensable, geopolitics, disintegration, competency, hegemonic, shortcoming, navigability, constrained, tranquility, the US-China, comprehensive.

**Introduction -** India's role as a mediator in the global conflict is deeply rooted in its history. **Sayers, Matthew R.** (2012) said that the culture of mediation derives from its ancient religious philosophy of Hinduism and Buddhism which stands on the principle of peaceful resolution of conflict. The beauty of mediation is depicted in the epics of Ramayana and Mahabharata. One such incident is when lord Krishna mediated between the two warring parties in Mahabharata<sup>1</sup>.

In the present world order, India positions itself as the fastest-growing economy in the world with a reliable and stable market for the world economy. India's strategic might burgeoning is not limited to the subcontinent but also to the global level (**Pillalamarri, A.**, 2023)<sup>2</sup>. India being the world's largest democracy holds soft power to a considerable extent.

**Schiff, J.** (2005) mentioned in his article that India is endowed with a strategic position, stable growth rate and self-reliance, making it a natural ally and counter-balancing force between the USA and China hegemony conflict.<sup>3</sup>

In essence, India's role as a mediator is underpinned by its historical ethos, global presence, and the respect it commands on the world stage, making it an indispensable bridge between two of the world's superpowers.

**The odyssey of the USA and China and the Status Quo:** The US and China are the two most important countries in the world in terms of economy, politics, geography, defense, and power influence.

The US has been the greatest power since the First World War and has had great influence on the world since then, be it the global economy, geopolitics or soft power influence. Being the leader of the Western block and flag bearer of the democratic world order the US holds major

influence in global politics. The US controls the major global institutions such as the United Nations, World Bank, IMF, WHO, and WTO. The USA has its preferences and reservations in the current world order (**Schere, E.**, 2021).<sup>4</sup> Whereas, China on the other hand is a rising power in global power politics. **Mansbach, R. W., & Ferguson, Y. H.** (2021) mention that, Since the disintegration of USSR in the 1991, its successor Russia has had limited resistance competency to the US hegemony<sup>5</sup>. China emerged as a counterforce against the US hegemonic world order. It has overcome the shortcomings of Russia which include a closed market policy, limited navigability, constrained economy, limited foreign exchange reserves, rigid foreign policy etc. (**Foot, 2020**)<sup>6</sup>

After taking all of these factors into consideration and establishing a relationship between both of these countries in the present global dynamics, one inevitable question arises: Is the US and China in the Thucydides trap?

This is one of the most prominent questions of the 21<sup>st</sup> century among the various geopolitical analysts around the world. However, both sides have categorically rejected any such claims, at least publicly. Many geopolitical thinkers and political analysts have attempted to explain this situation in their understanding but the proximity of the situation can be traced in the theory of Thucydides trap.

Thucydides trap is a situation where an existing power is challenged by the emerging power for the hegemony, hence war is apparent, and it is described and popularized by Graham T. Allison, (2012). The origin of the concept is traced back to 431 BC when a military general and Athenian thinker Thucydides suggested the inevitable war between Athens and Sparta in the Peloponnesian War. Since Spartans feared the rising power of the Athenians which

paved the ground for the serious confrontation due to the challenge by the rising power Athens on the existing power Sparta.

**Graham T. Allison** (2012) in his article in The Financial Times, studied the 16 occurrences in the history of such power rivalry and found that there are 12 such instances when war happened.<sup>7</sup>

Taking the queue from these lines, the present relationship between the US and China is believed to be in the Thucydides trap by many strategic analysts. The changing dynamics between both countries are neither new nor disguised anymore after the recent Donald Trump's trade war with China has brought the economic tensions between the two parties into the limelight. The gigantic economic powers have eventually locked into the rivalry for hegemony (**Rushe, D.**, 2019, August 23).<sup>8</sup>

**Sarhan, F.** (2023, October 10) in his article in Forbes highlighted that it is a multidimensional conflict that is not only limited to military dominance but also extended to geopolitical, economic, trade, technology, diplomacy and human rights<sup>9</sup>. The tension between these two parties has a lot of stakes in the peace of the world since both are great economic and military powers.

In such a situation a third and neutral front is the need of an hour and that could be India. According to **Freedom House (2023)**, India being the largest democracy is largely appreciated and trusted by the West including the USA. It is a strong member of Asia,<sup>10</sup> NAM (non-aligned movement) and historic relations with the USSR during the Cold War brought it closer to all non-Western countries (**Cohen, S. F.**, 2004).<sup>11</sup>

India is truly a historic global leader and a Vishwa guru (global teacher). India deems fit and a perfect match for the mediator in the US-China conflict. Being a mediator between the US and China won't be a cakewalk for India<sup>12</sup>(**Kim and Singh, 2020**). There will be challenges associated but also there will be blessing in disguise for India. Let us discuss various aspects of the US-China conflict and the role of India as a mediator.

#### **India's relationship with the USA:**

**1. Economic:** India-US bilateral trade in goods and services which continued to rise and has likely surpassed \$200 billion in calendar year 2023 despite the challenging global trade environment. The bilateral goods and services trade between the US and India has almost doubled since 2014 (**United States Trade Representative, 2024**).<sup>13</sup>

**2. Political:** Both countries share the commitment to Human rights, freedom, the rule of law, democratic values and peaceful co-existence (**The White House, 2023**).<sup>14</sup>

**3. Strategic:** India and the USA are members of many strategic forums such as Quad (USA, India, Japan, Australia), I2U2 (Israel, India, USA, UAE), G20 etc. (**Council on Foreign Relations, 2023**).<sup>15</sup>

**4. Security:** Both countries share the same view on the peace and security in the Indian Ocean region and are ready

to cooperate in the counter-balancing measure against any adversaries that intend to destabilize the strategic fabric in the region by the act of aggression or otherwise (**Miller & Harris, 2023**)<sup>16</sup>.

#### **5. Defence:**

a. India and the USA have signed many pacts in the recent past which brought both countries closer to each other.

b. India has signed 4 foundational defence agreements with the USA i.e. GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018), and BECA (2020).

c. Joint production of GE F-414 jet engines in India will provide a boost to indigenous fighter aircraft production. (**Lalwani & Singh, 2023**)<sup>17</sup>.

#### **India's relationship with China:**

**1. Historical:** India was the first non-socialist country to establish a diplomatic relationship with China on April 1, 1950.

**2. Cooperation:** An agreement on peace and tranquillity along LAC (Line of Actual Control) was signed in 1993 and in 2005 India established a Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity<sup>18</sup>(**Muni, 2020**).

**3. Trade and Economic:** China was India's largest trading partner between 2018 to 2021. Bilateral Trade between these two has soared to USD 136 billion (**PIB, 2022**).<sup>19</sup>

**4. Recent Development:** In 2014 Xi Jinping visited India. Nathu la route opened for Kailash Man Sarovar Yatra. E-Visa facility for Chinese tourists (**Bhatia, 2021**)<sup>20</sup>.

#### **Factors influencing India's role as a mediator:**

**1.** India has had historical ties with China since ancient times, with many Chinese philosophers coming to India for their studies and research purposes<sup>21</sup> such as Sima Qian (he mentioned India as Yuandu and Tiandu), Faxian (a Buddhist scholar), and Huen Sang (who met King Harshvardhan) which establishes deep cultural and historical ties with China (**Embassy of India, 2013**).

**2.** Similarly, India has deep strategic ties with the USA presently, the USA has recognized India as a nuclear power nation and signed a nuclear agreement in 2005 which makes it the first nation to accept India's nuclear power<sup>22</sup>(**Sultan & Adil, 2008**).

**3.** India has been accepted by both countries as a non-partial and non-aggressor (**Rao, 2019**)<sup>23,24</sup> **Rao, S. (2019), India's Role in Global Politics: A Comparative Analysis.**

**4.** India's economic dependence on China and the US makes India a remarkable candidate to mediate their conflict since the value of trade between India and the USA is \$192 billion (**United States Trade Representative, 2023**)<sup>24</sup> and the trade value between India-China for the same period is \$136 billion<sup>25</sup> (**Chinese customs, 2023**). It is highly unlikely for both the economies to ignore India largely.

**5.** India stands tallest in terms of infantry which show-

cases its defence capabilities.<sup>26</sup> Indian technological advancement through self-made Brahmos nuclear missiles, nuclear triad, S-400 triumph, Anti- Sat strike capabilities ensures India's dominance and self-dependency (Kanwal, 2012).

6. Indian democracy in principle appreciated by the USA (The White House, 2021)<sup>27</sup> and in practice appreciated by China (Kohli, 2001).<sup>28</sup>
7. Its rule of law, human rights values, refugee protection and the concept of "VasudhevKutumbkam" represent the true nature of Indian philosophy<sup>29</sup> (Warrier, 1953).

#### Issues associated with India's mediation in the USA-China conflict:

1. Neither the USA nor China trust India's intentions. During the Cold War India formed NAM which was mainly treated as the *B-wing* of the USSR which many times infuriated the USA<sup>30</sup> (Laskar, 2004).
2. India's development of nuclear capabilities shocked China and made it more protectionist (Ballawar, 2022).<sup>31</sup>
3. Historically, India has never been in the block of the West nor does it have any racial similarities with the West hence there is no natural alliance (Chatterjee, 2019).<sup>32</sup>
4. India and China fought a full-fledged war in 1962 and continuous border conflict made India and China hostile to each other (Britannica, 2024).<sup>33</sup>
5. India's Intervention in east Pakistan and carving out the new country Bangladesh made the USA cautious (Bose, 2011).<sup>34</sup>
6. Integration and assimilation of Sikkim as a state of India made China anxious and more cautious (Bajpai, 2018).<sup>35</sup>
7. Both countries are poles apart, the USA is capitalist-democratic and China is a Socialist-Communist country<sup>36</sup> (Smith, 2022).
8. Except for trade, they do not lie on the same page. It is highly intricate for India to mediate between these two since they both have no cross-overs or any cultural influence (Verma, 2023).<sup>37</sup>

In conclusion, it can be said that India needs to look at things as they are and not how they ought to be. It needs to align the alignments and shall not fall into the game of zero-sum game between the great power politics of Cold War 2.0 as modern political scholar term the relationship of the USA and China. There is no doubt that India is the perfect match for the mediator between the USA and China due to its historical ties, cultural values, deep strategic engagement and economic dependence. It is also true that great things come at a great cost and eventually mediation between these two has intrinsic and extrinsic challenges as well.

However, if we look purely from the perspective of India there is a *blessing in disguise for India* in the conflicting relations between USA and China. India will emerge as the great power of the world if the current situation prevails for

a longer duration. India's exports may boost in the international market. Since both are the giants of the world trade and keep slapping sanctions on each other it might create a void in the exports of food, energy, medicines and IT services to the global market which India may bridge, provided India's domestic demand fulfilment. India may witness a high number of companies shifting their bases from China to India a recent trend observed in the post covid world. The coming years are of great importance for India and it needs to be ready for any eventuality.

#### References:-

1. Sayers, Matthew R. (2012), *Claiming Modes of Mediation in Ancient Hindu and Buddhist Ancestor Worship*, Journal of Ritual Studies, 26(1), 5.
2. Pillalamarri, A. (2023), *How India Arrived on the World Stage in 2023*, The Diplomat. (<https://thediplomat.com/2023/12/how-india-arrived-on-the-world-stage-in-2023>)
3. Schiff, J. (2005), *Opening Its Doors: India's Emergence on the Global Stage*, The Diplomat (<https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781589065680/ch01.pdf>)
4. Schere, E. (2021), *Soft Power - The Underestimated Strategy for Global Influence*, The Fletcher Forum of World Affairs, 45(2). (<https://ssrn.com/abstract=3922807>)
5. Mansbach, R. W., & Ferguson, Y. H. (2021), *The Return of Geopolitics and Declining U.S. Hegemony*, In *Populism and Globalization* (Chapter 3).
6. Foot, R. (2020)., *China's rise and US hegemony: Renegotiating hegemonic order in East Asia?* International Politics, 57, 150–165
7. Allison, G. T. (2015), *The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?* The Atlantic, (<https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756/>)
8. Rushe, D. (2019, August 23), *Here are the reasons for Trump's economic war with China*, The Guardian (<https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/23/trump-china-economic-war-why-reasons>)
9. Sarhan, F. (2023, October 10), *US-China Trade Tensions To Impact The Environment And Geopolitics*. Forbes (<https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/10/10/us-china-trade-tensions-to-impact-the-environment-and-geopolitics/?sh=5afd453f301e>)
10. Freedom House. (2023), *Freedom in the World 2023: Democracy Under Siege*. Retrieved from (<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/democracy-under-siege>)
11. Cohen, S. F. (2004), *India: Emerging Power*, Brookings Institution Press (<https://www.brookings.edu/books/india-emerging-power/>)
12. Kim and Singh (2020, September 16), *Prospects for Crisis Management on the China-India Border*, United States Institute of Peace (USIP) (<https://www.usip.org/publications/2020/09/prospects-crisis-management>)

- china-india-border)
13. United States Trade Representative. (2024, January 12), *Joint Statement on the United States-India Trade Policy Forum*(<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/january/joint-statement-united-states-india-trade-policy-forum>).
  14. The White House. (2023), *Joint Statement from the United States and India*(<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/06/22/joint-statement-from-the-united-states-and-india/>)
  15. Council on Foreign Relations. (2023), *Strategic Forums: India and the USA*(<https://www.cfr.org/asia/india>)
  16. Miller, M. C., & Harris, C. (2023), *India's Efforts to Strengthen Indian Ocean Security*, Council on Foreign Relations(<https://www.cfr.org/blog/indias-efforts-strengthen-indian-ocean-security>)
  17. Lalwani, S & Singh, V (2023), *A Big Step Forward in U.S.-India Defense Ties*, United State Institute of Peace (<https://www.usip.org/publications/2023/06/big-step-forward-us-india-defense-ties>)
  18. Muni, S. D. (2020), *India and China Relations: A Historical Perspective*. International Journal of Humanities & Social Science Invention (IJHSSI), 9(7), 21-26.
  19. Press Information bureau(2022, August 19), *Indian exports to China witness growth*, PIB(<https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1795642>).
  20. Bhatia, R. (2021), *India-China Relations: Recent Trends and Future Prospects*, Diplomatist. (<https://diplomatist.com/2021/03/22/the-future-of-india-china-relations/>)
  21. Embassy of India, Beijing(2013, August 21), *India-China Bilateral Relations – Historical Ties*, Archived at the Wayback Machine.
  22. Sultan, M., & Adil, M. B. (2008), *The Henry J. Hyde Act and 123 Agreement: An Assessment*. South Asian Strategic Stability Institute. Archived from the original (PDF) on September 18, 2011. Retrieved August 21, 2011.
  23. Rao, S. (2019), *India's Role in Global Politics: A Comparative Analysis*, International Relations Review, 36(2), 87-102.
  24. United States Trade Representative. (2023), *India Trade & Investment Summary*.(<https://ustr.gov/countries-regions/south-central-asia/india>)
  25. Chinese customs (2023, January 13), *Total India-China trade for calendar year (CY) 2022 stood at US\$135.98 billion, 8.4 percent higher than the US\$125 billion mark in 2021*(<https://www.india-briefing.com/news/india-china-bilateral-trade-and-investment-prospects-26894.html>)
  26. Kanwal, G. (2012, September 24), *India's Military Modernization: Plans and Strategic Underpinnings*, The National Bureau of Asian Research (NBR) Commentary for the U.S. Senate India Caucus(<https://www.nbr.org/publication/indias-military-modernization-plans-and-strategic-underpinnings/>)
  27. The White House (2021, September 24), *The United States and India – Global Leadership in Action* (<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-the-united-states-and-india-global-leadership-in-action/>)
  28. Kohli, A. (2001), *The Success of India's Democracy*, Cambridge University Press(<https://assets.cambridge.org/97805218/01447/sample/9780521801447ws.pdf>)
  29. Warriar, A. G. K. (1953), *Maha Upanishad. Theosophical Society*, Madras Online, Verse VI.71–73.
  30. Laskar, R. K. (2004), *Respite from Disgraceful NDA Foreign Policy*, Congress Sandesh, 6(10), 8.
  31. Ballawar, N. (2022, April 14), *Analysing China's Nuclear Capabilities and Implications for India*, Orcasia.org(<https://orcasia.org/article/124/analysing-chinas-nuclear-capabilities-and-implications-for-india>)
  32. Chatterjee, P. (2019), *India's Foreign Policy: A Historical Perspective*, Oxford University Press (<https://www.scribbr.com/citation/generator/apa/>)
  33. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, January 3), *Sino-Indian War*, *Encyclopedia Britannica* (<https://www.britannica.com/topic/Sino-Indian-War>)
  34. Bose, S. (2011). *Transforming India: Challenges to the World's Largest Democracy*, Harvard University Press(<https://www.scribbr.com/apa-style/format/>)
  35. Bajpai, G. S. (2018, November 1), *China's Shadow over Sikkim: Sikkim, India, and Communist China*, Indian Defence Review(<https://www.indiandefencereview.com/spotlights/chinas-shadow-over-sikkim-sikkim-india-and-communist-china/>)
  36. Smith, J. (2022), *Comparative Analysis of Political and Economic Systems: USA and China*, Journal of International Relations, 45(3), 189-205(<https://doi.org/10.1177/17504813221099191>)
  37. Verma, R. (2023), *Challenges of Mediation: India's Role in US-China Relations*, International Journal of Diplomacy and Conflict Resolution, 12(2), 87-102.

\*\*\*\*\*

# Impact of Monetary policy on Inflation in India

Anil Chouhan\*

\*Assistant Professor, SAM Global University, Raisen (M.P.) INDIA

**Abstract :** The objective of this paper is to analyze and discuss the impacts of monetary policy on India inflation, identify the major drawbacks of the policies in minimizing the inflation rate and suggest policy recommendations on some key issues of India inflation. To estimate the effects of the monetary policy in India, at first the impact of different monetary policy tools used by the "Reserve Bank of India" Next, the impact of the monetary policy of India's bank and government have been analyzed for which the data on money supply, growth of the GDP, changes in the price level, and changes in the unemployment rate have been quantitatively analyzed. We mainly used Consumer Price Index to determine the level on inflation in India. We have further analyzed whether there is any correlation between (a) inflation rates and money supply, and (b) inflation rates and growth of GDP. The conclusions drawn are grounded in the results of comprehensive qualitative and quantitative analyses. We have found the correlation, the impacts of monetary policy and inflation, their drawbacks and possible solutions such as independence of the monetary policy from the fiscal policy and enhancing the transparency, communication and signaling effect of policy moves, and control money supply through various open market operations. Due to limited access to comprehensive data, some of our analysis relies on hypotheses and models, resulting in variations depending on the model used. Recently, several attempts by the RBI to control inflation through restrictive monetary policies have led to a slowdown in economic growth, sparking ongoing debates among academics and policymakers regarding the effectiveness of monetary policy in India. In this context, the current study aims to assess the causal relationship between monetary policy and its primary objectives—economic growth and inflation control in India. The methodology employed is Granger Causality testing in the frequency domain, as developed by Lemmens et al. (2008), with the weighted average call money rate serving as a proxy for monetary policy. In view of the fact that output gap is one of the determinants of future inflation, an attempt has also been made to study the causal relationship between output gap and inflation. The results of empirical estimation show a bi-directional causality between policy rate and inflation and between policy rate and output, which implies that the monetary authorities in India. Policymakers are equally focused on both inflation and output growth when formulating policy. Moreover, efforts to control inflation often impact output to the same extent, or even more, than inflation itself, thereby hindering the growth process. Previous studies on India have also found a positive relationship between the output gap and inflation.. Furthermore, the output gap causes inflation only in the short-to medium-term

**Keywords:** Monetary Policy, Inflation, Output Gap, Granger Causality, Frequency Domain.

**Introduction -** Monetary policy in India is equally important as in developed countries. Monetary policy basically targets price stability. For any government, one of the most urgent economic issues is to stabilize the price and maintain a price level within the limits of purchasing power of the common people. The notion that monetary policy should affect inflation dynamics is an old one, dating at least to Friedman's dictum that inflation is always a monetary phenomenon (1970). In his famous "Critique," Lucas (1975) showed how changes in monetary policy could, in principle, affect inflation dynamics. However, Lucas considered only very stylized monetary policies. There are several ways in which monetary policy may have changed over time. Ball, Mankiw, and Romer (1988) have argued that changes in monetary policy may lead to changes in the frequency of

price adjustment. The New Open Economy Macroeconomics (NOEM) literature, pioneered by Obstfeld and Rogoff (1995), suggests that monetary policy affects the real economy through the interest rate and exchange rate channels. Monetary policy is concerned with the measures taken to control the supply of money, the cost and availability of credit. Like many developing countries, the primary focus of monetary policies in India is to obtain high sustainable growth. However, to achieve and maintain a higher growth rate, policy makers need to understand the determinants of growth as well as how policies affect growth. In a developing country like ours the monetary policy has been effectively used as a tool for overcoming depression and inflation. Along with economic growth monetary policy also has to ensure price stability, as

excessive inflation has an adverse distribution effect and hinders economic development.

#### Literature Review:

There are several theories and empirical studies have been conducted on monetary policy globally over the past decades. The management and control of money supply through the monetary policy implemented by a country's central bank can play a crucial role in managing inflation and promoting economic stability & controlling of inflation in that country. The monetarist approach, that money supply growth causes inflation, can be tested by observing the correlation between the rate of inflation and the rate of monetary growth. Causality can be established through statistical methods and institutional proof. The direction of causality can be detected by examining the timing of the relationship between changes in monetary growth and changes in inflation. Monetarists Cagan (1956) and Friedman (1956,1975) explained money supply as one of the major causes of inflation. The economists began to believe that increasing the monetary supply at a low but constant rate is the best way of maintaining low inflation and growth of the economy. Sunkel (1960) said that from a structuralism viewpoint, budget deficits and consequent expansion in money supply are not autonomous while the necessity of the essential commodities in the domestic market goes up, import is a must. As a result, rising imports and devaluation generate domestic inflation, price level spirals and borrowing through central bank increases the money supply causing a further rise in the price level. However, a tight monetary policy in this context may lead to shortages of essential commodities in the domestic market. So, the some degree of control of monetary authorities is desirable. Friedman (1968) studied the role of monetary policy in the U.S economy and suggested that by setting a steady course, that course one of steady but moderate growth in the quantity of money, the monetary authority could make a major contribution to promoting economic stability with avoidance of either inflation or deflation of prices. It was found that in the developed nation's money supply changes precede price changes, which precede real production changes, lending support to the view that money supply changes are more likely to lead to inflation in this subsample (Cagan 1956; Deaver 1970; and Vogel 1974). He also mentioned that price changes are likely to be followed by money supply changes in less-developed economies. Another interesting finding was that generally the relationship between money supply changes and real production changes is positive for less advanced economies, but negative or negligible for the advanced. This subsequent finding suggests that mild inflation may stimulate real economic growth. The evidence on developing countries supports the argument that governments should not depend on expansionary monetary developments to induce growth. They will be retarding growth while at the same time reducing the welfare of the public by the deterioration of real balances by the induced

inflation. Evidence on the inflationary impact of deficits through their impact on money supply growth includes those by, for example, Aghevli and Khan (1978) in the case of Columbia, Indonesia, Dominican Republic, Brazil and Thailand. Rwegasira (1974), in a study which linked deficits with rising prices, concluded that government expansionary finance which characterized the economy from 1963-72, had been one of the sources of rising prices. He pointed that other important sources, like inelasticity in agriculture and falling import capacity, joined deficit financing in causing upward pressure on the general price level. A combination of declining productivity, declining production and inefficiency accompanied by excessive money supply in the economy seems to be important in the process of inflation according to Malima (1980), implying that an increase in the rate of growth of output and a reduction in the rate of money supply growth could be a solution to inflation.

**Objectives:** The objective of this paper is to analyze and discuss the impacts of monetary policy on India inflation. Identify the major drawbacks of the policies in minimizing the inflation rate and suggest policy recommendations on some key issues of the India inflation identify major challenges and suggest policy recommendations

The Objectives of the study are listed below:

1. Discussion on the correlation between monetary policy and inflation
2. Fluctuation of inflation rates over time in India and its present condition due to monetary policies
3. Impacts of monetary policy on inflation and the consequences
4. To determine appropriate policies to control inflation rates in India

#### Finding Objectives:

**Correlation between monetary policy and inflation:**Traditionally, it is believed that inflation is ultimately a monetary phenomenon, i.e., sustained inflation is the outcome of excessive money supply. Although it is the general wisdom that monetary policy tools are of immediate influence in controlling inflation. However, recent evidence clearly demonstrates that monetary policy alone may not effectively address the issue with the inflationary impacts of external shocks

**Global economic slowdown-** The covid-19 pandemic and the ongoing Russia-Ukraine conflict have led to a slowdown in global economic growth, affecting India's exports and overall economic performance

**Supply Chain Disruptions-** Disruptions in global supply chains, particularly, in the semiconductor and electronics sectors, have impacted India's manufacturing and export sectors.

**Inflationary Pressures-** Rising global commodity prices, particularly crude oil, have led to higher inflation in India, affecting the country's economic growth and stability.

**Geopolitical Tensions-** Escalating tensions between major global powers, such as the US & China, have created

uncertainty and volatility in global markets, affecting India's economy.

**Impacts of monetary policy on inflation and the consequences:** Monetary policy has positive and negative impacts on inflation. Middle class people are turning into lower middle class ones and the latter in turn joining the ranks of the poor. The poor are turning poorer from living costs outpacing earnings and buying powers of non-affluent sections of people decreasing dramatically from the lower purchasing power of the currency as such or the lowered value of their savings. We can say that inflation also directly lowers living standard. Because of inflation people enjoy same amount of product at higher price an increase in the general price level leads to a reduction in the purchasing power of currency. In other words, when prices rise, each unit of money buys fewer goods and services. The impact of inflation is not uniform across the economy, resulting in hidden costs for some and benefits for others due to the decline in money's purchasing power.

**To Determine Appropriate Policies To Control Inflation Rates in India:** There are a number of methods that have been suggested to control inflation. Central banks can affect inflation to a significant extent through setting interest rates and through other operations. High interest rates and slow growth of the money supply are the tradition always through which central banks fight or prevent inflation, though they have different approaches. Monetarists emphasize keeping the growth rate of money steady, and using monetary policy to control inflation (increasing interest rates, slowing the rise in the money supply). Keynesians emphasize reducing aggregate demand during economic expansions and increasing demand during recessions to keep inflation stable. Control of aggregate demand can be achieved using both monetary policy and fiscal policy (increased taxation or reduced government spending to reduce demand).

**Conclusion:** The purpose of this study has been to discuss the relative impact of monetary policies on economic activities in India. The growing importance of monetary policy and the diminishing role played by fiscal policy in economic stabilization efforts may reflect both political and economic realities of our country. Moreover, inflation acts as an important and key variable which influences other macro economic variables of a country. We have seen that, the central bank uses interest rates and the money supply and many other monetary tools to guide economic growth by controlling inflation and stabilizing currency. We have analyzed the consumer price index and several other indicators to understand the impact of monetary policy on inflation. We have found out that, the inflation rates are co-related with the growth rate of gross domestic product and money supply in India. There is positive co-relation between the rate of inflation and rate of change in GDP at constant prices in India. Furthermore, there is negative co-relation between rate of inflation and changes in money supply in India. India had favorable current account position for which it could keep its currency slightly stronger. However, it should

adopt some contractionary policy because of rising current account deficit. We believe that, the monetary policy should be contractionary at times, even if it reduces economic growth of the country because in the long run, it may bring about stability to our economy. Moreover, we find a lag in the policy response of India Bank to higher inflationary expectations. They don't have sufficient and reliable policies to cope with inflation and even if they do, they are not actively well-used. In today's environment of global finance, fixed exchange rates is often not a viable option for fighting inflation. Thus, governments must make important decisions about monetary policy.

**References:-**

1. Aleem, A. (2010). Transmission mechanism of monetary policy in India. *Journal of Asian Economics*, Volume 22, Issue 2, pp.186-197.
2. Bhalla, S. (1981). India's closed economy and world inflation. In R. Williams (Ed.), *World inflation, developing countries*. Washington, DC: Brookings Institute.
3. Bhattacharya, R., Patnaik I. and Shah, A. (2011). Monetary policy transmission in an emerging market setting. *IMF working paper*, WP /11/5.
4. Brahmananda, P. and Nagaraju, G. (2002). Inflation and growth in the world: Some simple empirics. In M. Ahluwalia, Y. Reddy, and S. Tarapore (Eds.), *Macroeconomics and monetary policy: Issues for a reforming economy*, pp.43-66. New Delhi: Oxford University Press.
5. Kapur, M. and Behera, H. (2012). Monetary Transmission Mechanism in India: A Quarterly Model. *RBI Working Paper Series*, WPS (DEPR) 09/2012.
6. Mohanty, D. (2014). Why is recent food inflation in India so persistent? A speech at St. Xavier's college, Mumbai, 13th Jan
7. Aghevli and Khan. 1978, "Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries", *IMF, Staff Papers*, Vol. 25, No. 3, pp. 146-162
8. Andreas and Reschreiter, 2011 The effects of the monetary policy regime shift to inflation targeting on the real interest rate in the United Kingdom, *Economic modelling*. -Amsterdam [u.a.] : Elsevier, ISSN 0264-9993, ZDB-ID 868243. - Vol. 28, 1/2, pp. 754-759
9. Antonio, 2012, Money Growth and Inflation in the Euro Area: A Time Frequency View. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, Vol. 74, Issue 6, pp. 875-885, 2012
10. Ball and Mankiw et al, 1988. "The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Tradeoff," *Brookings Papers on Economic Activity*, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 19(1), pages 1-82.
11. Salunkhe bhavesh, Patnaik Anuradha The Impact Of Monetary Policy On Output And Inflation In India: A Frequency Domain Analysis.

## कृषि क्षेत्र के विकास में भूमि सुधार का योगदान

श्रीमती सुमन भवर\* डॉ. नीमा चुण्डावत\*\*

\* शोधार्थी, भूपाल नोबल्स युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

\*\* शोध निर्देशिका (अर्थशास्त्र) भूपाल नोबल्स युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

**शोध सारांश** - आजादी के पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था पाई जाती थी जिसके कारण कृषि और किसानों की दयनीय स्थिति होने से भारत में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था पाई जाती थी जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदार प्रथा जिसके अंतर्गत जमींदारों द्वारा कृषकों से भूमि कर एकत्रित किया जाता था जमींदार कृषकों और राज्यों के मध्य मध्यस्तों का काम करते थे सरकार का कुल आय में भाग जो जमींदार द्वारा एकत्रित किया जाता था उसका 10 से 11 प्रतिशत भाग सरकार के पास जाता शेष भाग जमींदारों को दिया जाता था जिससे उनका गुजारा कर सके।  
**शब्द कुंजी** - किसानों को भूमि सम्बंधित अधिकारों की सुरक्षा, भूमि सुधार कार्यक्रम, रोजगार में वृद्धि।

**प्रस्तावना** - आजादी के पश्चात भारत में कृषि से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हुआ भारत में तीव्र गति से कृषि को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदार व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा अनुमान लगाया गया कि कृषि क्षेत्र का 52% भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था में 40: भाग जमींदार व्यवस्था में शेष महालवाड़ी व्यवस्था का भाग था इस व्यवस्था में सबसे अधिक शोषण कृषकों का जमींदारों द्वारा किया जाता था क्योंकि जमींदार व्यवस्था को असीमित अधिकार दिए गए थे।

**भूमि सुधार का अर्थ** - भूमि सुधार के अंतर्गत वे सभी कार्य शामिल किये जाते हैं जिनके द्वारा भूमि का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है।

प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल के अनुसार 'भूमि सुधारों का अर्थ व्यक्ति और भूमि के सम्बन्ध तथा संस्थागत परिवर्तन से है'।

प्रो.सैम्युलसन ने कहा है कि - 'सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी को सोना में बदल दिया है'।

आजादी के पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था पायी जाती थी, जैसे -रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदार प्रथा आदि।

**रैयतवाड़ी व्यवस्था** - रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बरार, पूर्व पंजाब, असम में लागू की गई थी। इसमें काश्तकारी भूमि का स्वामी होता जब तक वह भूमि पर राज्य को नियमित रूप से कर देता रहता था, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाता। उसे भूमि में काम लेने, बेचने, हस्तांतरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का अधिकार था। रैयतवाड़ी प्रणाली में स्वामित्व के आधार पर अलग-अलग मालगुजारी तय की जाती थी। मध्य-प्रदेश में 20 वर्ष, महाराष्ट्र में 30 वर्ष तथा तमिलनाडु में 40 वर्ष के लिए तय की जाती थी।

**महालवाड़ी व्यवस्था** - महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बैंटिक द्वारा आगरा और अवध में लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में मालगुजारी की दृष्टि से पूरा गाँव ही एक संपूर्ण इकाई माना जाता था। जो भूमि गाँव में खाली होती थी उस पर गाँव के समाज का अधिकार होता था। गाँव का कोटवार

मालगुजारी एकत्रित करता था जिसके लिए उसको होता कमिशन मिलता था। सहभागी को अपनी इच्छानुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार था। यदि सहभागी उस भूमि को छोड़ देता था तो उस पर गाँव के समाज का अधिकार माना जाता था।

**जमींदारी प्रथा** - प्रथम ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में प्रारम्भ हुआ था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के गर्वनर कार्लवालिस ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से उसका ही स्थायी बंदोबस्त कर दिया था। इस प्रणाली में जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था भूमि संबंधी सभी अधिकार उसी के हाथ में होते थे। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था। लेकिन एक मध्यम वर्ग के माध्यम से होता था जिसे जमींदारी कहते थे।

**स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार** - स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के कई कार्यक्रम लागू किए गये, उनका मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास के साथ-साथ कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीवन स्तर को उंचा उठाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किये हैं जैसे मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन, जोतों की सीमा का निर्धारण।

**मध्यस्थों की समाप्ति** - स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने जमींदारी, जागीरदार, इनामदार, आदि सभी मध्यस्थों की समाप्ति कर भूमि पर कृषकों को भू-स्वामी संबंधी अधिकार प्रदान कर दिये हैं। देश की 40 प्रतिशत भूमि पर मध्यस्थ फैले थे।

**काश्तकारी सुधार** - काश्तकारी सुधार में लगान का नियमन किया गया। काश्तकारों एवं बटाईदारों को उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। कई राज्यों ने छोटी जोतों पर लगान को समाप्त किया गया।

**कृषि का पुनर्गठन** - सरकार ने कृषि पुनर्गठन हेतु अनेक संस्थागत परिवर्तन किये हैं, ताकि समाजवादी समाज की स्थापना हो कृषि क्षेत्र में सुधार, विकास के लिए नयी तकनीकी और तरीकों को अपनाया गया जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े किसानों की आय में बढ़ोतरी हो यह प्रक्रिया कृषि के



क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की जाती है।

**अध्ययन का उद्देश्य** - प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में वृद्धि करना

**शोध विधि** - प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तरीय का अध्ययन किया गया शोध अध्ययन में पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों का उपयोग कर निष्कर्ष निकाले गए

**तालिका क्रमांक 01: कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का अनुपात**

भूमि का अनुपात	जिला		कुल
	बड़वानी	धार	
1 एकड़ तक	8 (10%)	12 (15%)	20 (12.5%)
1-2 एकड़	22 (27.5%)	25 (31.25%)	47 (29.37%)
2-4 एकड़	24 (30%)	19 (23.75%)	43 (26.87%)
4 एकड़ से अधिक	21 (26.25%)	20 (25%)	41 (25.63%)
किराए की जमीन	5 (6.25%)	4 (5%)	9 (5.63%)

**सर्वेक्षण से प्राप्त स्रोत-** तालिका क्रमांक 01 से यह स्पष्ट है कि लगभग 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास एक एकड़ तक भूमि है, लगभग 29.37 प्रतिशत के पास 1 से 1 एकड़ के बीच भूमि है, 26.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं

के पास 2 एकड़ से 4 एकड़ के बीच भूमि है, 25.63 प्रतिशत के पास 4 एकड़ से अधिक भूमि है। 160 उत्तरदाताओं में से 5.63 प्रतिशत किराए की जमीन पर काम करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास स्वयं की लगभग 1 से 4 एकड़ कृषि भूमि है।

**उपसंहार-** भारत में पिछले 70 वर्षों में भूमि सुधार के कई कार्यक्रम प्रारंभ किये गए जिसके अंतर्गत जमींदार उन्मूलन, अधिकतम जोत सीमा निर्धारण, चकबंदी, लगान एवं पट्टे की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी इससे भूमि सुधार की और प्रशंसनीय प्रगति हुई।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. जयप्रकाश मिश्र, 2003, कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पेज न. 171-176
2. डॉ. पी.डी. माहेश्वरी एवं डॉ. शिलचन्द्र गुप्ता, भारतीय आर्थिक नीति, 2006, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पेज न. 221-223
3. डॉ. अनुपम गोयल भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.बी. पीडी., (2019-20), पब्लिकेशन, आगरा मथुरा पेज न. 77
4. डॉ. रितु तिवारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, (2021), मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पेज न. 54-58

\*\*\*\*\*

## किशोरियों का साथियों के साथ समायोजन का अध्ययन

डॉ. ममता खपेडिया\* रिंकी भाबर\*\*

\* सहा. प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शा.स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत  
\*\* सहा. प्राध्यापक (गृह विज्ञान) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - किशोरावस्था किसी भी समाज की वास्तविक पूंजी है। इन्हे राष्ट्र, समाज के विकास के लिए सुरक्षित एवं सुरक्षित किया जाना चाहिए। किशोरावस्था बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है, संपूर्ण बाल विकास में इस अवस्था का बहुत अधिक महत्व होता है यह अवस्था शारीरिक और मानसिक उतथल पुथल भरी होती है। किशोरावस्था लोगों के जीवन में एक कठिन विकास अवधि का प्रतिनिधित्व करती है किशोरावस्था में किशोरी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं वर्तमान समय में किशोरिया अपने साथियों के साथ समायोजन में एक विशेष प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है।

समायोजन की अवधारणा सबसे पहले डार्विन ने इसे भौतिक दुनिया में जीवित रहने के लिए एक अनुकूल के रूप में इस्तेमाल किया था मनुष्य अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होने से उत्पन्न होने वाली शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मांगों को समायोजन करने में सक्षम है। समायोजन घर की जीवन स्थितियों में, स्कूल में, व्यस्क होने पर कार्य स्थल में, वृद्धावस्था में एक संगठन आत्मक व्यवहार में, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें एक सुखी और सुख हाल जीवन की ओर ले जाती है स्वयं एवं अपने साथियों के साथ समायोजन व्यक्ति के जीवन और शिक्षा में विकास के लिए अति आवश्यक होता है।

समायोजन मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती व्यक्ति की इच्छाओं, विचारों, प्रेरणाओं, और लक्ष्य, आदि के संबंध में जितना अधिक समन्वय होता है समायोजन उतना ही अधिक अच्छा होता है यदि इसमें आवश्यकता से कम समन्वय हो तो समायोजन दुर्बल होगा। व्यक्ति की इच्छा विचार आचार्य परिणाम और लक्षण आदि की पूर्ति की मात्रा कम और किस रूप में हुई है इस पर समाचार आधारित होता है उनकी पूर्ति कितनी अधिक होगी समायोजन उतना अधिक अच्छा होगा व्यक्ति की इच्छाओं परिणाम लक्षण सामाजिक मूल्यों से कहा तक मेल खाते हैं यह भी समय समायोजन को प्रभावित करता है।

**आवश्यकता एवं महत्व** -किशोरावस्था एक समस्याओं से भारी अवस्था होती है इसे शारीरिक एवं मानसिक उताल-पुथल भारी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में किशोरी को समायोजन में अनेको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरिया राष्ट्र के विकास का एक अच्छा खासा भविष्य है, इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शोध अध्ययन हेतु 'किशोरियों के साथियों के साथ समायोजन का अध्ययन' विषय की आवश्यकता है। इस

अध्ययन का बहुत अधिक राष्ट्र के विकास हेतु प्रभाव पड़ेगा राष्ट्र के विकास में किशोरावस्था का समायोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

**उद्देश्य:**

1. किशोरियों के साथियों के साथ समायोजन का अध्ययन करना।
2. किशोरियों की शैक्षणिक योग्यता का अध्ययन करना।

**प्रतिदर्श इकाई** - प्रस्तुत अध्ययन में 50 किशोरियों का चयन किया गया है

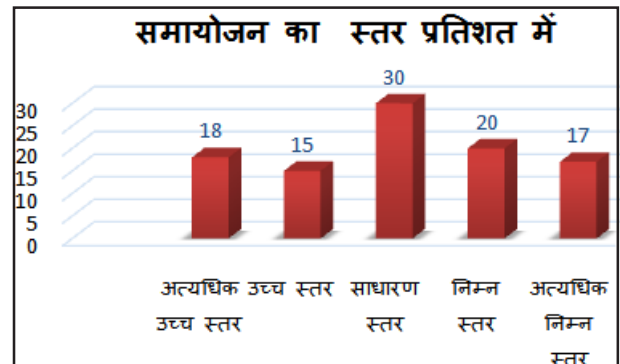
**अध्ययन के चर** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वतंत्र चर में किशोरियों। आश्रित चर किशोरियों का समायोजन एवं शैक्षणिक अध्ययन एवं परिवार का आकार आदि।

**समंक संकलन के स्रोत** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रारंभिक समंक हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया। द्वितीय समंक के लिए लघु शोध, इंटरनेट, पुस्तक, एवं अन्य साधनका प्रयोग किया गया।

**सारणीयन एवं वर्गीकरण-**

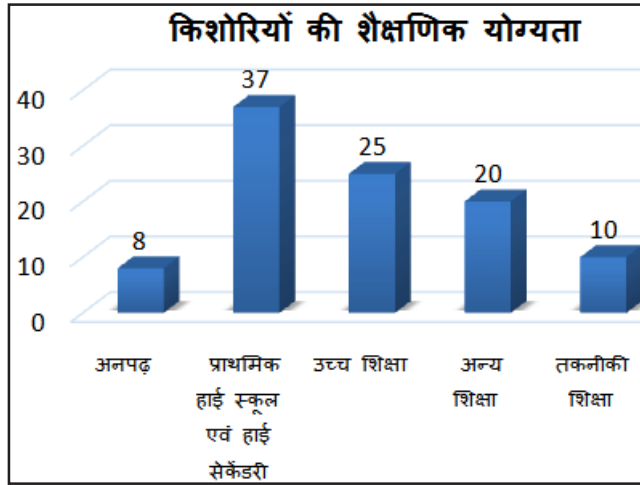
**तालिका नं. 01: किशोर -किशोरियों के साथियों के साथ समायोजनके स्तर संबंधित विवरण**

क्र.	विवरण	समायोजन का स्तर प्रतिशत में
1	अत्यधिक उच्च स्तर	18
2	उच्च स्तर	15
3	साधारण स्तर	30
4	निम्न स्तर	20
5	अत्यधिक निम्न स्तर	17
		100N=50



**तालिका नं. 02: किशोरियों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरण।**

क्र.	विवरण	किशोरियों की शैक्षणिक योग्यता
1	अनपढ़	08
2	प्राथमिक हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी	37
3	उच्च शिक्षा	25
4	अन्य शिक्षा	20
5	तकनीकी शिक्षा	10
		100N=50



**निष्कर्ष:**

1. किशोरियों का अपने साथियों के साथ क्रमशः अत्यधिक उच्च स्तर, उच्च स्तर, साधारण स्तर, निम्न स्तर, अत्यधिक निम्न स्तर 18%, 15%, 30%, 20%, 17%, प्रतिशत पाया गया।
2. किशोरियों का शैक्षणिक शोध अध्ययन से पाया गया कि किशोरियों का प्रतिशत क्रमशः अनपढ़, प्राथमिक हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी, उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा 08%, 37%, 25%, 20%, एवं 10% प्रतिशत पाया गया।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. आहूजा राम 2000 'सामाजिक समस्याएं' रावत पब्लिकेशन' दिल्ली।
2. तोमर रामविहार सिंह पारिवारिक 'समाजशास्त्र तथा आदर्श' अजमेर प्रकाशन <https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2212099.pdf>
3. <https://g.co/kgs/cxBcbhJ>, <https://g.co/kgs/jkyJnix>, <https://www.ijrti.org>
4. <https://www.drishtias.com/hindi/daily-news-analysis/feminization-of-agriculture>
5. <https://kurukhtimes.com/node/89>

\*\*\*\*\*

## व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं रोजगार (नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में)

डॉ. पूजा तिवारी\*

\* सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि देश का आर्थिक विकास करना है और जनता के जीवन स्तर को उपर उठाना है तो शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा भी जरूरी है, सभी देशवासियों के सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह अपना जीवन सामाजिक मापदंडों के अनुसार ही जीता है, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त अभिकरण है, जिसके कारण मनुष्य पशु से अलग है दोनों में मुख्य फर्क यही है की मनुष्य के पास शिक्षा है वह संस्कृति से ओतप्रोत है आज आवश्यकता इस बात की है की सभी विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाये। इस शोध आलेख के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों को विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया गया है।

**प्रस्तावना** – व्यावसायिक शिक्षा एक व्यक्ति को आपेक्षित कौशल के साथ लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसमें कैरियर और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आदि शामिल है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1980 को लागू करने के सम्बन्ध में सन 1988 में शिक्षा के व्यावसायिकरण पर केंद्र द्वारा आर्थिक रूप से संरक्षित योजना (CSS) पूरे देश में प्रारंभ की गयी।

व्यावहारिक कौशल इस शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र से व्यावसायिक विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान आदि के विभिन्न विषय रखे गये हैं जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

व्यावसायिक शिक्षा के कई क्षेत्र हैं जैसे सौन्दर्य और स्वास्थ्य कल्याण, हस्तशिल्प, जैविक खेती, बागवानी, वेब डिजायनिंग, वर्मी कम्पोस्ट, फैशन डिजायनिंग, कुक्कुट प्रबन्धन पर्यटन, बिक्री कौशल, मेडिकल प्लांट, खुदरा प्रबन्धन आदि।

प्रस्तुत आलेख के माध्यम से इवेंट मैनेजमेंट में कैरियर और फैशन डिजायनिंग में विद्यार्थी किस प्रकार से अपना कैरियर बना कर जीविका उपार्जन कर सकते हैं इसको विस्तारपूर्वक बताया गया है।

**इवेंट मैनेजमेंट**– इवेंट मैनेजमेंट का अर्थ है आयोजनों का प्रबंधन, यह कार्य इवेंट मैनेजमेंट कम्पनियों द्वारा किया जाता है। इवेंट मैनेजर का कार्य होता है किसी भी आयोजन के आरम्भ से अंत तक होने वाले हर कार्यक्रम, हर पड़ाव का सुचारु संचालन। आज के युग का महत्वपूर्ण रोजगार इवेंट मैनेजमेंट को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका कार्यक्षेत्र महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुका है।

**कार्य क्षेत्र**– विवाह समारोह, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन, फिल्मों के

प्रीमियर शो, स्टेज शो, सौन्दर्य प्रतियोगिताये, नये उत्पादों का प्रदर्शन, ऐड शो एवम अन्य बड़े कार्यक्रम या पार्टियाँ आदि।

**योग्यताएं** – इस कोर्स में एडमिशन हेतु किसी भी विषय के साथ बारहवीं पास होना एवम पी.जी.डिप्लोमा के लिए स्नातक होना जरूरी है। इस कोर्स के लिए विद्यार्थियों की अंग्रेजी में अच्छी पकड़ होना चाहिए।

इस प्रकार से जो यूवा अच्छी तर्कशक्ति, भाषा का ज्ञान, आकर्षक व्यक्तित्व एवं प्रस्तुतीकरण में माहिर हों उनमें रचनात्मक प्रबन्धन प्रायोगात्मक सोच, व्यवहार कुशलता हो वो अपने इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी खोल सकते हैं, इस क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व आपके संपर्क सूत्रों और क्षेत्रों का होता है जितने ज्यादा संपर्क होगा उतने ज्यादा कार्य करने के अवसर होंगे।

इवेंट मैनेजमेंट और जनसंचार से सम्बन्धित पाठ्यक्रम इन संस्थानों में उपलब्ध हैं — देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, नेशनल स्कूल ऑफ इवेंट इंडौर जामिया मिलिया इस्लामिया रिसर्च सेटर, दिल्ली, भारतीय जनसंचार संस्थान जे.एन.यू. दिल्ली यसेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन मरीन लाइंस मुंबई, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूर, कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे।

**फैशन डिजायनिंग में कैरियर** – फैशन और ड्रेस डिजाइन का जिक्र आते ही कला का एक उत्कृष्ट नमूना हमारी आँखों को चमकदार रंगों और डिजाइन के माध्यम से चमत्कृत कर देता है। तेजी से बदलते ट्रेंड के साथ फैशन के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण भारत में ड्रेस डिजाइनर की मांग बढ़ती जा रही है, यह भारतीय फैशन डिजाइनर का ही कमाल है की भारत की माडल्स दुनिया भर में धूम मचा रही है, आज मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, रितु कुमार, तरुण तहिलियानी, रितु बेरी, जे.जे. वलाया, सव्यसाची मुखर्जी, विक्रम फर्निंस, मनीष अरोरा, दिवंगत रोहित बल, अनीता डोंगरे, मसाबा गुप्ता।

अनामिका खन्ना और नैसी त्यागी आदि को सभी लोग पहचानते हैं इस क्षेत्र में मेहनत के साथ यश और कमाई भी है क्योंकि दुनिया में हर सप्ताह फैशन बदल जाता है नित नये डिजाइन बनाना बहुत मेहनत का काम होता है।

**शैक्षणिक योग्यता-** इस पाठ्यक्रम में मात्र 12 जीपरीक्षा 50% अंको से पास होना जरूरी है एवं स्नातकोत्तर हेतु स्नातक की परीक्षा 50% अंको के साथ पास होना जरूरी है।

फैशन एवं ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स करने वाले प्रमुख संस्थान - 1. राष्ट्रीय फैशन तकनीक संस्थान, नई दिल्ली 2. मध्यप्रदेश के विभिन्न महिला पोलिटेकनिक संस्थान 3. एस.एन.डीटी वीमेन यूनिवर्सिटी, मुंबई 4. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इंदौर 5. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेकनोलोजी, गांधीनगर, गुजरात।

### रोजगार एवम आय की संभावनाएं:

1. फिल्म और टीवी सीरियलों एवम कार्यक्रमों में कास्टयूम डीजायनर के रूप में अवसर।
2. सरकारी एवम प्राइवेट डिपार्टमेंट में हैण्डलूम और कपडा बनाने के क्षेत्र में अवसर।
3. खेल से सम्बन्धित ड्रेस तैयार करने सम्बन्धी व्यापार।
4. फैशन शो ओर्गनाइज करना।
5. बुटिक और कपडों का व्यापार करना।

आरम्भ में आय या वेतन कितना मिलेगा यह कहना मुश्किल है किन्तु अनुभव के साथ साथ अच्छी कमाई होना तय है आज हम देखते हैं की नैन्सी त्यागी ने फर्श से अर्श का सफर अपनी आत्मनिर्भरता एवम विश्वास से ही तय किया है एक आम लड़की जिसने सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन से

,आम मार्किट के सस्ते कपडे और साड़ियो से अद्भुद डिजाइन के गाउन तैयार करके कांस तक में धूम मचा दी है कल तक जिस आम लड़की को कोई नहीं जानता था आज हर व्यक्ति उसके गुणगान कर रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा का महत्व आज के समय में बहुत बढ़ गया है ये एक ऐसी शिक्षा है जो विद्यार्थियों को विशेष कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वे किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। आज के प्रतिस्धात्मक युग में सिर्फ पारम्परिक शिक्षा से ही अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते इसलिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए है।

निष्कर्ष स्वरुप व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार का एक गहरा सम्बन्ध है जब हम व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते हैं और उसे समाज में उचित स्थान प्रदान करते हैं, तब हम रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस दिशा में सरकार, संस्थाएं और समाज सभी को मिल कर प्रयास करना होगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भंडारी, जयन्तिलाल, केरियर के सोपान, इंदौर।
2. स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
3. वोकेशनल एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, दि रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मोडर्न इकॉनमी।

\*\*\*\*\*

## वेद, उपनिषद एवं भारतीय साहित्य में महिलाओं की भूमिका : श्रीमद्भगवद्गीता के विशेष संदर्भ में

भावना तिवारी\*

\* शोधार्थी (समाज कार्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - भारतीय दर्शन और साहित्य में नारी की भूमिका सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में समान अधिकार प्राप्त थे, जिसके प्रमाण गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों के विचार-विमर्श से मिलते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दार्शनिक जीवन दृष्टि है, महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों और मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं को समान रूप से स्वीकार करती है। गीता में वर्णित कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के सिद्धांत न केवल पुरुषों के लिए, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक उन्नति में लिंग कोई बाधा नहीं है।

इस शोध पत्र में गीता के स्त्री-सशक्तिकरण संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हुए भारतीय महिला दार्शनिकों के योगदान को भी समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही, यह अध्ययन आधुनिक संदर्भ में गीता के संदेश को नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। आज जब महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तब गीता में वर्णित सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। यह शोध पत्र इस विचार को प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि भारतीय दर्शन में नारी केवल श्रद्धा का नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान का भी प्रतीक रही है, और गीता का संदेश आज भी महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए उतना ही उपयोगी है जितना प्राचीन काल में था।

**शब्द कुंजी** - वेद, उपनिषद, गीता, नारी सशक्तिकरण, भारतीय दर्शन, महिला दार्शनिक, भक्ति आंदोलन।

**प्रस्तावना** - भारतीय दर्शन में स्त्रियों को सदा से ही सम्मानित और विशेष स्थान प्रदान किया गया है। वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक, महिलाओं ने न केवल धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के विकास में योगदान दिया है, बल्कि समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा, धर्म, राजनीति और दर्शन के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषियों ने न केवल ब्रह्मविद्या पर गहन चर्चा की, बल्कि ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों की ऋचाओं की रचना भी की। यह दर्शाता है कि उस समय स्त्रियों को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति और दार्शनिक संवाद में समान अवसर प्रदान किए गए।

महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद्गीता का उल्लेख आता है, जो केवल युद्ध और नीति का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का भी सार प्रस्तुत करती है। श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान, कर्म, भक्ति और ज्ञानयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जो न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में किसी जाति, वर्ग या लिंग का कोई बंधन नहीं है। श्रीकृष्ण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान मोक्ष प्राप्त करने और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होने के योग्य हैं।

भक्ति आंदोलन ने भी महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जहाँ मीराबाई, अक्का महादेवी, संत जनाबाई जैसी महान विभूतियों ने समाज

की रूढ़ियों को तोड़कर अपने आध्यात्मिक पथ को चुना। आधुनिक काल में सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा जैसी महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई, जिससे यह प्रमाणित होता है कि स्त्रियाँ केवल एक पारिवारिक संरचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने की भी क्षमता रखती हैं।

आज जब महिला सशक्तिकरण और समानता की बात हो रही है, तब श्रीमद्भगवद्गीता और अन्य शास्त्रों के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। यह शोध पत्र महिलाओं की भूमिका का गहराई से अध्ययन करेगा और यह विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार गीता और अन्य शास्त्र नारी सशक्तिकरण के सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं। साथ ही यह भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इन दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान के लिए लागू किया जा सकता है।

यह शोध पत्र महिलाओं की भूमिका का गहराई से अध्ययन करेगा और यह विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार गीता और अन्य शास्त्र नारी सशक्तिकरण के सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं।

**वेदों और उपनिषदों में महिलाओं की भूमिका:**

**वेदों में महिलाओं का योगदान:** वेदों में महिलाओं को न केवल सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, बल्कि उन्हें शिक्षा, ज्ञान, और आध्यात्मिकता में भी समान अधिकार दिए गए थे। वैदिक काल में महिलाएँ न केवल गृहस्थ

जीवन का संचालन करती थीं, बल्कि समाज सुधार, धर्म, और दर्शन में भी अपनी भूमिका निभाती थीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कई ऐसी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की और धर्मशास्त्रों में योगदान दिया।

### प्रमुख वैदिक विदुषियाँ

1. **गार्गी वाचनवी** - बृहदारण्यक उपनिषद में उनका उल्लेख मिलता है, जहाँ उन्होंने विद्वानों की सभा में महान ऋषि याज्ञवल्क्य से आत्मा और ब्रह्मज्ञान पर गहन शास्त्रार्थ किया। उनकी तर्क शक्ति और ज्ञान के कारण उन्हें तत्कालीन विद्वानों द्वारा षड्वह वादिनीष की उपाधि दी गई थी।

2. **मैत्रेयी** - ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी, जिन्होंने भौतिक संपत्ति के बजाय ब्रह्मज्ञान को सर्वोच्च माना। बृहदारण्यक उपनिषद में उनके संवाद मिलते हैं, जहाँ वे आत्मा और मोक्ष पर गहन प्रश्न करती हैं। उनकी ज्ञान-पिपासा और दार्शनिक दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

3. **लोपामुद्रा** ऋषि अगस्त्य की पत्नी, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों की रचना की। उनके योगदान से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में महिलाएँ न केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित थीं, बल्कि धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं।

4. **विश्ववारा** - ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, और उन्होंने कई वैदिक मंत्रों की रचना की। वे वेदों की गहरी ज्ञाता थीं और उनकी रचनाएँ ईश्वर और आत्मा के ज्ञान को विस्तार से समझाने में सहायक हैं।

5. **अपाला** - ऋग्वेद में उनका उल्लेख है, और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा तथा आरोग्य विज्ञान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी रचनाएँ आयुर्वेद और स्वास्थ्य विज्ञान की नींव रखने में सहायक मानी जाती हैं।

6. **रोमशा, शाश्वती, घोषा और श्रद्धा कामायनी** - ये सभी वैदिक विदुषियाँ थीं, जिन्होंने धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया।

**उपनिषदों में महिलाओं की भूमिका-** उपनिषदों में महिलाओं को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वे आत्मा, ब्रह्म, और मोक्ष जैसे विषयों पर गहन चर्चा कर सकती थीं। उपनिषदों की शिक्षाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान किसी लिंग विशेष का विषय नहीं है, बल्कि वह सभी के लिए खुला है।

1. **गार्गी वाचनवी** - उपनिषदों में गार्गी को एक महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म, आत्मा, और जगत के संबंध में गहन प्रश्न किए। उनका संवाद याज्ञवल्क्य के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने ब्रह्म को 'अव्यक्त तत्त्व' के रूप में परिभाषित किया। यह चर्चा भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण संवादों में से एक मानी जाती है।

2. **मैत्रेयी** - उपनिषदों में मैत्रेयी के संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि 'धन और भौतिक सुख से शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता,' बल्कि केवल ब्रह्मज्ञान से ही वास्तविक मोक्ष संभव है। यह विचार आगे चलकर अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों में से एक बना।

**श्रीमद्भगवद्गीता में नारी दृष्टिकोण-** श्रीमद्भगवद्गीता केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें स्त्रियों के आध्यात्मिक उत्थान, कर्म, भक्ति और ज्ञानकी समानता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। गीता में श्रीकृष्ण ने स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञान के योग्य माना है।

**स्त्रियों के आध्यात्मिक अधिकार** - श्रीमद्भगवद्गीता में नारी के आध्यात्मिक और सामाजिक अधिकारों की जो व्याख्या की गई है, वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि महिलाओं को पुरुषों के समान आत्मज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का अधिकार प्राप्त है। वैदिक काल से ही भारतीय परंपरा में महिलाओं को केवल परिवार और समाज तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ज्ञानार्जन, धर्म और नीति में भी समान स्थान दिया गया। श्रीकृष्ण स्वयं गीता में यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में लिंग कोई बाधा नहीं है।

स्त्रियों के मोक्ष प्राप्ति का अधिकारकृष्णगीता के नवम अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, वह परमगति को प्राप्त कर सकता है-

**मां हि पार्थ व्यपाश्रित्येऽपिस्युः पापयोनयः।**

**स्त्रियोवैश्यास्तथाशूद्रास्तेऽपियान्तिपरांगतिम्॥ (9.32)**

इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। यह विचार आधुनिक समय में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।

गीता में नारी को केवल मोक्ष प्राप्ति तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उनके भीतर स्थित दिव्य शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। श्रीकृष्ण कहते हैं-

**मृत्युःसर्वहरश्चाहमुदभवश्चभविष्यताम्।**

**कीर्तिःश्रीर्वाचनारीणांस्मृतिर्मेधा धृति क्षमा॥ (10.34)**

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों में विद्यमान कीर्ति, श्री (लक्ष्मी), वाणी (सरस्वती), स्मृति, मेधा (बुद्धि), धृति (धैर्य) और क्षमा जैसी विशेषताएँ ईश्वरीय गुणों के समान हैं। यह सिद्ध करता है कि स्त्रियाँ केवल करुणा और सहिष्णुता का प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि उनमें तेज, बुद्धि और शक्ति भी समाहित है। यह विचार स्त्री सशक्तिकरण की उस अवधारणा को बल देता है, जो यह मानता है कि महिलाएँ केवल एक सहयोगी शक्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निर्णय लेने वाली इकाई हैं।

गीता का कर्मयोग सिद्धांत भी महिलाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। श्रीकृष्ण कर्म के महत्व को समझाते हुए कहते हैं-

**कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषुकदाचन।**

**माकर्मफलहेतुर्भूमतिसङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥(2.47)**

इस श्लोक में वे बताते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह शिक्षा न केवल पुरुषों, बल्कि महिलाओं के लिए भी समान रूप से लागू होती है। जब महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं तब कृष्णजीति, विज्ञान, समाज सेवा, व्यापारकृतब गीता का यह संदेश उन्हें यह प्रेरणा देता है कि वे बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को निभाएँ और आत्मनिर्भर बनें।

भक्ति मार्ग में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं-

**पत्रंपुष्पफलंतोयंयोभक्त्याप्रयच्छति।**

**तदहंभक्त्युपहृतमश्नामिप्रयतात्मनः॥(9.26)**

यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान किसी भी व्यक्ति की भक्ति को

स्वीकार करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मीराबाई जैसी भक्त कवयित्री इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए भक्ति मार्ग को अपनाया और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की। गीता यह सिद्ध करती है कि भक्ति, ज्ञान और आत्मानुभूति के मार्ग में कोई भेदभाव नहीं है, और स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, गीता यह भी स्पष्ट करती है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता-

### वासांसिजीर्णानि यथा विहाय

### नवानिगृह्णातिनरोऽपराणि।

### तथा शरीराणिविहायजीर्ण-

### न्यन्यानि संयातिनवानिदेही॥(2.22)

इस श्लोक में श्रीकृष्ण आत्मा को शरीर से अलग बताते हैं और यह समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार स्त्री-पुरुष समानता की गहरी अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यदि आत्मा न तो पुरुष है और न स्त्री, तो आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। यह विचार आधुनिक समाज में लैंगिक समानता के लिए एक सशक्त दर्शन प्रदान करता है।

गीता का यह दार्शनिक दृष्टिकोण आज के युग में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो यह स्पष्ट करता है कि स्त्रियाँ भी आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं और समाज के उत्थान में समान रूप से योगदान दे सकती हैं। इस प्रकार, गीता का संदेश न केवल प्राचीन भारत की महिलाओं के लिए, बल्कि आधुनिक युग में भी उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

### भारतीय महिला दार्शनिकों का योगदान:

#### भक्ति आंदोलन और महिला संतः

1. **मीराबाई** - कृष्ण भक्ति की प्रतीक, जिन्होंने समाज के विरोध के बावजूद अपने भक्ति मार्ग को चुना।
2. **अक्का महादेवी** - कर्नाटक की वीरशैव संत, जिन्होंने शिव भक्ति को आत्मसमर्पण का माध्यम बनाया।
3. **संत जनाबाई** - महाराष्ट्र की संत, जिन्होंने जाति और लिंग भेदभाव को तोड़ते हुए भक्ति का प्रचार किया।
4. **अंडाल (गोदा देवी)** - तमिलनाडु की भक्ति संत, जिन्होंने विष्णु भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया।
5. **कर्मवती देवी** - मध्यकालीन संत, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में योगदान दिया और स्त्री स्वतंत्रता पर जोर दिया।

#### आधुनिक भारतीय महिला दार्शनिकः

1. **सावित्रीबाई फुले** - भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक क्रांति की शुरुआत की।
2. **महादेवी वर्मा** - आधुनिक भारतीय साहित्य और नारी वादी विचारधारा की प्रख्यात लेखिका।
3. **सरोजिनी नायडू** - स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री, जिन्हें 'इनाइटिगेल ऑफ इंडिया' कहा जाता है।
4. **मदर टेरेसा** - करुणा और सेवा के प्रतीक, जिन्होंने गरीबों और

जखरतमंदों की सेवा की।

5. **माता अमृतानंदमयी (अम्मा)** - आध्यात्मिक गुरु, जो प्रेम और सेवा के माध्यम से समाज कल्याण कर रही हैं।

6. **दया बाई** - समाज सेवा और आदिवासी उत्थान में योगदान देने वाली आध्यात्मिक महिला।

**आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता**- श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित नारी सशक्तिकरण के सिद्धांत केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में, जब महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, व्यापार और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, तब गीता का संदेश उनके आत्मनिर्भरता और आत्म-साक्षात्कार के मार्ग को और अधिक स्पष्ट करता है।

गीता यह स्पष्ट करती है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता और आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है। आज महिलाएँ न केवल अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी सफल हो रही हैं। गीता के कर्मयोग और भक्ति योग के सिद्धांत उन्हें यह प्रेरणा देते हैं कि वे बिना किसी बंधन या सामाजिक बाध्यता के, अपने कर्म और आत्म-विकास पर ध्यान केंद्रित करें।

इतिहास में, भक्ति आंदोलन के दौरान मीराबाई, अक्का महादेवी, और अन्य महिला संतों ने समाज के बंधनों को तोड़कर यह सिद्ध किया कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग सभी के लिए खुला है। गीता में वर्णित विचार, कि 'पुण्ये जो कोई भी प्रेम पूर्वक भक्ति अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ', इस बात की पुष्टि करता है कि आध्यात्मिकता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

आज जब महिलाओं को समान अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब गीता का कर्मयोग सिद्धांत यह प्रेरणा देता है कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहें, बिना परिणाम की चिंता किए। शिक्षा, तकनीक, सामाजिक कार्यों और व्यवसाय में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह प्रमाणित करती है कि वेदों और गीता में जो अधिकार उन्हें दिए गए थे, वे केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी सार्थक हैं।

इस प्रकार, गीता का संदेश केवल आध्यात्मिक जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और उनके समाज में योगदान की आवश्यकता को भी बल देता है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ, बल्कि जीवन दर्शन है, जो नारी उत्थान के लिए एक स्थायी प्रेरणा बना रहेगा।

**निष्कर्ष** - भारतीय दर्शन में महिलाओं को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता में महिलाओं की भूमिका को समान रूप से स्वीकार किया गया है। भक्ति आंदोलन से लेकर आधुनिक समाज तक, महिलाओं ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है।

आज के युग में, जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो गीता का संदेश हमें यह बताता है कि आत्मा न तो पुरुष होती है, न स्त्री। अतः हर व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष का समान अधिकार प्राप्त है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ सकते हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**



1. रामसुखदासस्वामी (1976) गीता प्रबोधिनी, गीता प्रेस, गोखपुर, उत्तर प्रदेश।
2. देसाई, ए. एस. (1987). समाज कार्य शिक्षा का विकास. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, मंत्रालय, समाज कल्याण, भारत सरकार, दिल्ली।
3. ब्रह्मचारी, नवीनकृष्ण 'विद्यालंकार' (1997, 24 फरवरी). श्रीमद्भगवद् गीता, श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ, मथुरा। प्रथम संस्करण - ॐ विष्णुपादश्रीश्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की आविर्भावा पृष्ठ 81, 101, 120, 233।
4. शर्मा, डॉ. अर्चना (2016). भारतीय परंपरा में धर्म की अवधारणा एवं मानवतावाद, (प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व) काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पृष्ठ 213-217।
5. गोवेन्द्र, गायत्री एवं गोवेन्द्र, अमृत (2017). श्रीमद्भगवद् गीता में तनाव प्रबंधन, देव संस्कृति इंटरडिसीप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल, खंड 10।
6. कृष्ण, डॉ. दत्तू मुरली (2019). भगवद् गीता और विज्ञान: एक समीक्षा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान, खंड 10।
7. बर्मोला, कैलाश चंद्र (2020, अगस्त), भगवद् गीता: संघर्ष समाधान की एक तकनीक. एमिटीबिजनेसजर्नल, एमिटीइंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर एंड एलाइडसाइंसेज, एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, जयपुर।
8. सिंह, डॉ. सुषमा (2021). पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और बौद्धिक संपदा अधिकार एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी, खंड 4।
9. त्यागी, आयुषी (2022), गीता प्रथम अध्याय पाठ का महत्व और लाभ।
10. भारती, शैलेंद्र (2020). सारेगामा भक्ति।
11. <https://www.jagran.com/spiritual/religion-geeta-jayanti-2021-5-shloka-of-geeta-which-give-right-direction-to-life-22290208.html>
12. [https://youtu.be/ypxjmZ\\_OFw?si=iZ6Gj\\_eckhWSQxTJ](https://youtu.be/ypxjmZ_OFw?si=iZ6Gj_eckhWSQxTJ)
13. <https://youtu.be/-9oBsKtGd38?si=UzO8tSAvA5GJS GS8>
14. <https://youtu.be/l2MU7wveU9c?si=ZjVNshSthVhX398D>
15. [https://youtu.be/s2bbePyJ2\\_g?si=whjY2h7CCqDGXYaq](https://youtu.be/s2bbePyJ2_g?si=whjY2h7CCqDGXYaq)
16. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bhagavad\\_Gita](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita)
17. <https://www.facebook.com/swami.ramdev/videos/881160363675810/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>
18. <https://dkvaas.org/blogs-1/f/the-importance-of-social-work-in-the-bhagavad-gita>

\*\*\*\*\*

## भारत में पर्यावरण सम्बन्धी कानून एवं नीतियों का अध्ययन

डॉ. नीतू\*

\* असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) भारत

**प्रस्तावना** – पर्यावरण शब्द परि+आवरण शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा आवरण जिसके चारों ओर से हम घिरे हुये होते हैं। अर्थात् हम अपने चारों ओर जिन जीव जन्तुओं, पेड़-पौधों व अन्य अनेक सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को देखते या महसूस करते हैं, उनसे बने वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। इसमें वातावरण या पर्यावरण के अतिरिक्त जलमण्डल, थलमण्डल तथा वायुमण्डल भी सम्मिलित रहते हैं। किसी भी स्थान के भौतिक, जैविक, अजैविक घटकों से बने संसार को उस स्थान का पर्यावरण कहते हैं।

भारतीय संविधान जो 1950 में लागू किया गया था, परन्तु इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जोड़ा गया था। सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर, दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48ए तथा 51ए (जी) जोड़ दिये। अनुच्छेद 48ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा, वनों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा एवं उसमें सुधार सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 51ए (जी) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, सभी जीवधारियों के प्रति दयालु बने एवं उसका संवर्धन करे।

**पर्यावरण संरक्षण में कानून व नियम का महत्वपूर्ण योगदान निम्न हैं-**

1. **जल अधिनियम, 1974-1977 :-** जल प्रदूषण में उद्योगों की वृद्धि तथा शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप हाल ही के वर्षों में नदी तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्या काफी महत्वपूर्ण बन गई है। अतः इसे घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्त्राव उस जल में नहीं मिलने दिया जाए, जो पीने के पानी के स्रोत, कृषि उपयोग तथा मत्स्य जीवन के पोषण के योग्य हो, नदी व दरियाओं का प्रदूषण भी देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर हानि पहुँचाने का कारण बनता है।

यह अधिनियम 26 मार्च, 1974 से पूरे देश में लागू किया गया। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण को रोके तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करे। इस कानून ने एक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की। इस कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में मिला देता है, तो उसे कानून में निर्धारित दंड दिया जायेगा।

जल प्रदूषण को रोकने में जल अधिनियम, 1977 भी एक महत्वपूर्ण

कानून है जिसे राष्ट्रपति ने दिसम्बर, 1977 को मंजूरी प्रदान की। जहाँ एक ओर यह जल प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है, वहीं जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी करता है।

**यह अधिनियम केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों को निम्न शक्तियाँ प्रदान करता है:-**

1. किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार।
2. किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का अधिकार।
3. औद्योगिक ईकाइयाँ तरल कचरा तथा सीवेज के तरीकों के लिए बोर्ड से सहमति ले।

2. **वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 :-** प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। यह अधिनियम 29 मार्च, 1981 को पारित हुआ तथा 16 मार्च, 1981 से लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर-गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएँ और गंदगी को नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत केन्द्रीय बोर्ड को मुख्यतः राज्य बोर्ड के काम में तालमेल बैठाने का अधिकार दिए गये हैं।

**इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार व केन्द्र सरकार दोनों को ही निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई हैं-**

1. वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना।
2. प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना।
3. अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन की जाँच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार।
4. अधिनियम के प्रावधानों को उलंघन करने वाले के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार।
5. प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार।

3. **वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 :-** वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम इसमें सर्वप्रथम सन् 1952 में भारतीय वन्यजीवन बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अन्तर्गत वन्य-जीवन पार्क और अभयारण बनाए गए। 1972 में भारतीय वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि, उद्योगों और शहरीकरण से वनों के कटाव को रोका जा सके। वनों के अधिक कटाव से अनेक वन्य जन्तुओं की कई

प्रजातियाँ लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह अधिनियम प्रारम्भ किया है।

**इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:**

1. चिड़ियाघरों व अभयारण्यों में वंश वृद्धि करना।
2. राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना।
3. संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण प्रदान करना।
4. संकटग्रस्त वन्यप्राणियों की सूची बनाना तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना।
5. वन्यजीवन के लाभों की जानकारी का शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना।

**4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 :-** भारत सरकार न वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश कदादे रोकना है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय वन नीति 1952 घोषित की गई लेकिन वनों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक होने से वन संरक्षण को भी बल मिला। सन् 1951 से 1980 के बीच वन भूमियों का अपरदन 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष था अब इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भूमि का अपरदन 55 हजार हेक्टेयर हो गया है।

**इस अधिनियम में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है-**

1. वन सम्बंधी योजनाएँ इस प्रकार हो ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले।
2. वनों की कटाई जहाँ तक सम्भव हो रोका जाना चाहिए।
3. पशुओं के लिए चारागाहों को ध्यान रखना चाहिए व चारे उत्पादन हेतु विशेष प्रावधान किया जाने चाहिए।
4. कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि कुछ समय में पुनः पेड़-पौधे उग सकें।
5. पहाड़ों, जल क्षेत्रों, ढलान वाली भूमियों पर वनों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

**5. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून :-** भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग अधिनियम का प्रावधान नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, 2000 पारित किया गया है। ध्वनि प्रदूषकों को अपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 तथा 290 का प्रयोग किया जा सकता है।

**6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 :-** सर्वप्रथम 5 जून, 1972 में स्टॉकहोम में सम्पन्न हुआ। इसी सम्मेलन को देखते हुए, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया, यह एक बहुत बड़ा अधिनियम है। जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, वातावरण में घातक रसायनों

की अधिकता को नियंत्रित करना। इस अधिनियम में 26 धाराएँ हैं। जिन्हे 4 अध्यायों में बाँटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवम्बर, 1986 से लागू किया गया है।

**इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है-**

1. मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना।
2. पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना।
3. पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना।
4. विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना।
5. मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना।

**7. जैव-विविधता संरक्षण, अधिनियम 2002 :-** सरकार ने जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया। इस कानून का उद्देश्य है जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए। भारत विश्व में जैव-विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर है। भारत में लगभग 45000 पेड़-पौधों व 81000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो विश्व की लगभग 7.1 प्रतिशत वनस्पतियों तथा 6.5 प्रतिशत जानवरों की प्रजातियों में से हैं।

**जैव विविधता कानून, केन्द्रीय सरकार को निम्न दायित्व भी सौंपता है-**

1. उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव जांचना जिनसे जैव विविधता को हानि पहुँचने की आशंका हो।
2. स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परम्परागत विधियों की रक्षा करना।
3. जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**8. राष्ट्रीय जलनीति, 2002 :-** राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। जल मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

**इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं-**

1. जल के बेहतर उपयोग व बचत के लिए जनता में जागरूक बढ़ाने की बात कही गई है।
2. जल बंटवारे की प्रक्रिया में प्रथम प्राथमिकता पेयजल को दी गई है।
3. इसमें पहली बार जल संसाधनों के विकास की बात कही गई है।

**9. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 :-** राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्तमान नीतियों का एकीकरण करती है। न्यायालय द्वारा पर्यावरण से हुई नुकसानी के लिए राहत और दुर्घटना से प्रभावी रूप से शीघ्र निपटने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति चलाई गई।

**इस अधिनियम में निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं-**

1. प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है।
2. सतत विकास का केन्द्र बिन्दु मानव है।
3. विकास के अधिकार की प्राप्ति पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
4. स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना।
10. वन अधिकार अधिनियम, 2006 :- वन अधिकार अधिनियम 18

दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया है। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई।

#### इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न है-

1. विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्स्थान का प्रावधान करता है।
2. जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागिदारी सुनिश्चित करता है।
3. जंगलों में रहने वाले लोगो तथा जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है।
4. पशु चराने तथा जल संसाधनों के प्रयोग का अधिकार देता है।

#### सुझाव :-

1. देश में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उससे सम्बन्धित कानूनों को कड़ाई से लागू करे।
2. स्कूल, कॉलेजो, विश्वविद्यालयों में प्रदूषण एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ताकि छात्रों को इसकी जानकारी हो सके और वे इसे अपना ले।
3. रेडियो और दूरदर्शन से प्रत्येक दिन 5 से 7 मिनट का प्रोग्राम प्रसारित किया जाना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार इस पर एक लंबा प्रोग्राम दिखाया जाना चाहिए।
4. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कार्य होना चाहिए कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उन सबकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया

भाव रखे।

5. वन संरक्षण अधिनियम में कानून को कड़ाई करना चाहिए ताकि वनों के कटाव पर रोक लगा सके। आज भी चौड़ी सड़को के लिये पेड़ काटे जा रहे हैं। जिसके कारण लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदूषण के कारण ही बहरापन, विकलांगता, अंधापन, कैंसर, अस्थमा आदि बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं।

**निष्कर्ष** - हमारी नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल दर्शाती है। पर्यावरणीय सम्बन्धी अधिनियम तो है पर इसका सुचारू रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। भारत में पर्यावरणीय की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नाले, नदियाँ तथा झीलें, औद्योगिक कचरे से भरी हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है। वन क्षेत्र में कटाव लगातार बढ़ता रहा है। जिसके परिणाम में हमें हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में स्पष्ट देखने को मिला है। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों को लागू किया गया है, उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनों के महत्व को समझा ही नहीं गया है। पर्यावरण नीति को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शशि शुक्ला एवं एनके0तिवारी:- पर्यावरण एक परिचय, राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा।
2. हमारा पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण समिति दिल्ली, पृष्ठ-45
3. तपन बिसवाला, मानवाधिकार, जेनूर एवं पर्यावरण, वीबा, 2008

\*\*\*\*\*

## जीव विज्ञान की उपलब्धि में इण्टरनेट की उपयोगिता का अध्ययन

डॉ. नाजिया कौशर\* रेनुका शर्मा\*\*

\* सहायक प्रध्यापक (शिक्षा) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

\*\* सहायक प्रध्यापक (शिक्षा) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

**शोध सारांश** - किसी भी अनुसंधान का सबसे आवश्यक एवं मूल्यवान कार्य होता शोध का अध्ययन करना। कोई भी शोधकर्ता अपने पूर्व में जो अध्ययन हुए उनका लाभ लेना पसंद करता है। क्योंकि कोई भी अध्ययन पूर्णतः अलग नहीं होता है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। विकसित शिक्षण प्रणाली, सरलता, संसाधनों की उपलब्धता मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक इत्यादि राष्ट्र के शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस अध्ययन से अभिप्राय है कि जिस विषय पर अनुसंधानकर्ता शोध करने जा रहा है उसके बारे में जो भी सुन्दर व सुखद भविष्य के लिए व्यक्ति सदा से ही अनुसंधान की ओर प्रवृत्ति रहा है।

**प्रस्तावना** - जीवन में अनेको परिवर्तन हुए है, इन परिवर्तनों में एक हैं इण्टरनेट। इण्टरनेट के माध्यम से हम अनेको जानकारीएँ एक ही समय पर एक ही स्थान पर प्राप्त कर पाते है। इण्टरनेट एक एक ऐसा संचार माध्यम है, जो सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सहायक होता है। इण्टरनेट ने कल्पनाओं को आज यथार्थ में बदल दिया है। जो हमने अपनी बाल्यावस्था में कहानियों में सुना था, वह व्यवहार से लाया जा चुका है। इण्टरनेट ने दुनिया को समेट दिया है। मनुष्य का मन कल्पनाशील है और भी जो नित नये की तलाश में रहता है। उसकी विवेकशीलता, कल्पना, मौलिकता और दक्षता से ही उसे सबसे भिन्न और सर्वोत्कृष्टता प्रदान की है। मनुष्य ने अपने युगों से प्राप्त अनुभवों एवं उपलब्धियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। इस हस्तांतरण को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक निर्देशन प्रक्रिया है जैसा कि एक बालक कुछ सम्भावना के साथ उत्पन्न होता है। जो अविकसित दशाओं में होता है, इसका विकास करना होता है तथा एक दिशा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा के द्वारा ही प्रदान की जाती है। वास्तव शैक्षिक प्रक्रिया बालकों को अच्छे जीवन की ओर निर्देशन देने प्रक्रिया है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में इनका अत्याधिक महत्व है। यह शिक्षा अध्यापकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुकूल वातावरण निर्मित करने में सहायक सिद्ध होगी।

**जीव विज्ञान अध्ययन में इण्टरनेट की उपयोगिता** - युवाओं के आचरण एवं मानसिकता का ज्ञान आदि कि अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए शोधकर्ता ने इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि जीव विज्ञान की उपलब्धि में इण्टरनेट की उपयोगिता के प्रति जागरूकता साकारात्मक सोच, व्यक्तिगत तथा वाह्य जगत से उनके संबंध आदि का बोध कराता है इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना।

जीव विज्ञान के अध्ययन और उपलब्धि में आई सी टी का संभावित उपयोग बहुत बड़ा है, यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है और नए लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। कंप्यूटर सीखने के प्रोग्राम समूह और वेब सीखने के लिए कई तरह के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें गैर-इंटरैक्टिव सामग्री

प्रावधान से लेकर अत्यधिक इंटरैक्टिव छात्र-केंद्रित सीखने के अनुभव शामिल हैं। न्यू साउथ वेल्स स्कूलों में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री में सूचना वेब साइट्स, ट्यूटोरियल या संशोधन सामग्री के रूप में कंप्यूटर लर्निंग पैकेज, छात्रों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर लर्निंग पैकेज, वर्चुअल फील्ड ट्रिप, सिमुलेशन और वर्चुअल प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, छात्र और शिक्षक ई-मेल, समाचार समूहों और चर्चा सूचियों, स्थानीय और वैश्विक संचार दोनों के लिए वीडियोकांफ्रेंसिंग और टेलीकोलैबोरेटिव परियोजनाओं के माध्यम से आपस में संवाद करने के लिए वेब का उपयोग कर रहे हैं। यह लेख छात्र सीखने में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और स्कूल प्रणाली के भीतर उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूपों पर ध्यान केंद्रित करेगा। संसाधनों की एक सूची प्रदान की गई है।

जीव विज्ञान और आईटी क्रांति जीव विज्ञान शिक्षण पारंपरिक रूप से तीन अलग-अलग वातावरणों में से एक या अधिक में होता है; व्याख्या कक्षा या कक्षा, प्रयोगशाला और मैदान ('बाहर')। हालाँकि, मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ इन तीनों शिक्षण वातावरणों की विशेषताओं को जीव विज्ञान के छात्र के कंप्यूटर डेस्क टॉप पर अनुवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। एक शिक्षक और उसके कुछ छात्रों द्वारा इसका परीक्षण करने पर आधारित है, जो जीव विज्ञान शिक्षा में आईटी की भूमिका उपलब्धि परिप्रेक्ष्य देता है, स्कूलों में वीएफटी के उपयोग का एक बहुत ही सकारात्मक विवरण प्रस्तुत करता है।

जीव विज्ञान शिक्षा में अध्ययन में इण्टरनेट की उपयोगिता के एकीकरण से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं जो शिक्षण और सीखने दोनों को बढ़ाते हैं। जो इस प्रकार हैं -

**लगाव और प्रेरणा** : पारंपरिक शिक्षण विधियाँ कभी-कभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में विफल हो सकती हैं, खासकर जब जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं से निपटना हो। इंटरैक्टिव सिमुलेशन, शैक्षिक खेल और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ जैसे आईसीटी उपकरण छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ सकते हैं, जिससे सीखना मजेदार हो सकता है और जिज्ञासा को बढ़ावा मिल सकता है।

**संसाधनों तक पहुँच :** आईसीटी के साथ, छात्र ऑनलाइन संसाधनों के भंडार तक पहुँच सकते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होंगे। डिजिटल पाठ्यपुस्तकें, ऑनलाइन पत्रिकाएँ, शैक्षिक वीडियो और वर्चुअल लैब छात्रों को उनकी भौतिक कक्षा की सीमाओं से परे अन्वेषण करने में सक्षम बनाती हैं।

**सहयोग और संचार :** आईसीटी उपकरण छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, चाहे वे एक ही कमरे में हों या दुनिया के विपरीत छोर पर। गूगल क्लास रूम, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों को विचारों को साझा करने, समूह परियोजनाओं पर काम करने और सहजता से संवाद करने में सक्षम बनाते हैं।

**सिम्युलेशन के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा :** विज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यावहारिक, व्यावहारिक अनुभव से बहुत लाभ उठाता है। हालाँकि, कुछ प्रयोग महंगे, समय लेने वाले या खतरनाक भी हो सकते हैं। आईसीटी आभासी सिम्युलेशन के उपयोग को सक्षम बनाता है, जहाँ छात्र नियंत्रित वातावरण में प्रयोग कर सकते हैं और वैज्ञानिक घटनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं।

**वास्तविक समय डेटा विश्लेषण :** विज्ञान अवलोकन, माप और विश्लेषण के बारे में है। आईसीटी उपकरण छात्रों के लिए वास्तविक समय में डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना आसान बनाते हैं। चाहे वह मौसम के पैटर्न को ट्रैक करना हो, वर्चुअल लैब में प्रयोग करना हो या बड़े डेटासेट का विश्लेषण करना हो, आईसीटी विज्ञान को अधिक सुलभ और मूर्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**निष्कर्ष -** इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह बात स्पष्ट होती है कि विज्ञान शिक्षा में आईसीटी की भूमिका परिवर्तनकारी है। वर्चुअल लैब और सिम्युलेशन से लेकर ऑनलाइन सहयोग टूल तक, प्रौद्योगिकी का एकीकरण विज्ञान सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए रोमांचक संभावनाएँ प्रदान करता है। हालाँकि, आईसीटी के वास्तव में प्रभावी होने के लिए, शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, और छात्रों को आवश्यक

संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डॉ. भटनागर ए. बी. एवं डॉ. श्रीमति मीनाक्षी भटनागर (2007) 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन' आर. लाल बुक डिपा मेरठा।
2. <https://teachers.institute/pedagogy-of-science/role-of-ict-in-science-education/>
3. <ce//efaidnbmnnnibpccajpcglclefindmkaj/https://www.ccmr.res.in/hindi/jigyasa-2017-18>
4. Bharthi, G. (1984), "A study of self concept and achievement Motivation of early adolescents." Ph.d. psy.Vol, P.541.
5. Gupta p. (1984) "Self concept, dependency and adjustment pattern of adanoloned Institutitalized preadopsents". Vol,1 P.369-70.
6. Kirkland, K., and Hollandsworth, J.G., Jr. (1979). Test anxiety, study skills, and academic performance. J. Coll. Stud. Person. 20,431 -435. (accessed November 15, 2003).
7. Klymkowsky, M.W., Garvin-Doxas, K., and Zeilik, M. (2003). Bioliteracy and teaching efficacy: what biologists can learn from physicists. Cell Biol. Educ. 2, 155-161. (accessed November 15, 2003).
8. King, G.A. : Shult I.Z. Sted, K. Gilpin, M & Cathers T. (1993)- "Self Evaluation and self concept of adolescents with physical disabilities", American Journal of occupational therapy 47.2.132-140.
9. Kabal D., Musek J. (2001) "Self and academic achievement Slovenia and France. Personality and individual difference" 30(5): 887-899.
10. ifescied.org/doi/10.1187/cbe.03-11-0022

\*\*\*\*\*

## भारतीय इतिहास में भक्तिकालीन संत पीपाजी का जीवन एवं कृतित्व एक अध्ययन

**डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत\***

\* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** – राव पीपा, जो बप्पा के नाम से भी उच्चारित किये जाते थे। ये बड़े ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं और उनकी प्रसिद्धी का कारण उनका शासक होना नहीं है, इसका कारण उनके द्वारा राज्य का त्याग कर संत प्रवृत्ति को अपनाया था। राव पीपा सन् 1360 ई. में गद्दी पर बैठे। इनका आरंभिक नाम प्रतापराव खींची था। संत बनने के पश्चात् संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये कड़वाराव के पुत्र थे। कड़वाराव के अन्य पुत्रों में भजनसिंह, चाचदेव व मलयसिंह का नाम आता है। इनमें से मलयसिंह ने मालवा में राघोगढ़ का राज्य स्थापित किया, मलयसिंह ने राघोगढ़ से शेरगढ़ लेकर अपने राज्य राघोगढ़ की स्थापना की एवं राघोगढ़ का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। पीपाजी ने अनेक वर्षों तक गागरोनगढ़ के राज्य पर शासन किया। उस समय के गुजरात, राजपूताना और मध्यभारत के राज्यों की राजकुमारियों से इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किये। पीपाराव के समय में दिल्ली के सुल्तान ने उनके राज्य पर आक्रमण किया। आक्रमण का कारण गागरोनगढ़ के द्वारा दिल्ली सल्तनत को कर नहीं देना था। जिसके कारण आक्रमण हुआ। अतः सुल्तान ने अपने सेनापति जिसका नाम जर्दफिरोज था, के सेनापतित्व में लगभग 12000 सैनिकों के साथ भयानक आक्रमण किया, परंतु राव पीपा ने अपने अदम्य साहस एवं अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया। इस आक्रमण में दिल्ली सल्तनत को मुंह की खानी पड़ी व गागरोनगढ़ पर अधिकार करने का सुनहरा अवसर खो दिया। इस युद्ध में राव पीपा के रण कौशल का प्रदर्शन सबने देखा, हालांकि इस युद्ध में स्वयं सुल्तान भी सम्मिलित था फिर भी वह इस युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने में विफल रहा व उसको दिल्ली खाली हाथ ही लौटना पड़ा।

प्रतापराव ने अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं किया। वे सभी धर्म के लोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। प्रतापराव के समय में भक्तिकाल का आगमन हो चुका था। उस समय में संत रामानंद और उनके शिष्य जिनमें कबीर, नानक, दादू, सेना, रविदास जनमानस में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का गुणगान किया करते थे। उस समय की भक्ति भावना से प्रतापराव भी अपने आप को नहीं बचा सके। प्रतापराव का मन भी प्रारंभ से ही युग की भावना के अनुरूप था। इन्होंने इसी भावना से प्रभावित होकर के प्रकाण्ड विद्वान स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में कबीर और रैदास उनके बड़े प्रशंसक थे।

तत्कालीन समय में समाज में विश्रमता व्याप्त थी। धार्मिक, समाजिक,

वर्ण,जाति के आधार पर समाज में घोर निराशा का वातावरण व्याप्त था। इसी आधार पर संतपीपा ने जाति पांति, बाह्य आडम्बर और धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की आलोचना की। उनकी दृष्टि में मानवमात्र समान है, किसी भी आधार पर उनमें भिन्नता नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज में अलख जगाने का प्रयास किया।

प्रतापराव की रानियों में सीतादेवी का स्थान प्रमुख माना गया है। इन्होंने अपने पति के संत बनने के पश्चात् उनका अनुकरण किया व आजीवन उनके साथ रही। सीतादेवी का वास्तविक नाम पद्मावती था। ये राजपूताना के सोलंकी टोड़ाराय की राजकुमारी थी। यही एकमात्र रानी थी, जिसने अपने पति के वैराग्य में उनका साथ दिया व दिव्य स्थान प्राप्त किया। इसी कारण उनको सम्मान के साथ सीता सहचरी कहा जाता है। इनके सम्मान में अनंतदास ने लिखा है-

**संपत विपत न जानही, करे कंत की सेवा**

**सो पतपाता नार है,रहै सबद का भेषा<sup>2</sup>**

संत पीपाजी की चार रचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इन रचनाओं में है पद, साखियाँ, ककहरा और चितावणी।

संत पीपाजी के संबंध में किंवदंती से जानकारी प्राप्त होती है कि इनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे। भरत राजमंडल के अनुसार जब अपनी रानी सीताबाई के साथ में श्रीकृष्ण से भेंट करने के लिए द्वारिका पहुंचे। जब उनकी भेंट श्री कृष्ण से नहीं हुई, तो वे अपनी रानी के साथ में समुद्र में कूद पड़े। फिर समुद्र के अंदर उनकी भेंट श्रीकृष्ण से हुई और ये वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ 8 दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ में उनके स्वर्ण भवन में रहे। जब वे बाहर आए तो शंख, चक्र, गदा और पद्म के छापों के निशान के साथ में आए। उनकी पत्नी सीताबाई को रूकमणीजी ने अपनी अंगूठी प्रदान की। इसी के बाद में द्वारिका में छापे देने का क्रम आरंभ हुआ, जो आज तक अनवरत् चल रहा है। ये वही छपा दिया जा रहा जो संत पीपाजी अपने साथ में लाए थे। संवत् 1415 ई. से अगले 25 वर्ष तक संत पीपाजी के शासन करने की जानकारी खिलचिपुर की हस्तलिखित ख्यात में मिलती है। पीपाराव के कोई संतान नहीं थी अतः इन्होंने कल्याणराव को गोद लिया था।<sup>3</sup>

पीपाजी स्वामी रामानंदजी के शिष्य थे उनको अपने गुरु पर अटूट विश्वास था इसी विश्वास के अनुरूप इन्होंने लिखा है-

**पीपा गुरु परताप तैं,जरगियों रगत विकारा**

**तन मन सब चाणन हुआ, लागी सबद कटारा।<sup>4</sup>**

भक्तिकालीन अन्य संतो के समान संत पीपाजी ने भी गुरु को मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया है और उनके प्रति अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है।

संत पीपाजी संत कबीर और संत रैदास के समकालीन थे और वे उनके गुरु भाई थे। संत रैदास ने उनके बारे में लिखा है-

**ना कबीर के लच्छमी,ना कोई मेरे ठाठ।**

**धन पीपा जिण तज्यो,सगरो राज अरू पाटा।<sup>5</sup>**

संत पीपा मानवतावादी संत थे दुसरो के दःख से प्रभावित होकर आपने अपनी वाणी के माध्यम से कहा है-

**पीपा पर उपकार में,अपने मन को मारा**

**पीर पराई समझ ले,अपना दुःख निसारां<sup>6</sup>**

प्रस्तुत पद के माध्यम से संत पीपाजी का मानवमात्र के प्रति कल्याणकारी भावना प्रतीत होती है। वे आजीवन इसी भावना का प्रचार-प्रसार करते रहे।

संत पीपा ने क्षत्रिय वर्ग द्वारा की जाने वाली हिंसा का विरोध किया है उन्होने हिंसा का स्थान छोड़कर सिलाई का कार्य प्रारंभ करवाने का श्रेय दिया जाता है अतः उनके अनुयाई पीपा दर्जी कहलाते है-

इतिहासकार अम्बादास माथुर ने उनके बारे में लिखा है-

**पीपा खींची भक्त थो,छोड़ रजपूती काम।**

**कपड़ों सीतो हाथ सूं,मन में जपतो राम।।**

**तबसे चली परंपरा,पीपा दर्जी काम।**

**सूचिकारी काम से,हुए जगत विख्यात्।<sup>7</sup>**

वर्तमान में राजस्थान राज्य में आहू और कालीसिंध नदि के संगम पर गागरोनदुर्ग स्थित है इसी गागरोनदुर्ग की पर्वतमालाओं के मध्य संत पीपाजी का भव्य मंदिर स्थित है इस मंदिर में संत पीपाजी एवं उनकी पत्नी

सीता सहचारी की मूर्तियाँ स्थापित है इनको देखने दूर-दूर से हजारों पर्यटक आते है।

मध्यकालीन संतो में पीपाजी एकमात्र ऐसे क्षत्रिय संत थे जिन्होने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया और राज्य वैभव का त्याग कर जनमानस की भवना के अनुकूल समाज में व्याप्त कुर्रतियों पर प्रहार किया और अपनी वाणी से भक्तिकाल को समृद्धि प्रदान करने का कार्य किया।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

- 1 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 12
- 2 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 65
- 3 चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम लेखक-देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 103
- 4 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 23
- 5 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 41
- 6 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 77
- 7 राजर्षि संत पीपाजी लेखक-ललित शर्मा प्रथम संस्करण:2012 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट,जोधपुर पृष्ठ संख्या 45

\*\*\*\*\*



## उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिलाषाओं का विश्लेषण

राकेश कुमार जीनगर\* डॉ. राखी शर्मा\*\*

\* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन (म.प्र.) भारत

\*\* सह-प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी बाह्य रूप से एक समान प्रतीत होते हैं, किंतु गहराई से देखने पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रवृत्तियों और अनुभूतियों के आधार पर हर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 'आकांक्षा' नामक एक विशिष्ट गुण विद्यमान होता है, जो उसे अपने भविष्य के प्रति योजनाएँ बनाने और यह लक्ष्य तय करने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, तब यही आकांक्षा उसे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को तय करने और उनकी पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। प्रारंभ में ये लक्ष्य केवल कल्पनाओं के रूप में होते हैं, किंतु समय के साथ वे धीरे-धीरे वास्तविक स्वरूप धारण करने लगते हैं।

**शब्द कुंजी** -शैक्षिक आकांक्षा, यथार्थवाद, आदर्शवाद, शैक्षिक उपलब्धि।

**प्रस्तावना** - शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। इसके माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं का विस्तार होता है, उसकी समझ और दक्षता में सुधार होता है और उसके आचरण में सकारात्मक बदलाव आता है। विद्या के माध्यम से मानव को सभ्य, संस्कारित और एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। आज के समय में हमारे देश में आर्थिक असमानता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को अपनी शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब समाज उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को अव्यावहारिक मानते हुए आलोचना करता है, तो वे विद्यार्थी स्वयं को असहज अनुभव करने लगते हैं, जिससे उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार, शैक्षिक आकांक्षाओं से जुड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत किशोर छात्रों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जब विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी अपने लिए भविष्य के शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वह उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास आरंभ करता है। किंतु कई बार अपेक्षित उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने पर वह उदासी का अनुभव करने लगता है। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक संवेदनशील माना जाता है। यही संवेदनशीलता कभी-कभी उनके लिए परेशानी का सबक बन जाती है। ऐसी ही समस्याओं में से एक है अपने शैक्षणिक उद्देश्यों में असफल होने के पश्चात हतोत्साह होकर नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ना।

शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श के अभाव में किशोर विद्यार्थी सोशल मीडिया, सामाजिक प्रभाव और बाहरी आकर्षण के प्रभाव में अपनी वास्तविक क्षमताओं से परे जाकर उच्च शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जब ये लक्ष्य पूरे नहीं होते, तो वे दिवास्वप्नों के चक्रव्यूह में उलझकर अपनी ऊर्जा का अपव्यय करने लगते हैं।

**समस्या कथन** - उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा के स्तर का विश्लेषण।

**समस्यात्मक विवरण में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषा**

**(क) उच्च माध्यमिक स्तर**

**सामान्य अर्थ**- उच्च माध्यमिक स्तर का तात्पर्य उन कक्षाओं से है, जो विद्यालयी शिक्षा के कक्षा 11 एवं 12 के स्तर पर संचालित होती हैं।

**विशेष अर्थ** - प्रस्तुत अध्ययन में उच्च माध्यमिक स्तर से आशय जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित, राजस्थान बोर्ड से संबद्ध प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों से है।

**(ख) विज्ञान वर्ग**

इस अध्ययन में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का अर्थ उन छात्रों से है, जो कक्षा 11 एवं 12 में राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान विषयों - जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित आदि विषयों को पढ़ते हैं।

**(ग) शैक्षिक आकांक्षा**

**सामान्य अर्थ**- शैक्षिक आकांक्षा का आशय विद्यार्थी द्वारा अपनी वर्तमान शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर भविष्य के लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति की अपेक्षाओं से है।

**विशेष अर्थ** - प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक आकांक्षा से आशय जिला चित्तौड़गढ़ के राजस्थान बोर्ड से संबद्ध प्राप्त स्कूलों में कक्षा 11 एवं 12 में पढ़ने वाले विज्ञान समूह के विद्यार्थियों द्वारा वी.पी. शर्मा एवं अनुराधा गुप्ता द्वारा निर्मित शैक्षिक आकांक्षा मापदंड (EAS&SG & Form P) पर प्राप्त किए गए अंकों से है।

**शोध के उद्देश्य** - उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे विज्ञान संकाय के छात्रों की शैक्षणिक अभिलाषा का स्तर का विश्लेषण करना।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग की छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का अवलोकन करना।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**शोध की परिकल्पनाएँ** – उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के छात्रों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर निम्न है।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग की छात्राओं का शैक्षिक आकांक्षा स्तर निम्न है।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है।

**शोध की परिसीमाएँ** – प्रस्तुत अध्ययन केवल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले तक सीमित है।

यह अध्ययन राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित है।

अध्ययन में केवल कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

इस अध्ययन का आधार 120 विद्यार्थियों का नमूना आकार और उनका शैक्षिक आकांक्षा स्तर तक सीमित है।

#### संबंधित साहित्य सर्वेक्षण

**शर्मा, एस. निधि (2002)**, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में 'उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षाओं पर माता-पिता के भावनात्मक संबंधों का प्रभाव' विषय पर अनुसंधान किया। अपनी शोध प्रक्रिया में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उच्च और निम्न निष्पत्ति वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन विद्यार्थियों के माता-पिता का अपनी संतान के प्रति उच्च सकारात्मक भावनात्मक संबंध होता है, उन विद्यार्थियों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके विपरीत, जिन विद्यार्थियों के माता-पिता का अपनी संतानों के प्रति भावनात्मक संबंध निम्न स्तर का होता है, उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में भी गिरावट देखी गई।

**गौतम, अमित एवं चंदेल, एन.पी.एस. (2016)**, दर्यालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) में 'विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन' विषय पर अनुसंधान किया। अपनी शोध प्रक्रिया में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, जबकि उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में कोई सार्थक अंतर परिलक्षित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा के मध्य एक हल्का नकारात्मक सह-संबंध (Negative Correlation) होता है।

**यादव, सुनील कुमार (2018)**, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में 'विज्ञान वर्ग के छात्रों की शैक्षणिक आकांक्षाओं पर पारिवारिक परिवेश का प्रभाव विषय पर शोध किया। अपने अध्ययन में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण अध्ययन के अनुकूल होता है, उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में वृद्धि देखी जाती है। विशेष रूप से विज्ञान समूह के छात्रों में यह प्रवृत्ति ज्यादा स्पष्ट रूप से पाई गई।

**सिंह, प्रिया (2021)**, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा पर विद्यालयी वातावरण का प्रभाव' विषय पर अनुसंधान किया। अपनी शोध प्रक्रिया में उन्होंने यह

निष्कर्ष निकला कि जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सुविधाएं, अनुभवी शिक्षक तथा परामर्शदाताओं का सहयोग मिला, उनकी शैक्षिक आकांक्षाएं अपेक्षाकृत उच्च स्तर की थीं। इसके विपरीत, संसाधनों की कमी वाले विद्यालयों के छात्रों में शैक्षणिक अभिलाषाओं का स्तर कम दर्ज किया गया।

**शेखावत, संजय कुमार (2019)**, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में 'राजस्थान के उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के छात्रों की शैक्षणिक अभिलाषाओं पर सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का प्रभाव' विषय पर शोध किया। अध्ययन में उन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों का शैक्षिक आकांक्षा स्तर अधिक था। साथ ही, जिन विद्यार्थियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में वृद्धि देखी गई।

**शोध विधि** – इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि (Descriptive Survey Method) का उपयोग किया गया। इस विधि के अंतर्गत क्रॉस-सेक्शनल सर्वे डिजाइन (Cross Sectional Survey Design) को अपनाते हुए समूह तुलना तकनीक (Group Comparison Technique) का प्रयोग किया गया।

#### अध्ययन चर (Variables)

1. लिंग- छात्र एवं छात्राएं
2. शैक्षिक आकांक्षा स्तर
3. शैक्षिक स्तर- उच्च माध्यमिक स्तर

**जनसंख्या एवं नमूना (Population & Sample)** – इस अध्ययन में जनसंख्या के रूप में चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) जिले में स्थित उन सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है, जो राजस्थान बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त हैं और जिनमें कक्षा 11 एवं 12 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

नमूने के रूप में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग के 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया। विद्यार्थियों के चयन हेतु बहुस्तरीय यादृच्छिक नमूना चयन विधि (Multi Stage Random Sampling Method) का प्रयोग किया गया।

क्र.	विद्यालय का नाम	लिंग		कुल विद्यार्थी
		छात्र	छात्राएं	
1	शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़	10	10	20
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निंबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	10	10	20
3	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राश्मी, चित्तौड़गढ़	10	10	20
4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेगु, चित्तौड़गढ़	10	10	20
5	राजकीय महाराणा सीनियर सैकंडरी स्कूल, कपासन, चित्तौड़गढ़	10	10	20
6	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूपालसागर, चित्तौड़गढ़	10	10	20

**अध्ययन उपकरण:** इस अध्ययन में उपकरण के रूप में डॉ. वी.पी. शर्मा एवं डॉ. अनुराधा गुप्ता द्वारा विकसित शैक्षिक आकांक्षा मापनी (Educational Aspiration Scale & Inventory & EAS&SG) का

उपयोग किया गया है।

**सांख्यिकीय विधियां:** इस अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) तथा प्राचल सांख्यिकी (Parametric Statistics) तकनीकों का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण एवं परिकल्पनाओं के जांच हेतु निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

माध्यमान (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation & SD), क्रांतिक अनुपात (Critical Ratio & CR), सार्थकता स्तर (Significance Level & SL)

**प्रदत्त विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण:-** प्राप्त आंकड़ों को संकलित करने एवं सारणीयन के पश्चात कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य विविध प्रकार की सांख्यिकीय गणनाओं द्वारा निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

**अध्ययन परिणाम एवं व्याख्या:**

**माध्यमान के आधार पर-** गणना के अनुसार, छात्रों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का माध्यमान 36.5 है, जबकि छात्राओं का शैक्षिक आकांक्षा स्तर का माध्यमान 39.3 है। इस गणना से स्पष्ट होता है कि छात्राओं की शैक्षणिक अभिलाषा का स्तर छात्रों की अपेक्षा 2.8 अंक अधिक है। यह अंतर दर्शाता है कि छात्राओं का शैक्षिक आकांक्षा स्तर अपेक्षाकृत उच्च है।

**प्रमाणित विचलन के आधार पर -** गणना के अनुसार, छात्रों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का मानक विचलन 15.2 है, जबकि छात्राओं का मानक विचलन 14.1 है। इस अंतर के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छात्रों का मानक विचलन छात्राओं की तुलना में 1.10 अधिक है। इसका अर्थ यह है कि छात्रों के शैक्षिक अभिलाषा स्तर में विविधता का स्तर अधिक है, भले ही उनका औसत आकांक्षा स्तर छात्राओं की तुलना में कम हो।

**क्रांतिक अनुपात के आधार पर-** गणना में प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 0.63 है, जो कि 0.05 स्तर (1.98) एवं 0.01 स्तर (2.62) पर निर्धारित मानक मूल्यों से काफी कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त मान दोनों ही स्तरों पर असार्थक है। फलस्वरूप, यह परिकल्पना स्वीकार होती है कि विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक अभिलाषा स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं का शैक्षिक आकांक्षा स्तर समान है, एवं इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

**अध्ययन निष्कर्ष:**

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर पर पढ़ रहे विज्ञान समूह की छात्राओं का शैक्षिक अभिलाषा स्तर छात्रों की तुलना में आंशिक रूप से अधिक है।
2. विज्ञान वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक आकांक्षा स्तर में छात्राओं की अपेक्षा विविधता का स्तर अधिक है।
3. विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अर्थात् शैक्षिक अभिलाषा स्तर का संबंध व्यक्ति के लिंग से नहीं होता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. शर्मा, आर.ए. (2009), शैक्षिक अनुसंधान, लाल बुक डिपो मेरठ।
2. गुप्ता, ए.पी. (2009), सांख्यिकीय विधियां, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
3. जायसवाल, सीताराम (2008), भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, विद्या प्रकाशक लखनऊ।
4. पाण्डेय, के.पी. (2012), शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
5. गौतम, अमित, चन्देल, एन.पी.एस. (2016), उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा।
6. अग्रवाल, जे.सी. (2010), शैक्षिक मनोविज्ञान, विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
7. मिश्रा, आर.सी. (2011), शैक्षिक अनुसंधान के सिद्धांत, विनय पब्लिकेशन मेरठ।
8. सक्सेना, एन.आर. (2013), शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, आर.लाल बुक डिपो मेरठ।
9. पाठक, रमेश (2015), शैक्षिक आकांक्षाएं एवं उपलब्धि, ज्ञानदीप प्रकाशन इलाहाबाद।
10. त्रिपाठी, एस.के. (2018), शिक्षा एवं समाजशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
11. मिश्रा, आर.के. (2017). शैक्षिक आकांक्षाएं और मानसिक विकास, ज्ञानदीप प्रकाशन, वाराणसी।
12. कुमार, संजय (2015). शैक्षिक मनोविज्ञान, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

प्रयोज्य प्रकृति	प्रयोज्य संख्या	माध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	स्वतंत्रता स्तर	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर	परिणाम
छात्र	60	36.5	15.2	3.10	118	0.63	0.05 असार्थक	स्वीकृति
छात्रा	60	39.3	14.1				0.01 असार्थक	

\*\*\*\*\*

## छठी शताब्दी ईसापूर्व में पर्यावरण चेतना का विकास

डॉ. नीलम सोनी\*

\* असि. प्रोफेसर, रामसहाय राजकीय महाविद्यालय, शिवराजपुर, कानपुर (उ.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानव एवं पर्यावरण का गहरा संबंध रहा है। पर्यावरण के प्रति सभी धर्मों का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है, भारतीय संस्कृति ने पर्यावरण को हमेशा से ही पूजनीय माना है। सिन्धु घाटी सभ्यता से हमें अंशुख्य ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें मानव के द्वारा, नीम, तुलसी, पीपल, बरगद, आदि अनेक वृक्षों को पूजने की परंपरा विद्यमान थी जो आज तक चली आ रही है प्रवृत्ति के प्रति यह आस्था हमें पर्यावरण के प्रति सुरक्षा की भावना को जन्म देती है अगर हम पूर्व समय में मुड़कर देखेंगे तो हम यह पायेंगे कि प्रकृति ने सिर्फ हमें साफ-स्वच्छ वातावरण दिया है जिसमें मानव ने अपना शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर जीवन को सफल बनाया है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय का मानव पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक था। सिन्धु घाटी की सभ्यता में अनेक वृक्षों की पूजा की जाती थी कहीं न कहीं मानव की यह आस्था मानव एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम के दर्शाती है। इसी तरह का प्रकृति प्रेम हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलता है हमारे महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत में भी मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन हमें अनेक साहित्यिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्री राम के द्वारा 14 वर्ष के वनवास का समय जो उन्होंने वनों में बिताया था अनेक साहित्यिक ग्रंथों में उनका सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में भी हमें अनेक मनोरम दृश्यों का उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त होता है।

जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी पर्यावरण संरक्षण पर अत्यधिक महत्व दिया गया है दोनों ही धर्मों का मुख्य उद्देश्य था कि हम कार्यों को इस तरह से करें ताकि पर्यावरण को किसी तरह की हानि न पहुंचे क्योंकि मानव की हर गतिविधि पर्यावरण के अंतर्गत ही होती है हर इक सांस पर्यावरण पर ही निर्भर है हमारा यह दायित्व है कि हम पर्यावरण को असंतुलित होने से बचायें क्योंकि जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक हमारा जीवन भी सुरक्षित है अगर पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जायेगा तो मानव जीवन की गतिविधियाँ प्रभावित होगी। जिससे वह अपने जीवन को की प्रभावित करेगा।

पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है ताकि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुन्दर स्वच्छ पर्यावरण उपहार स्वरूप दें। हमारे ऋषि, मुनियों ने भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति पर्यावरण की गोद में ही प्राप्त की हमारे मनीषियों ने चिन्तन एवं मनन स्वच्छ वातावरण में किया। उनके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में उनका चिंतन समग्र भारतीय

वाङ्मय में परिलक्षित होता है

प्राचीन भारतीय वाङ्मय के प्रथम सोपान ऋग्वेद के प्रथम उद्गाता ऋषि ने अग्नि में स्थित उर्जा और जीवन की पहचान कर सर्वप्रथम उसे स्तुत्य माना

**अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विवजम् ।  
होतारं रत्नघातमम् ॥**

अर्थात् सर्वप्रथम आधान किये जाने वाले यज्ञ को प्रकाशित करने वाले ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाले (देवताओं) का आह्वान करने वाले तथा धन प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। ऋग्वेद संहिता में इन्द्र, वरुण, पर्जन्य, सूर्य आदि सभी प्राकृतिक तत्वों में देवत्व का आधान किया गया है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति से प्रेम करने की विशेष परंपरा रही है आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व पर्यावरण के प्रति बुद्ध का लगाव देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनुष्य के कृत जानने में सक्षम थे इसलिये उन्होंने न सिर्फ खुद प्रकृति से प्रेम किया वरन् संघ के भिक्षुओं को विशेष निर्देश दिये कि उनके किसी भी कार्य से पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म जैसे वातावरण में होता है वह जीवन पर उसी वातावरण को पसन्द करता है। चाहे गौतम बुद्ध का जन्म हो या सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया और उसके बाद का उपदेशक जीवन या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति सभी प्रकृति के सौम्य घटा में घटित हुई। यही कारण है कि बौद्धधर्म के विकास में कृषि, वन, वृक्ष, और पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बुद्ध के उपदेशों में भी कृषि, वन और वृक्ष इत्यादि उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध शिक्षण में पेड़-पौधों, मानव, पशु-पक्षियों और प्रकृति से एकदम निकट का रिश्ता स्थापित किया गया है जिसमें सदस्य या अदृश्य सभी प्रकार के जीव जंतुओं के कल्याण के लिये सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में भी पर्यावरण से संबंधित उपदेश दिये गये हैं। विनय पिटक जिसे बौद्ध धर्म की आचार संहिता कहा जाता है पर्यावरण को संतुलित बने रहने के उद्देश्य से पेड़ काटने से विरत का उपदेश दिया गया है अगर कोई भिक्षु किसी तरह का पेड़ काटता है तो उसे पाराजिक नामक अपराध में रखा जाता है। इतना ही नहीं बौद्ध परंपरा में बारिश के मौसम में तीन महीने वर्षावास का विधान है जिसमें किसी भी भिक्षु को बाहर निकलने से मना किया गया है ता कि नये पौधों, हरे तृणों का मर्दन न हो तथा एक इन्द्रिय वाले जीव वनस्पति को पीड़ा न पहुँचे। बौद्धधर्म का मत है कि सभी जीव-जंतुओं, वनस्पतियों व मनुष्यों का जीवन एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए व्यक्ति को सभी जीवों का सम्मान

करना चाहिये। बौद्ध परम्परा अपने समस्त ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों सहित प्राकृतिक विश्व के साथ अपने अंतर को जोड़ने के लिये प्रोत्साहित करती है वयो कि बौद्ध दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु का भिन्न अस्तित्व नहीं है। पर्यावरण की अशुद्धता मन को प्रभावित करती है और मन की अशुद्धता पर्यावरण को दूषित करती हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिये हमे अपने मन को शुद्ध करना होगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया उन्होंने जल संरक्षण के उपाय किये और भिक्षुओं को जल संसाधनों को दूषित करने से रोका भगवान बुद्ध के उपदेशों में प्रकृति वन वृक्ष और समस्त जीवों का कल्याण महान भूमिका निभाते है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हुए, बुद्ध की विचारधारा में उनके उपदेशों में तथा संदेशों में वृक्षों के प्रति प्रेम तथा अन्य प्राणियों के प्रति असीम अनुराग परिलक्षित होता है इसी, अनुराग में बौद्ध दर्शन का पर्यावरणीय में नैतिकता के तत्व अन्तर्निहित है। महात्मा बुद्ध ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व पथ प्रशस्त कर दिया था, नियम बना दिये थे इन नियमों का सिर्फ उन्होंने स्वयं अनुपालन किया बल्कि भिक्षुओं नागरिकों और श्रेष्ठ जनों को भी इसे अपनाने के लिये प्रेरित किया। गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने को प्रकृति मय कर लिया, प्रकृति की गोद लुंबिनी वन में जन्म लिया बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया।

मृगो से पूर्ण हरे-भरे वन ऋषिपत्तनम, मृगदाय, सारनाथ में धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और प्रकृति की गोद में साल वृक्षों के नीचे कुशीनगर में शरीर त्याग दिया। गौतम बुद्ध जीवन भर के स्वयं भिक्षुओं के साथ आम्रवन, वेणुवन, सिसिपावन, न्यग्रोधवन, जम्बुवन लटिठकावन आदि में रहे। उन्होंने सम्पूर्ण उपदेशों के लगभग दो तिहाई उपदेश श्रावस्ती के जेतवनराम और पूर्वराम बिहार में ही दिये। पालि त्रिपिटक में कहा गया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगुत्तर निकाय के अनुसार बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक वन क्षेत्र वन्य जीवों का घर है जब कोई भिक्षु वन क्षेत्र में निवास करे तो उसे उन जीव-जन्तुओं की सुरक्षा करना चाहिये बौद्ध धर्म का प्रथम नीतिगत वचन अहिंसा है बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति जीव हिंसा कर जीवन यापन करता है उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बौद्ध ग्रन्थ संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाने, पुल बंधवाने कुएँ खुदवाने, प्याऊ चलवाने आदि को महान पुण्य कार्य बताया गया है। जिसके बल पर मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में भी पर्यावरण से संबंधित बहुत से उपदेश प्राप्त होते हैं। विनयपिटक जिसे बौद्ध धर्म की 'आचार संहिता' कहा जाता है में बौद्ध संघ और भिक्षु भिक्षुणियों के आचार नियम के साथ ऐसी विभिन्न बातों का वर्णन है जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है। विनयपिटक में वातावरण को संतुलित बने रहने के उद्देश्य से पेड़ न काटने का उपदेश दिया गया गया है, इसके साथ ही भिक्षु पतिमोक्ख में प्राकृतिक तत्वों की सुरक्षा की भावना के कुछ नियम बताये गये है।

महावीर स्वामी ने भी पर्यावरण सुरक्षा से सम्बंधित अनेक उपदेश दिये हैं। उनका मानना था कि किसी भी जीवित प्राणी को मारना या चोट पहुंचाना स्वयं को मारने या चोट पहुंचाने के समान है दूसरों की करुणा स्वयं के प्रति करुणा है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग सभी धर्मों के साथ-साथ हैं कि साथ प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संबंधी निहितार्थों की एक अंतर्निहित प्रकृति है, जो प्रकृति और उसकी रचनाओं के प्रति आचरण का

पालन करना था। जैन धर्म मूल रूप से पाँच सिद्धान्तों पर आधारित है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रम्हचर्य इन्हीं मार्गों पर चलकर भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सकती है। जैन धर्म से सम्बंधित साहित्य में न केवल जीव जन्तु वरन् पेड़ पौधों पर दया करने का उपदेश दिया गया है उनका मानना था कि उपभोग से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं जो आगे चलकर जलवायु और प्रकृति के प्रदूषित होने का कारण बनते हैं जैन धर्म अपने जीवन जीने के निर्धारित तरीकों के माध्यम से पर्यावरण की बहुत रक्षा करता है जैन धर्म के सिद्धान्तों में अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पौधों, सच्चिज्यों, फलों और अनाजों की तुलना में कीड़े और जानवर अधिक विकसित माने जाते हैं इसलिए इस धर्म में अन्य सभी जीवित प्राणियों के लिये खाद्य श्रंखला को बरकरार रखते हुए शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धान्त बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय तक ही सीमित न होकर उससे कहीं अधिक बढ़कर सर्वजीव हिताय और सर्वजीव सुखाय तक है सम्पूर्ण जैन साहित्य में पर्यावरण के विषय में सूक्ष्म चिन्तन वर्णित है। जैन धर्म का चिन्तन मौलिक सिद्धान्तों से अनुप्राणित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को पर्यावरण के प्रथम सवांहक पुरुष माने जाते हैं भगवान ऋषभदेव ने असि, मसि, कृषि वाणिज्य और कला का सिद्धान्त दिया उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति में जीव की अवधारणा का सिद्धान्त प्रतिपादित किया साथ ही पर्यावरण का दायरा असीमित कर दिया। जैन धर्म समस्त जीवों के अस्तित्व एवं विकास में आस्था रखता है। जैन ग्रन्थों में पर्यावरण संरक्षण के लिये मानव चेतना को जाग्रत करना आवश्यक बताया गया है। अगर मानव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जाग्रत है तो वह कभी भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा बल्कि सर्वाधिक विकास के बारे में सोचेगा। जैन साहित्य के अनुसार, जनजागरण के द्वारा जो भी जैन सिद्धान्तों को जीवन में अपनाते हुये सभी जीवों को समान माना गया है एवं उनके प्रति मैत्री भाव का विचार रखा गया है अगर हम उनके प्रति हिंसा की नीति को अपनायेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होगा। महावीर स्वामी ने जिओ और जीने दो का सिद्धान्त दिया था। जैन साहित्य ग्रन्थ आचारांग सूत्र में षटकाय जीव निकाय के संरक्षण की बात प्रमुखता से की गयी है। जैन धर्म में श्रमणाचार एवं श्रावकाचार की वैज्ञानिकता को पर्यावरण के सन्दर्भ में प्रतिष्ठित किया गया है। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रम्हचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय हैं। जिनमें अहिंसा को पर्यावरण संरक्षण में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म एवं दर्शन पर्यावरण चेतना व पर्यावरण संरक्षण के चिंतन को संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति लगाव एवं संरक्षण की बात सभी धर्मों में की गई है। पर्यावरण पर धर्म का प्रभाव हमेशा ही रहा था कहीं न कहीं धर्म से जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण था। वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति मानवों के लापरवाही के परिणाम स्वरूप में अंसतुलन की स्थिति बढ़ती जा रही है। अगर हम अभी नहीं चेतें तो इसका परिणाम घातक जायेगा हमारा ये दायित्व होना चाहिये कि हम पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे तथा दूसरों को भी जागरूक करें तभी हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुन्दर पर्यावरण उपलब्ध हो सकें।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. निरंजना श्वेतकेतु बोरा-बौद्ध और जैन दर्शन के विविध आयाम प्रकाशक, निरंजना वोरा 2010, कृष्णा ग्राफिक्स, नारणपुरा जूना

- गाँव अहमदाबाद
2. प्रेम सुमन जैन-जैन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण, प्रकाशक साहित्य निकेतन जयपुर, मुद्रण, 2022
3. डॉ. शिवप्रसाद-जैन धर्म और पर्यावरण संरक्षण, पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, 2003
4. Bhage Handra Jain Bhaskar-जैन धर्म और पर्यावरण प्रकाशक New Bhartiya Book corporation Edition-2019
5. हरिवंश पुराण सर्ग 18/55
6. Ignited.in
7. Encyclopedia of Jainism
8. <https://www.pmindia.gov.in> 7 संघ
9. गीतांजली कुमारी-धम्मपद में पर्यावरणीय संरक्षण का विश्लेषण, 2019 Jetir March 2019, Volume 6, Issue 3
10. डॉ0 ध्रुव कुमार-बौद्ध धर्म और पर्यावरण (Mediamorcha.com)
- प्रभात प्रकाशन
11. Law Bhoomi
12. भारत आर्य-पर्यावरण संरक्षण में बौद्ध दर्शन का योगदान (Introduction Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol 4: ISsue 6 : June 2017
13. डॉ0 शबीना बेगम-बौद्ध धर्म में पारिस्थिकी चेतना-प्रवीन मिश्रा
14. पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत जैन दर्शन में daylife.page (प्रो0 डॉ0 सोहन राज तातेड़)
15. Jainavenue-<https://jainavenue.org>>Jainism and.....
16. डॉ0 रेनु जैन-जैन धर्म में पर्यावरण संरक्षण (शोध मंथन) तश्रि. दखत चजखख 2023
17. Igneted minds journals (<https://ignetted.in>>)
18. नीतू कुमारी-जैन आगम साहित्य के पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण (शोधपत्र) Vol-7 Issues-4 December 2019.

\*\*\*\*\*

## पृथ्वी पर जलीय चक्र एवं जल चक्र की क्रिया-विधि का अध्ययन

नेहा शर्मा \* डॉ. राजू शर्मा \*\*

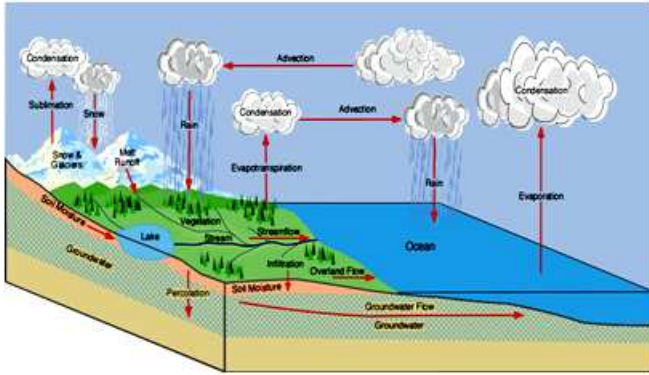
\* शोधार्थी (भूगोल) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पिलीबंगा, हनुमानगढ़ (राज.) भारत

\*\* शोध निर्देशक (भूगोल) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पिलीबंगा, हनुमानगढ़ (राज.) भारत

**शोध सारांश** – जल पृथ्वी पर एक आधारभूत संसाधन है, जो सभी प्राकृतिक संसाधनों में प्रमुख महत्ता रखता है। जल प्रकृति की रचना में सहभागी होकर सम्पूर्ण जीवमण्डल को आधार प्रदान करता है। इसका वितरण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर कई रूपों में पाया जाता है। इसका स्वरूप स्थिति एवं जलवायु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।

**पृथ्वी पर जलीय चक्र** – गैसीय अवस्था में वायुमण्डल में जलवाष्प के रूप में ठोस अवस्था में, सूक्ष्म हिम कणों के रूप में तथा द्रव अवस्था में, जलबून्दों के रूप में पाया जाता है। ये सभी दशाएँ तापमान में परिवर्तन के कारण बदलती रहती हैं तथा मौसमी प्रतिरूप को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी पर जैविक समुदाय को जल की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह जल संतुलित गुणवत्तायुक्त होना चाहिए मुख्यतः नदियों, झीलों तथा भूमिगत जलभर्ती से प्राप्त होता है। सागरीय जल लवणीय होने के कारण मानवीय उपयोग के लिए नहीं है। स्वच्छ जल का अधिकांश भाग हिम के रूप में जमा है, जो मानवीय पहुँच से काफी दूर है तथा उसका यथासम्भव उपयोग भी सम्भव नहीं है।

### जल चक्र प्रक्रिया



जलीय चक्र में जुल की जलमण्डल, वायुमण्डल तथा स्थलमण्डल पर नियमित चक्रीय व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। जल सागर, झील, नदियों, स्थल भाग (मृदा नमी) पौधे आदि से वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमण्डल में पहुँचता है तथा वहाँ बदलती मौसमी दिशाओं के अन्तर्गत संघनन द्वारा बादल बनकर यह राशि पुनः वर्षा के रूप में जलमण्डल तथा स्थल मण्डल पर पहुँचती है। जल की विभिन्न रूपों में सम्पन्न होने वाली यह चक्रीय व्यवस्था 'जलीय चक्र' कहलाती है।

जल चक्र में जल का परिसंचरण विभिन्न परिमण्डलों में भी स्वतन्त्र रूप में होता है। इसके अन्तर्गत वायुमण्डल में वायु का उर्ध्वार तथा क्षैतिज

परिसंचरण एक से दूसरे स्थान पर नमी का स्थानान्तरण जल मण्डल में सागरीय धाराओं द्वारा जल संचलन तथा स्थलमण्डल से नदियों एवं हिमनद द्वारा जल सागरों की ओर जाता है। इसी प्रकार मृदा के वाष्पीकृत एवं पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जित जल स्थल से अन्तःस्पन्दन द्वारा भूमि में पहुँचता है।

**जल चक्र की क्रिया-विधि** : पृथ्वी पर संचालित होने वाले जल चक्र के मध्य अनेक ऐसे अभिकरण होते हैं जो इसकी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। नमी की अवस्था तथा अवस्थिति में निरन्तर सम्बन्धित परिवर्तन होते रहते हैं तथा जो नमी वायुमण्डल को प्राप्त होती है वह जल, ओस हिम, पाले आदि किसी भी रूप में धरातल या समुद्रों को पुनः प्राप्त हो सकती है। अतः अवस्था एवं अवस्थिति में होने वाले इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जलीय चक्र की प्रक्रिया में बाधाएँ आती हैं।

सूर्य से प्राप्त ऊर्जा (तापमान) के कारण महासागरों का जल जलवाष्प का रूप धारण कर वायुमण्डल में प्रवेश करता है। महासागरों में स्थल की ओर चलने वाली पवन इस जलवाष्प को गति देती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करती हैं। इसके उपरान्त जलवाष्प का जब संघनन होता है, तो भूसतह पर वर्षा होती है तथा वर्षा से धरातल को प्राप्त होने वाला यह जल नदी नालों के रूप में पृष्ठ पर बहता है और अन्त में महासागरों में प्रवेश कर जाता है। सौर ऊर्जा से यह जलचक्र गति करता है।

इस प्रकार वर्षा से प्राप्त इस जल का कुछ भाग वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने से विनाश हो जाता है तथा कुछ जल नदियों, तालाबों, झीलों आदि से वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमण्डल में पहुँच जाता है। धरातल पर होने वाली जलवर्षा के कुछ भाग का भूसतह से नीचे अन्तःस्पन्दन हो जाता है। मृदा में इस जल भण्डार को 'मृदा जल भण्डार' कहते हैं। जिसका पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा विनाश होता रहता है। कुछ जल स्रोतों के जल पुनः धरातल पर आ जाता है तथा मृदा जल भण्डार से कुछ भाग नीचे की ओर संचरित हो जाता है। धरातल के नीचे संग्रहीत इस जलीय भाग को 'भूमिगत जल' कहते हैं। इस प्रकार विश्व स्तरीय जल चक्र में निम्न क्रिया विधियाँ महत्वपूर्ण हैं –

**वाष्पीकरण** : वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप दृष्टिगत जल अदृश्य वाष्प में बदल जाता है। सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर स्थित जल के जलवाष्प में

परिणत होने की प्रक्रिया को 'वाष्पीकरण' कहते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा महासागरीय जल वायुमण्डल में पहुँचता है। महासागरों से जल का वाष्पीकरण महाद्वीपों से अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण जल की पर्याप्त उपलब्धता होना है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में लोगों को लगभग 12500 वर्ष पूर्व मालूम था यूनानी विद्वानों ने वाष्पीकरण द्वारा जल स्रोत से जल के हास के बारे में विवरण दिये हैं, लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया विधि के बारे में व्यवस्थित जानकारी विगत दशकों से मिलने लगी है।

**वाष्पीकरण की प्रक्रिया :** वर्तमान में यह स्पष्ट हो चुका है कि वाष्पीकरण द्वारा किसी जलीय सतह का रूपान्तरण गैसीय आवरण में हो जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ही तरल को वाष्प में बदलती है जो 100°C पर प्रतिग्राम लगभग 539 कैलोरी होती है। गुप्त ऊष्मा की तापीय ऊर्जा तीव्र गति करते हुए कणों से गतिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी तरल अवस्था का वाष्पीकरण होता है तो वाष्प के उपरान्त तरल की ताप ऊर्जा कम हो जाती है। इसका उदाहरण, बौछारों के रूप में गिरने वाला जल है तथा स्नान के दौरान जल का वाष्पीकरण होने से शरीर के तापमान पर पड़ने वाला ऋणात्मक प्रभाव है।

**वाष्पोत्सर्जन :** वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़-पौधे अपनी जड़ों से नमी को अवशोषित करके पत्तियों द्वारा पुनः जल को वायुमण्डल में निर्मुक्त कर देते हैं। यह क्रिया पत्तियों में स्थित रन्ध्रों द्वारा सम्पादित होती है। इस प्रक्रिया में भूजल की काफी मात्रा में हानि होती है। इस माध्यम से जल की हानि मुख्य रूप से दिन में होती है। विभिन्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। जल चक्र की क्रियाविधि में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा कम पाये जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जबकि सघन वनस्पति आवरण वाले क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन तीव्र होने पर जलीय चक्र की क्रिया विधि भी तीव्र रहती है। जलीय चक्र की इस क्रिया विधि का भूजल की मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मृदा का गठन एवं संरचना भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ों को प्राप्त होने वाला जल अन्तःस्पन्दन द्वारा भूमि के अन्दर पहुँचता है। यह जल मृदा गठन की प्रकृति आधार पर ही स्पन्दित होता है।

**वर्षा :** किसी स्थान विशेष की वर्षा की दर को 'वर्षा की तीव्रता' कहते हैं अर्थात् किसी स्थान विशेष में वर्षा प्रतिदिन एवं प्रति घण्टे की दर से हो रही है। जिन स्थानों पर वर्षा की हवाएं सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं वहाँ वर्षा अधिक तीव्र होने की संभावना रहती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है, जबकि कभी-कभी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बहुत तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा से लाभ कम तथा हानि अधिक होती है। तीव्र वर्षा से प्राप्त जल का उसी गति से अन्तःस्पन्दन नहीं हो पाता है जिससे भूमिगत जलीय चक्र प्रभावित होता है। वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर ही उस क्षेत्र में वनस्पति तथा फसलों का विकास होता है।

वर्षा की मात्रा के साथ-साथ वर्षा के दिनों की संख्या भी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी स्थान पर प्राप्त होने वाली कुल वर्षा वर्ष के अधिकांश

दिनों में वितरित है तो जलीय चक्र के संतुलित होने के लिए आवश्यक है। कम वर्षा के कारण सूखा पड़ता है अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। इस प्रकार वर्षा के स्वभाव जलीय चक्र को क्रिया विधि को प्रभावित करता है। वर्षा के साथ ही हिमदृष्टि, ओस, तोषार, आदि भी जल को नियन्त्रित करते हैं। वर्षा की मात्रा के साथ धरातलीय उच्चावच का भी सामंजस्य होता है। वर्षा का स्वभाव तीव्र हो या ढीला, भूसतह का ढाल उसके प्रवाह, अन्तःस्पन्दन तथा वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं।

**अन्तःस्पन्दन :** वर्षा का पानी जैसे भूसतह पर पहुँचता है, उसके एक भाग को भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। पानी के अन्तःस्पन्दन की दर मृदा के संगठन तथा सुरचना से प्रभावित होती है। भूमि के जल को सोखने की क्रिया को 'अन्तःस्पन्दन' कहते हैं। वर्षा से प्राप्त जल का कुछ भाग ढाल के अनुसार प्रवाहित होता है। उसे 'सतही प्रवाह' कहते हैं। मृदा की प्रकृति अन्तःस्पन्दन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चिकनी मृदा में अन्तःस्पन्दन की दर न्यून होती है, जबकि बलुई मृदा में तीव्र होती है। वर्षा जल अन्तःस्पन्दन द्वारा भूमि रन्ध्रों में पहुँचकर भूमिगत जल के रूप में विद्यमान रहता है। मृदा रन्ध्रों में सामान्य रूप से वायु विद्यमान रहती है। जैसे-जैसे धरातलीय जल भूमि के अन्दर प्रवेश करता है तो इस वायु का स्थान ले लेता है। इस प्रकार वायु की मात्रा कम होने व पानी की मात्रा बढ़ने की स्थिति को 'जलाकान्त स्थिति' कहते हैं। यह भूमि की संतृप्त अवस्था होती है अर्थात् इस सीमा के बाद भूमिगत जल को धारण नहीं करती है।

**प्रकृति में जलीय-चक्र की महत्ता:** पृथ्वी पर जलीय चक्र विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलीय संचार के बिना जल संतुलन बिगड़ जायेगा और किसी भी तरह का जीवन असम्भव हो जायेगा। जल का वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमण्डल में जमा होना अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस पर मौसम परिवर्तन निर्भर करता है। पृथ्वी पर वर्षा की क्रियाशीलता जल चक्र द्वारा ही पूर्ण होती है। पृथ्वी पर विभिन्न जैव रसायन चक्रों द्वारा ही पूर्ण होती है। पृथ्वी पर विभिन्न जैव भूरसायन चक्रों के अन्तर्गत अवसादों एवं रासायनिक तत्त्वों के संचरण में वनस्पति प्रभावी माध्यम होती है। इस प्रकार जीवमण्डल में ये जैव भूरासायनिक चक्र जल के संचरण द्वारा ही सम्भव होते हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. Compiled from Tahal Report on Water Resource Planning for the State of Rajasthan : Shekhawati River Basin, 1998, Government of Rajasthan and CGWB, Western Circle, Jaipur, 2005
2. Dynamic Ground water Resource Assessment of India
3. Ground Water Year book Rajasthan (2020-21)
4. Ground Water Year book Rajasthan (2020-21)
5. Report on ground water level Scenario of Rajasthan Year 2020.
6. Source - Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York).

\*\*\*\*\*



## लिंगीय असमानता और चुनौतियां

डॉ. पिकी सोमकुवर\*

\* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – लैंगिक असमानता एक सामाजिक धारणा है। स्त्री और पुरुष एक जैविक तथ्य है यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जुड़ जाती है तो यह एक लैंगिक असमानता का रूप ले लेती है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है। प्रकृति में किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग आधारित नहीं होता है। परंतु फिर भी समाज में महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव होता है—जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा तथा रोजगार आदि। लिंग असमानता की वजह से महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, अवसरों की असमानता आदि का सामना करना पड़ता है। और जब यह महिलाएं निम्न जाति से आती हैं तो उनका शोषण और बढ़ जाता है। अधिकांश धार्मिक कृत्य महिलाओं के हिस्से में आते हैं परंतु जहां संस्कारों की बात हो तो उच्च जातियों में पुरुषों का तो उपनयन संस्कार होता है परंतु महिलाओं का नहीं। आज भी किसी मृत व्यक्ति को अग्नि देने का काम अधिकांशतः पुरुष ही करते हैं बहुत कम मामलों में महिलाओं को इस प्रकार के संस्कार करते हुए देखा जाता है। महिलाओं का समाजिकरण इस प्रकार होता है कि सारे व्रत की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है चाहे वह पति के लिए हो या पुत्र के लिए। देवदासी, नगरवधू इस प्रकार की प्रथाएं भी महिलाओं को धर्म के माध्यम से समाज द्वारा ही दी जाती थी। लैंगिक असमानता हमें मॉडर्न कल्चर लिव इन रिलेशनशिप में भी देखने के लिए मिलती है। श्रद्धा वालकर, निकी यादव यह हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पुरुष का चुनाव आप अपनी मर्जी से करें या परिवार की मर्जी से हो आपको हिंसा का सामना इसमें भी करना पड़ सकता है।

**शब्द कुंजी** – लिंग असमानता, समानता, अवसर, शिक्षा, शोषण, सामाजिकरण।

**प्रस्तावना** – लैंगिक असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर भेदभाव से है परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। महिलाएं घर समाज तथा कार्यस्थल पर शोषण अपमान और सबसे महत्वपूर्ण कदम कदम पर भेदभाव से ग्रसित होती हैं। महिलाओं की यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विकसित देशों में भी है। स्त्री और पुरुष एक जैविक तथ्य है यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जुड़ जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बनकर लैंगिक असमानता बन जाती है। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम ना होकर सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित है इसे बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिकरण की होती है। क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है इसलिए महिलाएं क्या करेगी और क्या नहीं करेगी इसका नियंत्रण भी काफी हद तक पुरुषों के हाथों में था। समाज में पुरुष और स्त्री के लिए अलग-अलग व्यवहार की व्यवस्था थी परंतु वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है लेकिन समानता अभी भी दूर है।

सिमोन दी बुआ के अनुसार महिलाओं की बराबरी की बात करते समय हमें उनके जैविक अंतर की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 'औरत पैदा नहीं होती है बल्कि समाज औरत को गढ़ता है।' वह बार-बार इस बात पर जोर देती है कि हमारा धर्म हमारी संस्कृति हमारा समाज लड़कियों को मजबूर करता है स्त्री बनने के लिए। सिमोन के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म में महिलाओं की पूजा भी होती है। धर्म तो वास्तव में पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है औरतों पर शासन करने का।

नीरा देसाई का मानना है कि हमारा सरोकार केवल सामाजिक घटनाओं से अध्ययन से नहीं है। बल्कि हम कानून की संरचना और महिला मुक्ति के रास्ते में आने वाली हर चीज को बदलना चाहते हैं। ऐसा करने में हम अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हिंसक संघर्ष में आ जाते हैं जो मूल्य तथा परंपरा की वकालत करते हैं।

बीना मजूमदार के अनुसार जब वह 1975 में प्रकाशित समानता रिपोर्ट की मसौदा समिति का हिस्सा थी तब वह और उनके सहयोगी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक सामूहिक चेतना बनाने की आवश्यकता पर निर्भर थे। अपनी मध्यमवर्गीय स्थिति और बेहतर शैक्षिक अवसरों के संपर्क के कारण, उन्होंने यह महसूस किया कि, भारत में गरीब वंचित महिलाओं के जीवन के अनुभव के बारे में जागरूकता के लिए कोई चेतना नहीं थी। उन्हें और उनके सहयोगियों को एहसास हुआ की प्रतिबद्धता के लिए काम करने के माध्यम से उन्होंने जो सामूहिक चेतना पैदा की है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

**शोध पत्र के उद्देश्य :**

1. ऐतिहासिक परिदृश्य में लिंग असमानता को समझना।
2. डॉ. बी आर अंबेडकर के महिलाओं संबंधी विचार को समझना।
3. हमारी धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार लिंग असमानता में भूमिका निभाती है इसका अध्ययन करना।
4. शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार लिंग असमानता को दूर किया जा सकता है का अध्ययन करना।

**शोध प्रविधि** – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया

है। अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है।

**संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन** – फ्रेंच इतिहासकार व विचारक मिशेल फूको (1980) में अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ़ सेक्सुअलिटी में ज्ञान और सत्ता के चरित्र की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह ज्ञान और सत्ता स्त्री को अनुकूलित करते हैं। उनके अनुसार शरीर एक ऑब्जेक्ट है जिसे समाज राजनीति व सत्ता अपने अनुसार बनाती व प्रशिक्षित करती है जैसे पुरुष हमेशा से समाज में अपने लिए अधिक स्पेस चाहता है। वही महिलाएं थोड़े से में ही खुद को संतुष्ट पाती हैं क्योंकि उसे ऐसी सामाजिक निर्मिति दी जाती है कि वह बड़ा न सोच सके। प्रभा खेतान (2010) के अनुसार भारतीय समाज में स्त्री अस्मिता का प्रश्न उठाती है जहां पहचान कि समस्या पुरुष के समक्ष नहीं आती उसकी पहचान स्थाई होती है स्त्री की तो पहचान ही उसकी अपनी नहीं पहले पिता, फिर पति। अगर दोनों ही ना हो यह विचारणीय प्रश्न है जेंडर के संदर्भ में समझा जाए तो स्त्री को सदा ही समाज में कमजोर व आश्रित माना गया जिसके लिए पहले पिता फिर पति के संरक्षण की व्यवस्था की गई।

डॉ. बी आर अंबेडकर (1976) के अनुसार लिंग असमानता का प्रयोग कहीं ना कहीं जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए भी किया गया है। एक आदर्श स्थिति के रूप में स्त्री रू पुरुष अनुपात बनाए रखना था इसके लिए 1. स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए 2. स्त्री को आजीवन विधवा रखा जाए जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। 3. विधुरो को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए। 4. विधुर का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य ना हो अर्थात् लड़कियों का बाल विवाह।

ऊपरी तौर पर देखने वाले व्यक्तियों को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगेगी किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करता है यह हैं:

1. शक्तियां विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना।
2. थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं है।
3. बालिका विवाह।

यदि भारतीय समाज में लिंग असमानता की ऐसी कुरीतियों का पालन हो रहा था तो इनको करने के पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या हमारे सामने नहीं है।

कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की परंतु जिसमें वैज्ञानिकता कम लिंग असमानता ज्यादा दिखाई देती है। जैसे ए के कुमार स्वामी (1913) के अनुसार सती सम्माननीय है क्योंकि यह पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की संपूर्ण एकात्मता और श्मशान से परे तक समर्पण को दर्शाती है क्योंकि इसमें पत्नीत्व को साकार रूप दिया गया है, जैसा कि उमा ने अच्छी तरह उस समय स्पष्ट किया है जब उन्होंने कहा था हे महेश्वर अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है यही उसका शाश्वत स्वर्ग है भावुकता में वह आगे कहती है मेरी धारणा है कि यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे लिए स्वर्ग की कामना करना बेकार है।

यहां पर दो बातें सामने आती हैं पहली पत्नीत्व की धारणा है तो फिर इसी प्रकार पतित्व धारणा भी होनी चाहिए थी पुरुष को भी अपनी मृत पत्नी के साथ सती होना चाहिए था। दूसरा की पत्नी का सामाजिकरण किस प्रकार से हुआ कि उसे सती होना अनिवार्य या योग्य लगने लगा।

इसी प्रकार डॉ केतकर (1907) के अनुसार वह बालिका विवाह की प्रशंसा में कहते हैं एक सच्चे आस्थावान स्त्री या पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष या स्त्री से लगाव या संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरांत बल्कि विवाह के पूर्व भी आवश्यक है क्योंकि एक अच्छे चरित्र के लिए यही सही आदर्श है। किसी अपरिणता को पवित्र नहीं माना जा सकता। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है इसलिए एक लड़की के लिए यह अच्छा होगा कि किसी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं जागृत होने से पूर्व ही उसे यह पता होना चाहिए कि उसे किससे प्रेम करना है और तभी उसका विवाह हो जाना चाहिए।

मालविका कारलेकर (1998) के अनुसार सत्ता और अधिकार के कारण सदियों से आमतौर पर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार रही हैं घरेलू शोषण को इन्होंने 5 कैटेगरी में विभाजित किया है – शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक। पत्नी को उसके ससुराल वालों और पति द्वारा कई कारणों से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है यह प्रताड़ना दहेज के लिए, घरेलू कामों के लिए या कभी-कभी केवल संतुष्टि के लिए ही हो सकती है। दुनिया भर में वर्ग, धर्म, समुदाय और भारत की जाति पृष्ठभूमि के मामलों के बावजूद पत्नी को पीटना दुर्घटन का सबसे आम रूप है।

जगन कराडे के अनुसार भारत में पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों ने महिलाओं को घर और कार्यस्थल के भीतर दोगुने दर्जे पर पहुंचा दिया है। पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार पीढ़ियों से उत्साहित है और दोनों लिंगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत के संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं लेकिन लिंग असमानता अभी भी बनी हुई है। भारत में भेदभाव का सबसे पहला और प्रमुख कारण मानसिक बनावट है। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं जहां पुरुष सभी निर्णय लेते हैं और महिलाओं को बस सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। रोटी कमाने से लेकर घर चलाने तक का फैसला सिर्फ एक आदमी ही करता है। 21वीं सदी में भी कई महिलाओं के पास अभी भी खुद से जुड़े फैसले लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। शादी से लेकर परिवार शुरू करने तक पुरुष ही हुकम चलाता है और महिलाएं उसका पालन करती हैं। शिक्षा का अभाव सभी बुराइयों का मूल कारण है इसलिए ज्योतिबा फुले, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, महर्षी धोंडो केशव कर्वे जैसे कई समाज सुधारक कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी साधन है। और ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप महर्षी करवे ने महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय शुरू किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल के रूप में एक बिल बनाया। भारतीय महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की एक लंबी परंपरा रही है उनमें से कुछ जिन्होंने बेच मार्ग बनाया है स्वर्गीय डॉ. आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर कमला सुहानी विज्ञान संकाय में पीएचडी करने वाली पहली महिला थी, राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर थी। डॉ चित्रा जयंत नाईक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाज सेविका थी। महात्मा फुले ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि बेहतर माना है। अपने सार्वजनिक जीवन में वे लिखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों मानवाधिकारों का आनंद लेने के लिए समान रूप से योग्य हैं। कृष्णाराज मैत्री के अनुसार लिंग समीकरण के दो पक्ष हैं – महिला और पुरुष। हमारा समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण निसंदेह पुरुषों

को विशेषाधिकार प्राप्त है।

लैंगिक असमानता के मुख्य कारण – निम्नलिखित है

1. पितृसत्तात्मक समाज
2. सामाजिकरण
3. घर परिवार एवं समाज का दबाव
4. मानसिकता
5. धर्म
6. वैधानिक स्तर
7. अशिक्षा
8. अंधविश्वास
9. आत्मविश्वास की कमी

### विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानता

**सामाजिक जीवन में** – परंपरागत रूप से घरेलू कार्य का तात्पर्य महिला से ही लगाया जाता है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना बच्चों के पालन पोषण तथा अतिथि सत्कार रहा है। वर्तमान समय में पुरुष और महिला दोनों ही कार्यशील होते हैं। फिर भी घर की पूरी जिम्मेदारी महिला की ही होती है। यदि पुरुष ऑफिस से आता है तो वह थका होता है परंतु यदि महिला ऑफिस से आती है तो उसकी थकान पर कोई चर्चा नहीं होती है। यदि महिला कोई भी कार्य करती है तो वह अपने पारिवारिक कार्य के अतिरिक्त कार्य होता है।

**निर्णय निर्माण क्षेत्र में** – गृहिणी होने के बावजूद घर के महत्वपूर्ण निर्णय में महिलाओं की भागीदारी सीमित होती है। घर में खाना क्या बनाया जाएगा यह निर्णय तो महिला ले सकती है परंतु किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय महिला अकेले नहीं ले सकती या उसकी भागीदारी अनिवार्य नहीं होती है। जितनी महिलाओं की आबादी है उस हिसाब से निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी कम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी महिला की निर्णय निर्माण क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं है।

**आर्थिक क्षेत्र में** – अभी भी अवसरों की असमानता कि वजह से आर्थिक क्षेत्र में महिला और पुरुष में असमानता दिखाई देती है।

**कार्यस्थल में** – सरकारी नौकरियों में समान काम समान वेतन की पॉलिसी लागू होती है परंतु ऐसे बहुत से कार्य हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है आज भी महिला मजदूर को पुरुष मजदूर से कम मजदूरी मिलती है। खेतों में भी अधिक परिश्रम वाले कार्य महिला मजदूर ही करती है जैसे धान की रोपाई। महिला मजदूर को किसी भी तरह की कोई छुटी नहीं मिलती है चाहे वह मासिक चक्र, गर्भावस्था हो, स्तनपान कराने वाली मां हो।

**धार्मिक क्षेत्र में** – हम चाहे सतत विकास के लक्ष्य में लिंग समानता को शामिल करें, महिला वर्ष मना ले, महिला दिवस मना ले, महिला दिवस पर वेबीनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कर ले परंतु वास्तविकता यही है कि आज भी विभिन्न प्रकार के मंदिरों में महिलाओं को जाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है जैसे सबरी माला मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर। आज भी मॉडर्न सोसाइटी में मंदिरों में पुजारी पुरुष ही है आज भी महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ने के बाद भी महिला शंकराचार्य के पद पर नहीं पहुंच पाई है।

**राजनीतिक क्षेत्र में** – विभिन्न राजनीतिक दल संविधान के दायरे में आते हैं संविधान से हमें समानता का अधिकार प्राप्त होता है परंतु इन्हीं राजनीतिक दलों में भी समानता दिखाई नहीं देती है आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सिर्फ एक महिला रक्षा मंत्री बनना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि देश के

महत्वपूर्ण मंत्रालय पुरुषों के पास ही रहते हैं। अधिकांश समय महिला को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया जाता है। मैं यह नहीं कहना चाह रही कि यह महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। परंतु महिला यदि घर को अच्छे से चला सकती है तो देश को भी अच्छे से चला सकती है। यदि लिंग आधारित असमानता को दरकिनार कर महिलाओं को सभी मंत्रालयों में कार्य करने के मौके मिले तो बेहतर होता। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति के समय भी महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता। यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में वर्तमान समय तक एक महिला प्रधानमंत्री दो महिला राष्ट्रपति रह चुकी है परंतु अमेरिका जैसे विकसित देश में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है।

**विज्ञान के क्षेत्र में** – विज्ञान का क्षेत्र सामने आते ही कहीं ना कहीं पर प्रगतिशील विचारधारा सामने आती है परंतु इस क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता विद्यमान है वैज्ञानिक समुदाय में नहीं लाओ की संख्या कम है और इसके साथ ही उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट पर भी लगा दिया जाता है। मुझे लगता है कि स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है हम उन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं परंतु वहीं दूसरी ओर मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को पता नहीं कितने लोग जानते हैं। एन ई पी में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इनको पढ़ाया जाना मैं समझती हूं महिला समानता की ओर यह एक कदम है। निश्चित ही यहां मोहना सिंह, भावना कंठ तथा अवनी चतुर्वेदी महिला फाइटर पायलट की उपलब्धि भी महत्वपूर्ण है।

**मनोरंजन के क्षेत्र में** – मनोरंजन के क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता दिखाई देती है। आप देखते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में एक्टर लंबे समय तक हीरो की ही भूमिका में रहता है परंतु एक्ट्रेस कुछ समय तक हीरोइन की भूमिका में रहती है फिर समय के साथ वह बहन, भाभी, बहू, सास, दादी आदि के रोल में आ जाती है। इसके अतिरिक्त महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में भी अंतर होता है इसके अतिरिक्त अधिकांश फिल्मों पुरुष प्रधान चरित्र पर आधारित होती है। हम देखते हैं कि पार्टिकुलर किसी एक एक्टर के नाम से ही फिल्म के हिट होने की गारंटी हो जाती है परंतु एक्ट्रेस के मामले में ऐसा दिखाई नहीं देता है। मनोरंजन के क्षेत्र में महिला को उसके रंग रूप से अधिक आंका जाता है और उन्हें इसी रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में ही अधिकांश टीवी शो में खलनायक के रोल में महिला को दिखाया जाता है। विज्ञानियों के माध्यम से भी महिलाओं के शारीरिक गुणों का बखान किया जाता है।

**खेल के क्षेत्र में** – खेल की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट है और हम पुरुष क्रिकेटर्स की कितनी पीढ़ियों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। वही महिला क्रिकेटर की बात करें तो मुझे लगता है कि अपने सन्यास के बाद भी मिताली राज को जानने वालों की संख्या कम ही होगी। अन्य खेलों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अहमियत दी जाती है। महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों की अपेक्षा पारिश्रमिक भी कम मिलता है। यदि कभी किसी पुरुष खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है और उसकी महिला मित्र वहां पर होती है तो भी उसके परफॉर्मेंस के लिए महिला को जिम्मेदार मान लिया जाता है।

**आंदोलनों में** – स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं का जिक्र कम ही होता है। चिपको आंदोलन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी चर्चा हुई परंतु इसमें भाग लेने वाली महिलाओं से अधिक चर्चाओं में पुरुष ही रहे।

संगठनों में – आज भी ऐसे संगठन हमारे समाज में है जिसमें महिलाओं को कोई उच्च पद प्राप्त नहीं हुए हैं।

#### लिंग असमानता को दूर करने के उपाय:

1. हमारी ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो तर्कपूर्ण नहीं है उनका त्याग करके।
2. महिलाओं को शिक्षित करके।
3. अवसरों की समानता प्रदान करके।
4. जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू करके।
5. धार्मिक कट्टरता का त्याग करके।
6. समाज में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा वर्ग का हो यदि वह किसी भी रूप से कन्यापूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, बलात्कार तथा किसी भी प्रकार के शोषण आदि जैसे कृत्यों में शामिल हो तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
7. पाठ्यक्रमों में लिंग आधारित असमानता संबंधित शिक्षा न दी जाए।
8. महिलाएं भी यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना करें।

**निष्कर्ष** – समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेडा 2030 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य पांच के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। (achieve gender equality and empower all women and girl)। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम द्वारा 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों की सूची में 135 में नंबर पर

है। इस सूची को बनाने समय 4 बैच मार्क होते हैं- 1 आर्थिक भागीदारी और अवसर 2. शिक्षा प्राप्ति 3. स्वास्थ्य और जीवन रक्षा 4. राजनीतिक अधिकारिता।

महिला और पुरुष समाज के स्तंभ है समाज में लैंगिक असमानता जानबूझकर बनाई गई थी जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो गया था परंतु अब समय और समाज दोनों ही बदल रहे हैं। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लिंग समानता को बनाना है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Ambedkar B R (1979) Cast in India : their mechanism genesis and development , writing and speeches, Education department Government of Maharashtra volume I
2. खेतान प्रभा (2010) अन्या से अनन्या, राजकमल प्रकाशन संस्करण, नई दिल्ली।
3. Beauvoir, Simone de (1971) The second sex, Oxford University press, New York.
4. Karade Jagan and Asha Suratkal (2017) “Analysis of Gender Inequality in Indian society to Pune city” scholarly research journal for humanity science and english language. Vol 4/22, page 5265. www.srjis.com
5. Karlekar Malavikar (1998) “Domestic Violence” economic and political weekly, Vol 33, no.27, page 1741
6. Rege Sharmila (1995) “Feminist pedagogy and sociology for emancipation in India” sociological bulletin, vol 44 issue 2 Sage journal

\*\*\*\*\*

## आधुनिक कृषि यंत्रीकरण में नवीन तकनीकी ज्ञान का अध्ययन मध्यप्रदेश के बड़वानी एवं धार जिले के सन्दर्भ में

श्रीमती सुमन भवर\* डॉ. नीमा चुण्डावत\*\*

\* शोधार्थी, भूपाल नोबल्स युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

\*\* शोध निर्देशिका (अर्थशास्त्र) भूपाल नोबल्स युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

**शोध सारांश** - आधुनिक कृषि यंत्रीकरण में नवीन तकनीकी ज्ञान को उर्जावान बनाने के लिये परम्परागत तकनीको एवं उपकरणों से कृषि करने के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करने से होता है। कृषि कार्यों में नयी किस्म के उन्नत बीज रासायनिक उर्वरको एवं विभिन्न किटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हुआ कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही। कृषि यंत्रीकरण का अर्थ कृषि कार्य में पशु शक्ति एवं मानव शक्ति के स्थान पर बिजली, डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाली यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। जैसे जुताई एवं बुवाई में ट्रैक्टर, सिंचाई के लिये पम्प सेट आदि सभी कार्य यंत्रों व मशीनों से जिए जाते हैं।

**शब्द कुंजी** - नई तकनीक, मशीनीकरण, उन्नत बीज और रासायनिक बीज।

**प्रस्तावना** - भारत देश कृषि प्रधान है। इसमें अन्य देशों के साथ भारत भी विकासशील देश में शामिल है। वर्तमान में देश की 139 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। देश की 69 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती हैं। जिनका जीविकोपार्जन का मुख्य संसाधन कृषि है। कृषि प्रधान देश में लगभग 60 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती है। देश में घरेलू उत्पाद के रूप में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का ही है जो लगभग उत्पादन की दृष्टि से 18-20 प्रतिशत है। आधुनिक तकनीक और यंत्र उपलब्ध होने के बाद भी छोटे किसान उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। खेती से होने वाले नुकसान के कारण किसान ऐसे दलदल में फसे हुए हैं कि वे नई तकनीकी कौशल से अभी भी परिचित नहीं हो पा रहे हैं। कृषि से संबंधित ऐसे व्यवसाय को ही सामूहिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार को ऐसे कौशल विकास तकनीकी के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। जिससे किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को वर्तमान में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।

**मध्यप्रदेश की सामान्य जानकारी** - 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश का पुराना नाम सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार था। मध्यप्रदेश के कुछ भागों में जनजातीय के लोग बहुसंख्यक हैं इसलिए इस प्रदेश को जनजाती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के कुल 10 संभाग हैं तथा कुल 55 जिले हैं और 313 तहसीलें हैं। इसी प्रकार 313 कुल विकासखण्ड हैं।

**मध्यप्रदेश में कृषि** - मध्यप्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है मध्यप्रदेश भारत के मध्य में स्थित है इसलिये मध्यप्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलो और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (20210) के अनुसार 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 होने

के साथ ही यह भारत की कुल जनसंख्या का 5.99 प्रतिशत है मध्यप्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है यहाँ राष्ट्रीय उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत सोयाबीन होता है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है यहाँ की मुख्य फसलें गेहू, चावल, मक्का और कपास है, दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्यप्रदेश का देश में पहला स्थान है। खाद्यान उत्पादन में मध्यप्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। यहाँ कई महत्वपूर्ण उद्योग भी स्थित हैं इनमें सीमेंट ईस्पात और कपड़ा उद्योग शामिल हैं।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 72.37 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जहां खेती ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। मध्यप्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 1.10 करोड़ है जिनमें कुल खेतीहर मजदूर 74 लाख हैं। मध्यप्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3.08 करोड़ वर्ग हेक्टेयर है।

मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने कई प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं जारी की हैं। जैसे - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल ऋण माफी योजना, कृषि शक्ति योजना। इन तीन योजनाओं को क्रमशः 2016, 2018 और 2019 वर्ष में अधिक बल दिया गया है। जिससे किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सके। ये सही जानकारी उन्हें समय से उपलब्ध कराई जाए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे- उन्नत बीज की उपलब्धता, भूमी सुधार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, किटनाशक दवाइयों की सहज उपलब्धता साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि ऐसे अनेक तत्व हैं जिनकी सहायता से ही कृषि विकास की दशा को उन्नत किया जा सकता है और कृषि विकास को बढ़ावा मिल सके। विभिन्न प्रकार से किसानों को खासतौर पर ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं

के माध्यम से लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक लाभकारी उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ा जा रहा है।

**अध्ययन के उद्देश्य** - प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि यंत्रिकरण में तकनीकी ज्ञान के प्रभाव को ज्ञात करना।

**शोध परिकल्पना** - मध्यप्रदेश के बड़वानी एवं धार जिले में कृषि विकास एवं तकनीकी परिवर्तनों का अंत संबंध एवं प्रभावों का विश्लेषण करने के लिये निम्न शोध परिकल्पनाएँ बनाई गई हैं।

1. अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन कार्यों के लिये नई पद्धति का ज्ञान है।

**शोधविधि** - प्रस्तुत शोध संबंधी आकड़ों का संग्रहण हेतु प्राथमिकता एवं दितयिक स्रोतों का प्रयोग किया गया है और इन्हीं स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए शोध मुख्यतः विभिन्न पुस्तकें पत्र-पत्रिकाओं शोध पत्रों समाचार पत्रों एवं भू अभिलेख, संखिकी अधिकारी, कृषि अधिकारी, आर्थिक सर्वेक्षण आदि द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित आकड़ों का उपयोग किया गया।

**तालिका संख्या 01: सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक**

सिंचाई तकनीक	जिला		कुल
	बड़वानी	धार	
ड्रिप सिंचाई	78 (97.5%)	47 (58.75%)	125 (78.12%)
पानी मोटर	80 (100%)	76 (95%)	156 (97.5%)
पंपिंग सेट	2 (2.5%)	10 (12.5%)	12 (7.5%)
नाली से, क्यारी बनाकर	3 (3.75%)	1 (1.25%)	4 (2.5%)

सर्वेक्षण से प्राप्त स्रोत

तालिका संख्या 1 में कृषि सिंचाई के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को दर्शाया गया है। तालिका देखने से ज्ञात होता है कि बड़वानी और धार जिले में कृषि सिंचाई तकनीक के रूप में सर्वाधिक पानी की मोटर का उपयोग किया जाता है यह तकनीक लगभग 97.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। ड्रिप सिंचाई तकनीक भी दोनों जिलों में लगभग 78.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। अतः दोनों जिलों में ड्रिप सिंचाई भी काफी लोकप्रिय सिंचाई तकनीक है। उसी प्रकार 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता पंपिंग सेट तथा 2.5 प्रतिशत

उत्तरदाता नालीक्यारी बनाकर सिंचाई करते हैं

**तालिका संख्या 02 : कृषि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण**

सिंचाई उपकरण	जिला		कुल
	बड़वानी	धार	
ट्रेक्टर	80 (100%)	80 (100%)	160 (100%)
हार्वेस्टर	42 (52.5%)	35 (43.75%)	77 (48.13%)
वीडकटर	40 (50%)	39 (48.75%)	79 (49.37%)
ट्रांसप्लान्ट	41 (51.25%)	38 (47.5%)	79 (49.37%)
थ्रेशर	45 (56.25%)	35 (43.75%)	80 (50%)
स्प्रेयर	34 (42.5%)	46 (57.5%)	80 (50%)

सर्वेक्षण से प्राप्त स्रोत

तालिका संख्या 02, बड़वानी और धार जिलों के उत्तरदाताओं द्वारा कृषि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। परिणाम तालिका के अनुसार, दोनों जिलों के सभी उत्तरदाताओं द्वारा अर्थात् 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कृषि के लिए ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा थ्रेशर एवं स्प्रेयर, 49.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वीडकटर एवं ट्रांसप्लान्ट तथा 48.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं द्वारा कृषि के लिए इन सभी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

**निष्कर्ष** - उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बड़वानी और धार जिले में कृषि कार्य हेतु नवीन तकनीकों का प्रभाव पड़ा जिससे लगभग आधे से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा कृषि के लिए इन सभी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

- डॉ. रीतु तिवारी (2021), भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पेज न. 106
- अनुपम गोयल (2019-20) भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.बी.डी. पब्लिकेशन आगरा-मथुरा पेज न. 146
- अर्चना यादव, (2010), कृषि विकाश में तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव पीएचडी थीसिस पेज न. 45

\*\*\*\*\*

## मुंशी प्रेमचन्द के लघु उपन्यास, निर्मला, प्रतिज्ञा का अनुशीलन

डॉ. अर्चना बापना\*

\* सहा. प्राध्यापक, एडवास महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - लघु उपन्यास साहित्य की ऐसी विधा है जो स्वरूप की दृष्टि से उपन्यास से छोटी होती है, परन्तु कथावस्तु की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है। जिसका प्रभाव वृहत् उपन्यासों के समान ही होता है। हिन्दी साहित्य जगत में भी लघु उपन्यासों से पृथक अस्तित्व के स्वीकार कर लिया गया है। लघु उपन्यास और वृहत् उपन्यास में आकार गत अन्तर प्रमुख है। साहित्य में भी इसके पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।

**डॉ. घनप्याम मधुप के अनुसार-** 'लघु उपन्यास में व्यक्ति या समाज के किसी एक कोण का गहन एवं सूक्ष्म चित्रण किया जाता है। प्रायः लघु उपन्यास लेखक के जीवन अनुभवों के संवदेन जन्म चित्र होते हैं। दो तीन पात्रों को लघुकथा फलक के आधार पर अभिव्यक्ति की संयतता से चित्रण करना ही लघु उपन्यास को उपन्यास से पृथकत्व प्रदान करता है।'

उपन्यास के समान ही लघु उपन्यास में कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रण, देशकाल, वातावरण, भाषा-शैली, उद्देश्य आदि होते हैं। जिस प्रकार उपन्यास में लेखक अपनी अभिव्यक्ति सशक्त रूप से करते हुए अपनी मान्यताओं और उद्देश्यों को पूर्ण करता है। वह अपनी कृति द्वारा बड़ी प्रखरता, स्पष्टता और साहसिकता से अपनी बात स्पष्ट करता है, उसी प्रकार जीवन मूल्यों की स्थापना और मान्यताओं को अभिव्यक्त करने में लघु उपन्यास भी श्रेष्ठ है, वे भी अपनी बात ज्यादा स्पष्टता और प्रखरता से करते हैं।

आज का मानव जीवन तनावपूर्ण हो गया है व विषम अन्तर्द्वन्द्वों से भरा हुआ है, उलझनपूर्ण तथा अवसाद से भरा हुआ है ऐसे में लेखक के लिए मानव जीवन के हर पहलू को पूर्ण समग्रता से प्रस्तुत करना अत्यन्त दुष्कर कार्य हो गया है। इसी दिशा में लघु उपन्यासकार ने जीवन के खण्ड चित्र को खण्डकाव्य की तरह अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना आरम्भ किया है। आकारगत सीमितता होने के कारण लघु-उपन्यास आज श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी हो गया है। इसका महत्व साहित्य के क्षेत्र में निर्विवाद है।

प्रेमचन्द ने गबन, गोदान जैसे उपन्यासों की सृष्टि कर साहित्य जगत में तहलका मचा दिया था। उनके दोनो उपन्यास ने ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह स्पष्ट किया। उस समय की परिस्थिति, देशकाल, वातावरण को बड़े ही प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत किया जिससे इस कृति ने साहित्य जगत में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया परन्तु वहीं पर उन्होंने निर्मला जैसे लघु उपन्यास की भी सृष्टि की, जिसका स्थान भी साहित्य जगत में गबन, गोदान की दृष्टि से कहीं कम नहीं है। लेखक ने गबन और गोदान में जीवन की पूर्णता को स्पष्ट किया वहीं 'निर्मला' प्रतिज्ञा जैसे लघु उपन्यासों में

उन्होंने जीवन के एक खण्ड चित्र को प्रस्तुत किया जिससे यह उपन्यास लघु होते हुए भी प्रभाविता में कोई कमतर नहीं है।

**प्रेमचन्द्र कृत निर्मला** - प्रेमचन्द्र का सर्वप्रथम लघु उपन्यास सन् 1928 में प्रकाशित हुआ। यह केवल उपन्यास का प्रारम्भ ही नहीं है, अपितु प्रेमचन्द के उपन्यासों में बदलाव को भी उपस्थित करता है। इसमें लघु उपन्यास का पूर्ण स्वरूप नहीं परन्तु उसका संकेत अवश्य है।

उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचन्द्र का आगमन हुआ तो क्रांति हो गई। विषय और शिल्प सभी में परिवर्तन नजर आने लगे। युग की समस्याएँ का प्रस्फुटन उनकी औपन्यासिक कृतियों में दिखाई देने लगा। 'निर्मला' का कथानक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसमें 'निर्मला' का नाम की एक किशोर कन्या और उसके वृद्ध पति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जटिलताओं और विडम्बनाओं का चित्रण है। दहेज की व्यवस्था न हो पाने की वजह से निर्मला के पिता निर्मला का ब्याह अपने प्रथम निश्चयानुसार डॉ. सिन्हा से न कर सके जिससे उन्हें विधुर वृद्ध वकील तोताराम की शरण लेनी पड़ी जो तीन पुत्रों के पिता और शरीर से नितान्त असमर्थ हो चुके थे। वकील तोता राम के तीन पुत्र मंसाराम, जियाराम, सियाराम हैं। तोताराम का शंकालु हृदय निर्मला के सतीत्व पर भी सन्देह करने लगा। अपनी कामुकता के प्रवाह में वे जो मानसिक पाप करने लग जाते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि निर्मला का सम्पूर्ण जीवन ही विशाक्त हो गया। पुत्र मंसाराम जिस पर पिता को यह सन्देह हो गया था कि उसका अपनी माता निर्मला के साथ अनुचित शारीरिक सम्बन्ध है वे उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। मंसाराम की कारुणिक मृत्यु हो जाती है। निर्मला का मातृ - स्नेह उमड़ पड़ता है परन्तु वह लाचार है। निर्मला और मंसाराम एक दूसरों को प्राणों से भी अधिक प्यारे थे पर दोनों का पारस्परिक प्रेम मांसल नहीं बल्कि सात्विक था। अभागिनी निर्मला ने अपने मातृत्व प्रेम को मंसाराम में केन्द्रित कर लिया तथा मंसाराम ने भी माँ के वात्सल्य को निर्मला में मूर्तिमान पाता था। शंकालु प्रवृत्ति की वजह से अन्त में दोनों लड़के भी हाथ से निकल जाते हैं। एक विषपान कर लेता है, दूसरा साधु के साथ निकल जाता है। फिर दोनों लड़कों की खोज में तोताराम भी घर से निकल जाते हैं और एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर निर्मला की भी मृत्यु हो जाती है। निर्मला की लाश उठाने के समय लौटे, डॉ. सिन्हा जो निर्मला के होने वाले पहले पति थे, का निर्मला के निकट आने के कारण पत्नी की फटकार को सह न सकने के कारण वही पर वे आत्मघात कर लेते हैं।

प्रस्तुत उपन्यास में अनेक सामाजिक घटनाएँ हैं जिनके मूल में अनमेल विवाह तथा देहज आदि जैसी कुप्रथाएँ ही हैं जिनके कारण न जाने कितने

भारतीय, उसके बच्चे घुल-धुलकर मृत्यु के मुँह में समाहित हो जाते हैं।

'निर्मला' भारतीय समाज की एक दर्दनाक कारुणिक कहानी है, जिसमें अर्थ से अधिक महत्व सामाजिक कुसंस्कारों को दिया गया है। कथानक संक्षिप्त है। बहुत संगठित है और अन्य उपन्यासों की अपेक्षा तीव्रता से घटित होता है। निर्मला उपन्यास में पात्रों की संख्या कम है। इसमें निर्मला तोताराम, मंसाराम, उदयभानु कल्याणी, कृष्णा आदि ही इस उपन्यास के प्रमुख और गौण पात्र हैं। निर्मला इसकी नायिका है इसी को लेकर कथानक का निर्माण हुआ है। बाकि अन्य पात्र उसके चरित्र को उभारते हैं।

निर्मला समाज में नारियों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो दहेज की कुप्रथा, अनमेल विवाह और असंगतियों के कारण जीवन भर असंतोष, मानसिक अन्तर्द्वन्द्व और विषम परिस्थितियों से जुझता रहता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु क्रांति का संदेश देती है। **उपन्यास में परिस्थितियों पर व्यंग्य है। प्रेमचन्द ने अन्त में निर्मला के मुख से कहलाया**

**'इसका विवाह सुपात्र के हाथ से करना'** इस प्रकार अन्त समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। अतः पूरे उपन्यास में कथानक का विन्यास चरित्रों के घात-प्रतिघात से हुआ है। मनोविज्ञान की प्रवृत्तियों का सहारा अधिकतर लघु उपन्यासों में लिया गया है। निर्मला भी इसका अपवाद नहीं है। प्रेमचन्द का हर पात्र एक जीवंतता का बोध करवाते हैं। पात्र काल्पनिक नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र अपने आसपास के हैं। अनमेल विवाह की शिकार निर्मला के अतृप्त मन का चित्रण प्रेमचन्द ने किया है - वह लेटे-लेटे देखती है- जियाराम उसके आभूषण चुराकर भाग रहा है। वह चाहती तो शोर मचा सकती थी, पर नहीं मचाती क्योंकि वह विमाता थी। वह कहती है 'मुझमें सारी बुराईयाँ ही बुराईयाँ हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाये तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊँ तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई।'।

निर्मला के रूप में भारतीय नारी मर्यादा का जो चित्र प्रेमचन्द जी ने प्रस्तुत किया है उसकी मसोस एवं मूक वेदना से सहृदय पाठक करुणाद्रुत हुए बिना नहीं रह सकता।

इस तरह कथानक का गठन, घटनाओं का शीघ्रता से घटित होना, कम पात्र होना, संवादों की संक्षिप्तता, वातावरण का कम चित्रण और उद्देश्य का कथानक में घुला होना ऐसे तत्व हैं जो इसे लघु उपन्यास कहलाने में सहायक हैं।

**डॉ. गणेश के अनुसार** - 'यद्यपि सेवासदन तथा प्रेमाश्रम की तुलना में इसका विषय बहुत सीमित है, तो भी समस्या के गहरे अध्ययन और मनोभावों के सूक्ष्मविश्लेषण की दृष्टि से यह प्रेमचन्द का सबसे सुन्दर उपन्यास है। कई सांयोगिक घटनाओं के तथा अन्य असंगतियों के होने पर भी निर्मला के पात्रों का क्रमिक विकास विशेषकर उनके मनोभावों का विकास अत्यन्त स्वाभाविक बना है। अनावश्यक तथा विशाल वातावरण के अभाव के कारण शनिर्मला के गठन में जो दृढ़ता आयी है। वह प्रेमचन्द के किसी अन्य उपन्यास में नहीं है।'

इस उपन्यास को हिन्दी का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त है।

**प्रेमचन्द कृत प्रतिज्ञा** - 'प्रतिज्ञा' उपन्यास प्रेमचन्द का दूसरा लघु उपन्यास है। यह उपन्यास भी सामाजिक समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है। कथावस्तु की दृष्टि से इस उपन्यास में कोई विशेष नवीनता नहीं है। कथा

वस्तु का मूलकेन्द्र बिन्दु है विवाह-इसमें प्रेमचन्द ने यदि एक ओर पूर्णा के माध्यम से नारी वैधव्य की तरफ संकेत किया है और विवशता पूर्ण जीवन को उभारा है तो दूसरी ओर सुमित्रा के माध्यम से नारी के विद्रोही रूप को भी प्रस्तुत किया है जो पुरुष अत्याचारों का निरन्तर विरोध करती रहती है।

अमृतलाल उपन्यास के प्रारम्भ से ही यह प्रतिज्ञा करते दिखाई देते हैं कि वह विधुर हाने के कारण किसी विधवा से विवाह करना चाहते हैं। यही सूत्र इस उपन्यास के मूल में है। अमृतलाल वनिता आश्रम की स्थापना करते हैं और यह कहते हैं कि 'मैं विवाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ परन्तु विवाह मैंने किसी विधवा के साथ नहीं किया बल्कि आश्रम के साथ ही किया है।'

अमृतराय के अलावा कमलाप्रसाद, दाननाथ, सुमित्रा, पूर्णा और प्रेमा आदि पात्रों द्वारा कथा को बुना गया है। कमलाप्रसाद और सुमित्रा के वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित इस उपन्यास की कथा का दूसरा तत्व विकसित होता है। कमलाप्रसाद से ही पूर्णा की कथा भी जुड़ी हुई है। घटना की स्थिति इस हद तक पहुँच जाती है कि पूर्णा आत्महत्या करने को विवश हो जाती है। अन्ततः समझा बुझाकर अमृतराय पूर्णा को वनिता आश्रम में भेज देता है। वहीं रहकर वह कृष्ण भक्ति में अपना जीवन लगा देती है। स्वयं तो बच जाती है और एक पति पत्नी के जीवन को नष्ट होने से बचा लेती है। इधर - प्रेमा के पिता प्रेमा का विवाह दाननाथ से कर देते हैं। दाननाथ पहले अमृतराय के मित्र रहते हैं। परन्तु बाद में धार्मिक मतभेद के कारण उनमें वैमनस्य हो जाता है। कमलाप्रसाद की नीचता के कारण दाननाथ को समाज में लज्जित होना पड़ता है। इसलिए अपने रास्ते को बदलकर वे अमृतराय से पुनः मित्रता बढ़ा लेते हैं। इन्हीं घटनाओं के साथ आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्री के अधिकार और उसके स्थान की चर्चा भी वे करते हैं। 'प्रतिज्ञा' उपन्यास की कथावस्तु में ज्यादा विस्तार नहीं है। पात्र संख्या भी ज्यादा नहीं है। पर जितने भी पात्र हैं वे मध्यमवर्गीय समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें मुख्यतः दाम्पत्य जीवन, विधवा विवाह, स्वच्छन्द प्रेम, स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर लेखक ने विचार किया है। इसके हर पात्र का सम्बन्ध किसी न किसी समस्या से है। पूर्णा वैधव्य को झेलती है। लेकिन कमलाप्रसाद की प्रवृत्ति उसे चंचल बना देती है। सुमित्रा विद्रोही नारी है। अमृतराय दाननाथ अन्य पात्र हैं जो उपन्यास की मूल समस्या के आदर्श और यथार्थ पक्ष को उभारते हैं। पात्र संख्या कम है, कथावस्तु में भी ज्यादा विस्तार नहीं है, उद्देश्य जरूर इकट्ठा नहीं है अतः यह उपन्यास की अपेक्षा लघु उपन्यास की परम्परा के विकास को सूचित करता है।

1970 से 1980 के बीच के उपन्यासों में निम्नवर्गीय व मध्यवर्गीय लोगो की अर्थिक स्थिति परम्परागत रूढ़िवादिता पारिवारिक स्थिति का चित्रण है।

अतः शिल्प की दृष्टि से जितने प्रयोग उपन्यास साहित्य में हुए उससे अधिक ओर ज्यादातर प्रयोग लघु उपन्यास विधा में हुए।

वर्तमान युग तक आते-आते उपन्यास साहित्य ने शिल्प कला के कई सौपान तय किए हैं और आज हमें शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट रचनाएँ हिन्दी उपन्यास साहित्य में देखने को मिलती हैं, यदि यह कहा जाय कि शिल्पगत कलात्मक स्वरूप का विकास उपन्यास की अपेक्षा लघु उपन्यास में अधिक हुआ है तो अनुचित न होगा।

वर्तमान समय में उपन्यास बहिर्जगत की वस्तु ही नहीं अन्तर्जगत की वस्तु है। उपन्यास का मुख्य केन्द्र उसकी कथावस्तु है, जिससे उपन्यास का



ताना-बाना बुना जाता है, परन्तु कथावस्तु के साथ-साथ अन्य तत्वों को भी अपने में समाहित किया जाता है और अलग-अलग तत्व के अस्तित्व की अनुभूति भी पूरी तरह से होती है। वृहत उपन्यासों की तरह निर्मला, प्रतिज्ञा जैसे लघु उपन्यासों में भी हमें अन्य तत्वों की अलग-अलग अनुभूति बराबर होती है।

अतः निर्मला, प्रतिज्ञा जैसे लघु उपन्यास की सृष्टि मुंशी प्रेमचन्द ने की जिसका महत्व उनके वृहत उपन्यासों से कुछ कम नहीं। शिल्प व कथानक सभी दृष्टियों से उनके लघु उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण विधा बन गये।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. घनश्याम मधुप, हिन्दी के लघु उपन्यास पृ.60
2. 'निर्मला' प्रेमचन्द का लघु उपन्यास है शिल्प दृष्टि से इसमें उन उपन्यासों की अपेक्षा संगठनात्मकता मिलती है। डॉ. प्रताप नारायण टण्डन हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास पृ. 116
3. प्रेमचन्द - निर्मला पृ. 175
4. डॉ. गणेशन - हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन पृ. 67
5. प्रेमचन्द - प्रतिज्ञा पृ. 149

\*\*\*\*\*

# Study of Effect of Temperature, Light intensity and Irradiation time during Decolouration Process of Methyl Green Dye

Dr. David Swami\*

\*Department of Chemistry PM College of Excellence SBN Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

**Abstract :** Methyl green is the oldest known synthetic groups. Most basic dyes of this series are beautiful crystalline Compounds with a reflex the colour of which is often complementary to the colour in solution. Methyl green a triarylmethane dye providing toxic effluents can be highly degraded using  $\text{TiO}_2$  catalyst. Photo catalytic degradation of methyl green dye have been studied with the help of variety of parameters which are effect of temperature, light intensity and irradiation time. The influence of temperature has been studied in the range from  $30^\circ\text{C}$  to  $55^\circ\text{C}$ . The rate constant increased with the increase in the light intensity.

**Keywords –** Methyl green, Toxic, Catalyst, Temperature, Light Intensity.

**Introduction -** It is well Known that dyes and their degradation by Products originated through oxidation, hydrolysis reactions are highly carcinogenic (1) These substances are highly toxic, Stable to natural decomposition. Decomposition of dye effluents has therefore required increasing attention (2) Earlier studies have shown that a wide range of organic substrates can be completely photo mineralized in the presence of  $\text{TiO}_2$  (3) Aqueous degradation of the commonly used textile dye methyl green has already been studied using heterogeneous catalysts such as  $\text{TiO}_2$  with artificial visible light source. The aim of this paper is to study the effect of temperature, light intensity and irradiation time during Decolouration process of Methyl green dye.

**Experimental:** Methyl green was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst  $\text{TiO}_2$  was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ( $3.8 \times 10^{-5}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ) using 300mg of  $\text{TiO}_2$  photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of  $30 \pm 0.3$  c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for  $\frac{1}{2}$  h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing

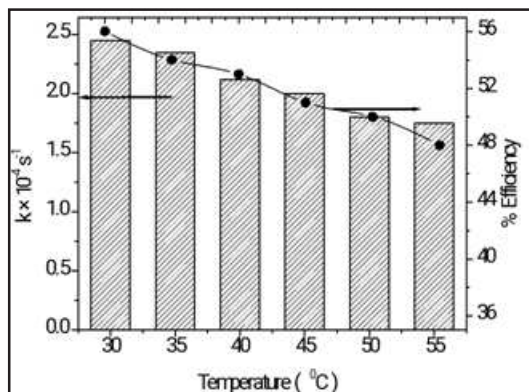
aqueous dye solution and  $\text{TiO}_2$  was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove  $\text{TiO}_2$  particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

## Results and Discussion:

**Effect of temperature:** One of the advantages of photoreaction is that it is not affected or slightly affected by temperature change (4, 5). The influence of temperature has been studied in the range from  $30^\circ\text{C}$  to  $55^\circ\text{C}$ . The results are shown in Table 1 and Fig. 1. Increase in temperature led to decrease the rate of degradation. This gradual decrease in the reaction rate values could be attributed to the following reasons: the adsorption rate decreased with increasing temperature because the adsorption is a heat releasing process, increase in reaction temperature tend to increase electron-hole recombination and with increase in temperature the solubility of oxygen in water decreased (6).

**Table 1: Effect of temperature:**  $[\text{MG}] = 2.5 \times 10^{-5}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ , pH = 10.0  
 $\text{TiO}_2 = 100$  mg/ 10 mL, Light intensity =  $20 \times 10^3$  lux,  
 Temperature =  $30 \pm 0.3$   $^\circ\text{C}$ .

Temperature (°C)	$k \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 \text{ s}$
30	2.45	2.82
35	2.35	2.94
40	2.12	3.26
45	2.00	3.46
50	1.80	3.85
55	1.75	3.96



**Fig. 1: Effect of temperature**

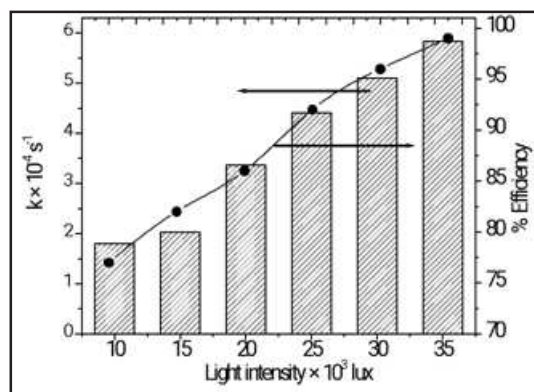
**Effect of light intensity and irradiation time:**

Photocatalytic reaction rate depends largely on the radiation absorption of the photocatalyst. Research studies revealed increase in the degradation rate, with increase in light intensity during photocatalytic degradation. The influence of light intensity on the rate of degradation has been examined at constant dye concentration ( $2.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ ) and catalyst loading (100 mg/ 100 mL). Rate constant increased from  $1.80 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$  to  $5.83 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$  on increase light intensity from  $10 \times 10^3 \text{ lux}$  to  $35 \times 10^3 \text{ lux}$ .

**Table 2: Effect of light intensity:** [MG] =  $2.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ , pH = 10.0

$\text{TiO}_2$  = 100 mg/ 100 mL, Light intensity =  $20 \times 10^3 \text{ lux}$ , Temperature =  $30 \pm 0.3 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Light intensity $\times 10^3 \text{ lux}$	$k \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 \text{ s}$
$10 \times 10^3$	1.80	3.85
$15 \times 10^3$	2.03	3.41
$20 \times 10^3$	3.37	2.05
$25 \times 10^3$	4.41	1.57
$30 \times 10^3$	4.49	1.54
$35 \times 10^3$	5.83	1.18



**Fig. 2: Effect of light intensity**

**Conclusion :** The influence of temperature has been studied in the range from  $30^\circ\text{C}$  to  $55^\circ\text{C}$ . The rate constant was decreased with increase in temperature photo catalytic reaction rate depends largely on the radiation absorption of the photo catalyst. Rate constant increased with increase in light intensity.

**Acknowledgment:** Author acknowledgement the support and laboratory facilities provided by Chemistry Department PMCOE S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) My sincere thanks to the technical staff of UGC-DAE, CSR, Indore for their kind co-operation and help offered during the work period.

**References:-**

1. Nam S., Tratnyek P.G. 2000 Reduction of azo dyes with zero valent iron. Water Res. 1837 -1845.
2. Brown M.A., Vito SC. Crit Rev. Environ. Sci. Technol 1993 – 249 – 32.
3. Blake DM Bibliography of work on the photo catalytic removal of hazardous compounds from Water and air USA : National Renewal Energy Laboratory 2001, – 253.
4. Herrera F., Kiwi J., Lopez A., and Nadtochenko V., Environ. Sci. Technol., 1999, 3145.
5. Amiri A. S., Bolton J. R. and Caster S. R., J. Adv. Oxid. Technol., 1996, 18.
6. Jiang Y., Sun Y., Liu H., Zhu F. and Yin H., Dyes and Pigments, 2008, 77.

\*\*\*\*\*

# Role of Judiciary in the Elimination of Juvenile Delinquency in the Present Social Justice System

Vikram Singh Chandel\*

\*Research Scholar, SOS Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

**Abstract :** “A child may be a person who will carry on what you have got started,” Abraham Lincoln said over a century ago. He will sit where you are and, after you are gone, he will decide what he thinks is important. You can make any plans you want, but he will determine how they are carried out. He will take control of your churches, schools, colleges, and businesses. He holds the futures of humanity in his hands. Children’s crimes are illegal actions that go against social standards. Child misconduct refers to criminal acts committed by children, with behavioral issues being a major cause of youth crimes in India. Child crime is a global issue, and many laws have been made to address it. These children may also engage in other criminal acts, including domestic abuse and disrespect towards women. The juvenile justice court ensures children have their rights, but may punish them in serious cases. The rate of crime among youths under 16 has increased in recent years, possibly due to factors like their upbringing, financial issues, a lack of education, or poor parental care. A concerning trend is the use of very young children, especially those under five to seven years old, as tools for committing crimes, as they are easily manipulated.

**Keywords:** Juvenile Delinquency, Crimes, Juvenile Justice, Judiciary, IJJO, BNS, BNSS.

**Introduction -** The Juvenile Justice Act, 2015 was passed to address the increasing crime rate among children under 18. It mandates the establishment of a Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee in each locality, focusing on adolescent recovery and care through various adjustment homes. The Act defines a child as someone under 18 years old and classifies them as either in conflict with the law or in need of care and protection. It also includes a provision to treat juveniles between 16 and 18 as adults in cases of serious offenses. The Act also addresses the issue of 39% of Child Care Teachers not enrolling in 2020, highlighting the need for revisions. Key amendments include incorporating genuine offenses with a sentence of more than 7 years without minimum and changing sentences with a sentence of 3 to 7 years from being cognizable to non-cognizable. The Act also amends some provisions related to selection and Child Welfare Committees.

Juvenile courts provide a unique and effective method to address adolescent wrongdoers, providing fundamental security to children who cannot legally protect themselves. The Adolescent Equity Board is a Juvenile Court established under sec- 4 of the Juvenile Justice Act (2015), which mandates the establishment of at least one Juvenile Justice Board in each district, consisting of a Principal Magistrate and two social workers, at least one of whom should be a woman. However, the order passed by the Board was deemed void ab initio in State of Himachal Pradesh v. Happy

(2019).

The Board is responsible for handling cases involving children in conflict with the law, which can be appealed to the High Court or Session Court. It can inquire into heinous offenses and conduct preliminary assessments within three months. The Board must inform parents and ensure child rights are protected during the inquiry and rehabilitation process. They can provide a translator if needed, transfer children to committees, and file First Information Reports. The Board also conducts inspections of residential facilities and recommends improvements in service quality.

Juvenile delinquency, involving illegal activities, is on the rise in India due to an increase in crime rates. The Nirbhaya Case of 2012 highlights the heinous offense of rape committed by a 17-year-old girl in a bus, which led to authorities changing the law to punish juvenile offenders, despite their right to think about their actions.

Juvenile delinquency in India is attributed to harsh disciplinary measures by parents and teachers, bad peer company, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and other mental disorders. Teenagers often fall prey to harmful new behaviors, leading to illegal acts. Social factors like broken homes, poverty, and beggary also contribute to delinquency in children in India.

The Indian legal system has evolved over time to address juvenile delinquency, with the first legislation being the Apprentices Act of 1850. The Reformatory Schools Act

of 1897 aimed to send children to reformatory schools, while the first Juvenile Justice Act of 1987 aimed to protect, rehabilitation, and reform juvenile delinquents. The Juvenile Justice Act of 2000 and the Juvenile Justice Act of 2015 further emphasized the importance of juvenile justice. The Indian judiciary plays a crucial role in addressing child delinquency, with the Juvenile Justice Board and courts making decisions that affect children. Governments have established Juvenile Courts, Boards, and Child Welfare Committees to regulate minor delinquents. However, the number of crimes committed by children aged 15-16 has increased, largely due to factors such as early-life experiences, dominant masculinity, upbringing, economic chaos, and lack of education.

**Difference between child and juvenile:** A minor is a person under the age of eighteen who does not have full legal responsibility. A kid accused of a crime goes to a Child Care Centre, while a juvenile is between sixteen and eighteen. Both terms relate to young people, but have different legal meanings.

**Juvenile justice and constitution of India:** The Indian Constitution is known as the country's fundamental law, outlining the rights and responsibilities of citizens. It also includes rules for the effective functioning of the government. Part III describes the Fundamental Rights of citizens, while Part IV details the Directive Principles of State Policies (DPSP), offering guidelines for creating government policies. Key rights for children's welfare include: the right to free education for children aged 6 to 14 (Article 21A), protection from hazardous work for those under fourteen (Article 24), shielding from abuse by adults (Article 39(e)), safeguarding against human trafficking (Article 39), and ensuring proper nutrition and living standards (Article 47). Additionally, Article 15(3) gives the state special powers to create laws for the upliftment of children and women.

**International concerns for juveniles:** The Convention on the Rights of the Child, adopted by the UNGA in 1989, prioritizes children's best interests. It emphasizes several rights:

1. Right of survival, ensuring children have a proper standard of living, including healthy nutrition.
2. Right to protection from inhumane practices, trafficking, and armed conflicts.
3. Right to participation, allowing freedom of speech, expression, religion, and opinion.
4. Right to development, covering educational, physical, mental, cultural, and recreational growth.

Article 34 safeguards children from sexual exploitation, while Article 37 states that imprisonment should be a last resort and for the shortest time, promoting children's liberty and focus on their reformation.

The law in the U. K. states that children should not be prosecuted in criminal courts. Delinquency can end with proper reform in remand homes, and only Juvenile Courts should handle these cases. The Children and Young

Offenders Act of 1933 and the Criminal Justice Act of 1948 support this. The 1908 Children Act allows for a separate Judicial Board in Juvenile Courts.

The system in the U. S. is simpler. First, the Police Officer will either keep the child in custody or release him. Then, he must inform and hand him over to the Juvenile Court. After the trial, children go to correction homes and are tried as adults only if they are closer to adulthood or commit crimes repeatedly that pose a danger to society.

**The International Juvenile Justice Observatory (IJJO):** It is an international organization that promotes policies and laws for the development and protection of juveniles worldwide. It also provides information about juveniles in conflict with the law.

**Doctrine of "Doli Incapax":** The concept of 'Doli Incapax' is a key principle in Criminal Law regarding a child's ability to commit a crime. In Indian law, this means that no child under seven can be tried for a crime. 'Doli Incapax' signifies a person's inability to commit a crime due to their age. As outlined in the UN Convention on the Rights of the Child, countries must set a minimum age for children's exemption from criminal responsibility due to their lack of understanding of their actions. For children aged 8 to 14, prosecutors must prove the crime. The aims of this doctrine include protecting children from harsh punishments and using reformatory approaches, acknowledging that children under seven lack the mental capacity to grasp the consequences of their actions.

**Penal provisions and related judgments:** Sections 82 and 83 of the Indian Penal Code, 1860 (now u/s 20 and 21 of BNS, 2023), discuss how juveniles are protected from prosecution. In *Kakoo v. State of Himachal Pradesh*, the Supreme Court reduced the sentence of a 13-year-old boy for raping a 2-year-old, emphasizing reformatory measures for juveniles. However, in *Heeralal v. State of Bihar*, a boy was judged mature enough for his actions after threatening and stabbing someone. The Supreme Court denied the appeal.

**The policy plays a vital role:** In the Juvenile Justice System, police officers act as gatekeepers, making initial decisions on how cases are handled. They have significant discretion, leading to only a few cases being pursued out of many incidents. When police receive information, juveniles must be placed in Special Homes instead of jails, with a Child Welfare Officer handling the situation and reporting to the Juvenile Justice Board. Police may grant bail based on initial facts. Interactions between police and youths often involve fear and distrust, while abrasive police behavior can worsen the situation.

**Analysis of the issue:** Analysis shows that poverty, broken homes, family tensions, emotional abuse, rural-urban migration, declining social values, parental abuse, a poor education system, and media influence are key factors contributing to child neglect and delinquency. Neglect by parents and society harms children's physical, mental, and

overall development.

In India, many of these factors are prevalent, and addressing them can help society. Children's well-being is essential for the country's future, supported by international agreements focused on juvenile justice and children's rights. This article discusses the growth of India's juvenile justice system, its constitutional framework, the Juvenile Justice Act of 2015, and the current state of delinquency, which has shown a concerning increase.

**Role of the judiciary:** The judiciary in India is crucial for protecting child rights and has made significant rulings. In *Sheela Barse v Union of India*, the Supreme Court directed the state to set up observation homes for minors accused of crimes during legal processes. The court also emphasized the need for juvenile courts and officials to ensure children's safety in these homes. In *Vishal Jeet v Union of India*, it ordered state governments to fight child prostitution and support juvenile victims. In *M. C. Mehta v State of Tamil Nadu*, the court ruled on child labor abolition and provided guidelines for education and health. Lastly, in *Sakshi v Union of India*, it instructed the government to research ways to prevent child abuse.

**Jurisdiction of the juvenile court:** The High Court ruled in *Om Prakash vs. State* that a juvenile court can handle a juvenile case even if it cannot confirm the accused's age. The High Court verified the person's age, determining he is not a child and sentencing him as an adult.

Section 20 of the Juvenile Justice Act outlines rules for children's cases in juvenile courts. The Minor Act addresses pending cases for minors in violation of the law, stating that "any court" means all criminal courts and that juvenile cases are not heard in criminal courts.

**Bail of the child:** Under the Juvenile Court's reasonable points, children are entitled to bail as defined by the Juvenile Justice Act. The Juvenile Board can deny bail for specific reasons. The NDPS Act addresses certain crimes that are considered a threat to society, and special laws have been created to manage these situations and the bail process.

In the case of *Gopi Ram vs. State of Haryana*, the court ruled that if it believes the accused may be innocent, it has the authority to grant bail. The court also stated that if the accused shows remorse and believes he will not commit a similar crime again, he should be released. According to both Section 437 of the Cr. P. C. (now u/s 480 of BNSS, 2023) and Section 37 of the NDPS Act, the burden of proof lies with the prosecution to prove guilt, while the accused must show grounds for proving innocence. The NDPS Act has strict bail conditions due to the serious nature of the offences it covers.

Section 439 of the Cr. P. C. (now u/s 483 of BNSS, 2023) also deals with discretionary powers regarding bail and is affected by Section 37 of the NDPS Act, which generally makes bail denial the norm. There are no provisions for anticipatory bail under the NDPS Act, but some special courts can hear applications for anticipatory

bail under Section 438 of the Cr. P. C. (now u/s 482 of BNSS, 2023) Anticipatory bail, also known as pre-arrest bail, relates to Section 20 of the TADA Act and Section 37 of the NDPS Act. If a court is liberal in its approach, it should consider granting bail if it believes the accused is not guilty. Certain conditions must be met before granting bail to someone accused under the NDPS Act: the court must have reasonable grounds to believe the accused is not guilty and is only being held due to the actions of others, and it must consider the likelihood of the accused committing a crime while released on bail. The historic case *Jitendra Singh vs. State of U. P* states that reasonable grounds are required for bail acceptance, and bail may be denied if these grounds are lacking.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, aligns with the United Nations Convention on the Rights of the Child, raising the minimum age for boys and girls to 18 years. It categorizes children into "children in need of care and protection" and "children in confrontation with the law." Each group receives different treatment regarding care, legal proceedings, and case outcomes. The Child Welfare Committee manages children needing care, while the Juvenile Justice Board handles those in conflict with the law. The Act establishes Observation Homes, Special Homes, and Comprehensive Children's Homes for different categories of children, and promotes community service, counseling, and rehabilitation options like adoption and sponsorship.

Under the Act, police have specialized roles, with every station having a Special Juvenile Police Unit (SJPU), and a Child Welfare Officer supports this unit. The Act also introduces social audits and ensures that voluntary organizations help bring children before the Child Welfare Committee. A juvenile cannot be detained in police custody or jail, and efforts must be made for release on bail or probation. Inquiries must be completed within four months unless extended and state governments are responsible for the Act's implementation.

**Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act in 2015:** The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act enacted in 2015 brings a new approach to handling child offenders in the country. Its main goal is to focus on rehabilitating and reintegrating child offenders into society. The Act acknowledges the unique needs and vulnerabilities of young individuals involved in crimes and categorize them based on age, distinguishing between "children in conflict with the law" and "children in need of care and protection." It encourages engaging delinquent children in alternative programs for rehabilitation rather than traditional punishments, promoting their welfare and successful social reintegration. The Act also emphasizes restorative methods over punitive ones to ensure the well-being of young offenders.

**Problems in administration of justice:** There are several problems in managing justice for child delinquency. First,

many states, following the Juvenile Justice Act of 2015, have not set up juvenile courts in all districts. This leads to non-experts making decisions about children. While this may be legal, it may not align with the law's intention. Juvenile courts should include social workers, and judges must understand child psychology and welfare. Secondly, the system tends to focus on punishment instead of reform, which is not in the best interest of the child.

**Preventing child delinquency:** Early intervention is seen as the best way to prevent juvenile crime. It requires individual, social, and organizational actions to stop teens from breaking the law. Some methods focus on punishment to deter offenders. Economic programs and community involvement can also help prevent youth delinquency.

**Recommendations:** The Juvenile Justice Act of 2015 made important improvements in the treatment of juveniles in the justice system. It established a clear division between two categories of juveniles, set up a Juvenile Justice Board, and allowed for the trial of juveniles aged 16 to 18 for serious crimes. However, there are concerns. The age from 16 to 18 is a time of vulnerability due to hormonal and mental changes. Trying these juveniles as adults can have lasting negative effects on their minds. Critics argue this approach conflicts with Article 14 of the Indian Constitution, which promotes equality before the law, and the UN Convention on Child Rights.

To prevent issues in the future, the government should provide children with a basic living standard and focus on their education and recreation. There should be training programs focused on child psychology, and social workers should be involved during investigations. Police should handle juveniles carefully, and staff at shelter homes must be well-trained. Public awareness is also crucial for understanding and supporting these children.

**Conclusion:** Children are the future of the world, and it is important to have laws that prevent juvenile delinquency for a better society. Early intervention is crucial, especially for children from difficult backgrounds, and NGOs should help improve the lives of these children.

Youth crime rates in India are rising, which is a serious issue. The government has made laws to lower juvenile crime, but these laws do not effectively deter such behavior, leading to poor results. Juvenile justice focuses on reform rather than punishment, and the 2015 Act is a key guideline. The juvenile justice system aims to address misbehavior and promote reform as an alternative to punishment. If children receive the right support and education, they can

become responsible citizens.

It is essential to reduce societal issues by teaching children ethical and spiritual values, as well as understanding child development. Parents should pay attention to their children's mental health to guide them properly. While the judiciary provides some guidance on child care, support should happen in local communities. Despite laws against delinquency, the issue remains, so focusing on children's needs is vital for their growth. The juvenile justice system should be backed by a thorough action plan to aid all neglected children, requiring cooperation from individuals and the community.

#### References:-

##### Books:-

1. Batra, V. (2016). Juvenile Justice: A Comprehensive Study. LexisNexis.
2. Mathur, N. N. (2020). Law Relating to Juvenile Justice in India. Universal Law Publishing.
3. Singh, K. (2017). Juvenile Justice System in India. Central Law Agency.
4. Das, B. (2019). Juvenile Delinquency and Justice: A Socio-Legal Study. Eastern Book Company.
5. Singh, M. K. (2018). Juvenile Justice: Law and Practice. LexisNexis

##### Research Articles:-

1. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2402082.pdf>
2. Sarma, A., & Deb, S. (2017). "Role of Juvenile Justice Boards in India: An Analysis." *Indian Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 23-39.
3. Patil, P., & Choudhary, M. (2020). "Rehabilitation of Juvenile Offenders in India: A Critical Appraisal." *The Indian Journal of Criminology and Criminalistics*, 41(2), 265-281.
4. Mukherjee, A. (2019). "Juvenile Justice in India: Challenges & Prospects." *Indian Journal of Criminology and Criminalistics*, 40(1), 78-94.

##### Websites:-

1. <https://indiankanoon.org/>
2. <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/juvenile-court-overview-32222.html>
3. <https://www.latestlaws.com/articles/overview-of-juvenile-justice-law-in-india-by-chhaya-khosla/>
4. <https://knowlaw.in/index.php/2021/03/17/juvenile-delinquency-a-rising-concern/>
5. <https://prsindia.org/billtrack/the-juvenile-justice-care-and-protection-of-children-amendment-bill-2021>

\*\*\*\*\*

## डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग

डॉ. अनिल तौहेल \*

\* सहा. प्रध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस, शास. तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभावी उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। AI तकनीकों का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार की भविष्यवाणी करने, डेटा विश्लेषण, विज्ञापन अनुकूलन, चैटबॉट्स, और व्यक्तिगत विपणन अभियानों में किया जाता है। यह शोधपत्र AI के विभिन्न अनुप्रयोगों, उनकी प्रभावशीलता, लाभों और चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह विश्लेषण करता है कि AI डिजिटल मार्केटिंग में कैसे नवाचार ला रहा है और भविष्य में इसके विकास की संभावनाएँ क्या हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि AI-समर्थित विपणन अभियानों की प्रभावशीलता पारंपरिक अभियानों की तुलना में अधिक है।

**प्रस्तावना** - डिजिटल मार्केटिंग आधुनिक विपणन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिजिटल मार्केटिंग में व्यक्तिगत विज्ञापन और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो रहा है। AI की सहायता से डेटा-संचालित निर्णय लिए जाते हैं, जिससे विपणन रणनीतियों की सटीकता बढ़ती है। इसके अलावा, AI उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर उनके अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करता है, जिससे विपणन अधिक प्रभावशाली होता है। AI-समर्थित टूल्स जैसे मशीन लर्निंग, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग को अधिक उन्नत बना रहे हैं।

### साहित्य समीक्षा

डिजिटल मार्केटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग पर कई शोध किए गए हैं। Smith et al. (2020) के अध्ययन के अनुसार, AI-आधारित मार्केटिंग अभियानों से ग्राहक संतुष्टि में 30% तक वृद्धि हुई। इसी तरह, Brown and Johnson (2019) ने अपने शोध में पाया कि मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण में अधिक सटीकता लाने में सहायक होता है।

भारतीय संदर्भ में, Gupta & Sharma (2021) ने डिजिटल मार्केटिंग में AI के प्रभावों पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि AI-समर्थित चैटबॉट्स और विज्ञापन रणनीतियाँ उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी रूप से लक्षित कर सकती हैं। Mishra & Patel (2022) ने बताया कि भारत में छोटे एवं मध्यम व्यवसाय (SMEs) AI-आधारित मार्केटिंग टूल्स का उपयोग कर अपने विज्ञापन अभियानों की लागत को कम करने और उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं।

**AI-आधारित सिफारिश प्रणाली का प्रभाव** - अन्य शोधों में, Lee et al. (2022) ने AI-आधारित सिफारिश प्रणाली की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि ग्राहकों की पसंद को समझने और उन्हें उपयुक्त उत्पाद सुझाने में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Kumar & Verma (2023) ने भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग में AI-आधारित

सिफारिश प्रणालियों के प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि AI-आधारित एल्गोरिदम के माध्यम से उत्पाद अनुशंसाएँ उपभोक्ताओं की खरीदारी की संभावना को 25% तक बढ़ा सकती हैं। Reddy & Nair (2023) के शोध ने दर्शाया कि Flipkart और Amazon जैसी ई-कॉमर्स कंपनियाँ AI-आधारित सिफारिश प्रणालियों के माध्यम से ग्राहकों की प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर अपनी बिक्री में 40% तक की वृद्धि कर रही हैं।

### AI-समर्थित SEO और डिजिटल विज्ञापन रणनीतियाँ

Singh et al. (2023) के शोध के अनुसार, AI-चालित SEO रणनीतियाँ वेबसाइट ट्रैफिक और ब्रांड दृश्यता में वृद्धि कर सकती हैं। AI का उपयोग कीवर्ड विश्लेषण, ट्रेंड पहचान, और सामग्री अनुकूलन में किया जा रहा है, जिससे वेबसाइट की खोज इंजन रैंकिंग बेहतर हो रही है। Choudhary & Reddy (2023) ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में AI के प्रभावों पर अध्ययन करते हुए पाया कि AI-समर्थित सामग्री निर्माण और उपभोक्ता सगाई रणनीतियाँ व्यवसायों की रूपांतरण दर (Conversion rate) में सुधार कर सकती हैं।

### भारतीय उपभोक्ताओं पर AI-आधारित मार्केटिंग का प्रभाव

Sharma & Das (2024) ने भारतीय उपभोक्ताओं पर AI-आधारित मार्केटिंग अभियानों के प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि AI-संचालित व्यक्तिगत विज्ञापन (Personalized Ads) उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। उनके शोध में पाया गया कि 72% भारतीय उपभोक्ता उन ब्रांडों को अधिक प्राथमिकता देते हैं जो व्यक्तिगत विज्ञापन और सिफारिशें प्रदान करते हैं।

Mehta et al. (2024) के अनुसार, भारतीय खुदरा कंपनियों (Retail Companies) AI-आधारित ग्राहक डेटा विश्लेषण का उपयोग कर ग्राहकों की खरीदारी की प्रवृत्तियों को समझने और उन्हें अधिक प्रासंगिक ऑफर प्रदान करने में सक्षम हो रही हैं।

**अनुसंधान पद्धति** - यह शोध गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों



पर आधारित है। प्राथमिक डेटा के रूप में एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 500 उपभोक्ताओं और 100 डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञों से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं। द्वितीयक डेटा विभिन्न शोध पत्रों, पुस्तकालय संसाधनों, और ऑनलाइन डेटाबेस से प्राप्त किया गया। डेटा संग्रह तकनीकों में ऑनलाइन प्रश्नावली, केस स्टडी, और उद्योग रिपोर्ट शामिल थीं। डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों और AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग टूल्स जैसे SPSS और Python लाइब्रेरी की सहायता से किया गया।

**उद्देश्य-** इस अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल मार्केटिंग में AI के विभिन्न अनुप्रयोगों का गहन विश्लेषण करना है। इसके तहत यह समझने का प्रयास किया गया कि AI किस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है और मार्केटिंग अभियानों की सफलता को बढ़ाता है। साथ ही, इस शोध में AI द्वारा उत्पन्न लाभों और संभावित चुनौतियों को उजागर करना तथा भविष्य में AI-आधारित डिजिटल विपणन की भूमिका का अनुमान लगाना शामिल है।

**डेटा विश्लेषण-** सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक डेटा के अनुसार, 72% उपभोक्ता मानते हैं कि AI-आधारित विज्ञापन अधिक प्रासंगिक और व्यक्तिगत होते हैं। वहीं, 65% विपणक मानते हैं कि AI-समर्थित विपणन अभियानों से ROI (Return of investment) में 30% तक वृद्धि हुई है। उपभोक्ता जुड़ाव (Engagement rates) AI-आधारित अभियानों में 40% अधिक पाया गया, जबकि क्लिक-थ्रू दर (CTR) 35% अधिक रही। पारंपरिक विपणन अभियानों की तुलना में AI-समर्थित अभियानों की प्रभावशीलता अधिक पाई गई। AI-आधारित सिफारिश प्रणालियों का उपयोग करने वाले ई-कॉमर्स व्यवसायों में बिक्री में 50% की वृद्धि देखी गई। डेटा से यह स्पष्ट होता है कि AI डिजिटल मार्केटिंग को अधिक प्रभावी बना रहा है और इसके उपयोग से उपभोक्ता जुड़ाव एवं ब्रांड वफादारी में सुधार हो रहा है।

डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग आधुनिक विपणन रणनीतियों को अधिक प्रभावशाली और डेटा-संचालित बना रहा है। इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि AI-समर्थित विपणन अभियानों की प्रभावशीलता पारंपरिक अभियानों की तुलना में अधिक है। AI तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से कंपनियाँ उपभोक्ता व्यवहार को अधिक सटीकता से समझ पा रही हैं और उनके अनुरूप सामग्री एवं विज्ञापन प्रस्तुत कर पा रही हैं।

### शोध के परिणाम

- व्यक्तिगत विपणन** - AI-आधारित सिफारिश प्रणालियाँ और चौटबॉट्स उपभोक्ता अनुभव को अधिक व्यक्तिगत और आकर्षक बना रहे हैं। भारतीय संदर्भ में, 72% उपभोक्ता व्यक्तिगत विज्ञापन को अधिक पसंद करते हैं।
- विज्ञापन अनुकूलन** - AI तकनीकों के उपयोग से डिजिटल विज्ञापन अभियानों में क्लिक-थ्रू दर (CTR) 35% अधिक पाई गई, जिससे विपणन की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई।
- ई-कॉमर्स में AI का प्रभाव** - AI-आधारित अनुशंसा एल्गोरिदम से ऑनलाइन खरीदारी की संभावना 25% तक बढ़ी है, और Flipkart और Amazon जैसी कंपनियों ने अपनी बिक्री में 40% तक वृद्धि दर्ज की है।
- SEO और डिजिटल रणनीतियाँ** - AI-समर्थित SEO अभियानों से वेबसाइट ट्रैफिक और ब्रांड दृश्यता में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

**5. छोटे एवं मध्यम व्यवसायों (SMEs) पर प्रभाव** - AI-आधारित मार्केटिंग टूल्स का उपयोग SMEs को कम लागत में प्रभावी विज्ञापन अभियानों को संचालित करने में मदद कर रहा है।

**चर्चा** - AI की बढ़ती भूमिका डिजिटल मार्केटिंग को और अधिक स्वचालित, प्रभावी और डेटा-संचालित बना रही है। यह देखा गया कि उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझने के लिए AI तकनीकों का उपयोग ब्रांडों को अधिक प्रासंगिक और लक्षित विज्ञापन बनाने में सहायता करता है। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी देखी गईं:

- डेटा गोपनीयता और नैतिकता** - उपभोक्ताओं के डेटा का व्यापक उपयोग उनके निजता अधिकारों पर प्रश्न उठाता है।
- तकनीकी जटिलता** - AI-आधारित टूल्स की स्थापना और प्रबंधन छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- व्यक्तिगत विज्ञापनों की सीमाएँ** - AI द्वारा अत्यधिक लक्षित विज्ञापन कभी-कभी उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से ट्रैक किए जाने का अनुभव दे सकते हैं।

### परिकल्पना परीक्षण:

इस शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया:

- $H_0$  (शून्य परिकल्पना): AI-समर्थित विपणन अभियानों और पारंपरिक विपणन अभियानों के बीच कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
- $H_1$  (वैकल्पिक परिकल्पना): AI-समर्थित विपणन अभियानों की प्रभावशीलता पारंपरिक विपणन अभियानों की तुलना में अधिक है। इस शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया:

परीक्षण विधि के रूप में टि-टेस्ट और अनोवा का उपयोग किया गया। प्राप्त डेटा के अनुसार, AI-समर्थित अभियानों में औसत उपभोक्ता जुड़ाव 68% था, जबकि पारंपरिक अभियानों में यह केवल 45% था। पी-मूल्य 0.03 प्राप्त हुआ, जो 0.05 के महत्व स्तर से कम था, जिससे  $H_0$  को अस्वीकार कर  $H_1$  को स्वीकार किया गया। यह निष्कर्ष निकलता है कि AI-समर्थित विपणन अभियानों की प्रभावशीलता पारंपरिक अभियानों की तुलना में अधिक है।

**निष्कर्ष एवं चर्चा** - डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभावी उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। AI तकनीकों का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार की भविष्यवाणी करने, डेटा विश्लेषण, विज्ञापन अनुकूलन, चौटबॉट्स, और व्यक्तिगत विपणन अभियानों में किया जाता है। यह शोधपत्र AI के विभिन्न अनुप्रयोगों, उनकी प्रभावशीलता, लाभों और चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह विश्लेषण करता है कि AI डिजिटल मार्केटिंग में कैसे नवाचार ला रहा है और भविष्य में इसके विकास की संभावनाएँ क्या हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि AI-समर्थित विपणन अभियानों की प्रभावशीलता पारंपरिक अभियानों की तुलना में अधिक है। **भविष्य की संभावनाएँ** : भविष्य में, AI डिजिटल मार्केटिंग में और अधिक नवाचार लाने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में AI का विकास संभावित है:

- स्वचालित सामग्री निर्माण** - AI-समर्थित टूल्स से व्यक्तिगत और उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री का स्वचालित रूप से उत्पादन किया जा सकता है।
- वॉयस एवं इमेज रिकग्निशन** - आवाज और छवि पहचान तकनीकों के उपयोग से उपभोक्ताओं को अधिक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान किया

जा सकता है।

3. **उन्नत ग्राहक सेवा** – AI-समर्थित वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट्स ग्राहक सेवा में नए मानक स्थापित कर सकते हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. **Brown, T., & Johnson, R. (2019).** Machine learning and big data analytics in consumer behavior analysis. *Journal of Digital Marketing Research*, 15(2), 112-130.
2. **Choudhary, A., & Reddy, P. (2023).** The role of AI in social media marketing: Content creation and customer engagement strategies. *International Journal of Marketing Innovations*, 28(1), 45-60.
3. **Gupta, R., & Sharma, M. (2021).** Impact of AI-supported chatbots and advertising strategies in digital marketing: An Indian perspective. *Indian Journal of Business and Management*, 10(3), 89-104.
4. **Kumar, S., & Verma, D. (2023).** AI-based recommendation systems and their impact on consumer purchase behavior in India. *E-Commerce Trends Journal*, 7(2), 56-73.
5. **Lee, K., Wang, H., & Chen, Y. (2022).** Effectiveness of AI-based recommendation systems in online retail. *Journal of Artificial Intelligence and Business*, 18(4), 150-167.
6. **Mehta, P., Sharma, L., & Desai, K. (2024).** AI-powered customer data analytics and its influence on Indian retail companies. *Retail Business & Analytics Journal*, 12(3), 78-95.
7. **Mishra, A., & Patel, V. (2022).** AI-driven marketing tools and their impact on Indian SMEs. *Indian Journal of Marketing Strategies*, 14(1), 33-50.
8. **Reddy, S., & Nair, P. (2023).** AI in e-commerce: A case study of Flipkart and Amazon's recommendation algorithms. *E-Commerce and AI Journal*, 6(2), 99-115.
9. **Sharma, K., & Das, P. (2024).** AI-powered personalized advertising and its impact on Indian consumers. *Journal of Consumer Insights*, 11(1), 22-38.
10. **Singh, R., Gupta, A., & Verma, S. (2023).** AI-driven SEO strategies and their impact on website traffic. *Journal of Digital Marketing and Technology*, 9(4), 61-80.
11. **Smith, J., Brown, L., & Taylor, R. (2020).** Artificial intelligence in digital marketing: Enhancing customer satisfaction. *Marketing Science Journal*, 25(3), 200-218.

\*\*\*\*\*

## नई शिक्षण क्षमताएँ: आधुनिक शिक्षा में नवाचार और तकनीकी एकीकरण

डॉ. अनिल तौहेल \*

\* सहा. प्रध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शास. तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - शिक्षा का क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है और नई तकनीकों के आने से इसमें और भी व्यापक बदलाव हो रहे हैं। पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, जो मुख्य रूप से किताबों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित थीं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, और ऑनलाइन लर्निंग की सहायता से अधिक प्रभावी हो रही हैं। इस शोध पत्र में आधुनिक शिक्षण क्षमताओं का विश्लेषण किया गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को अधिक रोचक, प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही, यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि इन तकनीकों को अपनाने में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है।

**शब्द कुंजी** -आधुनिक शिक्षा, तकनीकी एकीकरण, AI-आधारित चैटबॉट्स।

**प्रस्तावना** - शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है और इसकी गुणवत्ता का प्रभाव सीधा राष्ट्र की प्रगति पर पड़ता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र के बीच सीधा संवाद होता था, लेकिन आधुनिक युग में यह प्रणाली बदल रही है। आज शिक्षण में डिजिटल उपकरणों, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है। नई शिक्षण क्षमताओं का उद्देश्य न केवल जानकारी प्रदान करना है, बल्कि छात्रों की सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को भी विकसित करना है। इस शोध पत्र में आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग, उनकी प्रभावशीलता और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का गहन अध्ययन किया गया है। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें छात्र शिक्षक के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यह प्रणाली व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित थी, लेकिन इसमें तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं थी। औपनिवेशिक काल के दौरान स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिससे शिक्षा की संरचना अधिक संगठित हो गई।

20वीं शताब्दी में शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिला, जहाँ प्रिंट मीडिया, रेडियो, और टेलीविजन का प्रयोग शिक्षण में किया जाने लगा। 21वीं शताब्दी में इंटरनेट के आगमन ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, और मोबाइल एप्लिकेशन ने शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया। आज, शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रक्रिया बन गई है जहाँ छात्र और शिक्षक डिजिटल माध्यमों से किसी भी समय, कहीं भी जुड़ सकते हैं।

**साहित्य समीक्षा** - शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन को समझने के लिए पारंपरिक और आधुनिक शिक्षण प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

**Dewey** (1938) के अनुसार, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाता था, जहाँ छात्र केवल निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करते थे। दूसरी ओर, **Piaget** (1952) ने सक्रिय अधिगम (Active Learning) के सिद्धांत पर जोर दिया, जहाँ छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। वर्तमान समय में, शिक्षण विधियों में तकनीक का प्रयोग बढ़ने से शिक्षा अधिक संवादात्मक और छात्र-केंद्रित हो गई है। **Prensky** (2001) के अनुसार, डिजिटल शिक्षा प्रणाली पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यह छात्रों को उनके अनुसार सीखने की स्वतंत्रता देती है। **Anderson & Dron** (2011) ने अपने शोध में यह पाया कि ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करता है और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। **Means et al.** (2013) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पारंपरिक कक्षा शिक्षण से अधिक प्रभावी हो सकते हैं, यदि उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। भारत में ऑनलाइन शिक्षण के बढ़ते प्रभाव पर **Agarwal & Mittal** (2019) ने अपने शोध में कहा कि सरकारी और निजी स्तर पर कई प्लेटफॉर्म, जैसे कि **SWAYAM**, **NPTel** और **DIKSHA**, ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से उपयोग संभव नहीं हो पाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शिक्षा में उपयोग को लेकर कई शोध हुए हैं। **Luckin et al.** (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि AI आधारित शिक्षण प्रणाली छात्रों को व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करने में सहायक होती है। **Baker & Siemens** (2014) के अनुसार, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम छात्रों की प्रगति का विश्लेषण कर उनके लिए अनुकूल शिक्षण सामग्री प्रदान कर सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, **Sharma & Gupta** (2020) ने अपने शोध में यह उल्लेख किया कि AI-

आधारित चौटबॉट्स और स्मार्ट असिस्टेंट छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायक हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक और छात्र के बीच मानवीय संपर्क की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) आधारित शिक्षण तकनीकों पर किए गए कई शोध यह दर्शाते हैं कि यह जटिल अवधारणाओं को समझाने में प्रभावी साबित होती है। **Dalgarno & Lee** (2010) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि VR आधारित शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में सक्षम होती है, जिससे उनकी अवधारणात्मक समझ बेहतर होती है। भारत में, **Kumar et al.** (2021) ने अपने अध्ययन में यह बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में VR आधारित शिक्षण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण का मिश्रण होता है, शिक्षा प्रणाली में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। **Graham** (2006) ने इसे शिक्षण का भविष्य बताया, क्योंकि यह दोनों पद्धतियों के लाभों को समाहित करता है। **Horn & Staker** (2015) के अनुसार, ब्लेंडेड लर्निंग छात्रों को अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। गेमिफिकेशन (Gamification) आधारित शिक्षण के प्रभावों पर **Deterding et al.** (2011) ने अपने शोध में कहा कि खेल-आधारित शिक्षण छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाता है और उन्हें अधिक आकर्षक तरीके से सीखने में मदद करता है। भारतीय संदर्भ में, **Singh & Patel** (2022) ने यह निष्कर्ष निकाला कि गेमिफिकेशन का प्रभाव स्कूल स्तर की शिक्षा में अधिक सकारात्मक है, लेकिन उच्च शिक्षा में इसे प्रभावी बनाने के लिए अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

**शोध पद्धति** - इस अध्ययन में शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षण क्षमताओं के प्रभाव, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन एक मिश्रित विधि पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक और सांख्यिकीय दोनों प्रकार के शोध विधियों का समावेश किया गया है। यह शोध विधि अध्ययन के उद्देश्यों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है, क्योंकि यह दोनों प्रकार के डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने सर्वेक्षण : शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग किया गया। इसमें छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, और तकनीकी चुनौतियों पर प्रश्न पूछे गए। साक्षात्कार : शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गहन साक्षात्कार किए गए, ताकि तकनीकों की प्रभावशीलता और चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके। साहित्य समीक्षा : विभिन्न शोध पत्रों, रिपोर्ट्स, और सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा की गई ताकि पिछले अध्ययनों और नीतियों का विश्लेषण किया जा सके। सर्वेक्षण और नमूना आकार सर्वेक्षण का आकार : इस अध्ययन में 500 छात्रों और 200 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिनका चयन विभिन्न शैक्षिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय) से किया गया था। नमूना चयन : छात्रों और शिक्षकों का चयन सुविधाजनक नमूना विधि द्वारा किया गया, जो अध्ययन के लिए उपलब्ध संस्थानों और शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण : डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक आँकड़े जैसे औसत, प्रतिशत, और मानक विचलन का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय परीक्षण जैसे T-test और ANOVA का उपयोग किया गया ताकि विभिन्न शैक्षिक संस्थानों

और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।

**सीमाएँ** - यह अध्ययन समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण केवल कुछ संस्थानों और क्षेत्रों तक सीमित था। डिजिटल विभाजन की समस्या और सभी छात्रों को समान रूप से डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता नहीं थी, जिससे परिणामों पर प्रभाव पड़ा।

#### उद्देश्य :

1. नई शिक्षण तकनीकों (AI, VR, गेमिफिकेशन) का छात्रों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा के प्रभाव में अंतर का विश्लेषण करना।
3. शैक्षिक संस्थानों के बीच डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता में अंतर का अध्ययन करना।
4. शिक्षकों और छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा पर राय में अंतर का मूल्यांकन करना।
5. डिजिटल उपकरणों का उपयोग छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है या नहीं।
6. प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता के आधार पर डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता को समझना।

**डेटा विश्लेषण** - शोध में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों और रिपोर्टों का उपयोग किया गया है ताकि नई शिक्षण क्षमताओं के प्रभाव को मापा जा सके। इस शोध में नई शिक्षण क्षमताओं के प्रभाव, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया है। डेटा संग्रहण के बाद, इन उपकरणों का प्रयोग डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने, विभिन्न समूहों के बीच अंतर का मूल्यांकन करने और परिणामों को सांख्यिकीय दृष्टि से विश्लेषित करने के लिए किया गया।

**1. वर्णनात्मक आँकड़े** - डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक आँकड़े का उपयोग किया गया। इसमें माध्य, मानक विचलन, प्रतिशत और अन्य सारांशात्मक आँकड़ों का उपयोग किया गया ताकि छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का सामान्य विवरण प्राप्त किया जा सके। 75% छात्रों ने AI और VR को प्रभावी बताया, जबकि 60% ने गेमिफिकेशन को आकर्षक और प्रभावी माना। माध्य परीक्षा परिणामों में 15% सुधार दर्शाता है, और मानक विचलन में 20% सुधार देखने को मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि छात्रों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ है।

सारांश आँकड़े	प्रतिक्रिया (%)
AI/VR प्रभावी पाया	75%
गेमिफिकेशन प्रभावी पाया	60%
परीक्षा परिणामों में सुधार	15%
ध्यान केंद्रित करने में सुधार	20%

**2. T-test** - T-test का उपयोग शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच परीक्षा परिणामों में अंतर का परीक्षण करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में पाया गया कि शहरी छात्रों के परिणामों में ग्रामीण छात्रों के मुकाबले अधिक सुधार हुआ था, जो डिजिटल शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता और कनेक्टिविटी में अंतर को दर्शाता है।

T-value: 2.56 (P < 0.05)

यह दर्शाता है कि शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच परीक्षा परिणामों में

महत्वपूर्ण अंतर है।

समूह	माध्य परीक्षा परिणाम	T-value	P-value
शहरी छात्र	85%	2.56	<0.05
ग्रामीण छात्र	70%		

**3. ANOVA-** ANOVA का उपयोग विभिन्न शैक्षिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय) के बीच परीक्षा परिणामों में अंतर का परीक्षण करने के लिए किया गया। इस परीक्षण से यह साबित हुआ कि विभिन्न संस्थानों के बीच परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर था, जो डिजिटल शिक्षा के संसाधनों और शिक्षण विधियों के प्रभाव को दर्शाता है।

F-value: 5.32 (P<0.01)

यह दर्शाता है कि शैक्षिक संस्थानों के बीच डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतर है।

संस्थान	माध्य परीक्षा परिणाम	F-value	P-value
स्कूल	75%	5.32	< 0.01
कॉलेज	80%		
विश्वविद्यालय	90%		

**4. Chi Square Test - Chi Square** परीक्षण का उपयोग छात्रों और शिक्षकों के बीच डिजिटल शिक्षा पर राय के अंतर का परीक्षण करने के लिए किया गया। यह परीक्षण दर्शाता है कि छात्रों और शिक्षकों के विचारों में एक महत्वपूर्ण अंतर था, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता के संदर्भ में। Chi Square value: 12.3 (P<0.05)

यह दर्शाता है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच राय में महत्वपूर्ण अंतर था।

समूह	सहमत (%)	असहमत (%)	Chi Square value	P-value
छात्र	80%	20%	12.3	<0.05
शिक्षक	60%	40%		

**5. कोरिलेशन - Pearson Correlation** का उपयोग छात्रों के परीक्षा परिणामों और उनके डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बीच संबंध का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। यह विश्लेषण यह दर्शाता है कि डिजिटल उपकरणों के उपयोग और परीक्षा परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध है। **Pearson Correlation:** 0.75 (P<0.01)

यह दर्शाता है कि छात्रों के परीक्षा परिणामों और उनके डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध है।

वेरिएबल	कोरिलेशन मान	P-value
परीक्षा परिणाम और डिजिटल उपकरणों का उपयोग	0.75	<0.01

**6. Regression Analysis- Linear Regression** का उपयोग छात्रों की परीक्षा परिणामों को उनके डिजिटल उपकरणों के उपयोग के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए किया गया। यह विश्लेषण दर्शाता है कि डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ने से छात्रों के परिणामों में सकारात्मक सुधार हो सकता है। **Regression Coefficient:** 0.8

यह दर्शाता है कि डिजिटल उपकरणों के उपयोग में 1% वृद्धि से परीक्षा परिणामों में औसतन 0.8% सुधार हुआ है।

वेरिएबल	Regression Coefficient	P-value
डिजिटल उपकरणों का उपयोग	0.8	< 0.01

## 7. Factor Analysis

**Exploratory Factor Analysis (EFA)** - का उपयोग छात्रों और शिक्षकों के विचारों और अनुभवों के बीच सामान्य कारकों की पहचान करने के लिए किया गया। यह विश्लेषण दर्शाता है कि प्रमुख कारक जैसे तकनीकी ज्ञान, संसाधन उपलब्धता और प्रशिक्षण की आवश्यकता, डिजिटल शिक्षा के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। **Factor Loadings:** 0.85 प्रशिक्षण की आवश्यकता: 0.78

यह दर्शाता है कि तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता डिजिटल शिक्षा के प्रभाव को प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं।

फैक्टर	Factor Loadings	Eigen Value
तकनीकी ज्ञान	0.85	3.2
प्रशिक्षण की आवश्यकता	0.78	2.9

डेटा विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि नई शिक्षण तकनीकों जैसे AI, VR और गेमिफिकेशन ने शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक प्रभाव डाला है। छात्रों और शिक्षकों दोनों ने इन तकनीकों को स्वीकार किया, लेकिन कुछ चुनौतियाँ, जैसे प्रशिक्षण की कमी और डिजिटल विभाजन, भी सामने आईं। इसके अलावा, सांख्यिकीय परीक्षणों ने यह साबित किया कि डिजिटल शिक्षा का प्रभाव छात्रों के परिणामों और उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार ला सकता है, यदि उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध हों।

### निष्कर्ष :

1. सभी हाइपोथीसिस परीक्षणों में **P-value** 0.05 या उससे कम था, जिससे हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं।
2. यह अध्ययन साबित करता है कि नई शिक्षण तकनीकों छात्रों की सीखने की क्षमता, परीक्षा परिणामों, और उनकी भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, साथ ही शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा के प्रभाव में अंतर है।
3. शैक्षिक संस्थानों के बीच भी डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता में अंतर है, और शिक्षकों तथा छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा पर राय में भी अंतर है।

### भविष्य के लिए सुझाव:

1. सरकार और निजी क्षेत्र को डिजिटल शिक्षा के विस्तार और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
2. कम लागत वाले डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
3. AI, VR और गेमिफिकेशन जैसी तकनीकों को स्कूली शिक्षा में भी व्यापक रूप से अपनाने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।

**निष्कर्ष और सिफारिशें** - इस शोध पत्र में यह स्पष्ट हुआ कि नई शिक्षण क्षमताएँ पारंपरिक शिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावी, लचीली और समावेशी हो रही हैं। हालांकि, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी हुई है। सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को चाहिए कि वे डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पहल करें। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षण क्षमताएँ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और समावेशी बना रही हैं। विभिन्न शोधों के अनुसार, ई-लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी,

और ब्लेंडेड लर्निंग जैसी तकनीकों का उचित उपयोग छात्रों की समझ और प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हालांकि, भारत में डिजिटल शिक्षा को सफल बनाने के लिए कुछ बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों का तकनीकी प्रशिक्षण, और गामिफिकेशन जैसी नई शिक्षण विधियों को अपनाना।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. Agarwal, P., & Mittal, R. (2019). Digital education in India: Opportunities and challenges. *Journal of Indian Education*, 45(2), 65-78.
2. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
3. Baker, R. S., & Siemens, G. (2014). Educational data mining and learning analytics. *Cambridge Handbook of the Learning Sciences*, 2nd edition, 253-272.
4. Dalgarno, B., & Lee, M. J. (2010). What are the learning affordances of 3-D virtual environments? *British Journal of Educational Technology*, 41(1), 10-32.
5. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.
6. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
7. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. *Handbook of Blended Learning: Global Perspectives*, 3-21.
8. Horn, M. B., & Staker, H. (2015). *Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools*. Jossey-Bass.
9. Kumar, V., Singh, A., & Patel, S. (2021). Virtual reality applications in Indian medical education: A review. *Indian Journal of Medical Research*, 153(4), 345-359.
10. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson Education.
11. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. *Teachers College Record*, 115(3), 1-47.
12. Mishra, P., & Sharma, D. (2023). Digital learning in India: Challenges and solutions. *Indian Journal of Educational Research*, 10(2), 78-92.
13. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. Norton.
14. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
15. Selwyn, N. (2011). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Publishing.
16. Sharma, A., & Gupta, R. (2020). Artificial intelligence in Indian education: Possibilities and challenges. *Indian Journal of Educational Technology*, 6(1), 22-38.
17. Singh, R., & Patel, A. (2022). Gamification in Indian schools: An empirical study on student engagement. *Journal of Interactive Learning Research*, 33(2), 150-170.

\*\*\*\*\*

## डाकघर की सुकन्या योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन इन्दौर जिले के सन्दर्भ में

डॉ. जे.के. जैन\* डॉ. पी.के. सन्से\*\* विभा सोहर\*\*\*

\* प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, महु, जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत  
\*\* प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, महु, जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत  
\*\*\* शोधार्थी (वाणिज्य) देवी आहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह योजना विशेष रूप से डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है। इस शोध पत्र में इन्दौर जिले के विभिन्न आय-वर्गों एवं सामाजिक समूहों में इस योजना की प्रभावशीलता, जागरूकता, लाभप्राप्ति, और इसके समक्ष चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है।  
**शब्द कुंजी** – डाकघर, सुकन्या समृद्धि योजना, सामाजिक जागरूकता।

**प्रस्तावना** – सरकारी योजनाएँ सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाती हैं। ये योजनाएँ देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं। इनमें से डाकघर की एक प्रमुख योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया। यह योजना विशेष रूप से लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

यह शोध पत्र इन्दौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के कार्यान्वयन, लाभ और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है ताकि योजना की प्रभावशीलता और उसमें सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण किया जा सके।

### अनुसंधान के उद्देश्य :

1. इन्दौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता की स्थिति का अध्ययन करना।
2. योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाभान्वित परिवारों की संख्या का मूल्यांकन करना।
3. योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझना।
4. योजना के दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन करना।

**अनुसंधान पद्धति** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक आकड़ों का उपयोग किया गया है।

**सुकन्या समृद्धि योजना का संक्षिप्त परिचय** – सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक उसके माता-पिता या अभिभावक उसके नाम से खाता खोल सकते हैं। यह खाता डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत

निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

1. न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वर्ष।
2. अधिकतम जमा राशि 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष।
3. खाते की परिपक्वता 21 वर्ष के बाद या बालिका की शादी के समय (18 वर्ष की आयु के बाद) तक लेकिन शादी की तारीख से 1 महीने से पहले या 3 महीने के बाद समापन की अनुमति नहीं है।
4. ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित, वर्तमान में ब्याज दर 8.2 प्रतिशत वार्षिक (01-01-2024 से) गणना वार्षिक आधार पर, चक्रवृद्धि वार्षिक।
5. कर लाभ इस योजना के अंतर्गत जमा राशि और अर्जित ब्याज पर कर में छूट मिलती है।

### तालिका- 1: सुकन्या समृद्धि योजना जमा राशि

क्र.	वर्ष	जमा राशि (करोड़ में)	आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी/वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में कमी/वृद्धि
1	2011-12	-	-	-
2	2012-13	-	-	-
3	2013-14	-	-	-
4	2014-15	13.53	-	-
5	2015-16	19.27	42.42	42.42
6	2016-17	44.26	227.12	129.68
7	2017-18	71.83	430.89	62.29
8	2018-19	92.58	584.26	28.89
9	2019-20	124.97	823.65	34.99
10	2020-21	140.53	938.65	12.45

स्रोत : इन्दौर सिटी डिवीजन

वार्षिक औसत वृद्धि दर 29.700 %

सुकन्या समृद्धि योजना में इंदौर जिले के लिए 2014-15 से 2020-21 तक जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014-15 में जमा राशि 13.53 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 140.53 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में 34.99% और 2020-21 में 12.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में वार्षिक औसत वृद्धि दर 29.70% रही, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना ने लोगों का विश्वास जीता है और बालिकाओं के भविष्य सुरक्षित करने के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हुई है।

## तालिका- 2: सुकन्या समृद्धि योजना

क्र.	वर्ष	खातों की संख्या (हजारों में)	आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी/वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में कमी/वृद्धि
1	2011-12	-	-	-
2	2012-13	-	-	-
3	2013-14	-	-	-
4	2014-15	6.50	-	-
5	2015-16	61.24	842.15	842.15
6	2016-17	68.75	957.69	12.26
7	2017-18	73.13	1025.08	6.37
8	2018-19	125.72	1834.15	71.91
9	2019-20	140.36	2059.38	11.64
10	2020-21	140.95	2068.46	.42

## स्रोत : इंदौर सिटी डिवीजन

### वार्षिक औसत वृद्धि दर 40.754 %

इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014-15 के बाद से खातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जहाँ 2015-16 में 61.24 हजार खाते दर्ज हुए और 2020-21 तक यह बढ़कर 140.95 हजार हो गए। आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि 2068.46% तक पहुंच गई, जबकि वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 40.75% रही। यह डेटा दर्शाता है कि योजना में निवेश और जनसंख्या की जागरूकता में निरंतर सुधार हुआ है।

### योजना के उद्देश्य:

1. लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना।
2. लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3. समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच किसित करना।

### सुकन्या योजना के लाभ/गुण:

1. आर्थिक सुरक्षा- बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
2. उच्च ब्याज दर - अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर मिलती है।
3. कर में छूट - जमा राशि और ब्याज पर कर लाभ मिलता है।
4. बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच - समाज में बेटियों के भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

**इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना का कार्यान्वयन**-इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार-प्रसार डाकघरों और बैंकों द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है, जहाँ शिक्षा

का स्तर और जागरूकता अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद, कुछ ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों में योजना के प्रति जागरूकता और पहुंच सीमित है।

1. जागरूकता कार्यक्रम-इंदौर जिले में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ सुकन्या समृद्धि योजना के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। स्कूलों, आँगनवाड़ियों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से बालिकाओं के माता-पिता को योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है।

2. खाता खोलने की प्रक्रिया-इंदौर में डाकघरों और बैंकों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन कभी-कभी दस्तावेजीकरण की समस्याएँ और तकनीकी अव्यवस्थाएँ सामने आती हैं। **लाभार्थियों की स्थिति** -इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हजारों खाते खोले गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अधिक होने के कारण लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण अपेक्षाकृत कम खाते खोले गए हैं।

### योजना के प्रति लोगों की जागरूकता:

1. इंदौर शहर में अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते हैं।
2. शहरी क्षेत्र - बैंकिंग सेवाओं की सुलभता और मीडिया के प्रचार-प्रसार के कारण जागरूकता अधिक है।
3. ग्रामीण क्षेत्र - पोस्ट ऑफिस तक पहुंच की कमी और जागरूकता अभियानों के अभाव के कारण योजना का क्रियान्वयन कमजोर है।

### सुकन्या योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन

#### सकारात्मक पहलू:

1. उच्च ब्याज दर - सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है।
2. कर लाभ - इस योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80उ के तहत कर में छूट मिलती है।
3. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा - लड़कियों की शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए एक निश्चित बचत का प्रावधान।
4. सरकारी गारंटी- यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम कम है।

#### नकारात्मक पहलू:

1. जागरूकता की कमी - ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है।
2. नकद जमा की आवश्यकता - डिजिटल लेन-देन की सुविधा सीमित होने के कारण कई लोगों को पोस्ट ऑफिस जाकर नकद जमा करना पड़ता है।
3. लंबी अवधि का लॉक-इन - खाता 21 वर्ष के लिए लॉक होता है, जो कई परिवारों के लिए असुविधाजनक है।
4. महंगाई का प्रभाव - भविष्य में महंगाई बढ़ने पर जमा की गई राशि की क्रय शक्ति कम हो सकती है।

**इंदौर जिले में योजना से संबंधित चुनौतियाँ**-हालाँकि सुकन्या समृद्धि योजना के कई लाभ हैं, लेकिन इंदौर जिले में इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी देखी गई हैं-

1. जागरूकता की कमी - ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में योजना के प्रति जानकारी का अभाव है।



2. तकनीकी समस्याएँ – डाकघरों और बैंकों में ऑनलाइन सेवाओं की कमी के कारण खाता खोलने में देरी होती है।
3. लिंग असमानता – कुछ समुदायों में अभी भी बेटों की तुलना में बेटियों को कम प्राथमिकता दी जाती है।
4. दस्तावेजीकरण की समस्याएँ – गरीब परिवारों में आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म की सही तारीख आदि का न होना एक बड़ी बाधा है।
5. डिजिटल सारक्षता की कमी – ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा का अभाव और डिजिटल साक्षरता की कमी से योजना का प्रचार-प्रसार सीमित हो रहा है।

#### समाधान और सुझाव:

1. जागरूकता अभियान – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, आँगनवाड़ियों और पंचायतों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. तकनीकी सुधार – डाकघरों और बैंकों में तकनीकी सुविधाओं में सुधार कर बढ़ावा दिया जाए।
3. महिलाओं की भागीदारी – महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना के प्रचार-प्रसार में शामिल किया जाए।
4. सरलीकृत प्रक्रिया – दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।

**निष्कर्ष** – सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण और दूरगामी सोच वाली योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह योजना इन्दौर जिले में बालिकाओं के उज्वल भविष्य के लिए एक प्रभावी पहल है। हालाँकि, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जागरूकता में वृद्धि, तकनीकी सुधार, और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों को सुलझा लिया जाए तो यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, एस. (2023), 'सुकन्या समृद्धि योजना : एक वित्तीय समावेशन पहल का विश्लेषण', इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 12(1), 45-60।
2. शर्मा, आर. (2022), 'भारत में बालिका सशक्तिकरण: नीतियाँ और प्रभाव', नई दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन।
3. यादव, पी. (2021), 'ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और बचत योजनाएँ', मुंबई: सामाजिक अध्ययन संस्थान।
4. मिश्रा, के. (2020), 'सामाजिक कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन: एक नीति विश्लेषण', वाराणसी: गंगा पब्लिकेशन्स।
5. सिंह, वी. (2018), 'महिला कल्याण योजनाएँ और उनका सामाजिक प्रभाव', पटना: राष्ट्रीय नीति अनुसंधान केंद्र।

\*\*\*\*\*

## स्वामी दयानंद सरस्वती के वैचारिक आंदोलन का भारतीय शिक्षा नीति पर प्रभाव

हीरा लाल अहीर\* डॉ. राखी शर्मा\*\*

\* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत  
\*\* सह-प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – स्वामी दयानंद सरस्वती वह महान संत थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और तमाम प्रकार के आडंबरों का डटकर विरोध किया। उन्होंने हमेशा ऐसे अमानवीय आचरण के विरुद्ध आवाज उठाई जो समाज के विकास में बाधक थे। स्वामी जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और हिन्दू धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन महान कार्यों के लिए भारतीय समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा।

स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के प्रयासों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उनके विचारों और कार्यों को समझने के लिए विभिन्न रचनात्मक पहलुओं को समग्र रूप से शामिल करते हुए इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया गया है।

**शब्द कुंजी** – स्वामी दयानंद सरस्वती, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता।

**प्रस्तावना** – स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख पुरोधा थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के विरुद्ध अपने जीवन को समर्पित किया। उनका जन्म सन् 1824 में गुजरात के टंकरा नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में उनका नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद का प्रारंभिक जीवन धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण था, और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा में प्राप्त की।

स्वामी दयानंद ने स्वामी विरजानंद के सांख्यिक में वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत, अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञानता को दूर करने के लिए देशभर में भ्रमण किया। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि समाज रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण पतन की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने सन् 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रसार करना था। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने समाज को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क पर आधारित जीवन जीने का संदेश दिया। उनका योगदान भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### अध्ययन के उद्देश्य:

1. स्वामी दयानंद सरस्वती के पुनर्जागरण में योगदान का गहनता से अध्ययन करना।
2. सामाजिक कार्यों के माध्यम से मानव कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन करना।
3. स्वामी दयानंद के जनकल्याणकारी कार्यों का समाज पर क्या असर पड़ा, इसका अध्ययन करना।

4. स्वामी दयानंद के विचारों का भारतीय समाज में जागरूकता और बदलाव के संदर्भ में अध्ययन करना।

**शोध-प्रविधि** – प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक विश्लेषण एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें शोध सामग्री का संकलन प्रमुख ग्रंथों, पुस्तकों एवं विश्वसनीय स्रोतों से किया गया है। वस्तुतः यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को गहराई से समझा और अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। उनके शिक्षा संबंधी विचारों का विस्तार से उल्लेख उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' के द्वितीय और तृतीय समुल्लास में मिलता है। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का एक प्रभावी माध्यम बताया और इसे राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी माना।

स्वामी दयानंद का मानना था कि व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि व्यक्ति का समग्र विकास हो जाए, तो समाज का विकास स्वतः ही संभव है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुँचाना आवश्यक है। उनके अनुसार, माता-पिता, शिक्षक और समाज का यह दायित्व है कि वे बच्चों को ज्ञान, अच्छे संस्कार और सद्गुण प्रदान करें ताकि वे समाज के लिए उपयोगी बन सकें।

स्वामी दयानंद ने शिक्षा को समाज और राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व बताया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बालक को उचित शिक्षा मिले। उन्होंने अपने ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में

उल्लेख किया कि माता-पिता को अपने बच्चों को पांच से आठ वर्ष की आयु के बीच विद्यालय अवश्य भेजना चाहिए। स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि जो माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का महत्व हर व्यक्ति समझे और समाज में निरक्षरता समाप्त हो सके।

स्वामी दयानंद ने शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखते हुए इसे समाज सुधार का महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति के चरित्र निर्माण और नैतिक उत्थान का आधार माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, संस्कारवान और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

स्वामी दयानंद ने बालक-बालिकाओं दोनों के लिए समान शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उस समय समाज में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, जिसे उन्होंने समाज के पतन का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। स्वामी जी के अनुसार, जो लोग स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, वे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

स्वामी दयानंद ने वैदिक काल के उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थीं। उन्होंने गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और कात्यायनी जैसी विदुषियों का उल्लेख किया, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की थीं। स्वामी दयानंद का मानना था कि यदि स्त्री शिक्षित होगी, तो परिवार और समाज का विकास तेजी से होगा। उनके इन विचारों से प्रेरित होकर महात्मा मुंशीराम और लाला देवराज जैसे आर्य समाज के नेताओं ने कन्या पाठशालाओं की स्थापना की, जिससे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला।

स्वामी दयानंद ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए आर्य समाज के 28 नियमों में आर्य विद्यालयों की स्थापना को विशेष स्थान दिया। उन्होंने इन विद्यालयों में वेदों और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बनाया ताकि विद्यार्थियों को सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा के उद्देश्यों में अनाथ और निर्धन बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति को रोजगार दिलाना नहीं, बल्कि उसे ऐसा नागरिक बनाना है जो अपने कर्तव्यों को समझे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। उनके विचार शिक्षा को व्यक्ति के समग्र विकास का आधार मानते हैं, जो आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है।

स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी विचारों ने भारतीय समाज में जागरूकता और सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से न केवल शिक्षा का प्रसार हुआ, बल्कि समाज में व्याप्त अज्ञानता, कुप्रथाओं और अन्याय के खिलाफ एक नई चेतना का संचार

हुआ। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था, जो ज्ञान, नैतिकता और मानवता के मूल्यों पर आधारित हो।

**निष्कर्ष** - महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी साधन माना। उन्होंने मंदिर निर्माण, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर अनावश्यक खर्च को हतोत्साहित करते हुए उस धन को शिक्षा के प्रसार में लगाने का परामर्श दिया। उनका विश्वास था कि समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़ियों का समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

स्वामी दयानंद का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को सही-गलत का निर्णय करने की समझ प्रदान करती है। शिक्षा ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाती है। ज्ञान ही वह साधन है जो मनुष्य को जीवन में सफल बनाकर उसे समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। स्वामी दयानंद के अनुसार, शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे। उन्होंने अपनी रचना 'सत्यार्थ प्रकाश' में शिक्षा पद्धति का विस्तार से वर्णन करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या का अर्जन न होकर समाज में नैतिकता, सद्भावना और सेवा के संस्कार उत्पन्न करना भी होना चाहिए।

महर्षि दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार आज भी समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका शिक्षादर्शन व्यक्ति के समग्र विकास, समाज के सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. संपादक, पं. भगवद्गता, सत्यार्थ प्रकाश, प्रथम संस्करण, सरस्वती भवन प्रकाशन, दिल्ली, 2012.
2. पराशर, संदीप, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रथम संस्करण, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, 2005.
3. भाटिया, सुदर्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रथम संस्करण, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली, 2004.
4. मित्तल, डॉ. सतीश चंद्र, भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास, प्रथम संस्करण, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2005.
5. दास, एम.एन., पुरी, बी.एन., चोपड़ा, पी.एन., भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास (खंड 3), प्रथम संस्करण, सागर पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1975.
6. शर्मा, रामकिशोर, दयानंद और भारतीय समाज सुधार आंदोलन, प्रथम संस्करण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2010
7. अग्रवाल, महेश चंद्र, भारत में आर्य समाज का प्रभाव, प्रथम संस्करण, जयपुर, राजस्थान प्रकाशन मंडल, जयपुर, 2013
8. त्रिपाठी, हरिनारायण, महर्षि दयानंद के समाज सुधार कार्य, द्वितीय संस्करण, लखनऊ, साहित्य भवन प्रकाशन, 2011



## नवीकरणीय ऊर्जा : भविष्य की आवश्यकता

प्रो. रेणुका पाटीदार\*

\* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरुलाल पाटीदार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु, जिला इंदौर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों को अपने विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम इसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, आप देखते हैं कि कपड़े से लेकर भोजन तक जो कुछ भी आप उपयोग करते हैं, वह सब हम पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से प्राप्त करते हैं। दैनिक मानवीय गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन हैं। हालाँकि, इन संसाधनों का उपयोग करने से हमारे आस-पास का वातावरण भी प्रभावित होता है। इस प्रकार, आप देखते हैं कि हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख संसाधन हैं। प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होने वाला कोई भी स्थाई ऊर्जा स्रोत एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है और लगातार पुनः भरती रहती है। ये स्रोत लगातार नवीकृत होते रहते हैं और खत्म नहीं होते। चूँकि विश्व स्तर पर धारणीय सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। अतः यह नवीकरणीय ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए सतत विकास के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण संसाधन की भूमिका निभाती है। इस शोध पत्र में हम नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार, उसके साधन एवं महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे।

**शब्द कुंजी** – सतत विकास, आर्थिक विकास, प्रदूषण, संयुक्त राष्ट्र संघ।

**प्रस्तावना** – किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आवश्यक संसाधन है। बिना ऊर्जा के कोई भी देश आर्थिक विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विकास की होड़ में पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ है। नतीजतन इन संसाधनों की कमी होती चली गई और मनुष्य को ऐसे संसाधनों की जरूरत महसूस हुई जो प्रकृति की रक्षा करते हुए एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की बचत करते हुए विकास में भागीदार बने। चूँकि चिंता पूरे विश्व की थी अतः साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण सम्मेलन हुआ। जिसमें धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया गया। इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना एवं विश्व के सामने आने वाली तत्काल पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना। 14 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक धारणीय विकास लक्ष्य के 17 ऐसे पक्षों को अपनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। वास्तव में धारणीय विकास सम्पूर्ण विश्व में मानवीय गरिमा, समृद्धि, जैव मण्डल के संरक्षण तथा शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करना बहुत कठिन है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में भारत की मुख्य समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, खाद्यान, शहरों का बुनियादी विकास, ऊर्जा स्रोतों का संतुलित प्रयोग, गरीबी उन्मूलन, असमानता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, इसलिए यह भारत के लिए सामाजिक विकास का सुनहरा अवसर भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 लक्ष्यों में से सातवा लक्ष्य सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। सन 1990 से 2010 के बीच बिजली तक पहुँच रखने वाले लोगों की संख्या में 17 बिलियन

की वृद्धि हुई है और जैसे-जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे सस्ती ऊर्जा की माँग भी बढ़ती जा रही है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हमारे जलवायु तंत्र में भारी बदलाव ला रही है। इसका हर महाद्वीप पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया अभियान चलाया गया है, जो अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सन 2011 में अक्षय ऊर्जा से वैश्विक बिजली उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी थी जिसमें लगातार वृद्धि हुई है।

**नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख प्रकार** – नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनमें समय के साथ फिर से भरने की शक्ति होती है। ये मूलतः पाँच हैं। वे सौर, पवन, बायोमास, भूतापीय और जलविद्युत हैं। वे असीमित हैं और हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते।

**सौर ऊर्जा** – हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। हम इस ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे गर्मी और बिजली में बदल सकते हैं। हमारे लाभ के लिए इसका उपयोग करने के अन्य उपयोगी तरीके भी हैं। हालाँकि, सूर्य हमेशा दिखाई नहीं देता है, फिर भी, हम दिन के समय सौर पैनलों के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं।

इससे बिजली की बहुत बचत होगी। सौर ऊर्जा भविष्य है जिसे सभी को अपनाना चाहिए। यह बहुत किफायती भी है। इसके अलावा, यह छोटे समुदायों को बिजली देने के लिए भी पर्याप्त है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) के अनुसार, भारत के भूमि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन-घंटे ऊर्जा प्राप्त होती है और अधिकांश भाग प्रतिदिन 4-7 किलोवाट-घंटे प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित

किया जाता है। पूरे देश की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ही पर्याप्त है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के अनुमान के अनुसार, 3 प्रतिशत बंजर भूमि क्षेत्र को सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से कवर किये जाने से लगभग 748 गीगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती है। जो भारत सरकार द्वारा लक्षित 100 गीगावाट से कहीं अधिक है।

‘सौर ऊर्जा न केवल वर्तमान में बल्कि 21वीं सदी में ऊर्जा जरूरतों का एक प्रमुख स्रोत बनने जा रही है क्योंकि सौर ऊर्जा निश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है।’ - प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी

**जल ऊर्जा** - जल ऊर्जा से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसे हम बहते पानी की गतिज ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। पानी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है इसलिए बहते पानी का वेग बहुत अधिक होता है। इस प्रकार, इस वेग का उपयोग करके ऊर्जा बनाई जा सकती है।

हालाँकि, सूर्य के प्रकाश की तरह ही, किसी क्षेत्र में बहता पानी अप्रत्याशित होता है। फिर भी, हम इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाँध और कृत्रिम झीलें जरूरत के समय हमारी कई बार मदद करती हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा किये गए आकलन के अनुसार, भारत में 1,48,700एम.डब्ल्यू. की आर्थिक रूप से दोहन योग्य पनबिजली क्षमता है। यदि 94,000एम.डब्ल्यू. के पंप स्टोरेज की संभावित क्षमता में छोटी, लघु और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 6700एम.डब्ल्यू. की संभावित क्षमता को शामिल किया जाए तो भारत की जलविद्युत क्षमता लगभग 2,50,000एम.डब्ल्यू. होगी। ऐसे में देखा जाए तो लंबे समय तक टिके रहने, कम लागत और उच्च दक्षता के साथ-साथ कई अन्य लाभों के बावजूद वर्तमान में इसके 30 प्रतिशत से भी कम का दोहन किया गया है। ऐसे में इसका समुचित दोहन कर 5 गीगावाट से कहीं अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

**पवन ऊर्जा** - पवन ऊर्जा एक बेहतरीन नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब है हवा को दिशा में घुमाना जो ऊर्जा बनाने में मदद करता है। हम पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यह बहुत किफायती भी है।

हालाँकि, सौर ऊर्जा की तरह ही, हवा के पैटर्न का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, यह कभी-कभी ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन, यह अभी भी एक बढ़िया विकल्प है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एन.आई.डब्ल्यू.ई.) द्वारा किये गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि सात राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पवन से बिजली उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है। भूमि सतह से 100 मीटर ऊपर (ए.जी.एल.) इन सात राज्यों की पवन ऊर्जा क्षमता 293 गीगावाट है और 120 मीटर ए.जी.एल. पर क्षमता 652 गीगावाट है। जो भारत सरकार द्वारा लक्षित 60 गीगावाट से कहीं अधिक है। ऐसे में सरकार त्वरित मूल्यहास लाभ के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करके पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है।

अगर देखा जाए तो 7500 किमी. लंबी तटरेखा का प्राकृतिक लाभ होने के कारण भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन करने की अपार क्षमता है। इस अपार संभावना का लाभ उठाने हेतु भारत सरकार ने वर्ष

2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अधिसूचित किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जे.टी.) में अपतटीय पवन ऊर्जा अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

**जैव ईंधन** - जैव ईंधन को बायोमास भी कहा जाता है। वे नवीकरणीय ऊर्जा के एक विविध और तेजी से बढ़ते रूप को दर्शाते हैं। हम जीवित चीजों से कई सामग्रियों को ऊर्जा में बदल सकते हैं।

उदाहरण के लिए, हम सड़ते हुए पौधों, कचरे, खाद और यहाँ तक कि सीवेज का भी उपयोग कर सकते हैं। ये ईंधन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, यह कचरे के उचित निपटान में भी मदद करेगा। वर्तमान समय में इथेनॉल और बायोडीजल उपयोग में आने वाले सबसे प्रमुख जैव ईंधन में से हैं। इस दिशा में भारत सरकार जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के माध्यम से सकारात्मक प्रयास भी कर रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत और डीजल में 5 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य के साथ जैव ईंधन के प्रसार में गति लाना है। ऐसे में जैव-ईंधन तेल आयात पर निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।

**महासागर और भूतापीय ऊर्जा** - हम इस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। यह ऊष्मा ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से निकलती है। यह बहुत ही विश्वसनीय है और हम इसे स्थानीय स्तर पर आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए, हम इसे बहुत ही लागत प्रभावी विकल्प के रूप में देखते हैं।

दूसरे शब्दों में, ऊष्मा पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के मेटल तक जाती है। इसके परिणामस्वरूप गर्म भूमिगत झरने बनते हैं। इसी तरह, हम इस ऊष्मा का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार, भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन के लिए एक बहुत ही उचित विकल्प है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महासागर धरातल का 70 प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं और ज्वार ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा आदि रूप ऊर्जा की एक विशाल राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समुद्र और महासागरों की ऊर्जा क्षमता हमारी वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। आँकड़ों के अनुसार, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के लिये अनुमानित ऊर्जा क्षमता क्रमशः 12,455एम.डब्ल्यू. और 41,300एम.डब्ल्यू. है। ऐसे में इन ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम दोहन हेतु विभिन्न तकनीकों का विकास किया जा रहा है।

जबकि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भू-पृष्ठ में संग्रहित ऊष्मा के स्रोत के रूप में होती है, जो सतह पर गर्म स्रोतों के रूप में निकलती है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने अनुमान लगाया है कि भू-तापीय ऊर्जा से संभावित 10 गीगावाट बिजली क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

**हरित हाइड्रोजन**- यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत-अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस दिशा में ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक ‘हरित हाइड्रोजन हब’ बनाना है जो वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

**भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास-** भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन तथा वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 500 जी.डब्ल्यू. तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। जिसे प्राप्त करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे- राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, सूर्यमित्र कार्यक्रम, सौर ऋण कार्यक्रम, पी.एम. -कुसुम योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, सौर पार्क योजना, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) योजना, हाइड्रोजन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा बजट 2022-23 में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा दक्षता, विद्युत गतिशीलता, भवन निर्माण दक्षता, ग्रिड से जुड़े ऊर्जा भंडारण और हरित बॉण्ड के लिये कई घोषणाएँ कीं जो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभाएंगी।

ऐसे में अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी अहम है। आज आवश्यकता है कि भारत दूसरे देशों के लिये अक्षय ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति का एक स्रोत बने। उपर्युक्त विवरणों के आधार पर यह कहना अतिशयक्ति नहीं होगा कि यह क्षमता भारत में सुनिश्चित की जा सकती है और इसका व्यापक लाभ हम कई आयातों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

#### **नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व :**

1. नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है वस्तुतः पृथ्वी इनका प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण करती रहती है। ये पृथ्वी पर असीमित मात्र में उपलब्ध हैं तथा प्रदूषण रहित होने के कारण पर्यावरण हितैषी हैं।
2. नवीकरणीय ऊर्जा से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है जलवायु परिवर्तन को कम करती हैं।
3. नवीकरणीय ऊर्जा आर्थिक विकास को बढ़ाती है।
4. नवीकरणीय ऊर्जा से आयात पर निर्भरता कम होती है।
5. नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में विविधता लाती है।
6. नवीकरणीय ऊर्जा से जीवाश्म ईंधनों की अप्रत्याशित मूल्य उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।
7. नवीकरणीय ऊर्जा की लागत गैर-नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में कम होती है।
8. नवीकरणीय ऊर्जा गरीबी उन्मूलन में मदद करती है नवीकरणीय ऊर्जा से समावेशी आर्थिक विकास होता है।
9. नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनते हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
10. नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की अपेक्षा सस्ते एवं अधिक वहनीय हैं।
11. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही भविष्य के ऊर्जा संसाधन है जो किसी भी राष्ट्र के धारणीय विकास को सुनिश्चित करेंगे।
12. यह धारणीय विकास लक्ष्य (एस डी जी ) -7 'स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा' के अनुकूल है।
13. चूँकि भारत कर्क रेखा पर अवस्थित है अतः भारत के अधिकांश भागों में वर्षभर सौर प्रकाश उपलब्ध रहता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।

#### **नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ:**

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इसमें न्यूनतम या लगभग शून्य कार्बन व ग्रीनहाउस उत्सर्जन होता है। जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीनहाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं।
2. नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा असीमित होती है। इसलिये इसे ऊर्जा का स्थायी स्रोत भी माना जाता है, जबकि जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।
3. नवीकरणीय ऊर्जा रोजगार सृजन में भी सहायक है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वॉटर (सी.ई.ई.डब्ल्यू.) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 100000एम.डब्ल्यू. सौर ऊर्जा और 600000 एम.डब्ल्यू. पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य से लगभग 13 लाख (1-3 मिलियन) प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
4. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करेगा। इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफी स्थिरता भी आएगी।
5. डब्ल्यू.एच.ओ. की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खाना पकाने में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल की वजह से हर साल 5 लाख मौतें हो रही हैं। ऐसे में अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
6. डब्ल्यू.एच.ओ. एस.डी.जी.की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से महिला सशक्तीकरण व लैंगिक समानता (एस.डी.जी.-5) में भी वृद्धि देखने को मिली है।
7. अक्षय ऊर्जा स्रोत ही भविष्य के ऊर्जा संसाधन हैं जो किसी भी राष्ट्र के धारणीय विकास (एस.डी.जी.-7 - स्वच्छ एवं वहनीय ऊर्जा) को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो भारत पवन ऊर्जा क्षमता व सौर ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। देश में नवंबर 2022 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 42 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल की जा चुकी है और इस दिशा में सरकार निरंतर आवश्यक कदम भी उठा रही है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बन रही हैं।

#### **नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियाँ:**

1. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में अभी भी नए अनुसंधान, आधुनिक विकास सुविधाओं तथा बुनियादी ढाँचे की कमी है।
2. भारत, नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण अनिवार्य रूप से चीन, जर्मनी आदि देशों से आयात करता है। ऐसे में प्रणाली लागत में वृद्धि की समस्या इस दिशा में एक गंभीर चुनौती है।
3. शुरुआत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना हेतु निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसे में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता संस्थाओं तथा आम जनमानस दोनों को हतोत्साहित करती है।
4. हमारे देश में अधिकांशतः अच्छी योजनाएँ राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव में दम तोड़ देती हैं। ऐसे में इस दिशा में भी भूमि अधिग्रहण की समस्या, सरकारी अनुमोदन मिलने में देरी, सामग्री आपूर्ति सीमा आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
5. अक्षय ऊर्जा हेतु आज भी हमारे देश के बैंकों में सुविधाजनक ऋण सुविधा का अभाव है, जिसके कारण इसका लाभ आम जनमानस

आसानी से नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

6. इस संदर्भ में आज भी आम जनमानस के बीच जागरूकता की कमी है, जिसके कारण अक्षय ऊर्जा को अपनाने की गति धीमी है।

ऐसे में उपर्युक्त चुनौतियों को दूर करने के साथ ही ग्रीन फाइनेंसिंग एक्सप्रेस, हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन तथा राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु लोगों, परिवारों, समुदायों, संगठनों, सरकार और अन्य हितधारकों को प्रासंगिक स्तरों पर शामिल किया जाना चाहिये ताकि इस दिशा में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके।

इस प्रकार दुनिया की लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग समय की मांग है और यह अनिवार्य भी है कि अधिकांश नई ऊर्जा की मांग को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाए।

**सारांश** - संपूर्ण मानव समाज की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में ऊर्जा एक इंजन का कार्य करती है। हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2040 तक देश में बिजली की खपत 1280 टेरावाट प्रति घंटा हो जाएगी। ऐसे में सीमित जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत हमारी भविष्य की इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। देश की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर विशेष

ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसलिए प्रकृति प्रदत्त नवीकरणीय उर्जा संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की जरूरत है और इन संसाधनों के विकास के लिए उन्नत तकनीक को विकसित करने की बड़ी चुनौती दूसरी अन्य चुनौतियों के साथ अभी भी मुँह बाहे खड़ी है। हालाँकि मानव ने हमेशा हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है और उस पर विजय पाने में हमेशा सफल भी रहा है।

‘अब समय आ गया है कि हम अपने ग्रह को जलाना बंद करें और अपने चारों ओर प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना शुरू करें।’ (एंटोनियो गुटेरेस, यू.एन. महासचिव)

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियाँ और समाधान (2024) पीटर यांग द्वारा।
2. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और जलवायु परिवर्तन शमन (2011) आईपीसीसी द्वारा।
3. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा सौर ऊर्जा परिप्रेक्ष्य (2011)।
4. वैकल्पिक उर्जा : राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक - क्रिस्टोफर ए. साइमन द्वारा ।
5. <http://www.drishtiiias.com>
6. <http://www.eia.gov>
7. <http://www.un.org>
8. <http://www.india.gov.in>
9. <http://www.akshayurja.gov.in>

\*\*\*\*\*

# Digital Farming: New Perspective in Agricultural Development

Dr. Kumud Dubey\* Dr. Avinash Dube\*\*

\*MLC Govt. Girls P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

\*\* S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

**Abstract :** Digital farming combines farmers knowledge with new age technologies. It is the use of technology to improve crop quality and yields. It provides necessary resources, knowledge and skills for farmers to grow crops with proper management of natural resources. Technology has a major role in farming and agriculture practices and with the advent of digital technology, the scope has widened. The more digital farming is adapted the more precise farming can be, which helps to more efficient use of raw material.

**Introduction** - Agriculture is one of the major sectors in India that provide livelihood to a people. The majority of Indian population depends on agriculture as it is the major source of income. It is the oldest practice in the history of mankind. There has been tremendous growth and evolution in the field of agriculture.

Agriculture is important for more than just food production. It supplies raw materials to business including textiles, medicines and biofuels. Agriculture in India is largely dependent on nature, but climate and global warming issue make farming unpredictable. The need of the hours is to educate farmers in the use of modern technology and innovative approaches to increase productivity and raise profitability. Technology has a major role in farming and agriculture practices and with the advent of digital technology, the scope has widened. The use of modern technology has helped farmers to increase the production of crops and livestock.

The use of new technologies has also reduced the cost of production. The adaption of new technology has also led to the development of new methods of marketing and also created new jobs in agriculture sector. The present study deals with new technologies applied in farming sector. Availability of smart and digital apparatus make the farmer more aware with their job so that they can achieve their best in terms of production and also with environment conservation.

## Digital Farming can help farmers by:

1. Improve crop yield and quality- By making more information about planting new varieties, fertigation, pest control.
2. Save time and money- By using resources more efficiently.
3. Conserve Inputs: By applying resources precisely.

4. Reduce waste: Precise application of resources.
5. Improve compliance: By ensuring compliance with food standards and nutrition tracking.

**Principles of Digital farming:** Principles of digital farming includes:

1. Precision farming: Providing crops and soil with the exact amount of water, nutrients and pesticides they need.
2. Robotics: Using autonomous tracks and drones to improve logistics and data collection.
3. Data- analysis: Using big data analysis and remote sensing to improve farm management.
4. Artificial Intelligent: To predict genetic outcomes and plant breeding innovations.
5. Internet of things: To connect farmers directly to consumers.

## Emerging Techniques for Digital and Smart Farming:

**Digital farming apps:** These apps can help farmers make informed decisions in real time by providing a range of features. These include-

1. Agrimarket: It provides the market price of crops in markets within 50 km of the users location. It uses the users mobile GPS to automatically capture their location.
2. Agribegri: It is a farming market place app that advice farmers.
3. Pusa Krishi: This app provide information about technologies developed by the IARI ( Indian Agriculture Research Institute).
4. Agrivi: This help agrarians manage their enterprises by tracking field activities, controlling product quality and checking compliance with standards.
5. IFFCO Kissan App: It provides customized information to Indian farmers make more informed decisions.



6. De- Haat Farmer App: It is a one step platform that provides multiple services as frequent crop reminders, voice calls in regional languages, crop advisories, weather report, local mandi rates.
7. MP KISAN App: For farmers of MP, provides information on crop insurance claim calculation and future insurance premiums.
8. Agri setu: Knowledge and experience sharing platform for farmers, experts, suppliers and Buyers.
9. AgriCentral: A technology based app helps to make better decisions and increase profitability.

Apart from these Many more apps like Cropin Grow ,PM Kisan GOI,ICT 4 farmers , Ag Assist, My Cattle Manager , KISAN,Meghdoot, Mobi Agri, Boomitra Farmer ,Crop Survey,CIC Digital AgriHub, Digitalani Farmer ,Agriappare there which can serve for the betterment for Agriculture.

**Soil Sensors:** Nature of soil plays crucial role for farmers. By knowing the nature of soil farmer can enhance production and quality of products. Now a days various types of Soil Sensors are available by which one can know about Soil pH, Soil Temperature and humidity, Soil moisture etc.

**Remote Sensing tools:** Remote sensing tools are another add to help farmers. A small amount of wavelength from electromagnetic spectrum are used in remote sensors having application for agriculture purpose. The energy coming to plants in form of electromagnetic wave can be reflected, absorbed or transmitted by the plant. The reflection, absorption and transmission depends on the nature of plant and wavelength of energy. Remote sensing tools helps farmers in monitoring crop, monitoring water conditions, predicting weather condition, observing soil and air quality.

In addition to above tools devices like food sensors, Guidance and Tracing system, Variable rate input technology, Automatic section control, Automatic machinery and agriculture Robots, Drones can serve crucial role in farming digitalization.

By making use of new farming techniques farmer can achieve optimal crop development.

**Digital Farming in Indian Context (Our Region):** Digital agriculture has to be customized to be applicable to a typical Indian small farm if we want digital agriculture to be suitable and be available to a majority of Indian farms.Precise financial estimates of the cost of the technology per unit of land, per individual farmer and corresponding savings and return on investments are not available yet in Indian context. Thus, for digital agriculture to succeed in urban areas of India, the innovations must focus on low cast technology, easily portable hardware, policy renovations towards

facilitating digital agriculture, renting and sharing platforms for agriculture equipment and machinery.In order to ensure its widespread adoption, the entire value chain will need to work together and come to an agreement on how to address these issues.

To promote digitization in agriculture, Digital agriculture Mission was launched in September 2024 by Govt. of India. In our area digital farming is steadily progressing with government actively promoting the use of technologies like GIS, remote sensing, digital platforms for market assessment and crop advisory services.

Some areas where progress is being made are pilot projects are implemented in certain districts to introduce precision farming practices, crop insurance registration is linked with land records and trainings to educate farmers on using digital tools and platforms. During interaction with farmers of Nimar and Malwa region it is found that the use of digital tools are not so common although they are using apps like *Damini* and social media platform.

Simultaneously some challenges, as not all farmers are comfortable using digital tools, and uneven internet connecting in rural areas, accurate data collection for local area are existing which require continued efforts and ensure equitable access to digital technologies for all farmers.

**Conclusion:** Digital agriculture is ICT and data ecosystem to support the development delivery of timely targeted information and services to make farming profitable, sustainable, delivery safe, nutrients and affordable food for all.Since farmlands varies in different areas a “one size fits all” management approach won’t work for every farmer. The digital transformation of agriculture has the potential to benefit all farmers independent of size. Not all digital tools benefit all farmers equally but they open the door for a more diverse offering of tailored solutions to bring the most possible benefit to each farmer and each field. As the agriculture is the foundation of civilization and stable economy. We can say that to get more precise farming it is needed to adopt more digital farming.

**References: -**

1. Beriya Abhishek (2020), Digital Agriculture: Challenges and possibilities in India, CSD working paper series.
2. Mahindru T. (2019), Role of Digital and AI technologies in Indian agriculture: Potential and way forward, NitiAyog, Govt. of India.
3. Narendra V. N. etal. (2019), Digital Agriculture, Bulletin of Environment, pharmecology and life- Science, vol. 8(6), May, pp 164-170.
4. Roy P. &Saha P. (2022), Digital agriculture, the future of Indian farming., food and scientific report, pp 10-14.



# Digital Data Protection and Artificial Intelligence: A New Era in the World

Deepika Joshi \*

\*Research Scholar (Computer Science and I.T.) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University,  
Udaipur (Raj.) INDIA

**Abstract :** The modern world is encountering new challenges, and the nature and forms of crime have transformed. Where earlier physical conflicts dominated criminal activities, today, online and digital platforms have taken their place. Most work is now conducted digitally. All government schemes are being provided online, which requires individuals to share their personal information. At the same time, the use of social media compels people to disclose much of their private information voluntarily. However, uploading personal data on social media always carries a risk of misuse. In the present times, digital data is considered the new gold, and the importance of data security is increasing globally. European countries have already implemented strict data protection laws. India is also advancing towards this direction. The introduction of artificial intelligence has brought a modern revolution that has significantly impacted various fields. Every sector is striving to make use of artificial intelligence, highlighting its importance in development. The primary objective of artificial intelligence is to make human life easier and to facilitate operations efficiently. This research paper will discuss the significance and need for digital data protection and how artificial intelligence plays a role in regulating it. It will also examine the current data protection laws and how artificial intelligence contributes to legal frameworks for data security.

**Introduction** - Human rights are not only necessary but also extremely important for an individual's independent and dignified way of life. Without them, one cannot even imagine living as a human being. If these rights include personal identity and biometric data, they become even more significant. The Universal Declaration of Human Rights (1948) under Articles 8, 12, 17, 18, 19, and 28 is associated with these rights. At the national level, Articles 19 and 21 of the Indian Constitution also pertain to such rights. The Supreme Court has elaborated on these rights through various judgments. In the Aadhaar card case, *Puttaswami (R) vs. Union of India* (2017) 10 SCC, privacy was declared a fundamental right. Human rights are ethical principles that establish certain standards of human behavior. These rights are recognized separately from national and international laws. They are considered "inalienable" rights, meaning they are inherent to humans from birth and remain with them even after death. They are not influenced by a person's age, place of residence, language, or other factors. In this era of modern technology, any individual's information can reach any corner of the world in an instant. A person's personal information may be misused, leading to violations of human and fundamental rights. The issue of data protection was raised in the Indian Parliament in September 2023.

**Institution Made Stricter:** The institution was made stricter, following the recommendations of the Krishna Committee. However, this issue becomes significant only when discussions about data collection are held for a limited period. However, human rights organizations do not consider it a violation, as the European Union has already established a special law for data collection. Hence, it is seen as a necessary process, but its implementation remains incomplete. India is one of the 27 countries worldwide where individuals are considered guilty of data theft and misuse. The collection of personal data in India is included in the list of potentially harmful activities.

Since the year 2000, information technology has been made stricter, which has led to increased cyber security measures over the last few years. However, business activities related to data protection have not been fully regulated. The Indian government passed the **Personal Data Protection Bill 2023**, which includes regulations on listening to personal data. However, the law is still unclear on some aspects and does not entirely prohibit violations of human rights.

**European Union's Data Protection Regulation Law 2016:**

1. This law will create new international standards, particularly for the protection of online information on platforms such as Facebook, and will address data

breaches.

2. Due to this new law, the European Union will once again establish control over its data.
3. The European Union has imposed penalties of up to 20 million euro's (24 million dollars) or 4% of the company's annual global revenue for data misuse by companies.
4. This law legally ensures that individuals must be clearly informed about how their data will be used and must give their consent for its usage.

**Statistics: The Constitution of Human Rights** in Article 3 recognizes the importance of digital data protection, aligning with the **Universal Declaration of Human Rights in 1948**.

1. When rights are linked to personal digital data, they become as crucial as the right to property in a traditional sense.
2. With the advent of modern technologies, digital data has become extremely valuable today.
3. Compared to European countries, India lacks stringent digital data laws, leading to increased violations of privacy rights.
4. According to NCRB data (December 2023), 65,893 cybercrimes were registered in India in 2022, marking a 24.4% increase compared to 2021.
5. According to IBM cyber security reports, on average, a cybercrime occurs every 39 seconds, affecting around 2,200 people globally.
6. The Cyber Security Annual Report 2023 highlights an increase in the number of phishing incidents in the Netherlands.
7. Data security issues were not addressed in educational policies.
8. In 2021, the Indian government failed to implement a national cyber security framework.
9. In 2021, there were 7,867 data breaches in India.
10. India lacks a well-established policy on data collection and its use.

**Significant Decline in Data Protection:** Major data breaches in the world:

1. The largest attack in Paris
2. Inadequate data protection laws - European Union, Iceland
3. Lack of data protection laws - Malaysia, Nauru

**Other Countries' Laws:**

1. GDPR (General Data Protection Regulation) is the data and privacy protection law of the European Union.
2. It holds a rightful place in human rights concerning data privacy issues.
3. It regulates the collection and use of personal data.
4. It mandates the security of stored data.
5. It allows individuals to control their personal data.
6. It gives people the right to amend and update their information.
7. It provides legal provisions for the excessive collection

and misuse of data.

8. In 2020, Article 30 of the GDPR gave rise to the "Right to be forgotten".

**USA**

1. The USA does not have a uniform federal data privacy law, but it does cover health data, financial data, etc.

**Switzerland**

1. The data law guarantees the right to privacy.
2. Data processing without an individual's consent is restricted.

**Britain**

1. The Cyber Crime Act is the strictest in the world.
2. Storing any person's computer information illegally can result in 6 months in jail and a £70 fine.
3. Unauthorized data usage is a criminal offense.

**Canada**

1. Data must be stored in an encrypted form.
2. It is necessary to report if data is lost or leaked.

**Importance of Data Ethics**

Aspect	Description
Consent	Information Confidentiality
Security	Data Processing
Citizen Rights	Commercialization
Web User Assistance	Sending Commercial Messages

**Key Points of the Personal Data Protection Act, 2003**

1. This law applies to the storage of personal digital data.
2. The user must be informed about how their data will be used. If the data is transferred to goods or services outside India, consent is required.
3. Special permission is needed for processing sensitive data, and it should not be used for unauthorized purposes.
4. Organizations must keep personal data accurate, secure, and up-to-date, and delete data once the purpose is fulfilled.
5. Individuals have the right to access, modify, and delete their personal data.
6. If data privacy is violated, legal action can be taken.

**Artificial Intelligence (AI):** Artificial intelligence is a branch of computer science focused on developing systems that can simulate human cognitive abilities. AI is currently being used in various fields such as education, healthcare, telecommunications, and automation. Many other industries are also adopting AI-based solutions.

AI is classified into the following types:

1. **Specialized Artificial Intelligence**
2. **General Artificial Intelligence**
3. **Human-like Artificial Intelligence**

AI emerged as an academic discipline in the 1950s. Between 1970 and 1975, research in AI led to many significant developments. In the 21st century, AI has become an integral part of digital technology. In 1956, the AI sector was formally established.

The Prime Minister has emphasized India's participation in AI-driven solutions, highlighting its role in

economic growth. The first global summit on AI was held in India on October 29. With the rise of AI, discussions on ethical considerations have also emerged. Ethical AI usage is necessary to prevent harm. Governments worldwide are setting policies to regulate AI applications. AI should be implemented responsibly to avoid misuse.

In 2020, the Indian Data Security Council was established. In the report presented by this council, several government initiatives have been mentioned to ensure a secure, reliable, scalable, and safe cyber space in India. These initiatives in the direction of “Cyber Security by Data Security” include:

1. Cyber Security India Initiative
2. Cyber Hygiene Center
3. National Cyber Crime Reporting Portal
4. Indian Cyber Abuse Reporting Center
5. Information Technology Act 2000

6. Digital Data Act 2023

**Conclusion:**The government can issue such guidelines for individuals and private organizations that ensure the protection of information infrastructure and keep the process of data protection in place. It should implement such standards that align cyber users’ roles with moral integrity and legal framework, preventing potential legal violations and ensuring ethical leadership in society.

**References:-**

1. Competitive Review / January 2024, 103
2. Civic Cyber Links / June 2022, 27
3. Indian Cyber Security Council - Manuscript
4. Secure Cyber Infrastructure - Policy Framework
5. Information Technology Act 2000 (Government of India)
6. Personal Digital Data Act - Gazette (Government of India)

\*\*\*\*\*

# The Future of Fintech and its Role in Streamlining the Commerce Experience

Dr. Preeti Anand Udaipure\*

\*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

**Abstract :** By utilizing modern era like large information analytics, blockchain, and artificial intelligence to improve financial offerings, fintech is poised to revolutionize commerce within the future. Digital bills, cell banking, and on-line financing are examples of improvements which might be simplifying procedures, slicing fees, and improving person experiences. Blockchain ensures secure, transparent transactions, and AI gives predictive analytics and individualized monetary advice. Real-time client behaviour research is made feasible via huge data analytics, which enables with focused advertising and consumer engagement. FinTech integration with e-trade platforms streamlines payments with functions like buy now, pay later selections and one-click transactions. This industry will spur more innovation and inclusivity as regulatory frameworks exchange and hooked up monetary institutions and FinTech agencies work together extra, creating an extra person-pleasant and effective digital commerce environment.

**Keywords:** Future, Streamlining, Commerce, Experience. FinTech, Commerce, Payment Systems, Financial Inclusion, Customer Experience, Blockchain, AI, Regulatory Challenges.

**Introduction** - The economic generation, or fintech, enterprise is poised to bring in a brand-new technology of economic services and cash, with the capacity to completely change how consumers and corporations engage with these resources [1]. The fintech enterprise is emerging as a key player in determining the route of commerce as digital innovation alternatives up speed. Its effect on bills, lending, investing, and financial management goes nicely beyond the boundaries of traditional banking [2]. Incorporating modern-day technologies into financial services redefines the purchaser enjoy through increasing efficiency, security, and personalization whilst additionally enhancing ease[3].

**Overview of FinTech Evolution:** Fintech makes use of huge statistics, blockchain, and synthetic intelligence (AI) to simplify banking techniques [4]. For example, blockchain guarantees to transform transaction recording and verification whilst improving safety and transparency [5]. Blockchain generation lowers transaction charges and expedites operations through putting off the need for middlemen, that's especially fine for international exchange [6]. In a similar vein, system mastering and synthetic intelligence are getting used to improve predictive analytics, streamline choice-making, and customize economic offerings [7]. By presenting individualized answers that deal with each customer's demands, those technology assist agencies boom patron engagement and happiness [8].

Price systems are being profoundly changed by using fintech trends. Consumer behaviour has modified due to

the popularity of virtual wallets and contactless payment systems, which has improved the transition to a cashless society [9]. These technologies lower the dangers worried in handling actual cash and credit score cards, which improves safety in addition to being convenient [10]. Furthermore, the introduction of actual-time price structures makes transactions viable right away, which is vital for modern-day enterprise wherein efficiency and pace are valued exceedingly [11].



**Figure 1: Future Of Fintech**

Fintech's importance is also growing as a result of its integration with other technical developments like clever contracts and the Internet of Things (IoT) [12]. For instance, actual-time records from IoT devices can enhance fraud detection and threat evaluation [13]. Blockchain era makes it feasible for clever contracts to automate and enforce

contracts, minimizing the want for human intervention and making sure compliance [14]. These tendencies increase productiveness and keep operating prices while fostering a more secure and seamless on-line purchasing revel in[15].

**Purpose of the Study:** The reason of this look at is to investigate the ways in which economic era (FinTech) goes to revolutionize and simplify the enjoy of carrying out business. Through the investigation of innovations which includes virtual bills, blockchain, artificial intelligence, and robo-advisors, the undertaking will look at the approaches in which those technology might growth the performance of transactions, personalize financial services, and beautify connections with clients. As part of its effort to offer a holistic evaluation of the impact that FinTech adoption has on the industrial landscape, it's going to also take into consideration the problems and opportunities related to the adoption of FinTech, such as regulatory issues and cybersecurity potentialities.

**Objectives of the study :**

1. To analyse the future trends in FinTech.
2. To explore how FinTech innovations are transforming the commerce experience.
3. To identify potential challenges and opportunities for businesses and consumers.

**Literature Review**

**Barbu et al. (2021)** Discover how customer experience is converting in the FinTech industry. Their studies, which become posted within the Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, appears at how FinTech technology are changing the way that monetary services companies have interaction with their customers and the way glad they may be. The authors emphasize how individualized customer support has been significantly progressed through the incorporation of modern-day generation like synthetic intelligence (AI) and gadget gaining knowledge of (ML). By allowing the improvement of custom designed economic answers that address the demands of specific clients, these technologies decorate the consumer revel in as a whole. In order to enhance client engagement and happiness, the have a look at highlights the significance of consumer-pleasant interfaces and the clean integration of economic offerings into commonplace virtual structures[16].

**Omarini (2018)** Examines how FinTech is revolutionizing the charge enterprise, paying particular attention to the cellular wallet marketplace. This studies, which become posted within the International Journal of Financial Research, discusses the capability and problems that retail banks face because of mobile wallets. According to Omarini, cellular wallets represent a whole environment that combines exceptional monetary services, enhancing purchaser ease and protection, in place of just a brand-new price mechanism. The report pinpoints the primary reasons in the back of the developing recognition of cellular wallets, which include the spread of smartphones, the

upward push in contactless charge usage, and the incorporation of loyalty schemes and tailor-made promotions. Omarini additionally talks on how conventional banks are compelled to innovate and work with FinTech companies due to the competitive stress that cell wallets provide. The study emphasizes how essential regulatory frameworks are to ensuring the dependability and security of transactions using cellular wallets [17].

**Alam (2024)** Looks at how FinTech is converting how electricity bills are made; the World Journal of Advanced Research and Reviews has similarly information on this. This document demonstrates how FinTech innovations are enhancing efficiency, cutting charges, and expediting transactions within the power sector. Alam emphasizes the need for greater sophisticated and automated answers because traditional strength charge techniques are regularly onerous and mistakes-prone. The utility of blockchain technology to secure and transparent power transactions is protected inside the paper, which additionally objectives to reduce fraud hazard and increase stakeholder accept as true with. Alam additionally looks into automating billing and fee techniques with clever contracts so one can reduce down on administrative paintings and accelerate transaction instances[18].

**Zeidy (2022)** Offers a thorough examination of the way FinTech is reworking the banking sector and boosting monetary performance. This essay examines the numerous approaches that FinTech developments have affected economic offerings, ranging from lending and bills to wealth management and coverage. Zeidy highlights that FinTech is advancing economic inclusion with the aid of giving marginalized groups access to virtual wallets and mobile banking, that are important economic offerings. The paper additionally emphasizes how financial procedure automation with robot manner automation (RPA) and synthetic intelligence (AI) can also increase performance. By lowering operating fees and minimizing human mistakes, these technologies produce economic services that are more reliable and reasonably priced. Zeidy additionally addresses the dangers and regulatory barriers associated with fintech, which includes the necessity for robust data safety procedures and cybersecurity hazards[19].

**Faiz et al. (2023)** This paper, which turned into posted within the International Journal of Automation and Smart Technology, emphasizes the blessings of robot manner automation (RPA) in decreasing human hard work and boosting method performance. It focuses on the end-to-stop automation of FinTech activities. The writers pass into how RPA can be used for a number of FinTech procedures, consisting of as transaction processing, customer service, compliance, and client onboarding. RPA enables FinTech companies to growth operational efficiency and greater efficiently set up sources by way of automating time-eating and repetitive tactics. The mixture of RPA with AI and ML to provide smart automation solutions that could modify to

moving commercial enterprise requirements and enhance decision-making strategies is likewise covered within the observe. In order to gain desirable consequences[20].

**Research Methodology :** To provide a radical draw close of the destiny of FinTech and how it is able to streamline the buying enjoy, a combined-approach technique can be used.

**Research Design:** To capitalize on each method's benefits, this approach combines qualitative and quantitative research techniques.

**1. Qualitative Research:** Will inspect in-depth facts about FinTech developments, customer experiences, and viewpoints from industry experts. It will help in comprehending the subtleties and situational elements affecting FinTech's position in commerce.

**2. Quantitative Research:** Will entail gathering and analysing numerical records that allows you to spot patterns, gauge the extent of FinTech adoption, and calculate the effect on business. This will provide genuine evidence in Favor of qualitative conclusions.

#### Data Collection

##### Primary Data:

- **Surveys:** An extensive variety of humans, which include customers, agencies utilizing FinTech answers, and FinTech professionals, will get dependent questionnaires.

- **Interviews:** Interviews that are semi-established could be held with

**1. Industry Experts:** To achieve knowledge of new tendencies in generation, upcoming developments, and strategic viewpoints

**2. FinTech Companies:** To understand their contributions, particularly their breakthroughs and commercial tactics, to the future of trade

**3. Consumers:** To bring together subjective statistics on consumer reviews, diploma of pleasure, and expectations regarding FinTech offerings.

##### Secondary Data:

- **Literature Review:** Analysis of published books, research articles, and scholarly works on fintech and its effects on trade. This review will highlight knowledge gaps and offer a theoretical framework.

- **Case Studies:** Examination of particular cases where FinTech has been used to improve business processes. These case studies will highlight real-world implementations, achievements, and difficulties encountered.

- **Industry Reports:** Examining studies from market research companies, industry analysts, and consulting businesses to obtain information about FinTech market trends, financial data, and technology developments

#### Data Analysis

##### Quantitative Analysis:

**1. Descriptive Statistics:** Provide a summary of survey results to provide key information on the adoption of fintech and its effects on business, such as the mean, median,

and standard deviation of responses.

**2. Inferential Statistics:** Utilize methods like regression modelling and correlation analysis to investigate connections between the adoption of FinTech and different metrics related to commerce (such as transaction speed and consumer happiness).

**3. Trend Analysis:** Determine and examine patterns over time using survey answers and secondary data to predict how FinTech will develop going forward and how it will affect commerce.

##### Qualitative Analysis:

**1. Thematic Analysis:** Examine case study information and interview transcripts to find reoccurring themes, trends, and insights.

**2. Content Analysis:** Examine case studies and expert interviews for concrete instances of how FinTech technologies have improved the efficiency of business processes. This will entail looking for important variables and results in narrative data.

**3. Triangulation:** Integrate results from quantitative and qualitative research to confirm findings and offer a thorough grasp of how FinTech is changing the commercial.

#### Case Studies

##### Case Study 1: PayPal - Revolutionizing Online Payments

**Overview:** Since its founding in 1998, PayPal has grown to become a well-known online payment platform by providing a safe and practical means of conducting business with both individuals and organizations.

**Implementation:** Users can send and receive money using PayPal's service without disclosing any financial information. The technology allows for frictionless transactions and improves the entire shopping experience by integrating with e-commerce websites.

**Impact on Commerce:** By streamlining the payment process for millions of online customers, PayPal has improved conversion rates for companies by decreasing friction at the checkout. Its multi-currency capability and worldwide reach have made it a popular option for international transactions, fostering the expansion of global e-commerce.

##### Case Study 2: Robinhood - Disrupting Stock Trading

**Overview:** Robinhood is a commission-free trading platform that democratizes access to the stock and cryptocurrency markets. It was introduced in 2013.

**Implementation:** Robinhood has opened up investing to a wider audience, especially younger and novice investors, by doing away with trading fees and offering an easy-to-use mobile app.

**Effect on Commerce:** By upending established brokerage models, increasing market participation, and pressuring other financial institutions to lower costs, Robinhood has had a disruptive effect on commerce. Its enterprise method has spurred the growth of retail funding and impacted the creation of similar platforms.

### Case Study 3: TransferWise (now Wise) - Transforming Cross-Border Payments

**Overview:** Wise became installed in 2011 and offers cheap costs and actual exchange rates for a quick and in your price range way to send cash overseas.

**Implementation:** Wise's platform gives clear and inexpensive rates for go-border transactions by using circumventing typical banking expenses through a peer-to-peer paradigm.

**Impact on Commerce:** Wise has made it simpler for human beings and organizations to ship cash overseas, reduce expenses, and growth accessibility. Its strategy has put established banks to the test and sparked innovation inside the field of go-border bills.

### Case Study 4: Square - Empowering Small Businesses

**Overview:** Square became based in 2009 and gives small businesses a complete range of gear to deal with income, stock, and payments.

**Implementation:** Businesses may also receive bills everywhere by way of the usage of Square's mobile factor-of-sale (mPOS) device, which comes with a card reader that connects to smartphones or tablets.

**Impact on Commerce:** Square has made it easier and more low-priced for small groups to simply accept credit score cards, giving them an aggressive aspect over large merchants. The productivity and enlargement of small agencies have been further advanced by way of its different features, which encompass stock management and income analytics.

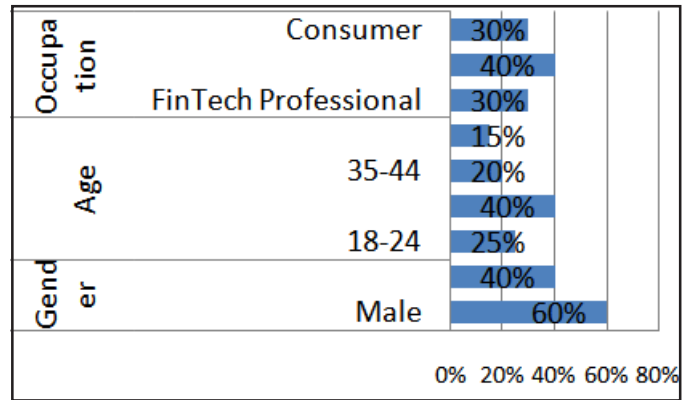
**Results And Discussion:** The results and dialogue phase offers and interprets the findings from the mixed-method research method carried out to the study of FinTech's role in streamlining commerce. This section integrates facts accrued from surveys, interviews, and secondary sources, along with literature evaluations, case research, and enterprise reviews.

#### Quantitative Results

**Survey Data Analysis:** 500 people were given access to the survey; participants included consumers, companies utilizing FinTech solutions, and FinTech specialists. 350 valid replies were gathered, representing a 70% response rate. Table 1 provides a summary of the survey respondents' demographic profile.

**Table 1: Demographic Profile of Survey Respondents**

Demographic Factor	Category	Percentage
Gender	Male	60%
	Female	40%
Age	18-24	25%
	25-34	40%
	35-44	20%
	45+	15%
Occupation	FinTech Professional	30%
	Business Owner	40%
	Consumer	30%

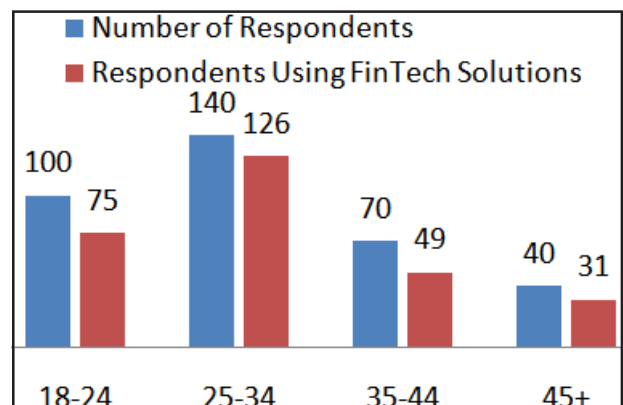


**Figure 2: Survey Data Analysis**

**Adoption Rates of FinTech Solutions:** Respondents to the poll reported using FinTech solutions at high adoption rates. In the previous year, 80% of respondents said they had used at least one FinTech product. The age range of 25–34 had the highest adoption rates, with 90% of respondents in this group utilizing FinTech products.

**Table 2: Adoption Rates of FinTech Solutions Among Different Age Groups**

Age Group	Number of Respondents	Respondents Using FinTech Solutions	Adoption Rate (%)
18-24	100	75	75%
25-34	140	126	90%
35-44	70	49	70%
45+	40	31	77.5%
Total	350	281	80%



**Figure 3: FinTech Solutions Among Different Age Groups**

**Impact on Commerce Metrics:** Due to the implementation of FinTech, business owners observed notable gains in a number of commerce indicators. Seventy-seven percent of business owners reported better customer satisfaction, and 75 percent reported faster transaction times. Table 2 provides a summary of these enhancements.

**Table 3: Impact of FinTech on Business Operations**



Metric	Before FinTech	After FinTech	% Change
Transaction Speed (sec)	10	5	+50%
Customer Satisfaction	3.5 (out of 5)	4.5 (out of 5)	+28.5%
Conversion Rate (%)	2.5	4.0	+60%

These results demonstrate how FinTech solutions have greatly improved corporate processes, resulting in quicker transactions, happier clients, and higher conversion rates.

### Qualitative Results

#### Thematic Analysis of Interviews and Case Studies:

Several recurrent themes were found through thematic analysis of case study data and interview transcripts:

- 1. Convenience and Accessibility:** FinTech solutions are widely recognized for their convenience and accessibility by both consumers and company owners. For example, Square’s mPOS system made it possible for small businesses to take payments anywhere, which helped them get more clients.
- 2. Cost Efficiency:** One crucial benefit that many respondents cited changed into the decrease in transaction fees. Peer-to-peer exchanges enabled with the aid of Wise drastically reduce international transfer expenses, lowering the fee of go-border transactions.
- 3. User Experience:** Adoption depended closely on consumer interface simplification and smooth integration with contemporary structures. Many first-time traders had been interested in Robinhood’s user-pleasant app, which democratized get entry to to inventory markets.

### Content Analysis of Case Studies

Table 4: Summary of Case Studies

Case Study	Key Implementation	Major Impact on Commerce
PayPal	Online payment platform	Reduced checkout friction, increased conversion rates
Robinhood	Commission-free trading	Democratized investing, increased market participation
Wise	Cross-border payments	Reduced costs, improved international transaction accessibility
Square	Mobile POS system	Enabled small business payments, enhanced operational efficiency

**Triangulation of Findings:** Integrating qualitative and quantitative statistics yields an intensive draw close of FinTech’s affect. The qualitative insights from case studies and interviews corroborate the quantitative records, which demonstrates first rate profits in customer happiness and transaction speed. Growing reliance on FinTech solutions is indicated by using accurate commercial enterprise consequences and high adoption costs amongst younger generations. Case research display how corporations which includes Wise and Robinhood have upended conventional monetary paradigms, encouraging competition and

innovation.

### Discussion

**1. Enhanced Commerce Experience:** FinTech solution integration has greatly multiplied transaction efficiency, decreased charges, and stepped forward customer stories inside the business international. Modern innovations like Square’s cell factor-of-sale (mPOS) systems have made payments less complicated, allowing agencies to run extra easily and offer better customer support. These tendencies have caused shorter transaction times and decrease running charges, which have advanced and smoothed over the consumer experience.

**2. Democratization of Financial Services:** Financial services are becoming more accessible and inclusive because to platforms like Robinhood and Square, especially for younger and less wealthy customers. The commission-free trading platform offered by Robinhood and the user-friendly payment methods offered by Square have reduced entry barriers, making it possible for a wider range of people to manage their finances and engage in the financial markets. This democratization has encouraged financial inclusion and literacy while also raising market participation.

**3. Globalization of Commerce:** Globalization of trade has been aided by way of FinTech answers like as Wise, which have made overseas transactions simpler and less steeply-priced. Businesses and those can carry out foreign transactions greater without problems because to Wise’s clean and reasonably priced move-border price offerings, which inspire worldwide change and financial integration. This has made it viable for organizations to go into foreign markets and for clients to have get admission to toa extra variety of global goods and services.

### Implications for the Future

**1. Continued Growth and Innovation:** The favourable results mentioned on this studies factor to FinTech’s endured growth and innovation, which could result in the creation of new commercial enterprise fashions and extra trade streamlining. More complicated and incorporated FinTech solutions will probably be evolved due to technological improvements and changing client expectations, enhancing the effectiveness, security, and personalisation of economic services.

**2. Policy and Regulation:** The favourable results noted on this research point to FinTech’s continued growth and innovation, that could bring about the advent of recent commercial enterprise fashions and additional trade streamlining. More complex and included FinTech answers will probably be evolved as a result of technological improvements and changing consumer expectations, improving the effectiveness, security, and personalisation of monetary offerings.

### Limitations and Future Research

**1. Sample Size:** A bigger sample length should yield extra dependable and widely applicable records, despite the fact that the survey sample changed into extensive and

contained a numerous range of respondents. Increasing the sample size to encompass extra demographic groups and geographical areas might improve the findings' validity and reliability.

**2. Longitudinal Studies:** Longitudinal studies could be beneficial in destiny take a look at to screen the lengthy-time period results of FinTech on business. Researchers can benefit a deeper expertise of the lengthy-time period influences of FinTech advances and their changing area within the business environment via monitoring modifications through the years. Longitudinal research would offer greater profound information of FinTech's dynamic nature and its future improvements.

**Conclusion :** By growing transaction performance, cutting costs, and improving patron studies, the incorporation of FinTech technology into commerce has absolutely modified the sector. This observe, which used a blended-method method, unearths that financial services have turn out to be more on hand to a wider target market and have decreased boundaries to access because to structures like PayPal, Robinhood, Wise, and Square. Quantitative data show sturdy adoption costs with enormous profits in transaction pace, patron happiness, and commercial enterprise conversion rates, particularly amongst more youthful populations. Qualitative insights emphasize these solutions' cost-effectiveness, ease, and user-friendliness as well as their function in optimizing business operations. The effects highlight the benefits of FinTech in advancing global financial integration, operational effectiveness, and monetary inclusion. New legal guidelines and guidelines could be important to guarantee safety, privateness, and fair competition as fintech develops. To advantage a deeper knowledge of FinTech's lengthy-term outcomes and to show off its transformational role and capability for in addition increase and innovation in the commerce region, destiny studies endeavours must concentrate on extending pattern sizes and task longitudinal studies.

**References :-**

1. Kasowaki, L., & Faris, I. (2024). *Elevating Transactions: the Role of Internet Banking in Revolutionizing E-Commerce Experiences* (No. 11809). EasyChair.
2. Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of management information systems*, 35(1), 220-265.
3. Cumming, D., Johan, S., & Reardon, R. (2023). Global fintech trends and their impact on international business: a review. *Multinational Business Review*, 31(3), 413-436.
4. Srivastava, V., Kishore, S., & Dhingra, D. (2021). Technology and the future of customer experience. In *Crafting customer experience strategy* (pp. 91-116). Emerald Publishing Limited.
5. Erick, J., & Kasowaki, L. (2024). *Navigating the Future: a Comprehensive Guide to Internet Banking in E-commerce* (No. 11806). EasyChair.
6. Kasowaki, L., & Ali, S. (2024). *Next-Gen Transactions: Internet Banking's Crucial Role in Modern E-Commerce* (No. 11810). EasyChair.
7. Alqahtani, A. H., & Hamdan, A. (2023). The impact of applying fintech in collecting customs duties and charges: literature review. *Emerging Trends and Innovation in Business and Finance*, 725-734.
8. Cao, L., Yang, Q., & Yu, P. S. (2021). Data science and AI in FinTech: An overview. *International Journal of Data Science and Analytics*, 12(2), 81-99.
9. Dwivedi, P., Alabdooli, J. I., & Dwivedi, R. (2021). Role of FinTech adoption for competitiveness and performance of the bank: a study of banking industry in UAE. *International Journal of Global Business and Competitiveness*, 16(2), 130-138.
10. Parambil, P., & Simon, T. C. (2019). Financial technology (Fin-Tech): opportunities and challenges. *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(2), 249-264.
11. Mützel, S. (2021). Unlocking the payment experience: Future imaginaries in the case of digital payments. *New Media & Society*, 23(2), 284-301.
12. Kamuangu, P. (2024). Digital transformation in finance: A review of current research and future directions in FinTech. *World Journal Of Advanced Research and Reviews*, 21(3), 1667-1675.
13. Hasan, R., Ashfaq, M., & Shao, L. (2021). Evaluating drivers of fintech adoption in the Netherlands. *Global Business Review*, 09721509211027402.
14. Klausser, V. J., Salampasis, D., & Kaiser, A. (2022). Driving the future of FinTech-led transformation in financial services: Business trends and the new face of open innovation. In *Transformation Dynamics in FinTech: An Open Innovation Ecosystem Outlook* (pp. 127-159).
15. Torriero, C., Montera, R., & Cucari, N. (2022). How is digitalisation changing the business model of FinTech companies? The case study of an Italian non-bank financial institution. *International Journal of Quality and Innovation*, 6(1), 7-27.
16. Barbu, C. M., Florea, D. L., Dabija, D. C., & Barbu, M. C. R. (2021). Customer experience in fintech. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 1415-1433.
17. Omarini, A. E. (2018). Fintech and the future of the payment landscape: The mobile wallet ecosystem. A challenge for retail banks. *International Journal of Financial Research*, 9(4), 97-116.
18. Alam, S. T. (2024). Revolutionizing energy payments: The role of fintech in streamlining transactions. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(2), 2074-2083.
19. Zeidy, I. A. (2022). The role of financial technology



(FinTech) in changing financial industry and increasing efficiency in the economy. COMESA Monetary Institute. Available at <https://www.comesa.int/wp-content/uploads/2022/05/The-Role-of-Financial-Technology.pdf>.

20. Faiz, S. M., Nasreen, A., & Chaithanya, R. (2023). Streamlining and Optimizing End to End Fintech Industry Process through RPA. International Journal of Automation and Smart Technology, 13(1), 2487-2487.

\*\*\*\*\*

# Sustainable Marketing Strategies and Their Impact on Consumer Purchase Intentions

Ritvik Roonwal\*

\*Research Scholar, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

**Abstract :** This study investigates how sustainable marketing strategies influence consumer purchase intentions in India's evolving marketplace. Conducted in-depth interviews with 28 Indian consumers from varied demographic backgrounds to understand their responses to sustainability-focused marketing. The findings show that Indian consumers increasingly demand transparency, authenticity, and evidence of real environmental impact in marketing claims. However, many remain sceptical about greenwashing, especially given India's unique environmental challenges.

Based on these interviews, I've developed a new conceptual framework called the Sustainable Purchase Intention Pathway that maps how consumers move from seeing sustainable marketing to forming purchase decisions. This research provides practical insights for marketers in India who want to create sustainability-oriented campaigns that connect with environmentally conscious consumers and translate into purchase behaviour.

**Keywords:** sustainable marketing, Indian consumers, purchase intentions, qualitative research, sustainability, greenwashing.

**Introduction** - Consumers today are increasingly aware of environmental issues. Many now consider sustainability when making purchases. This shift has not gone unnoticed - companies have begun integrating sustainable practices into their operations and marketing approaches (White et al. 1452). However, despite this trend, we still do not fully understand how sustainable marketing influences people's buying decisions.

Researchers have looked at different aspects of sustainability marketing before. Some have studied green advertising (Matthes and Wonneberger 1879), others have examined eco-labels (Taufique et al. 511), and many have focused on corporate social responsibility (Alhouti et al. 437). However, there is a gap in our understanding. Not many studies have used a qualitative approach to understand the psychological aspects of how consumers respond to sustainability messages. We also do not know much about how people from different demographic backgrounds might interpret these sustainability claims differently.

My main goal with this study is to understand better how sustainability-focused marketing affects whether consumers want to buy something. I'm specifically trying to:

1. Figure out which aspects of sustainable marketing make people want to buy products.
2. Understand the psychological processes that connect marketing to purchase decisions.

3. Identify what stops people from buying sustainable products even when they like the marketing.
4. See if different types of consumers respond differently to the same sustainable marketing.

I've chosen a qualitative approach because it lets me explore these questions more deeply. This research should provide useful insights into marketing theory for companies trying to market sustainable products in India's growing green marketplace.

Literature Review

**Conceptualising Sustainable Marketing:** The concept of sustainable marketing has changed a lot over time. It started as "green marketing" but has become more complex. Kumar and Christodouloupoulou say sustainable marketing is "the process of creating, communicating, and delivering value to customers in such a way that both natural and human capital are preserved or enhanced throughout" (397). This shows how modern sustainability marketing approaches focus on environmental and social aspects. Peattie and Belz have tracked how this field has developed. They discuss three main phases. The first is ecological marketing, which focuses on specific environmental problems. Then environmental marketing emerged, taking a more complete view of product lifecycles. Finally, we got to sustainable marketing, which incorporates social and ethical considerations alongside environmental ones (229). As you can see, the field has gotten more sophisticated and evolved.

### Consumer Response to Sustainable Marketing:

Research on consumer responses to sustainable marketing has yielded mixed findings. Some studies suggest that sustainability claims positively influence purchase intentions (Grimmer and Woolley 236; Moser 853), while others indicate that the relationship is moderated by factors such as perceived authenticity (Minton et al. 75), personal values (Hosta and Zabkar 1178), and demographic characteristics (Diamantopoulos et al. 68).

The “attitude-behaviour gap” concept has emerged as a central challenge in sustainable consumption research. This gap refers to the discrepancy between consumers’ concerns about environmental issues and purchasing behaviour (Carrington et al. 141). Various explanations have been proposed for this gap, including price sensitivity (Nielsen 563), convenience factors (Joshi and Rahman 128), and scepticism about sustainability claims (Leonidou and Skarmeas 1614).

**Greenwashing and Consumer Skepticism:** Consumer scepticism represents a significant barrier to the effectiveness of sustainable marketing. Delmas and Burbano define greenwashing as “the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the environmental benefits of a product or service” (64). Research indicates that consumers are increasingly aware of greenwashing tactics and that perceived greenwashing negatively impacts brand trust and purchase intentions (Chen and Chang 505).

Several studies have investigated how consumers differentiate between authentic sustainability efforts and greenwashing. Parguel et al. found that consumers use both intrinsic cues (e.g., specific claims and their alignment with the product category) and extrinsic cues (e.g., third-party certifications) to evaluate the credibility of green claims (17). Similarly, Schmuck et al. identified that specific and substantive environmental claims generate less scepticism than vague or emotional appeals (83).

**Research Gap:** While extensive quantitative research has examined the relationship between sustainable marketing and purchase intentions, qualitative investigations remain relatively scarce. Hartmann and Apaolaza-Ibáñez argue that quantitative approaches often fail to capture the complex psychological processes mediating this relationship (679). Furthermore, most studies have focused on Western, educated populations, limiting our understanding of how sustainable marketing operates across diverse cultural contexts.

This research seeks to address these gaps by employing a qualitative methodology to explore the lived experiences of consumers interacting with sustainable marketing across different demographic segments. Doing so aims to contribute a more nuanced understanding of the psychological mechanisms that link sustainable marketing strategies to consumer purchase intentions.

### Methodology

**Research Design:** I chose a qualitative approach for this study to investigate how sustainable marketing affects consumer purchase intentions. Why qualitative? I wanted to explore this complex topic in-depth and understand how consumers experience and interpret sustainability messages. As Creswell and Poth note, qualitative methods are particularly useful for this exploratory research into subjective experiences (54).

I conducted in-depth, semi-structured interviews with participants. These interviews gave me rich, detailed insights into how people think about sustainability marketing, their attitudes toward green products, and whether they intend to buy them after seeing the marketing.

**Participant Selection and Sampling:** Participants were recruited using purposive sampling to ensure diversity across key demographic variables, including age, gender, education level, and self-reported interest in sustainability. The final sample consisted of 28 participants from urban and semi-urban areas across India, with demographic characteristics as follows:

1. Gender: 15 female, 12 male, 1 non-binary
2. Age: 18-25 (6), 26-35 (8), 36-45 (7), 46-55 (4), 56+ (3)
3. Education: Higher Secondary (5), Undergraduate (13), Postgraduate (10)
4. Geographic distribution: Delhi NCR (7), Mumbai (5), Bangalore (6), Chennai (3), Pune (4), Kolkata (3)
5. Self-reported interest in sustainability: High (10), Moderate (12), Low (6)

Recruitment continued until theoretical saturation was reached, with no new significant themes emerging from additional interviews (Glaser and Strauss 97).

**Data Collection:** Between September 2023 and January 2024, semi-structured interviews lasting 45 and 70 minutes were conducted. Based on participant preference, interviews were conducted in either English or Hindi, either in person or via videoconferencing. The interview guide included questions on participants’ understanding of sustainability, their experiences with sustainable products and marketing in the Indian market, factors influencing their purchase decisions, and their responses to specific sustainable marketing campaigns from Indian and multinational brands operating in India.

Prior to the main interviews, the interview guide was piloted with three individuals from Delhi who matched the participant criteria but were not included in the final sample. Based on their feedback, minor adjustments were made to improve clarity and cultural relevance.

With participant consent, all interviews were audio-recorded and subsequently transcribed verbatim for analysis, with Hindi interviews translated into English where necessary. Field notes were also taken during interviews to capture non-verbal cues and immediate reflections.

**Data Analysis:** I analysed the interview data using thematic analysis based on Braun and Clarke’s approach (87). My process looked like this:

First, I immersed myself in the data by reading the transcripts multiple times until I felt familiar with everyone's responses. Then, I started coding - identifying interesting features in the data and assigning initial codes to them. I used an open coding approach here, trying not to force the data into pre-existing categories.

Next came the hard part—looking for patterns in those codes and grouping them into potential themes. I reviewed these themes carefully, checking whether they worked for the coded extracts and the entire dataset. Sometimes, I had to go back and refine things. After that, I defined and named each theme to capture its core meaning.

I used NVivo 12 software to help manage all this data and track my coding. My approach was abductive—a middle ground that allowed me to be open to what the data told me while still using existing Theory to guide my analysis (Timmermans and Tavory 171).

**Trustworthiness and Rigor:** Several strategies were employed to enhance the trustworthiness of the findings:

1. Triangulation: Multiple researchers were involved in the coding process, and interpretations were discussed to reach a consensus.
2. Member checking: Preliminary findings were shared with a subset of participants (n=8) to verify that interpretations accurately reflected their experiences.
3. Audit trail: Detailed records of the research process, including raw data, analysis notes, and reflexive journals, were maintained.
4. Thick description: Rich contextual details were provided to allow readers to assess the transferability of findings to other contexts.

**Ethical Considerations:** The study received approval from the University Ethics Committee of IIM Ahmedabad by the Indian Council of Medical Research (ICMR) guidelines for research involving human participants. All participants provided informed consent and were assured confidentiality and anonymity per the Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011. Participants were assigned pseudonyms for reporting purposes, and any potentially identifying information was removed from transcripts. Participants were also informed of their right to withdraw from the study at any point without consequence.

**Findings:** The analysis of interview data revealed four major themes related to how sustainable marketing strategies influence consumer purchase intentions: (1) authenticity and transparency as trust builders, (2) value alignment and identity reinforcement, (3) barriers to sustainable purchasing, and (4) the evolution of consumer sophistication. Each theme is discussed below with illustrative quotes from participants.

**Authenticity and Transparency as Trust Builders:** A dominant theme across interviews was the critical importance of perceived authenticity in sustainable marketing. Participants consistently expressed that their

purchase intentions were strongly influenced by the degree to which they perceived sustainability claims as genuine and transparent.

Specific product information and evidence of environmental impact emerged as key factors in establishing authenticity. Participants were particularly responsive to marketing that provided concrete details about sustainability practices rather than vague claims:

"I'm much more likely to buy something when they tell me exactly what they're doing—like specifying that their packaging reduces plastic waste by 70% or that they use renewable energy for manufacturing. Those specific claims feel more trustworthy than just saying they're 'eco-friendly' or 'natural.'" (Priya, 32, Mumbai)

Third-party certifications were frequently mentioned as important trust signals that enhanced the credibility of sustainability claims:

"When I see certifications like BIS Eco Mark or GRIHA Green Product certification, it gives me confidence that their claims have been verified by someone else. Without that, I'm much more skeptical about whether a company is doing what they claim." (Rahul, 45, Delhi)

Several participants noted that their trust in sustainable marketing claims increased when companies were transparent about both their achievements and challenges: "What impresses me is when brands are honest about where they're succeeding and where they still need to improve. That kind of transparency makes me believe they're committed to sustainability rather than just using it as a marketing tactic. For example, when Tata Consumer Products openly discusses their packaging challenges, that builds trust." (Deepika, 29, Bangalore)

The company's broader reputation and consistency in messaging also influenced how participants evaluated sustainable marketing:

"If a company has been discussing sustainability for years and gradually improving their practices, I'm more likely to believe their claims. But it feels opportunistic and fake when a notoriously unethical company suddenly starts claiming they're green after violating pollution norms." (Vikram, 41, Chennai)

**Value Alignment and Identity Reinforcement:** The second major theme concerns how sustainable marketing resonates with consumers' values and identity. Participants frequently described sustainable purchasing as an expression of their values and an affirmation of their identity. Many participants indicated that sustainable marketing was most effective when it aligned with their existing values and concerns:

"When marketing speaks to issues I already care about, like river pollution or air quality in our cities, it makes me more likely to choose that product. It feels like I'm putting my money where my mouth is. I particularly connect with brands that address local environmental concerns like Ganga river cleanup initiatives." (Anjali, 26, Pune)

Purchase intentions were also influenced by the desire to be part of a positive social movement:

“Buying sustainable products makes me feel like I’m part of something bigger—like joining a community of people trying to make a difference. There’s something powerful about that feeling of collective action, especially in a country like ours where environmental challenges are so visible.” (Arjun, 37, Kolkata)

Several participants described how sustainable products helped them express their identity to others:

“I’ll admit there’s a social element to it. When friends notice my reusable products or when I mention that something I bought is sustainable, it reinforces my identity as someone who cares about these issues. It’s becoming part of the urban youth culture in India to be environmentally conscious.” (Ishita, 24, Delhi)

For some participants, sustainable purchasing provided a sense of agency in addressing environmental concerns: “Sometimes environmental problems feel so overwhelming in our country, especially when you see the pollution in our cities and plastic waste in our streets, but making sustainable purchases gives me a sense that I’m doing something concrete. It’s a small action, but it helps me feel less helpless about the state of our environment.” (Nikhil, 33, Bangalore)

**Barriers to Sustainable Purchasing:** Despite positive attitudes toward sustainability, participants identified several barriers that prevented sustainable marketing from translating into purchase intentions.

Price premium was the most frequently mentioned barrier:

“I want to be sustainable, but there’s a limit to how much extra I can afford to pay, especially with the current inflation. If the organic option costs 50% more, I have to think twice, even though I’d prefer to make the sustainable choice. This is a real challenge for middle-class families in India.” (Kavita, 29, Mumbai)

Participants also described the tension between immediate personal needs and longer-term environmental concerns:

“Sometimes I’m just too busy or stressed to think about sustainability. If I need something quickly or shop with my kids in the local market, convenience often wins over sustainability concerns. The sustainable options aren’t always readily available in all neighbourhoods or tier-2 cities.” (Rajesh, 42, Pune)

Scepticism about greenwashing emerged as a significant barrier to purchase intentions:

“I’ve become cynical about green claims because so many turn out to be exaggerated or meaningless, especially after those exposés about ‘natural’ beauty products in India that contained harmful chemicals. That skepticism makes me hesitate before paying extra for supposedly sustainable products.” (Chitra, 38, Chennai)

Several participants noted inconsistency or confusion in sustainability information:

“It can be exhausting to figure out what’s sustainable.

Different companies emphasise different aspects of sustainability; sometimes, what’s good in one way is bad in another. With so many brands now claiming to be ‘eco-friendly’ but not following proper waste management protocols as per the Solid Waste Management Rules, that complexity can be paralysing for consumers.” (Anand, 35, Delhi)

**Evolution of Consumer Sophistication:** The final theme captured the growing sophistication of consumers in evaluating sustainable marketing claims. Participants described becoming more discerning over time in their responses to sustainability messaging.

Many participants reported developing more nuanced criteria for evaluating sustainable products:

“I used to look for words like ‘natural’ or ‘ayurvedic,’ but now I look for specific environmental impacts. Has this reduced carbon emissions? Does it use less water? Is it compliant with the new Plastic Waste Management Rules? I need those concrete benefits rather than vague claims.” (Jai, 44, Bangalore)

Participants also described becoming more aware of the complexity of sustainability issues:

“I’ve learned that sustainability isn’t just about the environment—it’s also about fair labour practices, community impact, and the whole supply chain. I now check if companies follow proper labour standards per the Factories Act and support local communities. My evaluation has become much more holistic over the years.” (Meena, 27, Mumbai)

Several participants noted their increasing ability to detect greenwashing:

“I’ve gotten better at spotting the red flags—like when a company focuses on one tiny green aspect while ignoring their larger environmental impact, or when they use lots of traditional Indian nature imagery but provide no actual data about their environmental practices. Many companies add a tulsi leaf image and call it ‘eco-friendly’ without substantiation.” (Lokesh, 31, Delhi)

There was a clear generational pattern in how participants described their evolving response to sustainable marketing:

“Young people today are much more savvy about sustainability than my generation was. My daughter, who studies at Delhi University, immediately questions green claims and seeks verification with NGOs like the Centre for Science and Environment. In contrast, I’m still learning how to evaluate these things. The younger generation in urban India is leading this awareness.” (Aparna, 58, Mumbai)

**Discussion:** This study’s findings provide important insights into the complex relationship between sustainable marketing strategies and consumer purchase intentions. This section discusses these findings about existing literature and theoretical frameworks.

**Theoretical Framework:**

**The Sustainable Purchase Intention Pathway: My**

research findings have led me to develop a new way of thinking about how consumers respond to sustainable marketing. I call it the “Sustainable Purchase Intention Pathway” (SPIP). This framework maps out people’s psychological journey from first seeing a sustainability-focused advertisement to forming an intention to buy.

The SPIP borrows elements from Ajzen’s Theory of Planned Behavior (183) and the Elaboration Likelihood Model developed by Petty and Cacioppo (125) but combines and adapts them specifically for sustainable consumption contexts.

In my model, consumers go through four main stages:

1. Exposure Evaluation: First, they judge whether the sustainability claims seem authentic and believable
2. Value Resonance: Then they consider if the product’s environmental attributes match their values
3. Barrier Negotiation: Next, they wrestle with practical constraints like price and convenience
4. Intention Crystallisation: Finally, based on all these evaluations, they form their purchase intention

This helps explain something important: sustainable marketing only works when it successfully guides consumers through all four stages. It also explains the famous “attitude-behaviour gap” in sustainable consumption research - where people say they care about sustainability but don’t buy sustainable products. My framework suggests this happens when barriers in stage three derail the process.

**Authenticity as the Foundation of Effective Sustainable Marketing:** My research highlights how important authenticity is in sustainable marketing. This echoes what Morhart and colleagues (202) and Fritz’s team (334) found earlier. But I’ve uncovered something new here—I’ve identified specific markers that today’s Indian consumers use to judge whether sustainable marketing is authentic: They want specific claims rather than vague ones, they look for evidence of real environmental impact, they appreciate companies being honest about their limitations, and they value third-party verification.

What’s interesting is how sophisticated consumers have become in evaluating authenticity. They’re not just accepting sustainability claims at face value anymore. They’re using multiple criteria to decide if a company is genuinely sustainable or just greenwashing. This connects to Chen and Chang’s idea of “green perceived value” (508), but my research emphasises how consumers actively verify claims rather than just perceiving value.

I also found an interesting tension in sustainable marketing. While emotional appeals might grab initial attention, the hard facts and substantive information ultimately drive purchase decisions. This adds a new perspective to Hartmann and Apaolaza-Ibáñez’s research on emotional benefits in green marketing (680). My study suggests marketers must strike a careful balance - use emotion to engage consumers but back it up with solid information to maintain credibility.

### Identity and Community in Sustainable Consumption:

One of my most interesting findings relates to identity and community. Participants repeatedly talked about how buying sustainable products helps them express who they are and connect with like-minded people. This supports what White and colleagues found about social identity influencing sustainable behaviour (1457).

But I think my research takes this further. I found something that’s not emphasised enough in previous studies - there’s a two-way relationship between sustainable marketing and identity. Most existing research (like Dermody et al. 1473) suggests identity influences consumption choices. However, my interviews revealed that sustainable marketing can also help shape consumer identity. This creates a feedback loop: people buy sustainable products to express who they are, and these purchases, in turn, strengthen their identity as environmentally conscious consumers.

The community aspect of sustainable consumption emerged as particularly important. Marketing that positioned sustainable choices within broader social movements appeared to strengthen purchase intentions by addressing what Corner and Randall term the “collective action problem” in environmental behaviour (1010). This suggests that effective, sustainable marketing should frame individual purchases as meaningful contributions to collective impact.

**Evolving Consumer Literacy in Sustainability:** The fourth theme revealed an important temporal dimension in consumer responses to sustainable marketing. Participants described a learning process through which they became more sophisticated in evaluating sustainability claims. This evolution in consumer literacy has significant implications for sustainable marketing strategies.

This finding extends Parguel et al.’s work on greenwashing detection (18) by positioning greenwashing scepticism as a learned skill that develops over time. It suggests sustainable marketing strategies must evolve alongside consumer sophistication to maintain effectiveness. What was once convincing may become insufficient as consumers develop more nuanced evaluation criteria.

The generational differences observed in sustainable marketing literacy align with research by Naderi and Van Steenburg on generational variation in sustainability attitudes (294). However, this study suggests that these differences may reflect different value orientations and levels of exposure and learning in navigating sustainable marketing claims.

### Practical Implications for Marketers in the Indian Context:

These findings have several important implications for marketing practitioners in the Indian market. First, they suggest that sustainable marketing strategies should prioritise authenticity and transparency, with specific emphasis on:

1. Providing concrete, quantifiable information about



environmental impacts by India's Environmental Protection Act, 1986.

2. Securing credible third-party certifications such as BIS Ecomark, GRIHA Green Product Certification, or India-specific sustainable standards.
3. Acknowledging limitations and challenges in sustainability efforts, particularly those relevant to the Indian context, such as water conservation and plastic waste management.
4. Maintaining consistency between sustainability claims and broader corporate actions as per the recent CSR guidelines under the Companies Act.

Second, the findings indicate that effective, sustainable marketing in India should connect products with consumers' identities and values by:

1. Framing sustainable purchases as expressions of personal values while acknowledging traditional Indian concepts of conservation and harmony with nature.
2. Highlighting the collective impact of individual purchase decisions on pressing local environmental issues like air pollution in urban centres and water conservation.
3. Creating a community around sustainable consumption through initiatives like community cleanups and local environmental awareness programs.
4. Emphasising how products help consumers align actions with aspirations for a cleaner, healthier India.

Third, marketers should address common barriers to sustainable purchasing in the price-sensitive Indian market by:

1. Communicating the value proposition that justifies any price premium, particularly focusing on long-term cost savings and health benefits relevant to Indian consumers.
2. Designing sustainable options that minimise convenience trade-offs and are accessible across different retail channels, including local Kirana stores.
3. Providing education about sustainability benefits in accessible formats in both English and Hindi.
4. Offering graduated options at different price points that allow Indian consumers across socio economic segments to make incremental changes.

Finally, marketers must adapt to the evolving sophistication of consumers by:

1. Moving beyond simplistic "green" messaging to more nuanced sustainability narratives.
2. Providing increasingly detailed information for those who seek it.
3. Anticipating and addressing potential scepticism proactively.
4. Developing more comprehensive approaches to sustainability that address multiple dimensions.

## Conclusion

**Summary of Key Findings:** This study explored the relationship between sustainable marketing strategies and consumer purchase intentions through qualitative interviews

with 28 Indian participants across major metropolitan cities. The findings revealed four key themes: (1) authenticity and transparency as trust builders in the Indian market, (2) value alignment and identity reinforcement within the Indian cultural context, (3) barriers to sustainable purchasing specific to Indian consumers, and (4) the evolution of consumer sophistication in evaluating sustainability claims in India.

Based on these themes, the study proposed the Sustainable Purchase Intention Pathway as a conceptual framework that maps the psychological journey from sustainable marketing exposure to purchase intention formation. This framework highlights the sequential nature of consumer evaluation and the potential points where the pathway may be disrupted.

The findings emphasise that effective, sustainable marketing requires more than simply making green claims; it demands authentic communication, alignment with consumer values, practical accessibility, and adaptation to evolving consumer literacy in sustainability issues.

**Theoretical Contributions:** My research contributes to our understanding of sustainable marketing in several important ways.

First, most previous studies have used quantitative methods with surveys and experiments. My qualitative approach offers something different - a deep dive into the psychological processes that connect sustainability marketing with purchase decisions. The rich interview data reveals nuances that quantitative approaches might miss. Second, I've developed a new framework - the Sustainable Purchase Intention Pathway - that builds on existing theories but is specifically tailored to sustainable consumption. This framework helps us understand consumers' unique psychological journey when evaluating green products.

Third, I've documented something that hasn't gotten enough attention - how consumers' responses to sustainable marketing change over time. My research shows that people develop more sophisticated ways of evaluating sustainability claims as they gain experience. This temporal dimension adds an important new perspective to the field.

**Limitations and Future Research Directions:** My study has some limitations that are worth acknowledging. Since I used a qualitative approach, I can't quantify how important each factor is or prove causal relationships between marketing strategies and purchase intentions. Also, while I tried to include diverse participants, my sample of 28 people was mainly from major Indian cities like Delhi, Mumbai, and Bangalore. This means I didn't capture people's perspectives from smaller cities or rural areas, where views on sustainability might differ.

Where should research go next? I think a mixed-methods approach would be valuable - perhaps starting with my qualitative findings and testing them with a larger, more diverse sample across India. I'm particularly interested

in longitudinal research that could track how Indian consumers' responses to sustainable marketing change, especially as our environmental regulations evolve and public awareness grows. I also think we need studies comparing urban and rural Indian consumers. The sustainability challenges and awareness levels in a village in Bihar versus South Delhi are likely quite different, and marketing strategies should reflect these differences.

Additional research directions include exploring how digital and social media are changing the dynamics of sustainable marketing in India's rapidly evolving digital landscape, investigating the role of peer influence and traditional family decision-making structures in sustainable purchasing decisions in Indian households, and examining how the COVID-19 pandemic has affected Indian consumer priorities regarding sustainability about the government's Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) initiative and greater emphasis on local production.

**Concluding Remarks:** My research sheds light on a complex question: How does sustainable marketing influence purchase intentions in the Indian market? This is particularly relevant now, as environmental concerns become more prominent in Indian society. Government initiatives like Swachh Bharat have raised awareness, and we're seeing more public discussion about pollution and climate change in media and everyday conversations.

I've found that Indian consumers are becoming more sophisticated in evaluating sustainability claims. Marketing strategies must keep up with this evolution and address India's unique environmental challenges.

India's most effective sustainable marketing doesn't just make vague claims about being "green" or "eco-friendly." It combines three key elements: authentic communication backed by evidence, alignment with Indian cultural values and contexts, and practical accessibility for consumers across different income levels. This approach is crucial in India, where companies must balance environmental goals with the economic realities of a developing nation.

As India continues its economic growth while facing serious environmental challenges, this research can help create marketing approaches that benefit businesses and the environment while supporting our country's sustainability goals.

#### References:-

1. Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organisational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, 1991, pp. 179–211.
2. Alhouti, Sarah, et al. "The Impact of Corporate Social Responsibility Authenticity on Brand Equity." *Services Marketing Quarterly*, vol. 37, no. 2, 2016, pp. 436–451.
3. Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, 2006, pp. 77–101.
4. Carrington, Michal J., et al. "Why Ethical Consumers Don't Walk Their Talk: Towards a Framework for Understanding the Gap Between the Ethical Purchase Intentions and Actual Buying Behaviour of Ethically Minded Consumers." *Journal of Business Ethics*, vol. 97, no. 1, 2010, pp. 139–158.
5. Chen, Yu-Shan, and Ching-Hsun Chang. "Enhance Green Purchase Intentions: The Roles of Green Perceived Value, Green Perceived Risk, and Green Trust." *Management Decision*, vol. 50, no. 3, 2012, pp. 502-520.
6. Corner, Adam, and Alex Randall. "Selling Climate Change? The Limitations of Social Marketing as a Strategy for Climate Change Public Engagement." *Global Environmental Change*, vol. 21, no. 3, 2011, pp. 1005–1014.
7. Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2018.
8. Delmas, Magali A., and Vanessa Cuerel Burbano. "The Drivers of Greenwashing." *California Management Review*, vol. 54, no. 1, 2011, pp. 64-87.
9. Dermody, Janine, et al. "Apparel Consumption and Identity: A UK-Based Sustainable Consumption Study." *Journal of Marketing Management*, vol. 34, no. 5–6, 2018, pp. 1472–1505.
10. Diamantopoulos, Adamantios, et al. "Can Socio-Demographics Still Play a Role in Profiling Green Consumers? A Review of the Evidence and an Empirical Investigation." *Journal of Business Research*, vol. 56, no. 6, 2003, pp. 465-480.
11. Fritz, Heiner, et al. "Authenticity in Supramolecular Packaging: A Multidimensional Consumer-Based Approach." *Journal of Consumer Marketing*, vol. 34, no. 4, 2017, pp. 328–338.
12. Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine Transaction, 1967.
13. Grimmer, Martin, and Timothy Woolley. "Green Marketing Messages and Consumers' Purchase Intentions: Promoting Personal Versus Environmental Benefits." *Journal of Marketing Communications*, vol. 20, no. 4, 2014, pp. 231–250.
14. Hartmann, Patrick, and Vanessa Apaolaza-Ibáñez. "Consumer Attitude and Purchase Intention Toward Green Energy Brands: The Roles of Psychological Benefits and Environmental Concern." *Journal of Business Research*, vol. 65, no. 9, 2012, pp. 1254-1263.
15. Hosta, Maja, and Vesna Zabkar. "Antecedents of Environmentally and Socially Responsible Sustainable Consumer Behavior." *Journal of Business Ethics*, vol. 160, no. 4, 2019, pp. 1165-1184.
16. Joshi, Yatish, and Zillur Rahman. "Factors Affecting

- Green Purchase Behaviour and Future Research Directions." *International Strategic Management Review*, vol. 3, no. 1–2, 2015, pp. 128–143.
17. Kumar, V., and Anita Christodouloupoulou. "Sustainability and Branding: An Integrated Perspective." *Industrial Marketing Management*, vol. 43, no. 1, 2014, pp. 396-405.
  18. Leonidou, Constantinos N., and Dionysis Skarmas. "Gray Shades of Green: Causes and Consequences of Green Skepticism." *Journal of Business Ethics*, vol. 144, no. 2, 2017, pp. 401-415.
  19. Matthes, Jörg, and Anke Wonneberger. "The Skeptical Green Consumer Revisited: Testing the Relationship Between Green Consumerism and Skepticism Toward Advertising." *Journal of Advertising*, vol. 43, no. 2, 2014, pp. 115-127.
  20. Minton, Elizabeth, et al. "Sustainable Marketing and Social Media: A Cross-Country Analysis of Motives for Sustainable Behaviors." *Journal of Advertising*, vol. 41, no. 4, 2012, pp. 69–84.
  21. Morhart, Felicitas, et al. "Brand Authenticity: An Integrative Framework and Measurement Scale." *Journal of Consumer Psychology*, vol. 25, no. 2, 2015, pp. 200–218.
  22. Moser, Andrea K. "Thinking Green, Buying Green? Drivers of Pro-Environmental Purchasing Behavior." *Journal of Consumer Marketing*, vol. 32, no. 3, 2015, pp. 167–175.
  23. Naderi, Iman, and Eric Van Steenburg. "Me First, Then the Environment: Young Millennials as Green Consumers." *Young Consumers*, vol. 19, no. 3, 2018, pp. 280-295.
  24. Nielsen, Richard P. "Changing Unethical Organisational Behavior." *Academy of Management Executive*, vol. 3, no. 2, 1989, pp. 123–130.
  25. Parguel, Béatrice, et al. "How Sustainability Ratings Might Deter 'Greenwashing': A Closer Look at Ethical Corporate Communication." *Journal of Business Ethics*, vol. 102, no. 1, 2011, pp. 15–28.
  26. Peattie, Ken, and Frank-Martin Belz. "Sustainability Marketing: An Innovative Conception of Marketing." *Marketing Review St. Gallen*, vol. 27, no. 5, 2010, pp. 8-15.
  27. Petty, Richard E., and John T. Cacioppo. *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. Springer-Verlag, 1986.
  28. Schmuck, Desirée, et al. "The Effects of Environmental Brand Attributes and Nature Imagery in Green Advertising." *Environmental Communication*, vol. 12, no. 3, 2018, pp. 414–429.
  29. Taufique, Khan M. R., et al. "The Influence of Eco-Label Knowledge and Trust on Pro-Environmental Consumer Behaviour in an Emerging Market." *Journal of Strategic Marketing*, vol. 24, no. 7, 2016, pp. 511–535.
  30. Timmermans, Stefan, and Iddo Tavory. "Theory Construction in Qualitative Research: From Grounded Theory to Abductive Analysis." *Sociological Theory*, vol. 30, no. 3, 2012, pp. 167–186.
  31. White, Katherine, et al. "Could You Turn Off the Lights? Approaches to Encouraging Sustainable Consumption in a Social Dilemma Context." *Journal of Consumer Psychology*, vol. 29, no. 3, 2019, pp. 1451–1465.

\*\*\*\*\*

## फैशन ब्रांडों की बिक्री बढ़ाने में सोशल कॉमर्स की भूमिका

डॉ. रुक्मणि यादव\* प्रो. प्रमोद यादव\*\*

\* सहायक प्राध्यापक, पीएमसीओई श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

\*\* सहायक प्राध्यापक, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आईपीएस अकादमी, इंदौर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - सोशल कॉमर्स ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया के सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो खरीदारी और उत्पाद प्रचार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। Facebook, youtube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म ने इस प्रवृत्ति को तेज कर दिया है, जिससे उपभोक्ता अपने पसंदीदा एप्लिकेशन से बाहर निकले बिना चीजों को खोज, देख और खरीद सकते हैं। यह सहज एकीकरण ग्राहकों के लिए खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाता है, इसे और अधिक सुविधाजनक और आनंददायक बनाता है। सोशल कॉमर्स व्यवसायों को लक्षित मार्केटिंग और व्यक्तिगत खरीदारी अनुभवों के माध्यम से उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए अभिनव तरीके प्रदान करता है। फैशन फर्म सोशल कॉमर्स को अपनाकर इस तकनीक-संचालित वातावरण में समृद्ध हो सकती हैं, जिससे सुविधा प्रदान करते हुए उपभोक्ताओं के साथ गहरे संबंध बन सकते हैं। सोशल कॉमर्स के लाभ में बढ़ी हुई उपभोक्ता वफादारी, कम विज्ञापन खर्च, बढ़ी हुई दृश्यता और डेटा-सूचित अंतर्दृष्टि शामिल हैं।

फैशन उद्योग में उत्पादों को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने और संभावित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बाजार विभाजन आवश्यक है। यह संगठनों को विभिन्न उपभोक्ता इच्छाओं और वरीयताओं को समझने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पाद, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन और वितरण में प्रभावी संशोधन की सुविधा मिलती है। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स मार्केटिंग रणनीतियाँ दुनिया भर में बाजार तक पहुँच को व्यापक बनाकर, जुड़ाव को बढ़ाकर और उपभोक्ता इक्विटी को बढ़ाकर राजस्व बढ़ा सकती हैं। सोशल कॉमर्स, जो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ सोशल नेटवर्किंग को एकीकृत करता है, अनुकूलित उत्पाद सुझाव और अत्यधिक लक्षित विज्ञापन जैसे लाभ प्रदान करता है। फिर भी, यह एल्गोरिदमिक परिवर्तन, प्रतिष्ठा संबंधी खतरे, सीमित उत्पाद प्रतिनिधित्व, साइबर सुरक्षा मुद्दे और बाजार की अधिकता जैसी कमियाँ भी प्रस्तुत करता है। उतार-चढ़ाव वाले बाजार में लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए फैशन कंपनियों के लिए बाजार विभाजन महत्वपूर्ण है।

**शब्द कुंजी** - सोशल कॉमर्स, फैशन, उपभोक्ता, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स।

**प्रस्तावना** - जब आप सोशल मीडिया साइट्स पर सीधे चीजें खरीदते और बेचते हैं, तो आप 'सोशल कॉमर्स' कर रहे होते हैं। पहले यह सिर्फ उत्पादों की समीक्षा और सुझाव हुआ करता था, लेकिन अब पोस्ट पर क्लिक करके उन्हें खरीदा जा सकता है और खरीदारी भी पहले से ही हो जाती है। जब सोशल मीडिया और इंटरनेट शॉपिंग एक साथ इतने अच्छे से काम करते हैं, तो ग्राहकों को ज्यादा दिलचस्प और इंटरैक्टिव शॉपिंग अनुभव मिल सकता है। हमारे खरीदारी करने का तरीका बदल रहा है क्योंकि सोशल कॉमर्स पूरे शॉपिंग अनुभव को सोशल मीडिया साइट्स पर डाल रहा है। Facebook, youtube और Instagram जैसे विशाल प्लेटफॉर्म, जिन पर अरबों सक्रिय लोग हैं, ने इस चलन को तेज कर दिया है। लोग अपने पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप को छोड़े बिना सोशल कॉमर्स के जरिए सामान ढूँढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप Instagram पर देखते समय कोई उत्पाद देख सकते हैं, उसे अपनी कार्ट में जोड़ सकते हैं और फिर ऐप को छोड़े बिना उसे खरीद सकते हैं। उपयोगकर्ता इस सहज विलय में रुचि रखते हैं, जिससे खरीदारी भी आसान हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सोशल बिजनेस को बढ़ने में भी मदद मिल रही है। दुनिया भर में 92% इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने फोन पर वेब का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया साइट्स खरीदारी का एक स्वाभाविक

हिस्सा बन गई हैं।

सोशल कॉमर्स कंपनियों को लक्षित मार्केटिंग और कस्टमाइज्ड शॉपिंग अनुभवों के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने के नए तरीके भी देता है। डेटा और AI का उपयोग करके, स्टोर व्यक्तिगत सौदे और सुझाव दे सकते हैं, जिससे खरीदारी का अनुभव हर तरफ बेहतर हो जाता है।

संक्षेप में, सोशल कॉमर्स खरीदारी को आसान, अधिक मजेदार और प्रत्येक ग्राहक के लिए अधिक अनुकूल बनाकर स्टोर के काम करने के तरीके को बदल रहा है। जैसा कि व्यवसाय और ग्राहक यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बदलते चलन का पालन कैसे किया जाए, यह एक रोमांचक समय है।

**अध्ययन का उद्देश्य:**

1. फैशन ब्रांड्स की मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियों पर सोशल कॉमर्स के प्रभाव की जांच करना।
2. प्रभावी मार्केटिंग और बिक्री के लिए सोशल कॉमर्स के पक्ष और विपक्ष की पहचान करना।
3. फैशन की सफलता में बाजार विभाजन का महत्व।

**फैशन ब्रांड्स की मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियों पर सोशल कॉमर्स के प्रभाव** - ई-कॉमर्स को सोशल मीडिया के साथ जोड़कर, 'सोशल कॉमर्स' ने फैशन फर्मों द्वारा अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के तरीके में

क्रांति ला दी है। इस विलय के परिणामस्वरूप व्यापार करने का एक अधिक सहभागी और ग्राहक-केंद्रित तरीका सामने आया है।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री विज्ञापनों के एक आवश्यक घटक के रूप में उभरी है। जब ग्राहक अपने अनुभव, स्टाइल संबंधी सिफारिशें और उत्पाद मूल्यांकन सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं, तो प्रामाणिक ब्रांड समर्थन स्थापित होता है। यह विश्वास बनाने में मदद करता है और ब्रांड को अधिक भरोसेमंद बनाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसे और बढ़ाती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर प्रभावी रूप से ब्रांड और उनके लक्षित दर्शकों के बीच की खाई को पाटते हैं, जिससे दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ती है।

दूसरा, इंस्टाग्राम शॉप्स और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा प्रत्यक्ष खरीदारी के अनुभव संभव हो गए हैं। ग्राहक ऐप को छोड़े बिना सहजता से उत्पादों को ब्राउज, खोज और खरीद सकते हैं। उपयोग में यह आसानी खरीदारी प्रक्रिया को छोटा करती है, जिससे राजस्व बढ़ता है।

लाइव स्ट्रीमिंग, पोल और प्रश्नोत्तर सत्र जैसे रीयल-टाइम जुड़ाव उपकरण ब्रांडों को अपने दर्शकों के साथ सीधे बातचीत करने, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और समुदाय की भावना पैदा करने की अनुमति देते हैं। ये इंटरैक्शन उपभोक्ता की पसंद और व्यवहार के बारे में भी जानकारी देते हैं।

इसके अलावा, सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डेटा और एनालिटिक्स ग्राहक की जनसांख्यिकी, खरीदारी के व्यवहार और ट्रेडिंग प्राथमिकताओं के बारे में उपयोगी जानकारी देते हैं। ब्रांड इस डेटा का लाभ उठाकर व्यक्तिगत अभियान तैयार कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।

अब रचनात्मक सामग्री के माध्यम से कहानी कहने पर जोर दिया जाने लगा है। फैशन ब्रांड अक्सर उपभोक्ताओं को लुभाने और ब्रांड के सिद्धांतों को बताने के लिए आकर्षक छवियों वाले पोस्ट और वीडियो बनाते हैं।

फैशन ब्रांड सोशल कॉमर्स को अपनाकर आज की तकनीक-संचालित दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। यह उन्हें अपने उपभोक्ताओं के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है और साथ ही उन्हें वह सुविधा भी प्रदान करता है जिसकी उन्हें जरूरत है।

### प्रभावी मार्केटिंग और बिक्री के लिए सोशल कॉमर्स के पक्ष और विपक्ष की पहचान करना।

जब विज्ञापन और बिक्री रणनीति की बात आती है, तो सोशल कॉमर्स कई तरह के फायदे और नुकसान पेश करता है।

#### फायदे:

**बेहतर जुड़ाव के जरिए ग्राहक वफादारी में सुधार:** सोशल कॉमर्स पोल, डायरेक्ट मैसेजिंग और लाइव स्ट्रीम के जरिए ग्राहकों के साथ रीयल-टाइम इंटरैक्शन की अनुमति देता है, जिससे व्यक्तिगत संबंध बनते हैं।

Instagram शॉप और इसी तरह के प्लेटफॉर्म ऐप से बाहर निकले बिना खरीदारी करना संभव बनाते हैं, जो खरीदारी की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाता है और ग्राहकों के लिए इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाता है।

**विज्ञापनों पर पैसे बचाएँ:** प्रभावशाली मार्केटिंग और उपयोगकर्ता-जनित सामग्री का लाभ उठाकर, आप विश्वसनीयता या प्रामाणिकता का त्याग किए बिना महंगे पारंपरिक विज्ञापनों पर कटौती कर सकते हैं।

**बढ़ा हुआ एक्सपोजर:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बड़े उपयोगकर्ता आधार

की बढ़ौलत, मार्केटर्स अपने व्यक्तिगत विज्ञापनों और AI-संचालित सुझावों के साथ दुनिया भर के लोगों तक पहुँच सकते हैं।

**डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेट्रिक्स उपभोक्ता की आदतों और स्वाद के बारे में आकर्षक विवरण प्रकट करते हैं, जिससे ब्रांड अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं।

**विपक्ष:** जब ब्रांड किसी खास प्लेटफॉर्म पर काफी हद तक निर्भर होते हैं, तो वे एल्गोरिदम समायोजन और नीति संशोधनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

**प्रतिष्ठा के लिए खतरा:** असंतुष्ट ग्राहकों की समीक्षा या टिप्पणियाँ जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं, जिससे कंपनी की छवि खराब हो सकती है।

प्लेटफॉर्म द्वारा उन पर लगाए गए नियमों के कारण ब्रांड खुद को अभिव्यक्त करने और अपने उत्पादों को निजीकृत करने की अपनी क्षमता में सीमित हैं।

ग्राहक साइबर सुरक्षा चिंताओं, जैसे डेटा उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने में झिझक सकते हैं।

**ओवरसैचुरेशन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर के कारण, छोटे ब्रांडों को खुद को अलग पहचान दिलाना अधिक चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

ब्रांड इन कठिनाइयों से सक्रिय रूप से निपटकर इसके खतरों को कम करते हुए सोशल कॉमर्स का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

**फैशन की सफलता में बाजार विभाजन का महत्व:** तीव्र प्रतिस्पर्धा फैशन उद्योग की पहचान है, क्योंकि कई ब्रांड और कंपनियाँ उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। फैशन उत्पादों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने और संभावित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, एक प्रभावी विपणन रणनीति को लागू करना आवश्यक है। फैशन कंपनियों को सबसे हालिया रुझानों के लिए प्रासंगिक बने रहना चाहिए और उपभोक्ता आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उद्योग में उपभोक्ता प्राथमिकताएं और रुझान तेजी से बदलते रहते हैं। एक गतिशील बाजार में, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद पेशकशों और विपणन रणनीतियों को अनुकूलित करने में उत्तारदायी होना महत्वपूर्ण है।

मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग रणनीतियों के विकास में अपरिहार्य है, क्योंकि यह संगठनों को ऐसी रणनीतियाँ विकसित करने में सक्षम बनाता है जो उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक और अनुकूलनीय हों। यह उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से खुद को अलग करने, संभावित उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। बाजार विभाजन संगठनों को उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रत्येक खंड के लिए उत्पाद, मूल्य, प्रचार और वितरण में अधिक कुशल समायोजन संभव हो पाता है।

कंपनियाँ सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापक और अधिक खंडित बाजार तक पहुँचकर उपभोक्ताओं की जरूरतों और इच्छाओं की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए उनसे सीधे बातचीत कर

सकती हैं। फैशन कंपनियाँ उचित बाजार विभाजन के कार्यान्वयन के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पादों को समायोजित करके अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, फैशन कंपनियाँ उपयुक्त बाजार विभाजन को नियोजित करके इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित कर सकती हैं, जो ओवरस्टॉकिंग या अंडरस्टॉकिंग की संभावना को कम करता है, जो संभावित रूप से लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है।

कई तरीकों से सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स मार्केटिंग रणनीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से फैशन उत्पादों को अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। प्रारंभ में, वैश्विक बाजार पहुंच का विस्तार, बढ़ी हुई सहभागिता का विकास और ग्राहक इक्विटी में वृद्धि सोशल मीडिया मार्केटिंग गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे, ई-कॉमर्स फैशन कंपनियों को एक व्यापक और अधिक विशिष्ट बाजार खंड को लक्षित करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, अपने बाजार का विस्तार करने, बिक्री प्रक्रिया को अनुकूलित करने, बिक्री क्षमता बढ़ाने, उपभोक्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने, ब्रांड जागरूकता बढ़ाने और नकली उत्पादों के जोखिम को कम करने के लिए, व्यापारियों को अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहिए और सोशल मीडिया पर सामग्री तैयार करनी चाहिए।

इसके अलावा, इंटरनेट और ऑनलाइन चैनलों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया में एक शक्तिशाली साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें नकली उत्पादों के जोखिम को कम करने की क्षमता है, विशेष रूप से उच्च-स्तरीय फैशन क्षेत्र में। नतीजतन, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया का लाभ उठाने वाली मार्केटिंग रणनीतियों को लागू करके फैशन उत्पादों की लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है, जो वैश्विक बाजार का विस्तार करने और अधिक उपभोक्ता जुड़ाव को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। व्यापारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने फैशन उत्पादों का विपणन करके अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी और भौतिक खुदरा प्रतिष्ठानों की सीमाओं को दरकिनार किया जा सकेगा। व्यापारी अपने ब्रांड की पहुंच को व्यापक बनाकर और ई-कॉमर्स के माध्यम से संभावित उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करके ब्रांड पहचान बढ़ा सकते हैं और खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

**निष्कर्ष** –सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग का एक साथ उपयोग, जिसे 'सोशल कॉमर्स' के रूप में जाना जाता है, उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके को बदल रहा है। लोगों को अब Facebook, youtube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को खोजने, ब्राउज करने और खरीदने

के लिए अपने पसंदीदा एप्लिकेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह प्राकृतिक मिलन खरीदारी को अधिक आनंददायक और कम बोझिल बनाता है। सोशल कॉमर्स फर्मों को अनुकूलित उत्पाद अनुशंसाओं और अत्यधिक लक्षित विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। समकालीन प्रौद्योगिकी-उन्मुख परिदृश्य में, फैशन फर्म सोशल कॉमर्स के उपयोग के माध्यम से फल-फूल सकती हैं। यह उपभोक्ताओं के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करेगा और उनकी सहजता की मांग को पूरा करेगा।

मार्केटिंग और बिक्री सोशल कॉमर्स से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अधिक एक्सपोजर, कम विज्ञापन लागत, अधिक वफादार ग्राहक और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें एल्गोरिदम में बदलाव, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, प्रतिबंधित उत्पाद अभिव्यक्ति, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और अतिसंतृप्ति शामिल हैं। फैशन उद्योग में ग्राहकों की इच्छाओं और जरूरतों को निर्धारित करने और वितरण, मूल्य निर्धारण, प्रचार और उत्पादों में प्रभावी बदलाव करने के लिए बाजार को विभाजित करना आवश्यक है। ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के इस्तेमाल से वैश्विक स्तर पर ब्रांड जागरूकता, उपभोक्ता भागीदारी और राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ऑनलाइन चैनल व्यापारियों को नकली सामान कम करने, ब्रांड पहचान बढ़ाने और भौगोलिक सीमाओं से बचने की अनुमति देते हैं, ये सभी चीजें अधिक मुनाफे और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले फैशन उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धा में योगदान करती हैं।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Nurpauzi, C., Alghazli, M., Khoirusifa, S., Hafidz, G., & Reviansyah, S. (2024). Influence of Market Segmentation on Fashion Products on Profitability Levels with Marketing Strategies Through Social Media and E-Commerce. *JUSTINFO | Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.33197/justinfo.vol1.iss2.2023.1746>.
2. IIFT Bangalore Blog(<https://www.iiftbangalore.com/blog/the-fashion-revolution-how-social-commerce-is-redefining-the-industry/>)
3. <https://www.wahool.com/resources/social-commerce-why-its-the-future-of-fashion/>
4. Pandey, S., and Chawla, D. (2019). Engaging m-commerce adopters in India. *J. Enterp. Inf. Manag.*, 32, 191-210. <https://doi.org/10.1108/JEIM-06-2018-0109>.

\*\*\*\*\*

## ई.एम.आई. चार्वाक दर्शन और मानव जीवन (सुभाषनगर, सागर के संदर्भ में)

प्रिया ठाकुर\* डॉ. सुनील साहू\*\*

\* छात्र, बीए तृतीय वर्ष, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत  
\*\* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – ई.एम.आई. का उपयोग आजकल एक आम सी बात हो गई है फिर चाहे वह एक मोबाइल फोन के लिए किए गए ई.एम.आई. के उपयोग से नाता रखता हो या चाहे बड़े-बड़े वाहनों और मशीनों के लिए ई.एम.आई. के उपयोग की बात हो एक व्यक्ति किसी ऋण और साथ ही किसी वस्तु के लिए ई.एम.आई. का उपयोग करता है ई.एम.आई. के उपयोग में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी प्रबल भागीदारी देखने में सामने आई है। ई.एम.आई.के द्वारा व्यक्ति अपनी कम आय में भी अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। चार्वाक दर्शन तीन नास्तिक दर्शनों में से प्रमुख नास्तिक दर्शन है। जो वर्तमान जीवन में सुख को महत्व देता है। इसका मानना है कि भविष्य की अनिश्चितियों के बजाय वर्तमान में सुख का अनुभव करना चाहिए। इस शोध पत्र में ई.एम.आई. सुविधा का उपयोग कर रहे व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। मासिक आय के आधार पर 10000 - 20000 तक वेतन पाने वाले लोगों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ई.एम.आई. के उपयोग की प्रवृत्ति अधिक देखी गई लगभग 73.3 प्रतिशत लोगों द्वारा वाहन के लिए ई.एम.आई. का उपयोग किया जा रहा है जबकि 16.7 प्रतिशत लोगों द्वारा किसी ऋण के लिए ई.एम.आई. की किस्त भरी जाती है। शोध पत्र में ई.एम.आई. सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की समस्याएं व सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

**शब्द कुंजी** – ई.एम.आई., चार्वाक दर्शन, मानव जीवन, ऋण।

**प्रस्तावना** – ई.एम.आई. क्या है ?

ई.एम.आई. का शाब्दिक अर्थ है सामान मासिक किस्त जिसे अंग्रेजी में Equated Monthly Installment भी कहा जा सकता है जब हम किसी कंपनी या बैंक से बड़ी राशि का ऋण लेते हैं तो उसके लाभ के साथ मूल राशि पर ब्याज भी जुड़ जाता है इस बढ़ती राशि को हम मासिक रूप से किश्त भरकर समाप्त कर सकते हैं इस मासिक किश्त का भुगतान ही ई.एम.आई. कहलाता है।

ई.एम.आई. वर्तमान मानव के लिए एक सुविधा का विषय है। ई.एम.आई. आजकल प्रत्येक वस्तु के लिए एवं अपनी आवश्यकताओं तथा अपनी शौक को पूरा करने का सबसे सरल रास्ता है। जिन व्यक्तियों का यह अनुमान होता है कि भविष्य में उनकी आय के स्रोत स्थिर बने रहेंगे या बढ़ाने की संभावना है वह अपनी वर्तमान आय कम होने के बावजूद अपनी अव्यवस्थाओं एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का क्रय इस आधार पर कर लेता है कि वह उन वस्तुओं का भुगतान ई.एम.आई. पर कर सकता है।

ई.एम.आई. के द्वारा व्यक्ति अपनी कम आय में भी अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है इस शोध पत्र में किसी व्यक्ति के जीवन के किसी विभिन्न पहलुओं अथवा सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन पर ई.एम.आई. के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया है। आजकल चार्वाक दर्शन के अनुसार यदि सुख प्राप्त करने के लिए उधार लेना पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह दर्शन इस विचार को प्रकट करता है कि

जब तक जीवन है, सुख से जीना चाहिए और यदि इसके लिए उधार लेना पड़े तो लेना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उधार चुकाने की चिंता नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 'ऋणकृत्वा घृतम पिबेत्' अर्थात् 'ऋण लेकर भी घी पियों।'

**शोध प्रविधि** – प्रस्तुत शोध पत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है जिसमें सर्वप्रथम प्रति चयन रीति का प्रयोग किया गया है। इस विधि के द्वारा कार्य क्षेत्र में से 30 इकाइयों का चयन किया गया है एवं उनका सर्वे किया गया सर्वे करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई जिसमें करीब 30 प्रश्नों के माध्यम से डेटा संग्रहण रीति के अंतर्गत जानकारी एकत्र की गई।

एकत्रित किए गए आंकड़ों को उनके समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत करके तत्पश्चात उनको सारणी के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। यंत्र एवं तकनीक के तौर पर प्राविधिक साक्षात्कार एवं अंतिम साक्षात्कार अनुसूची, सामान्य गणितीय रीति प्रतिशत रीति एवं ग्राफ चित्रों का प्रयोग किया गया है।

**साहित्य समीक्षा**

1. **कोयंबटूर शहर में वाणिज्यिक बैंकों के समान मासिक किस्त ई.एम.आई विकल्पों के प्रति उधारकर्ता की संतुष्टि** – बैंकिंग उद्योग सहित प्रत्येक उद्योग में ग्राहक संतुष्टि आवश्यक है। बैंकिंग संस्थान ई.एम.आई. सुविधा अपनी प्रभावी सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अन्वेषक ने ग्राहक संतुष्टि का विश्लेषण

करने और कोयंबटूर में वाणिज्यिक बैंकों में ई.एम.आई. ऋण सेवा के प्रभावों की जाँच करने का एक प्रयास किया है। उत्तरदाताओं की मासिक आय अधिक है और उन्होंने कोयंबटूर शहर में विलासिता की वस्तुओं और वाहनों को खरीदने के लिए ऋण लिया है।

**2. भारत में ई.एम.आई. निर्भरता का विकास : ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण** - समान मासिक किश्तें (ई.एम.आई.) उपभोक्ता वित्तपोषण की प्रमुख विशेषता बन गई हैं। जिससे परिवारों को बिना किसी अग्रिम भुगतानों के सामान और सेवाएँ खरीदने की अनुमति मिलती है। 2010 के बाद की अवधि में ई.एम.आई. संचालित ऋण में विस्फोट देखा गया। जिसमें आवास ऋण सबसे आगे रहे। वित्तीय वर्ष 2023 तक गृह ऋण कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का 47.7 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि 2005 में यह केवल 25 प्रतिशत था। (सीआरआईएफ हाई मार्क-2024)।

‘अभी खरीदें बाद में भुगतान करें’ (बीएनपीएल) योजनाओं जैसे अभिनव वित्तीय उत्पादों की शुरुआत ई.एम.आई. के उपयोग को और बढ़ावा दिया है।

**3. समान मासिक किश्त ई.एम.आई. योजनाएँ और अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) सेवाएँ कैसे आवेगपूर्ण खरीदारी को बढ़ावा देती है।** - ई.एम.आई. योजनाएँ और बीएनपीएल सेवाएँ काफी लचीलापन और सुविधा प्रदान करती हैं। लेकिन उनके साथ कुछ संभावित जोखिम भी जुड़े हैं, जिनका ग्राहकों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। शोध के अनुसार, यदि ऋण का उचित उपयोग नहीं किया जाता है तो अस्थिर भुगतान और आसान ऋण उपलब्धता की अपील के परिणामस्वरूप आवेगपूर्ण व्यय और अधिक वित्तीय कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

**4. मुम्बई की आय का 50 प्रतिशत से ज्यादा रकम ई.एम.आई. पर खर्च।**

**जानकारी संग्रह** - शोध पत्र के लिए तैयार किए गए प्रश्नों की प्रश्नावली के द्वारा कार्य क्षेत्र के लोगों का सर्वे कर आंकड़े एकत्रित किए गए। सर्वे के माध्यम से लोगों से निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए गए -

**उनसे प्राप्त आंकड़े निम्न अनुसार हैं-**

**आयु के आधार पर वर्गीकरण** - इस शोध पत्र के सर्वे के लिए 30 लोगों को चुना गया। जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया। 30 - 40 आयु वर्ग के लोगों में ई.एम.आई. के अधिक उपयोग की प्रवृत्ति देखी गई अर्थात् 30-40 का आयु वर्ग एक ऐसी अवस्था है जहां लोगों द्वारा नई वस्तुओं एवं नई इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में धन का निवेश किया जाता है।

**सारणी - 01: आयु के आधार पर वर्गीकरण**

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
20-30	1	3.5%
30-40	15	50%
40-50	5	16.6%
50-60	7	23.3%
60-70	2	6.6%
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

**लिंग के आधार पर वर्गीकरण** - सारणी एवं पाई चार्ट के आधार पर ई.एम.आई. के उपयोग का विवरण दर्शाया गया है। जिसमें 30 प्रतिशत महिला उत्तरदाता एवं 70 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता हैं। इस विवरण में असमानता के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारक हो सकते हैं। जिसमें पुरुषों की अधिक आय होने की संभावना है। जिससे उनकी क्रेडिट तक बेहतर पहुँच और ई.एम.आई. भुगतान करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही कुछ पारंपरिक लैंगिक कारक भी इस असमान विवरण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

**सारणी - 02: लिंग के आधार पर वर्गीकरण**

लिंग वर्ग	संख्या	प्रतिशत
महिला	9	30%
पुरुष	21	70%
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

**पेशे के आधार पर वर्गीकरण** - पेशे के आधार पर स्वरोजगार करने वाले लोगों का प्रतिशत ई.एम.आई. के उपयोग में सर्वाधिक 36.7 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि सबसे कम प्रतिशत 13.4 प्रतिशत निजी संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों का प्राप्त हुआ है। स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों में ई.एम.आई. के उच्च प्रतिशत विभिन्न कारणों से हो सकते हैं जैसे व्यवसायिक सम्पत्तियों (जैसे - उपकरण) में निवेश, ऋणों के माध्यम से व्यक्तिगत खर्च आदि। निजी क्षेत्र में ई.एम.आई. की हिस्सेदारी कम होने का कारण व्यक्तिगत खर्चों पर ऋणों की कम निर्भरता हो सकता है।

**सारणी - 03: पेशे के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण**

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
स्वरोजगार	11	36.7%
व्यापारी	07	23.3%
निजी संस्था में कार्यरत	04	13.4%
सरकारी कर्मचारी	08	26.6%
बेरोजगार	-	-
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

**मासिक आय के आधार पर वर्गीकरण** - मासिक आय के आधार पर वर्गीकृत किये जाने पर रुपये 10000 - रुपये 20000 कमाने वाले लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक 33.4% है। इससे स्पष्ट होता है कि कम आय प्राप्त करने वाले लोग अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ई.एम.आई. के उपयोग पर जोर देते हैं।

मध्यम आय वर्ग वाले लोगों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नकद लेन-देन से करने का सामर्थ्य नहीं होता इसलिए वे ई.एम.आई. के माध्यम से अपनी आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

**सारणी - 04: मासिक आय के आधार पर वर्गीकरण**

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
<10,000	-	-
10,000 - 20,000	10	33.4%
20,000 - 30,000	8	26.6%
30,000- 40,000	7	23.3%
40,000 - अधिक	5	16.7%
कुल	30	100%



### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**ई.एम.आई. के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण** - ई.एम.आई. के राय के आधार पर 50 प्रतिशत लोगों का यह कहना था कि प्रारंभ में तो कोई कठिनाई नहीं होती परंतु बाद में भुगतान करने में असुविधा होती है। इसका कारण यह हो सकता है कि प्रारंभ में व्यक्ति यह सोचकर ई.एम.आई. के लिए राजी हो जाता है कि इसका भुगतान बाद में भी किस्तों के रूप में भी कर सकता है किंतु प्रत्येक किस्त के समय उसे किसी न किसी करणों से ई.एम.आई. भरने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है।

### सारणी - 05: ऋण ई.एम.आई. की दस्तावेजी प्रक्रिया के अनुभव के आधार पर

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
सुविधाजनक	15	50%
बाद में कठिनाई	15	50%
नुकसान दायक	-	-
कुल	30	100%

### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**ई.एम.आई. सुविधा लेने के कारण के आधार पर वर्गीकरण** - इस आधार पर किए गए वर्गीकरण से पता चला कि 73.3% लोगों ने ई.एम.आई. सुविधा लेने का कारण वाहनों के क्रय करने की है जबकि केवल 16.7% लोगों ने ही ऋण के लिए ई.एम.आई. का भुगतान करते पाए गए हैं। वाहनों के लिए ई.एम.आई. भुगतान का उच्च प्रतिशत इस बात का संकेत हो सकता है कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वाहन खरीदने के लिए ई.एम.आई. जैसे वित्तपोषित साधनों का सहारा लेता है यह वाहनों की ऊँची कीमत एवं उपयोगी होने के कारण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ई.एम.आई. के लिए दूसरा सबसे आम कारण ऋण होता है जो व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण या शिक्षा ऋण हो सकता है।

### सारणी - 6: ई.एम.आई. भरने के कारण के आधार पर वर्गीकरण

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
ऋण	05	16.7
वाहन	22	73.3
वस्तु	03	10
कुल	30	100%

### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**ऋण की राशि के आधार पर वर्गीकरण** - ई.एम.आई. भरने का कारण पूछे जाने पर 30 में से पांच लोग अर्थात 16.7% लोगों का कारण ऋण पाया गया। इसी आधार पर एक और प्रश्न पूछा गया जो था कि आपका ऋण की राशि क्या है इसी आधार पर किए गए ऋण की राशि के वर्गीकरण में पाया गया की 60% लोगों अर्थात तीन लोगों ने 5 लाख से 50 लाख तक का लोन लिया है।

ऋण राशियों का वितरण इस बात का संकेत देता है कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवास, शिक्षा और व्यवसायिक उद्यमों जैसे प्रमुख कारकों के लिए ऋण लेता है।

### सारणी - 7: ई.एम.आई. भरने के कारण के आधार पर वर्गीकरण

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
50,000 - 1,00,000	-	-
1,00,000 - 5,00,000	1	20%

5,00,000 - 50,00,000	3	60%
50,00,000 - 1,00,00,00,0	1	20%
कुल	5	100

### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**बचत के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण** - लोगों से पूछा जाने पर कि वे बचत करते हैं या नहीं सभी का जवाब हां मिला फिर बचत का प्रकार पूछे जाने पर 40% लोगों का कहना था कि वे गहने खरीद कर बचत करते हैं जबकि 13.4% लोगों का कहना था कि वह अपने पैसों को बैंक में रखकर बचत करते हैं।

गहनों में बचत करने की उच्च प्राथमिकता यहाँ की सोच को परिलक्षित करती है। निवेश और सुरक्षा के रूप में सोने और अन्य कीमती धातुओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बैंक खाते, डाकघर खाते और संपत्ति निवेश भी पैसे बचाने के प्रमुख साधन हैं।

### सारणी - 8: बचत के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
गहने खरीदकर	12	40%
बैंक खाते में पैसे रखकर	4	13.4%
पोस्ट ऑफिस के खाते द्वारा	7	23.3%
प्रॉपर्टी खरीदकर	7	23.3%
कुल	30	100%

### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**ई.एम.आई. के उपयोग से बचत प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण** - लोगों पर ई.एम.आई. के उपयोग से उनकी बचत प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर 83.4% लोगों का कहना है कि उनकी बचत की प्रवृत्ति में कमी आयी है जबकि 6.6% लोगों का कहना है की ई.एम.आई. के प्रयोग से उनके बचत में सहायता हुई।

अधिकांश उत्तरदाताओं (83.4 प्रतिशत) का मानना है कि ई.एम.आई. का भुगतान करने से उनकी बचत प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ई.एम.आई. से जुड़े मासिक व्यय के कारण हो सकता है। एक छोटे हिस्से का मानना है कि ई.एम.आई. ने उन्हें बचत करने में मदद की है। संभवतः यह अनुशासित खर्च और नियोजित वित्तीय खर्च के कारण हो सकता है।

### सारणी - 9: ई.एम.आई. के उपयोग से बचत प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
बचत में सहायता	2	6.8%
बचत में कमी	25	83.4%
बचत का मौका नहीं	3	10%
कुल	30	100%

### स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

**ई.एम.आई. की किस्त भरने में देरी के आधार पर वर्गीकरण** - ई.एम.आई. की किस्त भरने में देरी का प्रश्न पूछे जाने पर 60% लोगों का जवाब नहीं था जबकि 40% लोगों की किस्त भरने में देरी हुई है। उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने (40 प्रतिशत) ई.एम.आई. भुगतान में देरी की सूचना दी जो उन पर होने वाले आर्थिक दबाव की ओर संकेत करती है। इससे देर से भुगतान शुल्क, क्रेडिट स्कोर को नुकसान और शायद ऋण चूक तक की समस्याएँ पैदा हो सकती है।

**सारणी - 10: ई.एम.आई. की किस्त भरने में देरी के आधार पर वर्गीकरण**

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
हां	12	40%
नहीं	18	60%
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

**ई.एम.आई. के उपयोग से लाभ के आधार पर वर्गीकरण** -ई.एम.आई. के उपयोग से लाभ के आधार पर वर्गीकरण में पाया गया की 70% लोगों को ई.एम.आई. के उपयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का लाभ हुआ जबकि 23.3% लोगों का कहना है की ई.एम.आई. के उपयोग से उनके व्यापार में वृद्धि हुई। अधिकांश उत्तरदाताओं (70प्रतिशत) का मानना है कि ई.एम.आई. के उपयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। यह उपभोक्ता वस्तुओं के स्वामित्व और किश्तों के भुगतान कर पाने की क्षमता के कारण हुआ है।

**सारणी - 11: ई.एम.आई. के उपयोग से लाभ के आधार पर वर्गीकरण**

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
स्वयं का घर	2	6.7%
सामाजिक प्रतिष्ठा	21	70%
व्यापार में वृद्धि	7	23.3%
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

**ई.एम.आई. व्यवस्था से संतुष्टि के आधार पर वर्गीकरण** - जब लोगों से यह पूछा गया कि वह ई.एम.आई. व्यवस्था से वे कितने संतुष्ट हैं तो 66.6% लोगों का जवाब अधिक प्रसन्न था जबकि 20% लोगों ने कहा कि वह ई.एम.आई. व्यवस्था से बहुत अधिक प्रसन्न है। अधिकांश उत्तरदाता या तो सन्तुष्ट है या बहुत सन्तुष्ट है जो ई.एम.आई. की सकारात्मक धारणा को प्रस्तुत करता है हालांकि एक छोटा हिस्सा ( 13.1 प्रतिशत) कुद असन्तुष्टि व्यक्त कर रहे है जो ब्याज की उच्च दरों ई.एम.आई. का प्रबंधन न कर पाने जैसी समस्याओं के कारण हो सकता है।

**सारणी - 12: ई.एम.आई. व्यवस्था से संतुष्टि के आधार पर वर्गीकरण**

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक	6	20%
अधिक	20	66.6%
थोड़ा कम	4	13.4%
कुल	30	100%

**स्रोत- स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।**

इस शोध पत्र से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि ई.एम.आई. का उपयोग आजकल एक आम सी बात हो गई है फिर चाहे वह एक मोबाइल फोन के लिए किए गए ई.एम.आई. के उपयोग से नाता रखता हो या चाहे बड़े-बड़े वाहनों और मशीनों के लिए ई.एम.आई. के उपयोग की बात हो एक व्यक्ति किसी ऋण और साथ ही किसी वस्तु के लिए ई.एम.आई. का उपयोग करता है।

**निष्कर्ष :**

1. ई.एम.आई. के उपयोग में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी प्रबल भागीदारी देखने में सामने आयी है।
2. लोग एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं नो के लिए ई.एम.आई. का भुगतान करते हैं।  
पैसे के आधार पर स्वरोजगार करने वाले लोगों द्वारा ई.एम.आई. का उपयोग सर्वाधिक 36.7% किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी, व्यापारियों एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा क्रमशः 26.6%, 23.3%, 13.4% की संख्या में ई.एम.आई. का उपयोग किया जा रहा है।
3. मासिक आय के आधार पर 10000 - 20000 तक वेतन पाने वाले लोगों में ई.एम.आई. के उपयोग की प्रवृत्ति अधिक देखी गई।
4. लगभग 80% विवाहित लोगों द्वारा ई.एम.आई. का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से स्नातक उत्तीर्ण लोगों द्वारा ई.एम.आई. के उपयोग में संकीर्णता देखी गई जो की UG और PG के बारे में क्रमशः 33.4% और 40% है। लगभग 73.3% लोगों द्वारा वाहन के लिए ई.एम.आई. का भुगतान किया जा रहा है जबकि 16.7% लोगों द्वारा किसी ऋण के लिए ई.एम.आई. की किस्त भरी जाती है।

**अनुशंसाएँ :**

1. लोगों को किसी भी प्रकार के लोन एवं वस्तु को खरीदते समय अधिक डाउन पेमेंट करनी चाहिए ताकि ई.एम.आई. में कमी हो सके और बाद में इसकी अदायगी में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
2. यदि आप आर्थिक तनाव का सामना कर रहे हैं तो आपको लोन की अवधि को बढ़ाकर इएमआईको कम करने का प्रयास करना चाहिए।
3. लोगों को एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं वाहनों या लोन के लिए ई.एम.आई. का उपयोग नहीं करना चाहिए इससे उन पर आर्थिक तनाव बढ़ेगा।
4. फिक्स्ड दर की स्थान पर इएमआईके लिए फ्लोटिंग ब्याज दर को चुनना चाहिए।
5. ई.एम.आई. की दरें कम होनी चाहिए इसके लिए सरकार एवं बैंकों को योजनाएं बननी चाहिए।

**संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. <https://sist.sathyabama.ac.in/sistnaac/document/1.7.4/1922-6.com-B©.con-batchro-26pdf>
2. <https://ifcat.org/papers/1JCRT2304348.pdf>
3. <https://economictimes.indiatimes.com/topic/have-loan-eni>
4. <https://timerofindia.com/owadensklag!transfarmingoraragementmarket-one-/apple-winning-the-time-47642/>
5. <https://www.ijsdrang/papers/TTSDR1303030pdf>
6. <http://www.deshbandhu.coin/ectitanial/litetcomplex-challenges-of-fareigos-trade-768-05-2>
7. <https://search.app/RShRvRAGV6HAu7bp9>
8. <https://search.app/ydwdG5sBRcRXn82c8>
9. <https://search.app/DtquDQrSTTZwfXz97>
10. <https://egyankosh.ac.in>

# To Study the Dietary Pattern in the Second Trimester of Pregnancy

Dr. Mamta Khapediya\* Roshni Singh\*\*

\*Assistant Professor (Home Science) Mata Jijabai Govt. Girls P.G College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA

\*\* Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

**Introduction** - The second trimester of pregnancy is a crucial period for both fetal development and maternal health, as it marks significant physiological changes that require adequate nutrition and care. This phase, spanning from the 14th to the 27th week of gestation, is characterized by rapid fetal growth, organ development, and increased maternal physiological adaptations. Proper nutrition plays a vital role in ensuring that both the mother and the growing fetus receive the necessary nutrients for optimal health and well-being.

During the second trimester, the fetus undergoes substantial growth, including organogenesis, skeletal formation, and neurological development. The fetal brain starts developing more complex structures, the bones begin to ossify, and the baby's overall size increases significantly. As a result, there is a greater demand for essential nutrients such as calcium, iron, folic acid, and protein. Calcium is necessary for strong bones and teeth, iron supports red blood cell production, and folic acid is crucial for preventing neural tube defects. The mother's diet should be rich in these essential nutrients to support the baby's proper growth and development.

Simultaneously, the mother's body undergoes various physiological changes to accommodate the growing fetus. One of the most significant changes is an increase in blood volume to ensure that adequate oxygen and nutrients reach the developing baby. This increase in blood volume also raises the mother's need for iron to prevent anemia. Additionally, the metabolic rate rises, leading to higher energy requirements. The mother may also experience changes in digestion and metabolism, making it necessary to consume a well-balanced diet that provides sustained energy throughout the day.

A well-balanced diet during the second trimester is crucial for maintaining both maternal and fetal health. It should include an adequate intake of macronutrients such as carbohydrates, proteins, and healthy fats. Carbohydrates are the primary source of energy and should come from whole grains, fruits, and vegetables rather than processed or sugary foods. Proteins are essential for fetal tissue growth

and maternal muscle maintenance, and they can be obtained from lean meats, poultry, fish, eggs, legumes, and dairy products. Healthy fats, found in sources like nuts, seeds, avocados, and olive oil, are important for the baby's brain and nervous system development.

In addition to macronutrients, micronutrients play a significant role in ensuring a healthy pregnancy. Key vitamins and minerals include vitamin D, calcium, iron, folic acid, and omega-3 fatty acids. Vitamin D and calcium work together to promote strong bone development in the fetus while also supporting the mother's bone health. Omega-3 fatty acids, particularly DHA (docosahexaenoic acid), are essential for brain and eye development and can be found in fatty fish such as salmon and in fortified foods. Pregnant women should also ensure an adequate intake of fiber, as digestive issues such as constipation are common during pregnancy.

Hydration is another important aspect of maternal health during the second trimester. As blood volume increases, the body requires more fluids to maintain circulation and prevent dehydration. Pregnant women should aim to drink plenty of water throughout the day and limit the intake of caffeinated and sugary beverages. Herbal teas and fresh fruit juices can also be healthy alternatives, provided they are consumed in moderation.

In addition to maintaining a nutritious diet, pregnant women should engage in moderate physical activity, as recommended by their healthcare provider. Gentle exercises such as walking, prenatal yoga, and stretching can help improve circulation, reduce stress, and alleviate common pregnancy discomforts like back pain and swelling. However, it is essential to listen to the body and avoid overexertion.

Overall, the second trimester is a critical time for both the mother and baby, making proper nutrition and self-care essential. By consuming a balanced diet rich in essential nutrients, staying hydrated, and engaging in appropriate physical activity, expectant mothers can support their health and promote optimal fetal development. Consulting a healthcare provider or a nutritionist can further ensure that

individual dietary needs are met, contributing to a healthy and successful pregnancy journey.

**Importance :**

1. Provides essential nutrients: A well-balanced diet is crucial during pregnancy as it provides the essential nutrients required for both the mother’s well-being and the baby’s healthy development. Proper nutrition ensures an adequate intake of vital vitamins, minerals, and macronutrients, which play a key role in fetal growth, organ formation, and overall development. These nutrients support crucial bodily functions, such as cell production, brain development, and immune system strengthening. By maintaining a well-rounded diet rich in fresh fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats, expectant mothers can ensure both their health and the baby’s well-being throughout pregnancy.
2. Supports healthy weight gain: Adequate nutrition helps the mother gain the appropriate amount of weight during pregnancy, reducing the risk of complications such as gestational diabetes and preeclampsia.
3. Reduces the risk of birth defects: Getting enough folic acid, calcium and other vital nutrients can help prevent neural tube defects and other birth abnormalities.
4. Promotes healthy fetal development: Proper nutrition supports the baby’s brain development, bone growth and overall health in the womb.
5. Reduces the risk of pregnancy complications: A healthy diet can lower the risk of gestational diabetes, preeclampsia, preterm birth and other pregnancy related complications.
6. Sets the stage for long term health: Good nutrition during pregnancy can have lasting positive effects on the child health, reducing the risk of chronic diseases later in life.

**Objectives:**

1. To examine the dietary habits and nutritional intake of pregnant women during their second trimester.
2. To assess the level of knowledge and awareness regarding proper dietary patterns among expectant mothers.
3. To evaluate the impact of dietary choices on maternal health and fetal development.
4. To identify gaps in nutritional knowledge and provide recommendations for improving dietary practices during pregnancy.

**Sample size:** In this paper, 50 pregnant women (second trimester) has been selected by random sampling method.

**Variables**

1. Independent variable is pregnant women.
2. Dependent variables are dietary pattern, knowledge and awareness.

**Sources of data collection:** In this paper, primary source is structured questionnaire and secondary source is books, magazines, newspaper and internet.

**Tabulation and classification:** Table for knowing the dietary pattern among pregnant women during second trimester:

S.	Category	No. of samples	Percentage
1.	Have very good dietary pattern	9	18%
2.	Have good dietary pattern	12	24%
3.	Have satisfactory dietary pattern	18	36%
4.	Have poor dietary pattern	11	22%

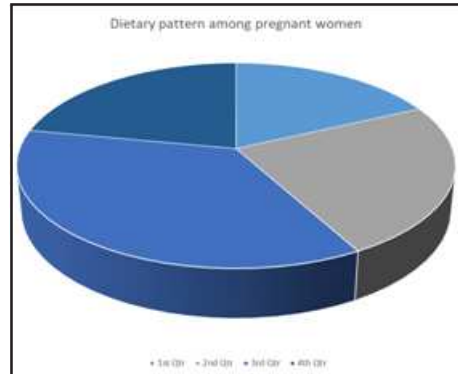
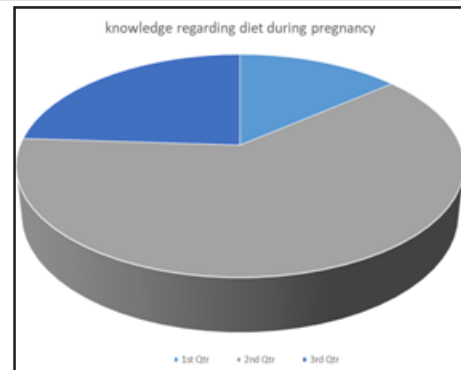


Table for assessing the knowledge and awareness about diet during pregnancy:

S.	Category	No. of samples	Percentage
1.	Have excellent knowledge	7	14%
2.	Have good knowledge	31	62%
3.	Have poor knowledge	12	24%



**Result and conclusions:** In this paper, we are able to know that 8% have very good, 24% have good, 36% have fair and 22% have poor dietary pattern during second trimester of pregnancy. Dietary pattern can be corrected by knowledge and awareness. So, 14% have excellent, 62% have good and 24% have poor knowledge and awareness regarding dietary pattern during pregnancy.

**Suggestion :** Diet plays a very important role in pregnancy because growth and development of fetus and health of mother is totally dependent on diet. So, we should educate mother regarding dietary pattern during pregnancy and bring awareness in the society.

**References:-**

1. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov>
2. <https://www.betterhealth.vic.gov.au>
3. <https://www.sciencedirect.com>
4. <https://onlinelibrary.wiley.com>
5. <https://www.researchgate.net>

## मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संगीता कुम्भारे\*

\*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था देश की विकेन्द्रीकृत नीति के अंतर्गत स्थापित हुई है। पंचायती राज के रूप में यह विषय मध्यप्रदेश को पंचायती राज व्यवस्था और उसके वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर केंद्रित है। छतरपुर जिले के कुल चयनित पंचायतों को उद्देश्य बना कर इसमें इन पंचायतों के आर्थिक प्रबंधन, बजटरी व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता देना है। ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। पंचायती राज व्यवस्था भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जो ग्राम पंचायतों को अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ प्रदान करती है। इस विश्वास के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास और प्रबंधन सम्बन्धी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार के 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार हुई थी जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियों का वितरण था।

पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण अंग है। 73वें संविधान संशोधन के बाद, यह व्यवस्था और सशक्त हुई है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों अंचलों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। भारत में पंचायती व्यवस्था केवल स्वतंत्रता के बाद की घटना नहीं है। वास्तव में, ग्रामीण भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्था सदियों से ग्राम पंचायत रही हैं। प्राचीन भारत में, पंचायतें आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली निर्वाचित परिषदें होती थीं। विदेशी प्रभुत्व, विशेष रूप से मुगल काल और ब्रिटिश काल के समय में प्राकृतिक, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को कम कर दिया था। हालाँकि, स्वतंत्रता-पूर्व काल में, पंचायतें गाँव के बाकी हिस्सों पर उच्च जातियों के प्रभुत्व के साधन थी, जिसने सामाजिक-आर्थिक स्थिति या जाति पदानुक्रम के आधार पर विभाजन को और बढ़ा दिया।

हालाँकि, संविधान के प्रारूपण के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज प्रणाली के विकास को गति मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है: 'राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।'

**कुँजी शब्द** - ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, वित्तीय मूल्यांकन, बजट आय-व्यय लेखा परीक्षण निधियों का प्रबंधन, विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक संरचना।

**प्रस्तावना** - मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था देश की विकेन्द्रीकृत नीति के अन्तर्गत स्थापित हुई है। पंचायती राज के रूप में ये विषय मध्यप्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था और उसके वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर केन्द्रीत है। छतरपुर जिले के कुछ चयनित पंचायतों को उद्देश्य बना कर इसमें इन पंचायतों को आर्थिक प्रबंधन बजटरी व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों का अध्ययन किया गया है। पंचायती राज का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता देना है। ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वतंत्रता से पूरा कर सकें।

पंचायती राज व्यवस्था भारत की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जो ग्राम पंचायतों को अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ प्रदान करती है। इस विश्वास के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। मध्यप्रदेश में इस व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार के 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार हुई थी जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियों का वितरण किया गया था।

**मध्य प्रदेश में पंचायती राज** - मध्य प्रदेश में पंचायती राज का तात्पर्य गांव के स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 और 1993 द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए अधिनियम पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज को ग्रामीण विकास और नागरिक केंद्रित शासन का दायित्व सौंपा गया है।

**मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास:**

1. जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की। इसका गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के कामकाज की जांच के लिए किया गया था।
2. मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करते हुए लोकतांत्रिक

विकेंद्रीकरण की सिफारिशों की। बाद में, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पर मेहता समिति की सिफारिशों की प्रयोज्यता की जांच के लिए 15 सदस्यीय पाण्डे समिति का गठन किया। पाण्डे समिति ने मेहता समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की। पाण्डे समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 पारित किया।

3. भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

4. मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 26 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश श्राम स्वराज्य स्थापित करने वाला पहला राज्य भी बना।

जैसा कि शोध का शीर्षक मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) है। किसी संगठन की वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वित्तीय साधनों के सभी पहलुओं का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है इसीलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय स्थिति को समझने की आवश्यकता है।

इस शोध में छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में वित्तीय मूल्यांकन का अध्ययन किया जायेगा जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास को निर्धारित किया जा सके और इस विकास में पंचायतों के महत्व को निर्धारित किया जा सके। जिसके द्वारा नई योजनाएँ और नीतियों के विकास के लिए प्रारूप तैयार किया जा सके।

**शोध अंतराल** - साहित्य समीक्षा में मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय विश्लेषण के पहलुओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। और इसीलिए यहां छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में वित्तीय सुदृढ़ता और विकास का एक साथ विश्लेषण किया जायेगा। शोध का मुख्य फोकस वित्तीय प्रदर्शन पर रहेगा और चयनित पंचायतों की वित्तीय गतिविधियाँ, क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान करती है? इत्यादि विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जायेगा। हालांकि छतरपुर जिले की पंचायतों का वित्तीय मूल्यांकन दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई नीतियों और योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव अभी भी सीमित है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और उत्तारदायी बनाने की आवश्यकता है।

**वित्तीय विकेंद्रीकरण:** वित्तीय विकेंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रक्रिया में पंचायतों को योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। छतरपुर जिले में पंचायतों को राज्य और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार होना, क्षमता की कमी और स्थानीय राजनीति।

**वित्तीय चुनौतियाँ और अवसर:** पंचायती राज संस्थाओं को अक्सर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। छतरपुर जिले की पंचायतों में भी संसाधनों की कमी है। समय पर फंड का आवंटन न होना और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ देखी गई हैं। इसके बावजूद कुछ पंचायतें अपने स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग करके विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं।

**सिफारिशें**

1. पंचायतों को वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
2. स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
3. वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए निगरानी तंत्र को सशक्त बनाया जाए।
4. यह साहित्य समीक्षा छतरपुर जिले की पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करती है जो कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

**शोध के उद्देश्य** - उद्देश्य वह है जिसे हम पाना चाहते हैं, जब भी कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो सर्वप्रथम लक्ष्य या उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लिये जाते हैं ताकि कार्य में गम्भीरता आ सके और शोध कार्य अपनी निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़े एवं जो अनुसंधान को दिशा प्रदान करें।

1. छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग की जांच करना।
2. छतरपुर जिले की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय विकेंद्रीकरण का आकलन करना।
3. छतरपुर जिले की पंचायतों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की मात्रा और उनकी आबंटन प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
4. छतरपुर जिले की पंचायतों द्वारा विकास कार्यों पर वित्तीय निवेश के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति का मूल्यांकन करना।
6. पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के प्रयासों का मूल्यांकन करना।
7. पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।
8. मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था छतरपुर जिले के अंतर्गत वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता और विकास को बढ़ावा देना है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए जिससे वे स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदार बन सके। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों का नियंत्रण भी सौंपा गया है।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य छतरपुर जिले की पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के उपयोग की गहराई से जांच करना है। यह अध्ययन इस बात की स्पष्टता प्रदान करेगा कि किस प्रकार से वित्तीय संसाधनों का आवंटन और प्रबंधन पंचायतों में किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

**शोध की परिकल्पनाएँ** - शोध हेतु किसी भी विषय का चयन तब किया जाता है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना हो। इस हेतु उद्देश्य को सार्थक सिद्ध करने के लिए एक सुव्यवस्थित वाक्य रूप परिकल्पना मानी जाती है। परिकल्पना एक विचार दशा या सिद्धांत होती है जो संभवतः बिना किसी विश्वास के साथ स्वीकार कर ली जाती है। जिससे कि उसके तार्किक परिणाम

निकाले जा सके और निर्धारित किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जाँच की जा सके। परिकल्पना शोध कार्य को निश्चितता प्रदान करती है।

### शोध की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित होगी:

1. छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों में कमी आई है।
2. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी के कारण संसाधनों का दुरुपयोग होता है।
3. वित्तीय विकेंद्रीकरण के बावजूद, छतरपुर जिले की पंचायतों में वित्तीय समस्याओं और प्रशासनिक चुनौतियों में सुधार नहीं हुआ है।

**शोध प्रविधि** - शोध प्रारूप एक वैचारिक संरचना है जिसके साथ शोध किया जाता है। यह समक के संग्रह, माप और विश्लेषण का एक ब्लू प्रिंट है। वर्तमान शोध मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध अध्ययन शोध विषय की रीतियों का चुनाव करना आवश्यक है। विषय के अध्ययन व अनुसंधान में सांख्यिकीय समक एकत्र करना जरूरी रहता है। सांख्यिकीय समक एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यही एक शोध की महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। जिस पर अनुसंधान रुपी भवन निर्मित होता है। यदि यह दोष पूर्ण रहता है तो परिणाम भी दोष पूर्ण रहेगा इसलिए समको को एकत्र करने से पहले कई बातों को ध्यान में रखना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। सांख्यिकीय अनुसंधान का पूर्व आयोजन ही इसकी सफलता एवं श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है।

कुछ इकाइयों के आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण समस्या का अध्ययन किया जा सकता है संग्रहण के विचार से समक दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समक एवं द्वितीयक समक।

**1. प्राथमिक समक**- प्राथमिक समक वे समक हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। हो सकता है कि उस विषय के संबंध में आंकड़े पहले भी इकट्ठा किए गए हो तो अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग में लाने के लिए आरंभ से अंत तक समक नए सिरे से एकत्रित करता है। चूंकि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार संकलित किए जाते हैं इसलिए इन्हें प्राथमिक समक कहा जाता है। प्राथमिक समक संकलन से पूर्व शोध विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर उनके सुझावों को आधार मानकर प्रश्नावली, प्रत्यक्ष साक्षात्कार आदि से अनुसूची तैयार करके इनके अलावा सैंपलिंग, अवलोकन एवं सर्वेक्षण इत्यादि जिनका उपयोग करके अपने शोध प्रबंध के लिए शोध सामग्री एकत्रित की जायेगी शोध से संबंधित अध्ययन क्षेत्रों का परीक्षात्मक विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाएगा।

**2. द्वितीयक समक**- शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक समक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द्वितीयक समक वे समक होते हैं जो पहले से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किया जा चुका होता है। एक अनुसंधानकर्ता उनको अपने प्रयोग में लाता है। यहां वह संग्रह नहीं करता है वरन् किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री को प्रयोग में लाता है तो इस प्रकार के समक को द्वितीयक समक कहा जाता है। द्वितीयक समक सामग्री वह है जिसे मौलिक स्रोतों से प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया जाता है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु द्वितीयक समक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द्वितीयक समकों के

द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का वित्तीय मूल्यांकन (छतरपुर जिले की चयनित पंचायतों के विशेष संदर्भ में) की वार्षिक रिपोर्ट शैड्यूल अध्ययन से संबंधित पत्र-पत्रिकाएं, शोध पत्र, समाचार पत्र, वेबसाइट, जनरल एवं अन्य प्रकाशित समक शोध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों के लगातार कार्यकाल से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

**शोध उपकरण और तकनीक** - वर्तमान शोध के लिए वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न उपकरणों या तकनीकों का उपयोग किया जायेगा। इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

1. वित्तीय उपकरण/तकनीक
2. सांख्यिकीय उपकरण / तकनीक

**1. वित्तीय उपकरण/तकनीक:** वित्तीय प्रदर्शन के अध्ययन और विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन उपकरण

- i. बैलेंस शीट और आय विवरण का तुलनात्मक विवरण
- ii. बैलेंस शीट और आय विवरण का सामान्य विवरण
- iii. प्रचलन विश्लेषण
- iv. अनुपात विश्लेषण

**2. सांख्यिकीय उपकरण/तकनीक:** शोध की प्रकृति और मांग के अनुसार कुछ सांख्यिकीय उपकरणों/ तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

### सांख्यिकीय उपकरण :-

- i. माध्य
- ii. राह - संबंध

ये सभी बुनियादी सांख्यिकीय उपकरण हैं जिनका उपयोग सांख्यिकीय उपकरण के रूप में किया जायेगा और परिकल्पना का परीक्षण 5% स्तर के महत्व पर किया जायेगा। एमएस-एकॉल और एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का उपयोग अध्ययन को आसान करने के लिए किया जायेगा और प्रस्तुति की आवश्यकता के अनुसार ग्राफ और चार्ट के मात्रात्मक समक के उपयोग की गणना भी की जायेगी।

**निष्कर्ष** - एक वित्तीय प्रदर्शन, बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि खाते का विश्लेषण है। जिसके अंतर्गत पंचायतों की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता के साथ-साथ शोधन क्षमता, तरलता, वित्तीय जोखिम, पूंजी मिश्रण और कार्यशील पूंजी का वित्तीय प्रदर्शन की एक इकाई के अंतर्गत विश्लेषण किया जायेगा। यह पूंजी के बेहतर स्रोतों और अनुप्रयोगों को भी इंगित करेगा। वित्तीय प्रदर्शन, किसी संगठन की समग्र दक्षता, वित्तीय जोखिम और शोधन क्षमता की स्थिति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है।

उपरोक्त सभी पहलू किसी भी संगठन के वित्तीय विवरण के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। इन सभी पहलुओं का उचित उपयोग, बेहतर प्रबंधन का गार्ग प्रशस्त कर सकता है जो अंततः संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत मददगार हो सकता है। शोध पंचायती क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि यह शोध पंचायती विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शोध अध्ययन के निष्कर्ष योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हित धारकों के लिए सहायक होंगे जो पंचायती क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ajit Kumar Jain, Local Government of Finance in India, Proceedings of the National Conference on Emerging

- Trends in Indian Local Government Finance held at National Institute of Rural Development, October, 20-25, Hyderabad, 1996.
2. Anil, K. Singh, State Panchayati Acts: A Critical Review, Voluntary Action Network India, New Delhi, 1995.
  3. Arjun Y. Darshankar, Leadership in Panchayati Raj: A Study of Beed District of Maharastra, Panchsheel Prakashan, Jaipur, 1979.
  4. Aronson, J. Richard and Hilley L-John, Finance State and Local Governments, The Brooking Institution, Washington, 1986.
  5. Barnabas, A.P. and O.P. Bhora, Finances of Panchayati Raj Institutions Case Studies, MO [F], Mimeo, May, New Delhi, 1995.
  6. Battacharya, S-N, Community Development - An Analysis of the Programme in India, Academic Publications, Calcutta, 1970.
  7. Bhargava, B-S, Politico-Administrative Dynamics in Panchayati Raj System, Ashish Publishing House, New Delhi, 1978.
  8. Chief Planning Office, Handbook of Statistics 2008-2009.

\*\*\*\*\*



## वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता : कारण, प्रभाव और समाधान

प्रो. आरती बारोठिया\*

\*सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना - 'जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं, जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं'** मेलिंडा गेट्स का यह कथन प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है, बल्कि उनकी उनकी प्रासंगिकता का भी निर्धारण करता है। वस्तुतः हम भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और अगर बेटा का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिये इस समस्या से निपटने में असाधारण सुधारात्मक नीतियों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), 2020 के अनुसार, भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच-समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा।

### लैंगिक असमानता से तात्पर्य:

1. लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है।
2. वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।
3. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

चिंताजनक हैं आँकड़े:

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सूची में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले पाँच देशों में शामिल है।
- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत (150वाँ स्थान) का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है।
- जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा- बांग्लादेश (50वाँ), नेपाल (101), श्रीलंका (102वाँ), इंडोनेशिया (85वाँ) और चीन (106वाँ)।
- जबकि यमन (153वाँ), इराक (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
- राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वाँ स्थान) बेहतर रहा है।
- लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है, आकड़ों के अनुसार, केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ ही संसद तक पहुँच पाती हैं ( विश्व में 122वाँ स्थान)।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण यह है कि भारतीय राजनीति में पिछले 50 में से 20 वर्षों में अनेक महिलाएँ राजनीतिक शीर्षस्थ पदों पर रही हैं। (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता आदि)
- महिलाओं के लिये शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वाँ है।
- जबकि इस मानक पर वर्ष 2018 में भारत का स्थान 114वाँ और वर्ष 2017 में 112वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है।
- 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है।
- WEF के आँकड़ों के अनुसार, अवसरों के मामले में विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है- भारत (35.4%), पाकिस्तान (32.7%), यमन (27.3%), सीरिया (24.9%) और इराक (22.7%)।

लैंगिक असमानता का अर्थशास्त्र:

1. महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का करीब-करीब आधा हिस्सा हैं, और इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक और दूरगामी असर होते हैं, जिनका समाज के हर स्तंभ पर असर दिखता है।
2. इस का आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा असर होता है। विश्व बैंक समूह की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ी थी।
3. यह एक बड़ी हानि है, जिसकी व्यापकता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खास तौर से तब, जब हमें यह पता चलता है कि अगर पुरुष और महिला कामगारों का वेतन एकसमान कर दिया जाए, तो इससे विश्व की संपत्ति में हर व्यक्ति की जिंदगी में करीब 23 हजार 620 डॉलर की वृद्धि हो जाएगी।

### लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र:

1. **सामाजिक क्षेत्र में-** भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन-पालन तक ही सीमित है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिये जाने वाले निर्णयों में भी महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त करती है।
2. **आर्थिक क्षेत्र में-** आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष के पारिश्रमिक में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं रोजगार के अवसरों में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।
3. **राजनीतिक क्षेत्र में-** सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं परंतु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं।
4. **विज्ञान के क्षेत्र में-** जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि प्रगतिशीलता की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में भी स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रवेश ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्त्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडंबना ही है कि हम मिसाइल मैक के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय ए. पी.जे अब्दुल कलाम से तो परिचित हैं लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से परिचित नहीं हैं।
5. **मनोरंजन क्षेत्र में-** मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है।
6. **खेल क्षेत्र में-** खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती है। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही, पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा है।

### लैंगिक असमानता के कारण:

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है।

- महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
2. भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।
3. राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
4. वर्ष 2017-18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2017-18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन-दीव में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है।
5. महिलाओं के रोजगार की अंडर-रिपोर्टिंग (Under - Reporting) की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
6. शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

### असमानता को समाप्त करने के प्रयास:

1. समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
2. राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है तथा इसमें भारत, विश्व में 69वें स्थान पर है।
3. भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अंगीकृत 'बीजिंग डिवलरेशन एंड प्लेटफार्म फॉर एक्शन' को

- कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहले जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।
4. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।
  5. आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
  6. लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो-तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।
  7. आगे की राह लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों - परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है।
  8. लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है, फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और समाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है।

#### 'जेंडर बजटिंग' क्या है?

1. लैंगिक समानता के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है।
2. महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive Budgeting-GRB) को अंगीकार किया था। जीआरबी का उद्देश्य है- राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना।
3. लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों - परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है।
4. जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालाँकि, जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिये जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिये जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लिंग और समाज - डॉ. गोपाल कृष्ण अग्रवाल।
2. लिंग और लैंगिकता - डॉ. रविन्द्रनाथ मुखर्जी।
3. दृष्टि : आई.ए.एस.।
4. भारतीय महिलाएँ : सशक्तीकरण एवं महिला सहकारिता - डॉ. रानी प्रभा सोलंकी।

\*\*\*\*\*

# Water Quality Index of Mansarovar Pond at Dhar (M.P.)

Dr. Dara Singh Waskel\* Dr. Bhagwan Singh Patel\*\*

\*Assistant Professor (Zoology) PMCOE Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

\*\*Assistant Professor (Zoology) PMCOE Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

**Abstract: Water quality index (WQI):** Study of water Quality index and bacteriological assessment of Mansarovar Pond at Dhar (MP) to certain the quality of water for public consumption. The water quality index and bacteriological parameters of this pond were observed seasonally during 2023–2024. The results obtained from the study revealed that the WQI of the pond was well within the permissible limits (WHO) and (BIS) and water is safe for drinking purposes.

**Keywords:** Water quality index, bacteriological parameters, WHO, BIS.

**Introduction** - Our earth is unique and provides one environment for the evolution of our life and natural resources for its maintenance. But due to man-made activities these resources are consumed and regularly deteriorated. Water is one of the most precious natural resources and is essential for everything on our planet to grow and prosper (Buragohain et al. 2007).

WQI is one of the most effective ways to communicate information on water quality trends with indicators. WQI is commonly used for the detection and evaluation of water pollution and may be defined as a rating reflecting the composite influence of the overall quality of a number of water quality parameters. Water quality index refers to physical, chemical, and biological characteristics of water. In response to the need for a uniform understandable yardstick of water quality, scientists worked out to compile all the water quality parameters into some convenient approach to represent an index, a procedure generally described as a “Water Quality Index (WQI)” (Horton, 1965; Brown, 1972; Otta, 1978).

**Materials and Methods:** In the present study, WQI has been calculated on the basis of Physico-chemical parameters. The main objective of the study was to know the water pollution of potable water from Mansarovar Pond, district Dhar. We know that water is essential for the life of organisms, including human beings who depend on good quality of water.

The Water Quality Index (WQI) was calculated using a weighted arithmetic index method and the quality rating/sub-index (Qi) corresponding to the 1<sup>st</sup> parameter PI, is a number reflecting the relative value of this parameter. The QI was calculated by using the following expression:

$$WQI = \sum_{i=1}^n \{ [M_i (-) I_i / (s_i - l_i)] \} \times 100$$

Where:

$M_i$  = Estimated values of the parameter in the laboratory.

$I_i$  = Ideal value of the 1<sup>st</sup> parameter.

$S_i$  = Standard value of the 1<sup>st</sup> parameter.

(-) = The sign indicates the numerical difference of the two values, ignoring the algebraic sign.

The overall WQI was calculated by aggregating the quality rating (Qi) with unit weight (Wj) linearly.

$$WQI = \frac{(\sum_{i=1}^n Q_i W_i)}{(\sum_{i=1}^n W_i)}$$

Mansarovar pond from 6 selected stations is studied carefully, and the calculations are made. Below 100, it means the water is permissible for drinking purposes.

**Results and Discussion:** Overall water quality index of Mansarovar Pond during 2023–24 observed 68%. Sampling stations were found of very good quality, and 32% Sampling stations were found of “good” quality of water. Water quality rating was very good at two stations, and four stations are quality rating of “very good” status. Disinfection of community surface water, proper supply system, periodical quality monitoring of drinking water sources, simple and economical water treatments like filtration, boiling, reverse osmosis would promote beneficial to water body.

Obtained results indicate that bacteriological contamination of water is seen. Something suggests that the need of source protection and regular treatment of water at local filter plants and any lacuna may result in serious health problems.

During the study, pond minimum WQI of Mansarovar Pond water was 33.780 at Station III during 2024, while maximum WQI of the same was 56.270 at Station V during 2023.

Over all QWI of all the sampling station during 2023 was 45.876 while the overall WQI during was 44.323 which

indicate “good to very good” station of pond water quality. The present study was also revealed that out of six sampling station, four station were WQI below 50 indicating that water quality is “very good” remaining two sampling station higher WQI ranged between 50 to 60 indicating that the WQI is interior to other station. Still that station of water quality is good and fit for human consumption. The result obtained from Mansarovar Pond was clearly indicate usability of but the agriculture land around the pond and uses of pesticides, improper disposal wastes, creating man-made pollution inside the water body and it can be harmful for public health. An action plan for drinking water safety should be applied, the plan should be based on the principal of multi barrier approach where by protection barrier were used to ensure the cleanliness, safety and reliability of drinking water.

**Table 1: Rating scale for WQI**

S.	WQI values	Water quality rank
1	0-25	Excellent
2	26-50	Very good
3	51-75	Good
4	76-100	Poor
5	100<	Unfit for drinking

**Table 2: Station wise WQI of Mansarovar pond during 2023-24**

S.	station	2023			2024		
		QiWi	WQI	Status	QiWi	WQI	Status
1	I	51.18	41.50	Very good	51.22	42.68	Very good
2	II	45.05	37.45	Very good	46.03	38.20	Very good
3	III	46.44	37.77	Very good	41.58	33.78	Very good
4	IV	56.67	46.06	Very good	56.06	45.70	Very good
5	V	68.22	56.78	good	67.22	56.21	good
6	VI	66.25	53.20	good	63.58	53.47	good

**Table 3: Season wise WQI of Mansarovar pond during 2023-24**

S.	Sea son	2023			2024		
		QiWi	WQI	Status	QiWi	WQI	Status
1	Rainy	52.58	42.77	Very good	53.55	48.35	Very good
2	Winter	56.66	45.38	Very good	55.48	42.90	Very good
3	Sum mer	51.28	41.69	Very good	52.92	43.22	Very good

**Acknowledgment:** the authors are to grateful dr. S. S. Baghel, Principal PMCOE Govt. P. G. College, Dhar and Prof. R. C. Ghawari HOD (Zoology) and dr. Sadhana Chauhan (Senior professor) PMCOE Govt. P. G. College Dhar for providing facilities. We are also thankful to PHE Office Dhar for help During study of the Mansarovar pond. Special thank are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

**References:-**

1. Brow, R. M. Mc cleiland, N. J. Deiminger, R. A. and ‘O’ Conner (1972): A water Quality index erasing the phycological barrier. Water poll. Res. Jou. 6:787-797.
2. Horton, R. K. (1965): An index number system for rating water quality, j. water poll. Cont. fed. 3:300-305.
3. Otta, W. R. (1978): Environmental indices: theory and practice Ama arbar science publishing, Miching (USA).
4. Waskel D. S. (2013): water quality index of sitapat pond at Dhar town (M.P.), Biotech Books, new Delhi 259-262.
5. APHA (2005): Standard method for Examination of water and waste water Ameriean public health association. 21<sup>th</sup>edt. Washington D.C.
6. BIS (1991): Specification for drinking water quality Indian standard institution New Delhi, India.
7. W.H.O. (1995): Guidelines for drinking water standard, world health Organisation.
8. Gaur. N., sarkar, A., Datta, D. et al. (2005): Evolution of water quality index and geochemical characteristics of surface water from Twang India. Sci. Rep, 12,11698.
9. Kant, N., Singh, P. K., Kumar, B. (2018): Hydrogeochemical characterization and ground water quality of Jamshedpur urban agglomeration in Precambrian terrain, Eastern India. J. Geol. Soc. India 92(1),67-75.
10. Sharma, G. et al (2021): Application of multivariate statistical analysis and water quality characterization of Parbati river, Northwestern Himalaya, India, discover, water 1 (1),5.
11. Waskel D. S. and Alawa K. S. (20017): A case study of krishnpura lake Indore M. P. Jour. Of Divya Shodh Samiksha Vol. (1): 20-22.

\*\*\*\*\*

# Unemployment in India: A Qualitative Exploration of Challenges and Possibilities

Dr. Vibha Nigam\*

\*Professor (Economics) PMCoE Mahakaushal Arts and Commerce College, Jabalpur (M.P.) INDIA

**Abstract :** Unemployment remains a persistent issue in India, affecting millions of individuals across urban and rural areas. This paper explores the socio-economic and psychological impacts of unemployment, highlighting its consequences on financial stability, mental health, social inequality, and crime rates. The study examines how joblessness leads to economic insecurity, forcing individuals into exploitative labor conditions and pushing families into debt cycles. It also delves into the emotional and psychological toll on unemployed individuals, who often experience depression, anxiety, and social isolation due to societal expectations and pressures. Furthermore, unemployment worsens existing social inequalities, disproportionately affecting marginalized communities and increasing crime rates as individuals resort to unlawful activities out of desperation. While government policies and economic reforms aim to address unemployment, structural inefficiencies and skill mismatches continue to hinder progress. This paper underscores the need for a holistic approach, including better employment policies, mental health support, and inclusive economic opportunities, to mitigate the challenges posed by rising unemployment in India.

**Keywords-** unemployment, financial stress, economic insecurity, structural inefficiencies.

## Introduction

**Context & Importance:** Unemployment in India is not just an economic issue; it is deeply intertwined with social structures, aspirations, and the quality of life of millions. A job is more than a source of income—it represents dignity, stability, and participation in economic progress. However, a significant portion of India's working-age population struggles to secure meaningful employment, often navigating a complex landscape of job shortages, skill mismatches, and structural barriers. The problem is not merely about numbers but about the quality of jobs available, the unpredictability of job markets, and the frustration of educated youth unable to find roles that match their aspirations.

The reality of unemployment is experienced differently across rural and urban regions, among men and women, and within different economic classes, making it a multidimensional issue. A lack of job security, underemployment, and informal labor further complicate the scenario. Beyond economic loss, prolonged unemployment breeds psychological distress, lowers self-esteem, and leads to social alienation, particularly among young people. By examining unemployment qualitatively, we can understand its deeper impact beyond mere statistics, revealing the narratives of those affected and the structural forces that shape their realities. Addressing unemployment requires a shift from a purely economic lens

to a holistic approach integrating policy, education, and societal change.

**Objective of the Study:** Unemployment is a persistent concern in India, influencing not only the economic well-being of individuals but also shaping social mobility, mental health, and generational aspirations. While many studies focus on statistical trends, this research aims to explore unemployment from a qualitative perspective—examining how joblessness is experienced, the frustrations of job seekers, and the structural challenges that hinder employment opportunities. Rather than just measuring unemployment rates, this paper delves into the narratives of those affected: young graduates struggling to find work, rural workers forced to migrate to cities, and women facing gendered barriers to employment.

By moving beyond numbers, this study seeks to understand how unemployment impacts identity, relationships, and long-term career trajectories. It also questions whether current policies and initiatives truly address the root causes of joblessness or merely serve as temporary fixes. Furthermore, the research aims to highlight the perspectives of various stakeholders—job seekers, employers, educators, and policymakers—to create a comprehensive understanding of the employment landscape. Ultimately, this study advocates for a more inclusive and holistic approach to tackling unemployment, one that aligns education, skill development, and economic

policies with the realities of job seekers across different socio-economic backgrounds.

**Scope of the Paper:** Unemployment in India is a vast topic with multiple dimensions, and this paper seeks to focus on key qualitative aspects rather than statistical analysis. The research will explore the lived experiences of unemployed individuals, highlighting the psychological, social, and financial struggles they endure. The study also covers the structural causes of unemployment, such as the disconnect between education and industry requirements, automation, and gender disparities in the workforce.

Another important focus will be the rural-urban employment divide. Rural unemployment is often disguised, with people engaged in low-paying, informal jobs that provide little security. In contrast, urban unemployment presents a different challenge, with an oversupply of graduates competing for a limited number of white-collar jobs. This study will also assess government policies, exploring whether initiatives like skill development programs and employment guarantee schemes genuinely improve employability or if they fall short in addressing systemic issues.

Additionally, the paper will discuss the impact of unemployment on different demographics, such as women, youth, and marginalized communities, to provide a holistic view. By emphasizing personal narratives and policy critiques, this study aims to move beyond numbers and offer a deeper understanding of India's unemployment crisis.

### Understanding Unemployment in India

**Defining Unemployment:** Unemployment, at its core, refers to the condition in which individuals who are willing and able to work cannot find suitable jobs. However, in the Indian context, defining unemployment is more complex due to the presence of a vast informal economy, seasonal employment, and underemployment. Unlike developed economies where employment is primarily formal and structured, India has a significant number of workers engaged in informal and unregulated jobs, making traditional unemployment metrics less reflective of reality.

In many cases, individuals are technically employed but earn far less than a living wage or work in conditions that offer no job security or career growth. The phenomenon of disguised unemployment is also prevalent, particularly in agriculture, where more people work than are actually required for productivity. Moreover, social and cultural factors influence employment patterns, with women often dropping out of the workforce due to familial responsibilities or safety concerns. Therefore, a rigid definition of unemployment fails to capture the depth of joblessness in India, making it essential to analyze the different ways unemployment manifests beyond simple economic measures.

**Types of Unemployment:** Unemployment in India takes various forms, each with its own causes and consequences:

1. **Structural Unemployment:** This occurs when there is a mismatch between the skills job seekers possess and the skills demanded by employers. Many graduates struggle to find jobs because the education system emphasizes theoretical knowledge over practical skills, making them unemployable in modern industries.
2. **Frictional Unemployment:** This is a temporary phase where individuals are between jobs or searching for better opportunities. While natural in any economy, frictional unemployment in India is prolonged due to bureaucratic hiring processes and a lack of career guidance.
3. **Disguised Unemployment:** Common in agriculture, this happens when more people are engaged in work than necessary, leading to inefficiency. Many rural workers remain "employed" but contribute little to productivity.
4. **Underemployment:** A significant portion of India's workforce is underemployed, meaning they work jobs that do not fully utilize their skills or pay below their qualifications. Many highly educated individuals take up low-paying jobs due to a lack of better opportunities.

Each of these forms of unemployment has distinct effects on individuals and the economy, making it crucial to address them through targeted policies and skill development initiatives.

**Experiences of Unemployed Individuals:** Unemployment is not just an economic statistic; it is a deeply personal and emotional experience. Many job seekers, especially young graduates, feel disillusioned when their education does not translate into employment. They invest years in acquiring degrees, only to realize that the job market is highly competitive and often favors those with practical skills over academic qualifications. This leads to frustration, self-doubt, and, in many cases, a loss of confidence in the system.

For rural workers, unemployment means migrating to cities in search of work, often ending up in exploitative labor conditions. Many are forced to take low-paying jobs in construction, domestic work, or street vending, with little to no legal protection. Women, in particular, face additional challenges as employers often hesitate to hire them due to societal biases and concerns over workplace safety. Even those who manage to secure employment often experience job insecurity, where they can be dismissed without warning. The psychological impact of unemployment is severe, leading to stress, anxiety, and in some cases, depression. Many unemployed individuals also struggle with societal pressure, as Indian culture often equates professional success with self-worth. Families expect young adults to secure stable jobs quickly, and when they fail to do so, it can lead to feelings of shame and isolation. Understanding these personal experiences is crucial in framing better employment policies that go beyond economic indicators and focus on human well-being.

### Causes of Unemployment in India

**Education and Skill Mismatch:** One of the major causes of unemployment in India is the disconnect between the

education system and industry requirements. The traditional curriculum in most Indian universities focuses heavily on theoretical knowledge rather than practical skills. As a result, graduates often find themselves unprepared for the demands of the job market. Employers seek candidates with hands-on experience, critical thinking abilities, and technical expertise—qualities that are rarely emphasized in mainstream education.

Despite the increasing number of degree holders, employability remains low because many institutions fail to update their courses in line with evolving industry needs. Fields like artificial intelligence, data science, and digital marketing are booming, yet most universities still follow outdated syllabi that do not equip students with relevant skills. Even vocational training programs, though promising, have limited reach and struggle with quality control.

Moreover, there is a strong cultural bias toward white-collar jobs, leading students to prioritize degrees over skill-based learning. Many graduates expect high-paying positions immediately after completing their education, only to face rejection due to a lack of real-world expertise. This education-employment gap contributes significantly to both unemployment and underemployment, forcing many to accept jobs below their qualifications or remain jobless for extended periods.

**Structural and Technological Changes:** The Indian job market is undergoing rapid transformation due to automation, artificial intelligence, and globalization. While technological advancements create new opportunities, they also displace a large portion of the workforce, particularly those in low-skilled jobs. Traditional manufacturing and clerical roles are being replaced by automated systems, reducing the demand for human labor. Many workers, particularly those in sectors like textiles, banking, and customer service, find themselves redundant due to digitalization.

Furthermore, the rise of the gig economy—where short-term contracts replace permanent jobs—has altered employment structures. While platforms like Uber, Swiggy, and freelance marketplaces provide temporary work, they do not offer long-term stability or benefits like health insurance and pensions. As a result, many workers remain in a precarious state, uncertain about their financial future.

**Gender and Social Barriers:** Unemployment in India is not just about the availability of jobs; it is also about who gets access to them. Women, marginalized communities, and differently-abled individuals face systemic barriers that limit their employment opportunities. Gender biases in hiring, workplace safety concerns, and societal expectations force many women out of the workforce, despite their qualifications. Even in urban areas, many employers hesitate to hire women due to maternity leave policies, family responsibilities, or cultural norms that discourage women from working late hours.

In rural areas, the situation is even worse. Many women

are engaged in unpaid household labor, and their contributions to agriculture or family businesses are often unrecognized. Those who wish to work outside their homes face limited job options and social resistance. Additionally, the gender pay gap remains a persistent issue, where women earn significantly less than men for the same work, further discouraging female workforce participation.

Caste and class also play a crucial role in employment opportunities. Individuals from marginalized communities often lack access to quality education, professional networks, and resources needed to secure stable jobs. Discrimination in hiring, though illegal, still exists in subtle forms, making social mobility difficult for many. Without structural reforms that promote equal opportunities, unemployment will continue to disproportionately affect these vulnerable groups.

### **Government Policies and Their Effectiveness**

**Employment Generation Programs:** The Indian government has launched several employment generation programs to tackle unemployment, but their effectiveness remains mixed. One of the most well-known initiatives is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which guarantees 100 days of wage employment to rural households. While MGNREGA has provided income support to millions, it is often criticized for offering only short-term relief rather than sustainable job creation. Many workers remain stuck in low-productivity jobs, unable to transition into more stable employment.

In urban areas, initiatives like Startup India and Skill India aim to boost entrepreneurship and workforce skills. However, these programs face challenges such as bureaucratic inefficiencies, lack of awareness, and mismatched training that does not align with industry demands. The reality is that most government schemes focus on quantity over quality—creating temporary jobs rather than fostering long-term career growth.

**Effectiveness of Skill Development Programs:** Skill development is a crucial solution to unemployment, but India's training programs often fall short. The Skill India Mission, launched to equip youth with vocational skills, has trained millions, yet many still struggle to find employment. One key issue is the quality of training—many institutions provide theoretical instruction with little hands-on experience. Employers often find that graduates of these programs lack practical skills, leading to a gap between training and actual job readiness.

Moreover, many skill development initiatives do not align with industry needs. For example, while sectors like IT, renewable energy, and data analytics are booming, most training programs still focus on traditional trades like plumbing and tailoring. There is a disconnect between what is being taught and what the job market demands, leading to a situation where people are skilled but not employable. Another issue is accessibility—many of these programs are concentrated in urban areas, leaving rural populations



behind. Women and individuals from marginalized communities face additional challenges in accessing training, as social norms and financial constraints often limit their participation. Without addressing these structural flaws, skill development programs will continue to fall short of their potential.

**Private Sector and Entrepreneurship Support:** The government has been actively promoting entrepreneurship as a solution to unemployment through schemes like Mudra Yojana and Stand-Up India, which provide financial support to small businesses. However, starting and sustaining a business in India is not easy. Many aspiring entrepreneurs struggle with bureaucratic hurdles, high taxation, and limited access to investment.

Additionally, risk-averse lending practices by banks make it difficult for new businesses to secure loans. While government schemes offer funding, many applicants face delays or rejections due to complex documentation requirements. For those who do manage to start a business, competition from large corporations and international brands makes survival challenging.

**The Role of Technology and the Future of Employment Automation and Job Displacement:** Technology is rapidly changing the employment landscape in India. Automation, artificial intelligence (AI), and robotics are replacing human labor in various industries, particularly in sectors like manufacturing, customer service, and even banking. While automation increases efficiency and reduces costs for companies, it also leads to widespread job displacement, especially for low-skilled workers.

In industries like automobile manufacturing, machines are now performing tasks that once required human hands, reducing the need for factory workers. Similarly, AI-powered chatbots and self-service kiosks are replacing customer service executives, making many traditional roles obsolete. The banking sector has also undergone digital transformation, reducing the need for clerical staff as online banking and mobile applications become more advanced. The biggest concern with automation is that it disproportionately affects workers who lack specialized skills. While new technology creates jobs in fields like cybersecurity, AI development, and digital marketing, these opportunities are primarily available to highly educated individuals. This creates a widening gap between the skilled and unskilled workforce, where only those who can adapt to technology-driven industries will thrive, while others risk being left behind.

**Emerging Sectors and Job Creation:** Despite concerns about job losses, technology has also opened doors to new employment opportunities. The IT sector, e-commerce, and renewable energy industries have created thousands of jobs in recent years. Companies like TCS, Infosys, and Wipro continue to hire professionals skilled in coding, data analytics, and cloud computing. With digital transformation accelerating, demand for software developers, blockchain

specialists, and AI engineers is growing.

The rise of the startup ecosystem in India has also fueled job creation. Cities like Bengaluru, Hyderabad, and Pune have become hubs for tech-driven startups, offering employment in areas like fintech, healthcare tech, and online education. Government-backed initiatives such as Make in India and Digital India aim to promote domestic manufacturing and IT infrastructure, leading to further job growth.

Additionally, sustainable energy and environmental technology sectors are expanding, with companies investing in solar and wind energy projects. As India pushes for cleaner energy alternatives, jobs in green technology, environmental consulting, and waste management are on the rise. These industries present an opportunity for employment growth, but only for those who receive adequate training in these emerging fields.

**Conclusion:** Unemployment in India is not just an economic issue; it is a deeply embedded social crisis with far-reaching consequences. The financial burden on families, coupled with mental health struggles, creates a vicious cycle of despair and economic instability. The disparities in job access further marginalize vulnerable communities, increasing frustration and, in some cases, leading to higher crime rates. Addressing unemployment requires a multi-faceted approach, involving educational reforms, skill development programs, and policy changes that promote job creation. Additionally, improving mental health accessibility and fostering inclusive workplaces can help mitigate the adverse effects of joblessness. While economic fluctuations are inevitable, a proactive and strategic intervention can reduce the severity of unemployment's impact, ensuring a more stable and equitable society. In conclusion, tackling unemployment effectively will require collective efforts from the government, private sector, and civil society to create sustainable and inclusive employment opportunities for all.

**References:-**

1. Basu, D., & Das, D. (2022). *Unemployment and economic growth in India: A structural analysis*. *Economic & Political Weekly*, 57(4), 32-41.
2. Bhattacharya, P. C. (2019). *Youth unemployment in India: Causes and policy implications*. *Journal of Asian Economics*, 65, 101-117.
3. Chakraborty, A. (2020). *The role of education in reducing unemployment in India*. *Indian Journal of Labour Economics*, 63(2), 265-280.
4. Deshpande, A. (2021). *Caste and unemployment in India: The persistent inequality*. *World Development*, 146, 105-114.
5. Dhingra, S. (2020). *Women and unemployment: The missing workforce in India*. *Economic & Political Weekly*, 55(33), 27-35.
6. Ghosh, J. (2021). *Structural unemployment in India: A policy perspective*. *Cambridge Journal of Economics*,

- 45(3), 567-586.
7. Government of India. (2023). *Periodic Labour Force Survey 2022-23*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
  8. ILO. (2022). *India Employment Report 2022: Trends and Challenges*. International Labour Organization.
  9. Jha, R. (2019). *Rural unemployment and migration patterns in India*. *Journal of Development Studies*, 55(5), 789-805.
  10. Kapoor, R. (2021). *Job creation in India: The challenge of skill mismatch*. *IIMB Management Review*, 33(1), 12-27.
  11. Khera, R. (2020). *The impact of COVID-19 on unemployment in India*. *The Indian Economic Journal*, 68(3), 456-472.
  12. Mehrotra, S. (2021). *The informal sector and unemployment crisis in India*. *Economic & Political Weekly*, 56(18), 10-18.
  13. Ministry of Labour and Employment. (2022). *National Employment Policy: A roadmap for job creation*. Government of India.
  14. Mitra, A. (2023). *Digital economy and employment trends in India*. *Journal of South Asian Development*, 18(1), 87-104.
  15. NITI Aayog. (2022). *Skill development and employment generation in India: A policy review*. Government of India.
  16. NSSO. (2021). *Unemployment trends in India: Findings from the 78th Round*. National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation.
  17. Ray, S., & Sinha, A. (2020). *Unemployment and mental health: The psychological impact of job loss in India*. *Indian Journal of Psychology*, 77(2), 125-139.
  18. Sen, A. (2019). *Poverty, unemployment, and social justice in India*. *Journal of Human Development*, 20(4), 312-328.
  19. Shah, M. (2021). *Gig economy and the future of employment in India*. *Indian Journal of Labour Studies*, 58(3), 221-239.
  20. Subramanian, S. (2022). *Youth unemployment and higher education in India: A paradox?* *South Asian Journal of Social Sciences*, 9(1), 55-73.

\*\*\*\*\*

# Financial Literacy and Portfolio Diversification: Evidence from India's Middle-Class Investors

Dr. Preeti Anand Udaipure\*

\*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

**Abstract :** This study examines the relationship between middle-class Indian investors' financial literacy and portfolio diversification. Assessing these investors' degree of financial literacy, determining the degree of diversification in their portfolios, and figuring out how financial literacy and investment choices are related are the goals. One hundred middle-class investors from various Indian cities participated in the poll, which was conducted using quantitative research. The results show that financial literacy is moderate, with an average score of 63.45 and a moderate level of portfolio diversification of 3.42. A moderately favourable association between the two variables is indicated by the estimated correlation between financial literacy and portfolio diversification ( $r = 0.45$ ), indicating that investors with high levels of financial literacy diversify their holdings effectively. Evidently, the results produced as a result of the regression analysis show that financial literacy explains 20% of the variance with regard to portfolio diversification proving once more its role in investment planning. Concerning the findings, the present paper depicts a need for more focus on improving Finance literacy with an aim of increasing portfolio diversification and thereby the overall financial quality of the middle-class investors in India.

**Keywords:** Financial Literacy, Portfolio Diversification, Evidence, India's, Middle-Class Investors.

**Introduction -** The financial literacy can be defined as the capacity of a person to make adequate and rational decisions as for personal investments, savings and, in general, financial planning. For instance, in India, where there is a rapidly growing economy and a tremendously large and diverse populace, everyone needs to be armed with knowledge on matters to do with financial management if they are to participate in the financial markets. Formerly, it was a relatively significant class in the investment category among different segments of the Indian society. Due to higher and growing incomes and financial freedom, the middle-class people are also actively participating in investments. However, this is a fact that, a large number of the investors lacks the financial literacy which is essential to make sound investment decisions, which in turn would enable them to optimize their investment portfolios. Consequently, poor, bad investment choices are taken, poor risk management, and the lack of diversification of the portfolio.

Portfolio diversification on the other hand, is a fundamental idea of investing in different classes of assets in an effort to reduce risks and increase possible gains. This is because through diversification of the investment portfolios, the fluctuations of the market do not greatly affect the investment. However, it becomes possible only when one knows the different opportunities in the investments

and how they are correlated in terms of risk & return. Financial literacy is one of the key factors that help determine the ability of an unfamiliar person in diversification of their investment portfolio. New generation Indian middle-class investors are more active in investing, but they fail to invest in other diversified instruments or manage different types of risks and returns on investment products.

The intention of this study is to determine the connection between financial literacy and portfolio diversification among Indian middle-class investors. Since this paper aims at establishing the financial illiteracy that can hinder investors from making the right decision in terms of diversification strategies to be employed, the paper undertakes an analysis of how the level of financial literacy negatively influences the methods used in diversification by these investors. Understanding of this relationship will also reveal not only the level of financial literariness of the middle class in India at the present state but also the means to improve financial enlightenment and investment productivity. With the increase in the number of the middle-class population of Indians involved in investment economy, financial literacy and a sound investment strategy would be vital to ensure the longevity of the demographics' financial health too.

**Research Objectives:** The primary objectives of the study are:

1. To gauge the degree of financial literacy of middle-class investors in India.
2. To assess the level of portfolio diversification among these investors.
3. To examine the relationship between financial literacy and portfolio diversification.
4. To determine the factors affecting the investment decisions and diversification plans of middle-class investors.

#### Review Of Literature

**Assefa and Rao (2018)** conducted a survey on investment decision and level of financial literacy among the salaried employee in Wolaita Sodo Town of Ethiopia, and also confirmed that high level of financial literacy had significant difference in the investment decision of the respondents.

They found out that there was higher probability of making right and more diverse investments for those who had higher level of financial literacy. They also pointed out the importance of financial education in raising the investment rate of return of the salaried employees particularly those in the developing country since they are financially illiterate.

**Bawre and Kar (2019)** synthesised the information on financial literacy and its dimensions and also analysed the socio-demographic factors in the context of urban Indian consumers. Their survey proved that primary socio-demographic factors such as age income, education and occupational status influenced the financial literacy levels of the individuals in urban areas. The authors pointed out that financial literacy is not evenly distributed among the population; it is higher among younger people and those with higher education level. This study pointed out that there is a need to ensure that there is personalization of the efforts toward financial literacy so that specific groups in the urban India can be economically empowered.

**Bayar, Sezgin, Öztürk, and aomaz (2020)** further investigated the between financial literacy and individual investor's financial risk tolerance using multinomial logistic regression analysis. The findings showed that financial knowledge was positively associated with risk taking since the literate persons had the ability to assess and manage risks. It was established from the research that well informed client was in a better position to be riskier and readier to diversify his or her portfolio, meaning that financial knowledge pressures an investors risk sector and his or her willingness to diversify their investment portfolio. which was also expanded by this research that enhancing financial literacy reduces the rate of reckless and ill decisions taken by individuals while investing their funds.

**Campbell, Ramadorai, and Ranish (2019)** analyzed whether individuals who are rich get even richer through speculation in the stock exchange as it analyzed the same using India markets. They realized that the higher the status of people, coupled with better policies in resources and finances they would amass even better stock in the market. The study found out that knowledge concerning financial

factors and information availability regarding stocks were critical in enabling people to benefit from stock markets particularly in new economy such as the India which has experienced tremendous growth in its financial markets.

**Chawla, Bhatia, and Singh (2022)** concerned with the influence of the parent in matters regarding guidance, money management and saving among the youths. To their findings, they noted that parents play a vital role in influencing the youth in terms of investment through financial knowledge. This is due the fact that people who were trained on how to talk about finance at home and learned finance from their parent's better investment disposition and high investment tendency towards long term investment plans. This paper focused on that importance of young age financial literacy and its impact on subsequent financial literacy.

**Dam and Hotwani (2018)** offered a conceptual definition of financial literacy and developed an assessment of it. Their work was designed in order to contribute to the development of the understanding of all those facets of financial literacy and how they might be assessed in various contexts. The measure they developed was an effective way to assess the levels of understanding regarding financial issues among people and could be applied in the process of decision making for policy purposes as well as used to design and implement special programs for particular subjects. The writers argued that, thus, there is need to improve the financial literacy by employing standard sources and structure.

**Research Methodology:** In the ever-evolving marketplace of India, one of the most significant factors with reference to the financial investment among the investors is financial literacy. In the course of investment, various methods have been adopted in an attempt to manage risks and achieve high returns on investment, and diversification of the portfolio has turn out to be among the most effective strategies. The financial literacy of middle-class Indian investors is often limited in terms of number, which might have serious implications for their investment decisions, for example, in relation to diversification of the portfolios. This endeavor aims to establish how peoples' financial literacy can predict diversification of the portfolio or investment portfolios of the middle class in India.

As this research targets the middle-class investors, the study is in a position to provide information regarding the effects of financial literacy on the chosen investment decision made by investors and also the diversification ratio of their investment strategies. The method that will be applied in this study is the quantitative technique of collecting and analyzing data from 100 investors from the middle-income class from selected cities in India. Determining if financial literacy and diversification among Indian investors are positively correlated is the aim of this article.

**Research Design:** In order to determine the connection between financial literacy and portfolio diversification among

middle-class Indian investors, the current study used a quantitative methodology. The research questionnaire was administered on the respondents with an aim of collecting the primary data. In order to determine how these two factors are related, statistical tests were conducted on the data collected.

**Sampling:** The target population for this research comprised the middle-class investors investing in India and who are currently active in their investment business, irrespective to their age factor, educational standard and geographical location in the country. To ensure that the sample was bias free and definitely representative of its population, a simple random sample with an aim of getting 100 participants was used which means that luckily everybody within the stipulated population was equal to make the list. One hundred was deemed sufficient to establish the correlations between the level of portfolio diversification and financial understanding as planned in the power analysis and in regard to the time and resources available for the operations.

**Data Collection Methods:** Questionnaires containing closed questions and 5-liked scale questions were administered to elicit data for the study. The questionnaire was divided into three parts, which include; personal information (age, educational level, income and occupation of the respondent),; financial knowledge (this section focused on the respondent's knowledge in the area of finance, investment, risk management and portfolio diversification; and investment knowledge and diversification (this section focused on the respondent's investment profile, investment types and the distribution of the portfolio). To ensure the returned results are relevant, reliable and valid, the researcher administrated the questionnaire to 10 respondents first to establish feasibility before implementing it on the rest total sample size.

**Data Analysis:** In order to analyze the collected data concerning the relationships of financial literacy and portfolio diversification the different statistical techniques were applied. Through the use of mean, standard deviations, and frequency distribution tables, the sample descriptive and the level of financial literacy were described. The direction and intensity of the link between portfolio diversity and financial literacy were ascertained using Pearson's correlation coefficient. Moreover, a multiple regression test was run in order to determine if financial literacy actually predicted the level of diversification of the portfolio among investors. All analyses were carried out using statistical packages like SPSS or R.

**Research Hypotheses:** The study will test the following hypotheses:

**H<sub>1</sub>:** Higher financial literacy is positively correlated with greater portfolio diversification among middle-class investors in India.

**H<sub>2</sub>:** Financially literate investors are more likely to utilize various asset classes (stocks, bonds, real estate, etc.) in

their portfolios.

**H<sub>3</sub>:** Middle-class investors with low financial literacy exhibit a more concentrated portfolio, leading to higher risk exposure.

**Validity and Reliability:** In order to maintain the validity of the data collection instruments, the study used pre-existing, established questions regarding financial literacy and portfolio diversification. The pilot test also tested and perfected the questionnaire so that it would accurately measure the constructs that it was designed to measure. Cronbach's Alpha, a statistical measure of internal consistency, was used to gauge reliability. The reliability of the study's instrument was ensured by a Cronbach's Alpha of 0.7 and higher, which indicated that the questionnaire items were consistently measuring the same underlying constructs.

**Ethical Considerations:** The research followed ethical standards in data collection and management. All participants provided informed consent, making them fully aware of the aim of the study prior to their involvement. Credibility of collected Data The participants' information was not revealed, and assignment of names given by them respondents' answers during analysis was removed to maintain confidentiality. It was an open study which was done in consultation with the subjects where no penalties were tendered against anybody who declined to participate or who dropped out in the middle of the study. This made it possible they into the groups to decide if they would want to or not to join into the proposed group.

**Limitations of the Study:**

- 1. Sample Bias:** Since the study is based on the middle-class investors of India only the results cannot be generalized over other classes or countries.
- 2. Self-Reported Data:** The survey data is self-reported hence might be influenced by social desirability bias or perhaps those involved in the survey cannot accurately recall events regarding their investments.
- 3. Cross-Sectional Nature:** The study will be conducted at one time hence limiting possibilities of inferring cause related outcomes.

**Result And Discussion:** The analysis considers how financial literacy drives diversification behavior among middle-class investors in India. The research is based on quantitative data obtained from the survey of 100 respondents. Regression analysis is used to ascertain the predictability of portfolio diversification as a result of financial literacy, correlation analysis is used to assess relationships among variables, and descriptive statistics are used to describe the data. All tests of statistics will be carried out using SPSS software, and the output tables will be given accordingly.

**Descriptive Statistics:** Descriptive statistics give a summary of the data, including important characteristics like mean, standard deviation, and frequency distribution of variables concerned with financial literacy and portfolio

diversification.

**Financial Literacy Levels:** The descriptive statistics of the 100 participants' financial literacy scores are displayed in Table 1 below. The financial literacy score is derived from answers to a series of questions measuring participants' knowledge about basic financial principles, risk management, and portfolio diversification.

**Table 1: Descriptive Statistics for Financial Literacy Scores**

Statistic	Value
Mean	63.45
Standard Deviation	15.23
Minimum	35
Maximum	90
Skewness	-0.20
Kurtosis	0.10

A moderate level of financial literacy is implied by the respondents' average score of 63.45, which has a standard deviation of 15.23. The values of skewness and kurtosis imply that the distribution of the financial literacy scores is fairly normal.

**Portfolio Diversification:** The portfolio diversification measure captures the number of types of assets (stocks, bonds, real estate, etc.) represented in the portfolios of the participants, with higher values being associated with more diversification.

**Table 2: Descriptive Statistics for Portfolio Diversification**

Statistic	Value
Mean	3.42
Standard Deviation	1.24
Minimum	1
Maximum	7
Skewness	0.35
Kurtosis	-0.32

The standard deviation is 1.24 and the average score for portfolio diversification is 3.42. This suggests that investors typically own portfolios that are modestly diversified. The distribution is weakly positively skewed, suggesting that there are some investors with more diversified portfolios than others.

**Correlation Analysis:** The degree and direction of the relationship between financial literacy and portfolio diversity are investigated using correlation analysis. The linear link between the two variables is measured by Pearson's correlation coefficient.

**Financial Literacy and Portfolio Diversification:** Table 3 illustrates the connection between an individual's financial literacy and investment diversification by examining the relationship between portfolio diversification and financial literacy. With a focus on the impact of financial understanding on portfolio mix, it illustrates how financial literacy influences investing decisions.

**Table 3: Correlation Between Financial Literacy and Portfolio Diversification**

	Financial Literacy	Portfolio Diversification
Financial Literacy	1	0.45
Portfolio Diversification	0.45	1

The Pearson correlation coefficient between financial literacy and diversification of portfolios is 0.45, which reflects a moderate positive relationship. The result reflects that greater financial literacy translates into more diversified investment portfolios for middle-class Indian investors. The finding is statistically significant at the 0.01 level as reflected through the p-value of 0.0001.

**Regression Analysis:** Regression is conducted to examine the predictive ability of financial literacy in portfolio diversification. A multiple linear regression model is employed in estimating the extent to which financial literacy drives portfolio diversification. Tables 4, 5, and 6 show the principal statistical analyses comparing financial literacy with portfolio diversification. The model summary gives an evaluation of the explanatory power of the regression model, while the ANOVA table tests the overall significance of the model. The coefficient table also includes estimates of the financial literacy's predictors of portfolio diversification in terms of size and statistical significance.

**Table 4: Model Summary**

Statistic	Value
R	0.45
R <sup>2</sup>	0.20
Adjusted R <sup>2</sup>	0.18
Standard Error of the Estimate	1.12

According to the research, financial literacy has a 0.20 influence on portfolio diversification, as indicated by the R-squared value of 0.20. The adjusted R-squared value of 0.18 takes account of the number of variables in the model and shows the financial literacy is a moderate influence on portfolio diversification.

**Table 5: ANOVA for Regression Model**

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	52.31	1	52.31	16.92	0.0001
Residual	211.48	98	2.16		
Total	263.79	99			

Significance of the regression model in ANOVA can also be noted from the F-value = 16.92 and p-value = 0.0001. This suggests that financial literacy has some positive role to play as a predictor of the variation in diversification of the portfolio.

**Table 6: Coefficients for Financial Literacy on Portfolio Diversification**

Variable	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Constant	1.56		2.63	0.010
Financial Literacy	0.03	0.45	4.11	0.0001

The coefficient of regression for financial literacy is 0.03; this means that for every one unit increased in financial

literacy, there is a 0.03 unit increase in portfolio diversification. The analysis of the result shows that the t-statistic is 4.11 while the p-value is 0.0001 which means that the financial literacy is a significant factor in determining the level of portfolio diversification.

In other words, the analysis of the data confirms that financial literacy plays a significant role in diversification of the portfolio for the middle-class investors in India. The direct and positive correlation between financial literacy and diversification provides the foundation for the reasoning that the more educated investor tends to diversify their portfolio more effectively. The regression equation also supports this assertion claiming that financial literacy explains 20% of the variations in portfolio diversification behaviour.

The rest of the diversification variation could be attributed to other possible factors such as risk-taking capacity, the level of income and investment, which could be captured in other studies.

**Conclusion:** This study examines how middle-class Indian investors' portfolio diversity is impacted by their level of financial literacy. It has been demonstrated that more portfolio diversity results from increased financial literacy, indicating that greater knowledge produces the best and lower-risk investing options. With a coefficient of determination of 0.20, the regression analysis also shows that the degree of financial literacy explains the degree of portfolio diversity. The degree of diversification also depends on several other factors; these are risk tolerance, income level, and investment experience among others. Specifically, the paper underlines the capability of enhancing such programs aiming at enabling investment decisions as well as diversification among middle-class investors in India to enhance their financial security and risk management strategies.

#### References:-

1. Ansari, Y., Albarrak, M. S., Sherfudeen, N., & Aman, A. (2022). A study of financial literacy of investors—A bibliometric analysis. *International Journal of Financial Studies*, 10(2), 36.
2. Arora, J., & Chakraborty, M. (2022). Role of financial literacy in investment choices of financial consumers: an insight from India. *International Journal of Social Economics*, 50(3), 377-397.
3. Assefa, M., & Rao, D. (2018). Financial literacy and investment behavior of salaried individuals: a case study of Wolaita Sodo Town. *Int. J. Bus. Manage. Invent*, 7(10), 43-50.
4. Bawre, S., & Kar, S. (2019). An investigation of the demographic factors affecting financial literacy and its components among urban Indians. *International Journal of Education Economics and Development*, 10(4), 398-426.
5. Bayar, Y., Sezgin, H. F., Öztürk, Ö. F., & amaz, M. Ü. (2020). Financial literacy and financial risk tolerance of individual investors: Multinomial logistic regression approach. *Sage Open*, 10(3), 2158244020945717.
6. Campbell, J. Y., Ramadorai, T., & Ranish, B. (2019). Do the rich get richer in the stock market? Evidence from India. *American Economic Review: Insights*, 1(2), 225-240.
7. Chawla, D., Bhatia, S., & Singh, S. (2022). Parental influence, financial literacy and investment behaviour of young adults. *Journal of Indian Business Research*, 14(4), 520-539.
8. Dam, L. B., & Hotwani, M. (2018). Financial literacy: Conceptual framework and scale development. *SAMVAD*, 15, 61-69.
9. Deepak, C. A., Singh, P., & Kumar, A. (2015). Financial literacy among investors: theory and critical review of literature. *International Journal of Research in Commerce, Economics & Management*, Volume, (5).
10. Gangwar, R., & Singh, R. (2018). Analyzing factors affecting financial literacy and its impact on investment behavior among adults in India.
11. Grohmann, A., Hübler, O., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. (2021). Financial literacy: Thai middle-class women do not lag behind. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, 100537.
12. Khan, M. T. I., Tan, S. H., & Gan, G. G. G. (2019). Advanced financial literacy of Malaysian Gen Y investors and its consequences. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 13(1), 83-108.
13. Lahiri, S., & Biswas, S. (2022). Does financial literacy improve financial behavior in emerging economies? Evidence from India. *Managerial Finance*, 48(9/10), 1430-1452.
14. Letamendia, L. N., & Poher, B. (2020). The effect of financial literacy on trust: do financially literate individuals have more trust in the financial system. *IE University*, (April).
15. Nguyen, D. T. (2017). Factors affecting financial literacy of Vietnamese adults: a case study for Hanoi and Nghe an. *Vnu Journal of Economics and Business*, 33(2).
16. Prasad, S., Kiran, R., & Sharma, R. K. (2021). Influence of financial literacy on retail investors' decisions in relation to return, risk and market analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 26(2), 2548-2559.
17. Raut, R. K. (2020). Past behaviour, financial literacy and investment decision-making process of individual investors. *International Journal of Emerging Markets*, 15(6), 1243-1263.
18. Sarkar, A. K., & Sahu, T. N. (2018). Investment behaviour: Towards an individual-centred financial policy in developing economies. *Emerald Publishing Limited*.
19. Singh, K. N., & Malik, S. (2022). An empirical analysis on household financial vulnerability in India: exploring the role of financial knowledge, impulsivity and money management skills. *Managerial Finance*, 48(9/10), 1391-1412.
20. Sivaramakrishnan, S., Srivastava, M., & Rastogi, A. (2017). Attitudinal factors, financial literacy, and stock market participation. *International journal of bank marketing*, 35(5), 818-841.

# Study of Ambient Air Quality in Rewa City (M.P.) in Reference of Respirable Suspended Particulate Matter (Rspm), Sulphur Di Oxide and Nitrogen Oxide.

Shrishti Singh\* Dr. Atul Tiwari\*\*

\*Research Scholar (Environmental Biology) APS University, Rewa (M.P.) INDIA

\*\* HOD (Environmental Biology) APS University, Rewa (M.P.) INDIA

**Abstract :** Air Pollution occurs due to the presence of undesirable solid or gaseous particles in the air in quantities that are harmful to human health and environment. Ambient air quality is known to be influenced by emission from the source, Meteorological condition and topography of the area. The concentration of particulate matter was found above the permissible limit in most of the sites while the concentration of gaseous pollutants was found within the permissible limit as per the standards given by Central Pollution Control Board (CPCB, 2009). Air pollution has been a steadily growing problem since the industrial revolution which started by the invention of technology that could use new source of energy. The sources were coal, oil and gases. This study was undertaken to assess the quality status ambient air pollutants SPM, RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>. The analysed values of SPM, RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> at the sampling sites clearly illustrates that the ambient air of Rewa city is primarily deteriorated by particulate matters (SPM, RSPM) and least by gaseous pollutants (SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>). Concentrations of all the pollutants were found to be highest during winter season followed by summer and least during post monsoon season respectively.

**Keywords-** Ambient air quality, RSPM, SPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>.

**Introduction** - Air pollution is one of the severe problem world is facing today. Rapid urbanization, unregulated industrialization, growing transportation on poor road condition, metal plating and agricultural activities, construction debris, garbage burning, and population growth deteriorates the ambient air quality. (Mangalekar *et.al.*, 2013, Tsang *et.al.*, 2008, Chaurasia *et.al.*, 2013, Sharma & Sharma 2016). Particulate matter and gaseous emissions of pollutant emission from industries and auto exhaust are responsible for rising discomfort, increasing airway diseases and deterioration of artistic and cultural patrimony in urban centers. Major components of air pollutants are dust and gases. The suspended dust in air is known as suspended particulate matter (SPM) and consists of solid and liquid particles emitted from numerous natural and manmade sources. About six thousands premature deaths annually were recorded alone in India due to polluted air (Kanwade *et.al.*, 2020). As India is a developing country, the population density is higher, which contributes to higher intake fractions of PM (Apte *et.al.*, 2012). In India, the dust pollutants contribute around 40% of total air pollution problems (Chauhan and Sanjeev 2008). Some workers have observed higher concentration of SO<sub>2</sub> in the ambient air as compared to present investigation (Mukhopadhyay and Mukherjee 2013, Nandanwar *et.al.* 2014). Various

researches have been carried out by Rani *et.al.*, 2011; Chakrabarti and Mitra, 2014; Richhariya, 2015; Simbi *et.al.*, 2017; Dwivedi and Tripathi, 2018 to evaluate the ambient air pollutants (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> and SPM). Hasan *et.al.*, (2018) observed that Nitrogen oxides has an important role in the formation of ozone in the atmosphere and sulphur dioxide is a highly reactive gas which affects the environment. Roadside dust by vehicular exhausts and various other anthropogenic activities contain considerable concentrations of particulates and gaseous pollutants. Present research work was undertaken to monitor the ambient air quality of Rewa city (M.P.).

## Materials And Methods

**Study Area:** The present research work was undertaken in Rewa city, which is situated on the north-eastern part of Madhya Pradesh state, central part of India. It lies between 24°18' and 25°12' north latitude and 81°2' and 62°18' east longitudes. Rewa has a humid subtropical climate, with cold, misty winter, a hot summer and a humid monsoon season. The average temperature being around 30°C (86°F). The geographical area of Rewa district is 6,314 kilometers. Rewa district is bounded on east and south-east by Sidhi, on the south-east by Sidhi, on the south by Shahdol and on the west by Satna district, Rewa city is lies about 450 KM north-east of state capital Bhopal and 130 KM south of



Prayagraj city. Nearby Rewa city there mega cement plants and some small scale industries present, including a few stone crushers.

**Sampling and Monitoring:** Sampling and Monitoring of ambient air quality was carried out at three locations in Rewa city. These stations are residential, commercial and industrial area respectively. According to CPCB (Central Pollution Control Board) the method prescribed for the pollutant gases and the particulate pollutants are very sensitive ones yet percentage of errors are very less. Sampling was carried out at three different locations using Respirable Dust Sampler (Envirotech model APM 460 BL-411) for 8 hours in a day at an average flow rate of 1.5 LPM as per the standards of Central Pollution Control Board (India). Monitoring is carried out covering a period of six months from February 2024 to July 2024. Suspended particulate matters (SPM) and respirable suspended particulate matters (RSPM) were collected on the dust cup and glass fabric filter paper respectively. Samples for determination of gaseous pollutants (SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>) were collected by bubbling air samples in Sodium tetra chloromercurate and Sodium hydroxide- Sodium arsenate absorbent solutions respectively in impingers at flow rate of 1.5 LPM. These samples were analyzed for SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> spectrophotometrically.

**Result And Discussion**

The detailed result of air quality monitoring are presented in Table 1 and 2.

The concentration of Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) in residential area (Niralanagar) was in the range of 68.18 to 98.32 µg/m<sup>3</sup>. The concentration of RSPM in commercial area (Shilpi Plaza) and industrial area (Naubasta) were observed in the range of 61.71 to 113.59 µg/m<sup>3</sup> and 78.89 to 115.83 µg/m<sup>3</sup> respectively. All the values were under the prescribed by National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) of 100 µg/m<sup>3</sup> for residential/ commercial and industrial area respectively. (Fig.1). Similar study of seasonal variation in ambient particulate of Durg city was studied by Sharma and Parvej (2003) in six sampling sites. As well as Kushwaha *et.al.*, (2008), Salve *et.al.*, (2006), Muneeswaran *et.al.*, (2003). The concentration of SO<sub>2</sub> in residential area (Niralanagar) was in the range of 21.02 – 23.55 µg/m<sup>3</sup>. The concentration of SO<sub>2</sub> in commercial area (Shilpi Plaza) and Industrial Area (Naubasta) were found in the range of 22.32 to 24.92 µg/m<sup>3</sup> and 25.31 to 26.31 µg/m<sup>3</sup> respectively. All the values of SO<sub>2</sub> are within the prescribed limit of the NAAQS of 80 µg/m<sup>3</sup> for residential, commercial and industrial area (Fig.1). Maurya (2005), Mondal *et.al.*, (2007). The concentration of NO<sub>x</sub> in residential area (Niralanagar) was found in the range of 34.19 to 35.13 µg/m<sup>3</sup>. The concentrations of NO<sub>x</sub> in commercial area (Shilpi Plaza) and industrial area (Naubasta) were found in the range of 35.03 to 37.76 µg/m<sup>3</sup> and 37.01 to 39.81 µg/m<sup>3</sup> respectively. All the values of NO<sub>x</sub> were within the prescribed standard by NAAQS of 80

µg/m<sup>3</sup> for residential, commercial and industrial area. Kushwaha (2008), Chaurasia and Kumar (2014).

The average concentration of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in residential area (Niralanagar) was found in the range of 81.38, 21.76 & 35.12 µg/m<sup>3</sup> respectively. The average concentration of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in commercial area (Shilpi Plaza) was observed in the range of 89.54, 22.79 & 36.11 µg/m<sup>3</sup> respectively. The average concentration of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in industrial area (Naubasta) was found in the range of 92.77, 25.43 and 37.71 µg/m<sup>3</sup> respectively.

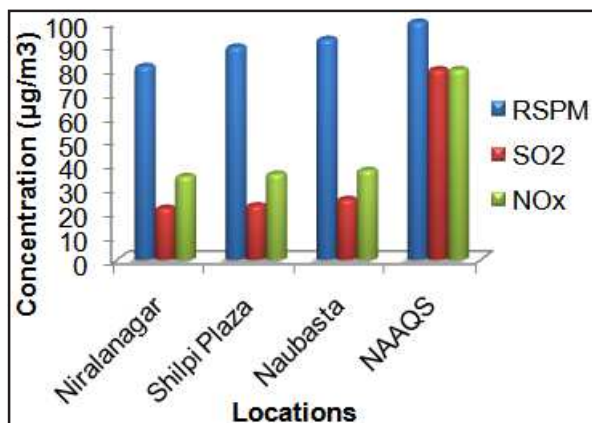
**Table 1:- Concentration (µg/m<sup>3</sup>) of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in different areas of Rewa city during the month of February – July, 2024).**

Location	Month	RSPM	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>
	February	98.32	23.55	34.19
	March	89.39	22.5	35.49
<b>Niralanagar (Residential Area)</b>	April	86.62	21.28	35.32
	May	73.49	21.15	35.38
	June	72.29	21.09	35.22
	July	68.18	21.02	35.13
<b>Average Concentration</b>		81.38	21.76	35.12
<b>Shilpi Plaza (Commercial Area)</b>	February	113.59	24.92	37.76
	March	99.56	22.8	36.42
	April	93.45	22.33	36.12
	May	86.64	22.19	36.23
	June	82.31	22.23	35.11
	July	61.7	22.32	35.03
<b>Average Concentration</b>		89.54	22.79	36.11
<b>Naubasta (Industrial Area)</b>	February	115.83	26.31	39.81
	March	97.79	25.62	38.89
	April	94.18	25.22	36.32
	May	85.32	25.11	37.1
	June	84.63	25.04	37.09
	July	78.89	25.31	37.01
<b>Average Concentration</b>		92.77	25.43	37.70
<b>NAAQS</b>		100.00	80.00	80.00

**Table 2 :- Average Concentration (µg/m<sup>3</sup>) of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in different areas of Rewa city during month of February – July, 2024 and compared with prescribed National Ambient Air Quality Standards (NAAQS).**

Location	Locations	RSPM	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>
<b>Residential</b>	Niralanagar	81.38	21.76	35.12
<b>Commercial</b>	Shilpi Plaza	89.54	22.79	36.11
<b>Industrial</b>	Naubasta	92.77	25.43	37.7
	<b>NAAQS</b>	100.00	80.00	80.00

**Fig 1:- Average Concentration (µg/m<sup>3</sup>) of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in different areas of Rewa city during month of February – July, 2024 and compared with prescribed National Ambient Air Quality Standards (NAAQS).**



Result of the study of the Rewa city is similar with research for other cities of India as the concentration of particulate matter is also high in other cities. High particulate concentration is due to heavy transport activity in study area, apart from industrial emission, dust from paved roads, garbage burning in open, population density, congestion, weather, type of fuel and vehicle used, topography of a region and other domestic purposes. The study revealed that concentration of the pollutants in residential, commercial and industrial area showed little variations indicates that pollutants are well dispersed within the urban area. The major concern is the particulate matter which affects the human health. The effect of pollutant especially the particulate matter in urban area depends on several factors like number of concentration, size composition, time of exposure, and lastly the receptor (in case of humans these factors depend on age, health conditions etc.) thus is necessary to monitor the air quality as well as the health effects on regular interval strategic locations. All pollutants were observed to be high in concentration during winters as compared to summer and monsoon, due to slow dispersion and dilution of pollutants.

**Conclusions:** Monitoring of air pollutants such as RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> at 3 locations during six month of 2024 revealed that the concentration of RSPM, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> at all the monitoring locations of residential, commercial and industrial were within the prescribed NAAQS at all the locations. It can be summarized that air pollution at the study site is primarily because of vehicular emissions by heavy traffic.

#### References:-

1. Apte, J. S., Bombrun, E., Marshall, J. D., & Nazaroff, W. W. (2012). Global intraurban intake fractions for primary air pollutants from vehicles and other distributed sources. *Environmental science & technology*; 46(6):3415-3423.
2. Chauhan, A., and Sanjeev. (2008). Impact of dust pollution on photosynthetic pigments of some selected trees grown at nearby of stone crushers. *Environment Conservation Journal*, 9(3), 11-13.

3. Chaurasia, S., Dwivedi, P., Singh, R. and Gupta, A.D. 2013. Ambient Air Quality Status and air quality Index of Bhopal City (Madhya Pradesh). India. *International Journal of Current Science* 9: 96-101.
4. Chakrabarti N, Mitra AK, (2014) possible pollution threat to the green buffer zone around tajmahal IOSR J Environ Sci Toxicol and Food Tech 8: pp. 68-72.
5. Chaurasia, S. and Kumar, S., Assessment of air pollution emission from wonder cement Ltd., Nimbahera, *Indian J. Environ. Prot.*, 34, (2014): 89-93
6. Dwivedi A. P., and Tripathi I. P., (2018) study on air quality data at various locations in three different areas of central india. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR)*.V (2):12-24
7. Hasan MM, Rabbi MA, Maitra B, Faruk O3, Sarwar M4 and Roy PK5, (2018) assessment of nitrogen oxides and sulphur dioxide content in the ambient air near the garments industries of bangladesh. *Journal of Environmental and social sciences*.V(5):1-4.
8. Kushwaha, S.K., Singh, R., Kushwaha, B.P., Pathak, V., Rai, O.P. and Dwivedi, R., A study of air quality and human health of certain villages of industrial area, Raigarh, *Indian J. Environ. Prot.*, 28, (2008): 709-713
9. Maurya, A., Status of ambient air quality at Jabalpur city- A case study, *Indian J. Environ. Prot.*, 25, (2005): 702-705
10. Mondal, G.C., Singh, A.K., Tewary, B.K., and Kamal, K.P., Assessment of air pollution in and around of Dhanbad *Indian J. Environ. Prot.*, 27, (2007): 13-22
11. Muneeswaran, S., Jebamani, M.I.S, Rajesewaran, S., and Chandrasekharan, S., Assessment of ambient air quality status during May-December 2011 in Commercialized and urbanized zones of Coimbatore, *Indian J. Environ. Prot.*, 33, (2013): 89-99
12. Mangalekar, S.B., Jadhav A.S. and Raut, P.D. 2014. Studies on Ambient Air Quality Status of Kolhapur City, Maharashtra, India Vol. 12, No. 3: pp. 15-22.
13. Mukhopadhyay, S. and Mukherjee, R. (2013). Assessment of ambient air quality of Purulia town, Purulia District, West Bengal, *India Biolife*, 1(4) : 189-94
14. Nandanwar, N.P., Dixit, A.K., Dixit, K.R., Wazalwar, S.S., (2014) comparative study of ambient air quality around chandrapur *international journal of scientific engineering and technology* 3(3): 267-275.
15. Rani B, Singh U, Maheshwari R (2011) Menace of Air Pollution Worldwide. *AdvBiores* 2: 1-22
16. Richhariya Neelam, (2015) study of chemical turbulence in ambient air quality in Satna (MP) india *international journal of pharmacy & life sciences*, 6(2), 4268-4271.
17. Salve, P.R., Maurya, A., Ramteke, D.S., and Wate, S.R., A study of air pollutants in Chandrapur, *Indian J. Environ. Prot.*, 26, (2006): 742-747
18. Sharma, R., and Parvej, S., Study of seasonal variation in ambient particulate of Durg city. *Indian J. Environ.*

- Prot., 23, (2003): 893-896.
19. Sharma, S .K. and Sharma, K., 2016. Ambient Air Quality Status of Jaipur City, Rajasthan, India. International Research Journal of Environment Sciences Vol. 5(1): 43- 48.
  20. Simbi J, Opeolu BO, Olatunji OS, (2017) selected gaseous pollutants level in ambient air around the vicinity of chemical industry in kwekwe, zimbabweasian J Chem. 29: 1639-1645.
  21. Tsang H., Kwok R., and Miguel, A.H. 2008. Pedestrian Exposure to Ultrafine Particles in Hong Kong under Heavy Traffic Conditions. Aerosol Air Quality Research 8: pp 19– 27.
  22. Kanawade, V. P., Srivastava, A. K., Ram, K., Asmi, E., Vakkari, V., Soni, V. K., Varaprasad, C., & Sarangi, C. (2020). What caused severe air pollution episode of November 2016 in New Delhi?. *Atmospheric Environment.*; 222: 117125.

\*\*\*\*\*

## सिंदूर पौधे का महत्व एवं उपयोगिता

डॉ. मनीषा दंडवते\*

\* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – सिंदूर का पौधा उससे प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रंग के लिये जाना जाता है। सिंदूर पौधे के बीज से प्राप्त रंग का उपयोग माँग में भरने वाले 'सिंदूर' में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग लिपिस्टिक एवं शरीर को रंगने वाले 'बॉडी-पेंट' या 'डाई' में किया जाता है। सिंदूर से प्राप्त प्राकृतिक रंग का उपयोग भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रंग लाने के लिये किया जाता है। भोज्य पदार्थों में प्रयुक्त रंग भोज्य पदार्थ के गुण एवं स्वाद में अंतर नहीं आने देता है। इसका उपयोग कुछ औषधियों में भी किया जाता है। सिंदूर का उपयोग प्रागैतिहासिक काल से माँग भरने के लिये किया जाता है। यह सुहागिनों के सोलह शृंगार में से एक है। स्त्रियाँ माँग में सिंदूर अपने पति के दीर्घायु होने एवं उसे बुरी नज़र से दूर रखने के लिये करती है। माँग में सिंदूर भरना हमारी वैदिक विवाह पद्धति की प्रमुख रस्म है।

इसके बीजों का पारंपरिक व्यंजनों में मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विशेषकर दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन में। बिकिसन नामक वर्णक उत्पन्न करने वाला यह एकमात्र पौधा है।

**शब्द कुंजी** – प्राकृतिक रंग, बॉडी पेन्ट, सोलह शृंगार, दीर्घायु, सिंदूर, वैदिक विवाह पद्धति, मसाले।

**प्रस्तावना** – सिंदूर का पौधा एक औषधीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम *Bixa orellana* है एवं यह बिकसेसी फैमिली का सदस्य है। यह पौधा सिंदूरी, कपीला, कमीला ट्री लैटिन में 'मालोटस फिलिपिनेसिस' नाम से प्रसिद्ध है। कई लोग इसे 'लिपिस्टिक ट्री' भी कहते हैं क्योंकि इस पौधे के फल को लिपिस्टिक का रंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंग्लिश नाम 'एन्नाटो' है। बिकसा ओरेलाना जिसे 'एचिओट' के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य अमेरिका का एक झाड़ी या छोटा पेड़ है।

यह पौधा एनाटो के स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो एक प्राकृतिक नारंगी-लाल मसाला (जिसे एचियोट या बिजोल भी कहा जाता है) जो इसके बीजों को ढँकने वाले नोमी एरिल से प्राप्त होता है। पिसे हुए बीजों का व्यापक रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन में पारंपरिक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है।

एनाटो और इसके अर्क का उपयोग 'औद्योगिक खाद्य रंग' के रूप में कई उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर, मार्जरीन, आइस्क्रीम, मीट और मसालों में पीले रंग के रूप में किया जाता है। उत्तर मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ स्वदेशी लोगों ने मूलरूप से बीजों का उपयोग लाल बॉडी पेंट और लिपिस्टिक बनाने के लिये किया था साथ ही मसालों के रूप में।

**व्युत्पत्ति और सामान्य नाम** – बिकसा ओरेलाना ये नाम लिनियस द्वारा दिया गया।

बिकसा जीनस का नाम आदिवासी 'ताइनो' शब्द से निकला है जबकि 'ओरेलाना' अमेजन खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना के सम्मान में रखा गया जो अमेजन नदी के शुरुआती खोजकर्ता थे। अचियोट झाड़ी के लिये नाहुआटल से निकला है। इसे एक्लोपस या इसके मूल 'टू पी' नाम उरुक या उरुकम (लाल रंग) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसे उपनाम 'लिपिस्टिक ट्री' कॉस्मेटिक के रूप में डाई के उपयोग से लिया गया है।

**उद्देश्य** – इसका उद्देश्य सिंदूर के पौधे का प्रागैतिहासिक महत्व एवं इसकी उपयोगिता समझाने के साथ ही साथ आज आधुनिक युग में जहाँ सौंदर्य प्रसाधनों में हानिकारक रसायनों जैसे कि बाजार के सिंदूर में लाल रंग के लिये  $PbO_2$  या लैड ऑक्साइड एवं सिनाबार का उपयोग किया जाता है। लिपिस्टिक में गंध एवं रंग के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले रसायन हेयर डाई में प्रयुक्त विभिन्न हानिकारक सिंथेटिक रसायनों के स्थान पर प्राकृतिक सिंदूर पौधे के बीजों से प्राप्त रंग अधिक लाभप्रद है। खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाने के लिये प्रयुक्त रासायनिक रंग इसे चटक रंग तो देते हैं परंतु ये वस्तु का स्वाद बदल देते हैं साथ ही त्वचा, जीभ इत्यादि के लिये भी नुकसानदायक होते हैं। अतः यदि हमारे प्राचीन ज्ञान का उपयोग हम करेंगे हमारे देश के पूर्वज (विशेषकर आदिवासी जनसमुदाय इस पौधे का उपयोग करते थे) जिन पेड़-पौधों का उपयोग करते थे वह स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये उपयोगी थे उनका पुनर्उपयोग एवं उनकी उपयोगिता को फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है एवं यही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

**विवरण** – बिकसा ओरेलाना एक झाड़ी के रूप में बारहमासी सदाबहार पेड़ है जो 6-10 मी. ऊँचा होता है इसमें 5 सेमी. (2 इंच) के चमकीले सफेद या गुलाबी फूलों के समूह होते हैं जो एक जंगली गुलाब के समान होते हैं जो शाखाओं के सिरे पर दिखाई देते हैं। 'बिकसा ओरेलाना' के फल गोलाकार, अंडाकार कैप्सूल होते हैं जो गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं, जो नरम काँटों से ढँके लाल-भूरे रंग के बीज की फली के समान होते हैं, प्रत्येक कैप्सूल या फली में 30-45 शंकु के आकार के बीज होते हैं जो पतले मोमी रक्त-लाल-अरील से ढँके होते हैं। पूरी तरह परिपक्व होने पर फली सूख जाती है तब सख्त हो जाती है। यह पौधा लाल-नारंगी एनटो वर्णक के स्रोत के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। यह वर्णक *Bixa orellana* के फल के Pericarp (बीजों को ढँकने वाली मोटी एरिल परत) से प्राप्त होता है। लाल-

नारंगी एनाट्रो रंग Caretenoid वर्णकों में समृद्ध होता है जिसमें 80% बिक्सिन (लाल वर्णक) और Norbixin या Oralin (पीला वर्णक) से बना होता है। एनाट्रो तेल में टोकोट्रिऑनॉल, बीटा कैरोटीन, आवश्यक तेल, संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड फ्लेवेनॉइड और विटामिन सी होते हैं।

**वितरण एवं उपयोग** – बिकसा ओरेलाना की सटीक उत्पत्ति अज्ञात है। यह उत्तरी दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मूल निवासी है। यह मैक्सिको से लेकर इक्वाडोर, ब्राजील और बोलिविया तक जंगली क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक आक्रामक प्रजाति है पर इसे दुनिया के कई क्षेत्रों में एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे भारत, श्रीलंका और जावा में मुख्य रूप से बीजों से प्राप्त होने वाली डाई के लिये उगाया जाता है, इसे बीज या कटिंग से लगाया जा सकता है।

सिंथेटिक रंगों ने उद्योग में क्रांति लाने से पहले बिकसा ओरेलाना (बिक्सिन वर्णक उत्पन्न करने वाला एकमात्र पौधा है) को व्यवसायिक रूप से पहली बार लगाया गया। एनाट्रो पिगमेंट का वैश्विक आर्थिक महत्व है क्योंकि यह भोजन, सौंदर्य, प्रसाधन और दवा उत्पादों को रंगने के लिये व्यापक रूप से उपयोग होता है। खाद्य-पदार्थों में इसका रंग स्वाद को प्रभावित नहीं करता है और विशाक्त नहीं होता। इसका उपयोग मुख्य रूप से आइसक्रीम, मीट, डेयरी उत्पाद (पनीर, मक्खन, मार्जरीन) और मसालों को रंगने के लिये एवं कॉस्मेटिक उत्पादों में हेयर कलरिंग (लाल रंग किसी विशिष्ट चरित्र को नाटक में, नृत्य में दिखाने में) नेल पॉलिश, साबुन और पेंट में।

**पाक कला में** – बिकसा ओरेलाना के बीजों को तेल में गर्म करके उनका रंग निकाला जाता है। फिर उसका उपयोग पनीर, मक्खन, सूप, ब्रेवी, सॉस, मीट अन्य वस्तुओं व्यंजनों में एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में किया जाता है जो भोजन में एक सूक्ष्म स्वाद, सुगंध एवं पीला-लाल रंग प्रदान करते हैं। सैजोन नामक मसाला पैकेट में जीरा, धनिया, लहसुन के साथ बिकसा ओरेलाना के बीज डाले जाते हैं जो कि स्पैनिश, लैटिन अमेरिकी, कैरेबियन व्यंजनों में उपयोग में आता है। एनाट्रो पिगमेंट का उपयोग पीले चावल बनाने में, ब्लाफ मछली बनाने में या पोर्क स्टू में प्रयोग किया जाता है। निकारागुआ में एचिओट का आम उपयोग मसाला पेस्ट के रूप में होता है।

**पारंपरिक उपयोग** – बिकसा ओरेलाना पौधे का सबसे पारंपरिक उपयोग विभिन्न जनजातियों और प्राचीन सभ्यताओं के बीच शरीर, चेहरे और बालों को रंगने के लिए या तो सजावटी उद्देश्यों के लिए या बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए शगुन के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग ब्राजील की जनजातियों द्वारा किया जाता है। एजटेक ने 16 वीं शताब्दी में 'पांडुलिपि' पेंटिंग के लिये लाल स्याही के रूप में एनाट्रो वर्णक का उपयोग किया था। सिंदूर को पारंपरिक रूप से चेहरे की सजावट के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंदूर एक लाल नारंगी रंग का सौंदर्य प्रसाधन होता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाएँ प्रयोग करती हैं।

'बिकसा ओरेलाना' का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इस पेड़ का उपयोग 'आयुर्वेद' में किया जाता है जो कि भारत की लोक चिकित्सा पद्धति है। जहाँ पौधे के विभिन्न भागों को चिकित्सा के रूप में उपयोगी माना जाता है।

सिंदूर का चलन प्राचीनकाल से जुड़ा है। हिंदू धर्म में सिंदूर को 'सौभाग्य' का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा शादी के दिन से शुरू होती है। सिंदूर सोलह शृंगार का हिस्सा है। सिंदूर का इतिहास लगभग

5000 साल पुराना है इसका जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया है – देवी माता 'पार्वती' और मां 'सीता' भी सिंदूर से मांग भरती थी। मान्यता है कि माता 'पार्वती' अपने पति भोलेनाथजी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिये सिंदूर लगाती थी। वहीं माता 'सीता' अपने पति प्रभु श्रीराम की लंबी उम्र की कामना के लिये मांग में सिंदूर लगाती थी एवं 'भगवान श्रीराम' को प्रसन्न करने के लिये 'हनुमानजी' ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगाया था इसलिये हनुमानजी की पूजा पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। इसलिये हनुमानजी की पूजा के दौरान सिंदूर का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा 'महाभारत' में द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं। सिंदूर लगाने को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर पांच स्थानों पर वास है इनमें से एक स्थान सिर भी है ऐसे में महिलाएँ सुख-समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिये मांग में सिंदूर लगाती हैं।

इस पौधे को रस्सी की चटाई बनाने के लिये तथा तने की रेषे एवं चिपकने वाले गोंद के लिये महत्व दिया जा रहा है।

रासायनिक सिंदूर एवं प्राकृतिक सिंदूर में अंतर यह है कि रासायनिक सिंदूर या वर्नीलियन का फॉर्मूला  $Pb_3O_4$  यह लाल रंग का होता है और इसमें Lead को पीसकर मिलाया जाता है यह चटक लाल रंग देता है। सिनाबार भी कभी-कभी सिंदूर के रूप में लगाया जाता है जिसमें मरकरी पाया जाता है जो कि जहरीला होता है। सिंदूर को लाल करने के लिये सिनाबार का उपयोग भी किया जाता है किन्तु प्राकृतिक सिंदूर हानिरहित होता है।

नेपाल में भगवान की पूजा में सिंदूर का विशेष महत्व है। नेपाली हिंदुओं में विवाह के समय मांग में भरे जाने वाले सिंदूर की प्रथा है जिसे 'सिउदो' या 'सिन्दूर हालने' कहते हैं जिसका अर्थ है कि लड़की ने 'जो मांग भरता है' उसे अपना 'जीवन साथी' मान लिया है। नेपाली संस्कृति में सिंदूर भरने की प्रथा बहुत पुरानी है, महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु एवं सुरक्षा के लिये प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर पौधे को पवित्र माना जाता है और विवाह के लिये वैदिक तिथियों को पालन करने वाले लोग सिंदूर पौधे से निकलने वाले प्राकृतिक रंग को इकट्ठा करने के लिये विवाह तिथि से एकत्रित होते हैं एवं पारंपरिक रूप से सिंदूर बनाते हैं। नेपाल में सीड पल्प का उपयोग तेल को रंग देने में, बटर को रंग देने एवं कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है एवं सौंदर्य प्रसाधन में हाथों को रंगने के लिये किया जाता है।

सिंदूर के फल भूरे रंग के होने से पहले इकट्ठा करके, इनके Spilt होने पर बीज इकट्ठा करते हैं उन्हें सुखाकर साफकर सिंदूर बनाया जाता है। नेपाली विवाह में नववधू को सिंदूर बॉक्स (सिंदूर को बट्टा) दिया जाता है।

भारतीय औषधीय शास्त्र विशेषकर आयुर्वेद के अनुसार Bixa Orellana की कड़वी, ठंडी, भूरी छाल का उपयोग रक्त संबंधी बीमारियों में, सरदरद, बुखार में किया जाता है पत्तियों का उपयोग रक्त शोधन में इसके बीजों से बना पेस्ट मच्छरों को दूर रखता है। यह एक बहुउपयोगी पौधा है जिसकी पत्ती, बीज, छाल, जड़ सभी औषधीय, खाने योग्य एवं फूड कलर के रूप में उपयोगी है। एज्जाटों बीज से रंग निकालने के पश्चात् इसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन से भरपूर होता है।

**निष्कर्ष** – सिंदूर का पौधा जिसका वानस्पतिक नाम 'बिकसा ओरेलाना' है। इस पौधे के बीज से न केवल प्राकृतिक रंग निकाला जाता है जिसका उपयोग माँग में भरने वाले 'सिंदूर' में किया जाता है बल्कि इस प्राकृतिक

रंग का उपयोग डाई, लिपिस्टिक तथा भोज्य पदार्थों में किया जाता है। बिक्सा ओरेलाना से प्राप्त लाल-नारंगी एन्राटो रंग Carotenoids से समृद्ध होता है जिसमें बिक्सिन (लाल वर्णक) एवं नॉरबिस्किन या Oralin (पीला वर्णक) से बना होता है। एनाट्रो तेल में टोकोट्रिऑनॉल, बीटा कैरोटिन, आवश्यक तेल, संतृप्त एवं असंतृप्त फैटी एसिड फ्लेवेनॉइड एवं विटामिन सी पाया जाता है इस प्रकार से पौधे से प्राप्त प्राकृतिक रंग का औद्योगिक उत्पादन किया जा सकता है जिससे प्राकृतिक रंगों का उपयोग बढ़ेगा जो हमारी प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाएगा। इस पेड़ का उपयोग हमारी भारतीय परंपराओं में प्रागैतिहासिक काल से किया जाता रहा है इसके चिकित्सकीय उपयोग भी ज्ञात हैं। इस पौधे की छाल, बीज, पत्ती सभी औषधीय गुण रखते हैं अतः इस पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाना एवं संरक्षित करना आवश्यक है।

हमारी प्राचीन संस्कृति मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों को संरक्षित करना, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारे रीति-रिवाजों में जो मूल भावनाएँ छिपी हैं उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से सिंदूर के पौधे का महत्व एवं उपयोगिता समझना आवश्यक है।

**सुझाव** - संधारणीय विकास लक्ष्य SDG Goals (2015) जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए और इन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में प्रचारित किया गया जिसके अंतर्गत भूमि के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, पानी बचाना आदि आते हैं। हमारे प्रागैतिहासिक वृक्षों जैसे सिंदूर के पौधे से प्राप्त डाई का उपयोग न केवल हमारे बाल स्वास्थ्य के लिये अच्छा है। यह बाल धोने के लिये प्रयुक्त पानी (बाल रंगने के लिये रासायनिक रंगों के प्रयोग से बाल धोने के लिये पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है) को कम करेगा बल्कि रासायनिक रंगों में प्रयुक्त रसायन हमारे पानी के स्रोतों में पहुँचकर उन्हें भी प्रदूषित करते हैं जिससे हमारा जलीय जीवन भी प्रभावित होता है अतः इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 'बिक्सा ओरेलाना' से प्राप्त प्राकृतिक रंग उपयोगी हैं इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिये।

फूड कलर्स या भोज्य पदार्थों में प्रयुक्त रंग जिसमें रसायनों का उपयोग होता है वे न केवल हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं बल्कि कई बार वे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर भोजन को विशाक्त कर देते हैं।

अतः प्राकृतिक रंगों का उपयोग खाद्य सुरक्षा के लिये भी आवश्यक है। इस पौधे के बीज एवम् पत्ती से प्राप्त चारे में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ये प्राकृतिक स्रोत के रूप में उपयोगी एवं हमारे पर्यावरण के लिये सुरक्षित है इसलिये इनका अधिक से अधिक उपयोग अनिवार्य है। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी आधुनिक युग की आवश्यकता है परंतु इनमें यदि प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए तो ये स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिये सुरक्षित होगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वहीलर, एल, बीच, ई (2019) 'बिक्सा ओरेलाना IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटर्ड स्पीसीज 2019'
2. लेवी, लुईस डब्लू, रेवाडेनेरा, डायना एम (2000) एनाट्रो - लॉरो, ब्रेब्रियल जे, फ्रांसिस एफ जैन - प्राकृतिक खाद्य रंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी IFT बेसिक सिम्पोजियम सीरिज न्यूयॉर्क मार्सेल डेकर पेज नं. 115 ISBN 978-0-8247-0421-6
3. बिक्सा ओरेलाना (लिपिस्टिक ट्री) के लिये पौधे की प्रोफाइल (पौधों का डाटाबेस, अमेरिकी कृषि विभाग) 2019
4. बोवियर, फ्लोरेंस, डोगबो, ओडेट, कैमारा, बिलाल (2003) 'खाद्य और कॉस्मेटिक प्लांट पिंगमेंट बिक्सिन का (एनाट्रो) जैव संश्लेषण'
5. ओचिओट : वह मसाला जो भोजन को पीला रंग देता है द स्पूसईटस (2019)
6. खरे, सी.पी. (2007) भारतीय औषधीय पौधे न्यूयॉर्क : स्प्रिंगर साइंस + बिजनेस मीडिया एलएलसी : ISBN 978-0-387-70638-2

\*\*\*\*\*

# Status, Cause and Resurrection of Rare, Endangered and Threatened Forest Tree species of Madhya Pradesh

Dr. Dinesh Kumar Dahare\*

\*Assistant Professor (Botany) PMCoE, BKSNGovt. P.G. College, Shajapur (M.P.) INDIA

**Abstract :** Present work deals with the current status of RET forest tree species of Madhya Pradesh in relation to their conservation strategies. Out of 260 tree species present in forest 40 species from 24 families reported as various categories of IUCN criteria of RET tree species. Due to their unsustainable utilization these species are now limited in forest area and remain very few in number. Forest department took initiative to conserve these species and raise saplings of 30 RET tree species in 11 research and extension circle nurseries throughout the Madhya Pradesh. Forest department also planted 10% of RET species in each plantation programme as mandate so that these tree species cover will be increase and restore naturally.

**Keywords:** Conservation, criteria, saplings, strategies, unsustainable.

**Introduction -** Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country with more than 260 tree species reported in forest, villages and urban settlements areas. The forest types of Madhya Pradesh are mainly montane subtropical, tropical moist deciduous, tropical dry deciduous and dry deciduous scrub forest (Champion, H. G. & S.K. Seth, 1968). The region has different types of landscapes valley, plains, plateau and hilly terrains which provide the diversity for tree species. The climate of the area is typical monsoonic with cool dry winter and warm moist summer. The Soil of the area is sandy loam to black cotton soil. In terms of forest canopy according to density classes, Madhya Pradesh has 6676.02 square km under very dense forest (2.17% of the geographical area), 34,341.40 square km under moderately dense forest (11.14% of geographical area) and 36,465.07 square km (11.83% of geographical area of the state) under open forest, as per Forest Survey of India (FSI) report 2011.

In recent past overall forest cover increase marginally due to inclusion of area under tree outside forest, but the dense forest cover reduces in Madhya Pradesh. However, due to unsustainable and species-specific utilization of plant resources for various purposes like timber, food, forage, medicinal use and poor regeneration, some major tree species were recognised under IUCN categories (2001), such as critically endangered, endangered, vulnerable and near threatened in forest area of Madhya Pradesh. For their restoration and conservation Forest Department raise saplings of these RET tree species in different research and extension nurseries of Madhya Pradesh and planted as ex-situ and in situ conservation practice in different forest area, parks and other places for their resurrection.

**Current status of RET tree species:** At present 40 tree species belonging to 24 families are reported under various categories of IUCN (K.K.Khanna et.al,2021). Such as 2 species critically endangered Salyakarni (*Dilleniapentagyna*) and Maida (*Litsea glutinosa*), 6 species as endangered Dahiman (*Cordia macleodii*), Sonpatha (*Oroxylum indicum*), Agnimanth (*Premnamollissima*), Garudphal (*Radermacherylocarpa*), Lodhra (*Symplocos recemosa*) and Charaigoda (*Vitex penducularis*).

11 species as Vulnerable Kumbhi (*Careya arborea*), Gabdi (*Cochlospermum religiosum*), Varuna (*Crateva religiosa*), Kala Sheesham (*Dalbergia latifolia*), Kekad (*Garuga pinnata*), Bijasal (*Pterocarpus marsupium*), Rohina (*Soymida febrifuga*), Kullu (*Sterculia urens*), Padar (*Stereospermum suaveolens*), Nirmali (*Strychnou-spotatorium*), Dudhi (*Wrightia tinctoria*) and 21 species as near threatened Haldu (*Adina cardifolia*), Khair (*Acacia catechu*), Dhawa (*Anogeissus latifolia*), Salai (*Boswellia serrata*), Achar (*Buchananialanzan*), Kharhar (*Ceriscoide-sturgida*), Tamoli (*Dolichandrone falcata*), Gadhapalash (*Erythrina suberosa*), Kuwarin (*Firmianacolorata*), Dhamin (*Grewia tiliifolia*), Anjan (*Hardwickiabinata*), Bhurkut (*Hymenodictyon orixense*), Tinsa (*Ougeiniadelbergioides*), Peelu (*Salvadora oleoides*), Kusum (*Scheichera oleosa*), Mokha (*Schreberaswietenoides*), Bhilma (*Semecarpus anacardium*), Khatamb (*Spondias pinnata*), Bherar (*Tamilnadia uliginosa*), Harra (*Terminalia chebula*) and Tilwan (*Wendlandia heynei*). Critically endangered and endangered tree species are remained in few patches in forest area also vulnerable and near threatened species has very poor status in forest area of Madhya Pradesh. Some

species like *Dalbergia latifolia*, *Buchananialanzan*, *Adina cardifolia* are produced and planted in good number and their status is now improving but other tree species in not fairly grown as much as required for their restoration. Out of 40 reported RET tree species 10 tree species still not grown in any nursery and is of much concern that how it will be conserved or restored.

**Causes of the current status of RET tree species:** The main reason for current status of Rare, Endangered and Threatened tree species is unsustainable utilization of plant resources by local peoples. The depletion in forest covers due to population reduction of trees and overexploitation of tree for various purpose of plant part or whole plant. Habitat loss or habitat fragmentation by encroachment of forest area for agriculture purpose and other activity also threatens locally available tree species, overgrazing in forest area affect the regeneration of some sensitive species because new saplings are grazed by animals or destruct by their movement in forest. Also, poor regeneration, false seeding, less germination, survival of saplings and natural barriers of germination affect the status of these RET tree species.

Destruction of forest, clearing and cutting of large number of trees for various development projects such as Roads, Dams, Power plants, Industry setup etc largely affect the specific species of any area, Over utilization of some local available plants for firewood, daily use and earning without knowing their status of regeneration, whole plant felling for any plant part, leaf or fruit collection by local people, overutilization of medicinal important RET species also increase in pollution and failure of pollination due to unavailability of those plants which required for pollinators attractions. Natural calamities such as flood, drought, land slide and fire also affect these tree species. The status of RET tree species will further become critical if appropriate conservation plans are not applied.

**Resurrection strategies for RET tree species:** All these RET tree species have unique quality of utilization purpose such as Bijasal, used to cure diabetes in ayurveda, having very good timber quality like teak, also used for fodder, Tinsa, used to improve women fertility in local tradition, Salai, producing medicinally important resin and gum; Dahiman, utilized to cure high blood pressure in ethnomedicine. Critically endangered Dahiman tree reporting some cancer-curing properties. Kala sheesham tree is used as fodder, medicines, best quality furniture and musical instruments. Lodhra, Padar and Sonpatha also utilize as medicines.

In order to revive the RET tree species, the forest department is producing saplings of these species in 11

research and extension circle nurseries of state with the special treatment they need for their survival and priority with locally available species. Providing special facilities for better germination and success ratio for overcome the barriers. Polyhouse, mist chamber, green shade net house, sprinklers, moisture controller, automation of temperature, humidity and other facilities arranged for controlled condition for germination, proper growth and survival of these RET tree species. Also, some tree species are produced with the help of plant tissue culture technique in SFRI and plantlets then provides to Research and Extension nurseries for further distribution in different region of Madhya Pradesh. At present forest department raised 47.93 lakh saplings of 30 RET tree species in various nursery of 11 research and extension circles of Madhya Pradesh forest department (Table.1). Saplings of RET tree species, which are used as lifesaving and medicine, are also the source of income of villagers and forest dwellers. Forest department mandatory plant 10 % of RET tree species in every plantation programme also RET special plantation planned to resurrect the tree species in forest area. Plants of RET species can be purchased by locals from the nurseries of the forest department at very nominal rates so that these species will be planted outside the forest for ex-situ conservation. But still 10 RET tree species Agnimanth (*Premnamollissima*), Lodhra (*Symplocos recemosa*), Charaigoda (*Vitex penducularis*), Varuna (*Crateva religiosa*), Kharhar (*Ceriscoidesturgida*), Kuwarin (*Firmianacolorata*), Peelu (*Salvadora oleoides*), Khatamb (*Spondias pinnata*), Bherar (*Tamilnadiauliginiosa*), Tilwan (*Wendlandia heynei*) saplings are not available and forest department need to produce those species saplings so that the status of these RET tree species could be improve.

**Table (see in next page)**

**References:-**

1. Champion, H.G. & S.K. Seth. 1968. A revised survey of the forest type of India. Govt. of India Publications, New Delhi.
2. <https://mpforest.gov.in/publicdomain/NMIS/RptCirWise.aspx>
3. <http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/347677/india-state-of-forest-report-2011/>
4. IUCN (2001). IUCN red list categories and criteria (version 3.1) <https://iucn-csg.org/red-list-categories>.
5. K.K. Khanna, P. Dubey, A.P. Tiwari, R.L.S. Sikarwar (2021). Studies on threat status of tree species of Madhya Pradesh. Indian forester, 147(2) 137-140. 2021, ISSN-0019-4816.



**Table 1: Availability of RET tree species Saplings at various R&E Circles of Madhya Pradesh**

S.	Species Name	Research and Extension Circle Name and Quantity of available plants (March 2025)										
		Indore	Khandwa	Gwalior	Jabalpur	Jhabua	Betul	Bhopal	Ratlam	Rewa	Sagar	Seoni
1	<i>Acacia catechu</i>	18752	16862	631510	11500	54563	485	14844	46822	29486	16561	1765
2	<i>Adina cordifolia</i>	0	1570	0	9398	33534	0	79298	0	4578	29152	3850
3	<i>Anogeissus latifolia</i>	0	0	0	280	0	0	4785	0	8431	800	0
4	<i>Boswellia serrata</i>	12194	1421	222695	5000	12000	15	0	10000	17214	2000	0
5	<i>Buchnanialanzan</i>	7533	3496	0	7549	4475	1535	18393	200	167197	10302	8975
6	<i>Careya arborea</i>	0	0	0	1437	0	2639	61145	0	1914	6736	0
7	<i>Cochlospermum -religiosum</i>	0	0	0	3620	0	0	17414	0	0	700	0
8	<i>Cordia macleodii</i>	6619	0	0	3101	0	0	0	0	11708	416	0
9	<i>Dalbergia latifolia</i>	9358	7142	15367	198251	74970	14127	180138	30307	59380	470930	114222
10	<i>Dilleniapentagyna</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0
11	<i>Dolichondre falcata</i>	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
12	<i>Erythrina suberosa</i>	216	1200	1546	822	7810	0	1000	2100	1200	0	0
13	<i>Garuga pinnata</i>	0	0	0	1000	0	0	311	0	0	6070	0
14	<i>Grewia tiliifolia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19026	0
15	<i>Hardwickiabinnata</i>	11256	9298	3900	7150	17970	25	26322	6335	0	20370	500
16	<i>Hymenodictyon -orixence</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5416	0	0
17	<i>Litsea glutinosa</i>	0	0	0	460	0	0	0	0	6800	1165	0
18	<i>Oroxylum indicum</i>	0	440	0	16747	0	5	6105	0	9345	8388	190
19	<i>Ougeinia oojainense</i>	5514	2538	1200	71310	24280	1298	159202	0	3800	144964	18209
20	<i>Pterocarpus marsupium</i>	6460	2255	2842	18738	14009	194	54384	1200	4980	34298	16478
21	<i>Radermachera xylocarpa</i>	110	1183	0	33049	0	5	5739	0	5434	1934	0
22	<i>Schereberasw -eitenioides</i>	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Scleichera oleosa</i>	26511	2981	19599	2822	20870	3345	174430	14331	25888	36800	34131
24	<i>Semecarpus anacardium</i>	1083	660	3100	18565	1000	90	7857	0	526	48650	119781
25	<i>Soymidafabrifuga</i>	0	0	0	1020	2900	0	0	0	1900	5600	0
26	<i>Sterculia urens</i>	1651	6701	1521	4091	30802	50	14444	500	3559	4863	345
27	<i>Stereospermum -chelonoides</i>	0	346	0	3701	0	0	200	0	10750	15523	549
28	<i>Strychnous potatorum</i>	0	0	0	66	0	0	0	0	3000	5000	0
29	<i>Terminalia chebula</i>	9320	2354	18460	138559	9935	12611	97198	2450	36301	49648	55156
30	<i>Wrightia tinctoria</i>	0	1850	0	1880	300	0	13084	0	1200	150	0
	<b>Total</b>	<b>4793274</b>										

\*\*\*\*\*

# Effect of Yoga as a Relaxation Technique on Sleep quality among School Students Appearing Board Exam

Ms. Sushruta Sahu\* Dr. Varsha Sharma\*\*

\*Research Scholar (Psychology) UCSSH, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

\*\* Assistant Professor (Psychology) UCSSH, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Abstract :** Yoga works as a relaxation technique to reduce stress, anxiety and enhances sleep quality and wellbeing. Yoga regulates sleep cycle which helps to manage emotional and cognitive functioning. Most of the students suffer from mental health issues specially who are appearing board exams due stress and pressure of exams, marks, future career and expectations for higher marks in board exams from others. Surya namaskar has been found in reducing stress, anxiety and insomnia. The major aim of the study was to understand the effect of yoga as a relaxation technique on sleep quality of students appearing board exam. 42 students who were appearing board exam and scored high in poor sleep quality selected for the study. Results found significant effect of yoga as a relaxation technique on poor sleep quality among school students appearing board exam both male and female. Surya namaskar is helpful for increasing poor sleep quality.

**Keywords:** Sleep quality, yoga, relaxation technique, school students.

**Introduction** - Yoga helps to balance between mind and body which recognized in ancient time. Today people are not giving much importance to yoga practices while yoga gives healthy life. Individuals who practice yoga could reach the higher psychological wellbeing and increase sleep quality. Yoga affects sleep quality of individuals for satisfactory and restful sleep.

Yoga works as a relaxation technique to reduce stress, anxiety and enhances sleep quality and wellbeing. Yoga works on both physical and mental health. It is holistic approach of mind and body to get overall fitness. Yoga regulates sleep cycle which helps to manage emotional and cognitive functioning.

Here are some major impacts of yoga:

1. Increases wellbeing and decreases mental stress
2. Helps in decision making
3. Physical health and strength
4. Helps in attention and concentration
5. Decreases mood disturbances
6. Reduces poor sleep quality

Sleep quality is different from sleep quantity. Sleep quantity is about the duration of sleep, how much time a person sleeps but sleep quality is about how well or satisfactory a person sleeps in during the duration. Good sleep quality is a level of satisfaction individuals feel next morning and poor sleep quality is a level of dissatisfaction individuals report next morning.

School students who are appearing board exams are adolescents. Adolescents is the period of physical,

emotional, psychological and social changes occurs. These changes affects an individuals' overall wellbeing which leads to lower sleep quality. They depend on substance abuse for releasing stress and restful sleep.

Most of the students suffer from mental health issues specially who are appearing board exams due stress and pressure of exams, marks, future career and expectations for higher marks in board exams from others. These issues are not focused and treated by students and family and teachers also. Academic stress impacts students' mental health which can lead to impact academic performance. These can increase the difficulties to concentrate, learning and sleep. Yoga is a relaxation technique specially Surya namasakar which includes 12 asanas that impacts full body and mind. Surya namaskar works on mind and body which gives satisfaction and relaxation. When mind and body is relaxed and stress free person gets more satisfactory sleep. Yoga regulates sleep pattern and manage stressful life.

Surya namaskar has been found in reducing stress, anxiety and insomnia. Yoga with breathing exercises treats headache, body pain, digestion issue and mental issues such as depression, stress, aggression and sleep disorder. Yoga can release exam stress, reduce poor sleep quality and increase attention & concentration in study.

## Review of literature

Yoga exercises in daily life help to reduce poor sleep quality and there is a significant effect of long term yoga practices on sleep quality (Banker, M. et al. 2013).

Yoga techniques and regular practices can reduce anxiety

and enhance sleep quality with encouragement to do yoga on regular basis (Lucas, 2024).

**Research Objective:** This study aim to understand the effect of yoga as a relaxation technique on sleep quality of students appearing board exam.

**Research Hypothesis:** There will be significant effect of yoga as a relaxation technique on sleep quality of students appearing board exam.

**Methodology:** Pre and posttest used to find the impact of yoga as a relaxation technique on sleep quality of students who were appearing in board exam.

**Participants:** A purposive sampling method used to select 42 students who were appearing board exam and who were scored high in poor sleep quality. 18 female and 24 male students were involved in the study.

**Procedure:** A government school's students selected from 10<sup>th</sup> class and consent was taken from all the participants. Students were given sleep quality scale to measure the level of sleep quality. 42 students were selected who had poor sleep quality and were given Surya namaskar as a relaxation technique. In posttest sleep quality scale were given again to measure post relaxation technique sleep quality scores.

**Result & Discussion:**

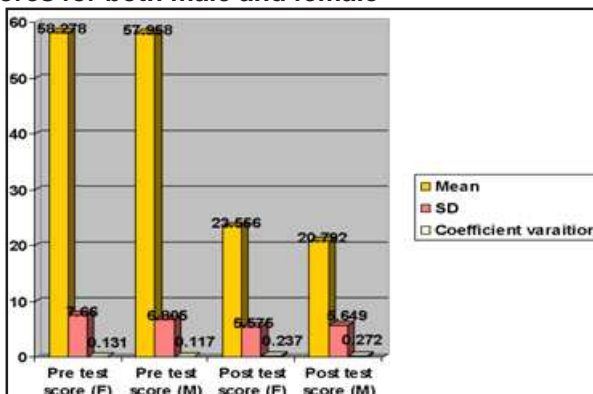
**Hypothesis:** There will be significant effect of yoga as a relaxation technique on sleep quality of students appearing board exam.

**Table 1: Descriptive statistics of pre and posttest scores for both male and female**

Descriptive Statistics

	SQ Score pre relaxation technique		SQ score post relaxation technique	
	Girls	Boys	Girls	Boys
N	18	24	18	24
Missing	0	0	0	0
Mean	58.278	57.958	23.556	20.792
Std. Deviation	7.660	6.805	5.575	5.649
Coefficient of variation	0.131	0.117	0.237	0.272
Minimum	44.000	44.000	11.000	11.000
Maximum	70.000	67.000	31.000	30.000

**Figure 1: Graphical representation of pre and post test scores for both male and female**



Descriptive statistics showing the mean score of girls (58.278) was higher compared to mean score of boys (57.958) in pre-test. In post sleep quality score, mean (23.556) was higher for girls (20.792) compared to boys students. Standard deviation for pre-test is 7.660 for girls and 6.805 for boys showing higher variability in sleep quality scores of girls. Standard deviation for posttest is 5.575 for girls and 5.649 for boys which is showing similar variability. Coefficient of variation is 0.131 for girls and 0.117 for boys in pre-test while 0.237 girls and 0.272 for boys in post test scores suggesting higher relative variance in boys compared to girls in pre-test and higher relative variance in girls compared to boys in posttest.

Results are indicating higher mean score for girls in both pre and post test sleep quality scores which is showing higher poor sleep quality scores of girls' students in both pre and post test. Standard deviation and coefficient of variation is suggesting higher variability in higher for girls in pre-test and higher for boys in post test and the results are not likely to random chance.

**Table 2: t test for poor sleep quality of pre and post test**

Paired Samples T-Test

Pre test	Post-test	t	df	p
SQ Score pre relaxation technique	SQ score post relaxation technique	31.837	41	< .001

Note. Student's t-test.

Results are showing significant effect of yoga relaxation technique on sleep quality among students appearing board exam. P value is <0.001 which is less than the threshold of 0.05 which is showing significant effect. Findings indicating that Surya namaskar can reduce poor sleep quality and enhances wellbeing of students.

**Conclusion:** Mental wellbeing is very important for students and lack of sleep can affect the wellbeing. Better sleep is a major thing to increase wellbeing in students. Results found significant effect of yoga as a relaxation technique on poor sleep quality among school students appearing board exam both male and female. Surya namaskar is helpful for increasing poor sleep quality. Students who are appearing board exam suffer from too much stress and anxiety for exams which affect sleep quality and overall mental health. Sleep quality need to be focused and treated specially in students.

**Recommendation:**

1. Gender dynamics can be measure in further studies for measure gender difference of yoga relaxation technique.
2. Yoga as a relaxation technique could use in schools for enhancing the wellbeing and decreasing poor sleep quality.

**References:-**

1. Bankar, M. A., Chaudhari, S. K., &Chaudhari, K. D. (2013). Impact of long term Yoga practice on sleep

- quality and quality of life in the elderly. *Journal of Ayurveda and integrative medicine*, 4(1), 28–32. <https://doi.org/10.4103/0975-9476.109548>
2. Importance of Yoga for Students in Their Development - The Blue Bells School. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from <https://thebluebells.org/blogs/importance-of-yoga-for-students-in-their-development/>
  3. Lucas Mullins, Larisa, "The Effects of Yoga on Anxiety and Sleep Quality Levels Among College Students" (2024). DNP Projects. 470. [https://uknowledge.uky.edu/dnp\\_etds/470](https://uknowledge.uky.edu/dnp_etds/470)
  4. MEA | Search Result. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from [https://www.mea.gov.in/search-result.htm?25096/Yoga:\\_su\\_origen,\\_historia\\_y\\_desarrollo](https://www.mea.gov.in/search-result.htm?25096/Yoga:_su_origen,_historia_y_desarrollo)
  5. Mental health of adolescents. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
  6. Progressive Muscle Relaxation (PMR) Technique for Stress & Insomnia. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from <https://www.webmd.com/sleep-disorders/muscle-relaxation-for-stress-insomnia>
  7. Relaxation techniques: Try these steps to lower stress - Mayo Clinic. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-technique/art-20045368>
  8. Why Mental Health is Important for Students — McMillen Health. (n.d.). Retrieved June 19, 2024, from <https://www.mcmillenhealth.org/tamtalks/student-mental-health>

\*\*\*\*\*

## प्राचीन भारतीय प्रतिरक्षा एवं सैन्य संगठन व युद्ध में नैतिक नियमों की उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में

डॉ. जे.के.संत\*

\* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** – रणक्षेत्र में युद्ध किस प्रकार करना चाहिए इस विषय में मनु ने व्यवस्था दी है – राजा को रणस्थल में चाहिए कि वह सेना को टोलियों अथवा जत्थों में आवश्यकता अनुसार विभाजित कर दें। इन जत्थों के अलग-अलग नायकों को नियुक्त उन्हें विभिन्न दिशाओं में स्थापित कर देना चाहिए। इन टोलियों के अलग-अलग नाम रख देना चाहिए जिससे कि उन्हें सुविधा पूर्वक संबोधित किया जा सके और युद्ध के लिए आदेश दिया जा सके। यदि सेना अल्प हो तो सेहत युद्ध करना चाहिए और यदि विशाल हो तो उन्हें फैल-फुटकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए। मनु ने व्यूह रचना करके युद्ध करना श्रेयस्कर माना है। (महाभारत में पांडव कौरव के बीच व्यूह रचना करके ही युद्ध में अभिमन्यु को मारा गया था) इसीलिए उनके निर्देश है कि समय और परिस्थिति के अनुसार सूची या वज्र व्यूह बनाकर रणस्थल में युद्ध करना चाहिए। कुशलता पूर्वक युद्ध के लिए इन व्यूहों की रचना का समर्थन महाभारत कार, कौटिल्य, कामन्दक आदि के ग्रंथों में भी किया गया है।<sup>1</sup>

युद्ध संचालन के विषय में मनु का आगे कथन है की समभूमि में रथारोहियों तथा अश्वारोहियों से पानी युक्त स्थानों पर नागारोहियों अथवा नौकारोहियों से और वृक्षों, झाड़ियों एवं कंटक वाले स्थलों में धनुर्धारियों एवं खंगचर्मधारण करने वाले सैनिकों को युद्ध में लगाना चाहिए।<sup>2</sup>

मानव धर्मशास्त्रकार ने अपने समय में कुछ ऐसे भू-भागों के नाम भी दिए हैं जहां के सैनिक विशेष कर वीर पुरुष माने जाते हैं। यह भूभाग कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शुरसेन है। मनु यह आदेश देते हैं कि इस भूभाग में उत्पन्न योद्धाओं को सेना के अग्रभाग में रखना चाहिए। इन योद्धाओं को उत्साहित करते रहना चाहिए। इनकी हर समय जांच करते रहना चाहिए और इनकी चेष्टाओं से परिस्थिति का बोध करते रहना चाहिए। इस प्रकार युद्ध संचालन के विषय में धर्मशास्त्रकारों के विचार महत्वपूर्ण हैं और जिनके व्यावहारिक रूप से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

**शत्रु को निर्बल बनाने की नीति** – शत्रु को निर्बल बनाने के लिए कर्षण एवं उत्पीड़न की नीति का आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में मनु का कथन है कि शत्रु के राष्ट्र को घेर कर, उसका उत्पीड़न करना चाहिए। शत्रु के घास, अन्न, जल और ईंधन आदि को भी नष्ट कर देना चाहिए। राष्ट्र के जलाशयों, नगर के दीवारों एवं परिखाओं को भी नष्ट कर देना चाहिए। रात्रि के समय में शत्रु राष्ट्र को विशेष रूप से त्रस्त करना चाहिए।<sup>3</sup> अन्य आचार्यों के मत का प्रतिपादन करते हुए कर्षण के प्रति कामन्दक का यह मत है कि राजा को कोष और दंड से रहित कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री का वध करवा देना

चाहिए।

**युद्ध के नैतिक नियम** – शास्त्रों में धर्म युद्ध के कतिपय नियमों का उल्लेख किया गया है। मनु युद्ध को वीरता प्रदर्शन संबंधी कृत्य मानते हैं। मनु ने छल कपट द्वारा योद्धा के वध की भर्त्सना की है। उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसमें मानव का युद्ध स्थल में वध नहीं करना चाहिए। यदि हम गंभीरता पूर्वक इन परिस्थितियों की विवेचना करें तो कुछ सिद्धांत हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं जो इस प्रकार हैं –

**(1) आयुध अथवा वहान विहीन शत्रु को मारना धर्म विरुद्ध है** – आयुध अथवा वहानों के अभाव के कारण जो व्यक्ति युद्ध करने में किसी प्रकार असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति की असमर्थता का लाभ उठाकर उसका वध कर देना धर्मयुद्ध के विरुद्ध है। इस सिद्धांत की स्थापना में मनु ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जो देखने योग्य हैं – भूमि पर स्थित (वाहन विहीन) व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। आयुध रहित अथवा टूटे हुए आयुध वाले भीत अथवा व्रणयुक्त पुरुष का रणभूमि में वध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वह पुरुष जो कवच रहित या नग्न है, उसका भी वध नहीं होना चाहिए।

**(2) अपने विपक्षी अथवा शत्रु को सचेत करके युद्ध करना चाहिए** – जो व्यक्ति असावधान अथवा युद्ध क्षेत्र में अचेत है, उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रणक्षेत्र में अचेत हो एवं दूसरे से युद्ध में संलग्न होने के कारण असावधान हो उसका वध किया जाना धर्मयुद्ध के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस सिद्धांत के समर्थन में धर्मशास्त्रकारों का आदेश है कि सोते हुए, दूसरे से युद्ध में संलग्न अथवा भूमि पर बैठे हुए पुरुष का वध नहीं करना चाहिए।

**(3) युद्ध न करने वाले का वध नहीं करना चाहिए** – इस सिद्धांत में मनु का आदेश है कि जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है केवल दर्शक है उसका वध नहीं करना चाहिए।<sup>4</sup>

**(4) पराजय स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी अवध्य होता है** – इस सिद्धांत का उल्लेख करते हुये मानव धर्मशास्त्रकारों ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने रणस्थल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और विजेता योद्धा की शरण ग्रहण कर ली है तो ऐसा व्यक्ति अवध्य है अर्थात् रणस्थल में हाथ जोड़े हुए, सिर के बाल खोले हुए, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहने वाले का वध नहीं करना चाहिए।

**(5) पुरुषत्व विहीन व्यक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए** – इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रण-स्थल में नपुंसक के वध किए जाने का निषेध

किया गया है (इसी लिए महाभारत में श्रीखंडी का वध नहीं किया गया था)।

**(6) भयाक्रान्त व्यक्ति का वध नहीं होना चाहिए-** जो व्यक्ति युद्ध नहीं करना चाहता युद्ध से डर कर अथवा घबराकर भागना चाहता है ऐसे व्यक्ति का वध नहीं किया जाना चाहिए।

**(7) निर्मम एवं क्रूर अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए-** धर्म युद्ध के अंतिम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मनु का कथन है कि शत्रु का वध ऐसे आयुधों से नहीं करना चाहिए, जिसके प्रयोग से मनुष्य को विशेष पीड़ा पहुंचती है और जिनका प्रयोग क्रूरता और नृशंसता प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसी सिद्धांत के दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने क्रूर आयुधों, कर्णों (जो वाण विधकर कठिनाई से निकाले जा सकें) विष आदि से बुझाए गए तथा प्रज्वलित अग्नि युक्त अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का सर्वथा निषेध किया है। क्योंकि ऐसे शस्त्रों के प्रयोग से वीरता का विशेष प्रदर्शन नहीं हो पता है बल्कि क्रूरता एवं नृशंसता का ही प्रदर्शन होता है। इस प्रकार शास्त्रकारों ने युद्ध में छल कपट दूंदता का आश्रय लेकर शत्रु का क्रूरता एवं नृशंसता पूर्वक वध करना उचित नहीं माना है। वीरता प्रदर्शन करते हुए नियमानुसार शत्रु का पराजय करना तथा मनु के मतानुसार धर्म युक्त है इस प्रकार धर्म युद्ध नियमों की चर्चा आवस्तबधर्मसूत्र याज्ञवल्क्य स्मृति रामायण महाभारत शुक नीति आदि ग्रन्थों में भी पाई जाती है।<sup>5</sup> गौतम ऋषि का कहना है कि जिन्होंने अश्व सारथी आयुध खो दिये हो, जिन्होंने हाथ जोड़ लिये हो, जिनके केश भागते-भागते बिखर गए हो जिन्होंने पीठ दिखा दी हो जो भूमि पर बैठ गए हो जो भाग कर वृक्ष पर चढ़ गए हो, जो दूत हो जो गाय या ब्राह्मण हो इनको छोड़कर किसी अन्य को समरांगण में मारना या घायल करना पाप नहीं है।<sup>6</sup> बौधायन धर्म सूत्र ने विषाक्त बाणों कर्णियों से मारना निसिद्ध माना है।<sup>7</sup> यही बात शांतिपर्व में भी कही गई है।

**वर्तमान संदर्भ में अनुकरणीय -** प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्रीय चिंतन का नवमूल्यांकन करते समय हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्थायें तथा उनका संगठन अत्यधिक प्रभावशाली था। प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं सेना का संगठित स्वरूप आज के संगठित संदर्भ में भी उतना ही उपयोगी है जितना पहले था। सेना के प्रकार उनके अलग-अलग चिन्ह, सेना के अधिकारियों की दक्षता, युद्ध का उचित समय, व्यूह बनाकर सेना का आगे बढ़ाना इत्यादि बातें आदि भी बहुत कुछ बातें सिखाती हैं। युद्ध के नैतिक तरीकों को ही उचित माना है। विजयी राजा का पराजित राजा के प्रति सम्मानित कर्तव्य की भावना अनुकरणीय तथ्य है। इसी आधार पर भी राम ने सुग्रीव तथा विभीषण को जीता हुआ राज्य लौटा दिया था। अपनी अधीनता में नहीं रखा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय ताशकंद समझौता के अंतर्गत भी ऐसा ही किया गया था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस समय भी विश्व प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्रियों का ऋणी है। एक बात अधिक ध्यान देने योग्य है कि युद्ध के समय राजा स्वयं युद्ध क्षेत्र में

आगे रहता था। आज भी सेनापतियों तथा शासकों को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए।

**निष्कर्ष -** उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय वांगमय में इस बात पर जोर दिया गया है कि पराजित राजा के राज्य का अपहरण नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसकी शक्ति को सीमित कर उसको अपना मित्र बना लेना ही श्रेयस्कर होता है। और इसी में विजयी और विजित दोनों राज्यों का कल्याण निहित है। इस पर विशेष प्रकाश डालते हुए आचार्य कौटिल्य ने विजयी राजा को विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विजेता राजा को अपने धर्म, प्रजा पर अनुग्रह करो कि मुक्ति, दान और प्रजा के कल्याण हेतु कार्यों द्वारा विजित प्रजा को प्रसन्न करना चाहिए।<sup>8</sup> जिस व्यक्ति ने अपने राजा के निमित्त विशेष परिश्रम किया है, उसको विशेष अधिकार एवं धन देना चाहिए। विजेता राजा को अपने नवीन राज्य की प्रजा के अनुकूल ही वेशभूषा, भाषा एवं आचरण करना चाहिए। वहां के देवता, समाज, उत्सव, विहार आदि के प्रति भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए।<sup>9</sup> ईसवी चौथी से दसवीं शताब्दी तक इस सिद्धांत का बहुत अधिक पालन किया जाता था। गुप्त राजवंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग में जो स्तंभाभिलेख है उसमें भी यही सूचित होता है, कि उस समय इस सिद्धांत का पूरा अनुसरण किया गया था। कालिदास ने भी इस प्रथा का उल्लेख किया है, इलियट और डाउसन ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं सेना का संगठित स्वरूप आज के संगठित संदर्भ में भी उतना ही उपयोगी है, जितना पहले था। हम यह कह सकते हैं कि इस समय भी विश्व प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्रियों का ऋणी है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. अर्थ0 10/6, द्रोणापर्व 75/27, 87/22-24, कर्णपर्व 11/14 व 29, कामन्दकीय, 19/40-55, अग्निपु0, 242/7-8
2. मनु 07/192
3. रेचन कोशदण्डाभ्यां महामात्य वधस्था। एतत्कर्षण मित्या छुराचार्याः पीडनमा। कामन्दकीय 08/58
4. नायुद्धमानं पश्यतं। मनु0, 7/92 उत्तरार्ध, प्रथम-द्वितीय शब्द
5. आपस्तम्ब0 2/5/10/12 महाभारत, भीष्मपर्व 1/27-32 यज्ञ 01/326
6. गौतम0, 10/17-18
7. बौधायन धर्मसूत्र, 1/10/10, अर्थ0 13/4 में भी इन नियमों का उल्लेख पाया जाता है।
8. स्वर्ध कर्मानुग्रह परिरदामान कर्मभिश्च प्रकृति प्रिय हितान्यनवर्तेत 13/5
9. तस्मात्समान शील वेषभाषा चारतामुपगच्छेत देशदैवतसमाजोत्सव विहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत। अर्थ0 13/5

\*\*\*\*\*

## 21वीं सदी का भारत और गांधीवाद

डॉ. नीरज कुमार \*

\* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - महात्मा गांधी ने आजादी से पहले जिन समस्याओं पर विचार किया था और जो समाधान सुझाया था उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और आगे भी बने रहने की पूरी संभावना है क्योंकि वे विशेषकर भारत के संबंध में गहरी समझ और नैतिकता पर आधारित रहे हैं। चाहे भारत के आर्थिक विकास और बढ़ती अमीरी के बीच संपत्ति के असंतुलित वितरण का सवाल हो या मशीनीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग से विशाल जनसंख्या के रोजगार का सवाल, अति उपभोक्तावाद की ओर बढ़ते कदम और पर्यावरण की समस्या, हिंसा का बढ़ता स्तर, विरोध के शांतिपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता और विश्व गुरु बनने तथा वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए उनके विचार नये भारत में भी प्रासंगिक रहेंगे। महात्मा गांधी के शिष्यों ने संविधान और सरकारी योजनाओं में उनके विचारों को अपेक्षा से बहुत कम स्थान दिया। वर्तमान केन्द्र सरकार जो महात्मा गांधी के विचारों का समर्थक नहीं रही है वह अपनी कई स्कीमों और योजनाओं में महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करते दिखाई देती है।

**शब्द कुंजी** - उपभोक्तावाद, जनसंख्या, रोजगार, अहिंसा, असमानता।

**प्रस्तावना** - सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन आकर पंगु हो गया था। इस देश के संसाधनों को ब्रिटेन के लिए लुटा खसोटा गया। जहां तक संभव हुआ भारत और उसके लोगों को चुसा गया, इसके धन-संपत्ति को सोख लिया गया। जब भारत आजाद हुआ उस समय यहां औद्योगिक विकास लगभग नग्न था। 1947 में भारत की साक्षरता 18 प्रतिशत थी। गरीबी का साम्राज्य था। तकनीक, आधारभूत ढांचा और अर्थव्यवस्था का नये सिरे से निर्माण करना था। 15 अगस्त 1947 को संविधानसभा में दिए प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल ने कहा था, 'मध्यरात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोष में सो रही है, हिन्दुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आंख खोल रहा है।'<sup>1</sup>

उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की खर्चीली शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाकर और भारतीय लोकतंत्र की समाप्ति एवं तानाशाही शासन की स्थापना की समस्त नकारात्मक भविष्यवाणियों को धता बताकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है जिसपर हर भारतीय को गर्व है इसलिए भी कि भारत में दुनिया के प्राचीनतम लोकतंत्र विद्यमान रहे थे। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताओं के अनुसार भारत प्रगति करता रहा भले गति अपेक्षाकृत धीमी रही। भारत आर्थिक सुधार और उदारीकरण 1991 में किया। इसके साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को दुनियाभर के निवेशकों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए खोला तो कुछ धीमी चाल के बाद रफतार पकड़ ली है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में संकुचन के बाद भरपाई करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत की छलांग लगाई थी। सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम विकास दर 2010 में 8.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी।<sup>2</sup> साल 2014 से 2023 के बीच भारत के जीडीपी में कुल 83 फीसद की बढ़त दर्ज की गई है। नौ सालों की वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से सिर्फ एक फीसदी नीचे रहा है क्योंकि चीन की

जीडीपी में 84 फीसद की बढ़त दर्ज की गई है।<sup>3</sup> इसी दौरान भारत ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्राजील की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लाइव मिंट के मुताबित, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पिछले साल अक्टूबर में अनुमान लगाया है कि भारत साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ के साथ ही वैश्विक वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी पिछले साल अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।<sup>4</sup> अगर भारतीय जीडीपी मौजूदा औसत छह-सात फीसद की दर से भी आगे बढ़ती रहती है तो भी वह साल 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इन देशों के लिए छह-सात प्रतिशत बढ़ोतरी तकरीबन असंभव ही है, क्योंकि जर्मनी और जापान की विकास दर क्रमशः ढाई और डेढ़ प्रतिशत ही है।<sup>5</sup>

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विजुअल कैपिटलिस्ट के अक्टूबर 2022 के जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया के दस अमीर देशों की सूची इस तरह बनेगी :-

10. इटली, 1.99 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
9. रूस, 2.113 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
8. कनाडा, 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
7. फ्रांस, 2.778 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
6. ब्रिटेन, 3.199 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
5. भारत, 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
4. जर्मनी, 4.031 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
3. जापान, 4.301 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
2. चीन, 18.321 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

1. अमेरिका, 25.035 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर<sup>9</sup>

1990 में चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5.46 गुणा बड़ी है।<sup>7</sup> चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में अपने यहां आर्थिक सुधार शुरू किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है।<sup>8</sup> आज भारत दुनिया के कुल जीडीपी के चार फीसद का हिस्सेदार है। 2017 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी।<sup>9</sup> अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में, भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निवेश बैंक ने लिखा है कि नवाचार, प्रौद्योगिकी, उच्च पूंजी निवेश और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की मदद करेगी।<sup>10</sup> अर्थशास्त्र में 2001 के नोबल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस का मानना है कि भारत का वक्त आ चुका है। प्रोफेसर माइकल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीन हैं, उन्होंने बीबीसी से कहा, 'भारत जल्द ही चीन की बराबरी कर लेगा। चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ेगी लेकिन भारत की नहीं।'<sup>11</sup>

भारत या किसी भी देश को किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए आर्थिक प्रगति आवश्यक है। सौभाग्य से नये भारत में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। भारत उभर रहा है। आज भारत न केवल अर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता और प्रगति की ओर अग्रसर है। ग्लोबल फायरपावर की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। चन्द्रयान, मंगलयान, शुक्रयान की इसरो की परियोजनाओं के माध्यम से भारत अंतरिक्ष विज्ञान और व्यावसाय में स्थान बना रहा है। जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोविड 19 संकट में भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराकर दुनिया में संकट के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्लोबल साउथ के देशों में भारत की छवी अच्छी बनी है। भारत के तकनीकी, शैक्षणिक और आर्थिक विकास से ये देश प्रेरणा ले रहे हैं। भारत इन देशों का नेता बनकर उभरा है। भारत को पश्चिमी देशों में भी महत्व दिया जा रहा है।

भारत में मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी को उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है। जिसपर दुनिया भर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक देशों की नजर है। बड़ी संख्या में कामगार वर्ग की उपलब्धता, अंग्रेजी जानने वाले तकनीशियनों आदि के कारण भारत दुनिया का बैंक ऑफिस बना हुआ है और मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। इंटरनेट के क्षेत्र में भी भारत आगे की ओर है। भारत का सावटवेयर के क्षेत्र में अग्रणी स्थान है।

इस प्रगतिशील नये भारत में राष्ट्रपिता, महान विचारक, नेता और कर्मयोगी महात्मा गांधी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान महान भारत के सपने देखे थे। भारत की कई चुनौतियों और समस्याओं पर विचार किया था। उन समस्याओं से नया भारत भी जुड़ रहा है। एक सशक्त, उन्नत, खुशहाल और महान राष्ट्र बनना है तो भारत को उन चुनौतियों से पार पाना होगा।

प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में एप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अमेरिका

के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम किया है। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए वो कहते हैं, 'भारत समस्याओं से दबा हुआ है। इंग्लैंड में भारतीय मूल के राणा मित्तर् ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक चीन के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर हैं और चीन पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने बीबीसी हिंदी को एक ईमेल इंटरव्यू में बताया कि भारत को अपने युवाओं को अधिक कुशल बनाने और शिक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'भारत की जनसंख्या युवा है, लेकिन चीन अभी भी शोध और विकास पर अधिक खर्च करता है, इसलिए भारत को अपनी जनसंख्यिकी से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर अधिक निवेश करना होगा।'<sup>12</sup>

आर्थिक असमानता का व्यापक दायरा है। जिससे देश की एक बड़ी आबादी बहुत की कम आय पर विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी तो भी इसमें ज्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है। आलोक पुराणिक मानते हैं, 'जहां एक ओर भारत दुनिया की तीसरी शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। वहीं, इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी जिसका लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन इससे आम लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक समृद्धि में नाटकीय बदलाव होने की संभावना कम है।'<sup>13</sup> 2023 में ऑक्सफैम ने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी' में बताया है कि भारत के सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है। देश की आधी यानी 50 प्रतिशत आबादी के पास इंडिया की कुल संपत्ति का सिर्फ 3 प्रतिशत है। इसके अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 के 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर (54.12 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंच गई है। यह एक ऐसी राशि है जो 18 महिने से ज्यादा के पूरे केन्द्रीय बजट को फंड दे सकती है।<sup>14</sup>

जब यह देश 1950 में लोकतांत्रिक घोषित हुआ तो देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद स्थापित करने की घोषणा की गई थी। क्या कारण है कि यह लक्ष्य आज भी धुवतारे की तरह कहीं दूर ठिठका हुआ लगता है। अरबपति खरबपति हो गए हैं और निर्धन और निर्धन हो हाने की राह पर चल दिए।<sup>15</sup>

प्रति व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2.6 हजार अमेरिकी डॉलर है तो अमेरिका में ये आंकड़ा 80 हजार डॉलर से ज्यादा है। 16 भारत में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 2.6 हजार डॉलर है लेकिन इसमें अरबपतियों की आय भी सम्मिलित है। यहां एक ओर दुनिया के सबसे सुविधाभोगी लोग हैं तो दूसरी ओर घोर अभाव में कठिनतम स्थिति में किसी तरह जीवन यापन करते लोग भी हैं।

महात्मा गांधी उद्योगवाद को विशेषकर भारत के लिए पसंद नहीं करते थे जिसकी ओर भारत बढ़ रहा है तथा इसमें अभी बहुत प्रयास करके उंचाईयां छूने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नये भारत में महात्मा गांधी के इस बात को स्वीकार करते हुए उद्योगवाद से दूर जा पाना मुश्किल है यही आज की वास्तविकता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी हर तरह के मशीन के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के परिश्रम की बचत मशीन का लक्ष्य होना चाहिए और प्रामाणिक मानव-कल्याण का विचार, न कि लोभ, उसका हेतु होना चाहिए।



लोभ के स्थान पर प्रेम को बिठा दीजिए, फिर सब ठीक हो जायगा। व्यक्ति के परिश्रम की बचत मशीन का लक्ष्य होना चाहिए और प्रामाणिक मानव-कल्याण का विचार, न कि लोभ, उसका हेतु होना चाहिए। लोभ के स्थान पर प्रेम को बिठा दीजिए, फिर सब ठीक हो जायगा। 17 वे सिंगर की सिलाई की मशीन का स्वागत करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा विरोध यंत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यंत्रों के पीछे जो पागलपन चल रहा है, उसके लिए है। 18 वे आगे कहते हैं कि उनसे मेहनत जरूर बचती है, लेकिन लाखों लोग बेकार होकर भूखों मरते हुए रास्तों पर भटकते हैं। समय और श्रम की बचत तो मैं भी चाहता हूँ, परंतु वह किसी खास वर्ग की नहीं, बल्कि सारी मानव-जाति की होनी चाहिए। कुछ गिने-गिनाये लोगों के पास संपत्ति जमा हो ऐसा नहीं, बल्कि सबके पास जमा हो ऐसा मैं चाहता हूँ। आज तो करोड़ों की गरदन पर कुछ लोगों के सवार हो जाने में यंत्र मदगार हो रहे हैं।<sup>19</sup> उनका कहना था कि सबसे पहले वैज्ञानिक सत्यों और आविष्कारों को निरे लोभ के साधन नहीं रहना चाहिये।<sup>20</sup>

महात्मा गांधी भले ग्रामीण और श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था के पक्षधर रहे हैं लेकिन नया भारत उद्योगवादी, शहरी और बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ही बढ़ रहा है। महात्मा गांधी के विचार इसके माध्यम से फैल रही आर्थिक असमानता को कम करने और सर्व कल्याण के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप जो असमानता और शोषण की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे निपटने के लिए साम्यवादी क्रांति के विकल्प के रूप में गरीबों-वंचितों के लिए और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के विचार महत्व रखते हैं। पूंजीपतियों में जो स्वार्थपरता है उससे उन्हें उपर उठाना चाहते हैं और उनको सबके कल्याण के लिए कार्य करने वाले योग्य साधन के रूप में बदल देना चाहते हैं। उद्योगपतियों को संपत्ति का न्यासी बना देना चाहते हैं।

वे मानते थे कि यदि वे उपकार की भावना रखकर अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो राज्य का ही काम करेंगे। ऐसे लोग संरक्षक बनकर रहते हैं, और किसी भी रूप में नहीं। मैं बुद्धिशाली आदमी को अधिक कमाने दूंगा, उसकी बुद्धि को कुंठित नहीं करूंगा। परंतु उसकी अधिकांश कमाई राज्य की भलाई के लिए वैसे ही काम आनी चाहिए, जैसे कि बाप कि सारे कमाऊ बेटों की आमदनी परिवार के कोष में जमा होती है। वे अपनी कमाई के संरक्षक बनकर ही रहेंगे।<sup>21</sup> महात्मा गांधी कहते हैं, यदि समाज का हर एक सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए करे, तो क्या इससे समाज की सुख-समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी? हम ऐसी जड़ समानता का निर्माण नहीं करना चाहते, जिसमें कोई आदमी अपनी योग्यताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर ही न सके। ऐसा समाज अन्त में नष्ट हुए बिना नहीं कर सकता। इसलिए मेरी यह सलाह बिलकुल सही है कि धनवान लोग चाहे करोड़ों रुपये कमायें (बेशक ईमानदारी से ही), लेकिन उनका उद्देश्य सारा पैसा सबके कल्याण में समर्पित कर देने का होना चाहिए।<sup>22</sup>

यही निहितार्थ लिए हुए जॉन रॉल्स अपने प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत में बताते हैं कि समाज के योग्य और संपत्तिशाली लोगों की कमाई में समाज के सबसे कमजोर को अवसर की समानता को बढ़ाने के लिए लाभ मिलना चाहिए। वे समाज को एक जंजीर की तरह देखते हैं और कहते हैं कि यह समाज उतना ही मजबूत माना जाएगा जितना की उस जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी। इसलिए समाज को मजबूत बनाने के लिए ऐसी कमजोर कड़ी

को खोजकर सबसे पहले मजबूत किया जाना चाहिए।

ऐसे ही विचार 2023 में ऑक्सफैम ने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान अपनी वार्षिक असमनता रिपोर्ट 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी' में व्यक्त किये गये हैं कि भारत के 10 सबसे अमीरों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाने से 1.37 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। यह 2020-2023 के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री (86,200 करोड़ रुपये) और आयुष मंत्रालय (3050 करोड़ रुपये) के अनुमानित फंड्स से 1.5 गुना ज्यादा है। इतने पैसों से देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। ऑक्सफैम ने कहा, 'अगर भारत के बिलियनेयर्स पर उनकी टोटल वेल्थ पर 2 प्रतिशत की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए, तो इससे देश में अगले तीन साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपये की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।'<sup>23</sup>

संपत्ति का व्यापक असमान वितरण न केवल सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है बल्कि सत्ता पर संपत्तिशाली का अनुचित प्रभाव भी स्थापित कर देता है। इस बुराई से भी महात्मा गांधी वाकिफ थे। आज भारत में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। सत्ता पर भारत के उद्योगपतियों के प्रभाव के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। भारत की अधिकांश मीडिया संस्थान पूंजीपतियों के स्वामित्व में हैं। महात्मा गांधी का विचार था कि जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच भारी अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।<sup>24</sup> उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी-खुशी से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर बरतने को तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे देश में हिंसक और खूंखार क्रांति हुए बिना न रहेगी।<sup>25</sup>

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए सपना देखा था कि आजाद हिन्दुस्तान में देश के बड़े से बड़े धनवानों के हाथ में हुकूमत का जितना हिस्सा रहेगा, उतना ही गरीबों के हाथ में भी होगा; और तब नई दिल्ली के महलों और उनकी बगल में बसी हुई गरीब मजदूर बस्तियों के टूटे-फूटे झोंपड़ों के बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है, वह एक दिन को भी नहीं टिकेगा।<sup>26</sup>

क्या नये भारत में भी गरीबों पिछड़ों की हितों की रक्षा के लिए महात्मा गांधी के उपर्युक्त विचार की प्रासंगिकता नहीं रहेगी? अवश्य रहेगी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में राज्य द्वारा अनुकरणीय नीति तत्व में कहा गया है कि (ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; और (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।<sup>27</sup> इस लक्ष्य को प्राप्त करना सरकारों का दायित्व है। जिसे प्राप्त करने में महात्मा गांधी के विचार सहायता करते हैं।

महात्मा गांधी कहते हैं, 'भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में केवल एक ही बार खाकर संतोष कर लेना पड़ता है; और उनके उस भोजन में भी सूखी रोटी और चुटकीभर नमक के सिवा और कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हमारा और आपका तब तक कोई अधिकार नहीं है जब

तक इन लोगों के पास पहनने के लिए पूरा कपड़ा और खाने के लिए पूरा अन्न नहीं हो जाता।<sup>28</sup> नये भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से इससे पार पाया जा सका है। समृद्धि का विस्तार हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने आर्थिक समानता के लिए कार्य करने का अर्थ बताया था कि एक ओर से जिन मुट्ठीभर पैसे वाले लोगों के हाथ में राष्ट्र की संपत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी संपत्ति को कम करना; और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी संपत्ति में वृद्धि करना।<sup>29</sup> आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। भारत के पास विश्व भूमि का 2.4 फीसदी है लेकिन यहां विश्व की 18 फीसदी आबादी बसती है। भारत के लिए इतनी आबादी को सुविधाएं उपलब्ध कराना एक चुनौती है तो अवसर भी है। भारत के पास युवा आबादी की बड़ी संख्या है। ऐसा किसी अन्य देश के पास नहीं है। इन्हें कुशल बनाकर अवसर के रूप में बदला जा सकता है।

ब्लूमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के हवाले से बताया कि भारत की जनसंख्या 1.428 142.86 करोड़ से अधिक है। जबकि, चीन की आबादी 1.425 अरब 142.57 करोड़ है।<sup>30</sup> यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में हैं। इसके अलावा 7 प्रतिशत 65 से ऊपर के आयु वर्ग में हैं। विभिन्न एजेंसियों के अनुमान से पता चला है कि भारत की जनसंख्या लगभग तीन दशकों तक बढ़ती रहने वाली है।<sup>31</sup> भारत चाहता है कि युवा शक्ति का लाभ उठाकर अर्थव्यवस्था को उंचाई पर ले जाया जाये। माना जाता रहा है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण अवसरों को बढ़ाते हैं और रोजगार में वृद्धि करते हैं लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन पर आधारित यह विश्लेषण काबिल-ए-गौर है कि 1999-2000 में अगर जीडीपी 1 प्रतिशत बढ़ती थी तो रोजगार में 0.39 प्रतिशत का इजाफा होता था। 2014-15 तक आते-आते स्थिति यह हो गयी कि 1 प्रतिशत जीडीपी बढ़ने से सिर्फ 0.15 प्रतिशत रोजगार बढ़ता है। मतलब जीडीपी बढ़ने, पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ने से अब लोगों को रोजगार नहीं मिलता। इसलिए जब कॉरपोरेट मीडिया अर्थव्यवस्था में तेजी-खुशहाली बताए तो भी उससे आम लोगों को खुश होने की कोई वजह नहीं बनती।<sup>32</sup> आज चांद पर जाने की जितनी चिंता है, धरती पर रोजगार को लेकर नहीं। गांधी विज्ञान के विरोधी न थे, लेकिन उन्हें 'इकोनॉमी' को लेकर ज्यादा चिंता थी। वे देश के बेरोजगारों को लेकर चिंतित थे, जो 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। वस्तुतः आज सिर्फ आर्थिक वृद्धि देखी जाती है, रोजगार घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता।<sup>33</sup>

हालांकि वर्तमान में फिर से दुनियाभर में अर्थव्यवस्था के खूलेपन के स्थान पर संरक्षतावाद दिखाई देने लगा है। आत्मनिर्भरता की बात भी की जाने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की नीति पर चल रहे हैं। यह महात्मा गांधी के स्वदेशी की भावना को ही अभिव्यक्त करता है। महात्मा गांधी के अनुसार, 'स्वदेशी की भावना का अर्थ है हमारी वह भावना, जो हमें दूर को छोड़कर अपने समीपवर्ती प्रदेश का ही उपयोग और सेवा करना सिखाती है।' अर्थ के क्षेत्र में मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और उन उद्योगों की कमियाँ दूर करके, उन्हें ज्यादा सम्पूर्ण और सक्षम बनाकर

उनकी सेवा करना चाहिए।<sup>34</sup> महात्मा गांधी का मानना था कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में हमने स्वदेशी के नियम को भंग किया है। इसीलिए जनता की अधिकांश गरीबी का कारण विदेशों पर निर्भरता है।<sup>35</sup>

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी चिंता भारत की विशाल आबादी को काम उपलब्ध कराने की थी मशीनीकरण और उद्योगवाद का विरोध संपत्ति के संकेन्द्रण के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ने की चिन्ता भी थी। नया भारत में मशीनीकरण और औद्योगिकरण जोर शोर से हो रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ऐसे में पकौड़े तलने जैसे रोजगार भी सुझाए जा रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्व-रोजगार, कुटीर उद्योग को सरकार द्वारा मुद्रा योजना और कई योजनाओं के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का प्रयास हो रहा है। महात्मा गांधी का कहना था कि देश के हर नागरिक को पूरा काम देने वाली अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए हमें उद्योगवाद का, केन्द्रित उद्योग-धंधों का और अनावश्यक यंत्रों का त्याग करना होगा।<sup>36</sup> भारत सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इसके साथ लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर भी पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। कोशिश यह है कि भारत अब आयात आधारित अर्थव्यवस्था से निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बने।<sup>37</sup> महात्मा गांधी को डर था कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए बेरोजगारी की समस्या को मशीन से बढ़ावा मिल सकता है। उन्हें यह भी डर था कि ऐसे यंत्र नहीं होने चाहिए जो काम न करने के कारण आदमी के अंगों को जड़ और बेकार बना दें।<sup>38</sup> उन्होंने कहा है कि यंत्रों से काम लेना उसी अवस्था में अच्छा होता है, जब कि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हों या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तान में तो है नहीं। यहां काम के लिए जितने आदमी चाहिए, उनसे कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं।<sup>39</sup>

निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के साथ ही साथ घरेलू उपभोक्ताओं के मांग में भी वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो और लोगों का जीवन स्तर उंचा उठे। वर्तमान समय में उच्च जीवन स्तर मापने का तरीका उच्च उपभोग का स्तर है। ऐसे अर्थशास्त्र से उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है। उपभोक्तावाद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ऐसे में अनियंत्रित उपभोग को बढ़ावा देने के स्थान पर नियंत्रित रूप में अभावों में जीवन यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाने की जरूरत है। यदि जीवन स्तर के मामले में लोगों का आदर्श अमेरिका की जीवन शैली होगी तो पर्यावरण का विनाश और बढ़ जाएगा। एक आकलन के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या तो विश्व की कुल जनसंख्या की मात्र 4.42 प्रतिशत है लेकिन वह विश्व के संसाधनों का करीब 28.97 प्रतिशत का उपभोग करती है।<sup>40</sup> वैश्विक आबादी को भौतिक संसाधन मुहैया कराने और सम्पन्नता के इस सार्वभौम जीवन-स्तर तक उठाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक ग्रहों की जरूरत पड़ेगी।<sup>41</sup>

महात्मा गांधी के जीवन काल में पर्यावरण प्रदूषण बड़ा मसला नहीं था फिर भी उनके विचार भविष्य की समस्याओं के लिए भी प्रासंगिक रहे हैं। जैसा कि उनका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्धरण कि 'पृथ्वी पर सभी की जरूरतों के लिए काफी संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन सभी के लालच के लिए जगह नहीं है,'<sup>42</sup> उनके विचार उपभोग को संतुलित बनाने में हमारी सहायता करती है। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों की जीवन शैली के मान्य सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार को अपनाते पर जोर दिया है। उन्होंने कहा था कि

यदि सादा जीवन जीने योग्य है तो यह प्रयत्न भी करने योग्य है, चाहे वह प्रयत्न किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही समुदाय द्वारा क्यों न किया जाये।<sup>43</sup> इस तरह आज मानव जीवन पर सबसे बड़े संकट के रूप में प्रकट पर्यावरण संकट की समस्या के प्रति महात्मा गांधी के विचार संवेदनशील बनाता है जिसकी नये भारत में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती रहेगी।

नये भारत में हिंसा पर नियंत्रण भी पाना होगा। मणिपुर में कुकी और मैतेई विवाद से उत्पन्न हिंसा हो या नूह (मेवात) की हिंसा या नक्सली हिंसा, जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य स्थानों पर नागरिकों द्वारा की गई हिंसा देश को परेशानी में डालता है और जान-माल का नुकसान करता है। जबकि शांतिपूर्ण साधनों से विरोध दर्ज किया जा सकता है या अपनी मांगे मनवाई जा सकती है। नये भारत में ऐसे हिंसा का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। अहिंसा के पूजारी के रूप में प्रसिद्ध महात्मा गांधी यहां महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। जहां अहिंसक साधनों का प्रयोग किया भी जाता है तो भी उसमें बहुत सी खामियां होती हैं वहां भी महात्मा गांधी के विचार सहायता कर सकते हैं। उनका सत्याग्रह का अस्त्र हमें सहायता प्रदान कर सकता है। महात्मा गांधी साध्य और साधन की एकता में विश्वास करते थे। अहिंसा को सत्य तक पहुंचने का साधन मानते हैं। उनका विचार था कि गलत साधन से सही साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए विरोध जताने के एक समुचित अहिंसात्मक साधन के रूप में सत्याग्रह का आविष्कार किया। वे सत्याग्रह के संबंध में बताते थे कि सत्याग्रही का अन्यायी को परेशान करने का इरादा कभी नहीं होता। वह उसे डराना भी नहीं चाहता; हमेशा उसके हृदय से अपील करता है। यही होना भी चाहिये। सत्याग्रही का उद्देश्य अन्याय करने वाले को दबाना नहीं, बल्कि उसका हृदय-परिवर्तन करना होता है।<sup>44</sup> महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम खुद को अपने शत्रु की स्थिति में रखकर उसके दृष्टिकोण को समझें, तो संसार के तीन-चौथाई दुःख-दर्द और गलतफहमियां मिट जायें। तब या तो हम अपने शत्रु के साथ जल्दी सहमत हो जायेंगे या उसके बारे में उदारतापूर्वक विचार करेंगे।<sup>45</sup> वे मानते हैं कि सत्याग्रह में जबरदस्ती का लवलेश भी नहीं होना चाहिये। हमें अधीर नहीं बनना चाहिये; और हम जिन साधनों को अपना रहे हैं, उनमें हमारी अटल श्रद्धा होनी चाहिये।<sup>46</sup>

भारत अतीत का अपना समुचित स्थान पाना चाहता है। भारत की भूमि अध्यात्म की भूमि रही है। भारत ने दुनिया को योग दिया है, अहिंसा, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के विचार दिये हैं। महात्मा गांधी इन सबमें विश्वास रखते थे। सर्वधर्म समभाव के संबंध में उनका कहना था कि सब धर्म एक ही स्थान पर पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं। अगर हम एक ही लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तो अलग-अलग रास्ते अपनाने में क्या हर्ज है? वास्तव में जितने मनुष्य हैं उतने धर्म हैं।<sup>47</sup> धर्मों की आत्मा एक है, परंतु वह अनेक रूपों में प्रकट हुई है।<sup>48</sup> महात्मा गांधी मानते हैं कि कम या अधिक संसार के सभी बड़े बड़े धर्म सच्चे हैं।<sup>49</sup> सभी धर्म समान और आदरणीय हैं। अहिंसा हमें सिखाती है कि हम दूसरों के धर्मों का वैसा ही आदर करें जैसा हम अपने धर्म का करते हैं।<sup>50</sup>

महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रिका से भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह के अनुसार पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत की खूबियों और खामियों को जाना समझा। उनके विचारों में वह गहराई दिखती है। गरीबी, असमानता, विशाल आबादी, कृषक समाज की आवश्यकता, उद्योगवाद, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर भारत के संबंध

में व्यावहारिक विचार रखें जिनका आज भी महत्व बरकरार है। उनको भारतीय धर्म, संस्कृति, मूल्यों और मान्यताओं की गहरी समझ थी। इन्हीं में उन्होंने अपना जीवन निर्देशक सिद्धांत सत्य और अहिंसा को अपना कर उसी के अनुसार भारत को गढ़ने का सपना देखा था। उनके विचार को आदर्शवादी नहीं हैं। व्यवहारिकता पर आधारित हैं इसलिए दुनिया भर में इन विचारों से सीखा जा रहा है। नये भारत में भी उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त किया जा रहा है। महात्मा गांधी के विचारों को अपनाकर ही भारत दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और शांति के उदान्त आदर्शों का विस्तार किया जा सकता है और भारत इसी से विश्व गुरु की भूमिका को चरितार्थ कर पाएगा। अतः आज के भारत में महात्मा गांधी के विचारों की भूमिका अभूतपूर्व है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचन्द्र, गुहा, 2012, *भारत नेहरू के बाद*, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, गुडगांव, पृष्ठ 7
2. अनंत प्रकाश, मोदी सरकार में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कितनी बदलेगी आम लोगों की जिंदगी, 28 जुलाई 2023, <http://www.bbc.com/hindi> देखा गया 7 अगस्त, 2023
3. वही
4. वही
5. वही
6. दुनिया के 10 सबसे अमीर देश कौन हैं और भारत किस पायदान पर है, 17 जनवरी 2023, <http://www.bbc.com/hindi> देखा गया 7 अगस्त, 2023
7. जुबैर अहमद, भारत क्या चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पीछे छोड़ देगा? विशेषज्ञों का जवाब, 15 अक्टूबर 2022, <http://www.bbc.com/hindi> देखा गया 10 अगस्त, 2023
8. वही
9. सुरेश सेठ, आर्थिक छलांग की असली सूरत, देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा लेकिन क्या होगा आम आदमी पर असर, 7 अगस्त, 2023, <http://www.jansatta.com> देखा गया 7 अगस्त, 2023
10. कुमार विवेक, गोल्डमैन सैक्स : 2075 तक अर्थव्यवस्था में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत, जाने कौन होंगे टॉप-3 देश, 11 जुलाई 2023, <http://www.amarujala.com> देखा गया 7 अगस्त 2023
11. अनंत प्रकाश, पूर्वोक्त
12. जुबैर अहमद, पूर्वोक्त
13. अनंत प्रकाश, पूर्वोक्त
14. ऑक्सफैम की रिपोर्ट : 1 प्रतिशत अमीरों के पास देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति, 50 प्रतिशत आबादी के पास सिर्फ 3 प्रतिशत संपत्ति, 17 जनवरी 2023, <http://www.bhaskar.com> देखा गया 10 अगस्त 2023
15. सुरेश सेठ, पूर्वोक्त
16. अनंत प्रकाश, पूर्वोक्त
17. गांधीजी, 1955, *सर्वोदय*, भारतन् कुमारप्पा (संपादित), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 49
18. गांधीजी, 1949, *हिन्द स्वराज्य*, अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी (हिन्दी अनुवाद), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 7

19. वही
20. गांधीजी, *सर्वोदय*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 48
21. गांधीजी, 1959, *मेरा समाजवाद*, आर.के.प्रभु (संग्राहक), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 27
22. वही, पृष्ठ 25
23. ऑक्सफैम की रिपोर्ट, पूर्वोक्त
24. गांधीजी, 1951, *रचनात्मक कार्यक्रम : उसका रहस्य और स्थान*, तृतीय परिवर्धित आवृत्ति, काशिनाथ त्रिवेदी (हिन्दी अनुवाद), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 40
25. वही
26. गांधीजी, *मेरा समाजवाद*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 28
27. *भारत का संविधान*, 2021, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भारत सरकार, पृष्ठ 21
28. गांधीजी, *मेरा समाजवाद*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 24
29. वही, पृष्ठ 27
30. रिजवान नूर खान, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना-चीन को पीछे छोड़ा, यूएस तीसरे नंबर पर, 19 अप्रैल 2023, <http://www.hindieconomicstimes.com> देखा गया 10 अगस्त 2023
31. वही
32. आलोक टंडन, जनवरी-जून 2016, *नेहरू और अम्बेडकर : भारतीय आधुनिकता के दो चेहरे*, अभय कुमार दुबे (संपादित), *प्रतिमान : समय समाज संस्कृति*, वर्ष 4, अंक 7, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 18-19
33. शंभुनाथ, अक्टूबर 2019, *गांधी के प्रयोग : सत्य और उत्तर-सत्य*, शंभुनाथ (संपादित), *वागर्थ*, भारतीय भाषा परिषद की मासिक पत्रिका, वर्ष 25, अंक 291, पृष्ठ 7
34. गांधीजी, 1960, *मेरे सपनों का भारत*, आर.के.प्रभु (संग्राहक), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 127
35. वही, पृष्ठ 130
36. गांधीजी, 1963, *ग्राम स्वराज्य*, हरिप्रसाद व्यास (संग्राहक), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ
37. सुरेश सेठ, पूर्वोक्त
38. गांधीजी, *हिन्द स्वराज्य*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 15
39. गांधीजी, *मेरे सपनों का भारत*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 108
40. विपुल सिंह, 2015, *पर्यावरण पर मानव पदचिन्ह : पर्यावरण परिवर्तन के ऐतिहासिक संदर्भ*, ट्रिनिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ 146
41. कमल नयन काबरा, जनवरी-जून 2016, *विकास का नया विमर्ष बनाम उपभोक्तावाद*, अभय कुमार दुबे (संपादित), *प्रतिमान : समय समाज संस्कृति*, वर्ष 4, अंक 7, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 153
42. विपुल सिंह, पूर्वोक्त, पृष्ठ 77
43. गांधीजी, *ग्राम स्वराज्य*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 15
44. गांधीजी, *सर्वोदय*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 94
45. वही, पृष्ठ 95
46. वही
47. गांधीजी, 1957, *सत्य ही ईश्वर है*, आर.के.प्रभु (संपादित), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ 58
48. वही, पृष्ठ 57
49. वही
50. गांधीजी, *सर्वोदय*, पूर्वोक्त, पृष्ठ 28

\*\*\*\*\*

# English for a Specific Purpose: Essay Writing for Undergraduate Students in North India

Dr. Omprakash Upadhyay\*

\*Assistant Professor (English) Kamla PG College, Dholpur (Raj.) INDIA

**Abstract :** English for a Specific Purpose (ESP) focuses on tailoring language instruction to meet the academic or professional needs of learners. In North India, undergraduate students often face challenges in essay writing due to linguistic and structural differences between English and their native languages. This research paper explores the importance of ESP in enhancing essay writing skills among North Indian students, analyzing the challenges they face and providing pedagogical strategies to improve their proficiency.

**Introduction** - English has become an essential tool for academic and professional success worldwide. In North India, where English is widely used in higher education, undergraduate students often struggle with essay writing due to linguistic interference, limited exposure to English, and inadequate training in academic writing conventions. English for a Specific Purpose (ESP) offers a focused approach to address these challenges by customizing language instruction to meet students' academic needs.

This paper aims to analyze the essay writing difficulties faced by North Indian undergraduate students and propose effective strategies within the ESP framework to enhance their writing proficiency.

## Challenges Faced by North Indian Undergraduate Students in Essay Writing

**Linguistic Interference:** The influence of native languages such as Hindi, Punjabi, and Bengali often leads to grammatical errors and awkward sentence structures in English essays.

**Limited Vocabulary and Expression:** Many students struggle with academic vocabulary and fail to express complex ideas clearly.

**Lack of Understanding of Essay Structure:** Students often struggle with thesis statements, coherence, cohesion, and logical argumentation.

**Grammar and Syntax Issues:** Common errors include subject-verb agreement, incorrect tense usage, and misplaced modifiers.

**Inadequate Exposure to Academic Writing:** The lack of academic writing training in schools and universities leaves students unprepared for university-level essays.

## ESP-Based Strategies to Improve Essay Writing Skills

**Needs Analysis:** Identifying specific linguistic and

academic needs of students can help tailor the instruction accordingly.

**Explicit Teaching of Essay Structure:** Introducing students to thesis statements, topic sentences, supporting details, and conclusion strategies.

**Lexical Development:** Incorporating vocabulary-building exercises to enhance students' academic language proficiency.

**Grammar-Focused Activities:** Implementing targeted grammar instruction to address common errors.

**Process-Based Writing Approach:** Encouraging brainstorming, outlining, drafting, peer review, and revision to improve writing quality.

**Use of Technology:** Digital tools such as Grammarly, Turnitin, and online writing labs can provide feedback and help students refine their writing skills.

**Interactive Learning Methods:** Group discussions, peer evaluations, and workshops can make the learning process more engaging and effective.

**Case Study:** Implementation of ESP Strategies in a North Indian University

A study was conducted in a North Indian university where ESP-based essay writing instruction was introduced to undergraduate students. The intervention included structured lessons on essay writing, vocabulary enhancement, and grammar exercises. Pre- and post-intervention assessments showed significant improvement in students' writing clarity, coherence, and grammatical accuracy.

**Conclusion:** ESP-based instruction plays a crucial role in enhancing essay writing skills among North Indian undergraduate students. By addressing linguistic challenges and incorporating structured writing strategies, students can

develop their academic writing proficiency. Future research can explore the long-term impact of ESP interventions and the role of digital tools in further improving essay writing skills.

**References:-**

1. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Palgrave Macmillan.
2. Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach. Cambridge University Press.
3. Hyland, K. (2006). English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book. Routledge.
4. Jordan, R. R. (1997). English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge University Press.
5. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. University of Michigan Press.

\*\*\*\*\*

## सोनभद्र जिले में मनरेगा का क्रियान्वयन : एक सामाजिक अंकेक्षण

डॉ. गुंजन श्रीवास्तव\*

\* सहायक प्रवक्ता (समाज शास्त्र) दि महाराजा सैय्याजी राव विश्वविद्यालय, वड़ोदरा (गुजरात) भारत

**प्रस्तावना** – सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं में वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। प्रथम चरण में यह सुविधा 200 जिलों में उपलब्ध करायी गई थी। अगले 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 600 जिलों में इसे लागू करना था। वर्ष 2007-08 में इस कानून का विस्तार 330 अतिरिक्त जिलों में किया गया, जबकि बाकी जिलों को इसमें शामिल करने की अधिसूचना 01 अप्रैल 2008 को जारी की गई।

भारत सरकार द्वारा नरेगा उत्तर प्रदेश राज्य में 2 फरवरी 2006 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्रदान करने की गारंटी के रूप में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में मनरेगा श्रमिकों की औसत मजदूरी 289/- रुपये प्रतिदिन हो गई है। तदुपरान्त शीघ्र ही यह योजना राज्य के 22 जिलों में 5 वर्ष के लिए शुरू की गई, ये जिले आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशांबी, खेरी, कुशी नगर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, सोनभद्र हैं।

**सोनभद्र जिले का भौगोलिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक विवरण** : भारत देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 16.61 करोड़ तथा क्षेत्रफल 241 हजार वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल 70 जिलों में सोनभद्र मात्र एक ऐसा जनपद है, जहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक खनिज, जल ऊर्जा, वन सम्पदा एवं प्राकृतिक सुन्दरता मौजूद है। सोनभद्र का क्षेत्रफल 6.788 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रारम्भ से ही जनजातिय संस्कृति का केन्द्र रहा है। सोनभद्र जनपद का सृजन 4 मार्च 1989 को किया गया था। यह 23.52 और 25.32 उत्तरी अक्षांश तथा 82.33 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी सीमा बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से मिलती है। यहाँ औसत वर्षा 1134 मिलीमीटर आंकी गई है। अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल संचय का कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण हर वर्ष जनपद को सुखे का सामना करना पड़ता है।

प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जनपद को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है- उत्तर की गंगा, सोन, कर्मनाशा और बेलन का मैदानी भाग, दक्षिण का सोन, रेण, बिजुल, कनहर से प्रभावित कैमूर रेंज का पठारी भाग, पूरब का बेलन, कर्मनाशा का मैदानी भाग तथा पश्चिम का बेलन का मैदानी भाग। दुद्धी, नगवा, घोरावल, अगोरी आदि का अधिकतम भाग वनों से आच्छादित है। जनपद के 75 प्रतिशत भागों में वन है जिनसे इमारती लकड़िया,

आँवला, हर्रा, बहेडा, मछुआ, बीड़ी, पत्ता, आम आदि वस्तुएँ प्राप्त की जाती है। जनपद का 25 प्रतिशत भाग मैदानी है, जहाँ खेती-बारी होती है।

**सारिणी संख्या-1: सोनभद्र जिले की जनांकिकी, सामाजिक व आर्थिक स्थिति**

	पुरुष	महिला	योग
1. जनसंख्या (हजार में)	971.34	891.21	1862.60
2. साक्षरता दर	74.92%	52.14%	64%
3. गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या (1997-98)	163893 (ग्रामीण)	6898 (नगरीय)	170791
4. अनुसूचित जाति (हजार में)	-	-	421.66
5. अनुसूचित जनजाति (हजार में)	-	-	385.02

**स्रोत** : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-सोनभद्र, कार्यालय-अर्थ एवं सांख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या प्रभाग, वर्ष 2005

**नोट** : उपर्युक्त आँकड़े जनपद के वर्ष 2011 के जनगणना के आँकड़ों पर आधारित हैं तथा निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का आधार 1997-98 वर्ष है।

**शोध प्रारूप** : सोनभद्र में कुल 8 विकास खण्ड हैं; दुद्धी, घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा, नगवा, चोपन, श्योरपुर, वभनी। पूरे ब्लॉकों में से एक ब्लॉक नगवा का चुनाव साधारण दैवनिदर्शन पद्धति द्वारा (Simple Random Sampling Method) किया गया। इस ब्लॉक के सम्पूर्ण गाँवों में से केवल दो गाँव का चयन उद्देशीय विधि द्वारा किया गया था, जो कि नक्सलवादी क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इस सर्वेक्षण हेतु जुलाई, 2008 में अध्ययन क्षेत्र में जाया गया। तत्पश्चात् साक्षात्कार पूर्व निरीक्षित किये हुए प्रश्नावली का प्रयोग करके परिवार के मुखिया से मनरेगा से सम्बन्धित क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसको प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषण द्वारा मनरेगा से सम्बन्धित योजनाओं के उपयोग एवं प्राप्त होने वाले सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित किया है, जिसके अन्तर्गत दो गाँवों रामपुर तथा करौँदिया के 284 परिवारों का अध्ययन शामिल है। वृत्तिक सूचना पुनः सर्वेक्षण क्षेत्र में अक्टूबर 2009 में एकत्रित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दोनों गाँवों के 100 व्यक्तियों का अध्ययन शामिल है जो कि मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे थे और इन सूचनाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र मनरेगा के अन्तर्गत कार्याजित मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में होने वाले व्यापक परिवर्तन पर आधारित है।

**मनरेगा के अन्तर्गत प्रदत्ता आय-व्यय का विवरण :** सोनभद्र में मनरेगा का प्रारम्भ 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण के साथ ही हुआ था। अप्रैल 2010 तक नगवा ब्लॉक के रामपुर व करौंदिया गाँवों के लिए अवमुक्त राशि क्रमशः 3.28 तथा 6.31 लाख रुपये हैं, जबकि सम्पूर्ण सोनभद्र क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के लिए आवंटित राशि 10262.85 लाख रुपये हैं जिनमें चालू वित्तीय वर्ष (2009-10) के द्वारा हुआ खर्च मात्र 3258.91 लाख रुपये ही है। सारणी-2 से प्राप्त सरकारी आँकड़े इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 व वर्ष 2008-09 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत सरकार द्वारा

**सारणी संख्या-2: विभिन्न वित्तीय वर्षों के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों पर किये गये खर्च का विवरण**

खर्च का विवरण(लाख रुपये में)	2006-07	2007-08	2008-09
1. प्रारम्भिक अवशेष धनराशि	0	0.657	2.94
2. वर्ष में प्राप्त धनराशि	3.08	13.95	21.72
3. अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज सहित)	0.00	0.00	0.02
4. कुल उपलब्ध धनराशि	3.08	14.63	24.60
5. कुल व्यय धनराशि	2.44	10.57	24.12
6. कुल व्यय धनराशि के सापेक्ष श्रम एवं सामग्री पर व्यय धनराशि का अनुपात	62: 37	62:38	49 : 51

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

**सारणी संख्या-3: मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या व जानकारीयों का वर्षवार विवरण**

	2006-07	2007-08	2008-09
1. कुल जॉबकार्ड धारक परिवारों की संख्या	198	410	410
2. वर्ष के दौरान रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	48	75	115
3. वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	48	75	115
4. वर्ष के दौरान प्रति परिवार औसत कार्य दिवसों की संख्या	35	55	40
5. बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने वाले परिवारों की संख्या	0	0	200
6. वर्ष के दौरान 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	0	5	12

**सारणी संख्या-4: मनरेगा से लाभान्वित होने वाले परिवारों का वर्गीकरण**

लाभान्वित	संख्या	प्रतिशत
हाँ	102	35.90
नहीं	182	64.10
योग	284	100.00

**सारणी संख्या-5: रोजगार योजना में रोजगार प्राप्त सदस्यों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण**

सदस्य संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	64	62.70
2	29	28.40
3	7	6.90
4	2	2.00
योग	102	100.00

उपलब्ध करायी गई धनराशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा सकी और प्रत्येक वर्ष आवंटित धनराशि का कुछ अंश अवशेष रह गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि या तो सरकारी आँकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या फिर उस क्षेत्र में कार्य को आशानुरूप सम्पन्न नहीं कराया गया। एक अन्य तथ्य यह उजागर होता है कि इसकी नींव में भ्रष्टाचार फलित हो रही है। वर्ष 2006-07 व वर्ष 2007-08 के दौरान जहाँ श्रम पर व्यय सामग्री पर व्यय के अनुपात में अधिक है, किन्तु वहीं वर्ष 2008-09 में यह अन्तर काफी कम है जो कि श्रम व सामग्री पर व्यय के सन्दर्भ में भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है (ट्रेज, ज्यां, खेड़ा, रीतिका व सिद्धार्थ, 2008)।

सारणी-3 से स्पष्ट है कि मनरेगा के माध्यम से औसत 100 दिन के रोजगार का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत रामपुर में 2008-09 के दौरान पंजीकृत 410 परिवार हैं। वर्ष 2006-07 में 35 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 में 55 प्रतिशत तथा वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत कार्यदिवस प्रत्येक परिवार द्वारा निर्मित किये गये, जिनमें पूरे 100 दिन का रोजगार वर्ष 2006-07 में 0 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 में 1.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2008-09 में 2.92 प्रतिशत परिवारों को ही प्राप्त हुआ। आँकड़ों से स्पष्ट है कि ऐसे परिवार की संख्या बहुत कम है जिन्होंने वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया (कौशिक, जगबीर, 2010)।

सारणी-4 व सारणी-5 द्वारा जुलाई 2008 में मनरेगा से लाभान्वित परिवारों का वर्गीकरण स्पष्ट होता है, जिसमें 35.9 प्रतिशत परिवार ही मनरेगा से लाभान्वित हुए थे जिसमें 62.7 प्रतिशत लोग परिवार के एक मात्र सदस्य थे जो कि रोजगार प्राप्त कर सके थे, जिससे मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त मजदूरी में अनियमितता परिलक्षित होती है।

**मनरेगा द्वारा लाभान्वित एवं प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विवरण का अध्ययन :**

**सारणी संख्या-6: पारिवारिक मासिक आय तथा व्यय के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण**

मासिक आय			मासिक व्यय		
आय (₹0)	संख्या	प्रतिशत	व्यय (₹0)	संख्या	प्रतिशत
200-900	127	44.7	300-900	82	28.9
900-1800	110	38.70	900-1800	135	47.5
1800-2700	32	11.30	1800-2700	37	13.00
2700-4500	15	5.30	2700-6000	30	10.60
योग	284	100.00		284	100.00



### सारिणी संख्या-7: मनरेगा द्वारा लाभान्वित परिवारों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों का वर्गीकरण

क्र.	विभिन्न प्रभाव	हाँ (%)	नहीं (%)	पता नहीं (%)
1	आर्थिक स्थिति में सुधार	25	65	10
2	भरण-पोषण में सहायक	10	80	10
3	ऋण भुगता में सहायक	45	50	5
4	चिकित्सा में सहायक	40	45	15
5	पारिवारिक कलह में वृद्धि	70	20	10
6	दहेज में वृद्धि	75	15	10
7	सामाजिक समरसता में वृद्धि	65	18	17

**नोट :** उपर्युक्त आँकड़े अक्टूबर 2009 में किये गये पुनः सर्वेक्षण के दौरान वैयक्तिक अध्ययन द्वारा लिये गये हैं, जिसमें 100 व्यक्तियों का अध्ययन सम्मिलित है।

जुलाई 2008 में किये गये सर्वेक्षण के दौरान 284 उत्तरदाताओं में 193 पुरुष व 91 महिलायें सम्मिलित की गई। प्रस्तुत सर्वेक्षण क्षेत्र में जनजातिय समुदाय की बाहुल्यता है, जहाँ पिछड़ा वर्ग 14.1 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति 15.1 प्रतिशत है, वहाँ जनजातियों का प्रतिशत 70.8 प्रतिशत के लगभग है। सारिणी संख्या-6 मासिक पारिवारिक आय-व्यय को स्पष्ट करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आय की तुलना में व्यय अधिक है क्योंकि जहाँ न्यूनतम मासिक पारिवारिक आय 200/- रुपये है वहीं न्यूनतम मासिक पारिवारिक व्यय 300/- रुपये हैं। दूसरी तरफ अधिकतम मासिक पारिवारिक आय 4500 रुपये व मासिक पारिवारिक व्यय 6000/- रुपये है अर्थात् लगभग सभी परिवार जीविकोपार्जन हेतु कर्ज लेने के लिए विवश है।

सारिणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों में से 45 प्रतिशत ग्रामीण निर्धन ऋण भुगतान कर पाने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं; वहीं इसका दूसरा पक्ष यह दर्शाता है कि मनरेगा के द्वारा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी साहूकार प्रथा व्याप्त है, जिनके द्वारा मनमाने ब्याज दर पर ग्रामीण निर्धनों को कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है (अधिकारी, अनन्दिता और भाटिया, कार्तिका : 2010)। सामान्य मजदूर यह सोचता है कि भविष्य में काम मिलने पर वह इसे चुका सकने में सक्षम सिद्ध होगा। किन्तु जब भविष्य में उसे काम प्राप्त नहीं हो पाता तो उसकी स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, जब विरासत में उसे धन, सम्पत्ति, जमीन प्राप्त न होकर कर्जा प्राप्त होगा और निर्धनता का दुष्चक्र पूर्व रूप में कायम रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी निरन्तर चलता रहेगा।

रामपुर ग्राम पंचायत की दौलतिया (35 वर्ष) अब काफी खुश है। उसका कहना है कि 'फाकाकशी के दिन लद गये तो छोटका बेटा कलुआ स्कूल जाने लगा है और हम दो साल से सोचते-सोचते रेड़ियो भी खरीद लिये।' इससे स्पष्ट है कि मनरेगा के द्वारा एक तरफ तो ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करने की लालसा में ये बाल श्रम को भी प्रोत्साहित कर रहा है। 40 वर्षीय विधवा सतवंशी अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर है।

मनरेगा ने ग्रामीणों को खरीद क्षमता तथा आमदनी को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की दर और कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि

से ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ गई है। आमदनी बढ़ने के फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों की अनाज, अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। (देखें सारिणी-5, सारिणी-6, सारिणी-7) मनरेगा के माध्यम से प्राप्त मजदूरी के द्वारा ग्रामीण अपने कृषि के लिए आवश्यक निवेश (खाद, बीज व कीटनाशक आदि) का खर्च वहन कर पा रहे हैं, इसके साथ ही उनके पास जो भी भूमि उपलब्ध है, उसमें सब्जियों या कम मौसमी चक्र वाले फसल लगाकर अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लायक थोड़ा बहुत अन्न या सब्जियाँ अवश्य उपजा ले रहे हैं, जबकि इससे पूर्व गाँव में इनकी भूमि अभिसंचित व बंजर अवस्था में पड़ी रहती थी।

मनरेगा से प्राप्त मजदूरी वर्ष में अल्प समय के लिए ही सही पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराती है और जो लोग अक्सर फाके की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराती है। करौंदिया पंचायत के बनारसी का कहना है कि 'भला हो सरकार व पंचायत का, जिन्होंने यहाँ काम चालू करवाकर मुझ जैसे भूमिहीन व्यक्ति को मजदूरी पर लगाया, जिससे मेरे घर-परिवार के लिए रोजी कमाने का आसरा मिला।'

सारिणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि मनरेगा सामाजिक समरसता का द्योतक भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि मनरेगा के अन्तर्गत जातीय असमानता को प्राथमिकता न देकर निर्धनता को प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ब्राह्मण सभी एक समान हैं, जिससे ग्रामीण भारत में व्याप्त जातीय गुट की अवधारणा स्वतः ही कमजोर सिद्ध हो रही है। मनरेगा के अन्तर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मनरेगा का सबसे बड़ा योगदान गाँवों के विकास में वहीं के ग्रामवासियों की सहभागिता तथा साथ में उन्हें रोजगार की प्राप्ति भी हुई है। मनरेगा के माध्यम से मजदूर अपना व अपने परिवार का खर्च वहन करने में सक्षम हो गया है, किन्तु मनरेगा का अन्य दुष्प्रभाव यह है कि यह ग्रामीणों के समक्ष सीमित काम को प्रस्तुत कर देगा। सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण निर्धनों से तालाब बनवाया जा रहा है। स्कूल, भवन व सड़क आदि बनवाये जा रहे हैं किन्तु इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है जो कि ग्रामीणों के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि तय करें। प्रत्येक गाँव की कुछ पारम्परिक विशिष्टता होती है, सरकार द्वारा उस विशिष्टता को प्रशिक्षण द्वारा प्रोत्साहित न करके उन्हें ऐसे कार्यों में नियोजित किया जा रहा है, जिसकी एक सीमा है, जिससे उस क्षेत्र के पारम्परिक उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना के अन्तर्गत कृत्रिम रोजगार की वृद्धि में मुख्य रोजगार की हानि होगी, इससे हानिकारक दुष्चक्र स्थापित हो सकता है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था परन्तु इससे कार्यरत रोजगारों का ही क्षय होने लगा।

### मनरेगा व महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति पर प्रभाव : सारिणी संख्या-8

सामाजिक समावेशन	2006-07	2007-08	2008-09
वर्ष में सृजित मानव दिवस	1613	4130	4599
(अ) कुल			
(ब) कुल में अनु० जाति	45	43	155
(स) कुल में अनु० जनजाति	1485	4032	8878
(स) कुल में महिलायें	785	1655	2105

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

रामपुर गाँव की कुल जनसंख्या 1428 में 704 पुरुष व 724 महिलायें हैं। अतः जनसंख्याओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। साथ ही सारिणी संख्या-9 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित मानव दिवसों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। जनजातिय क्षेत्रों में महिलाओं को अन्य समाज की अपेक्षा ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। लिये गये उत्तरदाताओं में 91 महिलायें व 193 पुरुष वर्ग है। मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को प्राप्त सबसे प्रमुख लाभ आर्थिक आत्मनिर्भरता है, जिसके फलस्वरूप वह कई महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो गई है। मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के हाथों में पहुंचे धन तथा अनाज से 'मानव विकास सूचकांक' में आशाजनक वृद्धि हुई है (कटारिया सुरेन्द्र : 2010)। सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि मनरेगा में मजदूरी कर रही महिलाओं ने अपनी आजीविका को पशु खरीदने, उनका उपचार कराने, बच्चों की पढ़ाई, रोगोपचार, पेयजल, पौष्टिक भोजन, बर्तनों तथा वर्षों से बची रही किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में लगाया। जबकि दूसरी तरफ पुरुष अपनी मजदूरी शराब सेवन करने पर व्यय करता है, जैसा कि सारणी संख्या-7 से स्पष्ट है कि इससे सामाजिक नैतिकता का पतन हुआ है और पारिवारिक कलह में वृद्धि हुई है। साथ ही मनरेगा के माध्यम से महिलायें आवश्यक धरलू सामान जैसे सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े, गहने खरीद रही है किन्तु इससे दहेज को प्रोत्साहन मिल रहा है। सारिणी संख्या-7 के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीणों का ऐसा मानना है।

मनरेगा का अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि पुरुष वर्ग धीरे-धीरे महिला वर्ग पर आश्रित होता जा रहा है तथा पुरुषों का बच्चों की शिक्षा, माता-पिता व परिवार की जिम्मेदारी से अलगवाव होता जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं पर काम का बोझ अत्यन्त बढ़ गया है क्योंकि उन पर धरलू व बाहरी काम दोनों का दबाव बढ़ गया है और उन पर दोहरा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक दोहन हो रहा है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि परिवार का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है, जबकि पति-पत्नी में परस्पर सहयोग हो किन्तु नकारात्मक सम्बन्ध बच्चों के पालन-पोषण पर दुष्प्रभाव डालती है।

रामपुर ग्राम पंचायत की महिला प्रधान मनभावती का कहना है कि 'इससे गाँव में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं। महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, कम से कम छोटी-मोटी जरूरतों के लिए वह अब किसी की मोहताज नहीं है।' यद्यपि सर्वेक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कार्यस्थल पर महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि न तो वहाँ शिशुओं की देख-रेख हेतु क्रेच की व्यवस्था है और न ही कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं को सामान्यतः पुरुषों की सहायक के रूप में पैसा दिया जाता है जो कि सामान्य मजदूरी से काफी कम होता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के योगदान के बावजूद उन्हें कृषक का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता। वहीं मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जा रहा है (खैरा, रीतिका व नायक, नन्दिनी : 2009)।

**मनरेगा और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव :** रामपुर गाँव की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या जनजातिय हैं, अतः उनकी प्रकृति पर निर्भरता स्वतः ही सम्भव है। मनरेगा का उद्देश्य सामाजिक वानिकी में वृद्धि करना है चाहे वह

जलसंरक्षण के अन्तर्गत तालाब अथवा बंधी के निर्माण द्वारा अथवा वनारोपण द्वारा। वन वर्षा एवं भूमिगत जल स्तर के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण सूखा रोकने के लिए अवश्य सम्भावनी है। रामपुर व करौंदिया की सूची पड़ी पहाड़ियों को हरा-भर कर पर्यावरण सुधार का कार्य किया गया।

#### सारिणी संख्या-9: निर्मित स्रोत

कार्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
बंधी 1 (अपूर्ण)	1 (अपूर्ण)	1 (अपूर्ण)	
तालाब	1	0	0
पौधारोपण	-	-	पूर्ण
निजी भूमि पर तालाब	0	1	3

स्रोत : www.sonbhadra.nic.in

इसी गाँव के कृषक जो अपनी जमीन बंजर जैसी होने के कारण मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, इस योजना के अन्तर्गत बंधी व तालाब के निर्माण हो जाने के बाद जमीन को सिंचित बना सके। फसल की पैदावार एक चक्रक से बढ़कर तीन चक्र हो गई है।

रामपुर व करौंदिया गाँव में एक तरफ सार्वजनिक स्रोतों का निर्माण किया गया किन्तु जिन सार्वजनिक स्रोतों की अधिक आवश्यकता थी उनके स्थान पर महत्वहीन स्रोतों का निर्माण किया गया जिसमें पानी भी उपलब्ध नहीं है। रामपुर एक पहाड़ी गाँव है जिसमें खेत ढलान पर स्थित है। अतः वर्षा ऋतु में पानी का बहाव तीव्र गति से आता है और खेतों को विनष्ट कर देता है, ऐसे में गाँव में चेकडेम की अधिक आवश्यकता है, जबकि गाँव में 5 तालाबों का निर्माण कर दिया गया है और बाँध के नाम पर मात्र 2 वह भी अपूर्ण बाँध है।

#### मनरेगा तथा नक्सलवाद :

#### सारिणी संख्या-10: विकास योजनाओं से पूर्ण लाभ प्राप्त न होने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का वर्गीकरण

क्र.	कठिनाईयाँ	संख्या (284)	प्रतिशत
1.	यातायात की असुविधा	240	84.5
2.	प्रधानों द्वारा अवहेलना/रिश्वतखोरी	200	70.4
3.	प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवहेलना/रिश्वतखोरी	221	77.8
4.	गरीबी	150	52.8
5.	योजनाओं की जानकारी का न होना	162	57.0
6.	शिक्षण संस्थाओं का न होना या दूर होना	68	28.9
7.	स्वास्थ्य/बिजली/पानी की सुविधा	118	41.5
8.	नक्सलियों/दलालों का भय	100	35.2

नक्सलवाद के प्रादुर्भाव का प्रत्येक राज्य में पृथक कारण है किन्तु मूलभूत कारण निर्धनता है और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान अवश्य सम्भव है। मनरेगा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसकी पहुँच देश के प्रमुख नक्सलवादी क्षेत्रों तक है। रामपुर-करौंदिया जाने वाली सड़क को कागजों पर कई बार बनाया गया। अब राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत 1.6 करोड़ की लागतसे बनने वाली सड़क आज भी अधूरी ही है किन्तु इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुँचायी जाती। सारिणी

संख्या- 10 से स्पष्ट है कि मनरेगा जैसी विकास योजना के पूर्ण लाभ प्राप्त न होने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों में 77.8 प्रतिशत लोगों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी व रिश्तवतखोर जिम्मेदार हैं। उसके पश्चात् 70.4 प्रतिशत प्रधानों को जिम्मेदार मानते हैं जबकि नक्सलियों के भय को मात्र 35.2 प्रतिशत लोग ही जिम्मेदार मानते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद को प्रोत्साहित करने में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व राष्ट्रगति वी०वी० गिरि का मानना था कि 'बेरोजगारी सब समस्याओं की जड़ है। इसी के कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है।' (कटारिया, सुरेन्द्र : 2010) बेरोजगारी व निर्धनता के परिणामस्वरूप जो युवा वर्ग नक्सलवादी गतिविधियों में संलग्न रहते थे, उनकी संख्या में भी काफी कमी आयी है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यदि प्रकरणों का विकास होगा तो गाँव का विकास होगा जो भविष्य में नक्सलवाद को स्वतः समाप्ति की ओर अग्रसर होगा।

मनरेगा के माध्यम से पिछड़े गाँव विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे गाँव में दूरसंचार माध्यमों का आवागमन हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के सम्पर्क में आने से उन्हें अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त हो रही है। मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त मजदूरी से पुरुष मजदूरों द्वारा रेडियो, मोबाइल जैसे संचार के साधनों का प्रयोग भी बढ़ रहा है, जिससे उन्हें गाँव से बाहर देश के अन्य भागों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी होती है जिससे उनमें जागरुकता में वृद्धि होती है और अज्ञानता में कमी आती है, क्योंकि नक्सलवादियों द्वारा सामान्यतः उनकी अशिक्षा व अज्ञानता का ही लाभ उठाया जाता है।

**निष्कर्ष व सुझाव :** उपर्युक्त सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है, स्थानीय दबंग एवं प्रभावी व्यक्तियों एवं अन्य निहित स्वार्थों पर कितना प्रभावी अंकुश लगा है? योजना के लक्षित लाभान्वित दुर्बल-गरीब वर्ग के लोग योजना का कितना लाभ उठा पा रहे हैं? अपने अधिकारों एवं हकों की पहचान करने की कितनी जागरुकता उनमें आयी है? क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रियाओं में कितनी सहभागिता दुर्बल-लाभान्वित वर्ग को मिल पा रहा है? मनरेगा के सन्दर्भ में कुछ सुझाव निम्न हैं:

1. मनरेगा ग्रामीणों को सीमित कार्य उपलब्ध कराता है, जिसके फलस्वरूप उनके परम्परागत व्यवसायों को क्षति पहुँच रही है। अतः मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित करना आवश्यक है जिससे स्थानीय संसाधनों का दोहन भलीभाँति हो सके और वे स्वयं के आय सृजन में सक्षम हो सकें व जिससे उनके जीवन को एक गति व निरन्तरता प्राप्त हो सके।
2. मनरेगा का उद्देश्य अधिकारों से वंचित समूह को समान अधिकार उपलब्ध कराना है ताकि वे जीवन-यापन के न्यूनतम जीवन-स्तर

को प्राप्त कर सकें। इसके अन्तर्गत मजदूरी में वृद्धि करना व बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराना सम्मिलित किया जाये ताकि इससे जुड़ने वाले व्यक्ति को किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो और सामाजिक शोषण से भी उनकी रक्षा की जा सके।

3. ग्राम सभा का उपयोग मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण में अधिक सार्थक रूप से किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जानकारी एवं जागरुकता के स्तर को इस उद्देश्य के साथ बढ़ाया जाये कि वे मनरेगा का काम लेते हुए उसकी कमियों को इंगित कर सकें।
4. ग्रामीण जनता में शिक्षा जानकारी एवं जागरुकता बढ़ाकर उन्हें 'शासित' वाली मानसिकता से उबारना है तथा अपने हक व अधिकारों को पहचान कर सामाजिक अंकेक्षण में प्रभावी जनसहभागिता करने में सक्षम बनाना है तो दूसरी ओर क्रियान्वयन तंत्र को पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील बनाने तथा उसमें सामाजिक अंकेक्षण की स्वीकार्यता बढ़ाकर उसे शासक वाली मनोवृत्ति से निकालकर लोक-सेवक मनोवृत्ति में ढालने की तरफ उन्मुख करना है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अधिकारी, अनिन्दता और भाटिया, कार्तिका, 2010, 'नरेगा वेज पेमेन्ट्स : केन वी बैंक ऑन द बैक्स', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीवली, xiv(1), 2 जनवरी : 30-37।
2. द्वेज, ज्यां; खेड़ा, रीतिका; सिद्धार्थ, 2008, 'नरेगा में भ्रष्टाचार : मिथक और वास्तविकता', योजना वर्ष : 53(8), अगस्त : 15-16।
3. खेरा, रीतिका और नायक, नन्दिनी 2009 : 'वूमन वर्कर्स एण्ड पर्सपेक्शन्स ऑफ द नेशनल रूरल इम्प्लायमेन्ट गारंटी एक्ट', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीवली, xiv(43) 24 अक्टूबर : 49-57।
4. केसरी, अर्जुनदास, 1994, 'यह सोनभद्र है', लोकरुचि प्रकाशन, सोनभद्र।
5. सिंह, रघुवंश प्रसाद, 2008, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दो साल', योजना वर्ष : 53(8), अगस्त : 7-10।
6. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, कार्यालय अर्थ व सांख्यिकाधिकारी अर्थ व संख्या प्रभाग, वर्ष 2005।
7. www.sonbhadra.nic.in
8. कौशिक, जगबीर, 2009, 'नरेगा गरीबों का सुरक्षा कवच', कुरुक्षेत्र, वर्ष : 56(2), दिसंबर : 3-8।
9. कटारिया, सुरेन्द्र, 2009, 'आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान', कुरुक्षेत्र, वर्ष : 56(2), दिसंबर : 9-12।

\*\*\*\*\*

# Impact of Ayushman Bharat Scheme on Beneficiaries in Rewa, Madhya Pradesh

Eshika Agrawal\* Dr. Kumud Shrivastava\*\*

\*Research Scholar (Economics) Govt. TRS College, Rewa (M.P.) INDIA

\*\* Professor (Economics) Govt. TRS College, Rewa (M.P.) INDIA

**Abstract :** The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan arogya Yojana (AB-PMJAY) is India's flagship health insurance scheme aimed at providing financial protection to economically vulnerable populations. This study examines the impact of the scheme on beneficiaries in Rewa, Madhya Pradesh, focusing on access to healthcare, financial relief and health outcomes. Through a mixed methods approach combining surveys and interviews, this paper highlights both the benefits and challenges faced by beneficiaries. Findings indicate improved healthcare access but also reveal gaps in awareness and hospital participation. Policy recommendations are proposed to enhance the scheme's effectiveness.

**Introduction -** Healthcare affordability remains a significant challenge in India, particularly for low-income populations. The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) was introduced in 2018 to provide cashless secondary and tertiary healthcare to over 500 million beneficiaries. This paper investigates how the scheme has affected the beneficiaries in Rewa, Madhya Pradesh, focusing on financial relief, hospital accessibility and service utilization.

**Research Objectives:**

1. The research will assess the demographics, accessibility and impact of Ayushman Bharat Yojana on population of Rewa.
2. To assess the impact of Ayushman Bharat scheme on healthcare outcomes and financial burden reduction in the region.
3. To evaluate the accessibility and utilization of healthcare services under the scheme.
4. To identify barriers faced by beneficiaries in availing scheme's benefits.

**Research Highlights:** The research for assessing the situation of Ayushman cardholders in Rewa had gone through several stages which includes use of stratified sampling method to conduct survey of around 100 beneficiaries and interviews from around 20-25 persons, health personnel's, and government officials.

**Field Survey Report**

(Collected data of about 100 Ayushman card holders through survey and interviews.)

Total Ayushman cardholders surveyed	100
Percentage of cardholders using the scheme for hospitalizations	65% (65 beneficiaries)

Average no. of hospital visits per year (per beneficiary)	2.5
Average distance travelled to nearest empanelled hospital	15km
Average claim amount reimbursed (per hospitalizations)	20,000
Percentage reduction in healthcare costs after using the scheme	60%
Percentage of claims rejected	8%
Beneficiaries reporting satisfaction with services	75%

**Further Analysis**

**1. Demographics of respondents**

- i. Male – 55%
- ii. Female – 45%

**2. Age groups:**

- i. 18-30 years – 20%
- ii. 31-50 years – 45%
- iii. 51-70 years – 25%
- iv. Above 70 years – 10%

**3. Financial Impact:**

- i. Average healthcare expense saved using Ayushman card: Rs 25,000/year per household.
- ii. Percentage of respondents reporting no out of pocket expenses: 60%

**4. Satisfaction levels:**

- i. Very satisfied- 50%
- ii. Somewhat satisfied- 30%
- iii. Neutral- 10%
- iv. Dissatisfied- 10%

**Analysis of survey reports:**

- i. Around 65% of surveyed cardholders actively use the

scheme, showing significant adoption but leaving a sizeable portion unutilized.

- ii. Beneficiaries report an average 60% reduction in out of pocket expenses, indicating improved affordability.
- iii. An average distance of 15km to hospitals suggests moderate accessibility but may be a barrier for rural populations.
- iv. A satisfaction rate of 75% shows positive perception but leaves room for addressing grievances related to claim rejections.

**Conclusion:** The questions arose at the starting of the research or the hypothesis proclaimed have been turned out to be true and explained briefly throughout the report.

The healthcare services provided are quite affordable and easily accessible to people seeking healthcare aid, thus benefitting them in the best way possible for all those who cannot afford quality treatment for several diseases.

Thus, it ensures welfare of people since:

- i. The scheme is well- utilized, with a significant majority relying on public hospitals.
- ii. Financial relief is notable, reducing financial pressure on patients.
- iii. Awareness campaigns enhancing scheme's reach and effectiveness.
- iv. Helping people with different socio-demographic background.

**Challenges associated to the**

**PM-JAY-AB scheme:** Though, this scheme of government

comes with several benefits, it also includes several leakages or loopholes:

- i. Firstly, India is not a corruption free nation, starting from the making of Ayushman cards to availing services and free treatment involves various malpractices.
- ii. Hospitals sometimes charge unnecessarily from patients in order to increase the bill to avail the full insurance amount by the government.
- iii. Not every hospital in a district is empanelled to provide its benefits, somewhere in rural areas only a few hospitals are authorized to provide treatments under AB PM-JAY scheme.

**Recommendations:**

- i. Firstly, regular verification of beneficiaries should be done to check proper functioning of the scheme.
- ii. Secondly, hospitals empanelled under the scheme should also remain under continuous check to create a corruption free environment from people.
- iii. Policymakers should be more focused on increasing hospital network coverage and improving claim processing systems.
- iv. Proper grievances redressed mechanism should be enforced.
- v. The hospital network should be increased to provide healthcare access in private hospitals along with government ones.

**Reference:-**

- 1. Personal Research.

\*\*\*\*\*

## भारतीय चित्रकला के वर्तमान आयाम व प्रो० भगवती प्रकाश काम्बोज

कुलदीप कुमार\* डॉ. निशा गुप्ता\*\*

\* शोधार्थी (चित्रकला) जे० के० पी० पीजी कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

\*\* एसोसिएट प्रोफसर (चित्रकला) जे० के० पी० पीजी कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव सभ्यता का विकास। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे-वैसे उसकी कला भी विकसित होती गयी। कला का उदय मानव की सौन्दर्य भावना का परिचायक है। आधुनिक कला विभिन्न आयामों के साथ पल्लवित एवं पुष्पित हो रही है। भारतीय चित्रकला के आधुनिक युग का प्रारम्भ 20वीं सदी से माना जाता है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धारक रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने देशी-विदेशी शैलियों का अध्ययन किया। नन्दलाल बसु अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्यों में से एक रहे हैं, जिन्होंने जलरंग व टेम्परा में ही प्रायः अपने चित्रों को बनाया है। कला और पहाड़ों के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति प्रो. काम्बोज का लगाव जन्मजात है। प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज का जन्म 15 अगस्त 1928 ई. में देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम गौरीशंकर था। बचपन से ही इनमें चित्रकला व प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति विशेष रुचि रही।

**प्रस्तावना** - चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव सभ्यता का विकास। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँखें खोली उसी समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को तूलिका के माध्यम से गुफाओं व चट्टानों की भित्तियों पर अभिव्यक्त किया। उसके जीवन की कोमल भावनाएँ तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियाँ उस समय की कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे-वैसे उसकी कला भी विकसित होती गयी। कला का उदय मानव की सौन्दर्य भावना का परिचायक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में- 'कला में मनुष्य अपनी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है।'

भारतीय चित्रकला का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही आरम्भ होता है। आरम्भ से ही मनुष्य अपनी मनःस्थिति को तूलिका के माध्यम से चट्टानों व गुफाओं की भित्तियों पर अभिव्यक्त कर सहज आनन्द की अनुभूति करता आया है।

किसी समय विशेष में मनुष्य जिस माहौल में रहा है अर्थात् उसके बीते असभ्य व सभ्य जीवन, शासक के आचार विचार, धार्मिक प्रभाव आदि ने चित्रकार की अभिव्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया है। इसी कारण चित्रकार ने कभी स्वतंत्र होकर चित्रण किया तो कभी अपने संरक्षक को खुश करने के लिए। धार्मिक भावना ने मानव हृदय को कठोर, हिंसक व आदिम प्रवृत्ति से सहज कोमल मनोभावों की ओर रूपान्तरित किया। बौद्ध धर्म का इसमें प्रमुख स्थान रहा है। गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने अजन्ता की जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों का निर्माण किया। ऐसा लगता है मानो असंख्य बौद्ध भिक्षु अपनी छैनी तथा तूलिका के माध्यम से सृजन करते हुए भगवान बुद्ध की साधना में लीन हो गये। इन भित्ति चित्रों पर किसी चित्रकार का नाम नहीं मिलता, लगता है कि गुरु-शिष्य के मधुर सम्बन्ध और समर्पण की भावना इन चित्रों में उतर आई हो। सम्भवतः शिष्य ने इसलिए अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि उसमें उसके गुरु का भी कार्य था और गुरु ने इसलिए नहीं लिखा कि उसमें शिष्य का भी चित्रण कार्य था।

पोथी चित्रण में बौद्ध धर्म से प्रेरित पाल चित्रशैली तथा जैन धर्म से

प्रेरित अपभ्रंश चित्रशैली ने ताडपत्र चित्रण में प्रसिद्धि पाई। राजस्थानी शैली की मेवाड़, मारवाड़, हाडौती, ढूँढाडी शैलियाँ लघु चित्रों के रूप में फली फूली। किशनगढ़ चित्रशैली में निहालचन्द द्वारा बनाये गये बनी-ठनी के सौन्दर्यपूर्ण चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय और ईरानी शैलियों के योग से बनी मुगल चित्रशैली ने अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ के समय में विशेष प्रसिद्धि पाई व शासक ने अपने शासक की रुचि के अनुरूप चित्रण किया। पहाडी चित्रशैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया।

अंग्रेजी शासन में पनपी कम्पनी शैली में चित्रकारों ने अंग्रेज अधिकारियों के अनुरूप चित्रण किया। पाश्चात्य प्रभाव भारतीय कला पर स्पष्ट आने लगा। राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तकनीक से प्रभावित होकर तैल माध्यम में पौराणिक चित्र बनाये। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से चित्रकला के विकास की यह धारा बंगाल शैली से होते हुए आधुनिक कला संगठनों की ओर बढ़ती चली गयी। आज कलाकार अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्र चित्रण कर रहा है।

**मुख्य भाग** - आधुनिक कला विभिन्न आयामों के साथ पल्लवित एवं पुष्पित हो रही है। भारतीय चित्रकला के आधुनिक युग का प्रारम्भ 20वीं सदी से माना जाता है। राजा रवि वर्मा केरल के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने यूरोपियन शैली का अनुकरण करके भारतीय देवी-देवताओं तथा पौराणिक व्यक्तियों के चित्रों को तैल माध्यम में चित्रित किया है। वे भारत में तैल-चित्रण तकनीक को प्रारम्भ करने वाले अग्रणी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। श्रीकृष्ण और बलराम, रावण, सीता और जटायु, शकुन्तला, इन्द्रजीत की विजय, हरिश्चन्द्र आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं।

अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धारक रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने देशी-विदेशी शैलियों का अध्ययन किया। बाद में ई०वी० हैवेल की प्रेरणा के फलस्वरूप ही भारतीय कला के स्रोत अजन्ता, एलोरा तथा राजपूत शैलियों का भी अध्ययन किया। भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त कराने में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने जापानी चित्रकारों के प्रभाव

से एक नई विधि 'वाश टैकनीक' को जन्म दिया।

नन्दलाल बसु अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्यों में से एक रहे हैं, जिन्होंने जलरंग व टेम्परा में ही प्रायः अपने चित्रों को बनाया है। साथ ही आपने वाश टैकनीक में भी अनेक प्रसिद्ध चित्रों की रचना की है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की चित्र सज्जा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

'भारतीय कला-परम्परा में विनोद बिहारी मुखर्जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कला में विविधता है। भित्ति चित्र, कोलाज, वुडकट तथा केलीग्राफी आदि सभी प्रकार का कार्य आपने किया है। मुखर्जी की कला भारत की आधुनिक चित्रकला के विकास की वह कड़ी है जिसने उसे ऐसी स्वायत्तता प्रदान की जिसका आज वह सुख भोग रही है। आपने अतीत को अनदेखा नहीं किया बल्कि उसके आवश्यक पक्षों को नये युग के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। पुल, जंगल, मन्दिर का घण्टा तथा मध्यकालीन हिन्दी सन्त आपकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।'<sup>1</sup>

अमृता शेरगिल एक प्रतिभापूर्ण नारी-कलाकार थी। आज जब हम भारतीय चित्तेरों की बात करते हैं, तो अमृता का नाम आते ही एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आ खड़ा होता है, जिसकी कला पूर्व और पश्चिम की कला शैलियों के संगम के रूप में ही नहीं बल्कि भारत में आधुनिक कला के जन्मदाता के रूप में प्रतिष्ठित की जा सकती है। अमृता शेरगिल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने बीस वर्ष की अल्पायु में ही विदेशों में अपना सिक्का जमा लिया था। वधु का शृंगार, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, गणेश-पूजा, हल्दी पीसती औरतें, चारपाई पर विश्राम करती स्त्री, आदि आपके प्रसिद्ध चित्रों में से हैं।

'दाढ़ी व जुल्फों के श्वेत बालों से आवृत नारंग हँसमुख चेहरा, सफेद खादी का कुर्ता-पायजामा पहने, नंगे पैर, लम्बे कद का, लम्बे डग भरता व्यक्तित्व था एम०एफ०हुसैन का, उस हुसैन का जो स्वयं एक जिन्दा तस्वीर थे। ख्याति तो यूँ अनेक भारतीय चित्रकारों को मिली, पर प्रायः कॉफी हाउस में तथा युवावर्ग के बीच जब कला की चर्चा होती है तो हुसैन का नाम अवश्य अपने आप आ जायेगा। जो सम्मान व लोक प्रियता पिकासो को मिली है वही भारत में हुसैन को दिलखोलकर मिली है, सभी ओर से मिली है। सन् 1973 ई० में गणतन्त्र दिवस पर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से हुसैन को सम्मानित किया था।'<sup>2</sup>

हुसैन बुनियादी तौर पर एक प्रतीकवादी चित्रकार थे जिन्होंने असंख्य चित्रों की रचना की है। चित्रों में घोड़े की आकृति हुसैन का प्रतीक बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर 'रजा की रंगों के प्रति संवेदनशीलता निरन्तर बढ़ती गयी है।'

कला और पहाड़ों के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति प्रो. काम्बोज का लगाव जन्मजात है। नई सृजनात्मक प्रकृति की पहचान उनके काम में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। प्रो. भगवती प्रकाश काम्बोज का जन्म 15 अगस्त 1928 ई. में देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम गौरीशंकर था। बचपन से ही इनमें चित्रकला व प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति विशेष रुचि रही।

'प्रो० काम्बोज का विवाह 31, जनवरी सन् 1959 में पारिवारिक रीति-रिवाज के अनुसार श्रीमती इन्दिरा से हुआ। इनकी पत्नी की शिक्षा बी०ए० थी। उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। श्रीमती इन्दिरा तीन भाईयों में अकेली बहन थी। प्रो० काम्बोज की दो पुत्रियाँ और एक पुत्र है। सबसे बड़ी पुत्री श्रीमती श्रुति काम्बोज ने एम०एस०सी० रसायन विज्ञान से की तथा एम० फिल० की डिग्री प्राप्त की। डॉ० ऋचा काम्बोज ने नेशनल म्यूजियम से एम०ए० हिस्ट्री ऑफ आर्ट से किया और गाल्ड मेडलिस्ट रही

तथा डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की। ये एम० के० पी० पीजी कॉलेज, देहरादून में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार इनका पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा। प्रो० काम्बोज का जीवन बहुत ही आनन्द से व्यतीत हो रहा था अचानक ही फरवरी 2016 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया।'<sup>3</sup>

इन्होंने चित्रकला में परास्नातक की डिग्री डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज देहरादून से प्राप्त की। ये मृत्युपर्यन्त कला सृजन में सलंग्न रहे तथा विभिन्न एकल तथा सामूहिक कला प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करते रहे। इन्होंने देहरादून में कला के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अथक प्रयास किये। प्रो. बी.पी. काम्बोज अपनी कलाकृतियों के माध्यम से जनमानस के हृदय में सौन्दर्य रूपी दीपक को प्रकाशित करना चाहते थे। वे समाज को अध्यात्मिकता, आपसी प्रेम, सौहार्द की भावना, समाज सेवा तथा देश-भक्ति का संदेश देना चाहते थे। उनके चित्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव स्पष्ट झलकता है। उन्होंने अपने चित्रों में लकड़ी के प्राकृतिक पोट का प्रभाव सौन्दर्यपूर्ण ढंग से दर्शाया है। बुश से छिटकने के बाद उनके भावों को रंगों ने प्रेरणा के नये आयाम दिये हैं। निरंतर नई सृजनात्मक प्रवृत्ति की पहचान बन चुके इस महान शख्सियत की कृतियों ने सरहद की सीमाओं को लांघा है। प्रो. काम्बोज जी की कला के प्रति रुचि, लगन व निष्ठा के मूल मन्त्र को साबित करने का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने ड्राइंग एण्ड पेंटिंग में एम.ए. किया और एक चित्रकार के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की।

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका, नई दिल्ली तथा ललित कला अकादमी में आपका कार्य प्रदर्शित होता रहा। उन्होंने उत्तरांचल में कला की गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। कलाधरोहर के संरक्षण तथा प्रतिभावों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने वहाँ उत्तरांचल कला परिषद का गठन किया। इस परिषद का अध्यक्ष इन्हें ही नियुक्त किया गया। इन्होंने सरकार को कला की चेतना जगाने के लिए सुझाव दिये, जिससे इन्हें सरकार की ओर से सहयोग भी मिला। देहरादून में पहली प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिससे नवोदित कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। वे आगरा कॉलेज आगरा में कला विभाग में फैकल्टी ऑफ डीन रहे। वे कला शिक्षा में आदर्श शिक्षक की भूमिका को हमेशा प्रभावपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि हमारी शिक्षण पद्धति में मोटिवेशन नहीं है, इसी कमजोरी ने कला से जुड़े लोगों को ऐसी छूट प्रदान की है, जो नवोदित कलाकार सीखने की उम्र में अवाई के सपने देखने लगते हैं। मूल लक्ष्य से भटककर श्रेष्ठता को छूना असम्भव ही है। युवाओं का समय से पहले अधिक महत्वकांक्षी होना कला के क्षेत्र के लिए लाभप्रद नहीं है। वे कहते थे कि आधुनिक कला शैली से कलाकार प्रभावित है और कुछ नया करने की ललक में निरंतर परिवर्तन आम हो गया है।

कला और कलाकार के प्रचार-प्रसार के लिये अब छोटे-बड़े शहरों में कला वीथिकाएँ खुल गई हैं, जिनके द्वारा कलाकारों को प्रसिद्धि भी प्राप्त हो रही है। कला को जन-साधारण तक पहुँचाने तथा नये कलाकारों को आगे आने के अवसर प्रदान कर रही वीथिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. समकालीन कला, अंक 19, जून 2001, पृष्ठ संख्या 03
2. आधुनिक भारतीय चित्रकला डॉ. गिरार्ज किशोर अग्रवाल पृष्ठ संख्या 52
3. चिन्मय मेहता, उत्तरांचल की कला प्रकृति पर्यावरण एवं समाज से प्रतिबद्ध चित्रकार काम्बोज क कला सम्पदा एव वैचारिकी, अंक 10-मई-जून 2004

## सरकारी कामकाज में हिंदी : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आराधना सिंह\*

\* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** – भारत में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सरकारी कामकाज में इसके व्यापक उपयोग को लेकर अब भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह शोध आलेख सरकारी कामकाज में हिन्दी की वर्तमान स्थिति, उसके संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक बाधाओं, तकनीकी चुनौतियों और संभावित समाधान उपायों का विश्लेषण करता है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार, तकनीकी विकास, प्रशासनिक प्रशिक्षण और कानूनी अनुवाद की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। अतः सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रभावी उपयोग प्रशासनिक दक्षता पारदर्शिता और जनता की सहभागिता को बढ़ाने में यह आलेख सहायक हो सकता है।

**शब्द कुंजी** – सरकारी कामकाज, राजभाषा हिंदी, प्रशासनिक भाषा, भाषा नीति हिंदी और संविधान, सरकारी कार्यालयों में हिंदी, तकनीकी विकास और हिंदी, भाषा संबंधी चुनौतियाँ।

**प्रस्तावना** – हिन्दी हमारी मातृभाषा है, जिसके उत्थान की कामना सदैव भारतीय जनमानस में रही है। कभी भारतेन्दु ने निजभाषा उन्नति में ही समस्त उन्नति की बात कही थी यह उनकी चिन्ता भी थी और चिन्तन भी कि भाषा यदि उन्नत हो तो राष्ट्र भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा।

भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं स्वतंत्रता के बाद, हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में एकता और सुगमता लाई जा सके। हालांकि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को लेकर अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हिन्दी देश की एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और इसे अधिकांश लोग समझते थे। हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाना और जनता तक सरकार की नीतियों व योजनाओं को सहज रूप से पहुंचाना था।

राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उपयोग की जाती हैं, साथ ही राज्यों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने की अनुमति दी गई हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं, जैसे कि हिन्दी कार्यशालाएँ, राजभाषा पुरस्कार और कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग को बढ़ावा देना।

यद्यपि आधुनिक जीवन के विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है। इसीलिए प्रयोजनमूलक स्तर पर हिन्दी ने विभिन्न विषयों तथा कार्य क्षेत्रों में अपने-अपने विषय के अनुसार अपना विशिष्ट रूप धारण कर लिया है। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालयी हिन्दी कहा जाता है। कार्यालयी संदर्भ में भी हिन्दी एक विशेष प्रयुक्ति के रूप में उभरी है। वास्तव में कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है जिसके

अंतर्गत सरकार को देश के आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। अतः इन सभी कार्यों में प्रयुक्त भाषा कार्यालयी भाषा होती है। कार्यालयी हिन्दी का स्वरूप सामान्य बोलचाल की हिन्दी से भिन्न होती है। इसकी प्रकृति प्रायः तकनीकी और औपचारिक होती है और वह काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि से अलग होती है। इसमें जो कुछ कहा जाता है वह बंधे बंधाये वाक्यों या परिभाषिक शब्दावली के भीतर कहा जाता है।

मसौदा-टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन लेखन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने-अपने रूप को लिए होती है।

प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को वरीयता मिल रही है, बैंक, जीवन बीमा निगम, डाकतार, रेल, आयकर, दूरसंचार, भारत पेट्रोलियम गैस विविध एजेन्सी इस तरह के अन्य कई कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को वरीयता मिल रही है।

विगत वर्षों में हिन्दी का कृष्ण पक्ष ही था कि अधिकारिक स्तर पर वह अपने ही देश के प्रशासन की जुबान नहीं बन पाई। अतः हिन्दी प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप में नये अंदाज में आई किन्तु इसमें भी कुछ खामियाँ निकली। विद्वानों का विचार है कि ये कमियाँ मुख्य रूप से अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली और भाषिक संरचना तथा प्रयुक्ति के स्तर की हैं। ये कमियाँ और दुर्बलताएँ ही कार्यालयीन हिन्दी की समस्याएँ हैं। दरअसल प्रशासन के क्षेत्र में संवैधानिक अनिवार्यता के तहत देश के विभिन्न कार्यालयों में जब हिन्दी प्रयोग की बात उठी तब धीरे-धीरे कुछ समस्याएँ भी उठी। इनमें पहली समस्या अनुवाद की थी। अनुवाद के द्वारा अंग्रेजी की जगह आई नई हिन्दी अंग्रेजी से भी कठिन लगने लगी। अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार, 'अनुदित हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों के लिए नए-नए गढ़े हुए हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें अर्थ पर कम, शब्दों पर अधिक बल दिया जाता है,



परिणामतः वह हिन्दी लोगों के गले नहीं उतर रही है।<sup>1</sup>

हिन्दी के माध्यम से सरकारी कामकाज करने हेतु अंग्रेजी में स्थित सारी कार्यालयीन सामग्री की सुलभ हिन्दी में लाना समय की मांग बन गई। वैसे ही देश में कार्यालयीन अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती गई। कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में होने वाली समस्याएँ यह हैं कि उसकी भाषा मूलतः अमिधामूलक तथा अनालंकृत होती है। कार्यालयीन अनुवाद में एक तरफ प्रत्येक शब्द के साथ बाध्य रहना पड़ता है तो दूसरी तरफ ऐसे अनुवाद को कृत्रिमता एवं अटपटेपन से भी बचना पड़ता है डॉ. राजमणि तिवारी का कथन सही है कि 'कार्यालयी अनुवाद करते समय अनुवादक को छूट लेने की स्वतंत्रता नहीं है। उसे प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने की बाध्यता सी प्रतीत होती है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुवाद की भाषा कृत्रिम और अटपटी बन जाती है।'<sup>2</sup>

चूंकि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। सरकारी कामकाज हिन्दी में करने को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, मगर सरकारी विभागों का कामकाज हिन्दी में करने की नसीहत देने वाली केंद्र सरकार के सर्वोच्च मंत्रालय से हिन्दी गायब हो गई। इम्फाल और नार्थ ईस्ट के राज्यों से सूचनाओं के जबाव हिन्दी में आते हैं लेकिन दिल्ली स्थित मंत्रालयों को हिन्दी नहीं आता। प्रधानमंत्री (पीएमओ) में कामकाज जरूर हिन्दी में होता होगा लेकिन पत्राचार अंग्रेजी में हो रहा है। सूचना के अधिकार के तहत यहाँ से कोई जानकारी हिन्दी में मांगिये। आपको जबाव अंग्रेजी में मिलेगा। हाल ही में संगम नगरी के पार्षद के सवाल का जबाव अंग्रेजी में (पीएमओ ने) भेजा। केन्द्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपना जबाव अंग्रेजी में देते हैं। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के दतर ने हिन्दी में जबाव दिया।<sup>3</sup>

किसी भी राष्ट्र में एक या एक से अधिक भाषायें होती हैं जो सरकारी या प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे भारत में हिन्दी और अंग्रेजी प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग की जाती हैं और कुछ राज्य सरकारें हिन्दी के स्थान पर अपने राज्य की भाषा का प्रयोग करती हैं ऐसी स्थिति में आम बोलचाल की भाषा और प्रशासनिक कार्यालयों की भाषा में बहुत अंतर होता है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता का सर्वप्रमुख कारण प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक आसानी से सरकारी नीतियों, योजनाओं और नियमों को समझ सकें। हिन्दी में सरकारी कामकाज करने से यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा का प्रशासनिक रूप अंग्रेजी के ढांचे पर विकसित हुआ। इसलिए 'प्रशासनिक या कार्यालयी हिन्दी और आम हिन्दी भाषा में स्वरूप, संरचना, वाक्य गठन, शब्द भंडार आदि के स्तर पर बहुत अंतर पाया जाता है। प्रशासनिक कार्य मूल रूप में अंग्रेजी में होता है, उसके बाद हिन्दी में उसका अनुवाद किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अंग्रेजी रूप को ही प्रमाणिक माना जाता है।'<sup>4</sup>

कानूनी एवं संवैधानिक बाध्यता होने से हिन्दी को संविधान में राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 'प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएँ, संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट सरकारी पत्र, आदेश आदि जहाँ तक हो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित की

जाये। भारत सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी संकल्पों और विधायी अधिनियमों में धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने और जनता की सहायता करने के विचार से जहाँ तक संभव हो सके उन्हें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी निकाला जाये।'<sup>5</sup>

हिन्दी की उन्नति में अनुवाद कार्य का अभूतपूर्व योगदान है। अनेक हिन्दीतर क्षेत्रों की हिन्दीतर श्रेष्ठ रचनायें अनुवाद के कारण हिन्दी में आ गई हैं, जिनके कारण हिन्दी निश्चय ही समृद्ध होती जा रही है।

**हिन्दी के विकास में सरकार द्वारा उठाये गये कदम** - शासकीय स्तर पर विविध योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो, हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु रहा है। त्रिभाषा सूत्र का निर्माण एवं क्रियान्वयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं के प्रलोभन हिन्दी अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान एवं विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। कई सेवाभावी संस्थाएँ जैसे - भारतीय हिन्दी परिषद दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा (पुणे) नागरी प्रचारिणी सभा (काशी), दक्षिण के राज्यों में कार्यरत अनेक संस्थाएँ और महाराष्ट्र हिन्दी परिषद जब से संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है तब से प्रशासनिक स्तर पर अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम कार्यालयों में हो रहे हैं। हिन्दी लेखन प्रोत्साहन एवं प्रतियोगिता में कर्मचारीगण व्यापक संख्या में भाग ले रहे हैं। यद्यपि कार्यालयी हिन्दी में हिन्दी के मानकरूप का प्रयोग किये जाने का प्रयास हो रहा है। इस मानक हिन्दी की वर्णमाला, इसे लिखने का ढंग, वाक्य संरचना, व्याकरण आदि निश्चित किया गया है, ताकि सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारी उसी के अनुरूप कार्य कर सकें। केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग इस मानक हिन्दी या राजभाषा के विकास, रूप-स्थिरकरण एवं इसकी समृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न कार्यालयों के लिए उपयोगी शब्दावली का भी निर्माण किया गया है। बहुभाषिक कोश भी तैयार किये गये हैं।

हिन्दी में सरकारी कार्यों में चलन से सम्पूर्ण देश में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है और प्रशासनिक कार्यों में स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।

हिन्दी का प्रयोग करने से सरकारी अधिकारी और आम जनता के बीच संवाद अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा।

**सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग की चुनौतियाँ** - जहाँ सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाता है किन्तु किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखे तो हिन्दी प्रयोग में आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

सर्वप्रथम अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव आधुनिक समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे हिन्दी को प्रशासनिक कार्यों में वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए।

सरकारी दस्तावेजों वेबसाईटों और कम्प्यूटर प्रणालियों में हिन्दी का पूर्ण रूप भी से उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधनों की भी कमी है।

भारत के अधिकांश कानून और सरकारी नियम अंग्रेजी में बनाए गए हैं, जिससे हिन्दी में इनका अनुवाद और प्रयोग करना जाटिल हो जाता है। सरकारी कार्यों में हिन्दी प्रयोग की एक और समस्या यह है, भारत का बहुभाषी होना। भारत में विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं कई राज्यों में

हिन्दी को अपनाने में संकोच किया जाता है क्योंकि वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रभाव है।

सरकारी दफ्तरों में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा न मिलने का एक कारण यह भी है कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं जिससे हिन्दी का प्रयोग सीमित हो जाता है।

#### **सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के उपाय :-**

1. **नीतिगत सुधार** – केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें और इसे प्रशासनिक कार्यों का अभिन्न अंग बनाएं।
2. **तकनीकी विकास** – सरकारी वेबसाइटों, सॉफ्टवेयर और दस्तावेजों में हिन्दी को प्रमुखता देने के लिए तकनीकी सुधार किए जाने चाहिए।
3. **हिन्दी में प्रशासनिक प्रशिक्षण**– सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे इसे सुगमता से प्रयोग कर सकें।
4. **हिंदी में कानूनों का अनुवाद** – सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, कानूनों और नीतियों का हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को समझने में सुविधा हो।
5. **प्रेरणादायक योजनाएँ**–हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की योजनाएँ चलाई जानी चाहिए जैसे हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार देना।

**सारांश**– इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि हिन्दी का भविष्य स्वर्णिम है क्योंकि हिन्दी एक जीवंत भाषा है, इसकी सर्वांगीण उन्नति होगी, वह अपनी देश भाषाओं की प्रवृत्तियों, शब्दावली आदि को आत्मसात कर उत्तरोत्तर देश व्यापक बनेगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आज तूफान के बादल भले ही छाये हो, वातावरण में गड़गड़ाहट भले ही सुन पड़ती हो पर वह समय दूर नहीं है जब बादल छटेंगे, आकाश निर्मल होगा और स्वच्छ वातावरण की शरदकालीन निर्मल सूर्य रश्मियों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का मुख उत्फुल्लित दिख पड़ेगा।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. अर्जुन चव्हाण, मीडिया कालीन हिन्दी स्वरूप एवं संभावनाएँ, राजकमल प्रकाशन।
2. डॉ. अर्जुन चव्हाण, मीडिया कालीन हिन्दी स्वरूप एवं संभावनाएँ, राजकमल प्रकाशन।
3. अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, कृतिका, प्रकाशन वर्ष - 12- 13
4. डॉ. हरिमोहन, प्रशासनिक हिन्दी, तक्षशिला प्रकाशन, पृ. 52
5. डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी, वाणी प्रकाशन, पृ. 12
6. डॉ. संजीव कुमार जैन, अनुवाद विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन।
7. कैलाश नाथ पाण्डेय, प्रयोजन मूलक हिन्दी की नई भूमिका।

\*\*\*\*\*

## शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन

राधा रानी गौतम\* डॉ. खेल शंकर व्यास\*\*

\* शोधार्थी (शिक्षा) पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उदयपुर (राज.) भारत

\*\* डीन (शिक्षा) पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

**प्रस्तावना** - शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोधन व मार्गी-करण कर उसे समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है। ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सके। वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्य बदल चुके हैं। आज शिक्षा का उद्देश्य न केवल पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान प्रदान करना है बल्कि सह-पाठ्यक्रम व सहगामी क्रियाओं संबंधी जानकारी प्रदान करना भी है, जो कि अनुभव आधारित होता है और इसके लिए विद्यार्थियों का सृजनात्मक होना आवश्यक है अतः आज शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सृजनात्मक बनाने पर बल देता है इसलिए पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अधिक सर्जनशील बन सके, क्योंकि एक सर्जनशील बालक ही अपने अनुभवों, कलाओं, ज्ञान व कौशलों के आधार पर स्वयं को जीवन की विपरीत परिस्थितियों में समायोजित करने की सामर्थ्य रखता है।

अतः आवश्यकता है कि हम बालक के अंदर सृजनात्मक संबंधित विभिन्न गुण जैसे - भावना प्रबंधन, संबंधित घटनाओं के मध्य संबंध बनाना, नवीन विचार उत्पन्न करना संसार में दिए हुए पैटर्न ढूँढना आदि गुणों का विकास कर सके यदि छात्र का बुद्धि स्तर बढ़ेगा तो स्वतः ही उसका प्रभाव उपलब्धि अभिप्रेरणा पर पड़ेगा।

**शब्द कुंजी** - शिक्षक, शिक्षण परीक्षण संस्थान, उपलब्धि अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता।

**समस्या कथन** - शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का सृजनात्मकता की संदर्भ में अध्ययन।

**उद्देश्य :**

1. B.Ed संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन।
2. STC संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन।
3. B.Ed संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की सृजनात्मकता का अध्ययन करना।
4. STC संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की सृजनात्मकता का अध्ययन करना।
5. B.Ed एवं STC के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा सृजनात्मकता के मध्य सह सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

**परिकल्पनाएं :**

1. B.Ed एवं STC संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. B.Ed एवं STC संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की सृजनात्मकता के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. B.Ed एवं STC संस्थान के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं सृजनात्मकता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

**शोध विधि**

**अनुसंधान प्रारूप :** प्रकरण की प्रकृति व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस अनुसंधान में सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का उपयोग किया गया है।

**तकनीक**

**स्तरीय न्यादर्श तकनीक** - प्रस्तुत अध्ययन में स्तरीय न्यादर्श तकनीक का प्रयोग किया गया है इसमें अनुसंधानकर्ता विशिष्ट लक्षणों के आधार पर छोटे-छोटे समजात समूह बनाता है तथा जनसंख्या के स्तरों को निश्चित करता है।

**जनसंख्या व न्यादर्श**

1. **जनसंख्या**- कोटा शहर के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्ररीक्षणार्थी।
2. **न्यादर्श**-B.Ed एवं STC शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के 100 प्ररीक्षणार्थियों को लिया गया है जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्रों को सम्मिलित किया गया है।

**आंकड़े संकलन की योजना**

**प्रयुक्त उपकरण:** प्रस्तावित शोध अध्ययन में निम्न उपकरणों का उपयोग किया गया है।

1. **उपलब्धि अभिप्रेरणा**- वी. पी. भार्गव का अभिप्रेरणा मापनी
2. **सृजनात्मकता**- इसके लिए Divergent Production Ability Test Bettery (K.N. Sharma) का उपयोग किया गया इस बैटरी में 6 उप - जांच है यह मुख्य चार सृजन क्षमताओं के साथ-साथ कुल सृजनात्मकता को भी नापती है।

**3. आंकड़े का विश्लेषण**

1. मध्य
2. मानक विचलन
3. टी-परीक्षण

**आंकड़े का विश्लेषण**

1. **माध्य-** इसको ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक स्कोर को जोड़कर उसे स्कोर की संख्या से विभाजित कर देते हैं।
2. **मानक विचलन** - निराश्रित चर को आश्रित चर से तुलना करके विचलन निकाल सकते हैं।
3. **टी - परीक्षण** - जब दो जनसंख्या के औसत का अंतर निकालना होता है, तब टी-परीक्षण का उपयोग करते हैं घ या जब दो माध्यों की तुलना की जाती है।
4. **सहसम्बन्ध** - परस्पर आश्रित चरों के मध्य किसी भी प्रकार के प्रमाण को ज्ञात करने हेतु सहसम्बन्ध का प्रयोग किया जाता है।

### आंकड़े का विश्लेषण

#### परिकल्पना- 1

B.Ed एवं STC के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

#### उपलब्धित अभिप्रेरणा

सारणी (गणना)

	N	Mean	S.D	S.E	T.Value	निष्कर्ष
B.Ed	50	60.79	7.31	0.333	0.333	सार्थक अंतर नहीं है।
STC	50	60.55	7.21	0.727		

सारणी से पता चलता है कि B.Ed के कुल प्ररीक्षणार्थियों के प्राप्तांको का मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 60.79 तथा 7.31 और STC के कुल प्ररीक्षणार्थियों के प्राप्तांको का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन 60.55 तथा 7.21 प्राप्त हुआ दोनों वर्गों के प्राप्तांको से प्राप्त प्रमाणिक त्रुटि का मन 0.726 प्राप्त हुआ तथा 'टी' का मन 0.333 प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के अंश 98 पर उपरोक्त 'टी' का मन 0.05 स्तर पर दिए गए स्थानीय मान से कम है। अतः परिकल्पना 0.05 स्तर पर स्वीकृत सिद्ध होती है।

निष्कर्ष अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों वर्गों का उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

#### परिकल्पना- 2

B.Ed एवं STC के प्ररीक्षणार्थियों की सर्जनात्मकता के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी (गणना)

hy=2	N	Mean	S.D	S.E	T. Value	निष्कर्ष
B.Ed	50	129.86	18.659	1.9028	0.515	सार्थक अंतर नहीं है।
STC	50	128.88	19.387			

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि B.Ed के प्राप्तांको का मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 129.86 तथा 18.659 और STC के प्ररीक्षणार्थियों के प्राप्तांको का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन क्रमशः 128.88 तथा 19.389 प्राप्त हुआ। टी प्रशिक्षण सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत दोनों वर्गों के प्राप्तांको से ज्ञात प्रमाणिक त्रुटि का मन 1.9028 प्राप्त हुआ तथा टी-मान 0.515 प्राप्त हुआ स्वतंत्रता के अंश 98 पर उपरोक्त टी का मान 0.05 स्तर पर दिए गए सरणी मान से कम है। अतः परिकल्पना 0.05 स्तर पर स्वीकृत सिद्ध होती है।

निष्कर्ष - अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि B.Ed एवं STC के प्ररीक्षणार्थियों की सर्जनात्मकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

#### परिकल्पना- 3

B.Ed एवं STC के प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं

सृजनात्मकता में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

सारणी (गणना)

Hy=2	N	Mean	S.D.	(dx)(dy)		निष्कर्ष
उपलब्धि अभिप्रेरणा	100	60.67	7.25	29697.71	0.540	सामान्य धनात्मक प्रभाव पड़ता है।
सृजनात्मकता	100	129.37	19.01			

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि न्यादर्श में चयनित समस्त प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्राप्तांको का मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 60.67 तथा 7.25 और सृजनात्मकता का मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 109.37 तथा 19.01 प्राप्त हुआ। जबकि इसके प्राप्तांको के विचलनों की गुणनफल का योग 2967.71 प्राप्त हुआ तथा सहसंबंध सांख्यिकी विधि द्वारा इनके मध्य सहसंबंध का मन 0.540 है। जो की धनात्मक सहसम्बन्ध है अर्थात् सृजनात्मकता में वृद्धि होने पर उपलब्धि अभिप्रेरणा में सामान्य वृद्धि होती है।

**निष्कर्ष** - अतः या निष्कर्ष निकलता है की उपलब्धि अभिप्रेरणा व प्ररीक्षणार्थियों की सृजनात्मकता का सामान्य प्रभाव पड़ता है।

**परिणाम** - प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से निष्कर्ष निकलता है की सृजनात्मकता का बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर सामान्य धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः जिसमें शब्द निर्माण योग्यता, कहानी लेखन समस्या समाधान योग्यता विभिन्नता एवं समानता को परखने की योग्यता, वाक्य व शीर्षक निर्माण की योग्यता आदि पाई जाती है वह बालक सृजनशील होते हैं। और इन गुणों से उन्हें परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने को करने में सहायता मिलती है।

सभी विद्यार्थियों में अलग-अलग गुण होते हैं सामान्यतः देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर एवं अध्ययन रुचि अधिक होती है, उनकी अकादमिक उपलब्धि भी उच्च होती है। परंतु यह पूर्णतया अनिवार्य नहीं है कि जिन प्ररीक्षणार्थियों में सृजनात्मकता स्तर उच्च थे उनकी अध्ययन रुचि का स्तर व स्मरण शक्ति उच्च हो तथा यह भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है जिन प्ररीक्षणार्थियों में उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च हो उनके सृजनात्मकता स्तर में भी भिन्नता होती है।

अतः निष्कर्ष रूप में समस्त प्ररीक्षणार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा व सृजनात्मकता में सामान्य सहसम्बन्ध है।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Ai Xiao Xia(08 June 2010)"Creativity And Academic Achievement: An Investigation Of Gender Differences".
2. Abdullah N., Aizan H.T., Sherir J., Kumar Vijay, Malaysia (2009),"Relationship Between Creativity And Academic Achievement: A Study Of Gender Differences".
3. Anwar M.N., Anees M., Asma Khizar, Md. Gulam M.N. Pakistan, 2012,"Relationship Of Creativity Thinking With The Academic Achievement Of Senior Secondary Students".
4. Boloandifar S. Nooreen Noordin, 2013, Malaysia, "Investigation the Relationship Between Creativity And

- Academic Achievement”, Vol 65.
5. Eladi S., Batdi V., 2015, Turkey, “The Effect Of Different Application On Creativity Regarding Academy Achievement A Meta Analysis”.
  6. Gajda, 2016 “Effect Of Creativity and Academic Achievement (A Meta Analysis)”.
  7. Kotreshwaraswami A., 2014, Malaysia, “A Study Of Relationship Between Creativity And Academic Achievement Of Secondary School Puplis.
  8. Meera K.P., Remya P. 2015, “Effect of Extensive Reading and Creativity On Academic Achievement In English Language”.
  9. Naderi H. Abdullah R. Aizan H.T., V. Kumar, Malaysia, 2009, “The Relationship Between Creativity And Academic Achievement”.
  10. Taylor & Francis, Joseph C. Bentley, Feb. 1966, “The Journal Of Education Research Creativity And Academic Achievement”.

\*\*\*\*\*

## मध्य प्रदेश में कृषि विकास की आधारभूत संरचना (फसल में नियोजन का अध्ययन)

डॉ. भावना भटनागर\*

\* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पी.एम.सी.ओ.ई., शासकीय स्नानतकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि न केवल राज्य के लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि यह रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। इस कारण से कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि विकास के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से ही विश्व के विकसित राष्ट्र आज आर्थिक विकास के शिखर पर पहुँच चुके हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों के विकास में कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया।

मध्य प्रदेश में कृषि का इतिहास कोई नया इतिहास नहीं है बल्कि यह एक प्राचीन व्यवसाय है। भारतीय समाज में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कृषि विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉ. बी.सी. सिंह ने कहा कि 'सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के विकसित होने से दूसरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा आती है तो वह विकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा।' इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कृषि का प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि कोई भी राष्ट्र खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योगों को कृषि से ही कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है जैसे कि सूती वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफी, जूट, लकड़ी, वनस्पति घी, तेल आदि उद्योग कच्चे माल के लिए मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर होते हैं। साथ ही अन्य लघु उद्योगों को भी कृषि द्वारा ही कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है।

कृषि विकास के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। कृषि विकास का उद्देश्य है कि कृषि आधारित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, अधिक आय, अधिक रोजगार और किसानों के लिए बेहतर जीवन स्तर। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कृषि विकास ही आर्थिक विकास की कुंजी है और यदि राष्ट्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है तो स्वाभाविक है कि उस देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा और उसकी समस्त विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी।

**शब्द कुंजी** - कृषि, मध्य प्रदेश, अर्थव्यवस्था, रोजगार, विकास।

**फसल नियोजन**- म.प्र. एक बड़ा राज्य है। जहाँ किसान ऋणग्रस्त एवं दरिद्र है जिनके पास बहुत छोटे-छोटे कृषि भू-खण्ड है। अतः आर्थिक प्रेरणाओं के फलस्वरूप इनके फसली ढाँचे को परिवर्तित किया जाता है लेकिन अध्ययन के पश्चात् यह बात स्पष्ट होती है कि अभी भी सीमांत कृषक व्यवस्थित रूप से कृषि कार्य करने में असमर्थ है क्योंकि इसके पीछे मूल कारण प्रथम तो भू-खण्ड का आकार छोटा होना है द्वितीय किसान के पास तकनीकी ज्ञान का पर्याप्त अभाव है। इसकी वजह से कृषक व्यवस्थित रूप में कृषि कार्य संपन्न नहीं कर पाते।

वर्तमान युग में फसल नियोजन आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। तथा स्वस्थ एवं कुशल कृषि व्यवस्था की दृष्टि से यह आवश्यक भी है क्योंकि नियोजन के अभाव में देश के आर्थिक संसाधनों का न तो कुशलतम उपयोग हो पाता है और न ही उत्पादकता में वृद्धि होती है। अतः फसल नियोजन राज्य की कुशल कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सामान्यता

फसल नियोजन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में कुछ आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। जिनसे प्रथम तो भूमि का सही उपयोग होता है और दूसरे कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है जिससे कृषकों को आय में वृद्धि होती है। सामान्यता इसके विभिन्न रूप हैं जो निम्न प्रकार हैं

**(1) फसलों के परिवर्तन का स्वरूप:-** फसल नियोजन के अन्तर्गत सबसे प्रथम यह कार्य किया जाता है कि प्रतिवर्ष भूमि के टुकड़े पर फसलों का परिवर्तन किया जाए जिससे मिट्टी की उर्वरता दीर्घकाल तक बनी रहती है और भूमि को पड़ती रूप में छोड़ने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, साथ ही फसलों के परिवर्तन से नवीन फसल के पौधों में रोग और महामारियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है।

अतः फसल नियोजन की दृष्टि से प्रतिवर्ष नहीं तो कम से कम तीन वर्ष में फसलों में परिवर्तन करना आवश्यक है।

**(2) मिश्रित फसल पद्धति का अपनाना:-** फसल नियोजन के अन्तर्गत दूसरा कदम यह उठाया जाता है कि कृषि भूमि पर एक ही वक्त में एक ही खेत

में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं यह पद्धति तब अधिक उपयोगी होती है जबकि एक फसल तो अधिक गहरी जड़ों वाली हो और उसके पौधे एक दूसरे से काफी दूरी पर लगाए जाएं तथा दूसरी फसल छोटे पौधों वाली हो जिन्हें कि पहली फसल के दो पौधों के बीच लगाया जाए। इस प्रकार एक ही खेत में एक ही समय में दो फसलों का एक साथ बोना मिश्रित फसल पद्धति कहलाती है। इसका लाभ यह होता है कि प्रथम तो यह दोनों फसले अच्छा उत्पादन देगी और यदि किसी कारणवश एक फसल नष्ट होती है तो दूसरी फसल कम से कम किसान की लागत निकालने में मदद करेगी।

**(3) फसलों का वितरण:-** फसल नियोजन के अन्तर्गत तीसरा कदम यह उठाया जाता है कि किसान के पास उपलब्ध भूमि में प्रथम तो कौन सी फसलें कौन से क्षेत्र में उगाई जाएं तथा कितने क्षेत्र में वास्तव में फसल बोई जाए। यही स्थिति जब प्रदेश स्तर पर लगा की जाती है। तो इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाए तथा उस क्षेत्र में कितनी कृषि भूमि पर यह फसल बोई जाए। इसका एक लाभ यह होता है कि उस क्षेत्र में फसल से संबंधित मिट्टी परीक्षण कर फसल को बोया जाता है। जिससे उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और कृषक को विशिष्टीकरण के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती है।

**फसल नियोजन की आवश्यकता:-** म.प्र. एक कृषि प्रधान राज्य है तथा कृषि म.प्र. के निवासियों के जीवन का मूल आधार भी है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में फसल नियोजन को प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाए। फसल नियोजन के अपनाने से प्रदेश की कृषि एवं अर्थव्यवस्था दोनों को ही पर्याप्त लाभ प्राप्त होंगे। म.प्र. में फसल नियोजन के लिए व्यापक संभावनाएँ हैं। लेकिन पिछड़ेपन के कारण इसको अपनाने के अवसर बहुत कम दृष्टिगोचर होते हैं। जबकि फसल नियोजन आर्थिक समृद्धि को दृष्टि से आवश्यक है। अतः म.प्र. में इसको अपनाने की अत्यन्त आवश्यकता है और इसको अपनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं वे निम्न प्रकार हैं।

**(1) गहन एवं सूक्ष्म अनुसंधान:-** फसल नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है अतः इसको अपनाने के लिए बहुत गहन अनुसंधान करना आवश्यक है और इसके लिए वैज्ञानिकों को विशेष कार्य करने होंगे। जिसमें सर्वप्रथम इस बात को प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा कि राज्य के किन क्षेत्रों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। इस दृष्टि से कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान के माध्यमों से फसलों के क्रम में परिवर्तन करना होगा। द्वितीय फसल नियोजन के लिए यह भी आवश्यक है। कि कृषि वैज्ञानिकों को विभिन्न फसलों की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जो कि जलवायु की विषमताओं को सहन कर ले और अधिक उत्पादन भी दे सके। तृतीय कृषि वैज्ञानिकों को प्रदेश स्तर पर ऐसी फसलों का विकास करना होगा जो कि प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न मिट्टियों के अनुकूल हो क्योंकि प्रदेश में आज भी ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो मिट्टी के अनुकूल नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप न तो भूमि का सही उपयोग होता है और नही उचित मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। जिससे प्रदेश की कृषि व्यवस्था आज भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। साथ प्रदेश में अभी भी फसलों की पोषण आवश्यकताओं की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। जिसके कारण फसलें विभिन्न बीमारियों का शिकार होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि फसलों की पोषण आवश्यकताओं का ठीक-ठीक पता लगाया जाए और विभिन्न फसलों के रोगों, महामारियों का पता लगाया जाए तथा मिट्टी द्वारा छोड़े गये नाइट्रोजन

तत्वों का फसलों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है इसकी भी जानकारी प्राप्त की जाए। यह कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय है जो फसल नियोजन के लिए आवश्यक है। और यह सब जानकारीयों गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन द्वारा ही संभव है।

**(2) फसलीय ढाँचे का अध्ययन:-** म.प्र. में फसल नियोजन जैसी कोई नीति अभी तक प्राथमिकता क्रम पर लागू नहीं हैं जिसके कारण खाद्य एवं व्यापारिक फसलों के बीच कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अतः सरकार को कृषि वैज्ञानिकों के माध्यमों से यह अनुसंधान करना होगा कि प्रदेश में व्यापारिक एवं खाद्य फसलों के मध्य वितरण की व्यवस्था क्या है तथा कृषकों की कीमतों तथा लगान प्रेरणाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, और यह फसल नियोजन के लिए आवश्यक भी है।

**(3) कृषकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना:-** म.प्र. में कृषि एवं कृषकों के पिछड़ेपन का मूल कारण कृषि के प्रति अप्रशिक्षित होना है। इस दृष्टि से वे फसल नियोजन के प्रति अनभिज्ञ हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कृषकों को कृषि अनुसंधान के परिणामों की सूचना प्रभावशाली ढंग से दी जा सके तथा उन्हें नई कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इससे किसानों में एक नवीन जागरूकता उभर कर आयेगी और वे फसल नियोजन के प्रति पूर्ण रूप से प्रेरित होंगे।

**(4) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:-** फसल नियोजन की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कृषक नवीन कृषि तकनीक को अपनाए। ऐसी स्थिति में कृषकों को नवीन तकनीक अपनाने पर कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश का बोझ उठाना पड़ेगा। अतः उन्हें इस बोझ को उठाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करानी होगी, इसके लिए सरकार प्रयोग की दृष्टि से फार्म प्रदर्शन करने होंगे साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रचलित नवीन तकनीकों के प्रभाव का क्रियात्मक प्रदर्शन करना भी आवश्यक है जिससे कृषकों को उचित एवं प्रभावी मार्गदर्शन दिया जा सके। परिणामस्वरूप किसान वित्तीय सहायता व नवीन तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

**(5) प्रेरणास्पद योजनाएँ लागू करना:-** फसल नियोजन के यह आवश्यक है कि विभिन्न फसलों के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाये और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को प्रेरणादायक योजनाएँ लागू करना होगी। ऐसी दशा में सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उचित किस्म के बीजों एवं रासायनिक खादों को सस्ती दर पर कृषकों को उपलब्ध कराए तथा जो किसान इन योजनाओं के अनुरूप उत्पादन करके अधिक फसल देते हैं। उन्हें राज्य स्तर पर सरकार पुरस्कृत करें।

ऐसी दशा में कृषकों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और वे सरकारी योजनाओं के प्रति विशेष रूप से जागरूक होंगे। जिससे फसल नियोजन को अपनाने में सफलता प्राप्त होगी।

उक्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि म.प्र. में फसल नियोजन की मूलभूत आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब सरकार और किसान मिलकर इस दिशा में प्रयास करें कृषक इस कार्यक्रम में जागरूक हों और नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो तथा सरकार किसानों को फसल नियोजन के प्रति प्रेरित करने के लिए बीज, खाद, पानी आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराए तथा फसलों के उत्पादन में करों की छूट तथा वित्तीय

सहायता उपलब्ध कराए तभी उत्पादन वृद्धि संभव है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची:-**

1. म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन डॉ. प्रमिला कुमार, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
2. कृषि अर्थशास्त्र डॉ. जय प्रकाश मिश्र, साहित्य भव पब्लिकेशन, आगरा
3. भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र डॉ. एन.एल. अग्रवाल, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
4. कृषि विकास की समस्याएं श्री कृष्ण कुमार उमाहिया, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. भारतीय अर्थशास्त्र डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, डॉ. एस.सी. जैन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
6. भारतीय अर्थ व्यवस्था श्री मिश्र पुरी हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई
7. कृषि अभियंत्रण प्रो. श्री रंधावा चौहान, रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
8. कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रो. श्री के.एन. सहाय, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
9. कृषि अर्थशास्त्र श्री एस.सी. मित्तल, ऑरिएण्टल पब्लिशिंग हाउस, आगरा
10. सांख्यिकी के मूल तत्व डॉ. श्री के.एन. नागर, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
11. सांख्यिकी डॉ. श्री बी.एन. गुप्ता, साहित्य भवन, आगरा
12. अर्थशास्त्र डॉ. श्री वी.सी. सिन्हा, साहित्य भवन पब्लिशर्स, आगरा
13. कृषक जगत डॉ. साधन गंगराडे, कृषक जगत भवन, इन्दिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल
14. रिसर्च मैथडोलॉजी डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, डॉ. डी.पी. शुक्ला, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
15. रिसर्च मैथडोलॉजी डा. बी.एम. जैन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
16. अनुसंधान प्रतिधियाँ श्री सी.एम. चौधरी, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर
17. समाजिक अनुसंधान राम गोपाल सिंह भारती, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल 179
18. अनुसंधान परिचय पारसनाथ राय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
19. प्रारंभिक कृषि अभियांत्रिकी डॉ. हरेन्द्र सिंह चौहान, प्रकाशन निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पन्त, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, नैनीताल
20. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला दतिया
21. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, जिला दतिया-2002
22. वही 2006
23. वही 2007
24. वही 2009
25. रिसर्च लिंक डॉ. रमेश सोनी, डॉ. सत्यम सोनी, वर्धमान अपार्टमेंट ओल्ड पलासिया, इन्दौर
26. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका) ललिता खुराना ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली 2002-2010
27. योजना (मासिक पत्रिका) 538 योजना भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली
28. मध्य प्रदेश कृषि सांख्यिकी कृषि सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल 2002 - 2010
29. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल
30. म.प्र. की आधारभूत कृषि सांख्यिकी 2002 - 2010
31. समाचार पत्र
  1. दैनिक भास्कर, ग्वालियर
  2. दैनिक नई दुनिया, ग्वालियर
  3. दैनिक जागरण, ग्वालियर
  4. दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स
  5. दैनिक अमर उजाला
32. उन्नत कृषि यंत्रों पर दी जानेवाली सुविधाएं कृषि अभियांत्रिकी, संचालनालय, म.प्र. भोपाल
33. कृषि यंत्रों का रखरखाव श्री भीमसिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
34. Agricultural Economics Pranav K. Desai, Boitech Books, Delhi 180

\*\*\*\*\*



## ‘संचार के आधुनिक साधन मोबाईल’ का युवाओं के सामाजीकरण पर प्रभाव का अध्ययन कसरावद शहर के महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विशेष सन्दर्भ में

**डॉ. उषा यादव\***

\* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - वर्तमान समय में मोबाईल फोन दुनिया में पहले की संचार तकनीकों जैसे- टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों आदि की तुलना में तेजी से फैल रहे हैं। युवा वर्ग के बीच इस डिवाइस का उपयोग और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। और इसके इस्तेमाल पहुँच, सुक्ष्म समन्वय, सुरक्षा और मुक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मोबाईल फोन युवाओं और उनके साथियों के समूहों, माता-पिता और बच्चों के बीच एक सीधा संचार चैनल प्रदान करते हैं। इसलिए यह डिवाइस साथियों और परिवार के साथ-साथ सामाजिक सम्पर्क व बंधन को भी बढाता है। मोबाईल नये-नये फंक्शन के साथ युवाओं को सीखने के लिए प्रेरित कर समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। युवाओं के समाजीकरण पर मोबाईल फोन के प्रभाव अध्ययन करने के लिए शासकीय महाविद्यालय कसरावद के अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का द्वैव निदर्शन पद्धति से चुनाव कर शोध सम्बन्धी आकड़े एकत्रित कर उनके विश्लेषण के परिणाम युवाओं के समाजीकरण पर मोबाईल फोन पर प्रभाव को उजागर करते हैं।

**शब्द कुंजी** -सामाजीकरण, युवा, संचार के आधुनिक साधन मोबाईल फोन इत्यादि।

**प्रस्तावना** - मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है। वह केवल एक प्राणीशास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के न तो गुण होते और नहीं अवगुण होते हैं। वह न तो सामाजिक होता है, न असामाजिक और न समाज विरोधी ही। समाज के रीति - रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएँ रखता है, किन्तु वह कुछ विशिष्ट शारिरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है, इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है, लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक सम्पर्क से ही विकसित होती है उदाहरणार्थ, मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है जो समाज के सम्पर्क से ही व्यावहारिक रूप धारण करती है। सामाजिक सम्पर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति - रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं।

इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणीशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है, मानव को पशु स्तर से उंचा उठाकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अतः यह मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है।

वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग माना जा रहा है। जिसमें सूचनाओं को बड़े ही प्रभाव पूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा रहा

है। इस सूचना क्रांति ने मानव के पुराने सूचना स्रोतों को समाप्त ही कर दिया जो किसी समय में सूचना पहुँचाने के मुख्य कारगर साधन के रूप में उपयोग में लाए जाते थे उनकी जगह अब आधुनिक साधनों जैसे इन्टरनेट, टीवी, समाचार पत्र- पत्रिकाएँ, और इन सभी से अत्यधिक प्रभावशील एवं उपयोग में सर्वाधिक आसान मोबाईल फोन ने ले ली है। जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचनाएँ, विचार, भावनाएँ, कार्यों को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, कार्य क्षेत्र पर कार्यरत व्यक्तियों आदि को बहुत ही आसानी से कही से भी सूचनाएँ पहुँचाते हैं। जिस कारण मोबाईल फोन आज सर्वाधिक उपयोग और उपभोग किया जाने वाला आधुनिक साधन बन गया है। जो मानव जीवन को प्रभावित कर मानव की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है। विशेष रूप से युवाओं के समाजीकरण के बारे में यह एक सक्रिय और सामूहिक प्रक्रिया है। जहाँ माता- पिता, साथी, शैक्षणिक संस्थान और मीडिया इस प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक युवा, वयस्क दुनिया में सम्मिलित होने के लिए किसी समाज के मूल्यों मानदण्डों और विश्वासों को कैसे आत्मसात करते हैं। किशोरों की मुक्ति पारिवारिक दायरे से स्वतंत्र होने और अपने स्वयं के विश्वासों और मूल्यों के साथ स्वतंत्र सामाजिक अभिनेताओं के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया है।

हालांकि पिछले कुछ दशकों में मोबाईल फोन पर अध्ययन तेजी के लोकप्रिय हुए हैं परन्तु युवाओं के समाजीकरण पर मोबाईल के प्रभावों का अध्ययन अनुसंधान का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है।

**समाजीकरण**- समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसके माध्यम से हम किसी समाज या सामाजिक

समूह के तौर -तरीको को सीखते हैं। ताकि हम उस समाज के क्रियाशील सदस्य बनकर कार्य कर सकें।

**युवा**-युवास्था या किशोर अवस्था का अंग्रेजी शब्द Adolescence से लिया गया है जो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। जिसको अर्थ है 'बड़ा होना' या 'परिपक्व होना' या 'वयस्कता में बढ़ना' इस अवस्था को मानव विकास में एक संक्रमण कालीन चरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ जैविक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और समाजिक विशेषताएं आमतौर पर बच्चे जैसी मानी जाने वाली विशेषताओं से बदलकर वयस्क जैसी मान जाने वाली विशेषताओं में बदल जाती हैं।

मानव का सामाजीकरण उसके आसपास व्याप्त पारिवारिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जिससे उसका जीवनयापन सम्भव हो, पर निर्भर करता है।

मोबाईल फोन एक ऐसा ही आधुनिक साधन है जिससे मानव का न केवल दिन बल्की हर पल प्रभावित होता है। और मानव प्रजाति में सर्वाधिक युवा पीढ़ी इस संचार क्रांति के आधुनिक साधन मोबाईल से प्रभावित हो रही है। जिनका एक पल भी बिना मोबाईल फोन के नहीं गुजरता और ना ही कोई कार्य कर पाते हैं। जिस पर केवल उनका वर्तमान बल्कि भविष्य भी निर्भर करता है। इतिहास साक्षी है जब भी किसी साधन या वस्तु चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित ने अत्यधिक प्रभावित किया जाता है तो वह उसके सामाजीकरण या समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यही तथ्य वर्तमान समय में मोबाईल पर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है अगर उसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है और उसने मानव को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया है।

**संचार के आधुनिक साधन** - अपने विचारों, बातों, इच्छाओं, भावनाओं को समाज में, समूहों में परिवार में, या व्यक्तियों को प्रभावी व नवीन तरीको से पहुंचाने के साधनों को हम संचार के आधुनिक साधन कहते हैं।

**मोबाईल**-मोबाईल को 'हिन्दी में दूरसंचार यंत्र कहते हैं।' अर्थात दो संदेश वाहको या संदेश वाहक और संदेश लेने वाले के मध्य दुरी कितनी भी हो, एक दुसरे को संदेश बहुत ही सरल-सहज रूप से पहुंच जाता है।

**अध्ययनरत विद्यार्थी**-अध्ययनरत विद्यार्थी युवाओं का वह वर्ग है जो अपने जीवन को दिशा देने के लिये अपने सामाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका को मजबूत करने के लिए किसी भी शासकीय या अशासकीय शिक्षण संस्थान से ज्ञानार्जन कर रहे हैं।

**3. अध्ययन पद्धति :-** प्रस्तुत शोध-पत्र में शोध अध्ययन पद्धति निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

1. **अध्ययन पद्धति :-**स्वउद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति शोध-पत्र की अध्ययन पद्धति है।

2. **अध्ययन का समग्र :-**अध्ययन का समग्र शासकीय महाविद्यालय कसरावद में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समग्र निर्धारित किया गया है।

3. **अध्ययन की इकाई :-** शासकीय महाविद्यालय कसरावद में अध्ययनरत विद्यार्थी अध्ययन की इकाई है।

4. **तथ्यों का संकलन :-** तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक पद्धतियों के माध्यम से किया गया है।

**अ. प्राथमिक स्रोत :-**साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है।

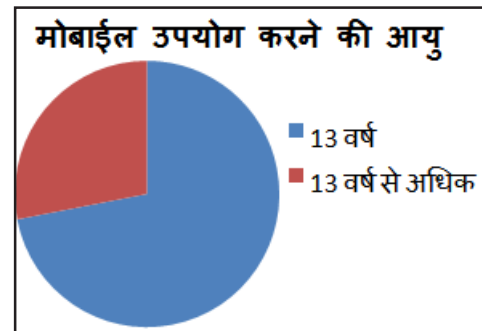
**ब. द्वितीयक स्रोत :-**पूस्तके पत्र-पत्रिकाएँ व इन्टरनेट के माध्यम से

द्वितीय तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

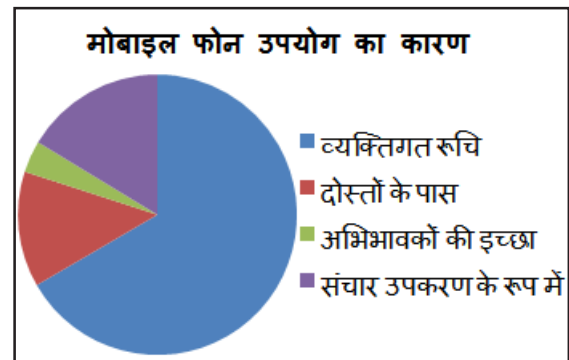
**5. शोध प्रक्रिया :-** शोध-पत्र को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया, इसके पश्चात एक साक्षात्कार अनुसूचि का निर्माण कर 50 अध्ययनरत विद्यार्थियों से साक्षात्कार अनुसूचि के विकल्पयुक्त प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया गया है। जिसके बाद प्राप्त तथ्यों को मास्टर-चार्ट के माध्यम से सांख्यिकीय रूप प्रदान कर कुछ मुख्य प्रश्नों का चित्रमयी प्रदर्शन किया गया है।

**निष्कर्ष :-**प्रस्तुत शोध-पत्र में विकल्पयुक्त प्रश्नों के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं

1. प्रस्तुत शोध विषय के अनुसार प्रश्न पूछा गया कि आप मोबाईल का प्रयोग किस आयु से कर रहे हैं पर सर्वाधिक 95.6% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे 13 वर्ष की उम्र से मोबाईल का प्रयोग कर रहे हैं।

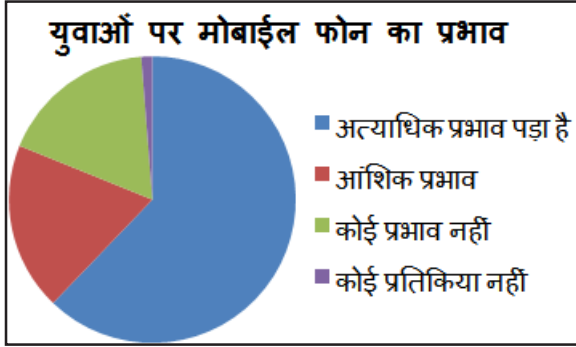


2. प्रस्तुत शोध विषय के प्रश्न मोबाईल उपयोग का कारण पूछने पर सर्वाधिक 66.6% ने कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण मोबाईल रखते हैं, 13.4% कहा कि उनके दोस्तों के पास मोबाईल है इसलिए उन्होंने भी मोबाईल लिया है। 3.7% ने कहा कि उन्होंने अपने अभिभावकों की इच्छा से मोबाईल लिया है। और 16.3% ने उत्तर दिया कि वे मोबाईल का प्रयोग केवल संचार उपकरण के रूप में करते हैं।

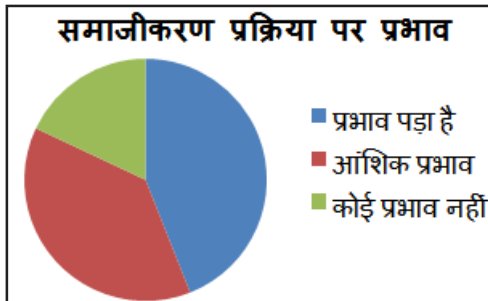


3. प्रस्तुत शोध विषय के अनुसार प्रश्न पूछा गया कि क्या युवाओं पर मोबाईल फोन का प्रभाव है पर सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कहा गया कि युवाओं पर मोबाईल फोन का प्रभाव अत्यधिक रूप से है, क्योंकि वर्तमान समय में युवावर्ग के पास यदि मोबाईल फोन न हो तो वह अपने आप को अधुरा व असहाय महसूस करते हैं। साथ ही वे अपना सर्वाधिक समय मोबाईल पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि 13 प्रतिशत का कहना है कि मोबाईल फोन का युवाओं पर आंशिक रूप से प्रभाव है। क्योंकि आज का युवा अपने भविष्य की चिन्ता में इस प्रकार लगा रहता है कि वह नये आधुनिक साधनों को भी भूल जाता है।

और अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता है। 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं मानना है कि युवा वर्ग पर वर्तमान समय में मोबाईल फोन का प्रभाव बिलकुल नहीं हुआ है क्योंकि उनके अनुसार युवा वर्ग के पास मोबाईल फोन से भी ज्यादा आधुनिक साधन उपलब्ध है जिसके माध्यम से वे मोबाईल का भी कार्य कर लेते हैं, या उन्हें आवश्यकता ही नहीं पडती। सबसे कम 10 उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।

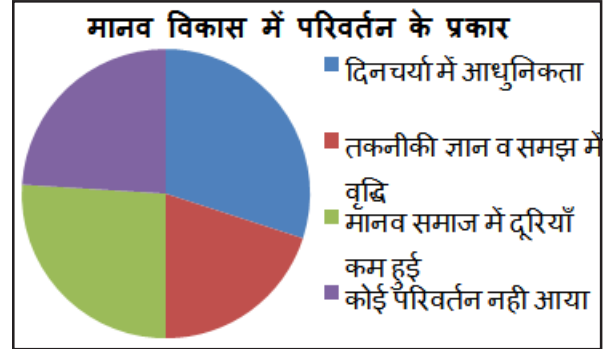


4. प्रश्न पूछा गया कि क्या मोबाईल फोन के द्वारा सामाजीकरण कि प्रक्रिया पर प्रभाव पडता है। पर सर्वाधिक 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमती जताई है, उत्तरदाताओं का कहना है, कि वर्तमान में युवाओं का सामाजीकरण मोबाईल फोन के माध्यम से निर्धारित हो रहा है। आज मोबाईल फोन केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का ही साधन मात्र नहीं रह गए है, बल्कि मोबाईल के माध्यम से आज व्यक्ति मनोरंजन के साथ ज्ञान अर्जन भी कर रहे है। जिससे उनके कार्य आसान होते जा रहे है। 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक रूप से सहमति जताई है क्योंकि उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में मोबाईल का युवाओं के जीवन में महत्व बढा है पर उनके सामाजिक पहलु विषय पर व्यापक रूप से प्रभाव नहीं पडता। शेष 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि मोबाईल फोन से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव समाजीकरण पर नहीं पडता क्योंकि उत्तरदाता मानते है कि मोबाईल फोन केवल संचार के साधन से अधिक कुछ नहीं है, जिसका उपयोग केवल आवश्यकता पडने पर ही किया जाता है।



5. मोबाईल फोन के माध्यम से मानव विकास में किस प्रकार के परिवर्तन आए है, पर सर्वाधिक 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मोबाईल फोन के आने से मानव की दिनचर्या में आधुनिकता का प्रभाव बढा है साथ ही बाहरी दुनिया से लगातार जुडा रहता है, जिससे उसे प्रत्येक घटना की जानकारी बडी तेजी से व सटीक प्राप्त हो जाती है। जबकि 20 प्रतिशत

उत्तरदाताओं का कहना है कि मोबाईल फोन के द्वारा व्यक्ति में तकनीकी ज्ञान व उसकी समझ का विकास हुआ है जिससे वह आज अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग बडी आसानी से कर सकता है, जो उसके बौद्धिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। 26 प्रतिशत का कहना है, कि मोबाईल के माध्यम से मानव समाज में दुरिया कम हुई है जिससे वे अपने परिजनो के हरदम नजदीक रहते है, और हर समय उनकी खबर भी प्राप्त हो जाती है। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार व्यक्ति के विकास को मोबाईल फोन ने किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया है।



**सुझाव :** वर्तमान सर्वेक्षण और अध्ययन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार है :

1. मोबाईल का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वह उपयोगकर्ता के बीच सराहनीय और उचित साबित हो।
2. जब युवा मोबाईल फोन से जुडते है या उनका उपयोग करते है तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग साइट का ही उपयोग करें।
3. मोबाईल का प्रयोग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
4. मोबाईल के अधिक प्रयोग के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए शिक्षण संस्थानों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।
5. अभिभावकों और शिक्षकों को युवाओं पर नजर रखनी चाहिए कि वह मोबाईल का उपयोग किस प्रकार की गतिविधि के कर रहे है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी - रविन्द्र नाथ मुखर्जी।
2. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी - डी.एन. श्रीवास्तव।
3. समाजशास्त्र के मूल तत्व - गुप्ता एण्ड शर्मा।
4. सामाजिक विचारक - रविन्द्र नाथ मुखर्जी।
5. सामाजिक विचारक का इतिहास - रामनाथ शर्मा।
6. Arnett, J.(1995) Adolescent's uses of Media For Sely-socialization, journal of Youth and Adulcescence,
7. Chen, Y.F. (2009 may ) The Mobile Phone and Socialization: Family vs Friends.
8. Kalogeraki Stefania, Papadaki Morina. The Impact of Mobile Phones on Teengers Socialization and Emancipaton .University of Crete Greece.

# The Role of Incubation Centers in Nurturing Startups: Fostering Innovation, Growth, and Sustainability

Anchal Ramtane\*

\*Asst. Professor (Zoology) Rajabhoj Govt. Degree College, Mandideep, Distt. Raisen (M.P.) INDIA

**Abstract :** This paper examines the pivotal role of incubation centers in nurturing startups, innovation, growth, and sustainability. Incubation centers provide early-stage startups with crucial resources such as office space, mentorship, funding access, and networking opportunities, which help reduce the risks and challenges associated with entrepreneurship.

The paper traces the evolution of incubation centers, from their early days supporting small-scale manufacturing businesses and ideas to their modern role across diverse industries like technology with a focus on India's growing startup ecosystem,

The paper explores various types of incubators, such as private, public, university-based, sector-specific, and virtual, highlighting the range of services they offer, including mentorship, technical infrastructure, business development support, and market entry strategies.

The paper concludes that while India's startup ecosystem is rapidly growing, further expansion of incubation support and infrastructure is necessary to sustain this momentum and drive long-term success.

**Keywords:** Incubation Centers, Startups, Innovation, Growth, Sustainability, Mentorship, Funding, India.

## Introduction

**1. Definition and Overview** -an organization or facility that provides support to early-stage startups and entrepreneurs to help them develop and grow their businesses. It offers a range of services, including office space, mentor ship, access to funding, networking opportunities, and business development resources. The goal of an incubation center is to nurture startups by reducing the risks and challenges they face during their initial stages, thereby increasing their chances of success and long-term sustainability.

inculcation centers have evolved over the years from supporting small-scale, manufacturing businesses to providing a wider range of services across diverse industries, including technology, healthcare, social enterprises, and more. They vary in structure, with some being privately funded by venture capitalists or corporations, while others are public or university-based, often focusing on economic development or academic research.

**2. History and Evolution of Incubation Centers-** The concept of business incubation dates back to the early 1950s when the first incubators were created to assist small manufacturing businesses in overcoming financial and operational difficulties. However, it was in the 1980s and 1990s that incubators gained significant momentum, particularly in technology-based industries, as the global

economy shifted towards innovation and entrepreneurship. Incubation centers today have expanded beyond their original manufacturing-focused roles to support a diverse range of industries, from information technology to social enterprises. This evolution reflects a growing recognition that innovation is vital for economic development and that nurturing entrepreneurial talent is essential to driving this innovation.

**Objective-** To Study The Role of Incubation Centers in Nurturing Startups Fostering Innovation, Growth, and Sustainability.

**Aims-** It aims to highlight how these incubation centers act as catalysts for innovation, growth, and sustainability by providing:

**1. Resources:** Offering shared office spaces, infrastructure, and access to advanced technology at reduced costs.

**2. Mentorship:** Guiding startups with expertise in business strategy, market research, and operational challenges.

**3. Networking Opportunities:** Connecting entrepreneurs with investors, industry leaders, and peer networks.

**4. Funding Access:** Helping startups secure seed funding, grants, or venture capital through partnerships.

**5. Skill Development:** Providing workshops, training programs, and seminars to enhance entrepreneurial skills.

**6. Market Entry Strategies:** Assisting in refining product ideas and scaling them to meet market demands.

**7. Sustainability Goals:** Encouraging green practices and innovation that align with long-term environmental and social sustainability.

**Study Material-** For this paper Magazine, newspaper, Govt of India report on STARTUP are used as a secondary data source .

**Data Source-** This topic underscores the importance of incubation centers as hubs of support, fostering a conducive environment for startups to thrive and contribute to economic growth and technological advancement.

**Startup India In Numbers (Jan 2016-Dec 2020)**

1. 41,317 startups recognized by DPIIT
2. 4.7 Lac jobs reported by 39,000+ startups
3. Rs 4,509 Crore of investments made in 384 startups through the Fund of Funds scheme
4. 590+ districts with at least one recognized startup
5. 44% of the recognized startups have at least one woman director
6. 30 States and UTs have a dedicated startup policy

**( Data Published by the DPIIT Govt of India “Evolution of Start UP in India” Capturing the 5-Year story )**

**Types of Incubators:** Incubators vary in their structures, services, and target markets. Understanding the different types of incubators is crucial for identifying how each caters to specific needs within the startup ecosystem:

**1. Private Incubators:** These are typically profit-driven entities supported by venture capitalists, angel investors, or private firms. Their primary focus is on high-growth, scale startups, often in technology or innovative sectors. They provide resources such as seed funding, business mentoring, and market access in exchange for equity or a stake in the startup.

**2. Public Incubators:** Sponsored by government agencies or non-profit organizations, public incubators are often part of national or regional economic development programs. They tend to focus on job creation, local economic growth, and supporting social enterprises. Public incubators may offer more affordable or subsidized services compared to private incubators and are typically less equity-driven.

**3. University-Based Incubators:** These incubators are run by universities or academic institutions and are focused on fostering innovation emerging from academic research or student ventures. They are often aligned with the institution’s research and development goals, helping startups leverage intellectual property, research collaborations, and academic networks.

**4. Sector-Specific Incubators:** Some incubators cater to startups within a specific industry or sector, such as biotechnology, clean energy, or fintech. These incubators provide specialized resources and mentorship that are specific to the industry, allowing startups to connect with key players and experts in their fields.

**5. Virtual Incubators:** With the rise of digital technologies, virtual incubators have emerged as a flexible alternative to traditional incubators. They offer online resources, mentorship, and networking opportunities to startups located anywhere in the world, providing a more accessible option for entrepreneurs who may not be able to attend a physical incubator.

**Key Services and Offerings:** Incubators provide a variety of services and resources that help early-stage startups address critical challenges. These offerings can be broadly categorized into tangible resources and intangible support:

**Tangible Resources**

**1. Office Space:** Many incubators provide affordable office space, which is often equipped with essential office furniture, internet access, and conference rooms. This allows startups to minimize overhead costs and focus on their core business activities.

**2. Technical Infrastructure:** Startups may have access to specialized equipment, technology platforms, or software that would otherwise be too expensive for them to purchase on their own.

**3. Legal and Administrative Support:** Incubators often assist with legal matters, such as business registration, intellectual property protection, and contract negotiations. They may also offer administrative support in areas like accounting and human resources.

**4. Intangible Support**

**5. Mentorship and Guidance:** One of the most significant benefits of incubation centers is access to experienced mentors. These mentors can offer valuable advice on business strategy, product development, marketing, and scaling operations.

**6. Networking Opportunities:** Incubators facilitate connections between startups, investors, potential clients, and other entrepreneurs. These networks are crucial for gaining access to funding, partnerships, and market opportunities.

**7. Training and Workshops:** Incubators often provide educational programs that help entrepreneurs develop essential skills in areas such as business management, sales, and financial planning.

**8. Access to Funding:** Many incubation centers assist startups in securing early-stage funding by connecting them with investors, including venture capitalists, angel investors, and grant opportunities. Some incubators also offer direct funding or seed investment in exchange for equity.

**Incubation centers provide a range of services to help startups grow and succeed. Key services typically offered include:**

**1. Mentorship and Guidance:** Experienced mentors and industry experts provide advice on business strategy, operations, marketing, fundraising, and scaling.

**2. Business Development Support:** Assistance with business planning, product development, market research, and customer acquisition strategies.

**3. Networking Opportunities:** Access to a network of investors, entrepreneurs, industry professionals, and potential customers to facilitate partnerships, funding, and collaboration.

**4. Office Space and Infrastructure:** Provision of affordable office space, high-speed internet, meeting rooms, and other resources to support day-to-day operations.

**5. Access to Funding:** Introduction to investors, venture capitalists, and angel investors, as well as opportunities to pitch for funding

**6. Workshops and Training:** Regular workshops, seminars, and training sessions on key business topics such as finance, marketing, legal issues, and technology.

**7. Legal and Administrative Support:** Help with company registration, intellectual property protection, tax planning, and compliance with local regulations.

**8. Technical Support:** Access to tech resources, including software, hardware, or technical expertise for product development and prototyping.

**9. Marketing and Branding Assistance:** Support in creating a brand identity, developing marketing strategies, and improving digital presence.

**10. Product and Market Validation:** Guidance on testing products and services in the market, gathering feedback, and iterating based on real customer input.

These services help startups reduce risk, increase their chances of success, and accelerate growth.

**Data & Journey :** India's startup ecosystem has experienced significant growth, supported by a network of incubation centers that provide essential resources and mentorship to emerging businesses. Here's an overview of the current landscape:

**1. Number of Startups and Incubators:**

**a) Startups:** As of 2018, India had approximately 50,000 startups, with around 8,900 to 9,300 being technology-driven. In 2019 alone, about 1,300 new tech startups were established, indicating the formation of 2-3 tech startups daily.

**b) Incubators:** The number of incubators in India has seen a substantial increase, growing fifteen-fold over the past two decades, largely due to proactive incubation policy

initiatives between 2008 and 2020. Data from Traxcn indicates that there are approximately 718 accelerators and incubators in the country.

**2. Incubation Support and Challenges:** Despite the growing number of startups, only 8.2% undergo incubation. Notably, 10% of incubators support 98% of these incubated startups, highlighting a concentration of resources within a limited number of incubators. (Economic Times)

India has about 0.8 incubators per million people, which is significantly lower compared to countries like the USA, UK, and China, each having 8-10 incubators per million. This disparity underscores the need for expanding incubation infrastructure to support the burgeoning startup ecosystem. (Economic Times)

**3. Regional Distribution:** South India leads in the number of startup incubators, with institutions like IIT Madras and IIM Bangalore playing pivotal roles in fostering innovation and entrepreneurship. (The New Indian Express)

**4. Economic Impact:** The average value of assets for every 100 incubated startups by the ninth year from incorporation is estimated at <sup>1</sup> 10,627 crore, reflecting the significant economic contributions of incubated startups over time. (The New Indian Express)

**Government Initiatives:** The Indian government has approved a 10-billion-rupee (\$119 million) fund to support the growing space sector, aiming to bolster its share in the global commercial space market by 2033. This fund will benefit 40 startups, with support varying between 100 million and 600 million rupees depending on their maturity level.

**Conclusion:** In summary, while India's startup ecosystem is expanding rapidly with increasing numbers of startups and incubators, there remains a need to enhance incubation support and infrastructure to sustain and accelerate this growth.

**References:-**

1. Daily NEWS PAPER
2. Report Published By Govt of India on "Evolution of Start UP in India" Capturing the 5-Year story)
3. Analysis of DPIIT (Dept of Promotion of Industry and Internal Trades
4. Atal Innovation Mission of NITI Ayog Govt of India

\*\*\*\*\*

## Between the Space and the Earth : A Study of 'Orbital' as Creative Non-Fiction

Dr. Kiran Sitole\*

\*Asst. Prof. (English) Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

**Abstract :** Creative non-fiction is a genre of literature that blends factual accuracy with narrative storytelling for an immersive and informative experience. "Orbital," by Samantha Harvey a beautiful scientific novel fits within this category which takes readers on a journey of space exploration. Samantha Harvey weaved scientific reality by literary techniques to convey real scientific principles with human experience and human emotion in her novel. This paper examines the structure, themes, characters and all over impact of "Orbital" as a creative non-fiction novel. My paper highlights how it bridges the gap between empirical knowledge and artistic expression of author.

**Introduction** - Difference between fiction and non-fiction have often been blurred in literature, particularly in the genre of creative non-fiction. "Orbital" is an example of informative and engaging storytelling. This novel allows readers to experience the mysterious marvels of space while maintaining a connection with human experience. The Booker Prize-winning novel by Samantha Harvey, offers a contemplative exploration of human existence with experience of six astronauts aboard the International Space Station Set over a single day. Author writes experience of these individuals as they complete sixteen orbits around Earth, each chapter corresponding to one orbit. This structure of writing allows readers to drown in joy into the astronauts' reflections on life, death, identity, and the interconnection of humanity. *Writing style is not one to be rushed either.* Harvey wrote clearly and articulately, with poetry and lyricism about science and beauty, geopolitics and personal stories. The whole package of Space Voyage is wrapped up in the grandeur of history and the humbleness of human insignificance within the immensity of the universe. This is a small novel but it has a BIG message.

*"How are we writing the future of humanity? We're not writing anything, it's writing us. We're windblown leaves. We think we're the wind, but we're just the leaf.....*

*.....Some metal separates us from the void; death is so close. Life is everywhere, everywhere."*

Space, by comparison, or at least the nearest region of space – "Earth's back garden" – seems more knowable and less lonely. With this extreme slender and stretchy her fifth novel, Harvey makes an ecstatic travel with an imagined crew on the International Space Station, and looks back to Earth with a lover's eye. Orbital goes into flight for a single day, though a day is a different kind of thing up here, where "the whipcrack of morning arrives every ninety minutes" and the sun is "up-down-up-down like a mechanical toy".

It's a nicely giddy structural ploy to align each and every chapter with an orbit of the Earth: 16 orbits all together. The mobile narrative sends out probes into past and future, but all is held in the looping motion of elliptical travel.

Samantha used amazing vocabulary in Orbital to illustrate things that might be missing at home like anticipated things, O nigiri, Skiing etc. It begins with stunning display of literary brilliance, its first half alive with breathtaking imagery and profound ideas of life and space. But as it progresses, its demand high reading skills. However, Orbital Offers a Fascinating thought provoking journey of space, not just once but sixteen times. Samantha Harvey never been visited to space but how beautifully she painted the practical aspects of life in space station in her words. She represented the eating, sleeping, work out and toileting habits in widely praised language. For its beautiful presentation Guardian Describes Orbital as an uplifting book in its blurb.

The story is set over the course of one 24-hour period on board the International Space Station. There are four astronauts and two cosmonauts who are following the journey of the first manned space craft to land on the moon since 1972 as well as a terrifying typhoon developing over the Pacific Ocean. During this day on board the ISS, they will orbit the earth sixteen times,

*"they'll see sixteen sunrises and sixteen sunsets, sixteen days and sixteen Nights"*

To assist the reader, Harvey has provided a map of their orbits across the globe so when they talk about what they can see from the window, we can track it for ourselves. It is the artistic beauty of characterisation that connect us with characters Characterization in orbital is subtle and focused on the astronauts' inner lives and perspectives, rather than elaborate backstories or dramatic conflicts, with each character representing a different facet of humanity's

relationship with space and Earth. The characters are not necessarily developed as individuals with complex personal dramas, but rather as representations of different aspects of humanity, such as faith, grief, and the search for meaning. **Anton (Russian)**: Described as sentimental and reflective. **Chie (Japanese)** is portrayed as methodical and wise. **Shaun (American)** Leans on his faith and sees the universe as a testament to design. **Pietro (Italian)** Considered the mind of the spacecraft. **Nell (British)** works for commitments. **Roman (Russian)** The commander, described as dextrous and capable.

The profound weirdness of experience makes Harvey's imaginative act all the more impressive. The account certainly doesn't lack verisimilitude. But the parts of the novel that stuck with me most were not the disorientating lack of gravity but the moments of reflection about what could be seen of the Earth spinning below. "Orbital" employs a unique narrative structure that intertwines factual exposition with character-driven storytelling. By using a first-person perspective, the novel places readers in the body of astronauts, scientists, and engineers, offering an intimate glimpse into the psychological and physical realities of space travel. The book's stylistic choices, including detailed descriptions and introspective monologues, enhance the reader's immersion in the subject matter.

*"We matter greatly and not at all. To reach some pinnacle of human achievement only to discover that your achievements are next to nothing and that to understand this is the greatest achievement of any life, which itself is nothing, and also much more than everything. Some metal separates us from the void; death is so close. Life is everywhere, everywhere.sm"*

One of the key strengths of "Orbital" is its ability to present scientifically accurate information within a compelling narrative. Isolation in space, the fragility of human existence, bonds they form with each other and emotions for Earth. Real scientific phenomena, such as microgravity effects on the human body and the physics of orbital mechanics, are seamlessly integrated into the storytelling, making complex concepts accessible to a general audience. It beautifully presents the earth from space. It is so beautiful, that globe.

*"Because who can look at man's neurotic assault on the planet and find it beautiful? Man's hubris. A hubris so almighty it's matched only by his stupidity."*

Over the sixteen orbits tracked by the novel, dazzling descriptions of the planet rhythmically recur. There is Africa, "chiming with light" that is almost audible. Gran Canaria's gorges pile the island up "like a sandcastle hastily built". There is the "soft brushed nickel" of the Mediterranean; Uzbekistan, an "expanse of ochre and brown"; the "clean and brilliant Indian Ocean of blues untold", Man-made border of light is visible on Earth: a long trail of lights between Pakistan and India – and even that disappears in the daytime. The light which strikes and stabs, sparkles and shimmers is able to make boundaries otherwise there is "no wall or barrier: no tribes, no war or corruption or

particular cause for fear"; instead "a rolling indivisible globe which knows no possibility of separation".

*"The earth, from here, is like heaven. It flows with colour. A burst of hopeful colour. When we're on that planet we look up and think heaven is elsewhere, but here is what the astronauts and cosmonauts sometimes think: maybe all of us born to it have already died and are in an afterlife. If we must go to an improbable, hard-to-believe-in place when we die, that glassy, distant orb with its beautiful lonely light shows could well be it."*

This is the Earth as experienced in the universe. The Earth majesty coexisting with, and increasingly shaped by, its temporarily dominant species. Individually as a human we are powerless in the face of nature. Collectively as a team we've utterly transformed every part of it in a plethora of deeply unknowable ways.

Creative non-fiction novel "Orbital" plays an essential role in bridging the gap between scientific understanding and public engagement. By employing a narrative approach, the book makes space exploration more relatable and emotionally resonant. Its reception among readers and critics highlights the growing appreciation for works that combine factual rigor with compelling storytelling, fostering greater interest in space sciences.

It exemplifies the power of creative non-fiction in transforming educational content into an engaging literary experience. By maintaining scientific authenticity while exploring human emotions and challenges, the novel serves as a model for how literature can contribute to scientific literacy and appreciation. As the genre "Orbital" will remain inspiring curiosity and understanding about the universe we inhabit.

However, some readers may find the novel's lack of a conventional plot challenging. "Orbital" prioritizes introspection and philosophical inquiry over traditional narrative structure, which may not appeal to those seeking a plot-driven story. Nonetheless, for readers open to a meditative and poetic exploration of existence, the novel offers a rewarding experience.

#### References:-

1. Orbital, Samantha Harvey, Jonathan Cape (UK)2 November 2023 Grove Atlantic,(US)5 December 2023
2. Orbital by Samantha Harvey, - Review, *The Guardian* 2025
3. Orbital by Samantha Harvey- Review, Goodreads 2025
4. Samantha Harvey's 'Orbital' and the art of looking back at Earth, Joshua Ferris, *The New York Times*, Dec. 5, 2023 2025
5. Samantha Harvey's 'Orbital' explores humanity through the eyes of astronauts, review, *The Washington Post*, 2025
6. Samantha Harvey's 'Orbital' and the future of space fiction, *Science Fiction Studies*, 2025
7. Orbital by Samantha Harvey, Daisy Butter, 10 February 2025
8. Language of waves and light, Review, Kate McLoughlin, TLS, Current Issue



## राष्ट्र निर्माण एवं शैक्षणिक समस्याएँ एक अध्ययन

श्रीमती चित्रमाला भिमटे\*

\* सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शास. महाविद्यालय, लामता, जिला बालाघाट (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - शिक्षा विहीन समाज के विकसित राष्ट्र की कल्पना करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है शिक्षित समाज ही राष्ट्र विकास की अवधारणा को साकार कर सकने में समर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाना संभव है। यह शिक्षा ही है, जो एक आम व्यक्ति को समाज से अलग एक विशिष्ट स्थान दिलवाने का सामर्थ्य रखती है।

'साविद्या या विमुक्तये' अर्थात् शिक्षा वहीं जो मुक्त करती है, मुक्ति का अर्थ तमाम बंधनों, अधविश्वार्यों एवं कुरीतियों से मुक्ति पाना और नयी समझ के माथ नई दृष्टि का निर्माण करने से है। यदि सीधे तौर पर देखा जाय तो शिक्षा से सीधा लाभ ज्ञान और तथ्यों की समझ जागृत करना है न कि कुछ रटे तथ्यों की लम्बी सूची तैयार करना। अच्छी शिक्षा का मकसद मानव में सोचने तथा विचार करने की क्षमता पैदा करता है अपने आने वाले कुल के लिए ऐसी क्षमता पैदा कर सकना, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों को अलग करने लायक हो जाए जिन पर ओर विचार करने की आवश्यकता है। यह छात्रता हग अच्छे अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जो हमें स्कूली तथा अन्य आगे की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर शिक्षा ही हमें वस्तु की परख करने की क्षमता प्रदान करती है।

शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमारे भीतर सही दृष्टिकोण, सही विचार तथा सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। जिससे हम अपने आपको जीवन की विषम परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढाल लेते हैं। शिक्षा जीवन में हमें मही फैमला लेने में मददगार सिद्ध होती है आप प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी समस्याओं, तनाव तथा दुख से गुजरना पड़ता है। इनमें हग बच नहीं सकते किन्तु ऐसी परिस्थितियों का एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। बल्कि ऐसी समस्याओं के भविष्य में आने पर स्वयं को पहले ही तैयार कर लेता है।

शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका न ही कोई आदि है और न ही अंत। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है बस यदि कुछ बदलता है तो वह है- शिक्षा का स्वरूप, माध्यमिक शिक्षा, उच्च तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा इत्यादि। विकास और आधुनिकता की दौड़ में आगे बने रहने के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था है- प्रोफेशनल एजुकेशन यह पारम्परिक एकेडमिक एजुकेशन से सर्वदा भिन्न है यह समस्त शिक्षाएँ हमें अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाती है यही विशेषता राष्ट्र विकास के घटकों के रूप में प्रयुक्त होकर विकास व उन्नति को सुदृढ़ करती है।

**शब्द कुंजी** - राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, विकास।

**उद्देश्य:**

1. राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के बढ़ते कदम का अध्ययन करना
2. शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्या के समाधान का अध्ययन करना।

**अध्ययन की शोध प्रविधि** - प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमको पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से आकड़ों से संग्रहण हेतु शासकीय, पत्र-पत्रिकाओं, सख्यकीय पुस्तिका, इन्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है।

**अध्ययन की प्रासंगिकता** - प्रत्येक शोध कार्य का एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण कार्य का अपना महत्व होता है उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आज शिक्षा का महत्व राष्ट्र निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण है शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षाविदों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस शोध पत्र के माध्यम से शिक्षा सम्बंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा तथा इसमें उभरने का मार्ग प्रशस्त होगा।

**राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के बढ़ते कदम** - शिक्षा विकास का आधारमूलक सत्य है इसी शिक्षा रुपी साध्य से हम विकास रूपी साधन को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के लगभग सभी समाजों और कालों में शिक्षा का महत्व एक समान बना रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति अत्यंत चिन्तनीय थी, लेकिन 1947 के बाद भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रभावशाली प्रयास हुए।

किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक ने संयोजित होने वाले कारकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कारक है सुदृढ़ समाज के निर्माण में प्रारंभिक शिक्षा मजबूत नींव की भूमिका निभाती है अगर नींव ही कच्ची हो तो समाज के सृजनात्मक विकास की परिकल्पना करना संभव नहीं होता है।

सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व को समझने एवं निवारण हेतु 1935 में केन्द्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। इसके पश्चात से प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास होते रहे। 1986 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और 1992 में उसमें किये गये संशोधन तथा इसकी कार्ययोजना के अनुरूप सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहल की गयी। 1994 यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 42 जिलों में लागू किया गया। ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी। 1985-1986 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम शुरु किया

गया था। सन 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई जिसमें आत्मनिर्भरता कौशल विकास उद्यमशीलता के द्वार सबके लिए खोल दिए गए।

भारत में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भारी मात्रा में अनुदान देती है भारत में शिक्षित व्यक्ति का औसत जहाँ स्वतंत्रता पश्चात 1951 में मात्र 18.33 प्रतिशत था। वही सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति लगातार सजगता व प्रयास के कारण 1961 में 28.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार यह बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया किन्तु बारीकी से अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि यह अभी अन्य तमाम विकासशील देशों के औसत से काफी कम है।

### भारत के साक्षरता की स्थिति

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल साक्षरता
1961	40.36	15.33	28.33
1971	45.95	21.97	34.45
1981	56.38	29.76	43.57
1991	64.13	39.23	52.21
2001	75.86	54.16	65.38
2011	82.14	65.46	74.04

### शैक्षणिक समस्याएँ:

1. अवैतनिक और कम योग्यता वाले शिक्षक- अवैतनिक व कम योग्यता वाले शिक्षक कई बार शासन वेतन समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाती तथा उनकी आजीविका का एकमात्र साधन वही होता है अतः वह शिक्षक का पद त्याग देते हैं। विशेष पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए अलग से शिक्षकों की भती नहीं हो पाती।
2. आपूर्ति और वर्दी की लागत- आपूर्ति चोर नदी की लागत भूमि व विद्यार्थी को शिक्षण के दौरान कितीने व यूनिफॉर्म की निःशुल्क व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे प्रवेश कम होते हैं।
3. लड़कियाँ होना (लैंगिक भेदभाव)
4. प्रकोप और महामारी
5. मातृभाषा और साक्षरता का प्रभाव
6. शिक्षा में बुनियादी ढाँचे की कमी
7. वित्तीय संसाधन और शिक्षा तक पहुँच में असमानता
8. आनलाइन शिक्षा प्रणाली में असमानता
9. आर्थिक स्थिति कमजोर
10. विद्यालयों, महाविद्यालयों पर स्थानीय जवाबदेही की कमी
11. शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं विसंस्कृतीकरण
12. संकीर्ण शिक्षा प्रणाली एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण
13. नैतिक शिक्षा, मूल्य, आदर्श अप्रासंगिक हो चुके हैं।
14. शिक्षकों की कमी - विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पूर्ति नहीं की जाती है जिससे सभी विद्यार्थियों की समस्या को हल कर पाना संभव नहीं हो पाता है।

### समाधान :

1. शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि।
2. पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक दृष्टिकोण पर तैयार करना।
3. शैक्षणिक अनुसंधानों पर विशेष जोर देना।
4. स्वायत्ता विद्यालयों तथा शिक्षण विभागों का विकास करना।
5. गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान प्रदान करना।
6. विद्यालय में कई पालियों में शिक्षण कार्य सम्पन्न करना।

7. छात्राओं के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त होस्टल की व्यवस्था।
8. नेशनल ओपन स्कूल की तर्ज पर अधिक शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।
9. शिक्षण गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए औचक निरीक्षण की व्यवस्था।
10. शैक्षणिक व्यवस्था को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाना।
11. सिखने के विविध विकल्प प्रदान करना - विविध शिक्षण अवसर प्रदान करके शिक्षार्थी की जरूरतों और रुचियों को बेहतर ढंग से पूर्ण करने के लिए प्रयास करें।

**निष्कर्ष** - शिक्षा एक अनमोल रत्न है इसकी प्राप्ति जितनी ही हो, वह कम ही प्रतीत होगी जिस प्रकार रत्न शुरुआत में पत्थर के आकार का होता है उसे बाद में जरूरत के अनुसार तराशकर अनमोल बना लिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था को आवश्यकता और समय के साथ परिवर्तित कर अनमोल बनाया जा सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि स्कूली शिक्षा समाप्त कर जो युवा बाहर निकलते हैं, उनके अध्ययन के विषयों की बुनियादी जानकारी का व्यवहारिक पक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र में राष्ट्र की जिम्मेदारी, नागरिकों के कंधों पर होती है। यह वह तय करते हैं कि उनका समाज का विकास किस दिशा में आगे बढ़े। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सुनिश्चित की गई शिक्षण व्यवस्था को क्या पुर्वमूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि हाँ तो पुर्वमूल्यांकन का क्या आधार होगा क्या यह उद्देश्य के आधार पर सर्वसम्मत होगी या आवश्यकता के आधार पर ऐसे तमाम प्रश्न आज युवार्यों के जहन में हैं, जो कि कल के राष्ट्र निर्माता भी होंगे।

शिक्षा का आधार चाहे जैसा भी हो किन्तु 21 वीं सदी की शिक्षण व्यवस्था में इस बात को ध्यान देना अनिवार्य है कि शिक्षा को आने वाले समय में उद्योग तथा समाज से सीधे जोड़ा जाये। इसके लिए आवश्यकता होगी उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की जिसके लिए एकेडमिक, औद्योगिक, और सरकारी तीनों क्षेत्रों को अपनी-अपनी भागीदारी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। इन तीनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से, भारत की महाशक्ति बनकर विश्व पटल पर चमकेगा। जिसके लिए शिक्षा राष्ट्र विकास की कुजी के रूप में कार्य करेगी।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बहादुर सिंह करुण, 'शिक्षा राष्ट्र विकास की कुंजी', कुरुक्षेत्र, पेज नम्बर (30-32) सितम्बर 2006
2. महेन्द्र सिंह यादव महेन्द्र, 'मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का बदलता परिदृश्य', कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2006, पेज नम्बर 34
3. कुंड प्रतिभा, 'शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान', योजना, मार्च 2016 पेज नम्बर (59-62)
4. डॉ. चन्द्रपाल, 'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरुक्षेत्र मार्च 2005, पेज नम्बर (25-27)
5. जे. पी. सिंह, 'शैक्षणिक पद्धति समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत', सन 2017 फिल लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
6. कुमार पार्थिव: 'शिक्षा हो आया ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव', कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2015, पेज नम्बर- 18
7. यादव प्रसाद बट्टी के, भारतीय शिक्षा का स्वरूप समस्या और समाधान, बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली, भारत 2021

## राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्र निर्माण में योगदान का अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे\*

\* सहा. प्राध्यापक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी, शास. महाविद्यालय, लालबर्वा, जिला बालाघाट (म. प्र.) भारत

**प्रस्तावना** – किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं खुशहाली में शिक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। तथा राष्ट्रीय शिक्षा नितियों में समय-समय में बदलाव लाए गए जिससे की राष्ट्रीय प्रगति में नए आयाम प्राप्त हो सके। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई जो 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। जिसका लिये हमारे देश के विकास के अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पूरा कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता सख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान सम्बंधी क्षमताओं का विकास हो सके।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना को एक विषय के रूप में विद्यार्थियों को पसंद के रूप में चुनने तथा उसके राजगार प्राप्ति कर सके ओपन इलेक्टिव विषय के रूप चुनने का अवसर होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में बदलाव लाने तथा राष्ट्र की सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है प्रारंभ से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न होता रहा है सन 1950 में प्रथम शिक्षा आयोग ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए भावना के आधार पर प्रवेश के लिए संस्तुति की। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहर लाल नेहरू के सुझाव पर डॉ. सी डी देशमुख की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के पूर्व राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य रूप से करने की प्रोफेसर के जी सैउडीन जो विभिन्न देशों में युवाओं की राष्ट्रीय सेवाओं का अध्ययन कर चुके थे उनका कहना था की राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवका के आधार पर प्रारंभ कि जानी चाहिए प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठ भूमि में चिंतन की धारा रही है। एक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज को बहुत कुछ व्यय करना पड़ता है। अतः यह ऋण उतारने के लिए उसे कम से कम अपने आस पास के समुदाय में कुछ समाज सेवा के कार्य अवश्य करना चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति भी हमें अपना दायित्व निभाना होता है। स्वतंत्र देश में केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है अपितु आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर बेहतर कार्य करके इन बुराईयों को कम कर सके इसमें उच्च शिक्षित युवाओं कि अहम भूमिका है यदि इन युवा वर्ग को समय पर पर्याप्त मार्ग दर्शन तथा अवसर मिले तो असमानता कि खाई को पाटने में कारगर साबित होंगे। भविष्य में देश की बागडोर सभालने वाली पीढ़ी को

समाज के विभिन्न वर्गों को तथा दलितों एवं शोषित लोगों की समस्याओं का प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक बोध हो ताकि वह उनकी एवं स्वयं की समस्याओं को हल कि दिशा में प्रवृत्त हो सके। 18 से 25 वर्ष की आयु में आदर्शवाद, देशप्रेम और कुछ कर गुजरने की चाहत से भरी हुई तरुणाई को ऐसे संस्कार एवं मार्गदर्शन दिए जाने चाहिए जो कि उन्हें श्रम की निष्ठा तथा प्रजातांत्रिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुशासन रख सके। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियावयन में प्रशासनिक तथा सामाजिक सरोकारों कि महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियाँ देश में अग्रणी रही है यह सब स्वयं सेवकों की निष्ठा एवं सकारात्मक सोच से ही संभव हो सका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी 24 सितंबर 1969 से ही राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ की गई है। इस इकाई से अनेक विद्यार्थी जुड़कर राष्ट्र की निरंतर कर रहे है।

**शब्द कुंजी** – राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा, व्यक्तित्व विकास।

**अध्ययन की शोध प्रविधि** – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमको पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से आकड़ों से संग्रहण हेतु शासकीय, पत्र-पत्रिकाओं, सखिक्कीय पुस्तिका, इन्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है। अध्ययन की प्रासंगिकता – प्रत्येक शोध कार्य का एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण कार्य का अपना महत्व होता है उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व को रेखांकित किया गया है जिससे युवा जुड़कर राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करके स्वयं का राष्ट्र के लिए योगदान सुनिश्चित कर सकते है। इस कार्यों से राष्ट्रीय प्रेम एवं देश सेवा का युवाओं में जोश जज्बा तथा उत्साह उत्पन्न होगा तथा सामाजिक सेवा सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायता प्रदान होगी।

**राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य**– समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है देश की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों से अवगत कराना है।

**राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम**– स्वास्थ्य जन स्वतच्छता एवं व्यक्तित्वगत स्वास्थ्य रही है सत्र 2024-25 के लिए लक्ष्य थीम – 'मेरा युवा भारत माय भारत के लिए युवा डिजिटल साक्षरता के लिए युवा।'

**राष्ट्रीय सेवा योजना का लायल** – शिक्षा द्वारा समाजसेवा एवं समाज सेवा द्वारा शिक्षा है इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों से अपेक्षा कि जाती कि वे जो जिस समाज में कार्य करते हैं उसे समझने का प्रयास करे समुदाय कि तुलना में स्वयं को समझना समुदाय की जरूरत और समस्याओं की पहचान करना तथा उन्हें समस्या के समाधान की प्रक्रिया में भागीदारी

बनाना स्वयं में सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेदारी का बोध विकसित करना समूह में रहने और जिम्मेदारियों को बांटने के लिए जरूरी क्षमता विकसित करना, नेतृत्व गुण एवं लोकतांत्रिक प्रवृत्ति विकसित करना, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सदभाव बनाए रखना।

**योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक एवं सामाजिक सरोकारों की अहम भूमिका** - प्रदेश की राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में देश में अग्रणी रही है। यह सब युवा पीढ़ी की सकारात्मक सोच से ही संभव हुआ है। भारत में युवा प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी 24 सितंबर 1969 से राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसका लक्ष्य शिक्षा द्वारा समाज सेवा तथा समाज सेवा के माध्यम से जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करना जिससे कि विद्यार्थी जिस समाज में वह कार्य करे उससे वह बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें एवं समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का अनुभव करें, उनकी कठिनाइयों को समझने तथा यथासंभव समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रहे। स्वयं में सामाजिक एवं नागरिक भावना के दायित्व का बोध हो सके। सामाजिक सहभागिता के लिए निपुणता प्राप्त करें।

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के रथ के चक्र पर आधारित है। सूर्य मंदिर का यह विशाल चक्र सृजनात्मक शक्ति, गतिशीलता एवं अपार ऊर्जा का प्रतीक है जो काल एवं स्थान से परे जीवन में गति का महत्व बताता है। इस प्रतीक चिन्ह में मुख्य रूप से दो रंग आ रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि में नीला रंग ब्रम्हाण्ड का प्रतीक है तथा लाल रंग उत्साह एवं स्फूर्ति का इस प्रकार से यह प्रत्येक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि स्वयंसेवकों को ऊर्जावान होकर वैश्विक स्तर पर परिवर्तन लाने एवं उसे उन्नत करने के लिए आठों पहर गतिमान रहना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य Not me but you अर्थात् मैं नहीं आप है। जो प्रजातांत्रिक ढंग से रहने के लिए तैयार करना है एवं निःस्वार्थ सेवा भाव की भावना विकसित करना है। यह सिद्धांत हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की सराहना करने वाले बनने के लिए प्रेरित करता है। साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव जागृत करता है।

**राष्ट्रीय सेवा योजना में नियमित गतिविधि** - राष्ट्रीय सेवा योजना में नियमित गतिविधियों के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम 120 घंटे का कार्य करना होता है। अनिवार्य गतिविधियों पात्रता में अभिमुखीकरण में राष्ट्रीय सेवा योजना का दर्शन, प्रेरणा गीत, नागरिकता बोध, यातायात नियमों, का पालन, पी टी योग, खेल एवं पर्यावरण जागरूकता की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। सत्र 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने मेंरी माटी में देश, एक पेड़ माँ के नाम, विद्यावान, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरूकता, इको क्लब, एड्स के प्रति जागरूकता।

जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सहभागिता करके स्वयं सेवक राष्ट्रीय दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हैं, अनुशासन में रहकर कार्यों को ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं एवं मिलजुलकर कार्यों को करते हैं। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है तथा सामाजिक, राजनीति, एवं आर्थिक पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है विद्यार्थियों में गीत संगीत के माध्यम से बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना से व्यक्तित्व का विकास होता है सात दिवसीय

विशेष शिविर में स्वयं सेवकों के साथ ग्रामीण जनो के मध्य जाकर, उनके सुझावों एवं सहयोग से स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता, नालियों की साफ सफाई एवं नारों के माध्यम से जन मानस में जन जागृति का संदेश दिया जाता है।

आज के वर्तमान समय में व्यक्तित्व विकास की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है उनके लिखित एवं मौलिक संप्रेक्षण तथा संवाद, क्षमता होनी चाहिए साथ ही नेतृत्व देने एवं टीम के साथ काम करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की क्षमता किसी कार्यक्रम को आयोजित करने एवं संचालन करने की क्षमता विकसित करने में राष्ट्रीय सेवा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

**विशेष शिविर**- राष्ट्रीय सेवा योजना में नियमित गतिविधियों के तहत विद्यार्थियों को अपने रिक्त समय का सदुपयोग संरचनात्मक कार्य में करने का अवसर मिलता है। वर्ष एक बार गोद ग्राम या अन्य ग्राम में आयोजित शिविर में उन्हें जीवन का अमूल्य अनुभव प्राप्त करते हैं। सात दिवसीय विशेष शिविर इकाई के 50% विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। शिविर के माध्यम से विद्यार्थी ग्राम में प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरण करते हैं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की जानकारी दी जाती है। एक साथ मिलकर कार्य करना, परियोजना कार्य में समन्वय, के साथ हाथ बटाना या मिलकर कार्य करना आदि की सिख मिलती है। तथा शिविर के दौरान प्रत्येक स्वयं सेवक अनुशासन में रहकर राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हैं।

**जागरूकता कार्यक्रम के आयोजनों में राष्ट्रीय सेवा योजना का सहयोग** - 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। इस योजना से पुरे जीवन काल में शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने में मदद मिली है। मतदाता जागरूकता, पोषण आहार, आद्र भूमि दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, युवा दिवस, सयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, अग्नि शमन दिवस, गांधी जयंती एवं भारत के महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में राष्ट्रीय सेवा योजना की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार के कार्यों से स्वयं सेवकों में समाज के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता एवं सेवा भाव की भावना पनपती है तथा समाज को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका में रहते हैं जल है तो कल है, पर्यावरण के दुश्मन तीन पाउच पन्निस पॉलिथीन, मानव मानव एक समान जात पात का मिटे निशान, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो जैसे अनेक प्रेरणादायी नारों से गांव-गांव में जाकर, शिविर तथा नियमित गतिविधियों के माध्यम से समाज में जन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है इससे जन मानस में कार्य करने तथा युवाओं को सहयोग देने की भावना पनपती है तथा प्रजातांत्रिक विचारधारा, वैज्ञानिक सोच एवं स्वप्रेरणा तथा अनुशासन की भावना प्रबल होती है।

**सुझाव :**

1. राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सत्र के प्रारंभ में जानकारी दी जानी चाहिए।
2. नियमित गतिविधियों में विशेष शिविर के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।
3. NCC की तरह NSS के स्वयंसेवकों के लिए ड्रेस कोड की राशि प्रदान की जानी चाहिए।

4. विद्यार्थियों के सतत व्यापक मूल्यांकन में NSS के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने की नीति बननी चाहिए।

**निष्कर्ष** - राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की भावना विकसित होती है एवं युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियों के भाग लेने से स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व में निखार आता है समुदाय से जुड़ाव होता है एवं समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायता करते हैं तथा इस प्रकार के कार्यों से समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सवेदंशीलता, सहानुभूति एवं मिलजुलकर कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है एवं समय-समय पर आयोजित स्वास्थ्य शिविरो एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों सहभागिता से नागरिक दायित्व का विकास होता है उन्हें राष्ट्र के प्रति प्रेम देश की एकता अखंडता एवं बंधुत्व बढ़ाने के लिए युवा वर्ग आगे रहकर कार्य करते

हैं, जिसे नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ परिस्थितियों को समझने की शक्ति उत्पन्न होती है, अंतः राष्ट्रीय सेवा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिससे जुड़कर युवा अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। एवं राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं।

#### **संदर्भ ग्रन्थ सूची:-**

1. राष्ट्रीय सेवा योजना के मैनुअल 2006 भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उच्च शिक्षा विभाग विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना भारतीय इंटरप्राइजेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश।

\*\*\*\*\*

## मध्यप्रदेश के धार जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता का वितरण प्रतिरूप : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. किरण मण्डलोई\*

\* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़नगर, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश** - किसी भी देश के समग्र विकास के निर्धारक घटकों में प्रमुख घटक साक्षरता है। देश के बहुआयामी विकास हेतु प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, परन्तु अभी भी देश के समग्र विकास हेतु आवश्यक कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव है। किसी भी देश का समान व वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है तो समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा में नहीं हैं उन्हें शिक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं में साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत न्यून है। प्रस्तुत अध्ययन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्राचीन समय से ही महिला शिक्षा का अभाव रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता उसकी अपनी विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। जिन समाजों में महिलाओं को परिसंचरण की स्वतंत्रता है या नहीं है, किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन समाजों में महिला साक्षरता के प्रति प्रतिकूल प्रभाव है।

**शब्द कुंजी** - साक्षरता, बहुआयामी, संसाधन, आदिवासी, आर्थिक स्थिति।

**प्रस्तावना** - किसी भी देश-प्रदेश के विकास को परखने का सर्वोत्तम उपाय वहां की महिलाओं की शिक्षा से आंकलन लगाया जा सकता है। महिलाएं परिवार रूपी गाड़ी की धुरी हैं। महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है क्योंकि वे ही परिवार को शिक्षित करती हैं। इसलिए गाँधीजी ने कहा था कि 'एक लड़की की शिक्षा एक लड़के से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है परन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित होता है।' शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, पथ-प्रदर्शक, है निर्माण है एवं विकास है।

भारत के विकास में महिला साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों से ज्यों-ज्यों महिला साक्षरता में वृद्धि होती गई है, वैसे-वैसे भारत विकास के प्रत्येक पथ पर अग्रसर हुआ है। जो व्यक्ति समझकर पढ़ना-लिखना एवं हस्ताक्षर करना जानते हैं, साक्षर कहे जाते हैं। असाक्षरता, व्यक्ति एवं समाज दोनों के विकास में बाधक हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार- 'केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है।'

**साहित्य समीक्षा :**

1. **त्यागी गुरसरनदास एवं विजय कुमार (2009) : 'उदीयमान भारत में शिक्षा'** - किसी भी व्यक्ति समाज तथा देश के समग्र विकास में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास के निर्धारक घटकों में प्रमुख घटक साक्षरता है। 'साक्षरता वास्तव में न तो पढ़ाई-लिखाई है और न ही कोई विशेष योग्यता। साक्षरता पढ़ने-लिखने की मनोदशा का एक यंत्र है।'

2. **डॉ. दीपारानी (2019) : 'उत्तराखण्ड के जनपद टिहरी में जनसंख्या का प्रतिरूप : एक भौगोलिक अध्ययन'** - साक्षरता मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान अनंतिम शक्ति है। साक्षरता और शिक्षा को सामान्यतः सामाजिक विकास के संकेतकों के तौर पर देखा जाता है।

3. **गजराज नेगी एवं विजय बहुगुणा (2019) : 'साक्षरता का स्थानिक वितरण प्रतिरूप - उत्तराखण्ड राज्य के गैरसैण विकासखण्ड (जनपद चमोली) के संदर्भ में : एक भौगोलिक अध्ययन'** - शोध क्षेत्र में भौगोलिक जटिलताओं के अध्ययन के कारण शिक्षा के स्तर में पर्याप्त लैंगिक साक्षरता अंतराल दृष्टिगोचर होता है।

4. **डॉ. जियालाल राठी (2024) : 'जनजाति क्षेत्र का साक्षरता परिदृश्य एवं सामाजिक परिवर्तन शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में'** - शोध पत्र में महिला एवं पुरुष साक्षरता का अध्ययन किया है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा भी रोटी, कपड़ा और मकान आदि की तरह मूलभूत आवश्यकता बनती जा रही है।

श्रीमती हंसा मेहता समिति (1962), कोठारी कमीशन (1964-66), नारी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1980) शिक्षा की चुनौतियां : नीतिगत परिप्रेक्ष्य, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार (1986), राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1987-88), राममूर्ति समिति रिपोर्ट (1990), जनार्दन रेवी समिति (1992) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) आदि विभिन्न नीतियों/समितियों के माध्यम से महिलाओं में शिक्षा के सही विकास और राष्ट्रीयजीवन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला है।

**अध्ययन क्षेत्र :**

अध्ययन क्षेत्र पश्चिमी मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले का धरातल भौगोलिक संरचना की दृष्टि से बहुत ही असमान है। जिले के उत्तर में मालवा का पठार, मध्य भाग पर्वतीय (विंध्याचल पर्वत श्रेणी) तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी व निमाड़ का मैदान है। अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में 22°43' से 23°10' उत्तरी अक्षांश एवं 74°28' से 75°42' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां के भौतिक एवं आर्थिक संसाधन बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षा भी इन्हीं संसाधनों के अभाव के कारण पिछड़ जाती है।

**अध्ययन का उद्देश्य** : प्रस्तुत अध्ययन में विन्ध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी के मध्य वनाच्छादित भू-आकृतिक रूप से विषम एवं पिछड़े भागों में स्थित आदिवासी बाहुल्य जिला धार (म.प्र.) की महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता को जानने का प्रयास किया गया है।

**शोध विधि** : प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक शोध आंकड़ों का संकलन विभिन्न प्रकाशित जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जनगणना पुस्तिका गजेटियर (2011) तथा अन्य पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया गया है। अध्ययन को रुचिकर एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए विभिन्न तालिकाओं, आरेखों एवं मानचित्र का प्रयोग किया गया है।

**महिला साक्षरता का वितरण** : भारत में भी विश्व के अन्य देशों की साक्षरता का प्रादेशिक वितरण असमान है। इसी प्रकार धार जिले में भी महिला साक्षरता का वितरण असमान पाया गया है। आर्थिक दृष्टि से उन्नत क्षेत्रों में साक्षरता सामान्य से अधिक एवं पिछड़े क्षेत्रों में कम पाई जाती है। किसी भी देश में साक्षरता का मापदण्ड प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का उच्च होना ही नहीं है अपितु शिक्षा के लिए प्रति व्यक्ति आय उच्च होने के साथ-साथ वहां का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं प्राकृतिक वातावरण भी उच्च होना चाहिए।

धार जिले में जनसंख्या का असमान वितरण है। जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 2185793 व्यक्ति है, जिसमें पुरुष 1112725 एवं महिला 1073068 है। जिले की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 1772572 व्यक्ति है। कुल ग्रामीण जनसंख्या में से पुरुष 895113 एवं महिलाएं 877459 हैं।

धार जिले की कुल साक्षरता 2011 के अनुसार 59 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 68.95 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 48.77 प्रतिशत है। जिले में कुल 08 तहसीलें (बदनावर, कुक्षी, मनावर, सरदारपुर, गंधवानी, धरमपुरी एवं डही) तथा 13 विकासखण्ड हैं। इन विकासखण्डों में 1477 आबाद ग्राम हैं जिनका अध्ययन इस प्रकार है।

### तालिका क्रमांक 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि धार जिले की विकासखण्डों में से धार विकासखण्ड में सबसे अधिक महिलाएं साक्षर (45.40 प्रतिशत) हैं। इसका कारण इस विकासखण्ड के धार मुख्यालय के समीप होने के कारण यातायात एवं शिक्षा की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हैं। धार विकासखण्ड मालवा पठार पर कृषि एवं उद्योग के कारण स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा मिली हुई है। इसी प्रकार सबसे कम साक्षर महिलाएं 24.80 प्रतिशत एवं सबसे अधिक असाक्षर महिलाएं 75.20 प्रतिशत बाग विकासखण्ड में हैं। इसका मुख्य कारण है, इन दुर्गम पर्वतीय व वनीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन की जनसंख्या का एक बड़ा भाग भूमिहीन, पिछड़ी तथा

अनुसूचित जाति, जनजातियों में रूढ़िवादी समाजों में स्त्री साक्षरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण अधिवास ऐसे हैं जहां यातायात, विद्यालयों तथा पर्याप्त शिक्षकों की सुविधाओं का न होना एवं महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।

### तालिका क्रमांक 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट है कि धार जिले की कुल 08 तहसील के 13 विकासखण्ड में कुल 1535 ग्राम निर्धारित हैं। उनमें से निवासरहित ग्राम 58 तथा निवासित ग्राम 1477 हैं। शोध अध्ययन में 1477 ग्रामों को शामिल किया गया है।

धार जिले में ग्रामवार महिला साक्षरता के वितरण को पांच भागों में बांटा गया है। (1) जिले में अति उच्च साक्षरता (80 से अधिक) 8 ग्रामों में अर्थात् सबसे कम 0.54 प्रतिशत पाई गई है। (2) उच्च साक्षरता (60-80 प्रतिशत) 88 ग्रामों में अर्थात् 5.96 प्रतिशत। (3) मध्यम साक्षरता (40-60 प्रतिशत) 636 ग्रामों अर्थात् 43.06 प्रतिशत। (4) निम्न साक्षरता (20-40 प्रतिशत) 624 ग्रामों में अर्थात् 42.25 प्रतिशत। (5) जिले में अति निम्न साक्षरता (0-20 प्रतिशत) 121 ग्रामों में अर्थात् 8.19 प्रतिशत ग्रामों में ही पाई गई है।

### महिला साक्षरता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

- 1) भौगोलिक कारक
- 2) आर्थिक कारक
- 3) सामाजिक कारक
- 4) सांस्कृतिक कारक
- 5) राजनीतिक कारक

**महिला साक्षरता में वृद्धि** - मध्यप्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण की दृष्टि से विभिन्न योजनाएं लागू की गई, जैसे लाइली लक्ष्मी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, गांव की बेटी एवं आधुनिक यंत्र लेपटॉप एवं स्कूटी आदि योजनाओं के माध्यम से जिले में महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है।

**निष्कर्ष** - जिला धार आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गरीबी, अज्ञानता एवं निजी उदासीनता के कारण उनकी मानसिकता भी कुछ वैसी ही बनी हुई है कि वे शिक्षा के महत्व को कम समझते हैं। ऐसे लोगों को समझाना ही होगा कि उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि साक्षरता भी उनके निजी एवं व्यावसायिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि साक्षरता की सार्थकता महिलाओं की शिक्षा एवं स्वरोजगार में रुचि से मानव प्रतिष्ठा में वृद्धि करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में जिले की महिलाओं में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। खासकर बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा/साक्षरता उन्हें छोटे परिवार के प्रति जागरूक बनाती है। वे विवाह भी जल्दी नहीं करती हैं तथा परिवार को शिक्षित एवं नियोजित हेतु सचेत रहती हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

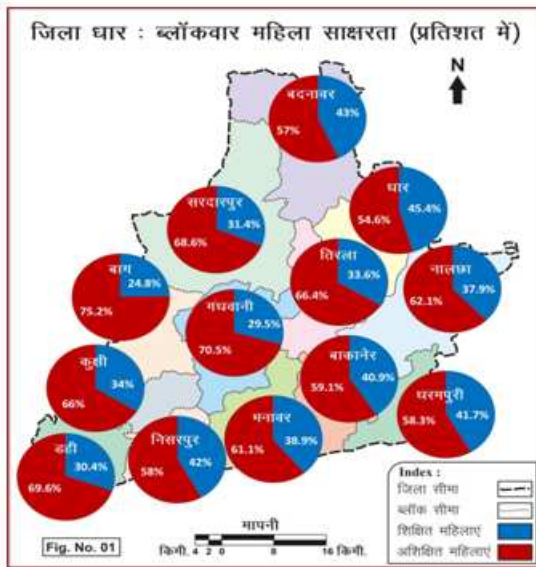
1. पण्डा बी.पी. (2004) : 'जनसंख्या भूगोल', मध्यप्रदेश शासक हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. त्यागी गुरसरनदास एवं विजय कुमार (2009) : 'उदीयमान भारत में शिक्षा', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. कुमार प्रमिला एवं शर्मा श्रीकमल (2015) : 'मध्यप्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. डॉ. दीपारानी (2019) : 'उत्तराखण्ड के जनपद टिहरी में जनसंख्या

- का प्रतिरूप : एक भौगोलिक अध्ययन' ISSN: 2249-894x, UGC APPROVED JOURNAL No. 48514, Vol.-8, May - 2019.
5. ब्रजेश कुमार पाण्डेय (2019) : 'जनसंख्या की साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना की विशेषताएं' ISSN: 2347-2944, 2582-2454, Vol.-11, Dec - 2019.
6. डॉ. जियालाल राठौर (2024) : 'जनजाति क्षेत्र का साक्षरता परिदृश्य एवं सामाजिक परिवर्तन : शहडोल संभाग के विशेष सन्दर्भ में' ISSN: 2249-894x, Vol.-14, Dec - 2024.

तालिका क्रमांक 01: जिला धार : विकासखण्डवार महिला साक्षरता 2011 (प्रतिशत में)

महिला साक्षरता	विकासखण्ड												
	बदनावर	सरदारपुर	तिरला	धार	नालछा	गंधवानी	बाग	कुक्षी	डही	निसरपुर	मनावर	बाकानेर	धरमपुरी
साक्षर	43	31.40	33.60	45.40	37.90	29.50	24.80	34	30.40	42	38.90	40.90	41.70
निरक्षर	57	68.60	66.40	54.60	62.10	70.50	75.20	66	69.60	58	61.10	59.10	58.30

स्रोत : सर्वे ऑफ इंडिया (2011)



तालिका क्रमांक 02: जिला धार : विकासखण्डवार ग्रामीण महिला साक्षरता का वितरण प्रतिरूप (प्रतिशत)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	साक्षरता वितरण एवं ग्रामों की संख्या					ग्रामों की संख्या
		0-20	20-40	40-60	60-80	80 से अधिक	
1	बदनावर	03	48	87	25	02	165
2	सरदारपुर	32	102	53	04	00	191
3	तिरला	13	79	43	10	00	145
4	धार	01	11	73	11	01	97
5	नालछा	20	73	74	11	02	180
6	गंधवानी	21	90	31	03	00	145
7	बाग	18	56	45	01	00	90
8	कुक्षी	05	20	21	01	00	47
9	डही	03	44	14	00	00	61
10	निसरपुर	03	12	38	03	01	57
11	मनावर	01	26	65	02	01	95
12	बाकानेर	01	25	70	07	00	103
13	धरमपुरी	02	36	51	11	01	101
	<b>योग</b>	<b>121</b>	<b>624</b>	<b>636</b>	<b>88</b>	<b>08</b>	<b>1477</b>

स्रोत : सर्वे ऑफ इंडिया (2011) एवं शोधार्थी एवं परिकल्पिता



## आचार्य विशुद्धसागर के साहित्य में अध्यात्म और दर्शन : एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण

डॉ. रचना तैलंग\* दिलीप कुमार जैन\*\*

\* प्राध्यापक (हिन्दी) शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.) भारत  
\*\* शोधार्थी (हिन्दी) शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना - 'अध्यात्म और चिंतन मानव जीवन के महनीय तत्व हैं जो जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। अध्यात्म के द्वारा हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानने का उपक्रम करते हैं। चिंतन हमें वस्तु के मूल स्वरूप को जानने की प्रेरणा प्रदान करता है। जब हमारा चिंतन सकारात्मक होता है तो व्यक्ति को वस्तु का मूल स्वरूप समझ में आता है इस मूल स्वरूप को जानने के पश्चात् व्यक्ति अध्यात्म की जिस दिशा में अग्रसर होता है वही उसके आत्मकल्याण का प्रबल आधार बनता है। भव-भव से बंधन मुक्त होने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को पहचाने और मोक्षमार्ग पर अग्रसर होकर मुक्ति को प्राप्त करे।'**

श्रमण संस्कृति वीतराग मार्ग की परिचायक है, इसे दूसरे शब्दों में दिगम्बर संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग व संयम की शिखर ऊँचाईयों की द्योतक है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर व 24 तीर्थंकरों ने दिगम्बरत्व को धारण कर तपश्चर्या के जिस मार्ग पर अपने जीवन को लगाया था उससे दिगम्बरत्व की अवधारणा भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अक्षय निधि बन गई थी।

दिगम्बर संस्कृति का जीवन और जगत से गहरा संबंध रहा है इसमें अध्यात्म और दर्शन का अत्यंत गंभीरता से अध्ययन देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक मानव चिंतन करता रहेगा तब तक उसके जीवन में दर्शन का महत्व बना रहेगा। अर्थात् जीवन और जगत के विश्लेषण से ही दर्शन का जन्म होता है। मानव ने सर्वप्रथम 'स्व' पर चिंतन किया। तत्पश्चात् अपनी निकटतम वाह्य वस्तुओं पर चिंतन किया। इस प्रकार 'स्व' और 'पर' चिंतन 'स्व' और 'पर' का चिंतन नहीं दर्शन के उद्भव का प्रथम सोपान है। 'कुछ दार्शनिकों का चिंतन यदि तर्क पर आधारित है तो किसी का आश्चर्य पर।'<sup>1</sup> किसी ने संदेह को अपने चिंतन का माध्यम बनाया तो किसी ने आत्मतत्त्व, बुद्धि, प्रेम, बाह्य जगत, आदि को प्रधानता दी है। इस तरह दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा, संदेह या मानसिक अशांति से होती है। मन के अन्दर अन्वेषण और शोध की प्रवृत्ति का जाग्रत होना दर्शन का विषय है।

**1. भारतीय दर्शन का मूल स्रोत -** भारतीय दर्शन के मूल स्रोत के रूप में 'दुःख निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा।' अतः जीवन के प्रति उदासीनता, बैचेनी, और असंतोष की भावना से दर्शन का प्रारंभ होता है। 'इसीलिए गौतम बुद्ध ने शांति की खोज में वनों एवं पर्वतों की कंदराओं में जाकर जीवन के लक्ष्यों पर विचार किया और यही से उनका दर्शन प्रारंभ हुआ।'<sup>2</sup>

भारतीय दार्शनिकों ने तत्त्व के साक्षात्कार या उपलब्धि को दर्शन कहा है। सबसे प्रमुख तत्त्व आत्मा है। कहा भी है- 'आत्मानि विज्ञायते सर्वभिदम विज्ञातम भवति' अर्थात् जो आत्मा को जान लेता है। 'मुक्तिपूर्वक तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को ही दर्शन कहा है।'<sup>3</sup> अतः 'दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है - देखना, विचारना, श्रद्धा करना।'<sup>4</sup>

यहाँ पर एक सीधा सा प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन में दर्शन की आवश्यकता क्यों हुई। इसके पीछे मुख्य कारण यह समझ में आता है कि मनुष्य दर्शन जगत से जुड़कर विभिन्न प्रकार का ज्ञान जीवन में प्राप्त करना चाहता है। दर्शन अर्थात् दार्शनिक चिंतन की 'बुनियाद'। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन उस तत्त्व की खोज करता है जिससे जगत के दुःखों का निवारण हो और किसी उपाय के द्वारा सर्वोच्च सुख की प्राप्ति की जाए। अतः सांसारिक दुःखों के बंधन की निवृत्ति ही जिसे मोक्ष कहा गया है, भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य रहा है।

**2. आचार्य विशुद्धसागर का दर्शन और अध्यात्म -** आचार्य विशुद्धसागर का सृजन मुख्य रूप से दर्शन और अध्यात्म को ही केन्द्र बिन्दु मानकर लिखा गया है। आचार्य श्री का मानना है कि सांसारिक प्राणी भौतिक चकार्चोर्ध में अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को भूलकर इस संसार में ऐसा उलझ जाता है कि उसे इस उलझन के परिणामों को भवों-भवों तक भोगना पड़ता है। यही वजह है कि आचार्य श्री व्यक्ति को वाह्य वस्तुओं के प्रति अनासक्त होकर आत्मतत्त्व से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अध्यात्म साधारण को असाधारण बना देता है। साधारण मनुष्य इच्छाओं के वशीभूत अतृप्ति में जीता है और असाधारण मनुष्य इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर आत्मसुख की अनुभूति करता है। साधारण व्यक्ति को सांसारिक सुख की तलाश होती है जबकि असाधारण व्यक्ति करुणा के भाव को अपनी आत्मा में जागृत कर उसे सम्यक्दर्शन का अंग बनालेता है। साधारण व्यक्ति मोह में जीता है और असाधारण व्यक्ति मोह छोड़कर पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आचार्य श्री का मानना है कि यदि व्यक्ति आत्मसुख की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे ममत्व भाव को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विषय कषाय में जीने वाला व्यक्ति उस शीतल सरोवर का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जो वो चाहता है। इसके लिए उसे विषय कषायों के दल-दल से निकलकर आत्मविशुद्धि में रमण करना होगा। आचार्य श्री लिखते हैं-

'विषयों की ज्वाला में  
जलने वालों को

समाधि जल से पूर्ण  
चैतन्य शीतल सरोवर का  
सुख प्राप्त नहीं होता।

वह विषय कषायों के दलदल में फँसकर  
आत्मविशुद्धि से हीन  
होकर रो रहा है।<sup>5</sup>

इस भौतिक संसार के क्रियाकलापों में व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसे जो कुछ इस संसार में दिख रहा है वही सत्य है। जबकि ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि जब तक बाह्य जगत की ओर रहेगी तब तक वह आंतरिक सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। पुण्य के प्रभाव से यदि मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होती है तो यह सब सामयिक है। इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इन अस्थिर चीजों के प्रति लगाव व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटकने के लिए विवश कर देता है। इस सत्य को जानने के लिए आचार्य श्री कहते हैं-

मत भूल जाना  
जो दिख रहा है  
लोक यश  
मान-सम्मान  
वह पुण्य का  
विपाक है।  
पाप-विपाक के  
आने पर दर-दर  
भटकना पड़ता है।  
अतः विपाक के  
मर्म को जान।<sup>6</sup>

आत्मसुख को प्राप्त करने के लिए हमें चिंतन-मनन करते हुए अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना होगा। अध्यात्म की अनुभूति वही कर सकता है जिसने संकल्पित भाव से संयम को धारण किया हो। संयम के द्वारा व्यक्ति असद्वृत्तियों का परित्याग कर सद्वृत्तियों की ओर प्रवृत्त होता है। ये सद्वृत्तियाँ व्यक्ति के जीवन में शुचिता का संचार करते हुए निर्मल भावों का प्रादुर्भाव कर आत्मप्रेरणा देकर सुख को प्राप्त करने की ओर इंगित करती हैं जो कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। संयम के महात्म्य को प्रतिपादित करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं-

'सुख का साधन है  
संयम भाव  
दुर्गत से रक्षक है  
संयम भाव  
सुगति का साधन है  
संयम भाव

प्राणी मात्र की  
प्रवृत्ति की निवृत्ति है  
संयम भाव  
संयम पर जो जीता है,  
वह पूज्यता को पाता है।<sup>7</sup>

इस प्रकार आचार्य विशुद्धसागर द्वारा अध्यात्म, दर्शन के स्वरूप को अपने सृजन के माध्यम से जिन उदात्त भावों के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की है वह निःसंदेह जगत के प्राणियों के लिए मोक्षमार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वास्तव में देखा जाये तो उनका समग्र सृजन अध्यात्म और दर्शन से ओतप्रोत है। मानव के अंदर व्याप्त उसकी शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने के लिए आचार्य श्री ने जो अध्यात्म की संजीवनी प्रदान की है तथा उससे आम श्रावकों में जो जागृति आयी है वह निश्चित रूप से उनके आत्मकल्याण की भावना को पुष्ट करेगी और उनका जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा।

**निष्कर्ष** - आचार्य विशुद्धसागर अध्यात्म और दर्शन के पुरोध हैं। अध्यात्म हमें आत्मदर्शन की प्रेरणा देता है और चिंतन के द्वारा हम इस भौतिक जगत के सत्यासत्य को जानने का प्रयास करते हैं। भौतिकता की चकाचौंध में फंसा हुआ व्यक्ति अध्यात्म के महत्व को नहीं समझ पाता और चिंतन की भावना उसमें जाग्रत नहीं होती। इसीलिए वह जीवन के उन मूल्यवान क्षणों को भी चूँ ही व्यतीत कर देता है, जो कि उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। विवेक और बोध की जाग्रति प्रत्येक मनुष्य में अपरिहार्य मानी गयी है, जब तक हम आत्मचिंतन के द्वारा उस जीवन के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक जीवन को अर्थवान बना पाना कदापि संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करे, आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त हो, मोह के बंधनों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे, विकारों से दूरी बनाते हुए यह प्रयास करे कि उसे आत्मविशुद्धि के माध्यम से कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होकर जीवन को सार्थक बनाना है।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Phylosphy being in wonder (दर्शन का उद्भव और आश्चर्य), प्लेटो का कथन।
2. जैन काव्यों का दार्शनिक मूल्यांकन, - डॉ. जिनेन्द्र जैन, पृष्ठ- 129
3. भारतीय दर्शन चटर्जी एवं दत्त, पुस्तक भंडार पटना, पृष्ठ-01,
4. सर्वदर्शन संग्रह (माधवाचार्य), भाष्यकार - प्रो. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', पूर्व पीठिका -पृष्ठ-26।
5. ज्ञायक भाव, (घातक), आचार्य विशुद्धसागर, पृष्ठ-389
6. वही, (कर्म विपाक), पृष्ठ-425
7. वही, (संयम धर्म), पृष्ठ - 259

\*\*\*\*\*